परीक्षा मंथन ™

करेंट अफेयर्स ईयरबुक

(Current Affairs YearBook)

2015-2016

भाग - 10, 11, 12 (त्रियांक)

संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की वर्ष 2015-16 की सभी आगामी परीक्षाओं तथा SSC, Bank, रेलवे आदि की भर्ती परीक्षाओं हेतु करेंट अफेयर्स का अत्यंत उपयोगी वार्षिक संकलन

विषय-प्रवेश

संपादक : अनिल अग्रवाल

प्रधान कार्यालय : 7R/5 ताशकंद मार्ग सिविल लाइंस, इलाहाबाद-211001

मोबाइल नं. : 09335151971

website : www.manthanprakashan.com

email : manthan.prakashan.@gmail.com

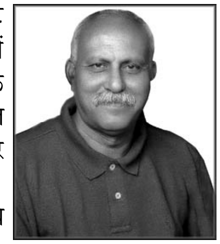
www.facebook.com/parikshamanthan

पंजीकरण संख्या : 64777/96

मूल्य : 120/- (एक सौ बीस रुपये मात्र)

सम्पादकीय

सुधी पाठकों,



'मंथन प्रकाशन' के त्रियांकों की शृंखला की चतुर्थ एवं आखिरी वार्षिक प्रस्तुति—'परीक्षा मंथन करेंट अफेयर्स ईयर बुक' (सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण-2015-16) का भाग-10,11,12 आपके हाथों में है, जिसे हमने पूर्णतः परीक्षोपयोगी बनाने का प्रयास किया है। इस त्रियांक में हमने सामयिक व समसामयिक घटनाओं एवं महत्त्वपूर्ण जानकारियों को परीक्षा के रुझानों के अनुरूप बिन्दुवार प्रस्तुत किया है। इसके विस्तृत एवं व्यापक फलक एवं प्रस्तुति को ध्यान में रखकर यह कहना समीचीन होगा कि इस त्रियांक का स्वरूप 'गागर में सागर' जैसा है।

यह त्रियांक नवंबर, 2015 के प्रारंभ तक अद्यतन है। इसके मुख्य आकर्षण हैं—'तृतीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन-2015', 'संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सम्मेलन-2015', 'विकास हेतु वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2015', चीन की एक बच्चा नीति में परिवर्तन', 'राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2015', 'आईएनडीसी (INDC) : जलवायु परिवर्तन पर भारत के अभिप्रेत योगदान', 'जी-4 समूह की शिखर बैठक', 'V-20' एवं 'W-20' आदि। ये सभी विषय आगामी एवं आसन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से विशेष रूप से प्रत्याशित हैं। यहां यह रेखांकित करना समीचीन रहेगा कि इस त्रियांक की उपादेयता वैसे तो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए है, किंतु 'भारतीय सिविल सेवा (IAS) मुख्य परीक्षा, 2015' के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इस परीक्षा को केंद्र में रखकर ही इस त्रियांक को गढ़ा गया है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देश की इस शीर्ष परीक्षा को ध्यान में रखकर 'मंथन प्रकाशन' द्वारा शीघ्र ही अलग से चुनिंदा निबंधों का एक संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। शीघ्र प्रकाश्य इस संकलन 'सिविल सेवा निबंध विशेषांक' में परीक्षा के प्रारूप को ध्यान में रखकर हमने ऐसे निबंधों को स्थान दिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित हैं।

आपको यह स्मरण करवाना चाहूंगा कि शीघ्र ही 'उ. प्र. सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (लोअर सबार्डिनेट) प्रारंभिक परीक्षा-2015' संपन्न होने जा रही है। इस परीक्षा पर केंद्रित सामग्री हम दो भागों में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसका पहला भाग (भाग-1) 'सामान्य अध्ययन तथ्य सार (General Studies Facts Roundup), सामान्य अध्ययन व प्रारंभिक गणित' बाजार में उपलब्ध है तथा परीक्षार्थियों के बीच इसकी जबरदस्त मांग बनी हुई है। इसका दूसरा एवं अंतिम भाग (भाग-2) 'करेंट अफेयर्स प्वाइंटर' ताजा-तरीन एवं परीक्षोपयोगी जानकारियों व तथ्यों के साथ परीक्षा के ठीक तीन सप्ताह पूर्व आपको उपलब्ध हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करने के साथ आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा अगला एवं नए वर्ष का पहला त्रियांक जनवरी, 2016 के प्रारंभ में प्रकाशित होगा।

संपर्क : 09335151971
09794530483

आपका
अनिल अग्रवाल
संपादक

हमारे करेंट अफेयर्स ईयरबुक (त्रियांक-2016) का प्रकाशन कार्यक्रम

* 15 जनवरी, 2016 भाग-1, 2, 3 त्रियांक
* 15 अप्रैल, 2016 भाग-4, 5, 6 त्रियांक
* 15 जुलाई, 2016 भाग-7, 8, 9 त्रियांक
* 15 अक्टूबर, 2016 भाग-10, 11, 12 त्रियांक

अपरिहार्य कारणों अथवा विभिन्न परीक्षा कार्यक्रमों को देखते हुए उपरोक्त तिथियों में हल्का फेरबदल संभव है।

राष्ट्रीय मंथन

● राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक घोषित ● 'आधार' पर संविधान पीठ का निर्णय ● दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स ● नीरांचल : राष्ट्रीय जलसंभर प्रबंधन परियोजना ● भारत द्वारा आपदा जोखिम शमन पर सेंडाई फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन ● कॉल ड्रॉप पर ट्राई के नए विनियम ● श्यामा प्रसाद मुखर्जी 'रर्बन' मिशन को स्वीकृति ● जनगणना 2011 के धर्म आधारित आंकड़े ● जनगणना 2011 : परिवारों की शैक्षणिक स्थिति ● संथारा प्रथा पर प्रतिबंध पर उच्चतम न्यायालय की रोक ● मानव डीएनए प्रालेखन विधेयक, 2015 ● भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष की उग्र होती समस्या ● 'मणिपुर आगंतुक एवं प्रवासी कामगार विधेयक-2015' ● पंचायत प्रत्याशियों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण पर रोक ● गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2015 ● राजस्थान में आरक्षण संबंधी दो विधेयक पारित ● वन रैंक, वन पेंशन ● देश में आत्महत्याओं पर एनसीआरबी की रिपोर्ट ● गोदावरी को जोड़ा गया कृष्णा से ● प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ● भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में 13 कानून समाहित ● 'मैगी' नूडल्स का उत्पादन पुनः प्रारंभ ● नगा अलगाववादियों से समझौता ● 'कौशल भारत' अभियान का शुभारंभ ● ग्रामीण भारत हेतु सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 के प्रॉविजिनल आंकड़े ● डिजिटल इंडिया सप्ताह ● भारतीय परमाणु बीमा पूल ● काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं आस्ति) और करारोपण अधिनियम, 2015 ● भारत में सामाजिक उपभोग के शिक्षा पर मुख्य संकेतक ● तीन नए नगरीय विकास मिशनों का शुभारंभ ● अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ● संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015 ● राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का विस्तार ● नीति (NITI) आयोग की स्थापना ● चेन्नई एवं जयपुर मेट्रो का शुभारंभ ● बाणसागर बांध विवाद ● 'नमामि गंगे' : एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन ● तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रारंभ ● हाल के वर्षों में लोक सभा का सर्वाधिक उत्पादक सत्र ● सरस्वती नदी की प्रामाणिकता सिद्ध ● नेट-निरपेक्षता का प्रश्न ● 'फेम-इंडिया' योजना ● 'सागरमाला' परियोजना : नीली क्रांति की ओर ● निर्धारित अंतर्देशीय जलमार्गों को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित करने को स्वीकृति ● 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय अभियान ● मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ ● राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना - 'हृदय'

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक घोषित

- 16 अक्टूबर, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर, न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ तथा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल) की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के गठन संबंधी संसद के अधिनियमों को असंवैधानिक करार देते हुए शून्य घोषित कर दिया।
- इस निर्णय के तहत 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने 'संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014' तथा 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' दोनों को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।
- उल्लेखनीय है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु अनुशंसा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 'कोलिजियम सिस्टम' के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन एवं अन्य तत्संबंधी प्रावधानों वाले ये दोनों अधिनियम संसद द्वारा अगस्त, 2014 में पारित किए गए थे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसंबर, 2014 को स्वीकृति दी गई थी।
- इन दोनों अधिनियमों को 13 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया गया था तथापि भारत के मुख्य न्यायाधीश (जिनके एनजेएसी के पदेन अध्यक्ष होने का प्रावधान था) द्वारा इस आयोग में शामिल होने वाले 2 प्रतिष्ठित नागरिकों के चयन हेतु सर्च कमेटी का सदस्य बनने से इंकार करने के कारण एनजेएसी का गठन नहीं किया जा सका था।
- इन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को जनवरी, 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर कर यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इससे न्यायपालिका की स्वायत्तता पर आघात पहुंचेगा और तदनुसार ये अधिनियम संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
- 7 अप्रैल, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय की 3-सदस्यीय पीठ द्वारा इन याचिकाओं को संविधान पीठ (5-सदस्यीय) को संदर्भित किया गया था जिसने अपने कुल 1,030 पृष्ठों के सद्यः निर्णय में यह कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का बुनियादी ढांचा है तथा सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती अतः एनजेएसी संबंधी इन अधिनियमों को निरस्त किया जाता है।
- संविधान पीठ ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि इनसे न सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्चता कम हो रही थी बल्कि राष्ट्रपति की भूमिका भी कमतर हो रही थी क्योंकि न्यायाधीशों के मामले में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करते बल्कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं।
- साथ ही इस संविधान पीठ ने यह मामला और बड़ी पीठ को भेजने की सरकार की मांग भी रद्द कर दी।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की 'कोलिजियम प्रणाली' (देखें–बॉक्स) पुनः बहाल हो गई है। हालांकि संविधान पीठ ने कोलिजियम प्रणाली में कम पारदर्शिता जैसी खामियों को स्वीकार करते हुए सरकार एवं अन्य हितधारकों से इस बारे में सुझाव मांगे हैं तथा कोलिजियम प्रणाली में सुधार की संभावनाओं पर 3 नवंबर, 2015 से सुनवाई प्रारंभ की गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय की इस संविधान पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर ने अलग से दिए गए फैसले में एनजेएसी संबंधी अधिनियमों की वैधानिकता पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने इन्हें न्यायिक सुधार की दिशा में एक कदम बताते हुए यहां तक कहा कि भविष्य ही बताएगा कि मैं सही था या नहीं। हालांकि बहुमत के फैसले को देखते हुए उन्हें एनजेएसी की वैधानिकता परखना बहुत उपयोगी नहीं नजर आया।

कोलिजियम प्रणाली

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अनु. 124, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अनु. 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु अनु. 222 तथा संयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अनु. 231 के तहत प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण न्यायपालिका से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। इस परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाने संबंधी 'कोलिजियम प्रणाली' की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 1993 में सुनाए गए फैसले से हुई। वस्तुतः इस सिस्टम की उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों की शृंखला में निहित है जिन्हें संयुक्त रूप से 'थ्री जजेस केसेस' कहा जाता है। ये तीन महत्त्वपूर्ण फैसले थे–एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) तथा 1998 का विशेष संदर्भ। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को व्याख्यायित करते हुए कहा कि उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति (एवं स्थानांतरण) में विधायिका एवं कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी के अनुरूप उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलिजियम द्वारा लिए जाते हैं जिनका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। यद्यपि राष्ट्रपति (सरकार) द्वारा इस संदर्भ में कोलिजियम की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है परंतु कोलिजियम द्वारा पुनः उसी सिफारिश को संस्तुत किए जाने पर वह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी।

'आधार' पर संविधान पीठ का निर्णय

- 15 अक्टूबर, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार को चार अन्य सामाजिक योजनाओं–मनरेगा, पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और जन धन में आधार का इस्तेमाल करने को स्वीकृति प्रदान कर दी।
- ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 11 अगस्त, 2015 को आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS; केरोसिन वितरण सहित) और एलपीजी सब्सिडी के लिए ही आधार के प्रयोग की मंजूरी दी थी और वह भी इस शर्त के साथ कि सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आधार अनिवार्य नहीं होगा। इस बारे में सरकार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों द्वारा व्यापक प्रचार भी करेगी।
- अपने 15 अक्टूबर के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह पुनः स्पष्ट किया है कि आधार का उपयोग सिर्फ स्वैच्छिक होगा। आधार अनिवार्य नहीं होगा और आधार न होने के कारण किसी को किसी सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई आधार कार्ड प्रस्तुत करने को मजबूर करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का भागी होगा।
- साथ ही संविधान पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के 2013 से अब तक जारी किए गए सभी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।
- आधार कार्ड की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं और आधार कार्ड से निजता के अधिकार (Right to Privacy) के हनन के मुद्दे पर सुनवाई अब नई संविधान पीठ करेगी जिसका गठन शीघ्र ही किया जाएगा।

दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स

- देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की लगातार बढ़ती समस्या से चिंतित सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2015 को व्यावसायिक/वाणिज्यिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाए जाने का आदेश दिया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ (अन्य सदस्य- न्यायमूर्तिद्वय अरुण मिश्रा एवं आदर्श कुमार गोयल) ने यह ऐतिहासिक आदेश दिया है।
- इस आदेश के तहत 1 नवंबर, 2015 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC : Environment Compensation Charge) देना होगा।
- टोल टैक्स के अतिरिक्त लगने वाले इस शुल्क के तहत हल्के एवं टू एक्सेल वाणिज्यिक वाहनों से 700 रु. और इससे बड़े (थ्री एक्सेल एवं इससे भारी ट्रकों) वाणिज्यिक वाहनों से 1300 रु. प्रति वाहन शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क टोल ऑपरेटर वसूल कर सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को दिल्ली सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार इस राशि के प्रदूषण नियंत्रण पर व्यय का ब्यौरा प्रत्येक 3 माह पर शीर्ष न्यायालय को देगी।
- प्रायोगिक तौर पर इस नई व्यवस्था को प्रारंभ में 1 नवंबर, 2015 से 29 फरवरी, 2016 तक लागू करने का आदेश दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 1 नवंबर, 2015 से इस आदेश का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के तहत यात्री वाहनों एवं बसों, उपभोक्ता वस्तु एवं खाद्य सामग्री ढोने वाले वाहनों तथा एंबुलेंस सेवाओं को इस पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश के तहत इस मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा 7 अक्टूबर, 2015 को दिए गए निर्णय (जिसके तहत टैक्सियों एवं छोटे ट्रकों जैसे टूएक्सल वाणिज्यिक वाहनों से 700 रु., थ्री एक्सल वाहनों से

1000 रु. और 4 एक्सल एवं इससे भारी वाहनों से 500 रु. का शुल्क लिए जाने का आदेश दिया गया था) को निरस्त कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह महत्त्वपूर्ण आदेश सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के अध्ययन का संज्ञान लेते हुए दिया गया है, जिसके अनुसार दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग 23 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों और 40-60 प्रतिशत तक भारी ट्रकों का गंतव्य दिल्ली न होकर आगे होता है तथा उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अतिरिक्त शुल्क आरोपित होने से इन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग चयन पर आने वाली अतिरिक्त लागत का अंतर संतुलित होगा।
- सीएसई के अध्ययन के अनुसार दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहन यहां परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण में कुल निलंबित कणों (Particulate Matter : PM) के लगभग 30 प्रतिशत और कुल नाइट्रोजन ऑक्साइड के 22 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी होते हैं।

नीरांचल : राष्ट्रीय जलसंभर प्रबंधन परियोजना

- 7 अक्टूबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 'राष्ट्रीय जलसंभर प्रबंधन परियोजना-नीरांचल' (National Watershed Management Project-Neeranchal) को 2142.30 करोड़ रु. (357 मिलियन डॉलर) के परिव्यय के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के जलसंभर घटक के लिए 'नीरांचल' परियोजना पूर्ववर्ती एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम के स्थान पर लाई गई है।
- यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ नौ राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में क्रियान्वित की जाएगी।
- इस परियोजना की 2142.30 करोड़ रु. की कुल लागत में सरकार का हिस्सा 1071.15 करोड़ रु. (50 प्रतिशत) होगा जबकि शेष राशि विश्व बैंक से ऋण घटक के रूप में प्राप्त होगी।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलसंभर घटक के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने, हर खेत को पानी (सिंचाई) सुनिश्चित करने तथा जल के प्रभावी उपयोग (प्रति बूंद ज्यादा फसल) के लिए 'नीरांचल' परियोजना को विशेष रूप से प्रारूपित किया गया है जिससे निम्नलिखित लाभ होंगे—
  - (i) इससे भारत में जलसंभर और वर्षा सिंचित कृषि प्रबंधन के तौर-तरीकों में संस्थागत बदलाव आएंगे।
  - (ii) इससे ऐसी विशेष प्रणालियां सृजित की जा सकेंगी, जो जलसंभर कार्यक्रमों तथा वर्षा सिंचित सिंचाई प्रबंधन के तौर-तरीकों को और बेहतर केंद्रित एवं अधिक समन्वित कर मापनयोग्य परिणाम उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगी।
  - (iii) इससे कार्यक्रम क्षेत्रों में उन्नत जलसंभर प्रबंधन तौर-तरीकों की सततता (जो कि परियोजना समर्थन हटाए जाने के बाद भी जारी रहे) के लिए रणनीतियां तैयार करने में भी मदद मिलेगी।
  - (iv) जलसंभर संलग्न उपागम के माध्यम से समावेशन और स्थानीय भागीदारी के मंच पर भावी लिंकेज के द्वारा उन्नत सहभागिता, आजीविकाओं एवं आय को समर्थन प्राप्त होगा।
- नीरांचल परियोजना के द्वारा पीएमकेएसवाई के बेहतर क्रियान्वयन परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इस कार्यक्रम से वर्षा जल के सतही अपवाह को कम करने, भूजल के पुनर्भरण को बढ़ाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बेहतर करने में सहायता प्राप्त होगी जिससे वर्षा सिंचित कृषि उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा तथा इसके साथ ही परियोजना क्षेत्रों में संबंधित कार्यक्रमों में बेहतर तालमेल के जरिए फसल गहनता भी बढ़ाई जा सकेगी।
- नीरांचल को कुछ इस प्रकार से प्रारूपित किया गया है कि विशेष रूप से पीएमकेएसवाई के जलसंभर घटक और सामान्य रूप से इसके सभी घटकों को तकनीकी सहायता सुलभ हो सके और तदनुसार इन्हें सुदृढ़ता प्रदान कर इसकी डिलिवरी क्षमता को संवर्द्धित किया जा सके।
- जलसंभर विकास परियोजनाएं वास्तव में क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं, अतः इनसे परियोजना क्षेत्र में रहनेवाले सभी लोग लाभान्वित होंगे।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DOLR) द्वारा देश के 28 राज्यों में जलसंभर विकास को समर्थन प्रदान करने हेतु एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) वर्ष 2009-10 से क्रियान्वित किया जा रहा था जिसने 2015-16 से पीएमकेएसवाई के जलसंभर घटक का रूप लिया था। नीरांचल परियोजना पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के स्थान पर पीएमकेएसवाई के जलसंभर घटक को समर्थन उपलब्ध कराएगी।
- उल्लेखनीय है कि देश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सुधार और निर्धनता उन्मूलन के मूल उद्देश्यों के साथ इन क्षेत्रों में संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु जलसंभर विकास कार्यक्रम 1970 के दशक से चलाए जा रहे हैं। इनमें वर्षा सिंचित क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन, भू-अपरदन को कम करना, मिट्टी की पोषकता में वृद्धि करना, भूमिगत जल का पुनर्भरण आदि शामिल होते हैं।

भारत द्वारा आपदा जोखिम शमन पर सेंडाई फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन

- भारत द्वारा आपदा जोखिम शमन (Disaster Risk Reduction) पर सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) का पूर्णतः और समग्र रूप से क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू द्वारा 24 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में 'आपदा जोखिम शमन हेतु निजी क्षेत्र भागीदारी का उन्नयन' विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की गई।

सेंडाई रूपरेखा (Sendai Framework) 2015-2030

यह एक 15 वर्षीय गैर-बाध्यकारी अंतर्सरकारी समझौता है जो आपदा जोखिम शमन हेतु राष्ट्रीय सरकारों की केंद्रीय एवं प्राथमिक भूमिका को स्वीकार करने के साथ अन्य हितधारकों यथा- स्थानीय सरकारों एवं निजी क्षेत्र के द्वारा उत्तरदायित्व की भागीदारी का आह्वान करता है। इस रूपरेखा के तहत आपदा जोखिम शमन हेतु 4 मुख्य प्राथमिकता कार्रवाइयां निश्चित की गई हैं—

1. आपदा जोखिम को समझना;
2. आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु आपदा जोखिम अभिशासन को सुदृढ़ करना;
3. प्रत्यास्थता (Resilience) हेतु आपदा जोखिम शमन में निवेश; तथा
4. प्रभावी अनुक्रिया हेतु आपदा तैयारियों का संवर्द्धन।

सेंडाई रूपरेखा के तहत तय 7 वैश्विक लक्ष्य इस प्रकार हैं—

(a) वर्ष 2030 तक वैश्विक आपदा मर्त्यता को सार्थक रूप से कम करना (2005-2015 अवधि की तुलना में 2020-2030 दशक में औसतन प्रति 1 लाख व्यक्ति वैश्विक मृत्यु दर में कमी लाना)।

(b) वर्ष 2030 तक वैश्विक रूप से प्रभावित लोगों की संख्या में सार्थक रूप से कमी लाना।

(c) वर्ष 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक हानियों को कम करना।

(d) वर्ष 2030 तक स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं सहित बुनियादी सेवाओं के अवरोध और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की आपदा क्षतियों को सार्थक रूप से कम करना।

(e) वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय एवं स्थानीय आपदा जोखिम रणनीतियों से युक्त देशों की संख्या में सार्थक वृद्धि करना।

(f) वर्ष 2030 तक वर्तमान रूपरेखा के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय कार्यवाहियों को अनुपूरित करने हेतु पर्याप्त एवं सतत समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सार्थक अभिवृद्धि करना।

(g) वर्ष 2020 तक बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों (Multi-hazard early warning systems) तथा आपदा जोखिम सूचना की लोगों तक पहुंच एवं उपलब्धता को सार्थक रूप से बढ़ाना।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005-2015 के दौरान आपदाओं के कारण वैश्विक स्तर पर 7 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 1.4 मिलियन से अधिक लोग घायल और 23 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए जबकि इनके कारण 1.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक हानि भी प्रत्यक्ष हुई।

- उन्होंने कहा कि भारत ने आपदा जोखिम शमन के क्षेत्र में अपने पड़ोसियों तथा अन्य देशों को सहायता प्रदान करने के प्रयासों में अभिवृद्धि की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के भाग के रूप में निजी क्षेत्र आपदा तैयारियों और उपशमन योजनाओं के साथ राहत और पुनर्स्थापना कार्यों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि 14 से 18 मार्च, 2015 के दौरान जापान के मियागी प्रीफ़ैक्चर के सेंडाई में 'आपदा जोखिम शमन पर तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन' (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction) का आयोजन किया गया था जिमसें 'ह्यूगो रूपरेखा 2005-2015' के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई थी तथा 'आपदा जोखिम शमन पर सेंडाई रूपरेखा 2015-2030' को अपनाया गया था।
- इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया था तथा उन्होंने वर्ष 2016 में 'आपदा जोखिम शमन पर सातवें एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' का आयोजन भारत में किए जाने की घोषणा की थी।

कॉल ड्रॉप पर ट्राई के नए विनियम

- दूरसंचार के संदर्भ में कॉल ड्रॉप (Call Drop) से तात्पर्य फोन कॉल के बीच में तकनीकी कारणों से कॉल के कट जाने से है, अर्थात जब कॉल के प्रेषक या प्राप्तकर्ता द्वारा फोन काटने से पूर्व स्वतः ही संपर्क टूट जाए तो इसे कॉल ड्रॉप कहते हैं।
- हाल के समय में विशेष रूप से देश के महानगरों में कॉल ड्रॉप की समस्या तेजी से बढ़ी है जिसका मुख्य कारण उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या की तुलना में दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा पर्याप्त और समुचित अवसंरचना (यथा- अधिक मोबाइल टॉवर, स्विचिंग क्षमताएं आदि) तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं न उपलब्ध करा पाना है।
- कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या को देखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा 16 अक्टूबर, 2015 को सख्त विनियम जारी किए गए हैं जिसके तहत एक कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार ऑपरेटर कंपनियों को ग्राहकों को एक रुपया देना होगा। हालांकि एक दिन में एक ग्राहक को अधिकतम 3 कॉल ड्राप के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सकेगी।
- ट्राई द्वारा जारी ये प्रावधान 1 जनवरी, 2015 से लागू होंगे।
- दूरसंचार ऑपरेटर कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने पर 4 घंटे में एसएमएस और यूएसएसडी के जरिए ग्राहक को इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही प्रीपेड ग्राहकों के खाते में यह राशि डालनी होगी जबकि पोस्टपेड ग्राहकों के अगले बिल में यह राशि कम की जाएगी।

- यह क्षतिपूर्ति राशि कॉल करने वाले उपभोक्ता को प्राप्त होगी तथा यह तभी दी जाएगी जबकि कॉल ड्रॉप प्रेषक के नेटवर्क की कमी से हुआ हो। प्राप्तकर्ता नेटवर्क की समस्या की वजह से हुए कॉल ड्रॉप के लिए क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- इससे पूर्व 15 अक्टूबर, 2015 को ट्राई द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों पर कॉल ड्रॉप सहित खराब गुणवत्ता वाली मोबाइल सेवाओं के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया था।
- इसके तहत तकनीक संबंधी गुणवत्ता मानदंडों को किसी एक तिमाही के संदर्भ में पूरा न करने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों पर लगाया जाने वाला जुर्माना 50,000 रु. से बढ़ाकर 1 लाख रु. कर दिया गया है जो कि लगातार अगली तिमाही और फिर क्रमिक तिमाहियों में मानदंडों का पुनः उल्लंघन होने पर क्रमशः 1.5 लाख रु. और 2 लाख रु. हो जाएगा। हालांकि ग्राहक सेवा गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन न होने पर किसी एक तिमाही के संदर्भ में जुर्माने की राशि को 50,000 रु. पर पूर्ववत रखा गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी 'रर्बन' मिशन को स्वीकृति

- 16 सितंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से संपोषणीय क्षेत्रों में रूपांतरित करने के महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य वाले 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन' (SPMRM : Shyama Prasad Mukherji Rurbun Mission) को 5,142.08 करोड़ रु. के आवंटन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2014-15 के संघीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु इस मिशन को प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी।
- रर्बन (Rurban : Rural + Urban) मिशन के तहत स्मार्ट ग्रामों के समूह (Cluster of Smart Villages) सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे।
- स्मार्ट ग्रामों के समूह ऐसे ग्रामीण संवृद्धि क्लस्टर होंगे जिनमें विकास की अंतर्निहित संभाव्यता होगी और ये पूरे क्षेत्र में समग्र विकास को सक्रिय करेंगे।
- स्मार्ट ग्रामों के इन समूहों को आर्थिक गतिविधियों की उपलब्धता, कौशल एवं स्थानीय उद्यमिता विकास तथा अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से विकसित किया जाएगा।
- ये समूह विधिक योजना मानकों के अनुरूप तैयार योजनाबद्ध विन्यास के साथ अच्छी तरह से निरूपित क्षेत्र होंगे जिन्हें राज्यों/संघीय क्षेत्रों द्वारा यथोचित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इनकी योजनाओं को अंतिम रूप से जिला योजना/मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- राज्य सरकारें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई क्रियान्वयन रूपरेखा के अनुसरण में इन समूहों की पहचान करेंगी।
- इन समूहों में भौगोलिक रूप से संलग्न ऐसी ग्राम पंचायतों के क्षेत्र शामिल होंगे जिनकी समग्र जनसंख्या मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 और मरुस्थलीय, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक होगी।
- जनजातीय और गैर-जनजातीय जिलों में इन समूहों के चयन हेतु पृथक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जहां तक उपयुक्त होगा, ये ग्राम समूह ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक अभिसरण इकाइयों का अनुसरण करेंगे।
- इस मिशन के तहत ग्राम समूहों के चयन हेतु केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसमें जिला, उप जिला और ग्राम स्तर पर जनांकिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यटन एवं तीर्थस्थल के रूप में महत्त्व तथा परिवहन कॉरिडोर प्रभाव का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण शामिल है। इस विश्लेषण के आधार पर मंत्रालय राज्यों को उप जिलों की ज्ञापक सूची उपलब्ध कराएगा जिसके पश्चात राज्य सरकारें क्रियान्वयन रूपरेखा में शामिल निदेशक मानदंडों के आधार पर ग्राम समूहों का चयन करेंगी।
- इस मिशन के तहत देश भर में अगले 3 वर्षों में ऐसे 300 रर्बन संवृद्धि समूहों को विकसित करने का लक्ष्य है।
- रर्बन समूहों का वित्तीयन, समूह में अभिसरित विभिन्न सरकारी योजनाओं (पंचायत स्तर की योजनाओं) के माध्यम से किया जाएगा। मिशन के तहत ऐसे रर्बन समूहों के विकास को समर्थन हेतु केंद्रीय हिस्से के रूप में प्रति ग्राम समूह, परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तक की राशि अतिरिक्त वित्तीयन समर्थन हेतु क्रिटिकल गैप फंडिंग के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
- विकास का अनुकूलतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए चयनित ग्राम समूहों हेतु अभीष्ट 14 घटक सुझाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं—आर्थिक गतिविधियों से संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण/कृषि सेवाएं/भंडारण एवं भंडारगृह, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, नलों से पेयजल आपूर्ति, ठोस एवं द्रव कचरा प्रबंधन, गांवों की सड़कें एवं नालियां, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, पूर्णतः सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, उन्नयित स्कूल/उच्चतर शिक्षा सुविधाएं, अंतर-ग्रामीण सड़क संयोजकता, नागरिक केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी हेतु नागरिक सेवा केंद्र/ई-ग्राम कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन एवं एलपीजी गैस कनेक्शन।
- राज्य रर्बन समूहों के लिए एकीकृत समूह कार्य योजनाएं (Integrated Cluster Action Plans) तैयार करेंगे जो ग्राम समूह हेतु रणनीति, मिशन के तहत ग्राम समूहों के लिए अभीष्ट परिणाम, विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित और राज्य क्षेत्र योजनाओं के तहत अभिसरित होने वाले संसाधनों और आवश्यक क्रिटिकल गैप फंडिंग के विस्तृत विवरण वाले व्यापक योजना दस्तावेज होंगे।
- रर्बन मिशन के तहत क्रिटिकल गैप फंडिंग के अतिरिक्त राज्य स्तर पर परियोजना विकास, क्षमता निर्माण एवं अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के संदर्भ में राज्य सरकारों को समर्थन हेतु पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के साथ इस मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय कदम उठाए जाएंगे।
- इस मिशन का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाओं की परिकल्पना

मिशन के तहत की गई है। इस मिशन के तहत अनुसंधान, विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक 'नवाचार बजट' (Innovation Budget) की भी व्यवस्था है।

- यह मिशन रर्बन संवृद्धि समूहों के विकास के माध्यम से समग्र क्षेत्रीय विकास को उत्प्रेरित करेगा जिससे अंततः देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के साथ शहरी क्षेत्रों पर से दबाव कम होगा जो कि देश को संतुलित क्षेत्रीय विकास और संवृद्धि की ओर आगे बढ़ाएगा।
- उल्लेखनीय है इससे पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं एवं आर्थिक अवसर उपलब्ध कराकर संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा 'पूरा' (PURA : Provision of Urban Amenities in Rural Area; भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत संकल्पना) योजना वर्ष 2004 में पायलट आधार पर विभिन्न राज्यों में प्रारंभ की गई थी जिसके अनुभवों के आधार पर फरवरी, 2012 में 'पुनर्संरचित पूरा योजना' (Restructured PURA Scheme) लाई गई थी। नया रर्बन मिशन इसी योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया है तथापि पूर्ववर्ती योजना की तुलना में नए मिशन का फलक काफी विस्तृत है।

जनगणना 2011 के धर्म आधारित आंकड़े

- भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना 2011 के धर्म आधारित आधिकारिक आंकड़े 25 अगस्त, 2015 को जारी किए गए।
- जनगणना 2011 के धर्म आधारित आंकड़ों के अनुसार 2011 में देश में कुल हिंदू जनसंख्या 966.3 मिलियन (96.63 करोड़) है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 79.8 प्रतिशत (पहली बार 80 प्रतिशत से कम) है। 2001-11 के दौरान हिंदू जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 16.76 प्रतिशत (1991-2001 में यह 19.92 प्रतिशत थी) रही है।
- 2011 में देश में कुल मुस्लिम जनसंख्या 172.2 मिलियन (17.22 करोड़) है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 14.23 प्रतिशत है। 2001-11 के दौरान मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 24.6 प्रतिशत रही है जो कि देश के सभी प्रमुख धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक है (हालांकि विगत दशक 1991-2001 के 29.52 प्रतिशत की तुलना में इसमें अच्छी कमी दर्ज हुई है)।
- 2011 में देश में कुल ईसाई जनसंख्या 27.8 मिलियन (2.78 करोड़) है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत है। 2001-11 के दौरान ईसाई जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 15.5 प्रतिशत रही है।
- 2011 में देश में सिख समुदाय की कुल जनसंख्या 20.8 मिलियन (देश की जनसंख्या का 1.72 प्रतिशत), बौद्धों की कुल जनसंख्या 8.4 मिलियन (देश की जनसंख्या का 0.7 प्रतिशत) तथा जैन मतावलंबियों की कुल जनसंख्या 4.5 मिलियन (देश की जनसंख्या का 0.4 प्रतिशत) है। 2001-11 अवधि में इन तीनों धर्मों को मानने वालों की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 8.4, 6.1 एवं 5.4 प्रतिशत रही है।
- जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में उपर्युक्त धर्मों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के मानने वालों की संख्या 7.9 मिलियन (देश की जनसंख्या का 0.7 प्रतिशत) है जबकि 2.9 मिलियन (देश की जनसंख्या का 0.2 प्रतिशत) लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने धर्म का उल्लेख नहीं किया गया।

कुल जनसंख्या में धर्मानुसार प्रतिशत

धर्म	कुल जनसंख्या में प्रतिशत	
	2001	2011
हिन्दू	80.5	79.8
मुसलमान	13.4	14.2
ईसाई	2.3	2.3
सिख	1.9	1.7
बौद्ध	0.8	0.7
जैन	0.4	0.4
अन्य	0.6	0.7
धर्म का उल्लेख नहीं	0.1	0.2
कुल	100.0	100.0

- ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के संदर्भ में 2011 में कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत क्रमशः 82.06 एवं 74.83 है जबकि मुस्लिमों का प्रतिशत क्रमशः 12.42 एवं 18.23 है।
- जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जहां देश का समग्र लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) 943 है वहीं हिंदुओं में यह 939, मुस्लिमों में 951, ईसाइयों में 1023, सिखों में 903, बौद्धों में 965 एवं जैनों में 954 है। अन्य धर्मों के लोगों में लिंगानुपात 1009 तथा धर्म का उल्लेख न करने वालों में 959 है।

धर्मानुसार दशकीय वृद्धि दर एवं लिंगानुपात

धर्म	दशकीय वृद्धि दर (%)	लिंगानुपात	
	2001-11	2001	2011
हिन्दू	16.8	931	939
मुसलमान	24.6	936	951
ईसाई	15.5	1009	1023
सिख	8.4	893	903
बौद्ध	6.1	953	965
जैन	5.4	940	954
अन्य	19.7	992	1009
धर्म का उल्लेख नहीं	314.3	—	959
कुल	17.7	933	943

- देश के सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः लक्षद्वीप (96.58%), जम्मू एवं कश्मीर (68.31%), असम (34. 22%), पश्चिम बंगाल (27.01%) एवं केरल (26.56%) में है।
- 2011 में ईसाइयों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः

नगालैंड (87.93%), मिजोरम (87.16%), मेघालय (74.59%), अरुणाचल प्रदेश (30.26%) एवं गोवा (25.10%) हैं।

- 2011 में राज्य की जनसंख्या में सिखों का सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में (57.79%), बौद्धों का सिक्किम में (27.39%), जैनों का महाराष्ट्र में (1.25%), अन्य धर्मों के मानने वालों का अरुणाचल प्रदेश में (26.20%) तथा किसी धर्म का उल्लेख न करने वालों का सर्वाधिक प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश (संयुक्त) में (दोनों में 0.48%) है।
- 2011 में राज्य/संघीय क्षेत्र की जनसंख्या में हिंदुओं के न्यूनतम प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः मिजोरम (2.75%), लक्षद्वीप (2.77%), नगालैंड (8.75%), मेघालय (11.53%) तथा जम्मू एवं कश्मीर (28.44%) है।
- 2001-11 अवधि में मुस्लिमों की दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से असम (34.22%), प. बंगाल (27.01%) तथा केरल (26.56%) ऐसे राज्य हैं जहां यह 1991-2001 की तुलना में अधिक रही है।
- यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि देश के सभी धर्मावलंबियों में महिलाओं की वृद्धि दर पुरुषों की वृद्धि दर से अधिक रही है।

जनगणना 2011 : परिवारों की शैक्षणिक स्थिति

- 24 सितंबर, 2015 को जनगणना 2011 के तहत देश के परिवारों (जिनमें कम से कम एक सदस्य 15 वर्ष या अधिक आयु का है) की शैक्षणिक स्थिति पर आंकड़े जारी किए गए।
- इन आंकड़ों के अनुसार देश में 15 वर्ष या अधिक आयु के कम से कम एक सदस्य वाले परिवारों की कुल संख्या 248.3 मिलियन (24.83 करोड़) है जिसमें से 122.9 मिलियन (49.5%) परिवारों में कम से कम एक सदस्य को मैट्रिक या उच्चतर स्तर की शिक्षा प्राप्त थी।
- एक दशक पूर्व (2001 में) ऐसे परिवारों का प्रतिशत मात्र 39.4 था।
- 2001 में 15 वर्ष या अधिक आयु के कम से कम एक सदस्य वाले परिवारों में कम से कम एक स्नातक सदस्य वाले परिवारों की संख्या 23.6 मिलियन (12.2%) थी जो कि 2011 में बढ़कर 41.4 मिलियन (16.7%) हो गई है।
- 2011 में देश में कम से कम एक पुरुष मैट्रिकुलेट या उच्चतर शिक्षा प्राप्त सदस्य वाले परिवारों की संख्या 104.7 मिलियन (42.2%) तथा कम से कम एक महिला मैट्रिकुलेट या उच्चतर शिक्षा प्राप्त सदस्य वाले परिवारों की संख्या 75.3 मिलियन (30.3%) थी।
- 2011 में देश में कम से कम एक पुरुष स्नातक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त सदस्य वाले परिवारों की संख्या 33.2 मिलियन (13.4%) और कम से कम एक महिला स्नातक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त सदस्य वाले परिवारों की संख्या 21.9 मिलियन (8.8%) थी।

संथारा प्रथा पर प्रतिबंध पर उच्चतम न्यायालय की रोक

- 'संथारा' या 'सल्लेखना' जैन धर्म की प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है जिसके तहत स्वेच्छा से उपवास द्वारा प्राणों का त्याग किया जाता है।
- इस प्रथा के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता निखिल सोनी द्वारा वर्ष 2006 में राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर इसे सती प्रथा (एवं इच्छा मृत्यु) के समकक्ष बताते हुए आत्महत्या की श्रेणी में रखने की मांग की गई थी।
- उक्त याचिका पर निर्णय देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त, 2015 को संथारा प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा संथारा लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 (आत्महत्या के प्रयास) और संथारा लेने हेतु उकसाने वालों के विरुद्ध धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया था।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद द्वारा उच्चतम न्यायालय में यह तर्क देते हुए याचिका दायर की गई थी कि जैन धर्म में संथारा प्रथा आत्म स्वतंत्रता एवं अंतिम साधना को व्यक्त करती है तथा यह आत्महत्या न होकर शोकमुक्त एवं सुख से समाधि लेना है। ज्ञातव्य है कि अल्पवयस्कों एवं स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा इसके अनुपालन का निषेध है।
- 31 अगस्त, 2015 को उच्चतम न्यायालय ने संथारा प्रथा पर प्रतिबंध के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाते हुए जैन मतावलंबियों को इस प्रथा के अनुपालन की छूट दे दी।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रतिबंध को हटाए जाने के पश्चात (हालांकि अभी इस मामले में अंतिम निर्णय आना शेष है) अब जैन समुदाय द्वारा पुनः घोषित रूप से संथारा प्रथा को अपनाने के मामले प्रारंभ हो गए हैं। बीकानेर (राजस्थान) की वयोवृद्ध जैन महिला बदनी देवी द्वारा संथारा लेकर 5 सितंबर, 2015 को मृत्यु का वरण किया गया।

क्या है संथारा प्रथा

संथारा प्रथा जैन समुदाय में हजारों वर्षों से प्रचलित है, जिसके तहत इन तीन स्थितियों में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न-जल त्यागकर मौत का वरण कर सकता है—(1) वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो, (2) वह गंभीर प्रकार की विकलांगता का शिकार हो, (3) वह मृत्यु के नजदीक (मरणासन्न) हो। इस प्रथा से जुड़ा ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जैन धर्म के अनुसार सामान्य जन, बच्चे एवं युवा किसी भी स्थिति में संथारा के तहत मृत्यु का वरण नहीं कर सकते हैं। संथारा प्रथा को कुछ दूसरे नामों यथा—'सल्लेखना', 'समाधि मरण', 'इच्छा-मरण' एवं 'संन्यास-मरण' आदि से भी जाना जाता है। सैद्धांतिक रूप से आत्महत्या का विरोध करने वाले जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति संथारा का निर्णय अत्यंत शांत चित्त से शांत क्षणों में लेता है। इस प्रकार वह सांसारिक बंधनों, माया-मोह, विषय-वासनाओं एवं प्रलोभनों से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसीलिए वह समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जैन मतावलंबियों का यह मानना है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीरजी ने संथारा के तहत ही मृत्यु का वरण किया था।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

- संथारा अहिंसा का एक अवयव है।
- संथारा उपवास के जरिए मृत्यु के वरण की धार्मिक प्रथा है।
- इस प्रथा को अपराध बताने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट ने जैन धर्म के विद्वानों से परामर्श नहीं लिया।
- यह प्रमाण भी नहीं लिया गया कि यह प्रथा जन स्वास्थ्य (Public Health) और नैतिकता (Morality) के विरुद्ध है।

मानव डीएनए प्रालेखन विधेयक, 2015

- हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Dept. of Biotechnology) द्वारा 'मानव डीएनए प्रालेखन विधेयक (Human DNA Profiling Bill), 2015' का मसौदा अपनी वेबसाइट पर जारी कर उस पर विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों एवं जनता की राय आमंत्रित की गई।
- उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में ही प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की योजना थी परंतु संसद में गतिरोध की स्थिति के कारण यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
- मानव डीएनए प्रालेखन विधेयक, 2015 का उद्देश्य मानव शरीर के अंशों (Bodily Substances) के डीएनए (DNA : Deoxyribose Nucleic Acid) विश्लेषण प्रालेखों (Profiles) के प्रयोग का विनियमन करना तथा डीएनए प्रयोगशालाओं, मानव शरीर अंशों के संग्रहण एवं संग्रहण से रिपोर्टिंग तक अभिरक्षण के लिए मानकों के निर्धारण हेतु 'डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड' (DNA Profiling Board) की स्थापना करना है।
- इस विधेयक में एक 'राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक' (National DNA Data Bank) की स्थापना करने, आंकड़ों के विभिन्न निर्धारित फोरेंसिक उद्देश्यों हेतु प्रयोग तथा अन्य संबंधित विषयों के संदर्भ में भी प्रावधान किए गए हैं।
- प्रस्तावित डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड में मॉलीक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, पापुलेशन बायोलॉजी एवं बायोएथिक्स के साथ-साथ सामाजिक विज्ञानों और विधि एवं आपराधिक न्याय क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह बोर्ड डीएनए प्रोफाइलिंग के संदर्भ में मानकों और विनियमों को परिभाषित करेगा। यह प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करने तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों की आंकड़ों तक पहुंच के प्रबंधन हेतु भी उत्तरदायी होगा।
- इस बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में होगा तथा यह अपनी आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा।
- इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति जैविक विज्ञानों के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों (कम से कम 15 वर्ष के अनुभव वाले) में से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इस बोर्ड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष (या उनके द्वारा नामित व्यक्ति) भी पदेन सदस्य होंगे। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के निदेशक इस बोर्ड के पदेन सदस्य सचिव होंगे।
- इस विधेयक में राज्य स्तरों पर भी ऐसे निकायों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- प्रस्तावित विधेयक के तहत केंद्र सरकार हैदराबाद में राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक की स्थापना करेगी तथा वह प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक की स्थापना करेगी।
- प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य डीएनए डाटा बैंक की स्थापना कर सकेगी तथापि प्रत्येक राज्य डीएनए डाटा बैंक को अपने पास संग्रहित सभी डीएनए डाटा को राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ साझा करना होगा।
- प्रत्येक डीएनए डाटा बैंक में विभिन्न श्रेणियों के डाटा निम्नलिखित सूचकों (Indices) के तहत सूचीबद्ध होंगे—
  - (i) अपराध दृश्य (Crime Scene) इंडेक्स;
  - (ii) संदिग्ध व्यक्ति (Suspects') इंडेक्स;
  - (iii) दोषी व्यक्ति (Offenders') इंडेक्स;
  - (iv) गुमशुदा व्यक्ति (Missing Persons') इंडेक्स;
  - (v) अज्ञात मृतक व्यक्ति (Unknown deceased persons') इंडेक्स;
  - (vi) स्वैच्छिक व्यक्ति (Volunteers') इंडेक्स; तथा
  - (vii) अन्य कोई डीएनए सूचक जिन्हें विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।
- इन सूचकों में से संदिग्ध एवं दोषी सूचकों के तहत डीएनए आंकड़ों के साथ संबंधित व्यक्ति की पहचान भी रहेगी जबकि शेष सूचकों के तहत जांच केस की संदर्भ संख्या रखी जाएगी।
- इस विधेयक के प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराधों के अतिरिक्त मातृत्व या पितृत्व विवादों, वंशावली संबंधी मुद्दों, सरोगेसी तथा आव्रजन एवं प्रव्रजन के संदर्भ में भी डीएनए आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकेगा।
- इस विधेयक में डीएनए आंकड़ों के दुष्प्रयोग पर 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2003 में मानव डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक का विचार दिया गया था तथा 2007 में इस विधेयक की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2012 में इस विधेयक का मसौदा जारी हुआ था जिसे विभिन्न सुझावों के आधार पर संशोधित कर अब नया मसौदा प्रस्तुत किया गया है।
- विभिन्न सामाजिक एवं विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा नागरिक अधिकार समूहों द्वारा मानव डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक का विरोध किया जा रहा है। उनके अनुसार इससे देश के नागरिकों के निजता (Privacy) के अधिकार का उल्लंघन होगा। कतिपय विशेषज्ञों के अनुसार डीएनए आंकड़ों की जातीय एवं सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग की जा सकती है तथा इनके दुष्प्रयोग की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे अदालतों में ट्रायल अवधि बढ़ने की भी आशंका व्यक्त की गई है क्योंकि अभी इस क्षेत्र में देश में विशेषज्ञों की कमी है। साथ ही इस पर आने वाले व्यय को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए आंकड़ों के संग्रहण रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण में मानवीय भूलों से हो सकने वाली गलतियों की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

- उल्लेखनीय है कि भारतीय न्यायालयों द्वारा आपराधिक जांच में डीएनए विश्लेषण को साक्ष्य के रूप में 1985 से स्वीकार किया जा रहा है। वर्ष 2005 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग के प्रयोग को शामिल किया गया है।
- वर्तमान में विश्व के लगभग 60 देशों में डीएनए डाटाबेस तैयार किए गए हैं तथापि अधिकांश देशों में यह केवल आपराधिक जांच हेतु प्रयुक्त होता है। हाल ही में कुवैत ने अपने नागरिकों और वहां रहने वाले विदेशियों की डीएनए प्रोफाइलिंग को कानून द्वारा अनिवार्य किया है।
- वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम के साथ उनके डीएनए प्रोफाइल को सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया।
- 2014 में गैर सरकारी संगठन लोकनीति फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से लावारिस मृतकों की डीएनए प्रोफाइलिंग अनिवार्य करने हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
- ज्ञातव्य है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 1990 में स्वायत्त संस्थान के रूप में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद की स्थापना की गई थी जो भारत में डीएनए विश्लेषण हेतु मुख्य केंद्र है।

भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष की उग्र होती समस्या

- क्या आपको मालूम है कि भारत में अवैध शिकार की वजह से उतने वन्यजीवों की मौत नहीं होती है, जितने कि मानव-वन्यजीव संघर्ष एवं निरंतर घटते वनावरण के कारण मारे जाते हैं। इस बात की पुष्टि भारत सरकार द्वारा जारी उन आंकड़ों से होती है, जिनके अनुसार वर्ष 2012 से 2014 तक मानव-वन्यजीव संघर्ष में 179 हाथी एवं 110 बाघ मारे गए, जबकि इसी समयावधि में शिकारियों द्वारा 20 हाथियों एवं 52 बाघों को मौत के घाट उतारा गया।
- उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या उग्र और विकराल हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष की उग्र होती समस्या की मुख्य वजह है वन्यजीव गलियारों के आस-पास मानव आवासों और हस्तक्षेप का बढ़ना।
- अब असम राज्य के तेलाग्राम में स्थित नुमालीगढ़ रिफायनरी का उदाहरण देखिए। इस रिफायनरी द्वारा वर्ष 2011 में देवपहाड़ फॉरेस्ट रिजर्व एवं काजीरंगा नेशनल पार्क के समीप हाथी गलियारा (Elephant Corridor) में एक दीवार का निर्माण करवाया गया था, जिसकी वजह से मई, 2015 में हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद अगस्त, 2015 में असम राज्य सरकार द्वारा इस दीवार को तोड़े जाने के आदेश दिए गए।
- ध्यातव्य है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से 5 जुलाई, 1996 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास के क्षेत्र को 'गैर-विकास जोन' (No Development Zone) घोषित किया गया था। इसके बावजूद रिफायनरी द्वारा यहां दीवार का निर्माण करवाए जाने से प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया। यहां यह जान लेना उचित रहेगा कि तेलाग्राम क्षेत्र (जहां नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थित है) हाथियों के पर्यावास के लिए विख्यात है। यहां से होकर हाथियों के झुण्ड गुजरते हैं। दीवार में फंसने के कारण हाथी के बच्चे न सिर्फ अपने झुण्ड से बिछड़ जाते थे, बल्कि चुटहिल भी हो जाते थे।
- नुमालीगढ़ रिफायनरी द्वारा स्थानीय हाथी पर्यावास को नष्ट किए जाने का यह मामला इस समय 'राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण' के समक्ष विचाराधीन है।
- प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में गैर-विकास जोन (No Development Zone) के बारे में भी जान लेना आवश्यक रहेगा। वर्ष 1994 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा गैर-विकास जोन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यह सिफारिश की गई थी कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य (संरक्षित क्षेत्र) की 5 किमी. त्रिज्या में चारों ओर किसी भी प्रकार के उद्योग एवं कारखाने लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस सिफारिश को स्वीकारते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसको अमली जामा भी पहनाया गया।
- इसी क्रम में मानव गतिविधियों के दुष्प्रभावों से संरक्षित क्षेत्रों के बचाव के लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट की पहल पर 'इको सेंसिटिव जोन' सृजित किए जाने की शुरुआत हुई तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित कर वन्यजीव अभयारण्यों की 10 किमी. सीमा को इसके दायरे में लाया जाना प्रारंभ किया गया। एनडीए सरकार द्वारा इनसे संबंधित राज्यों के कुल 452 में से 176 प्रस्तावों को अब तक औपचारिक स्वीकृति दी गई है।
- गैर-विकास जोन (No Development Zone) एवं इको सेंसिटिव जोन जैसे केंद्रीय प्रावधानों के बावजूद यदि भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं थम नहीं रही हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारों की तरफ से प्रायः नियमों की अनदेखी एवं उनका अतिचार किया जाता है। इसे नुमालीगढ़ रिफायनरी प्रकरण से समझा जा सकता है। इस रिफायनरी को दीवार बनाने के लिए भूमि असम सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, जबकि 'वन संरक्षण कानून, 1980' के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को उपलब्ध करवाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है।
- भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि वन कानूनों का कड़ाई से अनुपालन हो तथा वन्यजीव गलियारों के आस-पास हर प्रकार के मानव हस्तक्षेप तथा गतिविधियों को रोका जाए।

'मणिपुर आगंतुक एवं प्रवासी कामगार विधेयक-2015'

- बाहरी लोगों को मणिपुर में भूमि खरीदने की व्यवस्था देने वाला 'मणिपुर आगंतुक एवं प्रवासी कामगार विधेयक-2015' (Manipur Regulation of Visitors, Tenants and Migrant Workers Bill-2015) विवादों एवं विरोध का शिकार होने के कारण कानून नहीं बन पाया।
- राज्य विधान सभा में मार्च, 2015 में पारित हुए इस विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रखा था कि

इस बीच इसके व्यापक विरोध को देखते हुए इसे वापस ले लिया गया।

- मणिपुर के मूल निवासियों द्वारा न सिर्फ इसका विरोध किया गया, बल्कि हिंसक प्रदर्शन भी किए गए। इसमें पुलिस की गोली से एक छात्र की मौत भी हुई।
- विरोध के पीछे मणिपुर के मूल लोगों में व्याप्त असुरक्षा की वह भावना थी, जिसके चलते उन्हें यह लगने लगा था कि विधेयक के कानून बनने की स्थिति में मणिपुर में प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी और अपने ही राज्य में उनकी स्थिति अल्पसंख्यकों जैसी हो जाएगी।
- इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में यह जान लेना उचित रहेगा कि औपनिवेशिक काल में अपने वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश, नगालैण्ड एवं मिजोरम में प्रवेश के लिए 'इनर लाइन परमिट' को आवश्यक बनाया गया था, जो कि 'बंगाल पूर्वी सीमा विनियम, 1873' (Bengal Eastern Frontier Regu-lation, 1873) के तहत जारी किया जाता था। स्थानीय जनजातीय आबादी की संस्कृति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के बाद भी इस व्यवस्था को कायम रखा गया।
- ध्यातव्य है कि संदर्भित विधेयक का तीव्र विरोध मणिपुर में इनर लाइन परमिट की छह संयुक्त समितियों द्वारा ही किया गया था।

पंचायत प्रत्याशियों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण पर रोक

- 17 सितंबर, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन एसोसिएशन (AIDWA) की याचिका पर 'हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015' के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी गई।
- इस अधिनियम के तहत हरियाणा में पंचायत चुनावों के प्रत्याशियों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य कई पात्रता संबंधी प्रावधान किए गए थे।
- ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम हेतु विधेयक 7 सितंबर, 2015 को ही हरियाणा राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया था जिसे राज्यपाल ने उसी दिन अपनी स्वीकृति दे दी थी।
- इस अधिनियम के तहत पंचायत चुनाव हेतु सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष प्रत्याशियों हेतु न्यूनतम कक्षा 10, इन श्रेणियों की महिला प्रत्याशियों एवं अनुसूचित जाति के पुरुष प्रत्याशियों हेतु न्यूनतम कक्षा 8 तथा अनुसूचित जाति की महिला प्रत्याशी हेतु न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था।
- साथ ही पंचायत प्रत्याशियों के लिए घर में शौचालय होने, किसी बैंक या संस्थान का ऋण बकाया न होने, विद्युत बिलों का बकाया न होने तथा किसी अदालत द्वारा दोषसिद्ध न होने या कम से कम 10 वर्ष के कारावास के मामले का दोषारोपण न होने जैसी पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई थीं।
- सर्वोच्च न्यायालय की इस रोक के बाद हरियाणा में अक्टूबर, 2015 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक स्थगित कर दिए गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा से पूर्व राजस्थान राज्य द्वारा दिसंबर, 2014 में अध्यादेश जारी कर पंचायत चुनावों हेतु प्रत्याशियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान (जिला परिषद या पंचायत चुनाव हेतु न्यूनतम कक्षा 10 तथा सरपंच चुनाव हेतु सामान्य क्षेत्र के लिए न्यूनतम कक्षा 8 एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए न्यूनतम कक्षा 5) किए गए थे और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। जनवरी, 2015 के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक से इनकार कर दिया गया था।

गुजरात में अनिवार्य मतदान प्रावधान पर रोक

21 अगस्त, 2015 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में अनिवार्य मतदान का उपबंध करने वाले 'गुजरात स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2009' के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। उल्लेखनीय है कि गुजरात ऐसा प्रावधान करने वाला देश का पहला और अब तक का एकमात्र राज्य है। इस अधिनियम हेतु विधेयक गुजरात राज्य विधान सभा द्वारा मूलतः वर्ष 2009 में पारित किया गया था जिसे तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल द्वारा वापस लौटाने पर इसे पुनः 2011 में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था परंतु राज्यपाल ने इसे अपने पास रोके रखा था। गुजरात के नए राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली द्वारा नवंबर, 2014 में स्वीकृति के बाद यह विधेयक अधिनियमित हुआ था।

गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2015

- मूलतः वर्ष 2003 में गुजरात राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया 'गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2015' (Gujrat Control of Terrorism and Organised Crime Bill-2015) अंततः 24 सितंबर, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया। इस विधेयक को राज्य विधान सभा द्वारा मार्च-अंत, 2015 में पुनः पारित किया गया था।
- ध्यातव्य है कि अभी तक इस विधेयक को केंद्र सरकार की मंजूरी इसलिए नहीं मिल पाई थी, क्योंकि इस विधेयक में मोबाइल काल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य को मान्यता देने का प्रावधान है। इस प्रावधान पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था।
- गुजरात सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति का खंडन करने तथा आपराधिक मामलों में कानून बनाने के अधिकार के संबंध में समवर्ती सूची का हवाला देने के बाद लंबे समय से लटके इस विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया।
- इस विधेयक में जहां पुलिस को फोन टेप करने का अधिकार मिला हुआ है, वहीं यह भी प्रावधान है कि फोन टेपिंग एवं ई-मेल आदि को न्यायालय साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा।

- इस विधेयक में जहां वेश्यावृत्ति, मल्टीलेबल मार्केटिंग एवं पोंजी स्कीम को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है, वहीं आरोपी को अग्रिम या स्थायी जमानत न दिए जाने का भी प्रावधान है।

राजस्थान में आरक्षण संबंधी दो विधेयक पारित

- सितंबर, 2015 में राजस्थान राज्य विधान सभा द्वारा नौकरी एवं शिक्षा में आरक्षण संबंधी दो विधेयक पारित किए गए। इनमें पहला विधेयक है–'राजस्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (राज्य शिक्षण संस्थाओं में और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षण) विधेयक–2015' तथा दूसरा विधेयक है–'राजस्थान विशेष पिछड़ी जाति (राज्य शिक्षण संस्थाओं में और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षण) विधेयक-2015'।
- पहले विधेयक में जहां अनारक्षित वर्ग (सामान्य रूप से सवर्ण) में आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 14% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, वहीं दूसरे विधेयक में गुज्जर एवं कुछ अन्य समुदायों को विशेष पिछड़े वर्ग के तहत पांच प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है।
- इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद राजस्थान में कुल आरक्षण 69% हो गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में कर्नाटक में भी कुल आरक्षण 69% है।
- आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधान सभा द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि इन दोनों विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

वन रैंक, वन पेंशन

- केंद्र सरकार द्वारा 5 सितंबर, 2015 को सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) व्यवस्था लागू किए जाने की घोषणा की गई। ध्यातव्य है कि सेवानिवृत्त सैनिक पिछले 42 वर्षों से इस पेंशन नीति को लागू किए जाने की मांग कर रहे थे। वर्ष 1973 तक यह पेंशन नीति लागू भी रही, किंतु इसके बाद इसे खारिज कर दिया गया था।
- 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) से अभिप्राय उस पेंशन नीति से है, जिसमें किसी रैंक विशेष से सेवानिवृत्ति की तिथि अलग-अलग होने के बावजूद सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी को समान पेंशन प्रदान की जाती है। जैसे, वर्ष 1998 में मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए सैन्यकर्मी को इस व्यवस्था के तहत वही पेंशन प्राप्त होगी, जो वर्ष 2015 में मेजर के पद से सेवानिवृत्त होने वाले सैन्यकर्मी को।
- ध्यातव्य है कि सेवानिवृत्त सैनिकों की 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग को देखते हुए वर्ष 2010-11 में भाजपा सांसद भगत सिंह कोशियारी की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया गया था, जिसने इस पेंशन नीति को लागू किए जाने के पक्ष में सिफारिश दी थी। फरवरी, 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सरकार को यह निर्देशित किया गया था कि वह इस पेंशन नीति को लागू करे। देश की शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में विलंब होता देख सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल एवं धरना-प्रदर्शन किया गया।
- 'वन रैंक, वन पेंशन' की नीति के प्रभावी होने के बाद से प्रतिवर्ष (वन टाइम पेआउट) लगभग 8300 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ने का अनुमान है, जबकि भारत का रक्षा बजट 54,500 करोड़ रुपये है। यानी यह राशि रक्षा बजट की 16% है।
- 'वन रैंक, वन पेंशन' नीति को लागू किए जाने की घोषणा तो केंद्र सरकार द्वारा की जा चुकी है, किंतु इसे लेकर अनेक तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। इन समस्याओं पर निष्कर्ष देने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया जाना है, जबकि सेवानिवृत्त सैनिक पांच सदस्यीय समिति गठित किए जाने की मांग कर रहे हैं।

देश में आत्महत्याओं पर एनसीआरबी की रिपोर्ट

- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2014 में कुल आत्महत्याओं की संख्या 131666 रही। वर्ष 2013 में यह 134799 और 2012 में 135445 के स्तर पर थी।
- 2014 में देश में आत्महत्या करने वाले कुल किसानों की संख्या 5650 थी। इससे पूर्व 2013 में कृषि/कृषि संबंधी गतिविधियों में स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या 11772 और 2012 में 13754 थी।
- वर्ष 2014 में 20148 गृहणियों द्वारा आत्महत्या की गई जबकि 2013 में यह संख्या 22742 और 2012 में 21904 के स्तर पर थी।
- वर्ष 2014 में 8068 छात्रों ने आत्महत्या की जबकि 2013 में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 8423 और 2012 में 6654 थी।
- वर्ष 2014 में दिवालिया/कर्जदार होने के कारण 2308 लोगों ने आत्महत्याएं कीं जबकि विक्षिप्तता या मानसिक रोगों के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या 7104 रही।

गोदावरी को जोड़ा गया कृष्णा से

- आंध्र प्रदेश की दो महत्त्वपूर्ण नदियों–गोदावरी एवं कृष्णा को परस्पर जोड़ने का कार्य आंध्र प्रदेश की सरकार के प्रयास से सितंबर, 2015 में सम्पन्न हुआ। इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के पट्टीसीमा गांव के पास संचालित 'पत्तीसीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम' (Pattiseema Lift Irrigation Project) के जरिए गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक जल को मोड़कर 'पोलावरम नहर' द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया।
- 174 किमी. लंबी इस परियोजना के पहले चरण में लगभग 1300 करोड़ रुपये का खर्च आया है। यह लिंक स्थापित होने के बाद अब गोदावरी नदी का लगभग 80 हजार मिलियन क्यूबिक जल नहर के द्वारा कृष्णा नदी तक पहुंचाया जाएगा।
- जिस स्थान पर इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है उसका नाम–'इब्राहिमपट्टनम' है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है।

- गोदावरी एवं कृष्णा नदियों को जोड़ने की इस पहल को अत्यंत लाभकारी माना जा रहा है, क्योंकि इससे जहां पानी की कमी से जूझ रहे चिन्तूर, प्रकाशम, कृष्णा, गुंटूर, अनंतपुर, कडप्पा एवं कुरनूल जिलों को पेयजल उपलबध होगा, वहीं यहां के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भी मिलेगा। ध्यातव्य है कि उक्त सभी जिले 'कृष्णा डेल्टा क्षेत्र' एवं 'रायलसीमा क्षेत्र' के अंतर्गत आते हैं, जो कि कृष्णा नदी पर बनाए गए अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के कारण पानी की कमी से जूझ रहे थे। 'कृष्णा डेल्टा क्षेत्र' को धान के कटोरे के रूप में अभिहित किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व नदियों को परस्पर जोड़ने की परिकल्पना सबसे पहले दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने के लिए आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1972 में तत्कालीन केंद्रीय जल एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. कनूरी लक्ष्मण राव द्वारा भी गंगा-कावेरी को जोड़ने का समर्थन किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भी नदियों को परस्पर जोड़े जाने के हिमायती थे।
- भारत में 'नदी जोड़ो परियोजना' की रूपरेखा एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना के रूप में तैयार किए जाने तथा इसके लिए एक कार्यबल का गठन किए जाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व वाली राजग सरकार को जाता है। हालांकि बाद की सरकारों के कार्यकाल में इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अंततः वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुचारु रूप से इसके क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 'नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना' के तहत नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने बगैर केंद्रीय सहायता के देश में दो नदियों को जोड़ने का बड़ा काम पहली बार किया।
- अब केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बहने वाली इन नदियों को जोड़े जाने पर दोनों राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है। यह नदियों को जोड़ने की पहली 'राष्ट्रीय परियोजना' होगी, जिसका लोकार्पण दिसंबर, 2015 में प्रस्तावित है।

प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

- 7 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के समारोह में प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (First National Handloom Day) का शुभारंभ किया गया।
- इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 हेतु हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संत कबीर पुरस्कार भी प्रदान किए।
- साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चेन्नई विश्वविद्यालय के सीनेट भवन में पुरस्कृत बुनकरों की विशिष्ट कृतियों की एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया।
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन और हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया जाना न केवल भारत के हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करेगा बल्कि अच्छी गुणवत्ता के एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद के रूप में हथकरघा को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा।
- हथकरघा बुनकरी भारत में कृषि के बाद सर्वाधिक वृहद आर्थिक गतिविधियों में से एक है जो कि 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रही है।
- हथकरघा क्षेत्र देश के कुल कपड़ा उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत योगदान करता है तथा यह देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व के हाथ से बुने कपड़ों का 95 प्रतिशत भारत से आता है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हेतु 7 अगस्त की तिथि का चयन भारतीय इतिहास में इसके विशेष महत्त्व के कारण किया गया है। इसी दिन वर्ष 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसमूह की बैठक में 'स्वदेशी आंदोलन' प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी जिसमें घरेलू उत्पादों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरोद्धार शामिल था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन 7 अगस्त को प्रतिवर्ष देश भर में राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाएगा।
- 19 अक्टूबर, 2015 को भारत सरकार द्वारा 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड के प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया पर एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में 13 कानून समाहित

- 28 अगस्त, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में 13 कानूनों को समाहित करने हेतु आदेश जारी किया गया।
- उल्लेखनीय है कि 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act), 2013' को 1 जनवरी, 2014 से लागू किया गया था। इसमें 365 दिन बाद अर्थात 1 जनवरी, 2015 से 13 कानूनों को इसके क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाना था तथापि नई केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2014 को अध्यादेश जारी कर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन (जिनमें इन 13 कानूनों को भी शामिल किया गया था) किए गए थे।
- तथापि इन संशोधनों हेतु विधेयक को राज्य सभा में पारित करा पाने में असफल रहने पर 3 अप्रैल, 2015 को और पुनः 31 मई, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा यह अध्यादेश पुनः प्रख्यापित किया गया था। इस बार इस अध्यादेश की अवधि 31 अगस्त, 2015 तक थी परंतु सरकार द्वारा इसे पुनः प्रख्यापित करने की बजाए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को ही यथास्थिति जारी रखने का निर्णय लिया गया और तदनसुार इसमें 13 कानूनों को समाहित करने हेतु आदेश जारी किया गया है।
- इस प्रकार अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के दायरे से बाहर रखे गए 13 कानूनों (इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में वर्णित; जिनका केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु बहुधा प्रयोग होता है) को भी इस अधिनियम के दायरे में मुआवजे, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और अवसंरचना सुविधाओं के उद्देश्यों के तहत लाया गया है जिससे किसान और प्रभावित परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। मुख्यतः

राष्ट्रीय राजमार्गों, मेट्रो रेल, परमाणु ऊर्जा, विद्युत एवं अन्य अवसरंचना परियोजनाओं आदि से संबंधित ये 13 कानून इस प्रकार हैं- प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958; परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962; भारतीय ट्राम अधिनियम, 1886; भूमि अधिग्रहण (खान) अधिनियम, 1885; दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948; मेट्रो रेल (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956; पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962; अचल संपत्ति का अधिग्रहण और पुनर्अधिग्रहण अधिनियम, 1952; विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948; कोयला क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम, 1957; रेल अधिनियम, 1989; और विद्युत अधिनियम, 2003।

'मैगी' नूडल्स का उत्पादन पुनः प्रारंभ

- 27 अक्टूबर, 2015 को नेस्ले इंडिया द्वारा भारत में 'मैगी' नूडल्स का उत्पादन पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई। नवीनतम परीक्षणों में मैगी नूडल्स को खाने हेतु सुरक्षित पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि कंपनी ने इस खाद्य उत्पाद के नए लॉट के भारतीय परीक्षकों द्वारा अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इसका विक्रय प्रारंभ करने की बात कही है।
- 5 जून, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा नेस्ले कंपनी के नूडल्स ब्रांड 'मैगी' की सभी 9 किस्मों के विक्रय पर देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- भारत में खाद्य नियामक संस्था 'भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण' (FSSAI) ने प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि मैगी के सभी नौ प्रकार के नूडल्स खाने के दृष्टिकोण से असुरक्षित और खतरनाक हैं।
- एफएसएसएआई के अनुसार मैगी की जांच में पाया गया कि इसमें सीसे (लेड) की मात्रा तय सीमा से ज्यादा थी तथा नेस्ले द्वारा अतिरिक्त मोनो सोडियम ग्लूटामेट (MSG) न होने का लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया। साथ ही नेस्ले ने उत्पाद मंजूरी लिए बगैर और बिना जोखिम एवं सुरक्षा आकलन के मैगी ओट्स मसाला नूडल्स विक्रय हेतु जारी कर दिए। इसी आधार पर प्राधिकरण द्वारा मैगी के विक्रय पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया गया।
- उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम मार्च, 2014 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) द्वारा लिए गए मैगी के नमूनों की जांच में इनमें सीसे की अधिक मात्रा और एमएसजी की उपस्थिति पाई गई थी।
- मैगी में सीसे की मात्रा 17.2 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) तक पाई गई जो कि इसकी स्वीकार्य सीमा (0.01 पीपीएम से 2.5 पीपीएम) की तुलना में काफी अधिक थी।
- अपने-अपने राज्यों में मैगी के नमूनों के जांच में असफल होने पर जून, 2015 के प्रारंभ में दिल्ली, उत्तराखंड, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु आदि राज्यों द्वारा अपने यहां मैगी के विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- ज्ञातव्य है कि शरीर में सीसे की अधिक मात्रा होने पर लेड प्वाइजनिंग (पेंटर्स कालिक) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे रक्ताल्पता (एनीमिया), पेट दर्द, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, घबराहट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा रहता है। दीर्घकालिक विषाक्तता की स्थिति में किडनी एवं लिवर जैसे अंग प्रभावित होने का खतरा रहता है।
- मोनो सोडियम ग्लूटामेट (MSG) प्राकृतिक रूप से सब्जियों और टमाटर, सोयाबीन, खरपतवार, मशरूम और पनीर में पाया जाता है। प्राकृतिक स्रोतों के अलावा स्टार्च, चुकंदर, गन्ना या शीरे के किण्वन से भी इसका उत्पादन किया जाता है। गर्भवती महिलाओं और नवजात में यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। किसी खाद्य पैकेट पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि इसमें एमएसजी है तथा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसका उपयोग न करें।
- उल्लेखनीय है कि नेस्ले इंडिया बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले (Nestle) की अनुषंगी कंपनी है। नेस्ले राजस्व की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खाद्य उत्पाद कंपनी है जिसका मुख्यालय वीवे (Vevey), स्विट्जरलैंड में स्थित है।

नगा अलगाववादियों से समझौता

- 3 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में भारत सरकार और नगालैंड के अलगाववादी संगठन एनएससीएन (आईएम) (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड) के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह एवं नगा संगठन के महासचिव टी. मुइवा मौजूद थे।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980 के दशक में नगा नेशनल काउंसिल के साथ भारत सरकार के एक समझौते के खिलाफ इसाक सू और तुंगलांग मुइवा के नेतृत्व में एनएससीएन का गठन हुआ था। बाद में इससे अलग होकर खापलांग ने अपना अलग गुट तैयार कर लिया, जो कि शांति समझौते के खिलाफ रहा है।
- वर्ष 1997 में एनएससीएन (आईएम) के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद 80 दौर की वार्ताओं के बाद यह शांति समझौता भारत सरकार की ओर से नगा वार्ताकार आर.एन. रवि की मदद से हो पाया।
- इस ऐतिहासिक समझौते के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर, 2015 में एनएससीएन के खापलांग गुट पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। इस संगठन को पूर्वोत्तर में बमबारी एवं हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के कारण अवैधानिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967] के तहत अवैधानिक संगठन घोषित किया गया। इसके पहले खापलांग गुट के नेता खापलांग और निकी सुमी के लिए भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने क्रमशः 7 लाख एवं 10 लाख रुपए की इनामी राशि की घोषणा की थी।

'कौशल भारत' अभियान का शुभारंभ

- 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम 'विश्व युवा कौशल दिवस' के अवसर पर केंद्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'कौशल भारत (Skill India)' का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जुलाई, 2015 को वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' (NSDM : National Skill Development Mission) को संस्थागत ढांचा प्रदान करने को स्वीकृति दी गई। इसके तहत मिशन में त्रि-स्तरीय, उच्चाधिकार प्राप्त निर्णय लेने संबंधी संरचना होगी। शीर्ष पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिशन की गवर्निंग काउंसिल होगी, जो समग्र मार्गदर्शन और नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। कौशल विकास के प्रभार वाले मंत्री की अध्यक्षता वाली संचालन समिति गवर्निंग काउंसिल के निर्देशन पर मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करेगी। कौशल विकास सचिव मिशन निदेशक के रूप में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कौशल संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन, समन्वयन और अभिसरण सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य स्तर पर सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान करेगा। यह सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप-मिशन भी संचालित करेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और प्रशिक्षण निदेशालय मिशन के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। इस मिशन का 15 जुलाई, 2015 से औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है।

- 'कौशल भारत, कुशल भारत' की टैगलाइन वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत वर्ष 2022 तक 40.02 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- इसके साथ ही उन्होंने चार महत्त्वपूर्ण पहलों- 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन', 'राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति', 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' तथा 'कौशल ऋण योजना' को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया।
- 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' को केंद्र सरकार में पहली बार बनाए गए कौशल विकास मंत्रालय के जरिए लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 1 वर्ष में 24 लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगारों हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इस योजना में प्रशिक्षण पाने वाले लोगों का आकलन बाहरी संस्थान की ओर से किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रु. का आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अपनी साझेदार एजेंसियों के साथ मिलकर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा।
- 'कौशल ऋण योजना' के तहत अगले 5 वर्षों में 34 लाख युवाओं को 5 हजार से 1.5 लाख रु. तक का ऋण कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक भारत को 11.92 करोड़ दक्ष युवाओं की आवश्यकता होने का आकलन है।

नोट : 'राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति' का विस्तृत विवरण इसी अंक के 'राष्ट्रीय नीतियां' अध्याय में देखें।

ग्रामीण भारत हेतु सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 के प्रॉविजिनल आंकड़े

- सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC : Socio Economic and Caste Census) 2011 के तहत ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक स्तर संबंधी प्रॉविजिनल आंकड़े 3 जुलाई, 2015 को।
- एसईसीसी, 2011 के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में कुल परिवारों (ग्रामीण+शहरी) की संख्या 24.39 करोड़ है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों की संख्या 17.91 करोड़ है।
- देश के कुल ग्रामीण परिवारों में से 7.05 करोड़ (39.39 प्रतिशत) ऐसे हैं जो कि निर्धारित 14 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने के कारण वंचन श्रेणी हेतु विचार से स्वतः बाहर हैं।
- ग्रामीण परिवारों में ऐसे परिवारों की संख्या 16.50 लाख (0.92 प्रतिशत) है जो कि निर्धारित 5 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने के फलस्वरूप स्वतः वंचन श्रेणी में शामिल माने गए हैं।
- इस प्रकार ग्रामीण भारत के शेष 10.69 करोड़ परिवारों पर वंचनों के संदर्भ में विचार किया गया जिसमें से 2.00 करोड़ परिवारों ने वंचन की स्थिति रिपोर्ट नहीं की जबकि शेष 8.69 करोड़ परिवार वंचन के 7 आधारों में से किसी एक (या अधिक) आधार पर वंचित पाए गए।
- एसईसीसी, 2011 के तहत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त वंचन आंकड़े (Deprivation Data) वंचन के सातों आधारों के संदर्भ में अग्रलिखित तालिका में दृष्टव्य हैं—

क्र.	वंचन आधार	परिवारों की संख्या (एवं प्रतिशत)
1.	केवल एक कमरे, कच्ची दीवारों एवं कच्ची छत वाले परिवार	2.37 करोड़ (13.25%)
2.	परिवार में 18 से 59 वर्ष आयु के मध्य का कोई वयस्क सदस्य न होना	65.15 लाख (3.64%)
3.	महिला प्रमुख वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के मध्य का कोई पुरुष सदस्य नहीं है	68.96 लाख (3.85%)
4.	भिन्न रूप से सक्षम सदस्य वाले परिवार जिनमें कोई अन्य सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य नहीं है	7.16 लाख (.040%)
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार	3.86 करोड़ (21.53%)
6.	ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई शिक्षित वयस्क नहीं है	4.21 करोड़ (23.52%)
7.	भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का प्रमुख हिस्सा मेहनत मजदूरी से प्राप्त करते हैं	5.37 करोड़ (29.97%)

- एसईसीसी, 2011 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आय के स्रोत संबंधी आंकड़े अग्रलिखित तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं—

क्र.	परिवार आय का स्रोत	परिवारों की संख्या (एवं प्रतिशत)
1.	खेती	5.39 करोड़ (30.10%)
2.	अस्थायी मेहनत मजदूरी	9.16 करोड़ (51.14%)
3.	अंशकालिक या पूर्णकालिक घरेलू सेवा	44.84 लाख (2.50%)
4.	कूड़ा बिनना आदि	4.08 लाख (0.23%)
5.	गैर-कृषि स्वयं का उपक्रम	28.87 लाख (1.61%)
6.	भीख, दान आदि	6.68 लाख (0.37%)
7.	अन्य (सरकारी सेवा, निजी सेवा, सार्वजनिक उपक्रम रोजगार आदि सहित)	2.50 करोड़ (14.01%)

डिजिटल इंडिया सप्ताह

- 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम 'डिजिटल इंडिया' को गति प्रदान करने हेतु 'डिजिटल इंडिया सप्ताह' (Digital India Week) का शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में किया गया।
- इस वृहद समारोह में देश की 400 से अधिक प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) ने प्रतिभाग किया जिन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कुल मिलाकर लगभग 4.5 लाख करोड़ रु. की निवेश योजनाओं की घोषणा की। इनमें मुकेश अंबानी (रिलायंस) द्वारा 2.5 लाख करोड़ रु. तथा सुनील मित्तल (भारतीय एयरटेल) द्वारा 1 लाख करोड़ रु. की निवेश योजनाओं की घोषणा शामिल है।
- इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में डिजिटल क्रांति लाने के उद्देश्य से तैयार अनेक डिजिटल आधारित योजनाओं को प्रारंभ किया गया। इनमें भारत नेट (देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य), डिजिटल लॉकर (आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटलीकृत सहज उपलब्ध हो सकने की प्रणाली) सिस्टम, माईजीओवी डॉट इन का मोबाइल एप, स्वच्छ भारत का एप, ई-हस्ताक्षर फ्रेमवर्क, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आदि शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री द्वारा बीएसएनएल के 53 वाई-फाई हॉटस्पॉट का भी शुभारंभ किया गया। बीएसएनएल की योजना देश भर के पर्यटन, धार्मिक एवं व्यावसायिक स्थलों पर इस वर्ष के अंत तक 2500 ऐसे हॉटस्पॉट स्थापित करने की है।
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस दौरान मोबाइल से पहचान सत्यापन संबंधी कार्यक्रम को भी लांच किया गया हालांकि इसे अभी बीएसएनएल द्वारा ही लागू किया जाएगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभ या प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र इस प्रकार हैं—
  a. ब्रॉडबैंड हाइवे : सड़क हाइवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाइवे से शहरों को जोड़ा जाएगा।
  b. सभी नागरिकों की टेलीफोन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
  c. सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

डिजिटल लॉकर प्रणाली

डिजिटल इंडिया विजन के तहत प्रारंभ प्रमुख पहलों में से एक 'डिजिटल लॉकर प्रणाली' (Digital Locker System) के ट्रायल वर्जन का प्रारंभ फरवरी, 2015 में किया गया था तथा मात्र 100 दिनों के भीतर 1 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा डिजिटल लॉकर खोलने से इस प्रणाली की उपादेयता सुनिश्चित हुई है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य कागजी दस्तावेजों के इस्तेमाल के चलन को समाप्त करना है। डिजिटल लॉकर के तहत विभिन्न एजेंसियां कागजी दस्तावेजों को नागरिकों की आधार संख्या से संयुक्त कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल लॉकर में डाल सकती हैं। साथ ही नागरिक अपने कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के रूप में ई-हस्ताक्षर सुविधा का प्रयोग करते हुए अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर प्रणाली के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं—

(i) कहीं से कभी भी प्रिंट : सभी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रिंट किए जा सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही आपदा की स्थिति में भी दस्तावेज आसानी से मिल सकते हैं।

(ii) सुविधा : दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कोई लंबी कतार या प्रक्रिया नहीं।

(iii) निःशुल्क : डिजिटल लॉकर सुविधा के लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा और तदनुसार समाज के निचले स्तर के लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।

(iv) साझा योग्य : लोग विभिन्न एजेंसियों/विभागों के साथ बगैर फोटोकॉपी, स्कैन प्रतियों, अपलोड के दस्तावेजों को साझा कर सकते हैं।

(v) सत्यापन : इसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों और जारी प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है जिससे जाली दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल समाप्त होगा।

(vi) सुरक्षित : केवल दस्तावेजों के स्वामी को ही इन्हें देखने का अधिकार होगा और वह अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के आधार पर इन्हें साझा कर सकेगा।

d. ई-गवर्नेंस : इसके तहत तकनीक के माध्यम से शासन-प्रशासन में सुधार लाया जाएगा।

e. ई-क्रांति : इसके अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा।

f. इंफॉर्मेशन फॉर ऑल : सभी को जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी।

g. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन : सरकार का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए कल-पुर्जों के आयात को शून्य करना है।

h. आईटी फॉर जॉब्स : सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

i. अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स : इसके तहत बुनियादी स्तर पर कार्यक्रमों को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय परमाणु बीमा पूल

- भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये मूल्य के 'भारतीय परमाणु बीमा पूल' का शुभारंभ 13 जून, 2015 को किया गया। इसे 'सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट' (Civil Liability for Nuclear Damage Act-CLND) के तहत समूचे नाभिकीय उद्योग (Entire Nuclear Industry) के लिए बाध्यकारी बनाया गया है। ध्यातव्य है कि यह एक्ट वर्ष 2010 में पारित हुआ था, जिसके तहत परमाणु दुर्घटना होने की दशा में संचालक पर लागू अधिकतम देयता को सीमित किया गया है, ताकि वह दबावमुक्त होकर संयंत्र को संचालित कर सके।
- इसके तहत अब कोई परमाणु दुर्घटना होने की दशा में परमाणु संयंत्र संचालक, आपूर्तिकर्ता पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा।
- इस पूल की स्थापना 'जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' (GICI) एवं 11 अन्य गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा मिलकर की गई है। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की बीमा कंपनियां सम्मिलित हैं। इस पूल के लिए 500 करोड़ रुपये का योगदान ब्रिटिश पूल द्वारा दिया गया है।
- इस पूल के तहत जिन दो प्रकार की पॉलिसियों का प्रावधान है, वे हैं–'परमाणु आपूर्तिकर्ता विशेष आपात बीमा पॉलिसी' एवं 'ऑपरेटर देनदारी बीमा पॉलिसी'। इस प्रकार इसमें नाभिकीय संयंत्रों के संचालकों एवं आपूर्तिकर्ताओं दोनों को शामिल किया गया है।
- शुरुआती चरण में इस पूल के तहत परमाणु संयंत्र के बाहर के क्षेत्र, जिसे 'कोल्ड जोन' कहा जाता है, को बीमा के दायरे में लाया गया है।
- जानकारों का कहना है कि इस पूल को शुरू किए जाने से जहां नाभिकीय उद्योग की बाधाएं दूर होंगी, वहीं हम देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ा सकेंगे।

काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं आस्ति) और करारोपण अधिनियम, 2015

- विदेशों में काला धन रखने वालों के लिए सख्त सजा के प्रावधान वाला '<u>काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं आस्ति) और करारोपण अधिनियम, 2015</u>' [The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015] 27 मई, 2015 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर दिया गया।
- इस अधिनियम के प्रावधान उन सभी लोगों पर लागू होंगे जिनके पास अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं। इस अधिनियम के प्रावधान 1 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे।
- इस अधिनियम के तहत विदेशी आय और संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाएगा।
- इस अधिनियम में विदेशी आय पर कर चोरी करने पर पहली बार 3/10 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने तथा दूसरी बार (या उसके बाद प्रत्येक बार) यही अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष तक के कठोर कारावास के साथ-साथ 5 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत कर वंचन अपराध अशमनीय (non-compoundable) होगा तथा सेटलमेंट आयोग जा सकने की अनुमति नहीं होगी।
- विदेशी आस्तियों के लिए रिटर्न जमा करना (कर योग्य आय न होने पर भी) अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।
- विदेशी आय पर आय कर विभाग के सवालों का जवाब न देने पर भी इस अधिनियम में 50 हजार रु. से 2 लाख रु. तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कर अधिकारी विदेशों में जमा संदिग्ध काले धन की जांच के मामले में लोगों को समन या ई-मेल के जरिए नोटिस भेज सकेंगे अथवा फैक्स के माध्यम से सूचना मांग सकेंगे।
- <u>1 जुलाई, 2015</u> को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब तक अघोषित विदेशी संपत्ति या आय को सार्वजनिक करने हेतु 30 सितंबर, 2015 निर्धारित तिथि अधिसूचित की गई। जो लोग इस अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाई से बचना चाहते, वे इस तिथि तक अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति और खातों की जानकारी निश्चित फार्मेट में घोषित कर सकते थे तथा इसके बाद 31 दिसंबर, 2015 तक वे इस पर 30 प्रतिशत कर एवं 30 प्रतिशत जुर्माना अदा कर सकेंगे।
- ज्ञातव्य है कि 30 सितंबर, 2015 तक इसके तहत 638 व्यक्तियों द्वारा 4,147 करोड़ रु. की अघोषित विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा किया गया है। इससे सरकार को कर एवं जुर्माने के रूप में 2,488.20 करोड़ रु. की प्राप्ति होगी।
- अब यदि किसी व्यक्ति की अघोषित आय या संपत्ति सामने आती है तो उसे नए अधिनियम के तहत 30 प्रतिशत कर के अलावा 90 प्रतिशत जुर्माना देना होगा तथा उसे 10 वर्ष तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही दोषी व्यक्ति की विदेशी संपत्ति की जब्ती न किए जाने की स्थिति में उसकी भारत में समतुल्य परिसंपत्तियों की कुर्की एवं जब्ती का अधिकार भी जांच एजेंसियों को मिल जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के दायरे में वे लोग नहीं आते जिनके विदेशी खातों में 5 लाख रु. या इससे कम की राशि है।

भारत में सामाजिक उपभोग के शिक्षा पर मुख्य संकेतक

- केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के तहत जनवरी से जून, 2014 तक कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) के 71वें दौर के दौरान 'सामाजिक उपभोग : शिक्षा' पर हुए सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर एनएसएसओ द्वारा भारत में सामाजिक उपभोग के शिक्षा पर मुख्य संकेतक 30 जून, 2015 को जारी किए गए। इसके मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

➔ भारत में 7 वर्ष एवं अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर 75 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 71 प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में 86 प्रतिशत पाई गई।

➔ 7 वर्ष एवं अधिक आयु के व्यक्तियों में पुरुष साक्षरता दर 83 प्रतिशत जबकि महिला साक्षरता दर 67 प्रतिशत थी।

➔ वयस्क साक्षरता दर (15 वर्ष एवं अधिक आयु) 71 प्रतिशत के स्तर पर थी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 64 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 84 प्रतिशत थी।

➔ प्राथमिक स्कूल तक दूरी के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी भारत में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 99 प्रतिशत परिवारों ने घर से 2 किमी. के भीतर प्राथमिक स्कूल होने की जानकारी दी।

➔ लगभग 86 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों एवं 96 प्रतिशत शहरी परिवारों ने घर से 2 किमी. के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल होने की जानकारी दी जबकि 60 प्रतिशत ग्रामीण और 91 प्रतिशत शहरी परिवारों ने इतनी दूरी पर माध्यमिक स्कूल होने की जानकारी दी।

➔ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4.5 प्रतिशत पुरुष और 2.2 प्रतिशत महिलाओं ने स्नातक और उच्च स्तर की शिक्षा पूरी की थी जबकि शहरी क्षेत्रों में 17 प्रतिशत पुरुषों और 13 प्रतिशत महिलाओं ने शिक्षा का यह स्तर पूरा किया था।

➔ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 29 प्रतिशत परिवारों के पास कंप्यूटर उपलब्ध था। 14-29 वर्ष आयु वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 49 प्रतिशत व्यक्ति कंप्यूटर चलाने में सक्षम थे। 14 वर्ष एवं अधिक आयु वाले कम से कम एक सदस्य वाले परिवारों में लगभग 27 प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्रों में 16 एवं शहरी क्षेत्रों में 49 प्रतिशत) की सर्वेक्षण वर्ष, 2014 में इंटरनेट तक पहुंच थी।

तीन नए नगरीय विकास मिशनों का शुभारंभ

- 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन से तीन महत्त्वाकांक्षी नगरीय विकास पहलों का शुभारंभ किया गया। ये हैं—'अमृत : कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन' (AMRUT : Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation); 'स्मार्ट शहर मिशन' (Smart Cities Mission); एवं '2022 तक सभी के लिए आवास' मिशन ('Housing for All by 2022' Mission)।
- अगले 5 वर्षों में 'अमृत' मिशन हेतु 50,000 करोड़ रु. तथा 'स्मार्ट शहर मिशन' हेतु 48,000 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है जबकि '2022 तक सभी के लिए आवास' मिशन हेतु 3 लाख करोड़ रु. का व्यय करने की सरकार की योजना है। इन तीनों महत्त्वपूर्ण नगरीय विकास पहलों के प्रमुख तथ्यों को अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है—

I. अमृत (AMRUT) मिशन

➔ 'अमृत' या 'कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन' देश के ऐसे 500 शहरों एवं कस्बों में नगरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु क्रियान्वित किया जाएगा, जहां की आबादी एक लाख से अधिक है। साथ ही प्रमुख नदियों पर बसे शहरों, कुछ राजधानी शहरों और पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपों एवं पर्यटन क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

➔ राज्य इस मिशन के तहत चिह्नित शहरों की आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार कर केंद्र को भेजेंगे जिसके आधार पर निधियां जारी की जाएंगी। केंद्र सरकार परियोजनाओं का अलग-अलग आकलन नहीं करेगी जो कि जेएनएनयूआरएम की व्यवस्था से अलग हटकर है।

➔ इस कार्यक्रम के तहत 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों एवं कस्बों के लिए परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों एवं कस्बों के लिए परियोजना लागत की एक-तिहाई केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी। इस योजना हेतु धन का आवंटन प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र के शहरों/कस्बों की संख्या और वहां की शहरी जनसंख्या के अनुरूप किया जाएगा।

➔ इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता को 20 : 40 : 40 के अनुपात में 3 किस्तों में जारी किया जाएगा, जो राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित होगा। गत वर्ष के सुधारों से जुड़ी उपलब्धियों के आधार पर राज्यों/संघीय क्षेत्रों को बजट आवंटन का 10 प्रतिशत बतौर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

➔ जलापूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन के लिए केंद्र के परियोजना लागत के एक-तिहाई से लेकर 50 प्रतिशत तक के हिस्से के बाद राज्यों को शेष राशि जुटानी होगी। राज्यों का अपना हिस्सा 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

➔ केंद्र सरकार की ओर से वित्त स्थानांतरित कर देने के 7 दिनों के भीतर राज्यों को वह धन शहरी स्थानीय निकायों को भेजना होगा।

➔ इस मिशन के तहत सृजित होने वाली परिसंपत्तियों की संचालन एवं रखरखाव लागत के लिए प्रयोक्ता शुल्कों के आधार पर कार्य योजनाओं में कम से कम 5 वर्षों के लिए प्रावधान होने आवश्यक हैं।

➔ 22 अक्टूबर, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा अमृत मिशन के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान के 89 शहरों के लिए कुल 2,786 करोड़ रु. की लागत वाली राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

II. स्मार्ट शहर (Smart Cities) मिशन

- इस मिशन के अंतर्गत देश के कुल 100 चयनित शहरों को 'स्मार्ट शहर' के रूप में विकसित किए जाने की योजना है।
- 27 अगस्त, 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा इस मिशन हेतु 98 शहरों एवं कस्बों की सूची जारी की गई। इनमें 24 राज्य राजधानियां, 18 सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, 5 बंदरगाह शहर तथा 64 छोटे एवं मध्यम श्रेणी के शहर शामिल हैं। इनमें शामिल उत्तर प्रदेश के 12 शहर हैं—इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर एवं वाराणसी। अभी उत्तर प्रदेश के एक अन्य शहर (जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा रायबेरली एवं मेरठ के नाम भेजे गए हैं) तथा जम्मू एवं कश्मीर के एक शहर (श्रीनगर या जम्मू) को इस सूची में शामिल होना है।
- इन 98 चयनित शहरों का चयन एक 'सिटी चैलेंज प्रतियोगिता' के आधार पर किया गया जिसके तहत मिशन के लक्ष्यों को पाने की दिशा में शहरों की क्षमता को वित्तपोषण प्रक्रिया से जोड़ा गया था।
- वर्तमान वित्त वर्ष में देश के 20 शहर इस मिशन हेतु चुने जाएंगे जबकि शेष शहरों का चयन अगले 2 वर्षों में किया जाएगा।
- स्मार्ट शहर मिशन के तहत हर चयनित शहर को अगले 5 वषों के दौरान प्रति वर्ष 100 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- स्मार्ट शहर मिशन का उद्देश्य उपलब्ध परिसंपत्तियों, संसाधनों एवं बुनियादी ढांचे के कारगर इस्तेमाल हेतु स्मार्ट प्रविधियां अपनाने को प्रोत्साहित करना है, ताकि शहरी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके और स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण सुलभ हो सके। इसके तहत शहरी नियोजन पहलों में नागरिकों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- इस पहल के तहत बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें पर्याप्त एवं स्वच्छ जलापूर्ति, साफ-सफाई, ठोस कचरे का प्रबंधन, शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन की प्रभावी व्यवस्था, निर्धनों के लिए वहनीय आवास, विद्युत आपूर्ति, बेहतर आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी युक्त गवर्नेंस, नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत शहरी पर्यावरण शामिल हैं।
- स्मार्ट शहर से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोज्य वाहन (SPV) स्थापित किए जाएंगे जिसमें राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की 50 : 50 अंशधारिता होगी।
- परियोजनाओं के संदर्भ में न्यूनतम क्षेत्र मानक रेट्रोफिटिंग (कमियों वाले स्थान पर जोड़े जाने वाले भाग) के लिए 500 एकड़, पुनर्विकास हेतु 50 एकड़ तथा हरित क्षेत्र (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं के लिए 250 एकड़ निर्धारित किया गया है। यह पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों के संदर्भ में 50 प्रतिशत होगा।
- हासिल किए जाने वाले बेंचमार्कों में शामिल हैं—ऊर्जा आवश्यकताओं का 10 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाएगा, भवन निर्माण का 80 प्रतिशत हरित क्षेत्र होगा तथा नई (हरित क्षेत्र) परियोजनाओं में 35 प्रतिशत आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए होंगे।

स्मार्ट शहर

वर्तमान संदर्भों में एक 'स्मार्ट शहर' से तात्पर्य उस शहर में नगरीय सेनाओं की गुणवत्ता एवं निष्पादन के उन्नयन, बेहतर बुनियादी सेवाओं एवं अवसंरचना की उपलब्धता, स्वच्छ और संपोषणीय पर्यावरण तथा सरकारी सेवाओं, परिवहन एवं यातायात प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के लिए वहनीय आवास, सुरक्षा आदि हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों सहित स्मार्ट समाधानों के व्यापक प्रयोग से है। साथ ही इसमें आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में संपोषणीयता तथा निवासियों के बड़े भाग हेतु समुचित रोजगार की व्यवस्था होना भी शामिल है।

III. '2022 तक सभी के लिए आवास' मिशन

- शहरी आवास हेतु इस राष्ट्रीय मिशन को 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी क्षेत्र)' नाम भी दिया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत अगले 7 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ आवास निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस मिशन के राज्यों/संघीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित 4 प्रमुख घटक/विकल्प हैं—
  - (i) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी विकासकर्ताओं (डेवेलपरों) की भागीदारी के साथ झुग्गी (Slum) निवासियों का पुनर्वास।
  - (ii) ऋण संबद्ध ब्याज सब्सिडी के माध्यम से दुर्बल वर्गों के लिए वहनीय आवासों को प्रोत्साहन।
  - (iii) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वहनीय आवास।
  - (iv) लाभार्थी के व्यक्तिगत घर के निर्माण या विस्तार हेतु सब्सिडी।
- झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार प्रति मकान औसतन 1 लाख रु. का अनुदान उपलब्ध कराएगी जिसका उपयोग राज्यों द्वारा किसी भी झुग्गी पुनर्वास परियोजना हेतु किया जा सकता है।
- ऋण संबद्ध ब्याज सब्सिडी घटक के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए 15 वर्ष की अवधि हेतु आवास ऋणों पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी जो कि एनपीवी आधार पर लगभग 2.3 लाख रु. प्रति आवास होगी।
- शेष दोनों घटकों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रति आवास 1.5 लाख रु. की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह वृहद आवास योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी (ऋण संबद्ध सब्सिडी घटक के अतिरिक्त जो कि केंद्रीय क्षेत्र योजना होगी)।

- इस मिशन के तहत निर्मित होने वाले मकानों का स्वामित्व परिवार की महिला प्रमुख के नाम होगा अथवा परिवार के पुरुष प्रमुख और उसकी पत्नी के नाम संयुक्त रूप से होगा।
- यह मिशन देश के 4,041 वैधानिक नगरों में विस्तारित शहरी क्षेत्र को आच्छादित करेगा जिसमें प्रारंभिक रूप से 500 श्रेणी I नगरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन का ऋण संबद्ध सब्सिडी घटक प्रारंभ से ही देश के सभी वैधानिक शहरों में लागू किया जाएगा।
- 30 अगस्त, 2015 तक इस योजना के तहत 9 राज्यों के 305 शहरों एवं कस्बों की पहचान की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

- 21 जून, 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 192 देशों के 251 से अधिक शहरों में मनाया गया।
- दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राजपथ पर 35 हजार लोगों एवं 84 देशों के प्रतिनिधियों के साथ नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र संघ (एवं न्यूयॉर्क के हिंदू टेम्पल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में) में हुए कार्यक्रम की अगुवाई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की।
- इस अवसर पर गुजरात सरकार की 'योग ऑन रिवर' पहल के अंतर्गत 1500 प्रशिक्षित प्रतिभागियों ने भरूच में नर्मदा नदी में 500 नौकाओं पर योग किया।
- पाकिस्तान में योग दिवस का आयोजन केवल भारतीय उच्चायोग तक सीमित रहा। यमन एकमात्र ऐसा संयुक्त राष्ट्र देश था जहां योग दिवस नहीं मनाया गया। संख्या के हिसाब से दुनिया में 2 अरब लोगों ने यह दिवस मनाया।
- उल्लेखनीय है कि 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था।
- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दो विश्व रिकॉर्ड बने जिन्हें 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में जगह दी गई। पहला रिकॉर्ड एक स्थान पर सबसे अधिक लोगों के योग में इकट्ठा होने का है। इसके पहले 29,973 लोग एक जगह योग के लिए इकट्ठा हुए थे लेकिन 21 जून, 2015 को राजपथ पर 35,985 लोगों ने इकट्ठा होकर पहले का रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरा रिकॉर्ड 50 देशों के प्रतिनिधियों का एक साथ योग में भाग लेने का था जो 21 जून, 2015 को 84 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने से टूटा।

संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015

- संविधान (119वां संशोधन) विधेयक, 2013 राज्य सभा द्वारा 6 मई, 2015 को तथा लोक सभा द्वारा 7 मई, 2015 को पारित किया गया तथा 28 मई, 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद अगले दिन (29 मई को) यह 'संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015' [Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015] के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर अधिसूचित हुआ।
- इस अधिनियम का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सरकारों के मध्य हुए समझौते और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश को निश्चित क्षेत्रों के हस्तांतरण तथा वहां के निश्चित क्षेत्रों के भारत में सम्मिलन को प्रभावी बनाना है।
- इस अधिनियम के माध्यम से भारत के प. बंगाल, असम, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेदों में संशोधन में संशोधन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य 4,096.7 किमी. अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा रेखा है जो भारत के प. बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों से संलग्न है। यह भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं में सबसे वृहद अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है।
- भारत-बांग्लादेश सीमा के दोनों ओर एक-दूसरे देशों के अंतःक्षेत्र या एनक्लेव (Enclave) हैं जिन्हें स्थानीय रूप से 'चिटमहल' कहा जाता है। कुल मिलाकर 102 भारतीय इनक्लेव बांग्लादेश के क्षेत्र में हैं जबकि 71 बांग्लादेशी एनक्लेव भारत के क्षेत्र में हैं। इन एनक्लेवों के भीतर 28 काउंटर एनक्लेव और 1 (दहाला खगराबाड़ी) काउंटर-काउंटर एनक्लेव स्थित हैं।
- दोनों देशों के मध्य यह मुद्दा विभाजन के समय (जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था) से चला आ रहा है जिसके समाधान का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास 1972 के इंदिरा-मुजीब समझौते के तहत किया गया। तदनुसार, भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में 'भू-सीमा समझौता' (Land Boundary Agreement) हस्ताक्षरित हुआ जिसमें एक-दूसरे देशों के एनक्लेवों के आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सरल करने संबंधी प्रावधान थे। बांग्लादेश की संसद द्वारा तो 1974 में ही इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिया गया था परंतु भारत की संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन अब तक शेष था।
- सितंबर, 2011 में दोनों देशों के मध्य 1974 के भू-सीमा समझौते पर अतिरिक्त प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था।
- संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा उपर्युक्त भू-सीमा समझौते और तत्संबंधी प्रोटोकॉल का ही अनुसमर्थन किया गया है और इसमें एक-दूसरे को हस्तांतरित होने वाले क्षेत्रों का विवरण भी है।
- इस संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एनक्लेव बांग्लादेश को प्राप्त होंगे तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए गए हैं। भूक्षेत्र के आधार पर भारत की जहां 17,160.63 एकड़ भूमि बांग्लादेश को हस्तांतरित हुई है, वहीं बांग्लादेश की 7,110.02 एकड़ भूमि भारत को हस्तांतरित हुई है। भारत के प. बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम के क्षेत्रों की बांग्लादेश से लगी सीमाओं का सीमांकन भी इसके तहत किया जा रहा है।
- 6 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश-यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में दोनों पक्षों द्वारा अनुसमर्थन पत्रों का आदान-प्रदान किया गया तथा भूमि के आदान-प्रदान संबंधी आशय-पत्र हस्ताक्षरित किए गए। तत्पश्चात 6 जुलाई, 2015 से भारत और बांग्लादेश ने भू-सीमा समझौते के तहत एक-दूसरे के सीमा क्षेत्र में स्थित एनक्लेवों में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीयता की पसंद दर्ज करने के उद्देश्य से संयुक्त सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया।
- ज्ञातव्य है कि इस भू-सीमा समझौते के तहत प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) वाली भारत को हस्तांतरित होने वाली भूमि 2,777.038 एकड़ है जिसमें प. बंगाल में

2,398.05 एकड़, मेघालय में 240.578 एकड़ एवं त्रिपुरा में 138.41 एकड़ भूमि आएगी। दूसरी ओर प्रतिकूल कब्जा वाली बांग्लादेश को हस्तांतरित होने वाली भूमि 2,267.682 एकड़ है जिसमें प. बंगाल से 1,957.59 एकड़, मेघालय से 41.702 एकड़ और असम से 268.39 एकड़ भूमि जाएगी।

- दोनों देशों के मध्य एनक्लेवों और प्रतिकूल कब्जा वाले क्षेत्रों का भौतिक आदान-प्रदान और सीमांकन कार्य 31 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 के मध्य चरणों में संपन्न किया जा रहा है। इन एनक्लेवों को 31 जुलाई, 2015 की मध्य रात्रि से हस्तांतरित मान लिया गया है तथा सीमांकन का कार्य दोनों देशों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा 30 जून, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 30 नवंबर, 2015 तक इन एनक्लेवों के निवासियों की उनके द्वारा चयनित नागरिकता के आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने की आशा व्यक्त की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का विस्तार

- 9 जून, 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में संपन्न 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड' (NCRPB : National Capital Region Planning Board-1985 में गठित) की बैठक में देश की राजधानी दिल्ली की अवसंरचना पर बोझ कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के पुनर्विस्तार का निर्णय लिया गया।
- इस विस्तार के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीन अतिरिक्त जिले शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। ये हैं— मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) तथा जींद एवं करनाल (हरियाणा)।
- वर्तमान विस्तार के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त शामिल जिलों की संख्या 22 हो गई है जो कि इस प्रकार हैं—

राज्य	एनसीआर में शामिल जिले
हरियाणा	गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा), मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर
राजस्थान	अलवर, भरतपुर

आईएपी हेल्थफोन प्रोग्राम

- 3 जून, 2015 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा नई दिल्ली में 'आईएपी (IAP : Indian Academy of Pediatrics) हेल्थफोन प्रोग्राम' का शुभारंभ किया गया।
- यह देश भर में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु प्रारंभ विश्व का सर्वाधिक वृहद डिजिटल (मोबाइल फोनों की वृहद पहुंच का उपयोग करते हुए) जनशिक्षा कार्यक्रम है।
- यह कार्यक्रम आईएपी की पहल है जिसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा यूनिसेफ की भागीदारी के साथ प्रारंभ किया गया है।
- इस कार्यक्रम को वोडाफोन इंडिया द्वारा समर्थन उपलब्ध कराया गया है तथा बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत चलाए जाने वाले त्रिवर्षीय गहन जन-जागरुकता अभियान से भारत में वर्ष 2025 तक जन्म लेने वाले लगभग 60 मिलियन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने की आशा व्यक्त की गई है।

'खोया पाया' वेब पोर्टल

2 जून, 2015 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से **'खोया पाया'** वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट (http://khoyapaya.gov.in) पर सीधे जाकर खोए हुए बच्चों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी और प्राप्त की जा सकेगी।

यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में हर साल औसतन 1 लाख बच्चे (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार लगभग 70 हजार) गायब होते हैं। गत वर्ष संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2011 से जून, 2014 के बीच 3.27 लाख बच्चे लापता हुए (सर्वाधिक महाराष्ट्र से) जिनमें से 45 प्रतिशत बच्चों का पता नहीं लगाया जा सका था।

नीति (NITI) आयोग की स्थापना

- 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' (पूरा नाम-'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' ; NITI : National Institution for Transforming India) की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। ज्ञातव्य है कि योजना आयोग का गठन भी 15 मार्च, 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से ही किया गया था।
- नीति आयोग का संघटन इस प्रकार निर्धारित किया गया है—

(i) अध्यक्ष : प्रधानमंत्री।

(ii) शासी परिषद : यह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघीय क्षेत्रों के उप राज्यपालों से मिलकर बनेगी।

(iii) क्षेत्रीय परिषदें : ऐसे विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों जो एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करते हों, के संदर्भ में ये परिषदें आवश्यकता-आधार और विशिष्ट कार्यकाल हेतु गठित की जाएंगी। इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होंगे। इनका संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा तथा इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(iv) विशेष आमंत्रित : नीति आयोग में संबद्ध कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, विशेष जानकार और पेशेवर विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।

(v) पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा : अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अग्रलिखित शामिल होंगे—

(a) उपाध्यक्ष : प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(b) पूर्णकालिक सदस्य : प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(c) अंशकालिक सदस्य : अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन क्षमता में सदस्य जो कि चक्रीय आधार पर होंगे।

(d) पदेन सदस्य : प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य।

(e) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रधानमंत्री द्वारा नियत कार्यकाल के लिए, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाएगा।

- 5 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) के प्रोफेसर और एशियाई विकास बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके अरविंद पनगड़िया (13 जनवरी, 2015 को पदभार ग्रहण) को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही उन्होंने नीति आयोग में दो पूर्णकालिक सदस्यों- बिबेक देबरॉय (अर्थशास्त्री ; 21 जनवरी, 2015 को पदभार ग्रहण) और डॉ. वी.के. सारस्वत (पूर्व रक्षा आर एंड डी सचिव; 30 जनवरी, 2015 को पदभार ग्रहण) तथा चार पदेन सदस्यों- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और तीन विशेष आमंत्रितों- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलौत एवं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की नियुक्ति भी की।
- 7 सितंबर, 2015 को कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ रमेश चंद को नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

चेन्नई एवं जयपुर मेट्रो का शुभारंभ

- 29 जून, 2015 को चेन्नई की मुख्यमंत्री जे. जयललिता द्वारा 'चेन्नई मेट्रो' के प्रथम चरण (कोयमबेडु-अलान्दुर) के शुभारंभ के साथ मेट्रो रेल सुविधा वाला चेन्नई भारत का 7वां शहर बन गया है। इस मेट्रो के उद्घाटन के अवसर पर इसकी चालक एक महिला थीं।
- 3 जून, 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा हरी झंडी दिखाकर जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से जयपुर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया।
- जयपुर एवं चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, बंगलुरू, गुड़गांव और मुंबई के बाद भारत की क्रमशः छठीं एवं सातवीं संचालित मेट्रो रेल प्रणाली बनी हैं।

बाणसागर बांध विवाद

- बाणसागर बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित बांध है जिसका निर्माण 1973 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों के मध्य हुए समझौते के तहत 1978 में प्रारंभ हुआ था तथा इसका वर्ष 2006 में लोकार्पण हुआ था।
- इस बांध (ऊंचाई 67 मीटर एवं लंबाई 1,020 मीटर) के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव का व्यय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा 2:1:1 के अनुपात में वहन करना था तथा बाणसागर जलाशय के पानी का आवंटन भी इसी अनुपात में होना था।
- हाल ही में बाणसागर बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य जल के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा।
- मई, 2015 में उत्तर प्रदेश की मांग के बावजूद जब मध्य प्रदेश द्वारा बाणसागर जलाशय से पानी छोड़े जाने से इंकार कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में केंद्रीय जल आयोग से अपील की गई।
- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती के हस्तक्षेप के बाद इस मसले पर केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो सभी पक्षकार राज्यों से वार्ता कर इस मुद्दे का परीक्षण करेगी। अंततः जून, 2015 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य इस जल विवाद का तात्कालिक रूप से पटाक्षेप हुआ जब केंद्रीय मंत्री उमा भारती की अपील पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बाणसागर बांध से उत्तर प्रदेश के लिए पानी छोड़े जाने का आदेश दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि 1973 के समझौते के तहत बाणसागर बांध के जल में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 2 मिलियन एकड़ फीट तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार की हिस्सेदारी 1-1 मिलियन एकड़ फीट निर्धारित है। इस बहुउद्देशीय परियोजना में पुरानी सोन नहर प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए इसके माध्यम से मध्य प्रदेश (रीवा, सीधी, सतना एवं शहडोल जिले) में 2.49 लाख हेक्टेयर भूमि, उत्तर प्रदेश (मिर्जापुर एवं इलाहाबाद जिले) में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि तथा बिहार में 0.94 लाख हेक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई तथा मध्य प्रदेश में 425 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन करना शामिल है।

'नमामि गंगे' : एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन

- 13 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम 'नमामि गंगे' को स्वीकृति प्रदान की गई।
- इस एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करने संबंधी प्रयासों को व्यापक रूप से समेकित करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के तहत क्रियान्वित होगा।
- 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 20,000 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि गंगा नदी के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 30 वर्षों में हुए व्यय से चार गुना अधिक है।
- गंगा नदी संरक्षण की इस वृहद योजना में पूर्व योजनाओं की तुलना में क्रियान्वयन के प्रारूप में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत बेहतर और सतत परिणाम हासिल करने

के लिए नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को परियोजना में शामिल करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही अब इस कार्यक्रम में राज्यों के साथ जमीनी स्तर के संस्थानों यथा—शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्रियान्वयन स्तर पर शामिल किया जाएगा।

- यह कार्यक्रम 'स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन' (NMCG : National Mission for Clean Ganga) तथा इसके अनुषंगी राज्य संगठनों अर्थात, 'राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों' (SPMGs : State Program Management Groups) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा तथा एनएमसीजी जहां आवश्यकता होगी, वहां इस हेतु क्षेत्र कार्यालयों की भी स्थापना करेगा।
- 'नमामि गंगे' कार्यकम के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए परियोजना पर्यवेक्षण हेतु निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली प्रस्तावित है—राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यबल जिसकी सहायता एनएमसीजी द्वारा की जाएगी; राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति जिसकी सहायता एसपीएमजी द्वारा की जाएगी; जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति।
- केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों एवं परियोजनाओं का शत-प्रतिशत वित्तीय भार वह वहन करेगी ताकि कार्यक्रम की प्रगति को त्वरित गति प्रदान की जा सके।
- साथ ही पिछली गंगा कार्य योजनाओं के असफल परिणामों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि तक इस कार्यक्रम के परिचालन और परिसंपत्तियों के प्रबंधन की व्यवस्था स्वयं करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के अति प्रदूषित स्थलों (Pollution Hotspots) के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)/ विशेष प्रयोज्य वाहन (SPV) व्यवस्था को अपनाया जाएगा।
- गंगा को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी प्रयासों को सुचारु रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार की प्रादेशिक सैन्य इकाई (Territorial Army Unit) के तौर पर 'गंगा इको-टास्क फोर्स' की 4 बटालियनें स्थापित करने की भी योजना है और साथ ही प्रदूषण पर नियंत्रण और नदी के संरक्षण के लिए एक कानून बनाने पर भी अलग से विचार किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि गंगा नदी में व्याप्त प्रदूषण के उपशमन और जल गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1985 में 'केंद्रीय गंगा प्राधिकरण' और 'गंगा परियोजना निदेशालय' का गठन किया गया था तथा तत्पश्चात 14 जनवरी, 1986 को 'गंगा कार्य योजना' (GAP : Ganga Action Plan) का शुभारंभ किया गया था जिसके दो चरणों तथा हजारों करोड़ रु. के व्यय के बाद भी बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त हुए। इस कार्य योजना की समीक्षा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2009 को 'मिशन क्लीन गंगा' प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी तथा इस संदर्भ में पहले ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGBRA) का गठन भी किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि गंगा एवं देश की अन्य नदियों के संरक्षण एवं विकास हेतु जनजागरूकता विस्तार के लिए वर्ष 2015-16 को 'जल संरक्षण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।

तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रारंभ

- 9 मई, 2015 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं—अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

I. अटल पेंशन योजना (APY)

- यह पेंशन योजना मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति पेंशन प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
- अटल पेंशन योजना के तहत अंशदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रु./2000 रु./3000 रु./4000 रु./5000 रु. न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जो उनके अंशदान पर निर्भर करेगी।
- इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी तथा अंशदान की राशि योजना में शामिल होने के समय आयु पर निर्भर करेगी (न्यूनतम 42 रु. प्रतिमाह 18 वर्ष की आयु में)।
- केंद्र सरकार ऐसे प्रत्येक पात्र अंशदाता के खाते में हर वर्ष कुल अंशदान के 50 प्रतिशत के बराबर या 1000 रु. (इनमें से जो भी कम हो) की राशि का सह-योगदान 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) तक करेगी, जो नई पेंशन योजना (NPS) में 31 दिसंबर, 2015 से पूर्व शामिल हुए हैं तथा जो आयकरदाता नहीं हैं और किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।
- इस योजना के तहत अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी/पति को पेंशन प्राप्त होगी तथा उसके बाद नामित व्यक्ति को पेंशन निधि लौटा दी जाएगी।

II. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

- इस योजना का उद्देश्य देश के उन करोड़ों परिवारों तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाना है जो अभी भी बीमा सुविधा से वंचित हैं। इस योजना के पात्र वे सभी बैंक खाताधारक हैं जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
- इस योजना के तहत अंशदाताओं को मात्र 330 रु. वार्षिक प्रीमियम का भुगतान (बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से) करने पर 2 लाख रु. का जीवन बीमा प्राप्त होगा। इस योजना के तहत एक बार सदस्य बनने के बाद 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
- इस योजना (जो वस्तुतः 'टर्म इंश्योरेंस प्लान'- अवधि बीमा योजना है) में बीमा अवधि 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है तथा हर वर्ष ऑटो डेबिट से निर्धारित राशि जमा कर इसका नवीनीकरण होगा।
- यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और अन्य निजी क्षेत्र की इच्छुक बीमा कंपनियों द्वारा प्रशासित होगी।

III. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

- इस योजना का उद्देश्य देशवासियों को अत्यंत कम मूल्य पर दुर्घटना बीमा का लाभ उपलब्ध कराना है। इसके तहत अंशदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारक पात्र होंगे जिन्हें मात्र 12 रु. के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना में अंशदाता की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रु. तथा दुर्घटना में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रु. का जोखिम कवर या बीमा राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना का प्रीमियम भी लाभार्थी के बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से लिया जाएगा तथा इसकी बीमा अवधि भी 1 जून से 31 मई है जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण होगा।
- यह योजना साधारण बीमा निगम (GIC) तथा अन्य निजी क्षेत्र की इच्छुक कंपनियों द्वारा प्रशासित की जाएगी।

हाल के वर्षों में लोक सभा का सर्वाधिक उत्पादक सत्र

- संसद का विगत बजट सत्र संसदीय कार्य मंत्रालय और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आकलनों के अनुसार हाल के वर्षों का सर्वाधिक उपयोगी और उत्पादक संसदीय सत्र रहा। इस बजट सत्र के 4 माह (फरवरी-मई, 2015) के दौरान लोक सभा की उत्पादकता (संसदीय कार्य के लिए निर्धारित कुल घंटों की तुलना में वास्तविक कार्यकारी घंटे) 123.4 प्रतिशत रही, जो कि विगत 15 वर्षों में सर्वाधिक है।
- इस बजट सत्र में लोक सभा में 23 घंटे 45 मिनट अतिरिक्त कार्य किया गया। इसके फलस्वरूप लोक सभा ने 2005 के मानसून सत्र (जबकि लोक सभा की उत्पादकता 110 प्रतिशत रही) को भी इस सत्र में पीछे छोड़ दिया।
- इस बजट सत्र में राज्य सभा की उत्पादकता 106.79 प्रतिशत रही तथा विगत दशक में केवल दो सत्र (दोनों वर्ष 2009 में) ऐसे रहे हैं जबकि राज्य सभा में इससे अधिक कार्य हुआ था। ज्ञातव्य है कि 2009 के बजट सत्र के दौरान राज्य सभा में निर्धारित अवधि की तुलना में 113 प्रतिशत कार्य हुआ था।

सरस्वती नदी की प्रामाणिकता सिद्ध

- 6 मई, 2015 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुगलवाली गांव में खुदाई के दौरान जल की धारा फूटने से प्राचीन सरस्वती नदी के अस्तित्व से जुड़ी तमाम किवदंतियों और मिथकीय प्रसंगों का राज खुलता प्रतीत हो रहा है और इस नदी की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि प्रशासन की ओर से मनरेगा के तहत 21 अप्रैल, 2015 से रूलाहेड़ी एवं मुगलवाली गांव में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य आरंभ किया गया था तथा इसके बाद छलौर और मिल्कड़ा गांवों में भी ऐसी खुदाई शुरू हुई थी।
- मुगलवाली एवं रूलाहेड़ी गांव में खुदाई के दौरान कहीं 7 तो कहीं 10 फीट पर पानी मिल रहा है जबकि इस क्षेत्र में अन्य स्थानों पर जलस्तर 250 फीट तक नीचे है। इससे यह धारणा बलवती हुई है कि यहां से सरस्वती नदी बहती थी।
- प्रयोगशाला में हुई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जहां जल मिला है, वह एक प्राचीन नदी का तल है। राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से भी यमुनानगर में सरस्वती बहती थी। खुदाई के दौरान निकले पानी के साथ हिमालय क्षेत्र के छोटे-छोटे पत्थर और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। पानी के साथ मिले पत्थर घिसे हुए हैं जो प्रमाण है कि वे पानी के प्रवाह के साथ बहकर यहां तक पहुंचे हैं।
- इससे पूर्व भी सरस्वती नदी की खोज को लेकर देश-विदेश के संस्थान इसके अस्तित्व संबंधी सकारात्मक रिपोर्ट दे चुके थे।
- सरस्वती नदी को खोजने की आशा को विशेष बल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' के उपग्रह 'लैंडसेट' से प्राप्त डिजिटल तस्वीरों से मिला जिनमें जैसलमेर क्षेत्र में एक निश्चित पैटर्न में भूजल के उपस्थित होने की बात सामने आई।
- नासा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' के उपग्रह चित्रों से भी सरस्वती नदी प्रवाह क्षेत्र के साक्ष्य मिले थे तथा ओएनजीसी की 'सरस्वती परियोजना' के तहत दूरसंवेदन और भूगर्भीय अध्ययनों के आधार पर इसकी पुष्टि हुई थी।
- पूर्व में हुए तमाम शोध नतीजों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती एक विशाल नदी थी जो 6 हजार से 2 हजार ई.पू. तक अस्तित्व में थी।
- यह नदी संभवतः वर्तमान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों से होकर पाकिस्तान के क्षेत्र से होते हुए अरब सागर में गिरती थी।

नेट-निरपेक्षता का प्रश्न

- नेट-निरपेक्षता (Net-Neutrality) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 2003 में कोलंबिया लॉ स्कूल के कानून के प्रोफेसर टिम वू ने किया था। उन्होंने नेट निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा कि इसके अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार कंपनियों को इंटरनेट पर आने वाली सभी सूचनाओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को सभी सूचनाएं बिना किसी भेदभाव के पहुंचानी चाहिए। इसके अनुसार हर तरह की सर्फिंग के लिए गति बराबर होनी चाहिए। किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाने के लिए आपकी गति को सेवा प्रदाता तेज या धीमा नहीं कर सकता।
- नेट-निरपेक्षता के संबंध में हालिया विवाद तब उठा जब एयरटेल ने 'एयरटेल जीरो' नामक एक स्कीम शुरू की जिसके जरिए ग्राहक बिना डाटा शुल्क चुकाए चयनित मोबाइल एप्लीकेशनों का उपयोग कर सकते थे। बाद में एयरटेल पर पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत कंपनियों के बीच भेद-भाव करके नेट-निरपेक्षता का उल्लंघन करने का आरोप लगा। अंततः 'एयरटेल जीरो' के चलते 'फ्लिपकार्ट' ने 'एयरटेल जीरो' से अपना संबंध खत्म कर लिया।
- अप्रैल, 2015 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने एक सिफारिश की जिसके अनुसार आवाज और संदेश का इस्तेमाल करने वाली किसी भी कंपनी को चाहे वह विदेशी ही क्यों न हो सरकार से लाइसेंस लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंटरनेट प्रदाता कंपनियों को टेलीकॉम कंपनियों के पास पंजीकरण कराना चाहिए।

- इस सिफारिश पर ट्राई ने उपभोक्ताओं से उनके विचार मांगे जिस पर 11 लाख लोगों ने ट्राई को ई-मेल भेजे। ई-मेल भेजने वालों का यह भी आरोप था कि टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल एवं रिलायंस कुछ इंटरनेट प्रदाता कंपनियों से मिलकर नेट-निरपेक्षता पर हमला करने की कोशिश कर रही हैं।
- यदि इंटरनेट कंपनियों और टेलिकॉम कंपनियों के बीच इस तरह का समझौता हो जाता है तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा।
- यदि नेट-निरपेक्षता हटा दी जाए तो इंटरनेट प्रदाता कंपनी किसी भी वेबसाइट से करार कर सकती है। इंटरनेट उपभोक्ता उस वेबसाइट पर तो जल्दी पहुंच जाएंगे, अन्य वेबसाइटों के लिए अलग से पैसा देना होगा। इस तरह इंटरनेट प्रदाता कंपनी को दोहरा लाभ होगा, एक तरफ ग्राहक की ओर से दूसरा वेबसाइट से।
- वस्तुतः नेट-निरपेक्षता यदि खतरे में पड़ती है तो इंटरनेट अमीरों के लिए अलग होगा गरीबों के लिए अलग। आज जब दुनिया भर में इंटरनेट को 'सार्वजनिक सुविधा' घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ा है तो ऐसे में सरकार की और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की प्राथमिकता भारत में इंटरनेट को अधिक से अधिक फैलाने की होनी चाहिए, न कि इस क्षेत्र को नियामक कदमों के जरिए सीमित करने और उपभोक्ताओं के लिए महंगा करने की।

'फेम-इंडिया' योजना

- 8 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री अनंत गीते द्वारा 'फेम (FAME : Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles)-इंडिया' योजना का शुभारंभ किया गया।
- यह देश में पर्यावरण-मित्र वाहनों के विक्रय को त्वरित गति से बढ़ावा देने हेतु प्रांरभ 'विद्युत मोबिलिटी हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMEM : National Mission on Electric Mobility - वर्ष 2011 में स्वीकृत) के भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है।
- 'फेम-इंडिया' योजना का उद्देश्य देश में हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने और उनके विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के प्रथम चरण (2015-17) हेतु 795 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है तथा प्रारंभिक रूप से संघीय बजट 2015-16 में इस हेतु 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
- उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा जनवरी, 2013 में 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान-2020' जारी किया गया था। इसके तहत देश में वर्ष 2020 तक 60-70 लाख हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों के परिचालन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 'फेम-इंडिया' योजना के अंतर्गत देश भर के निम्नलिखित शहरों को आच्छादित किए जाने की योजना है—
  - (i) 'स्मार्ट सिटी' के तहत आने वाले शहर।
  - (ii) प्रमुख नगरीय संकुलन-दिल्ली एनसीआर, वृहत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू, हैदराबाद एवं अहमदाबाद।
  - (iii) सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों के अन्य मिलियन प्लस (1 मिलियन से अधिक आबादी वाले) नगरीय संकुलन/शहर
  - (iv) उत्तर-पूर्वी राज्यों के शहर।
- यह योजना सभी प्रकार के वाहनों-टू, थ्री एवं फोर व्हीलर, कार, एलसीवी, बस आदि) तथा सभी तरह के हाइब्रिड और पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है।

'सागरमाला' परियोजना : नीली क्रांति की ओर

- 25 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'नीली क्रांति' की दिशा में महत्त्वाकांक्षी 'सागरमाला' परियोजना ('Sagarmala' Project) की परिकल्पना और संस्थागत ढांचे को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के बंदरगाहों (Ports) के आस-पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना तथा बंदरगाहों तक माल (कार्गो) के दक्षता और किफायती ढंग से त्वरित आवागमन हेतु बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना है।
- सागरमाला परियोजना के नीतिगत मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय एवं नियोजन के विविध पहलुओं की समीक्षा तथा योजना एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति' (NSAC : National Sagarmala Apex Committee) का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय पोत परिवहन (Shipping) मंत्री हैं तथा हितधारक मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री और समुद्र तटीय राज्यों के मुख्यमंत्री/बंदरगाहों संबंधी मंत्री इसके सदस्य हैं।
- 5 अक्टूबर, 2015 को एनएसएसी की प्रथम बैठक केंद्रीय पोत एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई।
- इस महत्त्वपूर्ण परियोजना हेतु केंद्रीय स्तर पर कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 'सागरमाला विकास कंपनी' (SDC) का गठन किया जाएगा। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण हेतु वित्त वर्ष 2015-16 में 692 करोड़ रुपये की आवश्यकता व्यक्त की गई है।

निर्धारित अंतर्देशीय जलमार्गों को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित करने को स्वीकृति

- 25 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश के 101 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को नौपरिवहन हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग (NW-National Watarway) घोषित_ किए जाने के संदर्भ में कानून अधिनियमित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार नौपरिवहन के लिए किसी अंतर्देशीय जलमार्ग का तभी विकास कर सकती है जबकि संसद द्वारा कानून के तहत उसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाए। किसी अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिए जाने पर उसमें जहाजरानी के विकास और नियमन तथा यंत्रचालित वाहनों द्वारा नौपरिवहन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, तथापि जल के उपयोग, संबंधित भूमि, खनिज, अवयव, धातु, बालू आदि के स्वामित्व का अधिकार राज्य सरकार के पास ही रहता है।

- उल्लेखनीय है कि भारत के कुल अंतर्देशीय परिवहन में जलमार्गों का भाग मात्र 0.4 प्रतिशत ही है जबकि नीदरलैंड्स में ये 42 प्रतिशत, चीन में 8.7 प्रतिशत और अमेरिका में 8 प्रतिशत के स्तर पर है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय अभियान

- 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले के एचयूडीए ग्राउंड से केंद्र सरकार के सामाजिक क्षेत्र के पुनरोत्थान के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) का राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुभारंभ किया गया।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना एक साथ देश के अल्प (खराब) बाल लिंगानुपात (जहां लड़कियों की जनसंख्या का लड़कों की जनसंख्या से अनुपात काफी कम है) वाले 100 जिलों में प्रारंभ की गई है जिसमें हरियाणा (जहां बाल लिंगानुपात 834 के स्तर पर देश में सबसे कम है) के सर्वाधिक 12 जिले (महेंद्रगढ़ सहित जो न्यूनतम बाल लिंगानुपात 775 वाला जिला है) शामिल हैं। इस योजना में पंजाब के 11 जिले, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के 10-10 जिले, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली और गुजरात के 5-5 जिले, मध्य प्रदेश के 4 जिले, उत्तराखंड के 2 जिले तथा शेष सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के एक-एक जिले शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि बाल लिंगानुपात (CSR-Child Sex Ratio) को 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में सीएसआर वर्ष 1961 में 976 पर था जो कि वर्ष 2001 में 927 और पुनः वर्ष 2011 में 919 (ग्रामीण-923; शहरी-905) पर आ गया है।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के समग्र लक्ष्य हैं—
  (i) बालिका शिशु के जन्म पर खुशी एवं उत्सव मनाना।
  (ii) जेंडर अभिनत लिंग चयनित समापन (बालिका शिशु भ्रूण हत्या) पर रोक लगाना।
  (iii) बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना।
  (iv) बालिका की शिक्षा एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।
- 29 अक्टूबर, 2015 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना हेतु जागरूकता विस्तार के लिए सेलटिक (Celltick) मोबाइल मीडिया के साथ भागीदारी में देश के लगभग 100 मिलियन मोबाइल प्रयोक्ताओं तक इस योजना के व्यापक प्रसार के लिए एक नई पहल का शुभारंभ किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि इस राष्ट्रीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर प्रख्यात सिने-तारिका माधुरी दीक्षित को बनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इससे पहले 1 अक्टूबर, 2007 को 'बेटी बचाओ अभियान' नाम से राज्य स्तरीय योजना की शुरुआत की गई थी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ

- 19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीकानेर के निकट श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ (राजस्थान) से 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (Soil Health Card Scheme) का शुभारंभ किया गया।
- 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का नारा दिया गया।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत देश के प्रत्येक किसान को कृषि भूमि की मिट्टी की जांच हेतु कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे तथा अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड न सिर्फ मिट्टी की उत्पादकता से जुड़ी जानकारियां देगा बल्कि यह भूमि में उर्वरकों के समुचित उपयोग संबंधी सलाह भी उपलब्ध कराएगा। इस कार्ड का 3 वर्ष के अंतराल पर नवीनीकरण किया जा सकेगा।
- वर्ष 2015 के 'अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष' के रूप में मनाए जाने के संदर्भ में भारत द्वारा प्रारंभ इस योजना का संज्ञान लेते हुए विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा इसे बेहतरीन पहल कहा गया है।

2015 : अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष

20 दिसंबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के दौरान 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित करने के साथ वर्ष 2015 को 'अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष' (International Year of Soils) घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में मृदाओं के महत्त्व के प्रति जागरूकता का विस्तार करना है।

राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना - 'हृदय'

- 21 जनवरी, 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा देश की विपुल एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनरोत्थान के लिए 'राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना' (HRIDAY : National Heritage Development and Augmentation Yojna) का केंद्रीय योजना के रूप में शुभारंभ किया गया।
- 'हृदय' योजना के पहले चरण में जिन 12 विरासत शहरों को समग्र विकास हेतु चुना गया है, वे इस प्रकार हैं—वाराणसी एवं मथुरा (उत्तर प्रदेश), अमृतसर (पंजाब), वारंगल (तेलंगाना), अजमेर (राजस्थान), गया (बिहार), कांचीपुरम एवं वेल्लांकिनी (तमिलनाडु), अमरावती (आंध्र प्रदेश), बादामी (कर्नाटक), द्वारका (गुजरात) और पुरी (ओडिशा)। इस योजना का पूरा व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा चयनित 12 शहरों को कुल 500 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।
- 27 अक्टूबर, 2015 को 'हृदय' योजना के लिए आठ विरासत शहरों (वाराणसी, मथुरा, अजमेर, द्वारका, बादामी, वारंगल, अमरावती एवं वेल्लांकिनी) हेतु कार्ययोजनाओं को कुल 431 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है।

'प्रसाद' : राष्ट्रीय तीर्थस्थल एवं आध्यात्मिक आवर्धन कार्यक्रम

सभी धर्मों के तीर्थस्थलों के सौंदर्यीकरण किए जाने तथा वहां सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचों में सुधार किए जाने के दृष्टिकोण से एक राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक आवर्धन कार्यक्रम (PRASAD) की घोषणा वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में की गई तथा इस दिशा में पहल किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपयों की एक धनराशि प्रस्तावित कर दी गई है।

◆◆◆

राष्ट्रीय नीतियां

● राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2015 ● हरित राजमार्ग नीति, 2015 ● राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, 2015 ● राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 ● प्रस्तावित नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2015 ● प्रथम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2015

- 30 अक्टूबर, 2015 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजापति राजू द्वारा 'राष्ट्रीय नागर विमानन नीति' (NCAP : National Civil Aviation Policy), 2015 का संशोधित मसौदा जारी किया गया।
- इस नीति के उद्देश्यों में विभिन्न विमानन उपक्षेत्रों यथा- एयरलाइंस, हवाई अड्डों, कार्गो, रखरखाव-मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाओं, सामान्य विमानन, एयरोस्पेस विनिर्माण, कौशल विकास आदि के लिए अनुकूल वातावरण और समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ घरेलू टिकटों की संख्या 2022 तक 30 करोड़ एवं 2027 तक 50 करोड़ (साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टिकटों की संख्या 2027 तक 20 करोड़)) करने हेतु आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना शामिल है।
- इस नीति के तहत क्षेत्रीय संयोजकता योजना (RCS : Regional Connectivity Scheme) 1 अप्रैल, 2016 से लागू की जाएगी जिसके तहत एक घंटे तक की हवाई यात्रा का किराया लगभग 2500 रु. तक ही होगा।
- इस नीति में क्षेत्रीय मार्गों पर विमान सेवा संपर्क बढ़ाने हेतु आरसीएस एवं सीएटी IIA के अतिरिक्त सभी हवाई टिकटों (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- छोटे शहरों में 50 करोड़ रु. की लागत से सामान्य न्यूनतम सुविधाओं वाले (नो-फ्रिल) हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।
- इस नीति में 'मेक इन इंडिया' पर जोर देते हुए विमानों के रखरखाव और मरम्मत के साथ एयरोस्पेस निर्माण हेतु विनिर्माण सुविधाओं का देश में विस्तार किए जाने की बात कही गई है।
- नई नागर विमानन नीति में विमानन कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक करने का प्रस्ताव है।

हरित राजमार्ग नीति, 2015

- 29 सितंबर, 2015 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में 'हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण एवं अनुरक्षण) नीति, 2015' [Green Highways (Plantation, Transplantation, Beautification & Maintenance) Policy, 2015] का शुभारंभ देश में हरित राजमार्गों के विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया।
- हरित राजमार्ग नीति का उद्देश्य समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों की भागीदारी के साथ राजमार्ग कॉरिडोरों में हरियाली को संवर्द्धित करना है।
- इस नीति के तहत सभी राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लागत का 1 प्रतिशत राजमार्गों पर वृक्षारोपण और उनके रखरखाव के लिए पृथक रखा जाएगा जिससे प्रतिवर्ष वृक्षारोपण हेतु लगभग 1000 करोड़ रु. 'हरित राजमार्ग निधि' (Green Highway Fund) के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।
- यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी। स्थानीय लोगों और समुदायों को गरिमापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना इस नीति के विजन में शामिल है।
- इस नीति के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की 'भुवन' (Bhuvan) और 'गगन' (GAGAN) उपग्रह आधारित प्रणालियों का उपयोग करते हुए सशक्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रत्येक रोपे गए वृक्ष की गणना एवं लेखा परीक्षण तथा बेहतर कार्य करने वाली एजेंसियों को सम्मानित करने हेतु प्रावधान भी इस नीति में किए गए हैं।
- राजमार्गों पर सड़कों के किनारे 1200 सुविधाएं (Amenities) भी स्थापित की जाएंगी।
- हरित राजमार्ग नीति भारत के लिए आवश्यक वृक्षावरण क्षेत्र को पूरा करने में सहायता करने के साथ प्रदूषण में कमी लाने में सहायक होगी तथा इससे देश में सड़क हादसों में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

हरित राजमार्ग नीति की विशेषताएं

● वृक्षारोपण कार्य को सिविल कार्य से अलग रखना ● हरित कॉरिडोरों का सृजन ● पर्यावरण में सुधार ● रोजगार के अवसर ● राजमार्गों का सौंदर्य बढ़ाना ● स्थानीय लोगों के लिए ठोस लाभ ● उद्यमशीलता को बढ़ावा ● कुल परियोजना लागत का एक प्रतिशत वृक्षारोपण निधि के रूप में निर्दिष्ट।

राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, 2015

- 9 सितंबर, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति' (National Offshore Wind Energy Policy), 2015' को स्वीकृति प्रदान की गई।
- इस नीति के तहत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ : Exclusive Economic Zone) के भीतर अपतटीय क्षेत्रों के प्रयोग हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में अधिकृत किया गया है।
- साथ ही इस नीति के तहत राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE : National Institute of Wind Energy), चेन्नई को देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास और अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों के आवंटन के अतिरिक्त संबंधित मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय एवं संबद्ध कार्यों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है।
- इस स्वीकृति से देश में और उसके आस-पास तटीय आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील (देश का ईईजेड-एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन) की दूरी तक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और जल में अनुसंधान एवं विकास कार्यों सहित

अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं—
  - (i) देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा तथा इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु निवेश का संवर्धन करना;
  - (ii) अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना; तथा
  - (iii) इस क्षेत्र में कौशल क्षमता विकास एवं रोजगार सृजन के साथ कुशल मानव बल का सृजन करना।
- उल्लेखनीय है कि 7,600 किमी. लंबी भारतीय तटीय रेखा के साथ के समुद्री क्षेत्र में आरंभिक आकलनों से अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास की प्रचुर संभावनाओं के संकेत प्राप्त हुए हैं, जिसमें गुजरात तट से एक लाख मेगावाट तथा तमिलनाडु तट से 60 हजार मेगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के अनुमान शामिल हैं।
- वस्तुतः राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के माध्यम से सरकार अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास में उपतटीय (Onshore) पवन ऊर्जा विकास की सफलता को दोहराना चाहती है। इस नीति से सभी घरेलू और विदेशी निवेशकों एवं लाभार्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे तथा सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएंगी।
- इसके फलस्वरूप देश को ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने तथा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के लक्ष्यों को पाने की दिशा में अग्रसर होने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे देश के तटीय राज्यों यथा—गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ओडिशा आदि में नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।
- विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा को सर्वाधिक विकसित, लागत-प्रभावी एवं दक्षसिद्ध नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में से एक माना जाता है। भारत द्वारा अब तक उपतटीय पवन ऊर्जा विकास में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है तथा अब तक 23 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता संस्थापित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015

- 'राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (National Policy for Skill Development and Entrepreneurship), 2015' का औपचारिक अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जुलाई, 2015 को 'कौशल भारत' अभियान के शुभारंभ के साथ किया।
- इस नीति का विजन 'उच्च मानकों सहित बड़े पैमाने पर गतिमान रूप से कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण का पारितंत्र सृजित करना और उद्यमिता पर आधारित नवप्रवर्तन की संस्कृत को प्रोत्साहित करना है, जो देश में सभी नागरिकों की सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति और रोजगार का सृजन कर सके।'
- इसमें महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में उद्यमिता के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायरे के भीतर और बाहर संभावित उद्यमियों को शिक्षित और समर्थ बनाने की बात कही गई है।

प्रस्तावित नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2015

- 1 मई, 2015 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002 की राष्ट्रीय पर्यटन नीति के स्थान पर प्रस्तावित 'नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2015' का मसौदा जारी किया गया जिस पर विभिन्न हितधारकों एवं संबंधित पक्षों के सुझाव लेने के बाद अब शीघ्र ही अंतिम नीति मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वैश्विक पर्यटक आगमन में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.68 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 1 प्रतिशत और 2025 तक 2 प्रतिशत के स्तर पर लाने का लक्ष्य प्रस्तावित नीति में रखा गया है।
- प्रस्तावित नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2015 के महत्त्वपूर्ण तथ्य बिंदुवार इस प्रकार हैं—
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 पर पुनः ध्यान देते हुए ठोस 'कार्य योजना' के साथ सतत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से पर्यटन के विकास पर बल। पर्यटन विकास में सामुदायिक भागीदारी और रोजगार सृजन पर यह नीति मुख्य ध्यान केंद्रित करेगी।
- यह नीति भारत को 'अवश्य अनुभव करें' (Must Experience) और 'अवश्य पुनः आएं' (Must Re-visit) स्थान के रूप में विकसित एवं स्थापित करने के दृष्टिकोण को अपनाती है।
- इसमें एक 'राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड' (NTAB) के गठन का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा राज्यों/संघीय क्षेत्रों के पर्यटन मंत्री तथा पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे।
- नीति के समुचित क्रियान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकरण' (NTA) की स्थापना की जाएगी जिसमें अंतर्संबंधित विभागों/एजेंसियों तथा व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा।
- स्वच्छता, सुरक्षा (Safety) और स्वागत (Welcome) के पहलुओं को शामिल करते हुए यह नीति तैयार की गई है।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग के साथ मूलभूत अवसंरचना (हवाई, रेलवे, सड़कें, जलमार्ग आदि) के साथ-साथ पर्यटन अवसंरचना (स्वदेश दर्शन, 'प्रसाद' योजना, बौद्ध सर्किट आदि) के विकास पर बल दिया जाएगा।
- पर्यटन से संबंधित सभी क्षेत्रों में कौशल विकास के साथ पर्यटन और आतिथ्य शिक्षा के लिए समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

प्रथम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति

- 10 अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा भारत की पहली 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति' का शुभारंभ किया गया। ज्ञातव्य है कि देश में प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति का विशेष लक्ष्य देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक व्यापक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- गरीबों के लिए विशेष अनुकूल दृष्टिकोण से तैयार इस नीति के तहत देश के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु निधियां प्रदान करने के साथ-साथ देश के सभी अस्पतालों में मनोरोग स्वास्थ्य देखभाल एवं उपचार संबंधी विभाग खोलने के लिए संसाधन मुहैया कराए जाएंगे।

◆◆◆

अंतर्राष्ट्रीय मंथन

● चीन की 'एक बच्चा नीति' परिवर्तित ● शरणार्थियों को ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग की अनुमति ● संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य ● ब्रह्मपुत्र पर चीन के जांगमू बांध से विद्युत उत्पादन प्रारंभ ● वैश्विक निर्धनता पर विश्व बैंक के नवीनतम आकलन ● यूरोपीय शरणार्थी संकट ● सीरिया में रूस का हस्तक्षेप ● यूएन में पर्यवेक्षक देशों के झंडों संबंधी संकल्प पारित ● बुर्किना फासो में तख्तापलट असफल ● महिला सशक्तिकरण हेतु 'W-20' का प्रारंभ ● नेपाल : लागू हुआ नया संविधान ● श्रीलंका के गृहयुद्ध पर यूएनएचसीएचआर की रिपोर्ट ● विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं का नवीनतम पुनरीक्षण ● विश्व में सामाजिक सुरक्षा संजालों की स्थिति, 2015 ● नई स्वेज नहर का उद्घाटन ● विश्व के सर्वकालिक 10 सर्वाधिक धनी व्यक्ति ● ईरान और पी5+1 के बीच परमाणु समझौता ● ग्रीस का वित्तीय संकट ● यूएनएचआरसी में इजरायल के विरुद्ध प्रस्ताव ● अमेरिका में समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता ● रोहिंग्या शरणार्थी समस्या ● विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति, 2015 ● अमेरिका व क्यूबा के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति ● चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ● भारत यूएन के 4 निकायों में चयनित ● विश्व भर में मृत्युदंडों की स्थिति पर रिपोर्ट ● वैश्विक शस्त्र एवं रक्षा व्यापार की स्थिति ● नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन

चीन की 'एक बच्चा नीति' परिवर्तित

- 29 अक्टूबर, 2015 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक दंपत्ति एक बच्चा नीति में परिवर्तन करते हुए घोषणा की गई कि कोई दंपत्ति यदि चाहे तो वो दो बच्चे पैदा कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि चीन में विवादित 'एक बच्चा नीति' जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण हेतु वर्ष 1978 में प्रस्तुत की गई थी तथा इसे सितंबर, 1980 से लागू या क्रियान्वित किया गया था।
- हालांकि इस नीति के तहत कई क्षेत्रों को इससे छूट भी प्रदान की गई थी यथा, नृजातीय अल्पसंख्यकों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया था।
- वर्ष 2013 में जाकर इस नीति को शिथिल किया गया था जिसके तहत उन दंपत्तियों को दूसरा बच्चा उत्पन्न करने की छूट दी गई, जिन दंपत्तियों में माता-पिता में से एक अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे।
- चीन द्वारा अब दंपत्तियों को दो बच्चों की अनुमति दिए जाने का मुख्य कारण जनांकिकीय परिवर्तन हैं। ज्ञातव्य है कि चीन की 1.3 बिलियन की वृहद जनसंख्या अब तेजी से वृद्ध हो रही है जिससे वहां श्रम बल की उपलब्धता कम हो रही है।
- संयुक्त राष्ट्र के आकलनों के अनुसार वर्ष 2050 तक चीन में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के लगभग 440 मिलियन होने का अनुमान है। वर्ष 2014 में ही चीन की कार्यकारी जनसंख्या (15-59 वर्ष) में 3.71 मिलियन की कमी हुई है तथा इस प्रवृत्ति के जारी रहने का आकलन है।
- यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि चीन में एक बच्चा नीति के फलस्वरूप वहां काफी लैंगिक असंतुलन भी उत्पन्न हो गया है।

शरणार्थियों को ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग की अनुमति

- 28 अक्टूबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के अध्यक्ष थॉमस बाख (Thomas Bach) ने उच्च क्षमतावान शरणार्थी एथलीटों को ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग की अनुमति प्रदान किए जाने की घोषणा की।
- ज्ञातव्य है कि शरणार्थी एथलीटों को ओलंपिक खेलों में पहली बार प्रतिभाग की अनुमति दी गई है।
- आईओसी अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा रियो डि जेनेरियो में 15-21 अगस्त, 2016 के दौरान होने वाले ओलंपिक खेलों के 7 दिन पूर्व से 7-18 सितंबर, 2016 के दौरान होने वाले पैरालंपिक खेलों के 7 दिन बाद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक युद्धविराम (Olympic Truce) हेतु अंगीकृत प्रस्ताव (यूएन के 193 में से 180 सदस्य देशों द्वारा समर्थित) पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष की गई।
- इस घोषणा के फलस्वरूप अब शीर्ष स्तर के शरणार्थी खिलाड़ी (जिनका अब कोई गृह देश नहीं है) 2016 के ओलंपिक खेलों में ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक गान (Anthem) के साथ भाग ले सकेंगे।
- आईओसी अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में यूएन के सभी 193 सदस्य देशों से प्रतिभावान शरणार्थी एथलीटों की पहचान करने की भी अपील की गई।
- वर्तमान में विश्व में शरणार्थियों की संख्या लगभग 20 मिलियन है तथा यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर, 2015 के प्रारंभ में यूएन शरणार्थी निकाय के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस वर्ष 5 लाख से अधिक शरणार्थियों एवं आर्थिक प्रवासियों ने यूरोप में प्रवेश किया है तथा हजारों और ऐसे लोग आते जा रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शरणार्थियों में खेलों के माध्यम से आशा का सृजन करने हेतु 2 मिलियन डॉलर के एक कोष की भी स्थापना की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य

- 1 जनवरी, 2016 से मिस्र, सेनेगल, उरुग्वे, जापान और यूक्रेन वर्ष 2016-17 की अवधि (31 दिसंबर, 2017 तक) के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC; स्थापना-1946) के नए अस्थायी सदस्य बनेंगे।
- ये पांचों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के दौरान 15 अक्टूबर, 2015 को हुए चुनाव में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु निर्वाचित हुए हैं। ये सुरक्षा परिषद में चाड, चिली, लिथुआनिया, नाइजीरिया और जॉर्डन का स्थान लेंगे जिनका दो-वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त होगा।

- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य हैं—अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला। इनका सुरक्षा परिषद में कार्यकाल 31 दिसंबर, 2016 तक है।

ब्रह्मपुत्र पर चीन के जांगमू बांध से विद्युत उत्पादन प्रारंभ

- 13 अक्टूबर, 2015 को तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने अब तक के सबसे बड़े और विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जांगमू बांध (Zangmu Dam) के जल विद्युत केंद्र से चीन द्वारा विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया।
- ज्ञातव्य है कि भारत में इस बांध परियोजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल प्रवाह में कमी आने या अचानक पानी छोड़े जाने से बाढ़ आने का खतरा है। हालांकि चीन ने इस बांध को प्रारंभ करते हुए कहा है कि वह भारत की चिंताओं पर गौर करेगा तथा इस संबंध में उसके साथ संपर्क में रहेगा।
- तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की ग्यासा (Gyaca) काउंटी में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार जांगमू बांध और जल विद्युत केंद्र का निर्माण वर्ष 2009 में चीन द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा 2014 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 13 अक्टूबर, 2015 को इस जल विद्युत केंद्र की सभी 6 इकाइयों (समग्र क्षमता-510 MW) को पॉवर ग्रिड से जोड़ दिया गया।
- जांगमू बांध एक कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध (Gravity Dam) है जिसकी लंबाई 389 मी. (1276 फीट) और ऊंचाई 116 मी. (381 फीट) है। इस पर निर्मित जलविद्युत परियोजना की क्षमता 2.5 बिलियन किलोवाट प्रतिवर्ष आकलित की गई है।
- विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित यह बांध तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 140 किमी. और भारतीय सीमा से 550 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- जांगमू जल विद्युत परियोजना में बड़े पैमाने पर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो भारत के लिए चिंता का विषय है। यदि पानी बाधित किया गया तो ब्रह्मपुत्र पर भारतीय परियोजनाएं, विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग और लोअर सुहांसी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही किसी संघर्ष के समय चीन पानी छोड़ सकता है जिससे उत्तर-पूर्वी भारत में भारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- जांगमू के अतिरिक्त चीन द्वारा 2013 में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन अन्य जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इन परियोजनाओं के तहत डागू (Dagu), जिएक्सू (Jiexu) और जायचा (Jiacha) में बांध बनाए जा रहे हैं।
- इन सभी बांध परियोजनाओं को लेकर भारत द्वारा कई बार चीन सरकार से ऐतराज भी जताया गया है। तथापि चीन कहता रहा है कि ये 'रन ऑफ दि रिवर' परियोजनाएं हैं, जिनका डिजाइन पानी के भंडारण के लिए नहीं किया गया है।

चीन के बांध निर्माण से उत्पन्न खतरे

चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर बांध निर्माण से निम्न खतरे उत्पन्न होंगे—

1. इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा होगा। बांध बनाने की यह योजना सालवीन नदी के दर्रे के लिए भी खतरा पैदा करती है। यह दर्रा यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। उल्लेखनीय है कि बांध निर्माण के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण ही भारत, जापान आदि देशों में बांधों के निर्माण के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे हैं।
2. चीन द्वारा निर्मित बांधों से भूकंप का खतरा भी बढ़ गया है। 2008 में तिब्बती पठार के पूर्वी इलाके में भयंकर तबाही मचाने वाले भूकंप का मूल कारण बांध ही था। इस हादसे में 87,000 लोगों की जान चली गई थी। चीनी वैज्ञानिकों ने इसके लिए तब नवनिर्मित जिपिंगु बांध को जिम्मेदार ठहराया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विशालकाय बांध में भरे पानी के वजन के चलते ही भूकंप आया था।
3. पड़ोसी देशों पर प्रभाव : चीन द्वारा बांधों के निर्माण से इन नदियों के पड़ोसी देशों में जल प्रवाह में कमी आएगी। यद्यपि चीन इससे इंकार करता है और आश्वासन देता है कि पड़ोसी देशों में जल प्रवाह में कमी नहीं होगी परंतु चीन के द्वारा किसी भी देश से जल संधि करने से इंकार करने से उसकी मंशा स्पष्ट हो जाती है। दरअसल वह ऐसे किसी भी शर्त में नहीं बंधना चाहता जो नदियों के जल के संबंध में उस पर कोई अंकुश लगाए। उल्लेखनीय है कि यद्यपि भारत और पाकिस्तान के बीच भी नदियों पर बांध बनाने को लेकर विवाद रहा है और बगलिहार, तुलबुल, वुलर झील, झेलम पर बांध निर्माण या जल यातायात संबंधी भारत की परियोजनाओं पर पाकिस्तान आपत्ति जता चुका है, परंतु यह चीन की बांध निर्माण परियोजना से इस अर्थ में भिन्न है कि भारत इनका निर्माण करते समय पाकिस्तान के साथ हुई 1960 की सिंधु जल संधि का भी पालन कर रहा है। इसके विपरीत चीन नदियों के संबंध में अपने को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि में नहीं बांधना चाहता।
4. यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि चीन इन बांधों का उपयोग सामरिक उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है। यानी यदि भविष्य में पड़ोसी देशों के साथ विवाद हुआ तो वह इन बांधों के माध्यम से नदियों के जल को रोककर पड़ोसी देशों में सूखा और जल को छोड़कर बाढ़ ला सकता है। इस प्रकार ये बांध उसके लिए जल-बम (Water Bomb) का काम करेंगे।

भले ही चीन अपने पड़ोसी देशों को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा हो लेकिन उसका इतिहास बताता है कि पड़ोसी देशों की चिंताओं को चीन गंभीरता से नहीं लेता। चीन का नए बांध बनाने का फैसला एशिया में जल संसाधन की प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाएगा और पहले से धीमी पड़ी क्षेत्रीय सहयोग की गति को और धीमा करेगा। इसलिए भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम आदि देशों को भी चीन द्वारा किए जा रहे बांधों के निर्माण के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज करना चाहिए और उसके द्वारा किए जाने वाले कोरे वादों की बजाए एक स्पष्ट संधि पर हस्ताक्षर करने की बात चीन से करनी चाहिए।

ब्रह्मपुत्र नदी

चीन/तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम - यारलुंग सांग्पो

तीन देशों में प्रवाह - चीन, भारत, बांग्लादेश

लंबाई - 2900 किमी.

बेसिन - 6,51,334 वर्ग किमी.

उद्गम - तिब्बत में हिमालय के उत्तर में आंग्सी ग्लेशियर में यारलुंग-सांग्पो नदी के नाम से उद्गम होता है।

- दक्षिण तिब्बत में प्रवाहित होते हुए भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहां इसको दिहांग (सियांग) कहा जाता है।
- असम घाटी के दक्षिण-पश्चिम में यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है।
- बांग्लादेश के दक्षिण में जमुना नाम से प्रवाहित होकर पद्मा नदी से मिलती है जो बाद में मेघना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

वैश्विक निर्धनता पर विश्व बैंक के नवीनतम आकलन

- वैश्विक निर्धनता की स्थिति पर विश्व बैंक द्वारा अपने नवीनतम आकलन 4 अक्टूबर, 2015 को जारी किए गए।
- इन आकलनों के तहत वर्ष 2015 में पहली बार विश्व में अतिशय निर्धनता (Extreme Poverty) की स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या वैश्विक जनसंख्या के 10 प्रतिशत के नीचे (अर्थात एक अंकीय) आने का आकलन व्यक्त किया गया है।
- इससे स्पष्ट है कि लगभग एक चौथाई शताब्दी से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप निर्धनता में हो रही सतत कमी विश्व को 2030 तक निर्धनता उन्मूलन के ऐतिहासिक लक्ष्य के निकट ले जा रही है। हालांकि विश्व बैंक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति में अभी भी अनेक प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं।
- विश्व बैंक द्वारा अपने नवीनतम निर्धनता आकलन हेतु <u>1.90 डॉलर प्रतिदिन (2011 के मूल्यों पर) की अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा</u> (International Poverty Line) का प्रयोग किया गया है, जो कि क्रय शक्ति समतुल्यता (PPP : Purchasing Power Parity) आधार पर विभिन्न देशों में जीवनयापन लागत में भिन्नताओं पर नई सूचनाओं को शामिल करती है। इस नई अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा में विश्व के निर्धनतम देशों में पूर्ववर्ती रेखा (2005 के मूल्यों पर 1.25 डॉलर प्रतिदिन) की वास्तविक क्रय शक्ति को परिरक्षित किया गया है।
- नई अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा (और साथ ही जीवनयापन स्तरों पर नए राष्ट्र-स्तरीय आंकड़ों) का प्रयोग करते हुए विश्व बैंक के नवीनतम आकलन के अनुसार विश्व में अतिशय निर्धन व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2012 के 902 मिलियन से घटकर 2015 में 702 मिलियन अनुमानित है। वर्ष 1990 में यह संख्या 1,958 मिलियन और 1999 में 1,747 मिलियन थी।
- कुल वैश्विक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों का प्रतिशत वर्ष 2012 के 12.8 से घटकर <u>2015 में 9.6 प्रतिशत</u> रह जाने का अनुमान है। वर्ष 1990 में यह 37.1 प्रतिशत और 1999 में 29.0 प्रतिशत था।
- विगत कई दशकों में विश्व के तीन क्षेत्र- पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका वैश्विक निर्धनता के लगभग 95 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी रहे हैं। हालांकि, इन तीनों क्षेत्रों के बीच निर्धनता का संघटन नाटकीय रूप से स्थानांतरित हुआ है।
- 1990 में जहां पूर्वी एशिया क्षेत्र में विश्व के निर्धनों का लगभग आधा भाग निवासित था वहीं लगभग 15 प्रतिशत ही उप-सहारा अफ्रीका में था। 2015 के आकलनों के तहत यह स्थिति पूर्णतः विपरीत हो गई है तथा अब जहां पूर्वी एशिया क्षेत्र में वैश्विक निर्धनों का लगभग 12 प्रतिशत ही है, वहीं उप-सहारा अफ्रीका में विश्व के लगभग आधे निर्धन व्यक्ति हैं।
- विश्व बैंक के आकलन के अनुसार 2015 में उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सम्मिलित रूप से वैश्विक निर्धनों का लगभग दो-तिहाई भाग निवासित है।
- 2015 में <u>पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र</u> में निर्धनों की संख्या यहां की कुल जनसंख्या की 4.1 प्रतिशत है जो 2012 में 7.2 प्रतिशत थी।
- इसी अवधि में <u>लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र</u> में इसके 6.2 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।
- <u>उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र</u> में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत 2012 के 42.6 की तुलना में 2015 में 35.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- 2015 में <u>दक्षिण एशिया क्षेत्र</u> में निर्धनता का प्रतिशत 13.5 रहने का अनुमान है, जो 2012 में 18.8 प्रतिशत था।
- उल्लेखनीय है कि मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में संघर्षों और संकटपूर्ण स्थितियों के कारण यहां के विश्वसनीय वर्तमान निर्धनता आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।
- ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक द्वारा अप्रैल, 2013 में दो लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था- प्रथम, वर्ष 2030 तक अतिशय निर्धनता का उन्मूलन (जो कि सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्यों-SDGs में भी शामिल है) तथा द्वितीय, जनसंख्याओं के निचले 40 प्रतिशत की आय में वृद्धि के द्वारा साझा समृद्धि को प्रोत्साहित करना।

यूरोपीय शरणार्थी संकट

- एक तरफ जब इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी घोषित की जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस वर्तमान सदी के इन्हीं गुजरे पंद्रह वर्षों में सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर के पूर्वी तट तक लाखों लोग अपनी जमीन से बेदखल होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दर-बदर भटक रहे हैं और शरण की बाट जोह रहे हैं। यह एशिया का वह क्षेत्र है जिसे पश्चिम एशिया या मध्य एशिया कहते हैं, यहां लोगों का अपने देश से दूसरे देशों में पलायन इन पंद्रह वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। हालांकि एशिया महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों जैसे बांग्लादेश से लेकर म्यांमार (रोहिंग्या मुसलमान), लाओस, कंबोडिया आदि से भी विविध रूपों में लोग विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन पिछले पंद्रह सालों में दुनिया भर की सैन्य शक्तियों का रणस्थल वास्तव में उक्त वर्णित क्षेत्र रहा है जिसके एवज में पैदा हुई है- उस क्षेत्र में व्यापक अशांति, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कट्टरवाद, गृहयुद्ध की स्थिति तथा सबसे बढ़कर विस्थापितों और शरणार्थियों की समस्या।

- वर्तमान यूरोपीय संकट को यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह मात्र सीरिया की समस्या से उपजा नहीं है बल्कि इसकी जड़ें मध्य एशिया के अतीत से जुड़ी हुई हैं। यदि खाड़ी युद्ध के विस्तार में न जाएं तो भी, यदि 9/11 के बाद की स्थिति का विश्लेषण करें तो पाएंगे की इस क्षेत्र से लोगों का पलायन पिछले पंद्रह वर्षों में अनवरत चलता रहा है। पहले इराक में सद्दाम हुसैन के खात्मे के लिए चले अमेरिका एवं उसके सैन्य सहयोगियों के अभियान से लाखों नागरिक विस्थापित हुए तथा आस-पड़ोस के देशों में शरण लेने को मजबूर हुए, उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ दस साला अमेरिकी संघर्ष के चलते लाखों बेघर हुए। पिछले चार वर्षों में खासकर अरब वसंत की बयार आने के बाद पाकिस्तान से लेकर सीरिया होते हुए पूर्वी अफ्रीकी देशों तक गृहयुद्ध की जो स्थितियां बनी हुई हैं, उनसे शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या पैदा हुई है।
- यूरोपीय शरणार्थियों की समस्या वर्ष 2015 के अप्रैल माह में तब उजागर हुई जब लगभग दो हजार शरणार्थियों को लेकर यूरोप जा रही पांच नावें भूमध्य सागर में पलट गईं जिसमें लगभग 1200 लोगों की मृत्यु हो गई।
- 2 सितंबर, 2015 को तुर्की के बोड्रम नामक तटीय नगर के पास से एक तीन वर्षीय सीरियाई शिशु एलन कुर्दी के शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने से भूमध्य सागर में नावों पर सवार हजारों लोग जो यूरोप के विभिन्न देशों में शरण की बाट जोह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में आए।
- मौजूदा स्थिति यह है कि यूरोप में शरण को इच्छुक लोगों में सबसे अधिक संख्या सीरियाई नागरिकों (54%) की है, लेकिन इसमें अफगानिस्तान (15%), इरीट्रिया (6%) तथा नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, जाम्बिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं।
- वर्ष 2011 से यूरोप में शरण पाने को इच्छुक उक्त देशों के नागरिकों की सबसे अधिक संख्या वर्ष 2014 में रही, जब यूरोप में शरण के लिए कुल 6 लाख 26 हजार आवेदन प्राप्त किए गए। वर्ष 2015 के पूर्वार्द्ध में ही आश्रय के इच्छुक लोगों की संख्या 3 लाख 95 हजार तक पहुंच गई।
- यूरोप में शरणार्थियों की बड़ी संख्या के जाने का कारण यूरोप की शांतिपूर्ण एवं विकसित जीवन शैली है। यूरोप के तटीय देश जैसे इटली, ग्रीस और हंगरी शरणार्थियों के लिए यूरोप में प्रवेश के लिए दरवाजे की तरह हैं, लेकिन इन देशों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण शरणार्थियों की पहली पसंद जर्मनी है। जर्मनी, यूरोप का सबसे समृद्ध एवं ताकतवर देश है।
- एलन कुर्दी की तस्वीर जारी होने के बाद पूरी दुनिया में शरणार्थियों के प्रति संवेदना की एक लहर दौड़ पड़ी। 'डबलिन नियमन' एवं अन्य समझौतों को थोड़ी देर के लिए रोककर जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों के साथ-साथ पोप फ्रांसिस ने भी अपनी धरती पर शरणार्थियों का स्वागत किया।
- जर्मनी की एंजेला मर्केल के मानवीय कदम की दुनिया भर में सराहना हो रही है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जर्मनी के दक्षिणपंथी और नस्लवादी लोग शरणार्थियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, उनके हॉस्टलों एवं शिविरों को जलाया जा रहा है। वर्तमान जर्मनी लगभग आठ लाख शरणार्थियों के लिए आशियाना और आबोदाना का इंतजाम कर रहा है, यह चुनौतीपूर्ण है। इसी तरह जब वर्ष 1990-91 के मध्य जर्मनी में चार लाख 38 हजार शरणार्थी पहुंचे थे तब तत्कालीन सरकार और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी डीवीयू में ठन गई थी।
- जर्मन सरकार इस समय मात्र 2 लाख शरणर्थियों को वैध आश्रय देने की स्थिति में है, सितंबर, 2015 में जर्मन सरकार ने 2.5 लाख आवेदनों का निस्तारण किया।
- दूसरी तरफ यूरोप के अन्य देशों का रुख शरणार्थियों के लिए सख्त है। ब्रिटेन में डेविड कैमरन की सरकार ने बोर्ड लगा दिए हैं—'सॉरी आप नहीं आ सकते।' इसके अलावा हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य एवं पोलैंड ने नाकेबंदी कर रखी है। स्लोवाकिया ने कहा है कि वह सिर्फ ईसाई शरणार्थियों को बसाने पर विचार कर सकते हैं।
- लेकिन यह व्यापक शरणार्थी समस्या आर्थिक संकट से जूझ रहे यूराप के ही समाधान का विषय नहीं है। इस समस्या की जड़ में कहीं न कहीं अमेरिका भी है।
- अमेरिका आज खुद को दुनिया का नेतृत्वकर्ता बताता है तो अब जब यूरोप शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है तो अमेरिका को आगे आना चाहिए क्योंकि पहले इराक, फिर अफगानिस्तान, लीबिया और अब सीरिया में अमेरिका ने गृहयुद्ध की स्थिति बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है।
- इसलिए अमेरिका एवं अन्य पश्चिम देश खाड़ी देशों को महज अपनी ऊर्जा और सैन्य आवश्यकताओं के स्रोत के रूप में न देखें। उस क्षेत्र में सामान्य जनजीवन की स्थापना एवं धार्मिक साम्प्रदायिक कट्टरवाद से लड़ने के लिए युद्धक तरीकों के अलावा भी कुछ अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे किसी और एलन कुर्दी को समुंदर की रेत में दफन नहीं होना पड़ेगा।

सीरिया में रूस का हस्तक्षेप

- सीरिया वर्ष 2011 से ही गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। वहां असद सरकार एवं विद्रोहियों के बीच शुरू हुआ। संघर्ष आज व्यापक हो गया है। बशर अल असद की सेना को फ्री सीरियन आर्मी, आईएस और कुर्दों जैसे विद्रोही संगठनों से लड़ना पड़ रहा है।
- इस गृहयुद्ध के कारण सीरिया की 60 प्रतिशत जनसंख्या विस्थापन का शिकार हो चुकी है। यही विस्थापित लोग यूरोप की शरणार्थी समस्या के मुख्य कारण बने हैं। फिलहाल सीरिया में जारी गृहयुद्ध थमता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक तरफ असद सरकार को ईरान, ईराक, लेबनान जैसे देशों से समर्थन मिल रहा है तो दूसरी तरफ विद्रोहियों को अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सउदी अरब एवं कुवैत का समर्थन मिल रहा है।
- इसी बीच रूस ने सीरिया के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए इस्लामिक स्टेट एवं विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू किए।
- सितंबर, 2015 के अंत में शुरू किए गए रूसी हवाई हमले का बशर अल असद ने स्वागत किया जबकि अमेरिका एवं यूरोप के देशों ने इसका विरोध किया।
- रूस ने सीरिया में आईएस पर हवाई हमले का निर्णय संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई ओबामा-पुतिन की द्विपक्षीय बैठक के बाद लिया।

- रूस के हवाई हमलों के लिए सीरिया के लटाकिया में एयरबेस बनाया गया है।
- ब्रिटेन स्थित निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने 23 अक्टूबर, 2015 को कहा कि सीरिया में रूसी हवाई हमलों में कम से कम 446 लोग मारे गए जिसमें से एक-तिहाई से ज्यादा असैन्य नागरिक हैं। संस्था के अनुसार मारे गए 151 असैन्य नागरिकों में 38 बच्चे और 35 महिलाएं भी शामिल हैं। हमलों में 295 लड़ाके भी मारे गए जिनमें से 75 आईएस के जिहादी और 31 अल कायदा की सीरियाई शाखा के सदस्य थे।
- सीरिया में कई प्रतिष्ठानों का संचालन करने वाली सीरियन-अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी के अनुसार रूस देश के अस्पतालों पर 9 हवाई हमले कर चुका है।
- इसी बीच 20 अक्टूबर, 2015 को रूस और अमेरिका ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार दोनों देशों के लड़ाकू विमान सीरिया के अलग-अलग क्षेत्रों में उड़ान भरेंगे जिससे दोनों के बीच किसी टकराव से बचा जा सके।

यूएन में पर्यवेक्षक देशों के झंडों संबंधी संकल्प पारित

- 10 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्यों के झंडों को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय एवं इमारतों के सामने फहराने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव सितंबर, 2015 में अरब समूह के अध्यक्ष के रूप में इराक ने प्रस्तुत किया था।
- इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से भारत समेत 119 देशों ने इसके पक्ष में मत दिया जबकि अमेरिका एवं इजरायल सहित आठ देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। ब्रिटेन समेत 45 देशों ने इस मतदान में भाग नहीं लिया।
- इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश फिलिस्तीन और वेटिकन भी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपने झंडे लगा सकेंगे।
- 30 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पहली बार फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दो गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्यों क्रमशः वेटिकन को वर्ष 1964 में तथा फिलिस्तीन की वर्ष 2012 में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इन दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होने की संभावना बढ़ गई है।

बुर्किना फासो में तख्तापलट असफल

- पश्चिमी अफ्रीका स्थित स्थलरूद्ध देश बुर्किना फासो में राष्ट्रपति सुरक्षा रेजीमेंट (RSP : Regiment of Presidential Security) द्वारा 16 सितंबर, 2015 को तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति मिशेल काफांदो (Michel Kafando) को पद से हटाकर सत्ता पर अधिकार कर लिया गया।
- आरएसपी (जो कि पूर्व राष्ट्रपति ब्लेज काम्पोर द्वारा गठित एक विवादित स्वायत्त सैन्य यूनिट है) द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
- बुर्किना फासो में वर्ष 1987 में तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में आए राष्ट्रपति ब्लेज काम्पोर के अधिनायक शासन के विरुद्ध अक्टूबर, 2014 में वहां विशाल विरोध प्रदर्शन एवं दंगे (2014 Burkinabe Uprising) प्रारंभ हुए थे जिसका उद्देश्य 27 वर्षों से सत्ता पर काबिज ब्लेज काम्पोर के संविधान में परिवर्तन के प्रयासों (ताकि वे पुनः चुनाव लड़ सकें) को रोकना था।
- नवंबर, 2014 के प्रारंभ में राष्ट्रपति ब्लेज काम्पोर को अपदस्थ कर एक वर्ष के लिए संक्रमणकालीन सरकार का गठन किया गया था तथा 11 अक्टूबर, 2015 को वहां नई सरकार हेतु चुनाव की तिथि निश्चित की गई थी। 18 नवंबर, 2014 को मिशेल काफांदो ने संक्रमणकालीन सरकार के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था।
- अपदस्थ राष्ट्रपति ब्लेज काम्पोर के नेतृत्व वाली आरएसपी द्वारा ही सद्यः तख्तापलट किया गया तथापि अफ्रीकी संघ, इकोवास (ECOWAS) और बुर्किना फासो की सशस्त्र सेनाओं के दबाव में 23 सितंबर, 2015 को आरएसपी की सैन्य जुंटा (Junta) को तख्तापलट से पीछे हटना पड़ा और मिशेल काफांदो ने वहां पुनः कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है।
- अब बुर्किना फासो में नई सरकार हेतु आम चुनाव 29 नवंबर, 2015 को कराए जाने की घोषणा की गई है।

महिला सशक्तिकरण हेतु 'W-20' का प्रारंभ

- विश्व की 20 प्रमुख विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह 'जी-20' (G-20 : Group of Twenty) द्वारा 6 सितंबर, 2015 को महिला सशक्तिकरण हेतु वैश्विक मंच 'डब्ल्यू-20' (W-20) का शुभारंभ तुर्की की राजधानी अंकारा में किया गया।
- महिलाओं के इस वैश्विक मंच का उद्देश्य व्यवसाय क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में विस्तार के साथ लैंगिक समावेशी (Gender Inclusive) वैश्विक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण को संवर्द्धित करना है।
- उल्लेखनीय है कि जी-20 के शिखर सम्मेलनों के तहत 2012 में लॉस काबोस घोषणापत्र में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी की पूर्ण उपलब्धता, 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र में महिलाओं के वित्तीय समावेशन और शिक्षा को उन्नयित करने तथा 2014 में ब्रिसबेन घोषणापत्र में राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 तक महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य कार्य भागीदारी अंतराल (Work Participation Gap) को 25 प्रतिशत तक कम करने हेतु प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई थीं। डब्ल्यू-20 के अधिदेश (Mandate) में उपर्युक्त सभी प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति हेतु कार्य करने की बात कही गई है।
- हालांकि महिलाओं के इस मंच डब्ल्यू-20 का गठन अप्रैल, 2015 में ही हुआ था तथापि अंकारा में हुई जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की सद्यः बैठक (सितंबर, 2015) के दौरान इसका औपचारिक प्रारंभ किया गया है।
- डब्ल्यू-20 की प्रथम अध्यक्षा तुर्की की गुलदेन तुर्कतान (Gulden Turktan) बनी हैं तथा इस समूह में जी-20 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा नामित महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी।

- डब्ल्यू-20 के उद्घाटन आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशिका क्रिस्टीन लैगार्डे, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के महासचिव जोस एंजेल गुरिया; यूएन वीमेन की डिप्टी एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर लक्ष्मी पुरी आदि द्वारा संबोधित किया गया।
- ज्ञातव्य है कि जी-20 की सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में भारत के साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। वर्तमान में तुर्की इस समूह का अध्यक्ष है।

'डब्ल्यू-20' का प्रथम सम्मेलन

16-17 अक्टूबर, 2015 के दौरान इस्ताम्बुल (तुर्की) में नवगठित वैश्विक महिला मंच 'डब्ल्यू-20' का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जी-20 की सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की 36 प्रतिनिधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एवं यूएन वीमेन ने भागीदारी की। विएतनाम, कंबोडिया, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और युगांडा की प्रतिनिधियों ने इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाई गई डब्ल्यू-20 विज्ञप्ति में जी-20 नेताओं से शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता में संपर्कों को सुदृढ़ करने, कार्य और जीवन संतुलन के समर्थन, नेतृत्व पदों पर महिलाओं की संख्या में वृद्धि, वित्त तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, कार्यस्थल पर विभेदीकरण के उन्मूलन तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आदि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को संवर्द्धित करने का आह्वान किया गया। यह विज्ञप्ति आगामी 15-16 नवंबर, 2015 को अंताल्या (तुर्की) में होने वाले जी-20 के दसवें शिखर सम्मेलन में जी-20 नेताओं को अग्रसारित की जाएगी।

नेपाल : लागू हुआ नया संविधान

- 20 सितंबर, 2015 को नेपाल के तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरन यादव द्वारा वहां की संविधान सभा में अंगीकृत नए संविधान पर हस्ताक्षर के बाद नेपाल में नया संविधान लागू कर दिया गया है।
- इससे पूर्व नेपाल की 597 सदस्यीय संविधान सभा में उपस्थित एवं मत देने वाले 532 सदस्यों में से 507 ने नए संविधान के पक्ष में (जिसमें नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल, यूपीसीएन-एम आदि के सांसद थे) और 25 ने इसके विपक्ष में (जिसमें राजशाही एवं हिंदू समर्थक सांसद थे) मत दिया। मधेसी दलों और कई छोटे दलों द्वारा इस संविधान का विरोध करते हुए मतदान का बहिष्कार किया गया।
- इस प्रकार नेपाल का यह नया संविधान सर्वसम्मत संविधान नहीं बल्कि बहुमत से पारित संविधान है।
- यह संविधान 1950 के बाद से नेपाल का छठां तथा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार प्रथम संविधान है।
- उल्लेखनीय है कि नेपाल में 239 वर्ष से चली आ रही राजशाही की समाप्ति और माओवादियों का हिंसक विद्रोह खत्म होने के बाद मई, 2008 में वहां पहली संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। राजनीतिक दलों के परस्पर मतभेदों और विवादों के कारण यह संविधान सभा मई, 2012 में भंग कर दी गई थी तथा वहां दूसरी संविधान सभा नवंबर 2013 में निर्वाचित हुई थी जिसने 22 जनवरी, 2015 तक संविधान तैयार करने का कार्य पूरा करने का संकल्प लिया था परंतु विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेदों के कारण तय समयसीमा में संविधान को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।
- अंततः 8 जून, 2015 को नेपाल के 4 प्रमुख राजनीतिक दलों–नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–यूएमएल, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–माओवादी तथा मधेसी पीपुल्स राइट फोरम-डेमोक्रेटिक के मध्य ऐतिहासिक 16-सूत्रीय समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप वहां विगत कई वर्षों से संविधान का मसौदा तैयार करने पर जारी गतिरोध समाप्त हुआ था।
- नेपाल के नए संविधान के महत्त्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं—
  - (i) इस संविधान में 35 भागों के तहत 308 अनुच्छेद और साथ ही 9 अनुसूचियां शामिल हैं।
  - (ii) नए संविधान में नेपाल को अब हिंदू राष्ट्र के स्थान पर पंथनिरपेक्ष गणराज्य (Secular Republic) घोषित किया गया है।
  - (iii) नेपाल के इस संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली के साथ मिश्रित एवं संयुक्त निर्वाचन मॉडल अपनाया गया है।
  - (iv) नेपाल की संसद में दो सदन होंगे। निचले सदन में 275 सदस्य होंगे जबकि ऊपरी सदन 59 सदस्यीय होगा।
  - (v) इस संविधान के तहत संघीय प्रणाली को अपनाते हुए नेपाल में 7 राज्यों के संघ का प्रावधान किया गया है तथा संघीय संसद के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की अपनी विधायिका होगी।
  - (vi) नेपाल में राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्र का प्रमुख) राष्ट्रपति होगा जिसका चुनाव संसद और राज्यों की विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
  - (vii) नेपाल में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होगी जो कि संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होगी।
  - (viii) देश के सभी वर्गों (महिलाओं, पिछड़ों, जनजातियों, मुस्लिमों एवं दक्षिणी तराई क्षेत्रों सहित) को समुचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु आनुपातिक (Proportional) निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है।
  - (ix) इस संविधान में समलैंगिकों एवं ट्रांसजेंडरों को भी समान अधिकार दिए गए हैं तथा ऐसे प्रावधान वाला यह एशिया के किसी देश का पहला संविधान है।
  - (x) इस संविधान के तहत नेपाल की विभिन्न जातीय भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की गई है।
  - (xi) संविधान में विक्रम संवत को अपनाया गया है और तदनुसार यह संविधान 2072 वि.सं. में अधिनियमित हुआ है।
  - (xii) संविधान के तहत गाय को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिया गया है।
  - (xiii) संविधान में संघीय सरकार और राज्य सरकार तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा संवैधानिक न्यायालय द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(xiv) प्रांतों के सीमांकन का कार्य एक संघीय आयोग द्वारा किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संसद प्रांतों के सीमांकन पर दो-तिहाई बहुमत से निर्णय लेगी।

(xv) नेपाल के संविधान में नेपाली पुरुषों द्वारा विदेशी महिला से विवाह करने पर उनके बच्चे को नेपाली नागरिकता प्राप्त होने का प्रावधान है जबकि नेपाली महिला के विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उनके बच्चे को नेपाली नागरिकता नहीं प्राप्त होगी।

- नेपाल के मधेशी एवं थारू समुदायों (जो मुख्यतः तराई क्षेत्रों, जो कि भारत से संलग्न हैं, में निवासित हैं) द्वारा इस संविधान का उग्र विरोध किया जा रहा है, जो कि अपने पृथक राज्य की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इनके आंदोलन के कारण वर्तमान में भारत-नेपाल सीमा पर आवागमन बाधित है जिससे नेपाल में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत उत्पन्न हो गई है। 29 अक्टूबर, 2015 को नेपाल द्वारा चीन के साथ तेल आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है।
- 12 अक्टूबर, 2015 को सीपीएन-यूएमएल के नेता खड्ग प्रसाद (के.पी.) शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने इस पद हेतु पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को संसद (नेपाल की संविधान सभा ने ही अब वहां अंतरिम संसद का रूप लिया है) के 597 में से 338 सदस्यों के मत प्राप्त कर पराजित किया।
- 16 अक्टूबर, 2015 को यूसीपीएन-माओवादी की ओनसारी घरती मागर नेपाली संसद की नई अध्यक्ष चुनी गईं जो कि वहां संसद अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं।
- 28 अक्टूबर, 2015 को सीपीएन-यूएमएल की बिद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं तथा 31 अक्टूबर, 2015 को यूसीपीएन-माओवादी के नंद किशोर पुन वहां के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।

श्रीलंका के गृहयुद्ध पर यूएनएचसीएचआर की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र के घटक 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग' (UNHCHR : United Nations High Commission for Human Rights) द्वारा 16 सितंबर, 2015 को श्रीलंका में हुए गृहयुद्ध पर केंद्रित जांच रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जारी की गई। ध्यातव्य है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंहलियों एवं अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य वर्ष 1993 में गृहयुद्ध शुरू हुआ था, जो कि वर्ष 2009 में समाप्त हुआ। अल्पसंख्यक तमिल अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे।
- युद्धकाल पर केंद्रित 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग' की इस जांच रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध अपराध किए गए। रिपोर्ट में मुख्य रूप से श्रीलंका की सुरक्षा एजेंसियों एवं 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' (लिट्टे) को दोषी ठहराया गया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार गृहयुद्ध के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से गैरकानूनी हत्याएं (Unlawful killings), यौन एवं लिंग आधारित हिंसा (Sexual and Gender Based Violence), इच्छा के विरुद्ध बच्चों एवं वयस्कों को हथियारों को ले जाने के लिए बाध्य करना तथा युद्ध से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता से वंचित करने जैसे अपराध किए गए।
- इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान हुए अपराधों की जांच हेतु युद्ध अपराध न्यायालय की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि श्रीलंका सरकार पर संयुक्त राष्ट्र का विश्वास नहीं है।
- इस रिपोर्ट को राष्ट्र के एकीकरण के विरुद्ध बताते हुए श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे द्वारा इसका विरोध किया गया है। ध्यातव्य है कि इस रिपोर्ट में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल में तमिलों पर हुए अमानवीय कृत्यों को उजागर करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि तमिल अलगाववादियों के नाम पर सेना द्वारा सात लाख निर्दोषों को निशाना बनाया गया।

विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं का नवीनतम पुनरीक्षण

- संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के पापुलेशन डिवीजन द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर विश्व जनसंख्या की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ पूर्व एवं भावी प्रवृत्तियों संबंधी पुनरीक्षित आंकड़े 'विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं' (World Population Prospects) के तहत जारी किए जाते हैं।
- 29 जुलाई, 2015 को जारी विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं का 2015 का पुनरीक्षण (The 2015 Revision) इसका नवीनतम 24वां संस्करण है।
- विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं के नवीनतम पुनरीक्षण के अनुसार 2015-मध्य में विश्व की जनसंख्या 7.3 बिलियन (730 करोड़) के स्तर पर पहुंच गई है तथा इसमें विगत 12 वर्षों में ही लगभग 1 बिलियन की वृद्धि हुई है।
- मध्यम प्रजनकता आधार (Medium Fertility Variant) के आधार पर विश्व जनसंख्या के 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन तथा वर्ष 2100 तक 11.2 बिलियन के स्तर पर पहुंचने का आकलन व्यक्त किया गया है।
- वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर वर्तमान में 1.18 प्रतिशत वार्षिक है जो कि एक दशक पूर्व 1.24 प्रतिशत वार्षिक के स्तर पर थी।
- 2015 में विश्व जनसंख्या का 60 प्रतिशत एशिया में (4.4 बिलियन), 16 प्रतिशत अफ्रीका में (1.2 बिलियन), 10 प्रतिशत यूरोप में (738 मिलियन), 9 प्रतिशत लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में (634 मिलियन) तथा शेष 5 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका (358 मिलियन) एवं ओशिनिया (39 मिलियन) में निवासित है।

विश्व जनसंख्या (मिलियन में) का क्षेत्रवार वितरण

प्रमुख क्षेत्र	जनसंख्या 2015	जनसंख्या 2050	जनसंख्या 2100
अफ्रीका	1186	2478	4387
एशिया	4393	5267	4889
यूरोप	738	707	646
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन	634	784	721
उत्तरी अमेरिका	358	433	500
ओशिनिया	39	57	71
विश्व	7349	9725	11213

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश								
2015			2050			2100		
क्रम	देश	जनसंख्या (मिलि.)	क्रम	देश	जनसंख्या (मिलि.)	क्रम	देश	जनसंख्या (मिलि.)
1.	चीन	1376	1.	भारत	1705	1.	भारत	1660
2.	भारत	1311	2.	चीन	1348	2.	चीन	1004
3.	यूएसए	322	3.	नाइजीरिया	399	3.	नाइजीरिया	752
4.	इंडोनेशिया	258	4.	यूएसए	389	4.	यूएसए	450
5.	ब्राजील	208	5.	इंडोनेशिया	321	5.	डीआरकांगो	389
6.	पाकिस्तान	189	6.	पाकिस्तान	310	6.	पाकिस्तान	364
7.	नाइजीरिया	182	7.	ब्राजील	238	7.	इंडोनेशिया	314
8.	बांग्लादेश	161	8.	बांग्लादेश	202	8.	तंजानिया	299
9.	रूस	143	9.	डीआरकांगो	195	9.	इथियोपिया	243
10.	मेक्सिको	127	10.	इथियोपिया	188	10.	नाइजर	209

- 2015 में जनसंख्या की दृष्टि से चीन (1.4 बिलियन) और भारत (1.3 बिलियन) विश्व के दो सबसे बड़े देश हैं जहां कुल वैश्विक जनसंख्या के क्रमशः 19 एवं 18 प्रतिशत व्यक्ति रहते हैं। इनके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (0.32 बिलियन) का स्थान है।
- विश्व जनसंख्या संभाव्यताएं के नवीनतम पुनरीक्षण के अनुसार भारत वर्ष 2022 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।
- साथ ही इसमें 2050 तक नाइजीरिया (वर्तमान में 7वां स्थान) के जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर पहुंचने का आकलन व्यक्त किया गया है।
- 2015 में विश्व की कुल जनसंख्या में 50.4 प्रतिशत पुरुष तथा 49.6 प्रतिशत महिलाएं हैं। विश्व जनसंख्या की माध्यिका (Median) आयु 29.6 वर्ष है। विश्व जनसंख्या में 26 प्रतिशत व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु के हैं जबकि 62 प्रतिशत व्यक्ति 15-59 वर्ष आयु के और 12 प्रतिशत व्यक्ति 60 वर्ष या अधिक आयु के हैं।

विश्व में सामाजिक सुरक्षा संजालों की स्थिति, 2015

- 7 जुलाई, 2015 को विश्व बैंक द्वारा 'दि स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स (सामाजिक सुरक्षा संजालों की स्थिति), 2015' नामक रिपोर्ट जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के पांच सर्वाधिक वृहद सामाजिक सुरक्षा संजाल कार्यक्रमों में से सभी मध्यम-आय देशों (चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया) में चलाए जा रहे हैं और इनकी पहुंच 526 मिलियन (52.6 करोड़) व्यक्तियों तक है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MNREGA) विश्व का सर्वाधिक वृहद सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम है जो कि 182 मिलियन (18.2 करोड़) लाभार्थियों के साथ देश की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा संजाल उपलब्ध करा रहा है।
- भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 'जननी सुरक्षा योजना' (JSY) 78 मिलियन (7.8 करोड़) लाभार्थियों के साथ विश्व का सशर्त नकद हस्तांतरण (कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स) वाला सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है।
- भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 'मध्याह्न भोजन योजना' (Mid-day Meal Scheme) को विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम माना गया है जो लगभग 105 मिलियन (10.5 करोड़) लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' (IGNOAPS) को बिना शर्त नकद हस्तांतरण वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम माना गया है।
- विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2014 के मध्य विश्व के 120 विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा संजालों पर समग्र व्यय लगभग 329 बिलियन डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रु.) रहा है।
- तथापि अभी भी अल्प और अल्प-मध्यम आय देशों में निर्धनतम लोगों का तीन-चौथाई तथा मध्यम-आय देशों में निर्धनतम लोगों का एक-तिहाई से अधिक सुरक्षा संजाल कवरेज से बाहर है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के देशों द्वारा सामाजिक सुरक्षा संजाल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है तथा विभिन्न देशों में सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्यीकरण, प्रशासन, एकीकरण और मूल्यांकन का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

नई स्वेज नहर का उद्घाटन

- 6 अगस्त, 2015 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी द्वारा स्वेज नहर के विस्तार हेतु निर्मित 'नई स्वेज नहर' (New Suez Canal) का औपचारिक उद्घाटन इस्लामिया शहर में किया गया।
- इस अवसर पर आयोजित समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस ओलांडे, रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव तथा अनेक राष्ट्रों के प्रमुख/प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया।

- उल्लेखनीय है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ था तथा इस नहर के बनने से यूरोप से एशिया के मध्य सीधा जलमार्ग प्राप्त हुआ था (अन्यथा पहले जलपोतों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था)।
- मूल स्वेज नहर की लंबाई 164 किमी. (102 मील) है तथा स्वेज नहर के वर्तमान विस्तार (जिसे नई स्वेज नहर कहा गया है) के तहत मूल नहर के समानांतर 35 किमी. (22 मील) लंबी एक द्वितीय शिपिंग लेन निर्मित की गई है जिससे विपरीत दिशाओं में (दोतरफा) जलपोतों का आवागमन संभव हो गया है। इससे स्वेज नहर में जलपोतों की प्रतीक्षा अवधि के 11 घंटे से कम होकर मात्र 3 घंटे रह जाने का आकलन है।
- स्वेज नहर के इस विस्तार के तहत मूल नहर के 37 किमी. भाग को अधिक गहरा और चौड़ा भी किया गया है।
- स्वेज नहर के विस्तार हेतु परियोजना 5 अगस्त, 2014 को प्रारंभ हुई थी तथा एक वर्ष से कम समय में ही 16 जुलाई, 2015 को इसे पूरा कर लिए जाने की घोषणा की गई थी।
- लगभग 8.4 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से मिस्र को स्वेज नहर से प्राप्त होने वाली आय के 5 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष से बढ़कर आगामी वर्षों में 12.5 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुंचने का अनुमान है।
- उल्लेखनीय है कि स्वेज नहर का स्वामित्व एवं नौवहन प्राधिकार स्वेज नहर अथॉरिटी (1956 में मिस्र सरकार द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद गठित) के पास है तथा स्वेज नहर के इस विस्तार का निर्माण मिस्त्र के सशस्त्र बल की इंजीनियर शाखा द्वारा अरब कांट्रैक्टर्स, ओरस्कॉम कंस्ट्रक्शंस तथा 84 अन्य कंपनियों द्वारा मिलकर किया गया है।

विश्व के सर्वकालिक 10 सर्वाधिक धनी व्यक्ति

- जुलाई-अंत, 2015 में टाइम (TIME) मैगजीन द्वारा इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों एवं शिक्षाविदों से वार्ताओं के आधार पर विश्व के सर्वकालिक 10 सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की सूची जारी की गई है।
- इस सूची के अनुसार टिम्बकटू (वर्तमान माली, पश्चिम अफ्रीका) के सम्राट मनसा मूसा (1280-1337 ई.) अब तक के सबसे धनी व्यक्ति थे जो अपने साम्राज्य में विशाल स्वर्ण उत्पादन के चलते अपार संपदा के स्वामी थे।
- रोमन साम्राज्य के शासक आगस्टस सीजर (63 ई.पू.–14 ई.) को इस सूची में दूसरा तथा चीन के शांग वंश के शासक शेन जांग (1048–1085 ई.) को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- भारत के महान मुगल सम्राट अकबर (1542–1605 ई.) को विश्व के सर्वकालिक धनिकों में चौथा स्थान प्रदान किया गया है। अकबर का साम्राज्य तत्कालीन वैश्विक उत्पादन के एक-चौथाई के लिए उत्तरदायी था।
- तत्कालीन सोवियत संघ के तानाशाह शासक जोसेफ स्टालिन (1878–1953 ई.) इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं।
- इस सूची के अनुसार अमेरिका के सर्वकालिक सर्वाधिक धनी व्यक्ति उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी (1835–1919 ई.) हैं जिन्हें संपूर्ण विश्व के संदर्भ में छठां स्थान प्राप्त हुआ है।
- विश्व के सर्वकालिक सर्वाधिक धनिकों में अमेरिका के जॉन डी. रॉकफेलर (तेल उद्यमी; 1839–1927 ई.) को सातवां तथा इंग्लैंड के एलन रुफुस (सम्राट विलियम के भतीजे; 1040–1093 ई.) को आठवां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि नौवें स्थान पर अमेरिका के बिल गेट्स (माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक; जन्म–1955 ई.) हैं जो कि इस सूची में शामिल एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं।
- इस सूची में 10वें स्थान पर मंगोल सम्राट चंगेज खान (1162–1227 ई.) को रखा गया है जिन्हें 'टाइम' पत्रिका ने विश्व के सबसे विस्तृत भूक्षेत्र का शासक माना है।

ईरान और पी5+1 के बीच परमाणु समझौता

- 14 जुलाई, 2015 को ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने तथा उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने एवं उस पर लगे प्रतिबंधों में छूट देने के उद्देश्य से दुनिया के प्रमुख देशों (P5+1 : अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी) और ईरान के मध्य ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था।
- 'संयुक्त व्यापक कार्य योजना' (Joint Comprehensive Plan of Action) नामक यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक व्यापक समझौता है।
- 13 अक्टूबर, 2015 को ईरान की संसद द्वारा इस परमाणु समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के अनुसार समझौते के बाद ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयासों की जांच पर 15 दिसंबर, 2015 तक एक रिपोर्ट जारी की जाएगी।

विएना समझौता : प्रमुख प्रावधान

(a) समझौते के अनुसार ईरान अपने अल्प संवर्धित यूरेनियम भंडार का 98 प्रतिशत हिस्सा नष्ट करेगा। वर्तमान में उपस्थित 10 हजार किलोग्राम यूरेनियम को 300 किलोग्राम की मात्रा तक उसे लाना होगा। ईरान अगले 15 वर्षों तक यूरेनियम का 3.67% ही संवर्धन कर सकेगा जो कि नागरिक परमाणु ऊर्जा एवं अनुसंधान हेतु पर्याप्त है।

(b) ईरान को अपने मौजूदा नाभिकीय सेंट्रीफ्यूज (यूरेनियम संवर्धन हेतु प्रयुक्त होने वाले) में से दो-तिहाई सेंट्रीफ्यूज को भी हटाना होगा।

(c) ईरान अगले 15 वर्षों तक कोई नई यूरेनियम-संवर्धन इकाई भी स्थापित नहीं करेगा। साथ ही उसे अपनी फोर्डो इकाई में भी यूरेनियम-संवर्धन रोकना होगा।

(d) समझौते के अनुसार ईरान पर हथियार खरीदने के लिए लगाया गया प्रतिबंध पांच वर्षों के लिए जारी रहेगा जबकि मिसाइल खरीद पर प्रतिबंध आठ वर्ष तक बना रहेगा।

(e) ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को अपने परमाणु संयंत्रों एवं गतिविधियों की निगरानी की अनुमति देगा।

(f) अमेरिका एवं यूरोपीय संघ ईरान के ऊपर से मानवाधिकार हनन और आतंकवाद का समर्थन करने संबंधी लगे प्रतिबंधों को छोड़कर अन्य प्रतिबंध हटा लेंगे।

(g) ईरान अपने परमाणु संबंधी शोध एवं विकास कार्य को जारी रख सकेगा लेकिन यह कार्य उसे सीमित रखना होगा।

- इस समझौते के बाद ईरान के तेल निर्यात एवं अर्थव्यवस्था (तेल-गैस, जहाजरानी, वित्तीय लेन-देन, बैंक एवं एयरलाइंस आदि) पर लगे प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से हटा लिया जाएगा। साथ ही उसकी विदेशों में सील संपत्ति एवं धन को भी जारी किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले 24 नवंबर, 2013 को जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में ईरान एवं पी5 प्लस वन देशों के मध्य अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 2006 में पहली बार ईरान और पी5 प्लस वन देशों के बीच यह वार्ता शुरू हुई थी।

ग्रीस का वित्तीय संकट

- 5 जुलाई, 2015 को ग्रीस (यूनान) में वहां के संप्रभु-ऋण संकट (Government-Debt Crisis) से निपटने हेतु दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता पैकेज (Bailout Package) से जुड़ी शर्तों को स्वीकार करने या न करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय जनमतसंग्रह (Referendum) कराया गया।
- यह आर्थिक सहायता या बेलआउट पैकेज यूरोपीय आयोग (EC), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा संयुक्त रूप से 25 जून, 2015 को प्रस्तावित किया गया था परंतु इसके साथ ग्रीस में मितव्ययिता और सरकारी खर्चों में कटौती तथा करों में वृद्धि करने संबंधी कठोर शर्तें जुड़ी थीं।
- यह ग्रीस में 1974 के गणराज्य जनमतसंग्रह के बाद पहला जनमतसंग्रह था तथा आधुनिक ग्रीक इतिहास में ऐसा पहला जनमतसंग्रह भी था जो सरकार के स्वरूप से संबंधित नहीं था।
- प्रधानमंत्री एलेक्सिस त्सिप्रास ने ग्रीस की जनता से इस बेलआउट पैकेज से जुड़ी शर्तों को नकारने के लिए अपील की थी और कहा था कि यदि ग्रीस की जनता इन प्रस्तावों को स्वीकृति देती है तो उस स्थिति में वे इस्तीफा दे देंगे और कटौती प्रस्तावों को लागू नहीं करेंगे।
- 5 जुलाई, 2015 को संपन्न इस जनमतसंग्रह में ग्रीस की जनता द्वारा भारी बहुमत से आर्थिक सहायता पैकेज से जुड़े प्रस्तावों को नकार दिया गया।
- वस्तुतः ग्रीस का यह सरकारी या संप्रभु-ऋण संकट (जब सरकार अपनी गारंटी पर लिए गए विदेशी ऋणों को चुकाने में अक्षम प्रतीत हो तब यह स्थिति उत्पन्न होती है) वर्ष 2009 के अंतिम भाग से प्रारंभ हुआ था जिसकी पृष्ठभूमि में 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्रीक अर्थव्यवस्था की स्वयं की संरचनात्मक कमजोरियां तथा ऋणदाताओं के विश्वास में अचानक कमी मुख्य कारण थे। उस समय यह तथ्य भी सामने आया कि ग्रीस सरकार द्वारा अपने सरकारी ऋण स्तरों और घाटों संबंधी पूर्व आंकड़े गलत रिपोर्ट किए गए थे। इसके अतिरिक्त वहां सार्वजनिक व्यय भी अनियंत्रित होता जा रहा था।
- ग्रीस के इस संकट के उभरने के पश्चात यूरोपीय आयोग, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और आईएमएफ (जिन्हें 'Trioka' उपनाम दिया गया) मिलकर उसे संकट से उबारने हेतु मई, 2010 में 3 वर्षों की अवधि में 110 बिलियन यूरो का ऋण सहायता पैकेज देने पर सहमत हुए परंतु इससे मितव्ययिता, संरचनात्मक सुधारों और सरकारी संपत्ति के निजीकरण जैसी शर्तें जुड़ी थीं। परंतु एक वर्ष के बाद भी ग्रीस में मंदी की स्थिति बनी रहने पर फरवरी, 2012 में उसे 140 बिलियन यूरो का दूसरा ऋण सहायता पैकेज उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2013 और 2014 में ग्रीक अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार प्रत्यक्ष हुआ परंतु 2014 की अंतिम तिमाही में पुनः मंदी की स्थितियां दिखने लगीं। इस बीच जनवरी, 2015 में वहां समय-पूर्व संसदीय चुनाव कराए गए जिसके बाद वामपंथी सिरिजा (Syriza) पार्टी के नेता एलेक्सिस त्सिप्रास ने गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
- ग्रीस की नई सरकार ने चालू बेलआउट समझौतों की शर्तों को मानने से इनकार किया जिस पर ऋणदाता त्रयी (Trioka) ने चालू कार्यक्रम के तहत सभी सहायताओं को रोकने की घोषणा की हालांकि ग्रीस को नए पारस्परिक सहमत समझौते तक पहुंचने के लिए 4 माह का तकनीकी विस्तार उपलब्ध कराया गया।
- नया समझौता न हो पाने के कारण ग्रीस को दिया गया दूसरा बेलआउट पैकेज तकनीकी रूप से 30 जून, 2015 को समाप्त हो गया जिसके कारण ग्रीस आईएमएफ के ऋण की 1.5 बिलियन यूरो की किस्त चुका पाने में असफल रहा और इस प्रकार वह विश्व का 'डिफाल्टर' की श्रेणी में आने वाला पहला विकसित देश तथा 2001 में जिम्बाब्वे के डिफाल्टर देश बनने के बाद दूसरा ऐसा देश बना। 30 जून, 2015 की स्थिति के अनुसार ग्रीस का कुल सरकारी ऋण 323 बिलियन यूरो था।
- जनमतसंग्रह के बाद 7 जुलाई, 2015 को ग्रीस के मसले पर यूरोजोन का एक आपात सम्मेलन बुलाया गया जिसमें फ्रांस ने जहां ग्रीस के प्रति नरम रुख अपनाया वहीं जर्मनी ने चेतावनी दी कि बिना शर्त ग्रीस को ऋण सहायता नहीं दी जानी चाहिए। यूरोजोन के मंत्रियों ने ग्रीस से ऋण वापसी की नई योजना पेश करने को कहा।
- अंततः ग्रीस द्वारा प्रस्तुत नई योजना के आधार पर कुछ अन्य शर्तों के साथ 13 जुलाई, 2015 को यूरोजोन के नेता ग्रीस को तीसरा बेलआउट पैकेज (अगले 3 वर्षों में लगभग 97 बिलियन डॉलर/86 बिलियन यूरो की ऋण सहायता) प्रदान करने पर सहमत हुए। इसके तहत ग्रीस को कर बढ़ाने, बाजार सुधार लागू करने, पेंशन में कटौती करने और श्रम कानूनों में परिवर्तन करने जैसी कड़ी शर्तें लागू करनी होंगी। 15 जुलाई को ग्रीस की संसद द्वारा तत्संबंधी सुधारों हेतु विधेयक पारित कर दिया गया और तत्पश्चात 14 अगस्त, 2015 को ग्रीस की संसद द्वारा तीसरे बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी गई।
- इसके पश्चात 20 अगस्त को ग्रीस के प्रधानमंत्री त्सिप्रास द्वारा अपनी ही पार्टी के सदस्यों के विरोध के कारण इस्तीफा देकर नए चुनाव कराने की घोषणा की गई। 20 सितंबर, 2015 को संपन्न नए चुनावों के बाद वे पुनः ग्रीस के प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए हैं।

यूएनएचआरसी में इजरायल के विरुद्ध प्रस्ताव

- 3 जुलाई, 2015 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC : United Nations Human Rights Commission) में 2014 के गाजा संघर्ष में इजरायल द्वारा किए गए

कथित युद्ध अपराधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के आधार पर इजरायल के विरुद्ध प्रस्ताव (A/HRC/29/L.35) लाया गया।

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कुल 47 सदस्यों में से 41 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। प्रस्ताव के पक्ष में मत देने वालों में यूरोपीय संघ के 8 सदस्य- फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, लाटविया और लिथुआनिया (जो कि वर्तमान में यूएनएचआरसी के सदस्य हैं) भी शामिल हैं।
- अमेरिका ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपना मत दिया जबकि भारत, केन्या, इथिओपिया, पराग्वे और मेसीडोनिया मतदान से गैरहाजिर रहे।
- भारत द्वारा इस प्रस्ताव पर मतदान से गैरहाजिर रहने को भारतीय विदेश नीति में इजरायल को लेकर बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि परंपरागत रूप से भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इजरायल के विरुद्ध सभी प्रस्तावों का समर्थन किया जाता रहा है। गत वर्ष जुलाई में भी यूएनएचआरसी में लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने इजरायल के विरुद्ध अपना मत दिया था।

अमेरिका में समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता

- 26 जून, 2015 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 'ओबर्जफेल वर्सेज हॉग्स' (Obergefell v. Hodges) मामले में बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि देश का संविधान समलैंगिक जोड़ों को विवाह का अधिकार प्रदान करता है तथा समलैंगिक जोड़ों को राज्य द्वारा विवाह लाइसेंस प्रदान करने से इनकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन है।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ ही अमेरिका वर्ष 2015 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पांचवां और कुल मिलाकर 21वां देश हो गया है। इससे पूर्व इस वर्ष स्लोवेनिया, फिनलैंड, लक्जमबर्ग और आयरलैंड द्वारा समलैंगिक विवाहों को विधिक मान्यता प्रदान की गई थी।
- इनके अतिरिक्त नीदरलैंड्स (2001), बेल्जियम (2003), स्पेन (2005), कनाडा (2005), द. अफ्रीका (2006), नार्वे (2009), स्वीडन (2009), पुर्तगाल (2010), आइसलैंड (2010), अर्जेंटीना (2010), डेनमार्क (2012), ब्राजील (2013), फ्रांस (2013), उरुग्वे (2013), न्यूजीलैंड (2013) एवं ब्रिटेन (2014) द्वारा समलैंगिक विवाहों को विधिक स्वीकृति दी जा चुकी है।

  नोट : आयरलैंड में 22 मई, 2015 को हुए जनमतसंग्रह में 62.07 प्रतिशत मतदाताओं ने समलैंगिक विवाह के पक्ष में अपना मत दिया (आयरलैंड वस्तुतः विश्व का प्रथम देश है जहां इस संदर्भ में जनमतसंग्रह हुआ) तथा वहां इस संदर्भ में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। स्लोवेनिया और फिनलैंड में समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता तो मिल गई है तथापि यह अभी प्रभावी नहीं हुई है। स्लोवेनिया में इसके इसी वर्ष तथा फिनलैंड में 1 मार्च, 2017 से प्रभावी होने की आशा है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पूर्व भी अमेरिका के 37 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में समलैंगिक विवाह वैध था तथा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसे अब वहां के सभी राज्यों में विधिक मान्यता प्राप्त हो गई है और इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान करने वाला अमेरिका विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है।

रोहिंग्या शरणार्थी समस्या

- हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार म्यांमार के उत्तरी रैखाइन प्रदेश (अराकान क्षेत्र) के निवासी रोहिंग्या मुसलमान विश्व भर में शरणार्थियों के रूप में दर-बदर भटक रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या इस समस्या में मृत्यु का शिकार हो रही है।
- उल्लेखनीय है कि रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की सरकार व बौद्ध कट्टरपंथी, जो कि म्यांमार के शासन में बहुतायत हैं, म्यांमार का मूल निवासी नहीं मानते। उनका कहना है कि ब्रिटिश काल में वे मुसलमान अराकान क्षेत्र में बसाए गये थे। दूसरी तरफ रोहिंग्या मुलसमानों का कहना है कि उन्हें म्यांमार में रहते कई शताब्दियां हो गईं और म्यांमार के संसाधनों पर उनका भी बौद्धों की तरह ही हक होता है।
- म्यांमार के रैखाइन प्रांत में वर्ष 2012 में व्यापक दंगे हुए जिससे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत, थाईलैंड, मलेशिया व इंडोनेशिया की ओर से विस्थापित होना पड़ा। वर्तमान स्थिति यह है कि उनकी दस लाख जनसंख्या में से 2 लाख जनसंख्या विस्थापित व शरणार्थी के रूप में रह रही है।
- अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इन्हें 'बोट पीपुल' के नाम से पुकारने लगी क्योंकि ये अंडमान सागर व मलक्का जल संधि में नाव से एक देश से दूसरे देश में शरण पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के अनुसार जनवरी से मार्च, 2015 के मध्य मानव तस्करों के चंगुल से तकरीबन 25 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को नावों से बचाया गया। तस्करों के द्वारा समुद्र में छोड़ दिए जाने के बाद नावों पर सीमित खाद्य पदार्थ की उपस्थिति में इंडोनेशिया, मलेशिया व थाईलैंड के जल क्षेत्र में सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान मृत पाये गये।
- रोहिंग्या विस्थापितों की स्थिति को देखते हुए मलेशिया व इंडोनेशिया ने अस्थाई तौर पर उन्हें शरण देने को सहमति दी है। फिलीपींस सरकार ने भी 'बोट पीपुल्स' को शरण देने की इच्छा जाहिर की है। गाम्बिया की सरकार ने भी रोहिंग्या लोगों से अपना सरोकार व्यक्त करते हुए उनके कठिन समय में मदद करने का निर्णय लिया है।

विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति, 2015

- 29 मई, 2015 को संयुक्त राष्ट्र के निकाय 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO : मुख्यालय-रोम) द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति (The State of Food Insecurity in the World), 2015' जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990-92 में दुनिया में भूख-पीड़ित या गहन अल्पपोषित लोगों की संख्या 1 बिलियन (1000 मिलियन/1 अरब) थी जो 2014-15 में घटकर 795 मिलियन के स्तर पर है। इस कमी के लिए चीन के नेतृत्व में पूर्वी एशिया के देश सर्वाधिक उत्तरदायी रहे हैं।

- एफएओ के आकलन के अनुसार भारत में भूख-पीड़ित लोगों की संख्या 2014-15 में 194.6 मिलियन है जो कि विश्व में सर्वाधिक है। हालांकि भारत में भी इस संदर्भ में कमी दर्ज हुई है जो कि 1990-92 के 210.1 मिलियन से घटकर इस स्तर पर आई है।
- तथापि चीन में भूख-पीड़ित लोगों की संख्या में इस अवधि में काफी तीव्र कमी हुई है जो 1990-92 के 289 मिलियन से तेजी से घटकर 2014-15 में 133.8 मिलियन (भारत के बाद दूसरा स्थान) रही है।
- भारत और चीन के बाद 2014-15 में विश्व में भूख-पीड़ित लोगों की सर्वाधिक संख्या वाले देश क्रमशः हैं—पाकिस्तान (41.4 मिलियन), इथिओपिया (31.6 मिलियन), बांग्लादेश (26.3 मिलियन), इंडोनेशिया (19.4 मिलियन), तंजानिया (16.8 मिलियन), फिलीपींस (13.7 मिलियन), नाइजीरिया (12.9 मिलियन) और उत्तरी कोरिया (10.5 मिलियन)।
- एफएओ की इस रिपोर्ट के अनुसार विगत 25 वर्षों में विश्व के विकासशील क्षेत्रों में भूख-पीड़ित लोगों का प्रतिशत 23.3 से घटकर 12.9 रह गया है।

अमेरिका व क्यूबा के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति

- 17 सितंबर, 2015 को क्यूबा द्वारा 54 वर्षों के बाद अमेरिका में अपना राजदूत (जोस कैबेनास को) नियुक्त किया गया है।
- इससे पूर्व 1 जुलाई, 2015 को अमेरिका एवं क्यूबा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को ऐतिहासिक मोड़ देते हुए एक-दूसरे के यहां दूतावास खोलने की घोषणा की थी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा व उनके क्यूबा के समकक्ष राउल कास्त्रो ने 20 जुलाई, 2015 से दोनों देशों की राजधानियों में स्थायी दूतावास फिर से खोलने संबंधी पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
- इसके पहले 29 मई, 2015 को अमेरिका ने आधिकारिक रूप से क्यूबा को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्यों की सूची से निकाल दिया था। विदित है कि अमेरिका ने वर्ष 1982 में क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में डाल दिया था।
- अप्रैल, 2015 में पनामा सिटी में आयोजित 'अमेरिकियों के सम्मेलन' (Summit of the Americas) के सातवें संस्करण में क्यूबा को पहली बार शामिल किया गया। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति व क्यूबा के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई।
- इससे पूर्व 17 दिसंबर, 2014 को अमेरिका व क्यूबा ने 54 वर्षों के बाद अपने द्विपक्षीय संबंध पुनः शुरू करने की सहमति जताई थी। इस सहमति के तहत एक समझौता किया गया जिसके अनुसार क्यूबा की यात्रा पर आने वाले अमेरिकियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी परंतु इसे व्यापक रूप से अमेरिकी पर्यटन के लिए नहीं खोला जाएगा। इसके बाद 16 जनवरी, 2015 से अमेरिका व क्यूबा के मध्य नए और उदार यात्रा एवं व्यापार विनियम प्रभावी हो गए।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में हुई 'क्यूबा क्रांति' के बाद से अमेरिका व क्यूबा शीतयुद्ध की राजनीति में एक-दूसरे के वैचारिक शत्रु बने रहे। वर्ष 1961 में ही दोनों देशों ने एक-दूसरे की राजधानियों में स्थित अपने दूतावास बंद कर दिए थे। इसके बाद वर्ष 1962 के 'क्यूबा मिसाइल संकट' ने अमेरिका व क्यूबा के सभी तरह के कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए थे।

चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर

- 20-21 अप्रैल, 2015 के मध्य चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान 20 अप्रैल को दोनों देशों के बीच कुल 51 समझौते हस्ताक्षरित हुए जिसमें अधिकांश 'चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' (CPEC) से जुड़ी परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने से संबंधित हैं।
- यह वृहद आर्थिक गलियारा चीन के उत्तर-पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग (Xinjiang) के काशगर से प्रारंभ होकर पाक-अधिकृत कश्मीर से गुजरते हुए पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर तट पर स्थित ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा।
- कुल लगभग 2,442 किमी. लंबे इस आर्थिक गलियारे पर राजमार्गों, रेलमार्गों तथा तेल एवं गैस परिवहन हेतु पाइपलाइनों का विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- 46 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत वाला यह इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की प्रस्तावित '21वीं शताब्दी सिल्क रोड पहल' का विस्तार है तथा यह अब तक का चीन द्वारा घोषित सबसे बड़ा राष्ट्रपारीय निवेश है। इस कॉरिडोर को अगले 3 वर्षों में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।
- ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास भी चीन के सहयोग से ही हुआ है तथा सद्यः समझौतों के तहत इसे 2015 से 40 वर्षों के लिए चीन को सौंपे जाने का भी प्रावधान किया गया है।
- चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के संचालित होने से जहां पश्चिमी चीन के लिए अफ्रीका और मध्य-पूर्व तक व्यापार मार्ग उपलब्ध होगा वहीं ग्वादर बंदरगाह से चीन की तेल संसाधनों के लिए मध्य-पूर्व तक प्रत्यक्ष पहुंच उपलब्ध हो सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा भी स्थलरूद्ध अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के प्रयासों के तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह (जो कि ग्वादर बंदरगाह से कुछ मील ही दूर है) के विकास में भारी निवेश किया जा रहा है।

भारत यूएन के 4 निकायों में चयनित

- 8 अप्रैल, 2015 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) की संयोजन एवं प्रबंधन बैठक के दौरान भारत का 4 अनुषंगी निकायों में मौखिक मतदान के जरिए चयन किया गया।
- भारत को यूनीसेफ (UNICEF) के कार्यकारी बोर्ड हेतु 13 अन्य देशों के साथ जनवरी, 2016 से 3 वर्ष के लिए चुना गया है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के कार्यकारी बोर्ड में भी भारत 2016-18 अवधि हेतु पुनः चयनित हुआ है।
- साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम (यूएन-हैबिटेट) की शासी परिषद हेतु भी 2016-19 अवधि हेतु पुनः चुना गया है।
- इसके अतिरिक्त भारत को अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग (CCPCJ) में भी जनवरी, 2016 से 3 वर्ष की अवधि हेतु चुना गया है।

विश्व भर में मृत्युदंडों की स्थिति पर रिपोर्ट

- अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' द्वारा विश्व भर में मृत्युदंडों की स्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट 27 मार्च, 2015 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में वर्ष 2014 में 22 देशों में कुल कम से कम 607 मृत्युदंड (चीन के अतिरिक्त) क्रियान्वित किए गए जबकि 2013 में यह संख्या 778 थी। ध्यातव्य है कि इसमें चीन के आंकड़े (गुप्त होने के कारण) शामिल नहीं हैं तथापि इस रिपोर्ट के अनुसार, चीन में इस वर्ष दिए गए मृत्युदंडों की संख्या शेष सारे विश्व में दिए गए मृत्युदंडों की संख्या से अधिक रहने का आकलन है।
- वर्ष 2014 में विश्व के 2,466 लोगों को नई मृत्युदंड सजाएं सुनाई गईं जो कि 2013 से 28 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2014 में क्रियान्वित रिपोर्टेड मृत्युदंडों (चीन के अतिरिक्त) में सर्वाधिक मृत्युदंड (289+) ईरान में दिए गए जिसके बाद क्रमशः सऊदी अरब (90+), इराक (61+) एवं अमेरिका (35) का स्थान रहा।

वैश्विक शस्त्र एवं रक्षा व्यापार की स्थिति

- स्वीडन स्थित 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)' द्वारा 16 मार्च, 2015 को विश्व में शस्त्रों के हस्तांतरण पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स, 2014' जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-2014 की अवधि में भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है तथा कुल वैश्विक शस्त्र आयात में भारत का हिस्सा 2004-08 के 7 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। भारत के बाद इस संदर्भ में क्रमशः सऊदी अरब (5 प्रतिशत), चीन (5 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (4 प्रतिशत) और पाकिस्तान (4 प्रतिशत) का स्थान है।
- सिप्री के आकलन के अनुसार 2010-2014 अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश क्रमशः अमेरिका (31 प्रतिशत भाग) और रूस (27 प्रतिशत भाग) हैं जिनके बाद क्रमशः चीन (5 प्रतिशत), जर्मनी (5 प्रतिशत) और फ्रांस (5 प्रतिशत) का स्थान है।
- सिप्री की उपर्युक्त रिपोर्ट से पूर्व 7 मार्च, 2015 को अमेरिकी संस्था आईएचएस इंक. द्वारा अपनी वार्षिक 'ग्लोबल डिफेंस ट्रेड रिपोर्ट' जारी की गई थी जिसके अनुसार वर्ष 2014 में विश्व में रक्षा संबंधी उपकरणों (हथियारों सहित) के आयात के संदर्भ में भारत को पीछे छोड़ते हुए सऊदी अरब शीर्ष स्थान पर आ गया है।

नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन

पोलैंड में संसदीय चुनाव

- 25 अक्टूबर, 2015 को पोलैंड में संसदीय चुनाव कराए गए। वर्ष 1993 के नार्वे के संसदीय चुनावों के बाद यह ऐसा प्रथम यूरोपीय चुनाव था जिसमें दो सबसे बड़ी पार्टियों का नेतृत्व महिलाओं को सौंपा गया था।
- घोषित परिणामों के अनुसार बीटा सिजिडलो (Beata Szydlo) के नेतृत्व वाली लॉ एंड जस्टिस पार्टी (PiS) 37.58 प्रतिशत मतों के साथ 235 सीटें प्राप्त कर बहुमत पाने में सफल हुई जबकि प्रधानमंत्री इवा कोपाक्ज (Ewa Kopacz) के नेतृत्व वाले सिविक प्लेटफॉर्म दल (PO) को 24.09 प्रतिशत मतों के साथ 138 सीटें ही प्राप्त हुईं।
- पोलैंड में 1989 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के पश्चात ये वहां पहले ऐसे संसदीय चुनाव थे जिनमें कोई दल अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल हुआ है।
- पोलैंड की नई प्रधानमंत्री बीटा सिजिडलो नामित हुई हैं जो नवंबर, 2015 में पदभार ग्रहण करेंगी।

कनाडा में संघीय चुनाव

- कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमंस की सभी 338 सीटों हेतु संघीय चुनाव 19 अक्टूबर, 2015 को कराए गए।
- इन चुनावों में कुल 68.5 प्रतिशत मतदान हुआ।
- घोषित परिणामों के अनुसार जस्टिन ट्रूड्यू (Justin Trudeau) के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी ने 39.47 प्रतिशत मतों के साथ 184 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त किया जबकि प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी 31.89 प्रतिशत मतों के साथ 99 सीटें प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 44 सीटें प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रही।
- जस्टिन ट्रूड्यू ने 4 नवंबर, 2015 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव

- 11 अक्टूबर, 2015 को बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए।
- इस चुनाव में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको 83.47 प्रतिशत मत प्राप्त कर पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
- यह राष्ट्रपति लुकाशेंको का पांचवां कार्यकाल है तथा वे वर्ष 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं।

ग्रीस में संसदीय चुनाव

- ग्रीस में जनवरी, 2015 में हुए संसदीय चुनावों के बाद वहां वामपंथी सिरिजा (Syriza) पार्टी के नेता एलेक्सिस त्सिप्रास (Alexis Tsipras) ने गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था तथापि ग्रीस के आर्थिक संकट और बेलआउट पैकेज पर अपने सहयोगी सांसदों से असहमति के बाद उन्होंने 20 अगस्त, 2015 को इस्तीफा दे दिया था।

- तदनुसार, ग्रीस की संसद (Hellenic Parliament) की सभी 300 संसदीय सीटों में से 250 सीटों (शेष 50 सीटें वहां सबसे बड़ी पार्टी को प्राप्त होती हैं) के लिए नए चुनाव वहां 20 सितंबर, 2015 को कराए गए।
- इन चुनावों में 35.46 प्रतिशत मतों के साथ 145 सीटें (95+50 बोनस सीटें) प्राप्त कर सिरिजा पार्टी ने सफलता दर्ज की तथा उसकी सहयोगी इंडिपेंडेंट ग्रीक्स पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हुईं।
- एलेक्सिस त्सिप्रास ने 21 सितंबर, 2015 को पुनः ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है तथा ग्रीस में नई गठबंधन सरकार में सिरिजा पार्टी और इंडिपेंडेंट ग्रीक्स पार्टी शामिल हैं।

सिंगापुर में संसदीय चुनाव

- 11 सितंबर, 2015 को सिंगापुर में संसद की 89 सीटों हेतु आम चुनाव कराए गए। इनमें कुल 93.56 प्रतिशत मतदान हुआ।
- इस चुनाव में प्रधानमंत्री ली सीन लूंग (Lee Hsien Loong) के नेतृत्व वाली पीपुल्स एक्शन पार्टी (PAP) 69.9 प्रतिशत मतों के साथ 83 सीटें प्राप्त कर सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल रही।
- उल्लेखनीय है कि ली सीन लूंग वर्ष 2004 से सिंगापुर के प्रधानमंत्री पद पर हैं।

श्रीलंका में संसदीय चुनाव

- 17 अगस्त, 2015 को श्रीलंका में 15वीं संसद हेतु आम चुनाव कराए गए।
- ज्ञातव्य है कि श्रीलंका की संसद की कुल 225 सीटों में से 196 सीटों हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जबकि शेष सीटें विभिन्न दलों/समूहों को उनके राष्ट्रीय मत प्रतिशत के अनुसार प्रदान की जाती हैं।
- इन चुनावों में कुल 77.66 प्रतिशत मतदान हुआ।
- घोषित परिणामों के अनुसार प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) के नेतृत्व वाले 'यूनाइटेड नेशनल फ्रंट फॉर गुड गवर्नेंस' (UNFGG) ने कुल 106 सीटें (93 प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं 13 राष्ट्रीय आवंटन से) प्राप्त कीं जबकि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के नेतृत्व वाला 'यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलाएंस' (UPFA) 95 सीटें (83+12) प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा।
- प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति सिरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (SFP) के सहयोग से सरकार का गठन किया है तथा उन्होंने 21 अगस्त, 2015 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वे इससे पूर्व 9 जनवरी, 2015 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। इससे पहले वे 1993-94 एवं 2001-2004 के मध्य श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।

ब्रिटेन में पुनः कैमरून सरकार

- ब्रिटिश संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ कॉमंस' के लिए आम चुनाव 7 मई, 2015 को कराए गए। हाउस ऑफ कॉमंस की सभी 650 सीटों पर हुए इस चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की कंजरवेटिव पार्टी तथा एड मिलिबैंड के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के बीच था।
- 8 मई, 2015 को घोषित परिणामों के अनुसार कंजरवेटिव पार्टी 36.1 प्रतिशत मतों के साथ 330 सीटें (गत चुनाव से 24 अधिक) प्राप्त कर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल रही। ज्ञातव्य है कि 1992 के बाद पहली बार कंजरवेटिव पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है।
- प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टी को इस चुनाव में 29.0 प्रतिशत मतों के साथ 232 सीटें (गत चुनाव से 26 कम) ही प्राप्त हुईं।
- निकोला स्टर्जन के नेतृत्व वाली स्काटिश नेशनल पार्टी (SNP) इस चुनाव में 56 सीटें प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रही। 2010 के पिछले चुनाव की मात्र 6 सीटों की तुलना में यह इस दल की बड़ी सफलता है तथा स्कॉटलैंड में इसने अप्रत्याशित सफलता (वहां की कुल 59 में से 56 सीटें) हासिल की।
- इस चुनाव में एसएनपी की 20 वर्षीया म्हाइरी ब्लैक विजयी होकर विगत लगभग 360 वर्षों में वहां की सबसे युवा सांसद बनी हैं। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन में 2006 में चुनावों में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी।
- इस चुनाव में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में महिला सांसदों की संख्या पिछली बार के 147 से बढ़कर 191 हो गई है।
- ब्रिटेन के नए हाउस ऑफ कॉमंस में भारतीय मूल के 10 सांसद इस बार पहुंचने में सफल रहे जबकि गत चुनाव में यह संख्या 8 ही थी। इस बार विजयी रहे भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद हैं—लिसा नंदी, प्रीति पटेल, वैलेरी वाज, सुएला फर्नांडीज एवं सीमा मल्होत्रा (सभी महिलाएं) तथा कीथ वाज, आलोक शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, ऋषि सुनाक (इंफोसिस के संस्थापकों में से एक एन. नारायणमूर्ति के दामाद) एवं शैलेश वारा।
- उल्लेखनीय है कि मार्गरेट थैचर के बाद डेविड कैमरून पहले ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो एक पूर्ण काल के बाद अधिक सीटों के साथ पुनः सत्ता में आने में सफल हुए हैं। साथ ही वे 1900 में लॉर्ड सालिसबरी के बाद उच्चतर लोकप्रिय मत प्रतिशत के साथ पूर्ण काल के बाद पुनः सत्ता में आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।

◆◆◆

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

● तृतीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन, 2015 ● संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, 2015 ● संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा शिखर सम्मेलन ● जी-4 समूह की शिखर बैठक ● समान-विचार वाले विकासशील देशों (LMDC) की बैठक ● भारत-प्रशांत द्वीपीय देश फोरम का शिखर सम्मेलन ● 'विकास हेतु वित्त' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2015 ● सीडोक-2015 सम्मेलन ● अंटार्कटिक भू विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ● शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का शिखर सम्मेलन ● ब्रिक्स (BRICS) का सातवां शिखर सम्मेलन ● जी-7 का 41वां शिखर सम्मेलन ● एशिया-अफ्रीका संस्मारक सम्मेलन, 2015 ● उच्च-पर्वतीय एशिया में ग्लेशियर विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

तृतीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन, 2015

- भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (IAFS : India-Africa Forum Summit) अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ भारत के वर्तमान संबंधों के संवर्धन हेतु आधिकारिक प्लेटफॉर्म है जिसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है।
- प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन 8-9 अप्रैल, 2008 के दौरान नई दिल्ली में संपन्न हुआ था जिसमें भारत के साथ अफ्रीकी संघ (AU) द्वारा चयनित 14 देशों ने भागीदारी की थी। इस क्रम में द्वितीय शिखर सम्मेलन इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में 24-25 मई, 2011 के मध्य आयोजित किया गया था जिसमें भारत के साथ 15 अफ्रीकी देशों ने प्रतिभाग किया था।
- तृतीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन मूलतः नई दिल्ली में दिसंबर, 2014 में प्रस्तावित था तथापि कई पश्चिम अफ्रीकी देशों में घातक इबोला महामारी के प्रसार के कारण इसे टाल दिया गया था।
- तत्पश्चात, नए कार्यक्रम के तहत 26-29 अक्टूबर, 2015 के दौरान नई दिल्ली में तृतीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (3rd IAFS) का आयोजन किया गया। इस वृहद आयोजन हेतु अफ्रीकी देशों की अधिकतम उच्चस्तरीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा सभी 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों को निमंत्रित किया गया था तथा इस संदर्भ में कूटनीतिक स्तर पर भी विशेष प्रयास किए गए थे।
- तृतीय आईएएफएस सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा सभी अफ्रीकी देशों तक भारत की पहुंच संवर्द्धित करने का अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक आयोजन रहा। इससे पूर्व भारत में मार्च, 1983 में संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का शिखर सम्मेलन ही राष्ट्रों की उच्चस्तरीय भागीदारी की दृष्टि से इससे वृहद था जिसमें लगभग 140 देशों द्वारा प्रतिभाग किया गया था।
- इस वृहद एवं महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हेतु विशेष लोगो डिजाइन किया गया था जिसमें एक शेर का आधा भाग भारतीय शेर और दूसरा आधा भाग अफ्रीकी शेर के रूप में प्रदर्शित था। इसकी पृष्ठभूमि में भारत के मानचित्र को अफ्रीकी मानचित्र के साथ अतिव्यापित दिखाया गया था जो कि प्राचीन भारत-अफ्रीका संबंधों तथा अतिप्राचीन काल में गोंडवानालैंड (जब भारतीय उपमहाद्वीप स्थलीय रूप से अफ्रीका महाद्वीप का भाग था) को दर्शाता है। इस लोगो का ध्येय वाक्य (MOTTO) था- 'पुनर्जीवित भागीदारी-साझा दृष्टि' (Re-invigorated Partnership-Shared Vision)।
- तृतीय आईएएफएस सम्मेलन में 41 देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों सहित सभी 54 अफ्रीकी देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अफ्रीका महाद्वीप के बाहर अफ्रीकी देशों का यह सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले प्रमुख अफ्रीकी नेताओं में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे (जो कि वर्तमान में अफ्रीकी संघ के भी अध्यक्ष हैं), मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा, नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी, सूडान के राष्ट्रपति ओमार अल-बशीर, दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बूबाकेर केइता, मोरक्को के शाह मोहम्मद VI, सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद आदि प्रमुख थे।
- तृतीय आईएएफएस की पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में शांति पथ के निकट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा भारत और अफ्रीका की दोस्ती को समर्पित 'गुलाब उद्यान' का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा सभी 54 अफ्रीकी देशों के भारत में राजदूत/उच्चायुक्त और राजनयिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।
- तृतीय आईएएफएस के कार्यक्रमों का मुख्य आयोजन स्थल नई दिल्ली का इंदिरा गांधी एरेना (इनडोर स्टेडियम) था जहां 26 अक्टूबर को भारत और अफ्रीकी देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के साथ भारत की मेजबानी में इस सम्मेलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ। इस दिन भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ दो समझौते किए गए। इनमें पहला भारत और अफ्रीका के बीच राजनीतिक साझेदारी (क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों सहित) तथा दूसरा भारत और अफ्रीका के मध्य विकासात्मक भागीदारी के संवर्द्धन से संबंधित है।
- 27 अक्टूबर को भारत और अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसकी सह-अध्यक्षता भारत और जिम्बाब्वे के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई।
- 29 अक्टूबर को तृतीय आईएएफएस के सबसे मुख्य कार्यक्रम राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों एवं उनके प्रतिनिधियों की शिखर बैठक का आयोजन किया गया जिसका केंद्रीय विषय (Theme) था- 'प्रगति में भागीदार : एक गतिशील और परिवर्तनशील विकास एजेंडा की ओर' (Partners in Progress : Towards a Dynamic and Transformative Development Agenda)।
- इस शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे (अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष) द्वारा की गई।

- शिखर बैठक के उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी देशों को आश्वस्त किया कि भारत उन्हें रक्षा, सुरक्षा, कारोबार और बुनियादी ढांचे के निर्माण में हरसंभव मदद करेगा। उन्होंने भारत और अफ्रीका की दो-तिहाई आबादी के 35 वर्ष से कम आयु की होने का उल्लेख करते हुए वर्तमान शताब्दी को युवाओं की शताब्दी करार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विगत एक दशक से भी कम समय में भारत-अफ्रीका व्यापार दोगुने से अधिक होकर लगभग 72 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत द्वारा 2008 के प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन से अब तक अफ्रीका को 7.4 बिलियन डॉलर रियायती ऋण तथा 1.2 बिलियन डॉलर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता की गई है तथा विगत 3 वर्षों में भारत द्वारा 24,000 से अधिक अफ्रीकी छात्रों को प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराई गई है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर बैठक में अफ्रीका को अगले 5 वर्षों में 10 बिलियन डॉलर का रियायती ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने 600 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता भी प्रदान करने का ऐलान किया जिसमें 100 मिलियन डॉलर की 'भारत-अफ्रीका विकास निधि' तथा 10 मिलियन डॉलर की 'भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य निधि' शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगले 5 वर्षों में भारत द्वारा अफ्रीकी छात्रों को भारत में शिक्षा हेतु 50,000 छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाएंगी।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा परिकल्पित 'पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क' (जो भारत और 48 अफ्रीकी देशों को एक-दूसरे से जोड़ता है) और अफ्रीका में कौशल प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थानों के विस्तार में सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। भारत द्वारा 'पैन अफ्रीका वर्चुअल यूनिवर्सिटी' की स्थापना में भी सहायता दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी देशों से 'सौर ऊर्जा समृद्ध देशों के गठबंधन' (Alliance of Solar-rich Countries) में शामिल होने की अपील भी की जिसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 21) के दौरान 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में किया जाएगा।
- तृतीय आईएएफएस शिखर बैठक के अंत में भारत और अफ्रीकी देशों द्वारा हस्ताक्षरित 34 बिंदुओं वाला 'दिल्ली घोषणापत्र (Delhi Declaration), 2015' तथा 52 बिंदुओं वाला 'रणनीतिक सहयोग हेतु भारत-अफ्रीका फ्रेमवर्क' (India-Africa Framework for Strategic Cooperation) जारी किया गया। इन दोनों महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों में भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग, कृषि, ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य, शांति एवं सुरक्षा तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों (यथा- संयुक्त राष्ट्र, जी-77, यूएनएफसीसीसी, डब्ल्यूटीओ आदि) पर सहयोग को संवर्धित करने के उपायों के साथ इनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक नियमित औपचारिक पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित किए जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। भारत और अफ्रीकी देशों द्वारा सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में बहुप्रतीक्षित सुधारों के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय 69/560 को शीघ्र लागू किए जाने पर भी बल दिया गया तथा विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु एक-दूसरे की स्थिति और आकांक्षाओं को भी उन्होंने नोट किया।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस शिखर सम्मेलन के नेपथ्य में विभिन्न अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी की गईं।
- अगला भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, 2015

- 25-27 सितंबर, 2015 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में 'संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन (UN Sustainable Development Summit), 2015' का आयोजन किया गया।
- इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों में से 150 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों तथा शेष देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
- इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र के इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय (Theme) था— '2015 : टाइम फॉर ग्लोबल एक्शन फॉर पीपुल एंड प्लैनेट।'
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, 2015 के दौरान 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्यों द्वारा अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास हेतु एजेंडे 'ट्रांसफॉर्मिंग ऑवर वर्ल्ड : दि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development) को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया।
- इसके तहत वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी सम्मेलन में निर्धारित 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों' (MDGs : Millennium Development Goals; जिनकी अवधि वर्ष 2015 तक निर्धारित थी) के स्थान पर 2015-2030 अवधि के लिए नए 'सतत विकास लक्ष्य' (SDGs : Sustainable Development Goals) निर्धारित किए गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 पश्चात विकास एजेंडे या सतत विकास लक्ष्यों पर सर्वप्रथम जून, 2012 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन (Rio + 20; जो कि 1992 में रियो में ही संपन्न 'पृथ्वी सम्मेलन' के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुआ था) में औपचारिक चर्चा हुई थी तथा इस पर अंतरसरकारी वार्ताएं जनवरी, 2015 में प्रारंभ हुईं और अंततः 2 अगस्त, 2015 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों द्वारा सतत विकास के अगले 15 वर्षों के एजेंडे पर सहमति हुई जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के दौरान संपन्न सम्मेलन में औपचारिक रूप से अपनाया गया है।
- 'ट्रांसफॉर्मिंग ऑवर वर्ल्ड' शीर्षक वाले इस सतत विकास एजेंडे के तहत कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को शामिल

किया गया है जिन्हें वर्ष 2015 से 2030 की अवधि में प्राप्त किया जाना है (देखें–बॉक्स)। इन 17 सतत विकास लक्ष्यों के तहत 169 विभिन्न लक्ष्य और 304 तत्संबंधी संकेतकों को भी शामिल किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

1. निर्धनता : सभी स्थानों से सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करना।
2. भूख एवं खाद्य सुरक्षा : भूख (Hunger) की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।
3. स्वास्थ्य : स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना तथा सभी लोगों के लिए हर आयु में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
4. शिक्षा : समावेशी और समुचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन अधिगम (Learning) अवसरों को बढ़ावा देना।
5. लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण : लैंगिक समानता हासिल करना तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों का सशक्तिकरण।
6. जल एवं स्वच्छता : सभी के लिए जल एवं स्वच्छता (Sanitation) का सतत प्रबंधन और उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. ऊर्जा : सभी के लिए वहनीय, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
8. आर्थिक संवृद्धि : सभी के लिए पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और समुचित कार्य सहित निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना।
9. अवसंरचना, औद्योगीकरण : प्रत्यास्थी (Resilient) अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
10. असमानता : राष्ट्रों के बीच और उनके भीतर असमानता (Inequality) में कमी लाना।
11. शहर : शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, प्रत्यास्थी एवं सतत बनाना।
12. सतत उपभोग एवं उत्पादन : सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिमान (Patterns) सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों से निपटने हेतु अविलंब कदम उठाना।
14. महासागर : सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों एवं सामुद्रिक संसाधनों का संपोषणीय उपयोग एवं संरक्षण करना।
15. जैव विविधता, वन, मरुस्थलीकरण : पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण, पुनर्स्थापना और संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत रूप से प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूक्षरण को रोकना तथा इसका व्युत्क्रमण और जैव विविधता हानियों पर रोक लगाना।
16. शांति एवं न्याय : सतत विकास हेतु शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।
17. भागीदारियां : सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार और क्रियान्वयन के तरीकों को सुदृढ़ करना।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGs)

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGs : Millennium Development Goals) आठ अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समूह है जिन्हें वर्ष 2000 के संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि सम्मेलन में तत्कालीन सभी 189 सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके तहत वर्ष 2015 तक निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने पर सहमति हुई थी—

1. अतिशय निर्धनता और भूख का उन्मूलन
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि
3. लैंगिक समानता को संवर्धित करना
4. बाल मृत्यु दर को कम करना,
5. मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना
6. एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों का मुकाबला करना
7. पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना
8. विकास हेतु एक वैश्विक भागीदारी विकसित करना।

संयुक्त राष्ट के सदस्य देशों द्वारा हाल ही में अंगीकृत वर्ष 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में उपर्युक्त आठों सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा शिखर सम्मेलन

- 28 सितंबर, 2015 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 'संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा शिखर सम्मेलन' (UN Peace Keeping Summit) का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन की मेजबानी एवं अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की तथा इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष उपस्थित थे।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों को अधिक दक्ष, सशक्त एवं प्रभावकारी बनाने के साथ इनका आधुनिकीकरण किए जाने जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था।
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 69 शांति रक्षक मिशनों में से 48 में प्रतिभाग किया है जिनमें 1,80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों (किसी भी अन्य देश से अधिक) ने भागीदारी की है और इन शांति रक्षक मिशनों में 161 भारतीय सैनिकों ने जीवन का बलिदान किया है। साथ ही

८२ देशों के लगभग ८०० शांति रक्षक अधिकारियों को भी प्रशिक्षण भारत द्वारा दिया गया है।

- प्रधानमंत्री मोदी ने महिला शांति रक्षकों की अधिक संख्या वाली तीन पुलिस इकाइयों सहित ८५० सैनिकों की एक अतिरिक्त बटालियन के योगदान की घोषणा की। साथ ही उन्होंने शहीद हुए शांति रक्षकों की स्मृति में एक स्मारक बनाने की भी मांग की।
- इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि शांति रक्षक अभियानों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले भारत जैसे देश सुरक्षा परिषद का भाग ही नहीं हैं, जो किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक सेना भेजने का निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि आज शांति रक्षकों को सिर्फ शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने को नहीं बुलाया जाता, बल्कि उन्हें जटिल चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी दी जाती है तथा सुरक्षा परिषद के आदेश पत्र कई बार शांति रक्षकों को संघर्ष का भाग बना देते हैं जिससे उनके जीवन और अभियानों की सफलता पर खतरा उत्पन्न होता है। ये समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि सैनिकों का योगदान करने वाले देश निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अतः सुरक्षा परिषद के लंबे समय से लंबित सुधारों को तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बरकरार रखी जा सके।
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सम्मेलन के अंत में जारी घोषणापत्र में भारत, अमेरिका एवं चीन सहित 50 से अधिक देशों के नेताओं ने शांति रक्षक अभियानों के लिए अधिकाधिक सहयोग एवं योगदान के साथ इनके आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अभियानों के दौरान यौन उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को समर्थन देने का वादा भी किया।
- इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों के लिए 50 से अधिक देशों ने 40 हजार नए शांति सैनिक और पुलिस के अतिरिक्त 40 हेलिकॉप्टर, 15 सैन्य इंजीनियरिंग टुकड़ियां और 10 फील्ड अस्पताल के योगदान पर सहमति व्यक्त की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्थायी शांति सैनिक पुलिस स्क्वायड की स्थापना और ८००० सैनिकों का अतिरिक्त सेना बल बनाए जाने की घोषणा की।

जी-4 समूह की शिखर बैठक

- 'जी-4' विश्व के 4 प्रमुख देशों—ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का समूह है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए दबाव डालने में नेतृत्वकारी भूमिका में हैं तथा ये चारों देश सुरक्षा परिषद के विस्तार और इसकी स्थायी सदस्यता हेतु एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।
- 26 सितंबर, 2015 को न्यूयॉर्क में भारत के आमंत्रण पर जी-4 समूह के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक संपन्न हुई। ज्ञातव्य है कि यह शिखर बैठक वर्ष 2004 के बाद पहली बार हुई है।
- जी-4 समूह की सद्यः शिखर बैठक की मेजबानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तथा इसमें ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल तथा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने भाग लिया।
- यह शिखर बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु दस्तावेज के पाठ हेतु वार्ताएं प्रारंभ करने पर सहमति के संदर्भ में विशेष महत्त्वपूर्ण थी।
- जी-4 की इस शिखर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा परिषद में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचारकों और सभी प्रमुख महाद्वीपों की बुलंद आवाजों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के दौरान ही सुरक्षा परिषद में सुधारवादी कदम उठाए जाएं तथा साथ ही शीघ्र एवं निश्चित समय-सीमा में सुधार सुनिश्चित हों।
- इस शिखर बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में जी-4 देशों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि हाल के वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़े वैश्विक संघर्षों एवं संकटों से निपटने के लिए पहले की तुलना में आज अधिक प्रतिनिधिमूलक, वैध तथा कारगर सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है। उन्होंने माना कि 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है।
- जी-4 नेताओं ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि 2005 की विश्व शिखर बैठक (जहां सभी राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों ने सुरक्षा परिषद में शीघ्र सुधार का संयुक्त राष्ट्र सुधारों के एक आवश्यक घटक के रूप में समर्थन किया था) के बाद कोई सारवान प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने इस बात पर सुदृढ़ता के साथ बल दिया कि सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु संयुक्त राष्ट्र में चल रही प्रक्रिया, इसकी तात्कालिकता को देखते हुए, नियत समय सीमा में पूरी होनी चाहिए।
- सभी नेताओं ने सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु अंतर्सरकारी वार्ताओं (IGN : Inter-Governmental Negotiations) के लिए आधार के रूप में पाठ-आधारित (Text-based) वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय 69/650 को सर्वसम्मति से अपनाए जाने (जो कि 14 सितंबर, 2015 को अपनाया गया) तथा इस संदर्भ में अफ्रीकी समूह, कैरीकॉम और एल-69 समूह के सदस्य देशों के प्रयासों का स्वागत किया।
- जी-4 नेताओं ने सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणी की सदस्यता में अफ्रीका के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया और साथ ही विस्तारित एवं संशोधित सुरक्षा परिषद में छोटे द्वीपीय विकासशील देशों सहित छोटे और मध्यम आकार के सदस्य देशों के पर्याप्त एवं सतत प्रतिनिधित्व के महत्त्व को भी रेखांकित किया।
- सभी नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि जी-4 समूह के देश विस्तारित एवं संशोधित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु न्यायसंगत उम्मीदवार हैं और वे इस संदर्भ में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रयोजनों और सिद्धांतों की पूर्ति में लगातार योगदान करने तथा सुरक्षा परिषद में शीघ्र एवं सार्थक सुधार लाने की दिशा में प्रयासों को त्वरित करने की भी पुष्टि की।

समान-विचार वाले विकासशील देशों (LMDC) की बैठक

- 14-15 सितंबर, 2015 के दौरान नई दिल्ली में समान-विचार वाले विकासशील देशों (LMDC : Like-Minded Developing Countries) के जलवायु परिवर्तन वार्ताकारों की बैठक का आयोजन किया गया।
- इस बैठक में 13 देशों- अर्जेंटीना, बोलिविया, चीन, क्यूबा, अल सल्वाडोर, इक्वेडोर, ईरान, निकारागुआ, वेनेजुएला, मलेशिया, विएतनाम, सऊदी अरब और भारत के प्रतिनिधिमंडलों ने प्रतिभाग किया।
- इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर ने किया।
- इस बैठक का उद्देश्य पेरिस में होने वाले आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 21/CMP11) के संदर्भ में यूएनएफसीसीसी के तहत जलवायु परिवर्तन वार्ताओं और भावी पेरिस समझौते के संदर्भ में आगे बढ़ने हेतु एलएमडीसी को सर्वसम्मत परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराना था।
- इस बैठक में एलएमडीसी देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस सम्मेलन से पूर्व सीमित शेष समय को देखते हुए वार्ताओं की धीमी गति के प्रति गहन चिंता व्यक्त की गई। साथ ही वार्ताकारों ने बॉन में संपन्न डरबन प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड एक्शन (ADP) पर कार्यबल के विगत सत्र में पाठ आधारित (Text-based) वार्ताओं के न होने के प्रति गहन निराशा भी प्रदर्शित की।
- सभी प्रतिनिधियों ने इस बात को दोहराया कि जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया पर वार्ताओं हेतु यूएनएफसीसीसी ही प्राथमिक अंतर्सरकारी मंच है तथा इसमें समावेशी एवं पारदर्शी रूप से शीघ्र पाठ आधारित वार्ताएं आवश्यक हैं।
- एलएमडीसी प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पेरिस समझौते को उपशमन-केंद्रित ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें डरबन अधिदेश के तहत चिह्नित सभी 6 तत्वों- उपशमन, अनुकूलन, वित्त, क्षमता निर्माण प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण तथा कार्रवाई एवं समर्थन की पारदर्शिता के संतुलित और व्यापक रूप से उल्लेख के साथ क्षतियों एवं हानियों को भी समुचित रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- एलएमडीसी प्रतिनिधियों ने विकसित देशों से वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की मांग करते हुए इस संदर्भ में स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए कहा।
- उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विकासशील देशों के व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ाने वाली किसी प्रकार की बाध्यकारी पुनरीक्षण प्रणाली लाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों के अनुरूप अतिरिक्त और सतत आधार पर जलवायु वित्त उपलब्ध कराना होगा जो कि आधिकारिक विकास सहायता (ODA) से पृथक हो।
- एलएमडीसी प्रतिनिधियों ने 10-12 अक्टूबर, 2015 के दौरान बोलिविया द्वारा 'वर्ल्ड पीपुल्स कांफ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिफेंस ऑफ लाइफ' (बोलिविया के निक्विपाया, कोचाबांबा में संपन्न) का आयोजन किए जाने का स्वागत किया।

LMDC समूह

समान विचारों वाले विकासशील देशों के समूह (LMDC) में ऐसे विकासशील देश शामिल हैं जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों, यथा- संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूएनएफसीसी आदि पर एक-दूसरे के विचारों का समर्थन और पारस्परिक हितों का संवर्धन करते हुए एक वार्ताकारी समूह या ब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं। इनके समान विचार वस्तुतः किसी मुद्दे पर समान हितों की अवधारणा को व्यक्त करते हैं तथा समूह के रूप में ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना पक्ष अधिक बेहतर और शक्तिशाली रूप में रख पाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के वार्ताकारों के संदर्भ में एलएमडीसी समूह में भारत के अतिरिक्त अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बोलिविया, चीन, क्यूबा, इक्वेडोर, मिस्र, अल सल्वाडोर, जॉर्डन, इराक, कुवैत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, माली, निकारागुआ, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला एवं विएतनाम शामिल हैं। ये विश्व की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत-प्रशांत द्वीपीय देश फोरम का शिखर सम्मेलन

- 21 अगस्त, 2015 को भारत-प्रशांत द्वीपीय देश सहयोग मंच (FIPIC : Forum for India-Pacific Islands Co-operation) का द्वितीय शिखर सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया।
- इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग फोरम का पहला शिखर सम्मेलन सुवा (फिजी) में नवंबर, 2014 में (प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान) संपन्न हुआ था।
- भारत-प्रशांत द्वीपीय देश सहयोग मंच के भारत के अतिरिक्त प्रशांत क्षेत्र के 14 छोटे द्वीपीय देश सदस्य हैं। ये हैं—फिजी, नौरू, किरिबाती, माइक्रोनेशिया, कुक आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु, तुवालू, नीयू, पलाऊ, समोआ एवं टोंगा।
- जयपुर शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपर्युक्त सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया।
- इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में नई दिल्ली में 'समुद्री अर्थव्यवस्था एवं प्रशांत द्वीपीय देश' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की घोषणा की तथा प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के विशेषज्ञों को इसमें भाग लेने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने इन 14 देशों में से एक में इसरो (ISRO) के साथ भागीदारी में एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (Space Application centre) स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय नौसेना द्वारा प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों की तटीय निगरानी व्यवस्था एवं हाइड्रोग्राफी में मदद का भी प्रस्ताव किया।
- प्रशांत द्वीपों के नेताओं ने इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन तथा इससे उनके देशों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर गहन चिंता व्यक्त की तथा भारत द्वारा इन चिंताओं को आगामी पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सम्यक रूप से उठाने का आश्वासन दिया गया। सभी 14 प्रशांत देशों द्वारा संशोधित संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपने समर्थन को दोहराया गया।

- नौरू के राष्ट्रपति द्वारा नौरू में समुद्र तट पर दीवार निर्माण (जलवायु परिवर्तन से उठते समुद्र स्तर से बचाव हेतु) में सहयोग हेतु भारत के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

'विकास हेतु वित्त' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2015

- 13-16 जुलाई, 2015 के दौरान इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में 'विकास हेतु वित्त पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (Third International Conference on Finance for Development) का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किया गया।
- उल्लेखनीय है कि इस शृंखला के प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन मॉन्टेरे (मेक्सिको) में 2002 में किया गया था जिसमें सतत विकास हेतु वित्तीयन के स्वरूप पर सहमति (Monterrey Consensus) बनी थी। इस क्रम में दूसरा शिखर सम्मेलन 2008 में दोहा (कतर) में आयोजित हुआ था।
- अदिस अबाबा सम्मेलन में 2015-पश्चात विकास एजेंडे के तहत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति हेतु आवश्यक वित्त की उपलब्धता पर व्यापक विमर्श हुआ तथा अंततः सतत विकास के वित्तीयन हेतु नया 'वैश्विक एक्शन एजेंडा' (Global Action Agenda) अपनाया गया।
- अदिस अबाबा एजेंडे में वैश्विक वित्तीयन प्रक्रियाओं में सुधार लाने तथा आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने हेतु निवेशों का सृजन करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण उपाय स्वीकृत किए गए हैं।
- यह एक्शन एजेंडा वित्तीयन के सभी स्रोतों के साथ प्रौद्योगिकी, विज्ञान, नवप्रवर्तन, व्यापार और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को भी कवर करता है।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास कांफ्रेंस (UNCTAD) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर 3.3 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक की लागत आने का आकलन व्यक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के ही एक अन्य अनुमान के अनुसार आगामी 15 वर्षों में नए लक्ष्यों के संदर्भ में 172.5 ट्रिलियन डॉलर (11.5 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष) तक की आवश्यकता होगी।
- अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर निवेशों के संवर्धन के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन के स्तर हेतु मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से स्वीकृत किया गया है जिसमें विकसित देशों द्वारा वित्तीय योगदान को बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी विकसित करने के लिए कहा गया है।
- विकास हेतु वित्त पर इस नए वैश्विक एक्शन एजेंडे को 27 जुलाई, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

सीडोक-2015 सम्मेलन

- नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 7 से 9 सितंबर, 2015 तक 'सीडोक-2015' सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला अवसर था जब सीडोक की बैठक भारतीय उपमहाद्वीप में सम्पन्न हुई। ध्यातव्य है कि सीडोक संग्रहालयों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद 'आइकॉम' के लिए प्रलेखन हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति है।
- 'विविधता का प्रलेख संग्रह, सूचीबद्धता एवं संदर्भ' विषय पर केंद्रित 'सीडोक-2015' सम्मेलन का आयोजन आइकॉम द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला, इतिहास संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान के सहयोग से किया गया।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रलेखन (वह प्रमुख प्रणाली जिसके द्वारा सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित किया जाता है) से जुड़े विश्व भर के पेशेवरों (Professionals) को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करना, उनके बीच बातचीत को सुगम बनाना, विविध सांस्कृतिक धरोहरों से संबंधित सूचनाओं का एकीकरण, आदान-प्रदान एवं मध्यस्थता था।
- इस सम्मेलन में 42 देशों के 230 से ज्यादा प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिसमें सीडोक के सदस्य, वैश्विक ख्याति के विद्वान तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल थे।

अंटार्कटिक भू विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

- 12 से 17 जुलाई, 2015 के दौरान गोवा में 'अंटार्कटिक भूविज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी' (ISAES : International Symposium on Antarctic Earth Sciences) के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया।
- इस अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय भू विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया।
- उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिक भू विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 1963 में केपटाउन में किया गया था तथा इसके भारत में आयोजित होने का यह पहला अवसर है। इससे पूर्व एशियाई देशों में अब तक केवल जापान द्वारा इसकी मेजबानी की गई है।
- 12वें आईएसएईएस के केंद्रीय विषयों में अंटार्कटिका और सुपरकॉन्टिनेंट इवॉल्यूशन, अंटार्कटिक सतह प्रक्रियाएं, लैंडस्केप एवं क्रायोस्फीयर और जलवायु के साथ संबंध, अंटार्कटिक भू संरचना एवं क्रायोस्फीयर के साथ अंतर्क्रियाएं, अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर और जलवायु आदि शामिल थे।
- इस अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन केंद्रीय अंटार्कटिक और समुद्र अनुसंधान संस्थान (NCAOR), गोवा द्वारा किया गया था।
- इस संगोष्ठी में लगभग 40 देशों के 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने भागीदारी की। ज्ञातव्य है कि आईएसएईएस का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है।
- 12 जुलाई, 2015 को ही डॉ. हर्षवर्धन द्वारा गोवा के वास्को-डि-गामा में एनसीएओआर की नई 'आइसोट्रेस लेबोरेटरी' का उद्घाटन किया गया जो कि अनुसंधान हेतु विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का उच्च गुणवत्ता स्थिर समस्थानिक विश्लेषण उपलब्ध कराएगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत के अंटार्कटिका में दो क्रियाशील स्थायी अनुसंधान केंद्र–'मैत्री' (1989 में स्थापित) और 'भारती' (2012 में स्थापित) हैं। भारत का प्रथम अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र 'दक्षिण गंगोत्री' (1983 में स्थापित) अब बर्फ में दबकर समाप्त हो चुका है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का शिखर सम्मेलन

- 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO) मूल रूप से 1996 में स्थापित 'शंघाई फाइव' का उत्तरवर्ती संगठन है जिसे 2001 में वर्तमान स्वरूप दिया गया था। इसके 6 सदस्य देश चीन, कजाख्स्तान, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान हैं जिनमें से उज्बेकिस्तान के अतिरिक्त शेष पांचों राष्ट्र शंघाई फाइव के भी सदस्य थे। इस संगठन का मुख्यालय बीजिंग (चीन) में है।
- 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO : Shanghai Cooperation Organization) का 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 9-10 जुलाई, 2015 के दौरान ऊफा (रूस) में आयोजित किया गया।
- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी एवं अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अलमाजबेक अतमबायेव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान, कजाख्स्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव एवं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी प्रतिभाग किया।
- इस सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मंगोलिया के राष्ट्रपति साखियाजिन एल्बेगदोर्ज, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आर्मेनिया के राष्ट्रपति सर्ज सर्गसियान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गरबांगुली मलिकगुलयेविक ने भी भागीदारी की।
- एससीओ के इस शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को इस संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर के साथ इन दोनों देशों के शामिल होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद भारत और पाकिस्तान (अब तक इन्हें एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था) अगले वर्ष से इस संगठन के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे।
- एससीओ के ऊफा शिखर सम्मेलन में बेलारूस को पर्यवेक्षक (Observer) दर्जा दिए जाने तथा अजरबैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया और नेपाल को वार्ता भागीदार (Dialogue Partner) बनाए जाने को भी स्वीकृति दी गई। ज्ञातव्य है कि एससीओ में भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त ईरान, मंगोलिया एवं अफगानिस्तान को पर्यवेक्षक का तथा तुर्की एवं श्रीलंका को वार्ता भागीदार का दर्जा पहले से प्राप्त है।
- एससीओ के इस शिखर सम्मेलन के अंत में सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित 'ऊफा घोषणापत्र' (Ufa Declaration) जारी किया गया। इस घोषणापत्र में सभी नेताओं ने एससीओ के तहत एक नए विकास बैंक और विकास कोष के सृजन हेतु कार्य जारी रखने की बात कही और साथ ही एससीओ के सदस्य देशों से होकर गुजरने वाले 'सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट' संबंधी चीन के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों द्वारा यूक्रेन के मुद्दे पर फरवरी, 2015 में हुए 'मिंस्क समझौते' के क्रियान्वयन और युद्ध विराम के माध्यम से शांति स्थापना का आह्वान किया गया। इसके अतिरिक्त सभी सदस्य देशों द्वारा सीरिया की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हुए यहां की समस्या के कूटनीतिक समाधान, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बढ़ाने एवं इस्लामिक स्टेट (IS) के विस्तार पर चर्चा के साथ चरमपंथ, राष्ट्रपारीय अपराधों, साइबर खतरों, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक आदि हेतु सम्मिलित प्रयास करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- ऊफा सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा सीमा सुरक्षा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा चरमपंथ का मुकाबला करने हेतु नई संधि तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- शंघाई शहयोग संगठन का अगला (16वां) शिखर सम्मेलन सितंबर, 2016 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया जाएगा और रूस के स्थान पर अब अगले सम्मेलन तक उज्बेकिस्तान इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है।

ब्रिक्स (BRICS) का सातवां शिखर सम्मेलन

- 8-9 जुलाई, 2015 के दौरान रूस के बाश्कोर्तोस्तान संघीय क्षेत्र के ऊफा (Ufa) शहर में ब्रिक्स (BRICS : ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) का सातवां शिखर सम्मेलन (7th BRICS Summit) आयोजित किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी एवं अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई तथा इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ ने प्रतिभाग किया।
- ब्रिक्स का सातवां शिखर सम्मेलन 'ब्रिक्स साझेदारी : वैश्विक विकास का एक शक्तिशाली कारक' (BRICS Partnership : a Powerful Factor of Global Development) के केंद्रीय विषय (Theme) के साथ आयोजित किया गया।
- ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सदस्य देशों के मध्य सहयोग की अभिवृद्धि हेतु निम्नलिखित 10 प्रस्ताव (जिन्हें 'दस कदम' की संज्ञा दी गई है) रखे गए—
  - (i) वार्षिक ब्रिक्स व्यापार मेले का आयोजन।
  - (ii) रेलवे शोध केंद्र की स्थापना।
  - (iii) ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का आयोजन।
  - (iv) ब्रिक्स डिजिटल पहल।
  - (v) ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना।
  - (vi) राज्यों एवं स्थानीय सरकारों का मंच।
  - (vii) वार्षिक ब्रिक्स खेल प्रतियोगिता एवं ब्रिक्स स्पोर्ट्स काउंसिल।
  - (viii) इन देशों के शीर्ष ऑडिट संस्थानों के मध्य सहयोग।
  - (ix) शहरों के मध्य सहयोग।
  - (x) नवस्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रथम प्रमुख परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हो।
- ब्रिक्स के सातवें शिखर सम्मेलन में व्यापक प्रतिनिधिमंडल

स्तरीय विचार-विमर्श के पश्चात 9 जुलाई, 2015 को सदस्य देशों द्वारा 'ऊफा घोषणापत्र' (Ufa Declaration), 'आर्थिक सहयोग हेतु रणनीति' (Strategy for Economic Cooperation) तथा 'ऊफा कार्य योजना' (Ufa Action Plan) पर हस्ताक्षर किए गए।

- ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसियों (ECAs) की वार्षिक बैठक आयोजित किए जाने पर भी सहमति हुई तथा ब्रिक्स ईसीए की प्रथम बैठक इसी सम्मेलन के दौरान संपन्न हुई।
- ऊफा सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के नए वित्तीय संस्थानों- 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (NDB) और 'आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था' (CRA: Contingency Reserve Arrangement) की स्थापना हेतु गत वर्ष फोर्टालेजा (ब्राजील) में छठें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए समझौतों के लागू होने की घोषणा की गई।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा अप्रैल, 2016 से ब्रिक्स देशों की अपनी स्थानीय मुद्राओं में ऋण उपलब्ध कराए जाने का निश्चय सदस्य देशों द्वारा किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थापित किया गया है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रख्यात बैंकर के.वी. कामथ हैं।
- ब्रिक्स का अगला (8वां) शिखर सम्मेलन 2016 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में फरवरी, 2016 में भारत को रूस से ब्रिक्स की अध्यक्षता हस्तांतरित होगी तथा भारत दिसंबर, 2016 तक (कुल 11 माह) इस समूह का अध्यक्ष रहेगा। ज्ञातव्य है कि 2017 से ब्रिक्स का कैलेंडर वार्षिक कैलेंडर के अनुरूप हो जाएगा।

जी-7 का 41वां शिखर सम्मेलन

- 7-8 जून, 2015 के दौरान विश्व के 7 शीर्ष औद्योगिक एवं विकसित देशों तथा यूरोपीय संघ के समूह जी-7 (G-7 : Group of Seven) का 41वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जर्मनी के बावेरिया स्थित स्कलॉस एल्मू (Schloss Elmau) में आयोजित किया गया। यह रूस के बगैर इस समूह का 24वां शिखर सम्मेलन था।
- जी-7 का 40वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 4-5 जून, 2014 के दौरान ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में आयोजित किया गया था।
- जी-7 के 41वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा की गई तथा इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस ओलांडे, इटली के प्रधानमंत्री मैट्टियो रेंजी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने प्रतिभाग किया। इस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन-क्लॉड जंकर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क द्वारा किया गया।
- शिखर सम्मेलन के अंत में जी-7 समूह के सभी नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित 'स्कलॉस एल्मू घोषणापत्र' जारी किया गया। इसमें रूस द्वारा यूक्रेन की संप्रभुता में जारी हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की गई तथा एकजुट होकर रूस के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों को जारी रखने की बात कही गई। इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के अतिरिक्त अन्य वैश्विक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई जिसमें ग्रीस का ऋण संकट, आईएस के बढ़ते प्रसार और सीरियाई गृहयुद्ध, यमन संकट, दक्षिण एवं पूर्वी चीन सागर, ईरान आदि के मुद्दे प्रमुख थे।
- इस सम्मेलन में जी-7 समूह के नेताओं ने वैश्विक स्तर पर इस शताब्दी के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आधा करने का संकल्प लिया तथा तदनुसार 2010 के स्तर के मुकाबले इसके स्तर में 40-70 प्रतिशत तक कटौती करने का लक्ष्य तय किया गया है। जी-7 के नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए गरीब देशों की संसाधन और धन से सहायता करने पर भी सहमति जताई।
- जी-7 का अगला (42वां) शिखर सम्मेलन जापान के काशिको द्वीप में स्थित शीमा (Shima) में आयोजित किया जाएगा।

एशिया-अफ्रीका संस्मारक सम्मेलन, 2015

- 22 अप्रैल, 2015 को इंडोनेशिया के बांडुंग (Bandung) में वर्ष 1955 के ऐतिहासिक एशिया-अफ्रीका सम्मेलन (बांडुंग सम्मेलन) की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्मारक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा लगभग 80 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1955 में बांडुंग में ही एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिससे अंततः गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की नींव पड़ी थी। 1955 के बांडुंग सम्मेलन के आयोजन में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उच्च-पर्वतीय एशिया में ग्लेशियर विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- 10 से 6 मार्च, 2015 के दौरान काठमांडू (नेपाल) में 'उच्च पर्वतीय एशिया में ग्लेशियर विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा एकीकृत पर्वत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICIMOD) तथा नेपाल सरकार एवं वहां के काठमांडू एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया गया।
- इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत एशिया के उच्च-पर्वतीय क्षेत्र में ग्लेशियरों में वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों के साथ-साथ उनमें पहले हो चुके और भावी परिवर्तनों एवं तत्संबंधी निरीक्षणों पर विशद चर्चा की गई तथा ग्लेशियर डायनामिक्स (हिमनद गतिकी) पर भी महत्त्वपूर्ण अध्ययन और शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।

◆◆◆

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

● भारतीय राष्ट्रपति की पश्चिम एशिया यात्रा ● जर्मन चांसलर की भारत यात्रा ● प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ● प्रधानमंत्री मोदी की आयरलैंड यात्रा ● श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ● सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ● प्रधानमंत्री मोदी की मध्य एशिया यात्रा ● प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा ● मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ● तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ● प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा ● नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ● भारतीय राष्ट्रपति की स्वीडन और बेलारूस यात्रा ● प्रधानमंत्री मोदी की चीन, मंगोलिया और द. कोरिया यात्रा ● भारतीय राष्ट्रपति की रूस यात्रा ● प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा ● अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ● भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा ● भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा

भारतीय राष्ट्रपति की पश्चिम एशिया यात्रा

- भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 10-15 अक्टूबर, 2015 के दौरान मध्य एशिया के तीन देशों (जॉर्डन, फिलीस्तीन और इजरायल) की राजकीय यात्रा पर रहे।
- यह इन देशों के लिए किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्राएं थीं।
- भारतीय राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं शैक्षणिक शिष्टमंडल भी इस यात्रा पर गया था।
- अपनी इस पश्चिम एशिया यात्रा के प्रथम चरण (10-12 अक्टूबर) में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 10 अक्टूबर को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे जहां औपचारिक स्वागत के बाद उनकी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एनसौर के साथ द्विपक्षीय संबंधों और पारस्परिक महत्त्व के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई।
- इन वार्ताओं में दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में नई सहक्रियता की संभावना तलाशी। शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी और संयुक्त राष्ट्र संशोधन प्रक्रिया का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ जॉर्डन की आईसीटी कंपनियों के कार्य करने को बढ़ावा देने की इच्छा भी जताई।
- राष्ट्रपति मुखर्जी और शाह अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा इशिदिया शहर में जॉर्डन-भारत फर्टिलाइजर कंपनी (भारत के इफ्को और जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी का संयुक्त उपक्रम) द्वारा 860 मिलियन डॉलर की लागत से निर्मित विश्व के सबसे बड़े फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया। यह संयंत्र भारत को निर्यात करने हेतु फॉस्फोरिक एसिड तैयार करेगा।
- शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत को फॉस्फेट की आपूर्ति हेतु दीर्घावधिक व्यवस्था में शामिल होने तथा फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और डीएपी (डाई अमोनियम फॉस्फेट) की मांग को पूरा करने हेतु और संयुक्त उपक्रम स्थापित किए जाने की इच्छा जताई।
- भारत द्वारा परियोजना सहायता के लिए जॉर्डन को 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई और साथ ही भारत ने क्वीन जॉर्डन (क्वीन रानिया) ट्रस्ट को 1 लाख दिनार (लगभग 91.71 लाख रु.) दानस्वरूप भी दिए। भारत ने जॉर्डन में क्षमता निर्माण के क्षेत्र में 200 प्रशिक्षण संस्थानों में स्कॉलरशिप को बढ़ाने हेतु आईटीईसी स्लॉट की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करने की भी घोषणा की।
- 11 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुखर्जी ने अम्मान में महात्मा गांधी के नाम पर एक मार्ग का उद्घाटन किया। यहां सदजाग्लौल (ये जॉर्डन की शांतिपूर्ण क्रांति के नेता थे जो गांधीजी के समय सक्रिय थे) मार्ग के एक भाग का नाम महात्मा गांधी मार्ग रखा गया है। राष्ट्रपति मुखर्जी ने यहां शांति पार्क में जैतून का पौधा भी लगाया।
- भारतीय राष्ट्रपति ने अम्मान में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित किया। उन्हें जॉर्डन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई।
- भारतीय राष्ट्रपति की इस जॉर्डन यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 6 महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन (देखें- बॉक्स) हस्ताक्षरित हुए तथा इनके अतिरिक्त दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के मध्य सहयोग हेतु 10 अन्य समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

1. समुद्रीय परिवहन (Maritime Transport) पर करार।
2. भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान (FSI) और जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी (JID) के मध्य समझौता ज्ञापन।
3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
4. 2015-17 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम।
5. मानकीकरण एवं अनुरूपता आकलन (Standardization and Conformity Asessment) के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
6. जॉर्डन न्यूज एजेंसी (Petra) और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के बीच सहयोग करार।

- ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रपति की इस जॉर्डन यात्रा से पूर्व 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जॉर्डन की यात्रा की थी तथा जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और क्वीन रानिया 2006 में भारत आए थे।
- जॉर्डन के बाद अपनी इस पश्चिम एशिया यात्रा के द्वितीय चरण

(12-13 अक्टूबर, 2015) में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 12 अक्टूबर को फिलीस्तीन की प्रशासनिक राजधानी रामल्लाह (Ramallah) पहुंचे जहां उनका फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री डॉ. रामी हमदल्लाह और वहां के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

- 13 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रपति और फिलीस्तीनी राष्ट्रपति के मध्य पारस्परिक हित के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई।
- राष्ट्रपति अब्बास ने इजरायल-फिलीस्तीन संबंधों की स्थिति के बारे में बताते हुए फिलीस्तीन मामले के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। भारतीय राष्ट्रपति ने फिलीस्तीन के प्रति भारत के पूर्ण समर्थन पर जोर देते हुए बातचीत के जरिए मध्य-पूर्व (ध्यातव्य है कि पश्चिमी एशिया को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में मध्य-पूर्व के रूप में अभिहित किया जाता है) समस्या का समाधान निकालने की अपील की ताकि पूर्वी यरूशलम राजधानी के साथ संप्रभु और संयुक्त फिलीस्तीन राष्ट्र का निर्माण क्वार्टेट (Quartet) रोडमैप और संयुक्त सुरक्षा परिषद के तत्संबंधी प्रस्तावों कें अनुरूप सुरक्षित एवं मान्य सीमाओं तथा इजरायल के साथ शांति के साथ हो सके।
- राष्ट्रपति मुखर्जी ने फिलीस्तीन के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्तियों को 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिवर्ष और आईटीईसी स्लॉट को 50 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। भारत द्वारा फिलीस्तीनी प्राधिकरण को बजटीय सहायता अनुदान के रूप में 5 मिलियन डॉलर भी प्रदान किए गए।
- भारत द्वारा फिलीस्तीन में 17.79 मिलियन डॉलर के परिवयय से कुल 5 परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई। इनमें शामिल हैं—रामल्लाह में टेक्नो पार्क की स्थापना (12 मिलियन डॉलर); फिलीस्तीन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी की स्थापना (4.5 मिलियन डॉलर); गाजा में आईसीटी एवं नवप्रवर्तन में भारत-फिलीस्तीन उत्कृष्टता केंद्र (1 मिलियन डॉलर); पश्चिमी तट के बिर्जीट (Birzeit) विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मध्य पीएचडी कार्यक्रम में सहयोग (21,670 डॉलर); तथा अल-कुद्स (Al-Quds) विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना (2.68 मिलियन डॉलर)।
- भारतीय राष्ट्रपति ने रामल्लाह में यासर अराफात के मकबरे तथा गार्डन ऑफ नेशंस में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उन्होंने राष्ट्रपति अब्बास के साथ 'मैदान अल-हिंद' (भारतीय परिपथ) और 'शेरेपा अल-हिंद' (भारतीय सड़क) का भी उद्घाटन किया।
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अल-कुद्स विश्वविद्यालय में भारत-फिलीस्तीन आईसीटी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया तथा इस विश्वविद्यालय में उन्होंने भारतीय अध्ययन पीठ स्थापित करने की घोषणा की। अल-कुद्स विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति मुखर्जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। राष्ट्रपति मुखर्जी ने अबू दीस (Abu Dees) में लड़कों के लिए जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल का भी उद्घाटन किया।
- भारतीय राष्ट्रपति की इस फिलीस्तीन यात्रा के दौरान कुल 6 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए (देख- बॉक्स)।

भारत एवं फिलीस्तीन के मध्य हुए समझौता ज्ञापन

1. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और फिलीस्तीनी संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।
2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बिर्जीट विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।
3. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अल नजाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।
4. जामिया मिलिया इस्लामिया और अल कुद्स विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।
5. जामिया मिलिया इस्लामिया और अल इस्तिकलल विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।
6. जामिया मिलिया इस्लामिया और हेब्रान विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।

- अपनी इस पश्चिम एशिया यात्रा के तृतीय चरण (13-15 अक्टूबर, 2015) में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 13 अक्टूबर को इजरायल की राजधानी येरूशलम (Jerusalem) पहुंचे।
- ज्ञातव्य है कि इजरायल के साथ भारत के राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे।
- राष्ट्रपति मुखर्जी का इजरायल में राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन (Reuven Rivlin), प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) तथा वहां की संसद 'नेसेट' (Knesset) के अध्यक्ष यूली-योएल इदेलस्ताइन (Yuli-Yoel Edelstein) ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
- राष्ट्रपति मुखर्जी ने इजरायली राष्ट्रपति रिवलिन के साथ माउंट हर्जल जाकर होलोकॉस्ट अनुसंधान हेतु वैश्विक केंद्र, याद वाशेम (Yad Vashem) में होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्होंने यहूदीवाद (Zionism) के राजनीतिक पिता थियोडोर हर्जल के मकबरे पर भी पुष्पचक्र अर्पित किया। राष्ट्रपति मुखर्जी ने येरूशलम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया।
- 14 अक्टूबर को वहां के राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रपति का औपचारिक समारोहपूर्वक स्वागत किया गया जिसके बाद दोनों पक्षों के मध्य पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
- द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने अपने बहुपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा पारस्परिक लाभ के लिए इन संबंधों को और आगे बढ़ाने के तौर-तरीकों पर भी मंत्रणा की। दोनों पक्षों ने रक्षा उपकरणों और प्लेटफॉर्म सिस्टम में साझेदारी, सौर ऊर्जा, डेयरी विकास, जल प्रबंधन, बागवानी, पशुपालन, कृषि और सिंचाई तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। भारतीय राष्ट्रपति ने भारत की नई पहलों (यथा- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ गंगा, स्मार्ट शहर, स्टार्टअप

इंडिया आदि) के संदर्भ में इजरायल से भारत में निवेश बढ़ाने का आह्वान भी किया।

- 14 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति मुखर्जी ने इजरायल की संसद 'नेसेट' को संबोधित किया।
- 15 अक्टूबर को येरूशलम के प्रतिष्ठित हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया जो कि उनकी इस पश्चिम एशिया यात्रा के दौरान उन्हें दी गई ऐसी तीसरी उपाधि थी।
- राष्ट्रपति मुखर्जी इजरायल के तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास भी गए जहां उन्होने भारतीय समुदाय के एक आयोजन में प्रतिभाग किया।
- भारतीय राष्ट्रपति की इस इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारों के मध्य शासकीय स्तर पर 2 करार तथा दोनों देशों की शैक्षणिक संस्थाओं के बीच 8 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए (देखें बॉक्स)।

भारत एवं इजरायल के बीच हुए करार/समझौता ज्ञापन

A. शासकीय करार

1. आय और पूंजी पर करों के संदर्भ में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम और दोहरे कराधान के परिहार हेतु प्रोटोकॉल एवं अभिसमय के संशोधन के लिए प्रोटोकॉल।
2. 2015-2018 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम।

B. शैक्षणिक समझौता ज्ञापन

3. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और बेन-गरिऑन विश्वविद्यालय (BGU), नेगेव के मध्य समझौता ज्ञापन।
4. आईआईटी खड़गपुर और हिब्रू विश्वविद्यालय के बीच सहयोग करार।
5. सांस्थानिक सहयोग हेतु आईआईटी खड़गपुर और बीजीयू के बीच समझौता ज्ञापन।
6. जेएनयू और हिब्रू विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन।
7. आईआईटी खड़गपुर और हाइफा (Haifa) विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग हेतु फ्रेमवर्क)।
8. दिल्ली विश्वविद्यालय और बीजीयू के बीच समझौता ज्ञापन।जर्मन चांसलर की भारत यात्रा

जर्मन चांसलर की भारत यात्रा

- 4-6 अक्टूबर, 2015 के दौरान जर्मनी की चांसलर (शासनाध्यक्ष) डॉ. एंजेला मर्केल एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12-14 अप्रैल, 2015 के दौरान जर्मनी की यात्रा पर रहे थे।
- जर्मन चांसलर मर्केल की सद्यः भारत-यात्रा <u>तृतीय भारत-जर्मनी अंतर्सरकारी परामर्श</u> (IGC : Intergovernmental Consultations) के संदर्भ में हुई। भारत और जर्मनी के मध्य शीर्ष नेतृत्व स्तर पर प्रथम अंतर्सरकारी परामर्श मई, 2011 में नई दिल्ली में तथा द्वितीय अंतर्सरकारी परामर्श अप्रैल, 2013 में बर्लिन में आयोजित किया गया था।
- 4 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली पहुंची जर्मन चांसलर मर्केल का अगले दिन (5 अक्टूबर को) प्रातः राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया जिसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
- 5 अक्टूबर को ही भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चांसलर मर्केल से मुलाकात की और तत्पश्चात नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चांसलर मर्केल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों नेताओं ने गहन चर्चा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ तृतीय भारत-जर्मनी अंतर्सरकारी परामर्श (IGC) में प्रतिभाग किया।
- भारत-जर्मनी अंतर्सरकारी परामर्श के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत और जर्मनी के मध्य रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की जिसके तहत दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए संपूरकताओं तथा विदेश एवं सुरक्षा मुद्दों पर बढ़ते अभिसरण को सुदृढ़ किया जाएगा।
- अंतर्सरकारी परामर्श के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदार के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास की मौजूदा एवं उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए जी-20, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य बहुपक्षीय मंचों पर निकट समन्वय की प्रतिबद्धता जताई।
- दोनों पक्षों ने आतंकवाद और उग्रवाद के बढ़ते खतरे तथा इनकी वैश्विक पहुंच को लेकर अपनी चिंता साझा की तथा इन चुनौतियों से निपटने हेतु वे मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए। दोनों देशों द्वारा आतंकवाद निरोधक कार्रवाई पर संयुक्त कार्यसमूह की नियमित बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
- जर्मनी ने विभिन्न निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), ऑस्ट्रेलिया समूह एवं वास्सेनार व्यवस्था के साथ भारत की गहन भागीदारी का स्वागत करते हुए माना कि मिसाइल प्रसार के विरुद्ध हेग आचार संहिता जैसी पहलों में भारत की भागीदारी से इसकी कारगरता सुदृढ़ होगी।
- दोनों पक्षों ने भारत में जर्मनी की सहायता (विगत दो वर्षों में 1.15 बिलियन यूरो) से प्रारंभ 'हरित ऊर्जा कॉरिडोर' परियोजना के सफल कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया जिसका विस्तार 400 मिलियन यूरो से किया गया है। इस संदर्भ में जर्मनी के साथ 125 मिलियन यूरो के दो ऋण समझौते (हिमाचल प्रदेश हेतु 57 मिलियन यूरो एवं आंध्र प्रदेश हेतु 68 मिलियन यूरो के) भी हस्ताक्षरित हुए।
- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 'मेक इन इंडिया' के संदर्भ में भारत में जर्मन कंपनियों द्वारा निवेश को गति प्रदान करने हेतु एक पृथक निकाय स्थापित करने की घोषणा की गई।
- दोनों पक्षों द्वारा पेरिस में आयोजित होने वाले COP-21 में व्यापक और साम्यपूर्ण जलवायु परिवर्तन करार पर पहुंचने हेतु अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने अलग से जारी 'जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर

संयुक्त वक्तव्य' के तहत अपने साझे विजन और सहयोगात्मक कार्य को रेखांकित किया।

- वे दोहा चक्र के विकास संबंधी अधिदेश के अनुसरण में दिसंबर, 2015 में नैरोबी (केन्या) में होने वाले 10वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सारवान परिणाम प्राप्त करने हेतु निकटता से कार्य करने पर सहमत हुए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने ऊपरी गंगा नदी घाटी में एक परियोजना के लिए जर्मनी की प्रारंभ में 120 मिलियन यूरो का योगदान करने की मंशा का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य गंगा नदी घाटी के चुनिंदा शहरों में पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाना है।
- जर्मन चांसलर द्वारा जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से दो दशक पूर्व लापता हुई दसवीं शती ई. की मां दुर्गा (महिषासुरमर्दिनी) की दुर्लभ प्रतिमा भारतीय प्रधानमंत्री को वापस सौंपी गई।
- भारत-जर्मन अंतर्सरकारी परामर्श के पश्चात दोनों पक्षों द्वारा निम्नलिखित 18 करारों/समझौता ज्ञापनों (MOUs) पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें 14 शासकीय स्तर पर तथा शेष 4 दोनों देशों की संस्थाओं के मध्य हुए (देखें- बॉक्स)।
- उल्लेखनीय है कि समझौता वार्ताओं के दौरान भारत ने कुछ सब्जियों और फलों के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाई गई रोक का मुद्दा भी उठाया।
- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में जर्मनी के एकीकरण (1990) की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जर्मनी को अपनी बधाई भी प्रेषित की गई।
- 5 अक्टूबर की शाम को ही चांसलर मर्केल ने भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की जिसके बाद वे बंगलुरू के लिए रवाना हो गईं।
- 6 अक्टूबर, 2015 को बंगलुरू में चांसलर मर्केल जर्मनी द्वारा स्थापित राबर्ट बोश (Robert Bosch) इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर के अवलोकन हेतु गईं जहां उनकी अगवानी स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री ने की।
- इसके पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बंगलुरू के होटल लीला पैलेस में नास्कॉम और फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित व्यावसायिक फोरम '<u>भारत-जर्मनी शिखर सम्मेलन, 2015 : डिजिटाइजिंग टुमारो-टुगेदर</u>' में भाग लिया। इस व्यापार बैठक में जर्मन चांसलर ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते हेतु वार्ता बहाल करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक-दूसरे देश में अवसरों में वृद्धि होगी। इस बैठक के दौरान मोदी एवं मर्केल की उपस्थिति में दोनों देशों की कंपनियों के मध्य पांच बी2बी समझौतों की भी घोषणा हुई।

भारत और जर्मनी के मध्य हस्ताक्षरित करार/एमओयू

<u>A. शासकीय स्तर पर</u>

1. भारत में एक विदेशी भाषा के रूप में जर्मन को बढ़ावा देने तथा जर्मनी में आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन हेतु संयुक्त मंशा घोषणा (भारत के केंद्रीय विद्यालयों में अब अतिरिक्त विदेशी भाषा के तौर पर जर्मन पढ़ाई जाएगी)।
2. भारत सरकार और जर्मन सरकार के बीच विकास सहयोग पर वार्ता का सारांश रिकॉर्ड (जर्मनी द्वारा भारत की विकास परियोजनाओं हेतु 1.490 बिलियन यूरो की नई प्रतिबद्धता घोषित की गई है)।
3. भारत-जर्मनी सौर ऊर्जा साझेदारी के संबंध में विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU)।
4. कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त एमओयू।
5. सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
6. विमानन सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन।
7. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त मंशा घोषणा।
8. भारत-जर्मनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (IGSTC) के कार्यकाल विस्तार हेतु संयुक्त घोषणा।
9. उच्च शिक्षा में भारत-जर्मनी साझेदारी (IGP) पर समझौता ज्ञापन।
10. पादप संरक्षण उत्पादों पर संयुक्त मंशा घोषणा।
11. रेलवे क्षेत्र में सहयोग के और विकास पर संयुक्त मंशा घोषणा।
12. विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
13. भारत में जर्मनी की कंपनियों के लिए एक फास्ट-ट्रैक प्रणाली की स्थापना पर संयुक्त घोषणा (इसके तहत जर्मन कंपनियों को परियोजनाओं के लिए एकल बिंदु अनुमति सुविधा दी जाएगी)।
14. भारत से कॉर्पोरेट एक्जीक्यूटिवों एवं कनिष्ठ एक्जीक्यूटिवों के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर संयुक्त घोषणा।

<u>B. दोनों देशों की संस्थाओं के मध्य</u>

15. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एसेसमेंट (BFR) के मध्य खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर संयुक्त मंशा वक्तव्य।
16. एफएसएसएआई और जर्मनी के फेडरल ऑफिस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फूड सेफ्टी (BVL) के मध्य खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर संयुक्त मंशा वक्तव्य।
17. भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) और जर्मन एग्रीबिजनेस एलाएंस के मध्य कृषि अध्ययन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
18. भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और जर्मनी की लिनडाऊ (Lindau) नोबेल समादृत परिषद एवं फाउंडेशन के मध्य लिनडाऊ नोबेल समादृत बैठकों हेतु प्राकृतिक विज्ञानों में भारत के युवा वैज्ञानिकों की भागीदारी पर मंशा पत्र।

प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा

- 23-28 सितंबर, 2015 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर रहे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं वर्षगांठ से संबद्ध महत्त्वपूर्ण आयोजनों में प्रतिभाग के साथ-साथ बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना भी था।
- 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र पर गोलमेज बैठक से प्रारंभ हुए जिसमें उन्होंने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) से भारत में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया तथा 'मेक इन इंडिया' अभियान में भागीदारी की अपील की। इस बैठक में जेपी मॉर्गन के चेयरमैन एवं सीईओ जेमी डेमॉन, ब्लैक स्टोन के सह-संस्थापक एवं चेयरमैन स्टीव स्वार्जमैन, जनरल अटलांटिक के सीईओ बिल फोर्ड और एआईजी के प्रेसीडेंट पीटर हैंकाक सहित अमेरिकी उद्योग एवं निवेश जगत के अनेक दिग्गज शामिल थे।
- इसके पश्चात प्रधानमंत्री मोदी ने 'मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन : ग्रोथ स्टोरी फॉर इंडिया' विषय पर आयोजित गोलमेज बैठक में प्रतिभाग किया जिसका आयोजन प्रमुख रूप से मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक की न्यूज कॉर्पोरेशन ने किया था और इसमें अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों के सीईओ भी शामिल थे।
- 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, गुयाना के राष्ट्रपति डेविड ए. ग्रेंजर तथा सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डॉ. राल्फ गोंजाल्विस से भी मुलाकात की और उन्होंने कई अन्य व्यवसाय जगत के प्रतिनिधियों से भी भेंट की।
- 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला II, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम, सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री केनी डेविस एंटनी, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस एनेस्टेसिएडस से मुलाकात की।
- 25 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत आयोजित 'सतत विकास शिखर सम्मेलन' (इस सम्मेलन का विस्तृत विवरण इसी अंक में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन खंड में देखें) में प्रतिभाग किया जिसका आयोजन 2015-पश्चात विकास एजेंडे को औपचारिक रूप से अपनाए जाने हेतु किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में संबोधन दिया जिसमें उन्होंने सतत विकास के लिए विकसित देशों से आगे आने तथा जलवायु परिवर्तन पर अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने 'क्लाइमेट चेंज' से निपटने हेतु 'क्लाइमेट जस्टिस' की बात की तथा कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें जीवनशैली में बदलाव लाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी बल दिया ताकि इसकी विश्वसनीयता और औचित्य बना रहे। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया और ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए जाने पर बल दिया।
- 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावेदार देशों के समूह 'जी-4' की शिखर बैठक की मेजबानी की (इसका विस्तृत विवरण भी इसी अंक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन खंड में देखें) तथा उसके बाद वे सैन जोस (कैलिफोर्निया) गए जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और फिर वे टेस्ला मोटर्स के अवलोकन हेतु गए।
- सैन जोस (यह सिलिकॉन वैली का मुख्य शहर है तथा इसे सिलिकॉन वैली की राजधानी कहा जाता है) में प्रधानमंत्री मोदी ने एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, क्वालकॉम के पॉल जैकब्स, सिस्को के जॉन चैंबर्स, एडोब के सीईओ एवं प्रेसीडेंट शांतनु नारायण तथा इंडस एंटरप्रेन्योर्स के प्रेसीडेंट वेंक शुक्ला सहित सिलिकॉन वैली की अनेक प्रमुख आईटी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और इन सभी के साथ 'डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी डिनर' में उन्होंने भागीदारी की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 'डिजिटल इंडिया' के संदर्भ में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की अपील करते हुए आईटी कंपनियों को डाटा गोपनीयता एवं सुरक्षा के प्रति भी आश्वस्त किया। ज्ञातव्य है कि गूगल द्वारा भारत में 400 रेलवे स्टेशनों को निःशुल्क वाई-फाई से लैस करने (रेल टेल के साथ साझेदारी में इसका प्रारंभ मुंबई सेंट्रल से किया गया है) तथा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 5 लाख गांवों में सस्ता इंटरनेट पहुंचाने में सहायता की घोषणा की गई है जबकि क्वालकॉम द्वारा डिजिटल इंडिया लैब और एप्पल एवं फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों द्वारा भारत में विनिर्माण संयंत्र की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई है।
- अपने सैन जोस प्रवास के दूसरे दिन 27 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी हैकर स्क्वायर स्थित फेसबुक मुख्यालय गए जहां फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे गूगल के ऑफिस पहुंचे जहां सीईओ सुंदर पिचाई के अतिरिक्त गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज भी उपस्थित थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल अर्थ पर पटना के निकट 'खगौल' (जहां खगोलविद् आर्यभट्ट की वेधशाला थी) को दिखाने की गुजारिश की।
- 27 सितंबर को ही सैन जोस में प्रधानमंत्री मोदी ने नास्कॉम के समन्वय से आयोजित 'इंडिया-यूएस स्टार्टअप कनेक्ट, 2015' को संबोधित किया। भारत की कई प्रमुख स्टार्टअप कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी इसमें उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री

मोदी की इस यात्रा के दौरान ही क्वालकॉम द्वारा भारत में स्टार्टअप कंपनियों के वित्तपोषण हेतु 150 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई।

- इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सैन जोस के सैप सेंटर में भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने 'जैम' (J–जनधन योजना; A–आधार विशिष्ट पहचान; M–मोबाइल गवर्नेंस) से भ्रष्टाचार में कमी आने का भी उल्लेख किया। उसी दिन उन्होंने वापस न्यूयॉर्क प्रस्थान किया।
- 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस ओलांडे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। इन मुलाकातों में तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपने समर्थन का आश्वासन देने के साथ भारत को चार आयात नियंत्रक निकायों का सदस्य बनने सहित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का सदस्य बनने में समर्थन देने की भी बात कही। भारतीय प्रधानमंत्री तथा अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर्थिक एवं सुरक्षा के मुद्दों सहित रक्षा खरीद पर भी गहन विचार-विमर्श किया और साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिसंबर, 2015 से दिल्ली-सैनफ्रांसिस्को के बीच एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन चलाए जाने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर, मेक्सिको के राष्ट्रपति तथा फिलीस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।
- 28 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने 'संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक सम्मेलन' में भी प्रतिभाग किया (इस सम्मेलन का विस्तृत विवरण भी इसी अंक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन खंड में देखें)।

प्रधानमंत्री मोदी की आयरलैंड यात्रा

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर, 2015 को यूरोप के उत्तरी अटलांटिक स्थित द्वीपीय देश आयरलैंड की यात्रा संपन्न की।
- यह विगत 59 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आयरलैंड यात्रा थी।
- आयरलैंड की राजधानी डबलिन की गवर्नमेंट बिल्डिंग में आयरिश प्रधानमंत्री एंडा केनी (Enda Kenny) ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश भारत के दो आयरिश अधिकारियों—थॉमस ओल्डहैम (इन्होंने मार्च, 1851 में भारत के भूगर्भ सर्वेक्षक का पदभार संभाला था) तथा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन (इन्होंने 1898 में भारत का प्रथम भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया था) से संबंधित लेखों और पांडुलिपियों की प्रतिकृतियां आयरिश प्रधानमंत्री को भेंट की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी, संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित एक विशिष्ट हस्तशिल्प कृति भी भेंट की जो कि शैमरॉक (एक प्रकार का मोमबत्ती स्टैंड) का आयरिश प्रतीक है। प्रधानमंत्री केनी ने भारतीय प्रधानमंत्री को आयरलैंड क्रिकेट टीम की जर्सी और एक 'हर्लिंग किट' (हर्लिंग आयरलैंड के प्रमुख खेलों में से एक है) उपहारस्वरूप प्रदान किया।
- दोनों नेताओं के मध्य वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों को संदर्भित करते हुए गुरुवर रबींद्रनाथ टैगोर और महान आयरिश कवि डब्ल्यू.बी. यीट्स की मित्रता का उल्लेख किया।
- दोनों पक्षों ने आतंकवाद एवं कट्टरवाद सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और यूरोप एवं एशिया की परिस्थितियों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्धारित समय-सीमा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सदस्यता हेतु आयरलैंड से समर्थन की मांग की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने डबलिन में भारतीय समुदाय की एक बैठक को भी संबोधित किया। आयरलैंड में संस्कृति की शिक्षा देने वाले जॉन स्कॉटिश स्कूल के 20 आयरिश छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में संस्कृत श्लोकों का गायन किया।
- इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी की पुष्टि की।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

- 14-16 सितंबर, 2015 के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर रहे।
- उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2015 में संपन्न श्रीलंका के संसदीय चुनाव के बाद वे पुनः वहां के प्रधानमंत्री (चौथी बार) बने हैं तथा शपथ ग्रहण के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी जो कि श्रीलंका द्वारा भारत के साथ प्रगाढ़ पारस्परिक संबंधों को दिए जाने वाले महत्त्व को प्रदर्शित करता है।
- इससे पूर्व श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने भी अपने निर्वाचन के पश्चात पहली राजकीय यात्रा 15-18 फरवरी, 2015 के दौरान भारत की ही संपन्न की थी तथा इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 मार्च, 2015 के मध्य श्रीलंका की यात्रा पर रहे थे।
- 14 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे श्रीलंकाई प्रधानमंत्री की अगले दिन हैदराबाद हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके बाद दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुए—

(i) दक्षेस (SAARC) क्षेत्र के लिए उपग्रह के कक्षा आवृत्ति समन्वय (Orbit Frequency Co-ordination) पर भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय करार।

(ii) स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, धर्मस्व न्यासों तथा शिक्षा एवं व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से श्रीलंका में लघु विकास परियोजनाओं (SDP) के क्रियान्वयन हेतु भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में एमओयू का नवीनीकरण।

(iii) वावुनिया (श्रीलंका) के डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों के वॉर्ड हेतु चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में एमओयू।

(iv) श्रीलंका में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं की स्थापना पर पत्रों का आदान-प्रदान।

- अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भारतीय विदेश मंत्री, रेल मंत्री एवं वित्त मंत्री सहित कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।
- इससे पूर्व श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की भारत यात्रा के दौरान 16 फरवरी, 2015 को भारत और श्रीलंका के मध्य निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हस्ताक्षरित हुए थे—

(i) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों में सहयोग के लिए करार (नागरिक परमाणु सहयोग के संदर्भ में श्रीलंका द्वारा किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला समझौता)।

(ii) वर्ष 2015-2018 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम।

(iii) नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में श्रीलंका की भागीदारी हेतु समझौता ज्ञापन।

(iv) कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन के तहत 2014-15 कार्ययोजना।

सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- हिंद महासागर स्थित अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स माइकल 25-27 अगस्त, 2015 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा पर रहे।
- वे इसके पहले वर्ष 2005 एवं 2010 में राजकीय यात्रा पर तथा 2011 एवं 2012 में दिल्ली सतत विकास सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत आए थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 मार्च, 2015 को सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर रहे थे जो कि वर्ष 1981 के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई सेशेल्स की पहली यात्रा थी।
- सेशेल्स के राष्ट्रपति की सद्यः भारत यात्रा के दौरान उनकी भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात के अतिरिक्त 26 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और तत्पश्चात दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित समझौते/समझौता ज्ञापन/दस्तावेज हस्ताक्षरित हुए—

(i) वायु सेवा (Air Services) समझौता।

(ii) सेशेल्स को भारत द्वारा दूसरा डोर्नियर समुद्री विमान प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन (ज्ञातव्य है कि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान की थी)।

(iii) करारोपण के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु समझौता।

(iv) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।

(v) नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा पर प्रोटोकॉल।

(vi) भारत द्वारा सेशेल्स के अलडाबरा (Aldabra) द्वीप के नैविगेशनल चार्ट की प्रस्तुति।

करारोपण सूचना पर भारत-सेशेल्स समझौता

करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान पर भारत-सेशेल्स समझौता विशेष महत्त्वपूर्ण है जिससे कर अपवंचना (विशेषकर भारत से भेजे जाने वाले काले धन) की रोकथाम में मदद मिलेगी। इस समझौते के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—

a. इस समझौते से भारत और सेशेल्स के सक्षम प्राधिकारियों को सूचना के आदान-प्रदान के जरिए करों के संबंध में दोनों देशों के घरेलू कानूनों के प्रशासन और क्रियान्वयन की सुविधा होगी।

b. समझौते के तहत जो भी सूचना प्राप्त होगी वह गोपनीय मानी जाएगी तथा इसे कराधान, कर वसूली तथा करों के संबंध में प्रवर्तन, अभियोजन या अपीलों के निर्धारण से संबंधित व्यक्तियों या प्राधिकारियों (अदालतों या प्रशासनिक निकायों सहित) के समक्ष ही प्रकट किया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति या निकाय या प्राधिकार या न्यायिक क्षेत्राधिकार को वह सूचना देने के लिए उस देश से लिखित अनुमति लेनी होगी जो सूचना भेज रहा है।

c. इस समझौते के तहत किसी भी प्रक्रिया से संबंधित मतभेद को दूर करने के लिए एक पारस्परिक सहमति प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है।

d. इस समझौते में कोई वित्तीय शर्त नहीं है। केवल 500 यूएस डॉलर से अधिक का असामान्य खर्च होने की स्थिति में, उसे भारत सरकार वहन करेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा कर सूचना के आदान-प्रदान पर इसी प्रकार के द्विपक्षीय समझौते अर्जेंटीना, बहामास, बहरीन, बेलिज, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, जिब्राल्टर, गर्नसे, आइल (Isle) ऑफ मैन, जर्सी, लाइबेरिया, लिचटेंस्टाइन, मकाओ, मोनाको और सैन मैरिनो के साथ भी किए गए हैं।

- अपनी इस यात्रा के दौरान सेशेल्स के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के मौर्या होटल में फिक्की, एसोचैम और सीआईआई द्वारा आयोजित भारतीय उद्यमियों की बैठक को संबोधित किया तथा उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) में 'नीली अर्थव्यवस्था हेतु समुद्री सुरक्षा' विषय पर व्याख्यान भी दिया।
- 27 अगस्त, 2015 को सेशेल्स के राष्ट्रपति ने मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर से मुलाकात के अतिरिक्त सेशेल्स टूरिज्म बोर्ड के एक कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया।

- उल्लेखनीय है कि मार्च, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशेल्स के मध्य निम्नलिखित समझौते/सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुए थे—
  - (i) समुद्री सहयोग के तहत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हेतु समझौता।
  - (ii) सेशेल्स के एजम्पशन (Assumption) द्वीप में अवसंरचना विकास हेतु समझौता।
  - (iii) नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
  - (iv) हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
  - (v) ब्लू इकोनॉमी पर सहयोग हेतु संयुक्त कार्यबल की स्थापना पर सहमति।
- अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स में भारत द्वारा स्थापित प्रथम तटीय निगरानी रडार प्रणाली (CSRS) का उद्घाटन किया तथा उन्होंने सेशेल्स के नागरिकों को भारत आगमन पर 3 माह का निःशुल्क वीजा प्रदान करने तथा शीघ्र ही आगमन पर वीजा दिए जाने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेशेल्स को भारत द्वारा प्रदत्त 75 मिलियन डॉलर के ऋण एवं अनुदान के बेहतर और शीघ्र उपयोग के लिए भी कहा।
- ज्ञातव्य है कि 115 द्वीपों वाले सेशेल्स (राजधानी-विक्टोरिया) की जनसंख्या मात्र लगभग 90 हजार है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के सभी राष्ट्रों में न्यूनतम है।

प्रधानमंत्री मोदी की मध्य एशिया यात्रा

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-13 जुलाई, 2015 के दौरान मध्य एशिया के 5 देशों क्रमशः उज्बेकिस्तान, कजाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान की राजकीय यात्रा संपन्न की।
- वें 6-7 जुलाई के मध्य उज्बेकिस्तान, 7-8 जुलाई के मध्य कजाख्स्तान, 10-11 जुलाई के मध्य तुर्कमेनिस्तान, 11-12 जुलाई के मध्य किर्गिजस्तान तथा 12-13 जुलाई के दौरान ताजिकिस्तान की यात्रा पर रहे।
- अपनी इस मध्य एशिया यात्रा के बीच में 8-10 जुलाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के ऊफा शहर जाकर वहां 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एवं 15वें एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) शिखर सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया।
- प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस मध्य एशिया यात्रा के प्रथम चरण में 6 जुलाई, 2015 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे जहां उनकी अगवानी उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शवकत मिरोमोनोविच मिर्जियोयेव ने की।
- ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेक राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के साथ पारस्परिक महत्त्व के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई जिसके पश्चात दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया तथा दोनों देशों के बीच 3 समझौता दस्तावेज (देखें-बॉक्स) भी हस्ताक्षरित हुए।
- वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग विस्तार के साथ पारस्परिक रणनीतिक, आर्थिक एवं ऊर्जा क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने के उपायों पर व्यापक चर्चा की तथा उज्बेकिस्तान से 2014 के यूरेनियम आपूर्ति समझौते (जिसके तहत उज्बेकिस्तान द्वारा भारत को 2,000 मीट्रिक टन 'यलो केक'–यूरेनियम अयस्कों से निष्कर्षित यूरेनियम सांद्र पाउडर की आपूर्ति की जानी है) के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदमों पर भी विमर्श किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संपर्क संयोजकता को संवर्धित करने पर बल देते हुए जहां 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' में उज्बेकिस्तान के शामिल होने का प्रस्ताव दिया वहीं उन्होंने भारत को 'अश्गाबात समझौते' में शामिल किए जाने के संदर्भ में उज्बेकिस्तान से समर्थन भी मांगा।
- दोनों देशों द्वारा रक्षा एवं साइबर सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग संवर्धन के साथ पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने हेतु मिलकर कार्य करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति करीमोव को 13वीं शताब्दी के सूफी कवि अमीर खुसरो की फारसी कृति 'खम्स-ए-खुसरो' की प्रति भेंट की। माना जाता है कि खुसरो के पिता उज्बेकिस्तान से भारत आए थे।
- 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने ताशकंद में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए (ज्ञातव्य है कि 1965 के भारत-पाक युद्ध के समापन हेतु तत्कालीन सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुए ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी, 1966 को हस्ताक्षर के बाद ताशकंद में ही शास्त्रीजी का निधन हो गया था) तथा इसी दिन उन्होंने वहां भारतीय छात्रों और भारतीय समुदाय की बैठक को भी संबोधित किया।

भारत-उज्बेकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित समझौते

1. पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर अंतर्सरकारी समझौता।
2. दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के मध्य सहयोग पर प्रोटोकॉल।
3. 2015-17 के लिए सांस्कृतिक सहयोग का अंतर्सरकारी कार्यक्रम।

- अपनी इस मध्य एशिया यात्रा के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को कजाख्स्तान की राजधानी अस्ताना पहुंचे। ज्ञातव्य है कि कजाख्स्तान वर्तमान में मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार राष्ट्र है।
- 7 जुलाई को ही भारतीय प्रधानमंत्री ने अस्ताना के नजरबायेव विश्वविद्यालय में भाषण दिया तथा गुमिल्योव यूरेशिया नेशनल यूनिवर्सिटी में 'भारत-कजाख्स्तान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र' (यहां भारत द्वारा प्रदत्त सुपरकंप्यूटर परम स्थापित किया गया है) का उद्घाटन किया।

- प्रधानमंत्री मोदी ने कजाख्स्तान के प्रधानमंत्री के साथ भारत के ओएनजीसी विदेश लि. और कजाख्स्तान के कजमुनायगैस द्वारा संयुक्त रूप से कैस्पियन सागर के सतपायेव ऑयल ब्लॉक में ड्रिलिंग कार्य का औपचारिक शुभारंभ भी किया।
- 8 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री की कजाख्स्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके पश्चात दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित 'तेज कदम' शीर्षक वाला संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और 5 महत्त्वपूर्ण समझौतों (देखें-बॉक्स) पर भी हस्ताक्षर संपन्न हुए।
- द्विपक्षीय वार्ता में दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा, कनेक्टिवटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश तथा सांस्कृतिक समन्वय की अभिवृद्धि के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दों पर पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों पक्षों के मध्य परस्पर कनेक्टिविटी विस्तार के संदर्भ में 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' की रूपरेखा में निकट सहयोग करने पर सहमति हुई जिसमें ईरान-तुर्कमेनिस्तान-कजाख्स्तान रेल लिंक (जो दिसंबर, 2014 से परिचालित हुआ है) को इस कॉरिडोर से जोड़ना शामिल है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति नजरबायेव को भारत में उद्भूत धर्मों से संबंधित पुस्तकों का एक सेट (जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी अनुवाद, बाल्मीकि रामायण का फारसी अनुवाद, कल्पसूत्र, अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिता आदि शामिल हैं) उपहार में दिया।
- कजाख्स्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापार समूहों की एक गोलमेज बैठक को भी संबोधित कर वहां की कंपनियों से भारत में रेलवे, आवास, स्मार्ट सिटी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया।
- उल्लेखनीय है कि कजाख्स्तान का विश्व में यूरेनियम उत्पादन में शीर्ष स्थान है तथा उसने 2010 से 2014 के मध्य भारत को 2,100 टन यूरेनियम की आपूर्ति की थी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कजाख्स्तान से अगले 5 वर्ष में 5,000 टन और यूरेनियम की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है।

भारत-कजाख्स्तान के मध्य हस्ताक्षरित समझौते

1. सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर समझौता।
2. रक्षा एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता।
3. शारीरिक (Physical), सांस्कृतिक एवं खेल के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
4. रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
5. प्राकृतिक यूरेनियम कंसन्ट्रेट की आपूर्ति हेतु भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और कजाख्स्तान की 'काजएटप्रोम' के बीच दीर्घावधिक संविदा।

- कजाख्स्तान के बाद अपनी इस मध्य एशिया यात्रा के बीच में 8-10 जुलाई, 2015 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस के ऊफा शहर गए जहां उन्होंने क्रमशः 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (8-9 जुलाई) तथा 15वें एससीओ शिखर सम्मेलन (9-10 जुलाई) में प्रतिभाग किया (विस्तृत विवरण हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' खंड देखें)।
- अपनी मध्य एशिया यात्रा के तृतीय चरण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात पहुंचे जहां अगले दिन 11 जुलाई को उनकी वहां के राष्ट्रपति गुरबांगली बरदिमुहामेदोव के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके पश्चात दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और दोनों देशों के मध्य 7 महत्त्वपूर्ण समझौतों (देखें-बॉक्स) पर भी हस्ताक्षर संपन्न हुए।
- द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने जहां अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में शांति और स्थिरता पर जोर दिया वहीं आतंकवाद, संगठित अपराधों तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने हेतु सहयोग के विस्तार पर भी सहमति व्यक्त की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता में 10 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत एवं लगभग 1,800 किमी. लंबी 'तापी गैस पाइपलाइन परियोजना' (TAPI : तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत) के शीघ्र क्रियान्वयन पर बल दिया जिसके वर्ष 2018 तक पूर्ण होने की आशा व्यक्त की गई है। साथ ही उन्होंने तुर्कमेनिस्तान को 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण भी दिया।
- 11 जुलाई को ही प्रधानमंत्री मोदी ने अश्गाबात में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा वहां उन्होंने एक पारंपरिक चिकित्सा एवं योग केंद्र का भी उद्घाटन किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बरदिमुहामेदोव को विशेष दस्तकारी वाली घोड़े की काठी (जीन) उपहार में दी।

भारत-तुर्कमेनिस्तान के मध्य संपन्न समझौते

1. रासायनिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन।
2. भारत के विदेश सेवा संस्थान और तुर्कमेनिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन।
3. खेल के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
4. वर्ष 2015-2017 अवधि हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग कार्यक्रम।
5. योग एवं परंपरागत औषधि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
6. पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
7. रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।

- 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी अपनी मध्य एशिया यात्रा के चतुर्थ चरण में किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे जहां अगले दिन 12 जुलाई को उन्होंने विजय स्मारक पर शहीदों को

श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञातव्य है कि 'किर्गिजस्तान' का वहां अर्थ '40 कबीलों का देश' है।

- 12 जुलाई को ही भारतीय प्रधानमंत्री की किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति अलमाजबेक अतामबायेव के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके पश्चात दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और 4 महत्त्वपूर्ण समझौते (देखें-बॉक्स) हस्ताक्षरित हुए।
- द्विपक्षीय वार्ता में दोनों पक्षों द्वारा जहां विश्व में कट्टरवाद एवं आतंकवाद के विस्तार पर गहन चिंता व्यक्त की गई वहीं व्यापार एवं निवेश, पर्यटन एवं संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास आदि क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर भी सहमति हुई।
- दोनों देशों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास को वार्षिक आधार पर आयोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 में भारत में आयोजित प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद 2015 में मार्च माह में दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास—'खंजर 2015' किर्गिजस्तान में संपन्न हुआ था।
- प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा वहां के 'नेशनल सेंटर ऑफ कॉर्डियोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन' में स्थापित 'किर्गिज-इंडिया माउंटेन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर' में भारत एवं मध्य एशिया के बीच पहले टेलीमेडिसिन लिंक का शुभारंभ भी किया।
- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति को रेशम और ऊन का हाथ से बुना एक गलीचा उपहारस्वरूप दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इन 5 मध्य एशियाई देशों में केवल किर्गिजस्तान में ही लोकतंत्र वास्तव में स्थापित है।

भारत-किर्गिजस्तान के मध्य संपन्न समझौते

1. रक्षा क्षेत्र में सहयोग और वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए समझौता।
2. चुनाव के क्षेत्र में पारस्परिक समझ एवं सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
3. मानकीकरण (Standardization) के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
4. संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।

- अपनी इस मध्य एशिया यात्रा के पांचवें और अंतिम चरण में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे पहुंचे जहां अगले दिन 13 जुलाई को उनकी ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके पश्चात संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और दो महत्त्वपूर्ण समझौतों (देखें-बॉक्स) पर हस्ताक्षर संपन्न हुए।
- द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने जहां आतंकवाद और कट्टरवाद के सफाए के साथ व्यापार और उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन पर सहमति व्यक्त की, वहीं दोनों देशों के बीच ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, औषधि, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल्स तथा संस्कृति एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग विस्तार पर भी बल दिया गया।

भारत-ताजिकिस्तान के मध्य संपन्न समझौते

1. वर्ष 2016-2018 अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम।
2. ताजिकिस्तान में 37 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना हेतु मौखिक नोट का आदान-प्रदान।

- दोनों पक्षों ने 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' पर चर्चा के साथ प्रस्तावित पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान ट्रांजिट व्यापार करार में भारत को भी शामिल किए जाने की संभावना पर जोर दिया।
- दुशान्बे में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवर रबींद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया तथा वे भारत-ताजिकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल भी गए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने ताजिक राष्ट्रपति रहमान को 17वीं शती के भारतीय शायर अब्दुल कादिर 'बेदिल' (जिन्हें ताजिकिस्तान में महानतम फारसी शायर माना जाता है) के मकबरे की एक लघु पेंटिंग भेंट में दी।

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) भारत, रूस, ईरान और मध्य एशिया के बीच माल यातायात हेतु प्रस्तावित समुद्री, रेल एवं सड़क मार्ग है। आईएनएसटीसी परियोजना हेतु मूलतः 2002 में रूस, ईरान और भारत द्वारा समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इस परियोजना के अन्य महत्त्वपूर्ण सदस्य देशों में अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाख्स्तान एवं बेलारूस शामिल हैं। हाल की अपनी मध्य एशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ताजिकिस्तान से इस परियोजना में शामिल होने का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 अगस्त, 2015 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा पर रहे।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी इस्लामी देश की यह उनकी पहली यात्रा थी तथा यह 1981 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूएई यात्रा भी थी।
- 16 अगस्त को यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अबू धाबी के क्राउन प्रिंस तथा यूएई सेना के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान ने किया जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई के संस्थापक को श्रद्धांजलि देने हेतु शेख जायेद ग्रैंड मस्जिद गए।
- 16 अगस्त को ही अबू धाबी में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की तथा इसी दिन उन्होंने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण द्वारा आयोजित उद्यमियों की बैठक को संबोधित करते हुए भारत में निवेश को विस्तारित करने का आह्वान किया।
- 17 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने मसदर शहर (जिसे 'शून्य कार्बन' शहर माना जाता है) का दौरा कर वहां की हरित एवं प्रदूषणमुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रति अपनी रूचि को प्रदर्शित किया।

दुनिया का पहला जीरो कार्बन शहर : मसदर

- संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी से 17 किमी. की दूरी पर स्थित शहर मसदर की गणना न सिर्फ विश्व के प्रमुख स्मार्ट शहरों में की जाती है, बल्कि यह दुनिया का पहला 'जीरो कार्बन' शहर भी है।
- ध्यातव्य है कि जीरो कार्बन शहर से अभिप्राय एक ऐसे शहर से होता है, जहां यातायात से लेकर घरेलू रसोई तक में कार्बन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया हो एवं वहां सुविधाओं के अन्य विकल्पों को विकसित कर लिया गया हो।
- मसदर की खूबी यह है कि यहां न तो कार्बन का उत्सर्जन करने वाली कारें और गाड़ियां हैं और न ही किसी तरह का धुआं और कूड़ा-करकट। यह इस प्रकार संभव हुआ है कि यहां ऊर्जा के उपभोग के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को विकसित किया गया है। इसके लिए यहां 88 हजार सौर पैनल 54 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।
- मसदर में जहां विद्युत एवं जल आपूर्ति को सेंसर्स तकनीक आधारित बनाया गया है, वहीं प्राकृतिक हवा को ठंडी हवा के रूप में घरों तक पहुंचाने के लिए विंड टॉवर्स का विकास किया गया है। इस शहर का विकास पूर्णतः पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखकर किया गया है।

- 17 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी की क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।
- द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत-यूएई भागीदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों पक्ष सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक अभिसमय (Convention) को अपनाए जाने हेतु मिलकर कार्य करने पर भी सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के मध्य नियमित वार्ता प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया तथा हिंद महासागर एवं खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहयोग और पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया एवं खाड़ी क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की अभिवृद्धि हेतु मिलकर कार्य करने पर भी सहमति जताई। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं तथा संघर्ष की स्थितियों में मानवीय सहायता हेतु सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्ष पारस्परिक व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु 75 बिलियन डॉलर की 'भारत-यूएई अवसंरचना निधि' की स्थापना के साथ द्विपक्षीय व्यापार में अगले 5 वर्षों में 60 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य पर भी सहमत हुए।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 बिलियन डॉलर के स्तर पर रहा है तथा यूएई वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा (चीन एवं यूएसए के बाद) व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2014-15 में यूएई को भारत का निर्यात 33 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है तथा यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
- द्विपक्षीय वार्ता में जहां यूएई ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपने समर्थन को दोहराया, वहीं दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग संवर्धन के साथ सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग विस्तार हेतु दोनों देशों के सशस्त्र बलों के मध्य नियमित अभ्यास को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई द्वारा अल आइन में पश्चिम एशिया के प्रथम स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना तथा 2021 में मंगल ग्रह हेतु अंतरिक्ष मिशन भेजे जाने की योजना का स्वागत किया।
- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में नए हिंदू मंदिर की स्थापना हेतु भूमि आवंटित करने के निर्णय की घोषणा वहां के क्राउन प्रिंस ने की जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया।
- अपनी इस यूएई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 17 अगस्त को ही दुबई पहुंचे जहां उन्होंने यूएई के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री (जो कि दुबई के शासक–'अमीर' भी हैं) मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम से मुलाकात एवं वार्ता की।
- 17 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित किया।

संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात सात अमीरातों–अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजाएराह, रास अल-खैमाह, शारजाह और उम्म अल-कुवैन का संघ है जिसकी स्थापना दिसंबर, 1971 में हुई थी। इनमें प्रत्येक अमीरात का शासक वंशानुगत 'अमीर' होता है जो मिलकर संघीय सुप्रीम काउंसिल बनाते हैं। इनमें से एक अमीर को यूएई का राष्ट्रपति चुने जाने का प्रावधान है तथापि अबू धाबी (जो कि यूएई की राजधानी भी है) का अमीर ही परंपरागत रूप से यूएई का राष्ट्रपति होता है, अतः यह पद भी वंशानुगत हो गया है। यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति (और अबू धाबी के अमीर) खलीफा बिन जायेद अल नाहयान हैं जो वर्ष 2004 से इस पद पर हैं। ज्ञातव्य है कि यूएई के पास विश्व का सातवां सबसे बड़ा तेल भंडार है।

मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित देश मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी अपनी पत्नी इसौरा न्यूसी तथा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 4-8 अगस्त, 2015 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा पर रहे।
- उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2015 में मोजाम्बिक के चौथे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी एशियाई देश की यह उनकी पहली यात्रा थी। उनसे पूर्व के तीनों राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आ चुके हैं।
- मोजाम्बिक के राष्ट्रपति न्यूसी की सद्यः भारत यात्रा मोजाम्बिक की स्वतंत्रता और भारत के साथ उसके राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हुई।
- 5 अगस्त को मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके दौरान मोजाम्बिक में भारतीय सहयोग एवं निवेश से चल रही रेलवे, हाइड्रोकार्बन एवं कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

- द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात भारत और मोजाम्बिक के मध्य 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन' भी हस्ताक्षरित हुआ।
- 5 अगस्त को ही नई दिल्ली में राष्ट्रपति न्यूसी ने फिक्की, एसोचैम और सीआईआई द्वारा आयोजित भारतीय उद्यमियों की बैठक को संबोधित किया तथा उसी दिन उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।
- अपनी इस भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति न्यूसी 6 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचे जहां अगले दिन 7 अगस्त को उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के शिक्षकों एवं छात्रों से भेंट की। ज्ञातव्य है कि वे 2003 में यहां के छात्र रहे थे।
- अपने अहमदाबाद प्रवास के दौरान राष्ट्रपति न्यूसी ने साबरमती-आश्रम, दीन दयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय तथा आणंद के दुग्ध केंद्र का भी अवलोकन किया।
- यह उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्ष 2014-15 में भारत और मोजाम्बिक के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.4 बिलियन डॉलर के स्तर पर रहा तथा अफ्रीका महाद्वीप में कुल भारतीय निवेश का लगभग एक-चौथाई (7 बिलियन डॉलर से अधिक) मोजाम्बिक में ही निवेशित है।

तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र तंजानिया के राष्ट्रपति जकाया किकवेट ने 17-21 जून, 2015 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की।
- तंजानिया के राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा के दौरान भारत और तंजानिया के मध्य 19 जून को निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुए—
  - (i) सरकारी सांख्यिकी में सहयोगात्मक कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एमओयू।
  - (ii) कृषि सांख्यिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा जैव सूचना विज्ञान में क्षमता निर्माण हेतु एमओयू।
  - (iii) लेक विक्टोरिया पाइपलाइन परियोजना के विस्तार हेतु 268.35 मिलियन डॉलर की ऋण शृंखला हेतु भारत के एक्जिम बैंक और तंजानिया सरकार के बीच ऋण करार।
  - (iv) लेक विक्टोरिया पाइपलाइन परियोजना के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने हेतु भारतीय सार्वजनिक उपक्रम वाप्कोस और तंजानिया सरकार के बीच करार।
  - (v) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
  - (vi) जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू और जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान पर प्रोटोकॉल।

प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा

- 6-7 जून, 2015 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ गया था।
- 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के साथ बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई जिसके बाद दोनों पक्षों के मध्य कुल मिलाकर 22 समझौते/समझौता ज्ञापन (MoU)/अन्य दस्तावेज हस्ताक्षरित हुए।
- भारत और बांग्लादेश के मध्य हस्ताक्षरित इन समझौतों में ऐतिहासिक भू-सीमा समझौते संबंधी दस्तावेज (इन पर हस्ताक्षर के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित थीं) सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके तहत दोनों देशों द्वारा 1974 के भारत-बांग्लादेश भू-सीमा समझौते तथा भू-सीमा समझौते पर 2011 के प्रोटोकॉल के संदर्भ में अनुसमर्थन पत्रों (Instrument of Ratification) के आदान-प्रदान हेतु प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ तथा 1974 के भू-सीमा समझौते और 2011 के प्रोटोकॉल की क्रियान्वयन व्यवस्था हेतु दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ।
- भारत-बांग्लादेश भू-सीमा समझौते संबंधी उपर्युक्त दो दस्तावेजों के अतिरिक्त दोनों देशों द्वारा इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित अन्य समझौते इस प्रकार हैं—

1. तटीय नौवहन पर करार (द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु)।
2. द्विपक्षीय व्यापार समझौते का नवीकरण (सर्वप्रथम दोनों देशों के मध्य यह समझौता 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था)।
3. मानकीकरण (Standardization) के क्षेत्र में सहयोग हेतु द्विपक्षीय सहयोग करार।
4. ढाका-शिलांग-गुवाहाटी बस सेवा पर करार एवं इसका प्रोटोकॉल।
5. कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा पर करार एवं इसका प्रोटोकॉल।
6. अंतर्देशीय जलमार्ग पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल का नवीकरण (सर्वप्रथम इस हेतु 1972 में प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था)।
7. वर्ष 2015-17 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
8. भारत द्वारा बांग्लादेश को 2 बिलियन डॉलर की नई ऋण शृंखला (Line of Credit) प्रदान करने हेतु एमओयू (यह भारत द्वारा बांग्लादेश को प्रदत्त 800 मिलियन डॉलर की वर्तमान ऋण शृंखला के अतिरिक्त है)।
9. भारत से वस्तुओं को लाने-ले जाने हेतु बांग्लादेश के चिटगांग और मोंगला बंदरगाहों के प्रयोग पर एमओयू।
10. नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) और बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में समुद्रीय सहयोग पर एमओयू।
11. मानव तस्करी की रोकथाम हेतु द्विपक्षीय सहयोग पर एमओयू।
12. जाली करेंसी नोटों की स्मगलिंग और प्रचलन की रोकथाम पर एमओयू।
13. बांग्लादेश में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना पर एमओयू।
14. दोनों देशों के तटरक्षक बलों के मध्य सहयोग हेतु एमओयू।
15. सार्क के आईईसीसी-एसए (India Endowment for Climate Change-South Asia) के तहत बांग्लादेश को 70,000 उन्नत कुक स्टोव की आपूर्ति हेतु परियोजना के लिए एमओयू।
16. भारत के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और बांग्लादेश के राजशाही विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू।
17. बंगाल की खाड़ी में समुद्र विज्ञान (Oceanography) पर संयुक्त अनुसंधान हेतु एमओयू।

18. शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर मंशा वक्तव्य।

19. बांग्लादेश में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रचालन प्रारंभ करने हेतु बांग्लादेशी बीमा विकास एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा मंजूरी पत्र।

20. भारत के बीएसएनएल और बांग्लादेश की सबमरीन केबिल कंपनी लि. के मध्य पूर्वोत्तर भारत में बेहतर इंटरनेट सुविधा हेतु ब्राह्मनबरिया से अखौरा सीमा तक 22 किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबिल हेतु समझौता।

- भारतीय प्रधानमंत्री की इस बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया जिसका शीर्षक था : '<u>नूतन प्रोजोन्मा-नई दिशा</u>'।
- इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 6 जून, 2015 को संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के मध्य दो बस सेवाओं का शुभारंभ किया—

(i) ढाका-शिलांग-गुवाहाटी बस सेवा : यह बस सेवा सप्ताह में 6 दिनों के लिए ढाका और गुवाहाटी के मध्य प्रारंभ की गई है जिसमें दो स्टापेज शिलांग और सिलहट हैं।

(ii) कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा : इसके माध्यम से कोलकाता से अगरतला तक सीधी बस सेवा प्रारंभ की गई है जिसमें एक स्टापेज ढाका है। इस बस सेवा के प्रारंभ से प. बंगाल और त्रिपुरा की राजधानियों के मध्य सड़क यात्रा समय काफी कम हो गया है। यह बस सेवा भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी।

- 7 जून, 2015 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने वहां के राष्ट्रपति निवास बंग भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदत्त बांग्लादेश के प्रतिष्ठित 'मुक्ति संग्राम सम्मान' का प्रतीक चिह्न प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया जिसे बाद में नई दिल्ली में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों को सौंपा।

बीबीआईएन मोटर वाहन करार

15 जून, 2015 को भूटान की राजधानी थिम्पू में 4 सार्क देशों- बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN) के परिवहन मंत्रियों की बैठक में इन देशों के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के यातायात के विनियमन हेतु '<u>मोटर वाहन करार</u>' (BBIN Motor Vehicle Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए। ज्ञातव्य है कि इस समझौते को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 जून, 2015 को स्वीकृति दी गई थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप अब इस उप-क्षेत्र में इन देशों के बीच सीमा-पार सड़क यातायात सुरक्षित, आर्थिक रूप से प्रभावी और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होगा।

उल्लेखनीय है कि नंवबर, 2014 में काठमांडू में आयोजित सार्क देशों के 18वें शिखर सम्मेलन में 'सार्क मोटर वाहन करार' पर हस्ताक्षर होने थे परंतु पाकिस्तान के अड़ंगे के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं हो सके थे। तत्पश्चात 4 सार्क देशों के बीच उप-क्षेत्रीय मोटर वाहन करार को आगे बढ़ाया गया और सद्यः समझौता इसी का प्रतिफलन है।

- प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस बांग्लादेश यात्रा के दौरान 7 जून को <u>ढाकेश्वरी मंदिर</u> और <u>रामकृष्ण मिशन</u> गए तथा इसी दिन उन्होंने ढाका में बंग बंधु अंतर्राष्ट्रीय दीक्षांत समारोह केंद्र (BICC) में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया।
- इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से बांग्लादेश में खुलना-मोंगला रेल लाइन, कलौरा-शहबाजपुर रेल खंड के पुनर्वास, शरदाह की नेशनल पुलिस एकेडमी में भारत-बांग्लादेश मैत्री भवन, सिलायदहा के कठिबारी में रबींद्रनाथ भवन तथा फेनी नदी पर भारत-बांग्लादेश मैत्री सेतु निर्माण के शिलान्यास का अनावरण किया गया और उन्होंने तारापुर-कमला सागर सीमा हाट एवं बीएसटीआई में उन्नत प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया।

<u>नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा</u>

- 5-6 जून, 2015 के दौरान नीदरलैंड्स (हालैंड) के प्रधानमंत्री मार्क रूट (Mark Rutte) भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय राजनयिक और वृहद व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था।
- 5 जून को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रूट की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई।
- दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा पारस्परिक सहयोग संबंधी निम्नलिखित प्रमुख पहलों का स्वागत किया गया—

1. यूरोपीय भागीदारों के मध्य समन्वय हेतु एक '<u>यूरोपीय संघ- गंगा प्लेटफार्म</u>' का गठन करने की पहल जिसमें नीदरलैंड्स अग्रणी भूमिका निभाएगा।
2. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ अभिचिह्नित सहयोग के क्षेत्रों को अंतिम रूप देने तथा आगे बढ़ाने हेतु नीदरलैंड्स के विशेषज्ञों की टीम का भारत दौरा।
3. भारत में इलेक्ट्रिक वाहन इको सिस्टम के विकास हेतु सहयोग कार्यक्रम।
4. कोचीन शिपयार्ड लि. (CSL) और डच शिपबिल्डर रॉयल आईएचसी के मध्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित भारत में संयुक्त रूप से ड्रेजर्स (Dredgers) के निर्माण हेतु समझौता।
5. बिबकॉल (BIBCOL) और इंट्रावैक (Intravacc) के मध्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित भारत में खसरा-रूबेला के विरुद्ध टीकों के विकास और विनिर्माण पर करार।
6. सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
7. 3 वर्षों के लिए कृषि पर समझौता ज्ञापन का विस्तार।
8. कोहॉर्ट (Cohort) अध्ययनों के क्षेत्र में विद्यमान सहयोग का विस्तार करने हेतु करार।
9. निजी क्षेत्र के सहयोग से ई-स्वास्थ्य सेवा पहुंच और संवहनीयता हेतु नवाचारी डिजिटल समाधान ढूंढ़ने के लिए 'हेल्थ हैकटॉन' (Health Hacketon) पहल।
10. मुंबई शहर में और आस-पास अवसंरचना विकास एवं डिलिवरी में नीदरलैंड्स एवं महाराष्ट्र के बीच सहयोग जिसमें तटीय सड़कों एवं मेट्रो संबंधी चुनौतियों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल हैं।

11. तेलंगाना में कोल्ड चेन अवसंरचना, पशुधन एवं बागवानी उत्पादन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खाद्य एवं कृषि व्यवसाय क्षेत्र के विकास में ज्ञान की साझेदारी एवं सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए तेलंगाना सरकार और नीदरलैंड्स के वागेनिजेन विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।
12. भारत-नीदरलैंड्स कार्य योजना के तहत केरल में तिरूवनंतपुरम में सब्जियों एवं फूलों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
13. उद्यमशीलता विकास के उद्देश्य से छात्रों के लिए क्षमता निर्माण एवं मांग पर आधारित पाठ्यचर्या विकास को सुगम बनाने हेतु महाराष्ट्र के बारामती कृषि कॉलेज और नीदरलैंड्स के वान हाल लारेंस्टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज के मध्य समझौता।

भारतीय राष्ट्रपति की स्वीडन और बेलारूस यात्रा

- भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 31 मई से 4 जून, 2015 के मध्य क्रमशः स्वीडन और बेलारूस की राजकीय यात्रा पर रहे। इस दौरान 31 मई-2 जून के मध्य उन्होंने स्वीडन तथा 2-4 जून के मध्य बेलारूस की यात्रा संपन्न की। यह इन दोनों देशों के लिए किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी।
- राष्ट्रपति मुखर्जी के साथ एक उच्च स्तरीय राजनयिक और व्यापारिक शिष्टमंडल भी इस दौरे पर गया था।
- 1 जून को भारत और स्वीडन के मध्य निम्नलिखित 6 महत्त्वपूर्ण करारों/समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए—
  1. सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
  2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
  3. एक-दूसरे देश के राजनयिक पासपोर्टधारकों को वीजा आवश्यकता से छूट पर करार।
  4. ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान में सहयोग पर मंशा पत्र (LoI)।
  5. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और स्वीडन की रिसर्च काउंसिल फॉर हेल्थ वर्किंग लाइफ एंड वेलफेयर (FORTE) के मध्य जरावस्था अनुसंधान एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर मंशा ज्ञापन।
  6. भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजशेन (CDSCO) और स्वीडन की मेडिकल प्रोडक्ट्स एजेंसी (MPA) के मध्य औषधि उत्पादों के संदर्भ में सहयोग पर मंशा ज्ञापन।
- उपर्युक्त अंतर्सरकारी दस्तावेजों के अतिरिक्त राष्ट्रपति मुखर्जी की इस यात्रा के दौरान भारत और स्वीडन के शैक्षिक एवं शोध संस्थानों के मध्य भी 16 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए।
- अपनी इस यात्रा के द्वितीय चरण में राष्ट्रपति मुखर्जी 2 जून को ही बेलारूस की राजधानी मिंस्क पहुंचे।
- 3 जून को भारत और बेलारूस के मध्य निम्नलिखित 6 महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए—
  1. भारत-बेलारूस सहयोग के लिए रोडमैप (इसमें दोनों देशों के मध्य राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, निवेश, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा, धातु एवं खनन, पोटाश उर्वरकों, परिवहन एवं परिवहन अवसंरचना, कपड़ा, सैन्य प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन आदि विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है)।
  2. आय एवं पूंजी करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम और दोहरे कराधान के परिहार हेतु 1997 के समझौते में संशोधन हेतु प्रोटोकॉल।
  3. प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
  4. भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और बेलारूस के वित्त मंत्रालय के मध्य द्विपक्षीय सहयोग पर एमओयू।
  5. मानकीकरण और सूचना समर्थन के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
  6. भारत के कपड़ा मंत्रालय और बेलारूस के बेलेगप्रॉम के मध्य एमओयू।
- उपर्युक्त समझौतों के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में दोनों देशों के शैक्षिक संस्थानों के मध्य 7 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- भारत द्वारा बेलारूस को पारस्परिक रूप से सहमत संयुक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 100 मिलियन डॉलर की नई ऋण शृंखला प्रदान करने की भी घोषणा की गई।
- भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मिंस्क में बेलारूस की स्टेट यूनिवर्सिटी के कैम्पस में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया तथा इस यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई।
- राष्ट्रपति मुखर्जी ने वहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (BHEL) द्वारा स्थापित एक परियोजना का भी उद्‌घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी की चीन, मंगोलिया और द. कोरिया यात्रा

- 14-19 मई, 2015 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री तीन देशों-चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की राजकीय यात्रा पर रहे।
- अपनी इस त्रिदेशीय यात्रा के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 14-16 मई के मध्य चीन की यात्रा संपन्न की।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर, 2014 में भारत की यात्रा पर आए थे। ज्ञातव्य है कि चीन में वर्ष 2015 में 'भारत वर्ष' मनाया जा रहा है।
- 14 मई, 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चीन यात्रा का प्रारंभ चीन के शान्सी राज्य की राजधानी शियान (Xian; जो कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का गृहनगर है) से किया। ज्ञातव्य है कि सितंबर, 2014 में चीनी राष्ट्रपति ने भी अपनी भारत यात्रा की शुरुआत परंपराओं से हटकर अहमदाबाद से की थी।
- शियान में प्रधानमंत्री मोदी विश्व विरासत स्थल 'टेराकोटा वारियर्स म्यूजियम' के अतिरिक्त 'दाशिंगशान मंदिर' और 'बिग वाइल्ड गूज पैगोडा' (हंस पैगोडा) के अवलोकन हेतु गए। ऐतिहासिक बौद्ध पैगोडा के मुख्य महंत को प्रधानमंत्री मोदी ने बोधिवृक्ष का पौधा भेंट किया।

शियान के ऐतिहासिक स्थल

टेराकोटा वारियर्स म्यूजियम : इसमें चीन के प्रथम सम्राट क्विन शी हांग (Qin Shi Huang) के तृतीय शती ई. पू. के मकबरे के साथ शवाधान कला के रूप में दफनाई गई उनके सैनिकों एवं घोड़ों/रथों की टेराकोटा निर्मित प्रतिकृतियां प्रदर्शित हैं। इनकी खोज 1974 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा उपर्युक्त मकबरे को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है।

दाशिंगशान मंदिर : तृतीय शती ई. में जिन वंश के शासकों द्वारा निर्मित यह चीन के सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसे चीन में बौद्ध धर्म की तांत्रिक विचारधारा (वज्रयान) का जन्म स्थल माना जाता है। यहां अनेक भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने प्रवास कर बौद्ध ग्रंथों के चीनी भाषा में अनुवाद में योगदान दिया था।

बिग वाइल्ड गूज पैगोडा (हंस पैगोडा) : इस बौद्ध पैगोडा का निर्माण चीन के तांग वंश के शासकों द्वारा 652 ई. में कराया गया था। यहां चीन से भारत गए यात्री ह्वेनसांग द्वारा लाए गए अनुवादित बौद्ध ग्रंथों एवं कलाकृतियों को रखा गया है। इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

- प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को ही शियान से बीजिंग पहुंचे जहां अगले दिन (15 मई को) उनका औपचारिक स्वागत चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग द्वारा किया गया और तत्पश्चात दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और कुल 24 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जो इस प्रकार हैं—

1. चीन के चेंगदू और भारत के चेन्नई में महावाणिज्य दूतावास खोलने तथा ग्वांगझू में भारत के महावाणिज्य दूतावास के कांसुलर जिले के विस्तार हेतु प्रोटोकॉल।
2. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU)।
3. अहमदाबाद/गांधीनगर में 'कौशल विकास एवं उद्यमिता हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय संस्थान' की स्थापना में सहयोग पर कार्य योजना।
4. व्यापार वार्ता में सहयोग हेतु परामर्शी तंत्र पर एमओयू।
5. भारत के विदेश मंत्रालय और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मध्य सहयोग पर एमओयू।
6. रेलवे क्षेत्र में सहयोग हेतु कार्ययोजना (2015-16)।
7. शिक्षा विनिमय कार्यक्रम (छात्रवृत्तियों के प्रावधान सहित) पर एमओयू।
8. खनन और खनिज क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू।
9. अंतरिक्ष सहयोग रूपरेखा (2015-2020)।
10. भारतीय रेपसीड खाद्यान्न (Rapeseed Meal) के चीन में आयात हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमों पर प्रोटोकॉल।
11. टी.वी. प्रसारण क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू।
12. पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर करार।
13. भारत-चीन थिंक टैंक फोरम की स्थापना हेतु एमओयू।
14. भारत के नीति (NITI) आयोग और चीन की राज्य परिषद के विकास अनुसंधान केंद्र के मध्य आर्थिक एवं नीतिगत मुद्दों पर सहयोग हेतु एमओयू।
15. भूकंप विज्ञान और भूकंप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू।
16. महासागर विज्ञान, महासागर प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर के क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू।
17. भूविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग हेतु एमओयू।
18. राज्य/प्रांतीय लीडर्स फोरम की स्थापना पर विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रता हेतु एमओयू।
19. भारत के कर्नाटक और चीन के सिचुआन प्रांत के मध्य सिस्टर स्टेट/प्रांत संबंधों की स्थापना पर करार।
20. चेन्नई (भारत) और चोंगकिंग (चीन) के मध्य सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर करार।
21. औरंगाबाद (भारत) और हुनहुआंग (चीन) के मध्य सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर करार।
22. हैदराबाद (भारत) और किंगदाओ (चीन) के मध्य सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर करार।
23. 'गांधीवाद एवं भारतीय अध्ययन केंद्र' की चीन के फूदान विश्वविद्यालय में स्थापना हेतु एमओयू।
24. कुनमिंग में 'योग महाविद्यालय' की स्थापना हेतु चीन के युन्नान मिंजू विश्वविद्यालय के साथ एमओयू।

- प्रधानमंत्री मोदी ने बीजिंग के 'टेंपल ऑफ हैवेन' में भारतीय योग और चीन की ताइची (Taichi) परंपरा की संयुक्त गतिविधि में भी प्रतिभाग किया। इसके बाद वे शंघाई गए।
- इस यात्रा के दौरान 16 मई को शंघाई में भारतीय और चीनी कंपनियों के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक पार्क, विद्युत, इस्पात, फिल्म उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 22 बिलियन डॉलर से अधिक के कुल 26 करार/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए जिसमें भारत के मुंद्रा बंदरगाह और चीन के ग्वांगझू बंदरगाह के मध्य सिस्टर पोर्ट संबंधों की स्थापना पर करार भी शामिल है।
- 16 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई में भारत के आईसीआईसीआई बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन किया। इसी दिन उन्होंने शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया तथा वहां के फूदान विश्वविद्यालय में 'गांधीवाद एवं भारतीय अध्ययन केंद्र' का उद्घाटन भी किया।

चीन ने कैलाश मानसरोवर हेतु नाथू ला मार्ग खोला

22 जून, 2015 को चीन ने भारत के कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए सिक्किम के नाथू ला दर्रे से होकर जाने वाला मार्ग खोल दिया और तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को अनुमति प्रदान की। यह मार्ग विगत 44 वर्षों से बंद था। यह तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा हेतु अब दूसरा मार्ग होगा। उल्लेखनीय है कि अब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित लिपुलेख दर्रे के मार्ग से ही होती थी जो कि 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ विभीषिका में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। नाथू ला होकर जाने वाला यह मार्ग अधिक सुविधाजनक है तथा 1,500 किमी. लंबे इस रूट पर बस सुविधा भी उपलब्ध है।

- अपनी इस त्रिदेशीय यात्रा के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 17-18 मई के मध्य मंगोलिया की यात्रा संपन्न की। वे मंगोलिया की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
- उल्लेखनीय है कि 2015 मंगोलिया में लोकतंत्र की स्थापना का 25वां वर्ष और भारत-मंगोलिया कूटनीतिक संबंधों की स्थापना का 60वां वर्ष है।

गंडन बौद्ध मठ

प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर (Ulan Bator) स्थित 'गंडन बौद्ध मठ' के अवलोकन हेतु गए जहां उन्होंने मठ के मुख्य संरक्षक को बोधिवृक्ष का पौधा भेंट किया। ज्ञातव्य है कि तिब्बत शैली के इस बौद्ध मठ का निर्माण 1809 ई. में किया गया था।

- उलान बाटोर में मंगोलिया के राष्ट्रपति साखियाजिन एल्बेगदोर्ज और प्रधानमंत्री चिमेद सैखानबिलेग से उन्होंने 17 मई को द्विपक्षीय वार्ताएं की और तत्पश्चात भारत-मंगोलिया रणनीतिक भागीदारी हेतु संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और दोनों देशों के मध्य कुल 13 करार/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए, जो इस प्रकार हैं—
  1. संशोधित हवाई सेवा करार।
  2. सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर संधि।
  3. पशु स्वास्थ्य एवं डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर करार।
  4. परंपरागत औषधि प्रणालियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू।
  5. मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर एमओयू।
  6. मंगोलिया में भारत-मंगोलिया संयुक्त मैत्री स्कूल की स्थापना पर एमओयू।
  7. वर्ष 2015-2018 हेतु संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यक्रम।
  8. दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के मध्य सहयोग हेतु एमओयू।
  9. दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के मध्य सहयोग हेतु एमओयू।
  10. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू।
  11. सीमा निगरानी बलों के मध्य सहयोग संवर्धन पर एमओयू।
  12. भारत के टाटा मेमोरियल सेंटर और मंगोलिया के नेशनल कैंसर सेंटर के बीच रेडियोथेरेपी सिमुलेटर सहित भाभाट्रॉन-II टेली-थेरेपी इकाई मंगोलिया को उपहार में देने हेतु एमओयू।
  13. भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और मंगोलियाई विदेश मंत्रालय की डिप्लोमेटिक एकेडमी के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु एमओयू।
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगोलिया में अवसरंचना विकास परियोजनाओं हेतु 1 बिलियन डॉलर की ऋण श्रृंखला (Line of Credit) प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। साथ ही उलान बाटोर में 'अटल बिहारी वाजपेयी आईसीटी केंद्र' के उन्नयन हेतु भारत द्वारा 20 मिलियन डॉलर की सहायता दिए जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- मंगोलियाई राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को 'मोरिन खुर' नामक वाद्य यंत्र (एक प्रकार की सारंगी) भेंट की जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रामपुर लाइब्रेरी की मंगोलिया इतिहास पर 13वीं शती की 'जमीउत तवारीख' नामक दुर्लभ पांडुलिपि उपहारस्वरूप दी।
- मंगोलिया में एक खेल उत्सव (मिनी नादाम) के अवलोकन को गए प्रधानमंत्री मोदी को मंगोलियाई प्रधानमंत्री द्वारा 'कंथक' नामक रेस का घोड़ा भेंट किया गया। इस उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया।
- अपनी इस मंगोलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 17 मई को ही मंगोलियाई संसद 'ग्रेट हुराल' (Great Hural) को भी संबोधित किया तथा वे अवकाश के दिन वहां की संसद को संबोधित करने वाले पहले विदेशी नेता बने।
- अपनी इस विदेश यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 18-19 मई, 2015 के मध्य दक्षिण कोरिया (कोरिया गणराज्य) की यात्रा संपन्न की। ज्ञातव्य है कि दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाई जनवरी, 2014 में भारत दौरे पर आईं थीं।
- दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया और उसी दिन उन्होंने कोरियाई राष्ट्रपति के साथ पारस्परिक महत्त्व के विभिन्न द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता की।
- भारत और दक्षिण कोरिया पारस्परिक संबंधों को विशेष रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए तथा इस संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित 'विशेष रणनीतिक साझेदारी हेतु भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त वक्तव्य' जारी किया गया। दोनों देश वार्षिक शिखर वार्ता के आयोजन पर भी सहमत हुए हैं।
- भारतीय प्रधानमंत्री और कोरियाई राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित 7 महत्त्वपूर्ण करार/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए—
  1. आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम और दोहरे कराधान के परिहार हेतु करार।
  2. दृश्य-श्रव्य सह-उत्पादन में सहयोग पर समझौता।
  3. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के मध्य सहयोग हेतु एमओयू।
  4. विद्युत ऊर्जा के विकास और नव ऊर्जा उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में एमओयू।
  5. युवा मामलों में सहयोग हेतु एमओयू।
  6. सड़क परिवहन और राजमार्गों के क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा।
  7. समुद्री परिवहन एवं संभार तंत्र (Logistics) के क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू।

- प्रधानमंत्री मोदी ने कोरियाई राष्ट्रपति को बोधिवृक्ष का एक पौधा भी उपहारस्वरूप दिया।
- प्रधानमंत्री मोदी की इस दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के एक्जिम (एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट) बैंक द्वारा भारत में स्मार्ट शहरों के विकास तथा अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की भी घोषणा की गई।

भारतीय राष्ट्रपति की रूस यात्रा

- 7-11 मई, 2015 के मध्य भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रूस की राजकीय यात्रा पर रहे।
- राष्ट्रपति मुखर्जी की यह यात्रा रूस में द्वितीय विश्वयुद्ध (जिसे रूस में 'ग्रेट पैट्रियाटिक वार' कहा जाता है) पर विजय की 70वीं वर्षगांठ के समारोह हेतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हुई।
- 8 मई, 2015 को राष्ट्रपति मुखर्जी को मास्को स्थित रूसी विदेश मंत्रालय की डिप्लोमेटिक एकेडमी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई।
- 8 मई को ही मास्को विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुखर्जी की उपस्थिति में 'भारत और रूस के उच्च शैक्षिक संस्थानों के नेटवर्क' का शुभारंभ किया गया।
- राष्ट्रपति मुखर्जी की इस रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के उच्च शैक्षिक संस्थानों के मध्य पारस्परिक सहयोग हेतु 7 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। इसके अतिरिक्त रूस के विज्ञान फाउंडेशन और भारत के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के मध्य भी एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ।
- 9 मई, 2015 को द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित विजय दिवस समारोह के अवसर पर मास्को के रेड स्क्वायर पर भव्य एवं विशाल सैन्य परेड आयोजित हुई। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अतिरिक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एवं उच्च स्तरीय प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। इस परेड में भारत एवं चीन सहित 10 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भी प्रतिभाग किया। ज्ञातव्य है कि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन गतिरोध के कारण इस समारोह से दूर रहे।
- 10 मई को राष्ट्रपति मुखर्जी द्वारा मास्को में 'नमस्ते रशिया' महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव रूस के कई शहरों में नवंबर, 2015 तक चलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9-16 अप्रैल, 2015 के दौरान यूरोप (फ्रांस, जर्मनी एवं कनाडा) की राजकीय यात्रा पर रहे।
- अपनी इस यूरोप यात्रा के प्रथम चरण (9-11 अप्रैल) में प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे।
- 10 अप्रैल को उन्होंने पेरिस में यूनेस्को (स्थापना-नवंबर, 1945) मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को की महानिदेशक इरेना बुकोवा की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक वेब पोर्टल (www.ideaofyoga.org) का शुभारंभ भी किया।
- 10 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस (फ्रास्वां) ओलांडे के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई जिसके पश्चात दोनों देशों एवं उनकी कंपनियों के मध्य कुल 20 समझौतों/पहलों/घोषणाओं पर हस्ताक्षर हुए जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. भारत की एलएंडटी एवं फ्रांस की एरेवा (AREVA) के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) : जैतपुर (महाराष्ट्र) परमाणु विद्युत परियोजना के स्थानीयकरण को बढ़ाकर वित्तीय व्यवहार्यता हेतु लागत कम करने के साथ यह समझौता भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं स्वदेशी परमाणु ऊर्जा उद्योग के विकास में भी सक्षम बनाएगा।
2. न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (NPCIL) और एरेवा के मध्य इंजीनियरिंग-पूर्व समझौते : यह समझौता जैतपुर संयंत्रों के संदर्भ में ही तकनीकी पहलुओं (एरेवा, एल्साथॉम एवं एनपीसीआईएल के बीच) को स्पष्ट करने से संबंधित है।
3. इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज (CNES) के मध्य एमओयू : मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह से डाटा प्रयोग भागीदारी की अवधि 2 वर्ष और बढ़ाने हेतु।
4. इसरो तथा फ्रांस के सीएनईएस एवं ओनेरा के बीच एमओयू : भारतीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर Ka-बैंड प्रोपेगेशन प्रयोग हेतु।
5. इसरो और सीएनईएस के मध्य कार्यक्रम करार : मंगल अन्वेषण एवं संयुक्त भू प्रेक्षण मिशन सहित अंतरिक्ष उपग्रह और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग हेतु।
6. भारत और फ्रांस के खेल मंत्रालयों के मध्य सहयोग पर एमओयू।
7. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों के मध्य एमओयू।
8. एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के एएफडी वित्तीयन के साथ गारंटी समझौता।
9. भारतीय रेल मंत्रालय एवं फ्रेंच नेशनल रेलवे (SNCF) के बीच रेलवे प्रोटोकॉल : भारत में सेमी हाईस्पीड रेल और स्टेशनों के जीर्णोद्धार हेतु सहयोग के लिए। इसके तहत दिल्ली-चंडीगढ़ रेल लाइन की गति 200 किमी. प्रति घंटा करने हेतु अध्ययन में फ्रांस भागीदारी करेगा तथा अंबाला एवं लुधियाना रेलवे स्टेशनों को नए सिरे से विकसित करने में भी सहयोग करेगा।
10. सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था।
11. पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर मंशा पत्र (LoI)।
12. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) एवं फ्रांस के राष्ट्रीय निवारक पुरातात्विक अनुसंधान संस्थान के मध्य सहयोग हेतु एलओआई।
13. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (दिल्ली) तथा नेशनल आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट (पेरिस) के बीच एमओयू।
14. इंडियन हेरिटेज सिटीज नेटवर्क फाउंडेशन (IHCN) एवं फ्रांस के एएनवीपीएएच के मध्य सहयोग हेतु एमओयू।

15. ऐतिहासिक स्मारकों के जुड़वांकरण (Twining) हेतु प्रस्ताव।
16. 24 माह की अवधि हेतु भारतीय एवं फ्रांसीसी छात्रों के एक-दूसरे देश में प्रवास अनुमति के लिए वीआईई (वोलोंटैरिएट इंटरनेशनल एन एंटरप्राइज) योजना।
17. भारतीय आयुष मंत्रालय और फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के मध्य आयुर्वेद क्षेत्र में सहयोग पर एलओआई।
18. भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) और फ्रांस के राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता आयोग (CNCD) के मध्य एमओयू।
19. भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च (CNRS) के बीच सहयोग हेतु एमओयू।
20. भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग और फ्रांस के सीएनआरएस एवं यूपीएमसी के मध्य सहयोग पर एमओयू : अंडमान से लक्षद्वीप तक भारत के समुद्री क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं के हब एवं स्पोक नेटवर्क के साथ भारत में 'राष्ट्रीय समुद्री जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान' स्थापित करने हेतु।

- प्रधानमंत्री मोदी की इस फ्रांस यात्रा के दौरान भारत द्वारा फ्रांस से तत्काल आधार पर 36 रॉफेल जेट विमान खरीदे जाने पर भी सहमति हुई। विमानों का यह सौदा विगत 3 वर्षों से लंबित 126 रॉफेल विमानों के सौदे से इतर है।
- फ्रांस द्वारा भारत में 2 बिलियन यूरो (लगभग 6200 करोड़ रुपये) के निवेश की घोषणा की गई। फ्रांस भारत में 3 स्मार्ट सिटी विकसित करने में सहायता भी करेगा जिसमें पुडुचेरी और नागपुर शामिल होंगे।
- अपनी इस यूरोप यात्रा के द्वितीय चरण (12-14 अप्रैल) में प्रधानमंत्री मोदी 12 अप्रैल को जर्मनी के हैनोवर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष आयोजित हैनोवर मेले ('हैनोवर मेस्से'-विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला) में भारत पार्टनर देश है।
- 12 अप्रैल को ही हैनोवर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिटी हॉल में गांधीजी की आवक्ष प्रतिमा को अनावरण किया गया तथा उसके बाद हैनोवर मेले के उद्घाटन समारोह में उन्होंने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ प्रतिभाग किया।
- 13 अप्रैल को हैनोवर मेले में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जर्मन चांसलर के साथ भारतीय पैवेलियन (जिसमें मुख्य बल 'मेक इन इंडिया' पर था) का उद्घाटन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बर्लिन पहुंचे जहां वे पहले सीमेंस तकनीकी अकादमी देखने गए।
- 14 अप्रैल को चांसलर मर्केल से द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जर्मन रेलवे स्टेशन देखने गए जो कि यूरोप में एक अनोखा मॉडल रेलवे स्टेशन है।
- 14 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी यूरोप यात्रा के तृतीय चरण (14-16 अप्रैल) के लिए कनाडा के ओटावा पहुंचे। उल्लेखनीय है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कनाडा की पृथक यात्रा इससे पूर्व 1973 में हुई थी।
- प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा यात्रा का कार्यक्रम इस प्रकार रहा—

(i) 15 अप्रैल को ओटावा में औपचारिक स्वागत एवं तत्पश्चात कनाडा के गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन से मुलाकात और फिर प्रधानमंत्री (तत्कालीन) स्टीफन हार्पर के साथ द्विपक्षीय बैठक।

(ii) 15 अप्रैल को ही टोरंटो प्रस्थान जहां शाम को प्रधानमंत्री हॉर्पर के साथ वार्ता और रिको कोलिजियम (Ricoh Coliesium - आइस हॉकी स्टेडियम एवं प्रदर्शनी स्थल के रूप में प्रयुक्त होने वाला स्थान) में भारतीय डायस्पोरा कार्यक्रम में प्रतिभाग एवं संबोधन।

(iii) 16 अप्रैल को टोरंटो में ही पेंशन फंड बैठक एवं कतिपय व्यवसाय बैठकों में प्रतिभाग और तत्पश्चात एयर इंडिया स्मारक का अवलोकन।

(iv) 16 अप्रैल को ही वैंकूवर जाकर लक्ष्मीनारायण मंदिर की यात्रा एवं गुरुद्वारा भ्रमण तथा भारतीय समुदाय से चर्चा। उसी दिन शाम को भारत के लिए प्रस्थान।

- प्रधानमंत्री मोदी की इस कनाडा यात्रा के दौरान 15 अप्रैल, 2015 को हुए महत्त्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित असैन्य परमाणु आपूर्ति समझौते के तहत भारत, कनाडा की केमेको (Cameco) कंपनी से अगले 5 वर्षों में 3,000 मीट्रिक टन से अधिक (17.1 मिलियन पाउंड) यूरेनियम 280 मिलियन डॉलर की अनुमानित कीमत पर प्राप्त करेगा। उल्लेखनीय है कि कनाडा का यूरेनियम भंडार में ऑस्ट्रेलिया के बाद और यूरेनियम उत्पादन में कजाख्स्तान के बाद विश्व में द्वितीय स्थान है।
- इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष सहयोग, रेलवे, नागरिक विमानन, शिक्षा एवं कौशल विकास आदि के संदर्भ में भी समझौते हुए।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- 27-29 अप्रैल, 2015 के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घानी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे।
- यह सितंबर, 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा थी।
- 28 अप्रैल को राष्ट्रपति घानी की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक सहयोग के संवर्धन पर बल देते हुए भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण से जुड़े प्रयासों में अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत द्वारा निभाई जा रही विशेष भूमिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति घानी ने शैक्षिक वर्ष 2021-22 तक भारत द्वारा प्रतिवर्ष 1,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने के निर्णय का स्वागत किया।
- उन्होंने अप्रैल, 2015 में तीन बहुप्रयोजनीय 'चीतल' हेलिकॉप्टर उपहार में देने के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया।
- दोनों पक्षों द्वारा तीन माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई—

(i) प्रत्यर्पण संधि।

(ii) सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर करार।

(iii) आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि।

(iv) सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि।

(v) भारत और अफगानिस्तान के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहन यातायात के विनियमन हेतु मोटर वाहन करार।

(vi) राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश पर एमओयू।

- अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति घानी ने 28 अप्रैल को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स रिसर्च सेंटर में भाषण दिया तथा 29 अप्रैल को वे फिक्की, सीआईआई और एसोचैम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बैठक में भी शामिल हुए।

भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 मार्च, 2015 के दौरान श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे जो कि 28 वर्षों के पश्चात भारत के किसी प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा थी।
- प्रधानमत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत द्वारा रेलवे परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 318 मिलियन डॉलर की नई ऋण श्रृंखला (Line of Credit) जारी करने (रोलिंग स्टॉक की खरीद और रेल पटरी उन्नयन हेतु) पर सहमति व्यक्त की गई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका द्वारा मुद्रा विनिमय व्यवस्था (Currency Swap Arrangement) को पूर्व के 400 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर करने हेतु समझौता किया गया जिससे श्रीलंकाई रुपये को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।
- दोनों देश समुद्री अर्थव्यवस्था पर एक संयुक्त कार्यबल के गठन पर भी सहमत हुए। साथ ही दोनों पक्षों द्वारा मछुआरों के मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान ढूंढ़ने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों देशों द्वारा युवा विकास मामलों में दो समझौते किए गए तथा श्रीलंका में मतारा स्थित रूहुना यूनिवर्सिटी में रबींद्रनाथ टैगोर आडिटोरियम की स्थापना पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों पक्षों द्वारा सीमा शुल्क क्षेत्र में सहयोग पर समझौता भी किया गया जो पारस्परिक व्यवसाय अभिवृद्धि में सहायक होगा।
- प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मार्च को ही श्रीलंका की संसद को संबोधित किया तथा उसी दिन उन्होंने श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी को संबोधित किया।
- 14 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के तमिल बहुल शहर-जाफना और तलाइमन्नार गए। जाफना में उन्होंने इलावलाई उत्तर-पश्चिम आवासीय परियोजना का लोकार्पण किया (ज्ञातव्य है कि गृहयुद्ध में बर्बाद हुए इस शहर में बेघर तमिलों हेतु 50,000 आवासों का निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है जिनमें से 27,000 पूरे हो चुके आवासों को सौंपा गया) तथा वहां एक सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला भी रखी। तलाईमन्नार में भारत की सहायता से पुनर्निर्मित रेल लाइन पर एक रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा

- 11-12 मार्च, 2015 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस की राजकीय यात्रा संपन्न की।
- 11 मार्च को पोर्ट लुई में दोनों देशों के बीच निम्नलिखित 5 करार/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए—

(i) महासागर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।

(ii) वर्ष 2015-18 के लिए 'सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम' पर समझौता।

(iii) भारत से ताजे आम के मॉरीशस को निर्यात हेतु प्रोटोकॉल।

(iv) मॉरीशस के अगालेगा (Agalega) द्वीप पर समुद्री और वायु परिवहन सुविधाओं में सुधार हेतु समझौता ज्ञापन।

(v) होम्योपैथी और चिकित्सा की पारंपरिक पद्धति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

- द्विपक्षीय वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मॉरीशस में दूसरी 'साइबर सिटी' (प्रथम भारत के ही सहयोग से निर्मित हुई है) के निर्माण में सहयोग प्रदान करने तथा मॉरीशस को अवसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु 500 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- 12 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के 47वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया तथा इस अवसर पर उन्होंने मॉरीशस की नेशनल असेम्बली को भी संबोधित किया।
- 12 मार्च को ही भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मॉरीशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारत निर्मित ऑफ-शोर गश्ती पोत (OPV) बार्राकुडा (जिसे 20 दिसंबर, 2014 को मॉरीशस को सौंपा गया था) को मॉरीशस के नेशनल कोस्ट गार्ड (तटरक्षक बल) की सेवा में कमीशन किया गया। साथ ही उन्होंने पोर्ट लुई में विश्व हिंदी सचिवालय की आधारशिला रखी और वहां हिंदू पवित्र स्थल 'गंगा तालाब' (ग्रैंड बेसिन) में भगवान शिव की पूजा भी की।

◆◆◆

आर्थिक मंथन

● बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक की स्थापना ● 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम ● प्रशांत-पारीय भागीदारी (TPP) समझौता ● जून-अंत, 2015 में भारत का विदेशी ऋण ● वर्ष 2015-16 की चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति ● वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय ● परक्राम्य लिखत (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 ● स्टार्ट-अप और एमएसएमई हेतु दो नए कोष ● प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ● स्वर्ण मौद्रीकरण एवं सॉवरेन स्वर्ण बांड योजनाएं ● भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों को सैद्धांतिक स्वीकृति ● व्हाइट लेबल एटीएम परिचालन में एफडीआई सीमा हुई 100 प्रतिशत ● 'पेय एल्कोहॉल' का विनियमन प्राधिकार राज्यों को देने हेतु संशोधन स्वीकृत ● कृषिगत उत्पादन के नवीनतम आंकड़े ● सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में सुधार हेतु 'इंद्रधनुष' योजना ● भारत में प्रत्यक्ष होता 'राजकोषीय संघवाद' ● जैम त्रयी ● फसल बीमा पोर्टल ● राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ● ई-पर्यटक वीज़ा योजना का विस्तार ● प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ● राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रोत्साहन हेतु योजना ● एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) ● खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ● राष्ट्रीय आय 2014-15 के प्रॉविजनल आंकड़े ● 17 नए मेगा फूड पार्कों को स्वीकृति ● फोर्ब्स की 'ग्लोबल-2000' सूची ● वर्ष 2014-15 में भारत का विदेशी व्यापार ● सेशेल्स विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल ● प्रधानमंत्री 'मुद्रा' योजना का शुभारंभ ● नई विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-2020 ● परंपरागत मनीऑर्डर सेवा बंद ● संघीय बजट 2015-16 ● आर्थिक समीक्षा 2014-15 ● 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ● पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'श्रमेव जयते' योजना ● 'मेक इन इंडिया' वैश्विक पहल ● सुकन्या समृद्धि योजना ● यूरेशियाई आर्थिक संघ (EEU) का गठन

बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक की स्थापना

- 19 अक्टूबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आईडीएफसी बैंक के पूर्ण बैंक के रूप में परिचालन का औपचारिक शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी उपस्थित थे।
- इससे पूर्व 25 अगस्त, 2015 को कोलकाता में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बंधन बैंक का पूर्ण बैंक के रूप में औपचारिक उद्घाटन किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 अप्रैल, 2014 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि. (IDFC) तथा बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (BFSL) को भारत में नए बैंक प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी तथा तत्पश्चात आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत संतोषजनक पाए जाने के बाद बंधन बैंक को जून, 2015 में तथा आईडीएफसी बैंक को जुलाई, 2015 में आरबीआई द्वारा पूर्ण बैंक के रूप में कार्य करने हेतु यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था।
- इससे पूर्व यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई द्वारा 2003-04 में जारी किए गए थे जब कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था।
- आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक के प्रारंभ के साथ अब देश में निजी क्षेत्र के नए वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 9 हो गई है। शेष 7 हैं—एक्सिस बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस इंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक। इनके अतिरिक्त 13 निजी क्षेत्र के पुराने वाणिज्यिक बैंक हैं।
- अब भारत में प्रचालित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 149 हो गई है जिनका विवरण इस प्रकार है—
  - (i) 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (इनमें भारतीय स्टेट बैंक और उसके 5 सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय महिला बैंक एवं आईडीबीआई बैंक शामिल हैं)।
  - (ii) 13 निजी क्षेत्र के पुराने वाणिज्यिक बैंक
  - (iii) 9 निजी क्षेत्र के नए वाणिज्यिक बैंक
  - (iv) 43 विदेशी बैंक (26 देशों के)
  - (v) 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आईडीएफसी और बीएफसीएल

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि. (IDFC) भारत की एक महत्त्वपूर्ण अवसंरचना विकास वित्त प्रदाता कंपनी है जिसकी स्थापना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में राकेश मोहन समिति की सिफारिशों के अनुरूप 1997 में की गई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (CEO) विक्रम लिमये तथा एक्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉ. राजीव बी. लाल हैं। डॉ. लाल को ही नवस्थापित आईडीएफसी बैंक का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा अनिल बैजल को गैर-कार्यकारी चेयरमैन (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि आईडीएफसी बैंक द्वारा 1 अक्टूबर, 2015 से परिचालन प्रारंभ किया गया था।

बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. (BFSL) की स्थापना एक सूक्ष्म-वित्त (Microfinance) प्रदाता कंपनी के रूप में वर्ष 2001 में की गई थी जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह प्रदत्त ऋणों की दृष्टि से देश की सबसे वृहद सूक्ष्म-वित्त कंपनी है। बंधन बैंक का गठन 23 दिसंबर, 2014 को बीएफएसएल के स्वामित्व वाली 'बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स' के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया। बीएफएसएल के संस्थापक चेयरमैन चंद्रशेखर घोष ही बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बने हैं जबकि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अशोक लाहिड़ी को इस बैंक का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि कोलकाता मुख्यालय वाला बंधन बैंक भारत की स्वतंत्रता के बाद पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक है।

'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम

- 15 अगस्त, 2015 को लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में युवाओं में उद्यमिता (Entrepreneurship) को प्रोत्साहन देने हेतु 'स्टार्ट- अप इंडिया' (Start-up India) कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की घोषणा की।
- उन्होंने 'स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया' का आह्वान करते हुए कहा कि हमें स्टार्ट अप कंपनियों हेतु समर्थकारी प्रणालियों और व्यवस्थाओं पर ध्यान देकर भारत को विश्व में स्टार्ट-अप के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर लाना है। इस संदर्भ में

उन्होंने देश की 1.25 लाख बैंक शाखाओं में से प्रत्येक द्वारा कम से कम एक दलित या जनजातीय उद्यमी तथा कम से कम एक महिला उद्यमी को प्रोत्साहन दिए जाने की बात भी कही।

- 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन को त्वरित गति से बढ़ावा देने हेतु स्टार्ट-अप उद्यमों एवं कंपनियों को बैंक वित्तीयन एवं अन्य प्रोत्साहन उपाय उपलब्ध कराना है।
- इस कार्यक्रम के तहत नए उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक विनियामक स्वीकृतियों की प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा व्यवसाय हेतु बेहतर माहौल का सृजन एवं संवर्धन करना भी शामिल है।
- इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में देश में उद्यमिता पारितंत्र को विशेष रूप से बेहतर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश को स्टार्ट अप उद्यमों के संदर्भ में विश्व में शीर्ष पर लाया जा सके।
- अक्टूबर, 2015 में नास्कॉम (Nasscom) द्वारा जारी एक रिपोर्ट 'Start-up India : Momentous Rise of the Indian Start-up Ecosystem' के अनुसार वर्ष 2015 में भारत-आधारित स्टार्ट-अप कंपनियों में लगभग 5 बिलियन डॉलर का निवेश होने का आकलन है जो कि 2014 के 2.2 बिलियन डॉलर से 125 प्रतिशत अधिक है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2015 में 4,200 स्टार्ट-अप कंपनियों (जो 2014 से 40 प्रतिशत अधिक हैं) के साथ इजरायल को पीछे छोड़ते हुए विश्व में तीसरे सबसे बड़े (अमेरिका एवं ब्रिटेन के बाद) स्टार्ट-अप बाजार के रूप में उभरा है।
- नास्कॉम का आकलन है कि वर्ष 2010-14 अवधि में देश में स्टार्ट-अप कंपनियों में संचयी निवेश 3.2 बिलियन डॉलर रहा है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक युवा स्टार्ट-अप उद्यमों वाला देश है जहां इन उद्यमों में से 72 प्रतिशत के संस्थापक 35 वर्ष से कम आयु के हैं। साथ ही इस वर्ष महिला उद्यमियों का हिस्सा गत वर्ष से 50 प्रतिशत बढ़ गया है और कुल स्टार्ट-अप उद्यमों में से 9 प्रतिशत की सह-संस्थापक महिलाएं हैं।

स्टार्ट-अप उद्यम

स्टार्ट-अप (Start-up) से तात्पर्य एक उद्यमिता साहस (Entrepreneurial Venture) या एक नव प्रारंभ व्यवसाय से है जो कि एक कंपनी, उद्यम, भागीदारी या अस्थायी संगठन के रूप में पुनर्प्रयोज्य एवं मापनीय व्यवसाय मॉडल की उपलब्धि हेतु तैयार अथवा शुरू किया जाता है। ये कंपनियां या उद्यम सामान्यतः नवसृजित होते हैं, विकास प्रक्रिया में नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तथा लक्ष्यित बाजारों के लिए अनुसंधान एवं उपयुक्तता के आधार पर कार्य करते हैं। ज्ञातव्य है कि स्टार्ट-अप शब्द 1997-2000 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ था जब बड़ी संख्या में डॉट-कॉम कंपनियों की स्थापना हुई थी। इस पृष्ठभूमि के कारण कभी-कभी स्टार्ट-अप को मात्र टेक्नोलॉजी कंपनियां मान लिया जाता है, परंतु यह सही नहीं है। स्टार्ट-अप वस्तुतः ऐसे सभी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए प्रयुक्त होता है जिनसे उच्च महत्त्वाकांक्षा, नवप्रवर्तन, मापनीयता (Scalability) और वृद्धि की प्रवृत्ति संलग्न हो।

- भारत में वर्तमान में बंगलुरू, मुंबई और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की स्टार्ट-अप कंपनियों में कुल निवेशों में 93 प्रतिशत की भागीदारी है तथा सभी स्टार्ट-अप उद्यमों का 66 प्रतिशत इन्हीं तीन हाईटेक संकुलों (Clusters) में स्थित है। इनके अतिरिक्त अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और पुणे भी स्टार्ट-अप शहरों के रूप में उभर रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि देश में स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 18 अगस्त, 2015 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के तहत 'इंडिया एस्पिरेशन फंड' (IAF : India Aspiration Fund) और 'सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेज' (SMILE : SIDBI Make in India Loan for Enterprises) नामक दो महत्वपूर्ण कोषों का शुभारंभ किया गया है (इनका विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे प्रस्तुत किया गया है)।

प्रशांत-पारीय भागीदारी (TPP) समझौता

- 5 अक्टूबर, 2015 को लगभग 7 वर्षों की गहन वार्ताओं के बाद अमेरिका एवं जापान सहित प्रशांत रिम (Pacific Rim) क्षेत्र के 12 देशों के मध्य 'प्रशांत-पारीय भागीदारी' (TPP : Trans-Pacific Partnership) समझौते के मसौदे (Draft) पर अमेरिका के अटलांटा में सहमति व्यक्त की गई।
- यह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य प्रशांत रिम क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र और यूरोपीय संघ की ही तरह एकल बाजार का सृजन करना है।
- टीपीपी वस्तुतः प्रशांत-पारीय रणनीतिक आर्थिक भागीदारी समझौते (TPSEP or P4 : Trans-Pacific Strategic Economic Partnership) का ही विस्तार है जिस पर 2006 में ब्रुनेई, चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2008 से इस समझौते को व्यापक रूप प्रदान करने हेतु वार्ताओं में क्रमिक रूप से 8 अन्य देश- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, अमेरिका एवं विएतनाम शामिल हुए तथा इन्हीं 12 देशों द्वारा टीपीपी के मसौदे पर सहमति व्यक्त की गई है।
- ये सभी 12 देश समग्र रूप से विश्व अर्थव्यवस्था के लगभग 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप इन देशों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न मुद्दों से संबंधित व्यापार समझौता है। इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार बाधाओं (यथा-टैरिफ) को न्यून करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRS) हेतु एक समान रूपरेखा स्थापित करने, श्रम कानूनों एवं पर्यावरण कानूनों हेतु मानदंड लागू करने तथा एक निवेशक-राज्य विवाद निपटान प्रणाली स्थापित करने की बात कही गई है।
- वस्तुतः अमेरिका के ओबामा प्रशासन के मुख्य व्यापार एजेंडा लक्ष्यों में टीपीपी का क्रियान्वयन भी शामिल है। अमेरिका द्वारा इसे यूरोपीय संघ के साथ हुए उसके ट्रांस-अटलांटिक व्यापार एवं निवेश भागीदारी (TTIP) समझौते के समकक्ष रूप में देखा जा रहा है।
- टीपीपी समझौते पर अंतिम रूप से वर्ष 2016 में हस्ताक्षर होने तथा अगले दो वर्षों में सभी भागीदार देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात इसके लागू होने की आशा व्यक्त की गई है।

- प्रशांत रिम के अन्य देशों में इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया द्वारा भी टीपीपी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की गई है।

जून-अंत, 2015 में भारत का विदेशी ऋण

- मानक प्रथाओं के तहत भारत में विदेशी ऋण भार संबंधी आंकड़े मार्च और जून में अंत होने वाली तिमाहियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तथा सितंबर एवं दिसंबर में अंत होने वाली तिमाहियों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तद्नुसार 30 सितंबर, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून-अंत, 2015 में भारत के विदेशी ऋण भार संबंधी अद्यतन आंकड़े जारी किए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जून-अंत, 2015 में भारत का कुल विदेशी ऋण भार 482.9 बिलियन डॉलर के स्तर पर था, जो मार्चांत, 2015 के 474.4 बिलियन डॉलर की तुलना में 1.8 प्रतिशत (8.5 बिलियन डॉलर) तथा जून-अंत, 2014 की तुलना में 6.6 प्रतिशत (29.8 बिलियन डॉलर) की वृद्धि दर्शाता है।
- मार्चांत, 2015 की तुलना में जून-अंत, 2015 में भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि का मुख्य कारण अनिवासी भारतीय (NRI) जमाओं तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ECBs : External Commercial Borrowings) में वृद्धि है। हालांकि विदेशी ऋण की मात्रा में वृद्धि आंशिक रूप से मूल्यन प्रतिलाभों (Valuation gains) के कारण कम ही रही जिसका कारण भारतीय रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर का अधिमूल्यन था (जिसके न होने पर इस अवधि में यह वृद्धि 10.1 बिलियन डॉलर होती)।
- देश के विदेशी ऋण भार में वृद्धि वाला 2015-16 लगातार 14वां वर्ष है।
- जून-अंत, 2015 में देश के कुल विदेशी ऋण भार में सर्वाधिक भाग बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (185.4 बिलियन डॉलर; 38.4 प्रतिशत) का था जिसके बाद क्रमशः एनआरआई जमाओं (119.9 बिलियन डॉलर) तथा अल्पावधिक ऋणों (84.4 बिलियन डॉलर) का स्थान था।
- जून-अंत, 2015 में कुल विदेशी ऋण में अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता-Original Maturity) का भाग 17.5 प्रतिशत (84.4 बिलियन डॉलर) तथा दीर्घावधिक ऋण का भाग 82.5 प्रतिशत (398.5 बिलियन डॉलर) था। कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) की हिस्सेदारी में गिरावट का कारण सरकारी ट्रेजरी बिलों में एफआईआई निवेश का बाहर निकलना है।
- अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) के देश के विदेशी मुद्रा कोष से अनुपात में भी कमी हुई है (कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण का घटता प्रतिशत तथा विदेशी मुद्रा कोष में हुई वृद्धि, दोनों इसके लिए उत्तरदायी हैं) तथा यह मार्चांत, 2015 के 24.8 प्रतिशत से घटकर जून-अंत, 2015 में 23.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है।
- अवशिष्ट परिपक्वता (Residual Maturity) के आधार पर अल्पावधिक ऋण (इसमें वे दीर्घावधिक ऋण भी शामिल होते हैं जिनकी अदायगी आगामी 1 वर्ष के भीतर होनी होती है) के हिस्से में भी कमी आई है जो मार्चांत, 2015 के 38.9 प्रतिशत से कम होकर जून-अंत 2015 में कुल विदेशी ऋण के 38.3 प्रतिशत (189.1 बिलियन डॉलर) के स्तर पर रहा है। इसका देश के विदेशी मुद्रा कोष से अनुपात भी मार्चांत, 2015 के 54.2 प्रतिशत से कम होकर जून-अंत, 2015 में 51.9 प्रतिशत रह गया है।
- मार्चांत, 2015 के 89.8 बिलियन डॉलर की तुलना में जून-अंत, 2015 में सरकारी (संप्रभु; Sovereign) विदेशी ऋण 89.5 बिलियन डॉलर के स्तर पर थे। कुल विदेशी ऋण में सरकारी और गैर-सरकारी ऋण का भाग जून-अंत, 2015 में क्रमशः 18.5 प्रतिशत एवं 81.5 प्रतिशत था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी ऋण मार्चांत, 2015 के समान जून-अंत, 2015 में 4.5 प्रतिशत के स्तर पर रहे।
- जून-अंत, 2015 में भारत के विदेशी ऋण का सर्वाधिक भाग अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित था (58.1 प्रतिशत), जिसके बाद रुपया ऋण (28.4 प्रतिशत) का स्थान था। कुल विदेशी ऋण में एसडीआर (IMF के Special Drawing Rights) में 5.9 प्रतिशत, जापानी येन में 3.9 प्रतिशत तथा यूरो में 2.3 प्रतिशत मूल्य की दृष्टि से था।
- ऋण सेवा अनुपात (Debt-Service Ratio) मार्चांत, 2014 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर (मुख्यतः ECBs के उच्चतर पुनर्भुगतान के कारण) मार्चांत, 2015 में 7.5 प्रतिशत हो गया था जो कि जून-अंत, 2015 में भी इसी स्तर पर है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण मार्चांत, 2015 के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर जून-अंत, 2015 में 24.0 प्रतिशत हो गया है।

भारत के विदेशी ऋण के प्रमुख संकेतक

(बिलियन डॉलर)

मद	मार्चांत, 2015	जून-अंत, 2015
1. बहुपक्षीय ऋण	52.4	53.4
2. द्विपक्षीय ऋण	21.6	20.8
3. आईएमएफ	5.5	5.6
4. निर्यात क्रेडिट	12.6	12.1
5. वाणिज्यिक उधारियां	180.9	185.4
6. एनआरआई जमाएं	115.2	119.9
7. रूपया ऋण	1.5	1.4
8. अल्पावधिक ऋण जिसमें,	84.7	84.4
अल्पावधिक व्यापार क्रेडिट	80.8	80.0
कुल विदेशी ऋण (1 से 8)	**474.4**	**482.9**
दीर्घावधिक ऋण (1 से 7)	389.7	398.5
सरकारी ऋण	89.8	89.5
गैर-सरकारी ऋण	384.7	393.4

- इसी अवधि में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल विदेशी ऋण से अनुपात भी 72.0 प्रतिशत से बढ़कर 73.7 प्रतिशत हो गया है।
- भारत के कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात

मार्चांत, 2015 के 8.8 प्रतिशत से थोड़ा घटकर जून-अंत, 2015 में 8.7 प्रतिशत के स्तर पर रहा है।

- विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व के 20 सर्वाधिक ऋणग्रस्त विकासशील देशों में भारत का स्थान कुल विदेशी ऋण के संदर्भ में चीन, ब्राजील और मेक्सिको के बाद चौथा था। विदेशी ऋण स्टॉक के सकल राष्ट्रीय आय (GNI) से सबसे कम अनुपात के संदर्भ में भारत 23.0 प्रतिशत के साथ छठें स्थान पर (चीन, फिलीपींस, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं पाकिस्तान के बाद) था तथा विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा विदेशी ऋण को उपलब्ध कराए गए कवर के संदर्भ में भी भारत का छठां स्थान (चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, पेरू और ब्राजील से नीचे) था।

वर्ष 2015-16 की चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति

- 29 सितंबर, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 की चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति (Fourth Bi-monthly Monetary Policy) जारी की गई।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2015-16 की प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति 7 अप्रैल, 2015 को, द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति 2 जून, 2015 को तथा तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति 4 अगस्त, 2015 को जारी की गई थी।
- वर्ष 2015-16 की चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति के तहत वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि—
  - (i) चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF : Liquidity Adjustment Facility) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक कम करके 7.25 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत किया जाए (तदनुसार एलएएफ के अंतर्गत प्रतिवर्ती/रिवर्स रेपो दर 6.25 प्रतिशत से कम होकर 5.75 प्रतिशत तथा बैंक दर एवं सीमांत स्थायी सुविधा-एमएसएफ दर 8.25 प्रतिशत से कम होकर 7.75 प्रतिशत पर समायोजित हो गई हैं)।
  - (ii) अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR : Cash Reserve Ratio) को उनकी निवल मांग और मियादी देयताओं (NDTL : Net Demand and Time Liabilities) के 4.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाए।
  - (iii) नीलामियों के माध्यम से एलएएफ रेपो दर पर बैंक-वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर ओवरनाइट रेपो तथा बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 14-दिवसीय मियादी रेपो के साथ-साथ दीर्घावधिक मियादी रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए।
  - (iv) चलनिधि की निर्बाध उपलब्धता के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो और प्रतिवर्ती रेपो को जारी रखा जाए।
- इस द्विमासिक मौद्रिक नीति में भी सांविधिक तरलता अनुपात (SLR : Statutory Liquidity Ratio) में कोई परिवर्तन न करते हुए इसे 21.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
- मुद्रास्फीति की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए नीतिगत रेपो दर में वर्ष 2015 में की गई यह चौथी कमी है। इससे पूर्व 15 जनवरी, 2015 को, 4 मार्च, 2015 को तथा 2 जून, 2015 को रेपो दर में 0.25-0.25 प्रतिशतांक की तीन कटौतियां आरबीआई द्वारा की गई थी (इस प्रकार कुल मिलाकर वर्ष 2015 में अब तक रेपो दर में 1.25 प्रतिशतांक की कटौती की जा चुकी है)। इसके अतिरिक्त एसएलआर में विगत कटौती 3 फरवरी, 2015 को (22.0 से घटाकर 21.5 प्रतिशत) की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में आरबीआई की तरफ से नीतिगत दरों में 1.25 प्रतिशतांक की कटौती के बावजूद भी बैंकों द्वारा आम जनता या उद्योग जगत के लिए कर्ज की दरों में अधिकतम 0.75 प्रतिशतांक तक ही कमी की गई है जिसे देखते हुए आरबीआई द्वारा बैंकों की आधार दर (Base Rate—वह न्यूनतम दर जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को कर्ज देता है; वर्तमान में बैंक अपने-अपने फॉर्मूले पर इसका निर्धारण करते हैं) संबंधी नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है।
- वर्ष 2015-16 की चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति का जनवरी, 2016 तक 5.8 प्रतिशत तक पहुंचना अपेक्षित माना गया है, जो कि विगत द्विमासिक मौद्रिक नीति (अगस्त, 2015) में आकलित स्तर से मामूली सा कम है। ज्ञातव्य है कि फरवरी, 2015 में भारत सरकार और रिजर्व बैंक के मध्य 'मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौता' (Monetary Policy Framework Agreement) हस्ताक्षरित हुआ है जो कि आने वाले वर्षों में मौद्रिक नीति का रूप तय करेगा।
- जहां तक वर्ष 2015-16 के लिए जीवीए (आउटपुट) वृद्धि दर आकलनों का संबंध है, जोखिमों और अधोगामी संशोधन के बीच किए गए संतुलन को दर्शाते हुए तथा विभिन्न जोखिमों को लेकर अनिश्चितताओं की अधोगामी प्रवृत्ति को प्रकट करते हुए वर्ष 2015-16 के लिए वृद्धि दर अनुमान को पूर्वानुमानित 7.6 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया गया है।
- रिजर्व बैंक ने बैंकों की आधार दर, जो कि निधियों की उनकी सीमांत लागत पर आधारित होती है, के परिकलन पर बैंकों के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप राय जानने के लिए उपलब्ध कराया है। ये दिशा-निर्देश नवंबर, 2015 के अंत तक जारी किए जाएंगे।
- रिजर्व बैंक 1 जनवरी, 2016 तक अपने सभी प्रमुख विनियमों को अद्यतन करेगा और विनियमों के अनुपालन के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं को सुचारु बनाएगा। प्रमुख विनियमों को पूर्णतः अद्यतन कर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रिजर्व बैंक विनियामक संवादों में स्पष्टता को बढ़ाने का भी प्रयास करेगा।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा निवेश की अधिक पूर्वानुमान करने योग्य व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से ऋण प्रतिभूतियों (Debt Securities) में एफपीआई सीमाओं के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क (MTF) सरकार से परामर्श करते हुए तैयार किया गया है, जिसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं—
  - (i) आगे से, ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमाएं रुपये में मूल्यवर्गित कर घोषित/निर्धारित की जाएंगी।
  - (ii) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमाओं

को चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर मार्च, 2018 तक बकाया स्टॉक के 5 प्रतिशत तक किया जाएगा। समग्र रूप से, यह प्रत्याशा है कि इसके कारण सभी सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) से संबंधित वर्तमान 1,535 बिलियन (अरब) रु. की सीमा के अतिरिक्त केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 1,200 बिलियन (1.2 लाख करोड़) रु. के अतिरिक्त निवेश की गुंजाइश बनेगी।

(iii) इसके अतिरिक्त राज्य विकास ऋणों (SDLs) में एफपीआई निवेश हेतु एक पृथक सीमा होगी, जिसे मार्च, 2018 तक चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर बकाया स्टॉक के 2 प्रतिशत तक किया जाएगा। इससे मार्च, 2018 तक लगभग 500 बिलियन रु. की एक अतिरिक्त सीमा प्राप्त होगी।

(iv) सीमाओं में वृद्धि की घोषणा प्रत्येक छमाही में मार्च और सितंबर में की जाएगी तथा उसे प्रत्येक तिमाही में जारी किया जाएगा।

(v) सरकारी प्रतिभूतियों (SDL सहित) में निवेश करने की वर्तमान अपेक्षा, 3 वर्षों की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता सहित, जारी रहेगी।

(vi) वर्तमान वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए सीमाएं दो चरणों में (12 अक्टूबर, 2015 से तथा 1 जनवरी, 2016 से) बढ़ाई जाएंगी। प्रत्येक चरण में सीमाओं में वृद्धि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के संबंध में 130 बिलियन रु. (जिसमें दीर्घावधि निवेशकों के लिए 75 बिलियन रु. और अन्य के लिए 55 बिलियन रु.) तथा एसडीएल के संबंध में 35 बिलियन रु. (सभी एफपीआई निवेशकों के लिए उपलब्ध) होगी।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 1 दिसंबर, 2015 को जारी किया जाएगा।

वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय

- संघीय बजट 2015-16 में की गई घोषणा के अनुरूप 28 सितंबर, 2015 को वायदा बाजार आयोग (FMC : Forward Market Commission) का भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI : Securities and Exchange Board of India) में विलय प्रभावी हो गया।
- इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में कारोबार के प्रारंभ का परंपरागत घंटा बजाकर औपचारिक रूप से विलय की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 131 एवं 133 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 28 अगस्त, 2015 को अधिसूचना जारी कर वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय किए जाने तथा सेबी को ही जिंस (Commodities) वायदा बाजार का विनियमन सौंपे जाने की घोषणा की गई थी।
- इस अधिसूचना के तहत 'वायदा संविदा विनियमन अधिनियम (Forward Contracts Regulation Act), 1952' को निरस्त कर सेबी को वायदा बाजार विनियमन का हस्तांतरण किए जाने की तिथि 28 सितंबर, 2015 निश्चित की गई थी। उल्लेखनीय है कि इसी अधिनियम के तहत वायदा बाजार आयोग (FMC) का गठन 1953 में किया गया था जो कि अब तक भारत में कमोडिटी फ्यूचर्स के कारोबार का नियमन करता था।
- इसके अतिरिक्त 8 सितंबर, 2015 को 'प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम (Securities Contracts Regulation Act), 1956' में संशोधन (जिसके तहत अब वायदा बाजार का भी विनियमन लाया गया) को अधिसूचित किया गया था एवं इसके प्रभावी होने की तिथि भी 28 सितंबर, 2015 निर्धारित थी।
- इस प्रकार अब सेबी भारत में शेयर बाजार के साथ-साथ कमोडिटी बाजार का भी विनियामक निकाय बन गया है।
- उल्लेखनीय है कि सेबी की स्थापना 1988 में प्रतिभूति बाजार के विनियमन हेतु एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी तथा 1992 के सेबी अधिनियम के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ था।
- वस्तुतः सरकार द्वारा दोनों विनियामकों (एफएमसी एवं सेबी) के विलय का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जिंस व्युत्पन्न बाजार और प्रतिभूति व्युत्पन्न बाजार दोनों ही समान आर्थिक उद्देश्यों यथा—हेजिंग, प्रभावी मूल्य अन्वेषण एवं जोखिम प्रबंधन के लिए हैं तथा इनकी व्यापार रीतियों एवं प्रणालियों में निकट समानता है। साथ ही इस विलय से दोनों ही बाजारों में विनियमों का अभिसरण भी संभव हो सकेगा।
- वर्तमान में देश में कमोडिटी फ्यूचर्स हेतु 3 राष्ट्रीय स्तर के और 6 क्षेत्रीय स्तर के एक्सचेंज हैं जिनका सम्मिलित टर्नओवर 2014-15 में लगभग 60 लाख करोड़ रु. (इससे पिछले वित्त वर्ष में तो 101 लाख करोड़ रु. से अधिक) था।
- जिंसों के वायदा बाजार के विनियमन हेतु सेबी द्वारा एक पृथक कमोडिटी सेल (Cell) का सृजन तथा नए विभागों की स्थापना की गई है।

परक्राम्य लिखत (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015

- 22 सितंबर, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत 'परक्राम्य लिखत (Negotiable Instruments) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015' प्रख्यापित किया गया।
- इससे पूर्व 16 सितंबर, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी।
- इस अध्यादेश का उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 138 के तहत न्यायाधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण है।
- उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा 138 चेक (Cheque) के डिसऑनर/बाउंस होने से जनित अपराध से संबंधित है जिसके तहत किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता की स्थिति में आहर्ता (Drawer) द्वारा दिए गए चेक के डिसऑनर/बाउंस होने की स्थिति में उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है। परंतु यह वाद कहां दायर हो सकता है, यह स्पष्ट नहीं था।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में दिए गए एक निर्णय में इस संदर्भ में चेक जारी किए जाने वाले स्थान के क्षेत्राधिकार में वाद दायर होने की व्यवस्था दी गई थी। इस निर्णय से ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक संगठनों (जो कि चेक बाउंस होने पर वस्तुतः पीड़ित पक्ष होते हैं) के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने हेतु 'परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015' लोक सभा द्वारा 13 मई, 2015 को पारित हुआ था तथापि राज्य सभा में यह पारित नहीं हो सकता था।

- तत्पश्चात 15 जून, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 प्रख्यापित किया गया जिसके 31 अगस्त, 2015 को निष्प्रभावी होने (क्योंकि संसद के मानसून सत्र में भी तत्संबंधी विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका) के कारण अब पुनः यह संशोधन अध्यादेश लाया गया है, जो कि पूर्ववर्ती तिथि 15 जून, 2015 से ही प्रभावी होगा।
- इस अध्यादेश के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 की धारा 138 में संशोधन कर यह उपबंध किया गया है कि चेक डिसऑनर/बाउंस होने के मामले में चेक को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले स्थान के क्षेत्राधिकार में ही वाद दायर होगा।
- इस अध्यादेश के दायरे में खाते के जरिए चेक के भुगतान (या जमा) तथा खाते के अलावा चेक का भुगतान, अर्थात जब चेक अदाकर्ता बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किया जाए, इन दोनों को शामिल किया गया है।
- इस प्रकार चेक बाउंस होने से संबंधित मुद्दों में न्यायाधिकार क्षेत्र के स्पष्टीकरण से चेक की एक वित्तीय उपकरण के रूप में मान्यता में वृद्धि होगी तथा इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। इससे वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋणदाताओं को ऋण देने में सहूलियत होगी तथा चेक बाउंस होने पर वास्तविक पीड़ित पक्ष को अपने ही क्षेत्र में वाद दाखिल करने की सुविधा मिलेगी।

स्टार्ट-अप और एमएसएमई हेतु दो नए कोष

- 18 अगस्त, 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा देश में स्टार्ट-अप और एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए दो नए कोषों 'इंडिया एस्पिरेशन फंड' (IAF) और 'सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर स्माल इंटरप्राइजेज' (SMILE) का शुभारंभ किया गया।
- इन दोनों निवेश एवं ऋण कार्यक्रम कोषों का प्रारंभ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के तहत किया गया है।
- इंडिया एस्पिरेशन फंड (IAF) की स्थापना देश में स्टार्ट-अप पारितंत्र या वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए 'कोषों के कोष' (Fund of Funds) के रूप में की जाएगी।
- आईएएफ स्टार्ट-अप उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेश करने की बजाए विभिन्न वेंचर कैपिटल (Venture Capital) निधियों में निवेश करेगा ताकि वे एमएसएमई स्टार्ट-अप उद्यमों की इक्विटी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह नए निवेश विचारों एवं नवाचारों के साथ आने वाले वेंचर कैपिटलों की सहायता करेगा।
- आईएएफ हेतु प्रारंभिक निधि 2,000 करोड़ रु. रखी गई है तथा इसके तहत अब तक 750 करोड़ रु. से अधिक की राशि विभिन्न वेंचर कैपिटल फंडों को स्वीकृत की जा चुकी है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) आईएएफ में सह-निवेशक है।
- आईएएफ का प्रबंधन एक निवेश समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें नास्कॉम के पूर्व अध्यक्ष किरण कार्णिक, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन टी.वी. मोहनदास पई, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव हरकेश मित्तल, इंफोएज के संस्थापक संजीव भीखाचंदानी तथा इंडियन एंजेल नेटवर्क के सह-संस्थापक सौरभ श्रीवास्तव जैसे निवेश जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- स्माइल (SMILE : SIDBI Make in India Loan for Small Enterprises) का शुभारंभ 10,000 करोड़ रु. के प्रारंभिक आवंटन के साथ किया गया है।
- यह एक नवाचारी ऋण कार्यक्रम कोष है जो प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन के तहत शामिल 25 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- स्माइल भारतीय एमएसएमई उद्यमों को अर्द्ध-इक्विटी (Quasi-equity) और सावधि आधार (Term based) वाले अल्पकालिक ऋण कम सख्त नियमों एवं विनियमों के तहत उपलब्ध कराएगा।
- यह एमएसएमई उद्यमों को उनके ऋण-इक्विटी मानकों को पूरा करने तथा वृद्धि अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा।
- इन दोनों नए कोषों का उद्देश्य अगले 4 से 5 वर्षों में देश में स्टार्ट-अप और एमएसएमई उद्यमों में हजारों करोड़ रु. के निवेश को उत्प्रेरित करना तथा लाखों व्यक्तियों, मुख्यतः शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

- 17 सितंबर, 2015 को केंद्रीय खान एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खनन संबंधी परिचालनों से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित होने वाले लोगों और क्षेत्रों के कल्याण हेतु 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना' (PMKKKY) का प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई।
- इस योजना हेतु जिला खनिज फाउंडेशन (DMF : District Mineral Foundation) द्वारा सृजित निधियों का उपयोग किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—
  - (i) खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन; ये परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं के संपूरक का कार्य करेंगी।
  - (ii) खनन वाले जिलों में लोगों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिकी तथा पर्यावरण पर खनन के दौरान तथा उसके बाद पड़े प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना/दूर करना।
  - (iii) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधिक सतत आजीविका सुनिश्चित करना।
- इस योजना के तहत जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित करने हेतु जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करने पर ध्यान दिया गया है। पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला एवं बाल देखभाल, वृद्ध एवं अक्षम व्यक्तियों का कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता क्षेत्र इस योजना के तहत निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करेंगे।
- समर्थक एवं हितकारक जीवनयापन वातावरण के सृजन हेतु निधियों की शेष राशि सड़क, पुल, रेलवे एवं जलमार्ग परियोजनाओं, सिंचाई तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों को विकसित करने पर व्यय की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDR Act) 2015 के तहत खनन

संबंधी गतिविधियों से प्रभावित देश के सभी जिलों में 'जिला खनिज फाउंडेशन' (DMF) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

- पीएमकेकेकेवाई के शुभारंभ के दिन (17 सितंबर को) ही केंद्र सरकार ने डीएमएफ में खननकर्त्ताओं द्वारा देय अंशदान की दरों को अधिसूचित किया। इसके तहत संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि (12 जनवरी, 2015) से पूर्व निष्पादित सभी खनन पट्टों के संदर्भ में खननकर्त्ताओं को उनके द्वारा देय रॉयल्टी की 30 प्रतिशत राशि का अंशदान करना होगा जबकि इस तिथि के बाद आवंटित खनन पट्टों के संदर्भ में खननकर्त्ताओं द्वारा देय रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि का अंशदान डीएमएफ में किया जाएगा। इन अंशदानों से सृजित निधियों के माध्यम से ही डीएमएफ द्वारा पीएमकेकेवाई का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20-A के तहत पीएमकेकेवाई को लागू करने हेतु दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकारों को निदेश जारी किए गए हैं तथा राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इनको डीएमएफ हेतु बनाए गए नियमों में शामिल करें। साथ ही सभी डीएमएफ को भी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने तथा उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के बारे में आवधिक रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

स्वर्ण मौद्रीकरण एवं सॉवरेन स्वर्ण बांड योजनाएं

- 9 सितंबर, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वर्ण मौद्रीकरण योजनाओं (Gold Monetiziation Schemes) तथा सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना (Sovereign Gold Bonds Scheme) के प्रारंभ को स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 नवंबर, 2015 को किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि देश में निष्क्रिय सोने का प्रयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक कार्यों में करने हेतु स्वर्ण मौद्रीकरण योजनाओं तथा सोना खरीदने के विकल्प के तौर पर सरकारी स्वर्ण बांड लाए जाने की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संघीय बजट 2015-16 में की गई थी।
- इन दोनों ही प्रकार की योजनाओं का मूल उद्देश्य देश में तीव्र गति से बढ़ते सोने के आयात को कम करना है। इन योजनाओं के महत्त्वपूर्ण तथ्यों का विवरण अग्रलिखित शीर्षकों के तहत प्रस्तुत किया गया है—

I. स्वर्ण मौद्रीकरण योजनाएं (GMS)

- इसका उद्देश्य वर्तमान स्वर्ण जमा और स्वर्ण धातु ऋण स्कीमों में इस तरह सुधार करना है कि उन्हें और प्रभावशाली बनाते हुए उनका दायरा बढ़ाया जा सके।
- जीएमएस से भारतीय रत्न एवं आभूषण क्षेत्र (जो कि भारतीय निर्यात में प्रमुख योगदान करता है) को लाभ होगा। ज्ञातव्य है कि 2014-15 में रत्न एवं आभूषण का भारत के कुल निर्यात में 12 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अतिरिक्त जीएमएस के तहत एकत्र स्वर्ण से न केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वर्ण भंडार में वृद्धि होगी बल्कि सरकार की उधार लागत भी कम होगी।
- संशोधित स्वर्ण जमा योजना (GDS) और स्वर्ण ऋण योजना (GML) के तहत इनके दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किए गए हैं। सोने की कीमतों में परिवर्तन का जोखिम नवसृजित 'स्वर्ण भंडार निधि' (GRF : Gold Reserve Fund) द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही सरकार की उधार लागत में आने वाली कमी को इसमें हस्तांतरित किया जाएगा।

(i) संशोधित स्वर्ण जमा योजना (GDS)

- इस योजना के तहत कोई निवासी भारतीय व्यक्ति या संस्थान अपने सोने (बुलियन या आभूषण) की न्यूनतम 30 ग्रेन (Grains) मात्रा को बैंकों में जमा कर, केवाईसी नियमों के साथ 'स्वर्ण बचत खाता' खोल सकेगा। इस खाते में ग्राम के रूप में सोना रखा जाएगा।

नोट : वित्त मंत्रालय द्वारा मई, 2015 में तथा 4 नवंबर, 2015 को जारी इस योजना की विज्ञप्ति के तहत न्यूनतम जमा सोने की मात्रा 30 ग्राम है, परंतु मंत्रिमंडल की स्वीकृति की विज्ञप्ति में यह 30 ग्रेन (1 ग्रेन = 0.065 ग्राम) दी गई थी।

- स्वर्ण को जमा करने से पूर्व हॉलमार्किंग केंद्र (जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड-BIS से मान्यता प्राप्त हो) से उसकी जांच करानी होगी। ये संकलन एवं शुद्धता जांच केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
- संकलन एवं शुद्धता जांच केंद्र सोने को शोधकों (Refiners) के पास भेजेंगे। यदि बैंक सोने को अपने पास नहीं रखते तो शोधक स्वर्ण को अपने गोदामों में रखेंगे। शोधकों की सेवाओं का भुगतान बैंक करेंगे तथा ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- संशोधित योजना के तहत स्वर्ण जमा 1-3 वर्ष की अल्पकालीन अवधि (जिसे 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है), 5-7 वर्ष की मध्यकालीन अवधि तथा 12-15 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि के लिए (जिसे समय-समय पर निश्चित किया जाएगा) किया जा सकेगा। सावधि जमा की तरह ही इसमें भी लॉक-इन पीरियड होगा तथा समय पूर्व जमा वापस लेने पर पेनाल्टी देय होगी।
- अल्पकालीन अवधि के लिए जमा पर ब्याज दर बैंक निर्धारित करेगा जबकि मध्यकालीन और दीर्घकालीन जमा के संबंध में ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर आरबीआई की सलाह पर तय की जाएगी। अल्पकालीन जमा पर ब्याज दर ग्राम में तथा मध्यकालीन और दीर्घकालीन जमाओं पर ब्याज दर रुपये में मूल्यवर्गित होगी।
- अल्पकालीन अवधि की जमा पर ग्राहक के पास वापस लेने का विकल्प रहेगा जिसके तहत मूल जमा और अर्जित ब्याज को जमा के समय निर्धारित तरीके से सोने या नकद (वापसी के समय की कीमतों पर) के रूप में वापस लिया जा सकेगा। मध्यकालीन और दीर्घकालीन अवधि की जमाओं पर वापसी केवल नकद में होगी जो वापस लेने के समय सोने की कीमत के आधार पर तय होगी।
- इस योजना के तहत अल्पकालीन जमा के तहत जमा सोने को सिक्कों और ज्वेलर्स को उधार देने हेतु प्रयुक्त किया जाएगा जबकि मध्यकालीन और दीर्घकालीन जमा के तहत जमा सोने का उपयोग नीलामी, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सिक्कों तथा ज्वेलर्स को उधार देने में होगा।
- इस खाते से प्राप्त होने वाली ब्याज राशि सभी प्रकार के करों (यथा–आय कर, संपत्ति कर एवं पूंजीगत लाभ कर) से मुक्त होगी।

- मध्यकालीन और दीर्घकालीन जमा के अंतर्गत सरकार की मौजूदा उधार लागत और सरकार द्वारा देय ब्याज दर के अंतर को स्वर्ण भंडार निधि में जमा किया जाएगा।

(ii) संशोधित स्वर्ण धातु ऋण योजना (GML)

- बैंक द्वारा ज्वेलर्स के लिए एक स्वर्ण धातु ऋण खाता खोला जाएगा जो स्वर्ण के ग्रामों में मूल्यवर्गित होगा।
- संशोधित जीडीएस के अल्पकालीन जमा के तहत एकत्र सोने को आरबीआई के निर्देशन में बैंकों द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत ज्वेलर्स को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्वर्ण ऋण की स्वीकृति हो जाने पर ज्वेलर्स को शोधकों द्वारा सोने की आपूर्ति की जाएगी। बैंक इस संदर्भ में ज्वेलर्स के स्वर्ण ऋण खाते में आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे।
- जीएमएल पर लागू ब्याज दर सभी बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय करेंगे।
- जीएमएल की अवधि इस समय 180 दिन है। स्वर्ण जमाओं पर न्यूनतम लॉक-इन पीरियड एक वर्ष के आधार पर और प्राप्त अनुभवों को देखते हुए भविष्य में जीएमएल की अवधि की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक होगा तो समुचित संशोधन किया जाएगा।

II. सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना (SGD)

- इस योजना से सोने की मांग में कमी आएगी तथा प्रतिवर्ष 300 टन सोने की छड़ों एवं सिक्कों में होने वाले निवेश को इस सरकारी स्वर्ण बांड में लगाया जा सकेगा। इस योजना से स्वर्ण आयात को कम करने तथा चालू खाते के घाटे (CAD) को सीमित रखने में मदद मिलेगी।
- सॉवरेन (सरकारी) स्वर्ण बांडों (SGD) को वर्ष 2015-16 एवं उसके आगे की अवधि हेतु सरकार के बाजार ऋण कार्यक्रम के भीतर जारी किया जाएगा। वित्त मंत्रालय से सलाह कर आरबीआई इनकी जारी होने वाली मात्रा का निर्धारण करेगा।
- स्वर्ण कीमतों में परिवर्तन के जोखिम को स्वर्ण भंडार निधि (GRF) द्वारा वहन किया जाएगा जबकि सरकार की उधार लागत में कमी से हुए लाभ को इस निधि में हस्तांतरित किया जाएगा।
- एसजीडी रुपये में भुगतान पर जारी किया जाएगा और यह स्वर्ण के ग्रामों में मूल्यवर्गित होगा।
- ये बांड भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाएंगे जिनकी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सार्वभौम (Sovereign) गारंटी होगी।
- जारीकर्ता एजेंसी वितरण लागत और मध्यवर्ती चैनलों को विक्रय कमीशन का वहन करेगी जिसका पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इस बांड का विक्रय केवल निवासी भारतीय व्यक्तियों/संस्थानों को किया जाएगा। बांड की अधिकतम सीमा एक समुचित स्तर पर रखी जाएगी जो प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 ग्राम से अधिक नहीं होगी।
- इन बांडों पर ब्याज दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा। यह ब्याज दर निवेश के समय सोने के मूल्य के अनुरूप तय की जाएगी तथा तयशुदा आधार पर ब्याज दर परिवर्तनशील या स्थिर होगी। 30 अक्टूबर, 2015 को इनके संदर्भ में 2.75 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर (छमाही आधार पर देय) निर्धारित की गई है।
- ये बांड डीमैट या पेपर रूप, दोनों ही तरह के होंगे। इनमें न्यूनतम निवेश सीमा 2 ग्राम सोने के आधार पर होगी।
- सोने की कीमत संदर्भ दर पर तय की जाएगी और कुल रकम रुपये में आरबीआई द्वारा बांड जारी होने और वापसी के अवसर पर संदर्भ दरों के आधार पर तय होगी। यह दर बांड जारी करने, वापस लेने, एलटीवी उद्देश्य और ऋणों की वापसी हेतु प्रयुक्त होगी।
- बैंक/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/डाक घर/राष्ट्रीय बचत पत्र एजेंट एवं अन्य बांड विक्रय और वापसी का माध्यम होंगे जो कि कमीशन आधार पर कार्य करेंगे।
- 8 साल की अवधि वाले इन बांडों में पांचवें साल से निकासी का भी विकल्प रहेगा। इन्हें दीर्घकालीन निवेश के संदर्भ में ही जारी किया जाएगा, ताकि सोने की कीमतों के मध्यकालीन उतार-चढ़ाव से निवेशकों की सुरक्षा हो सके।
- इन बांडों को ऋण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनका ऋण-कीमत अनुपात समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित साधारण स्वर्ण ऋण के समान होगा।
- इन बांडों का एक्सचेंजों में सरलता से विक्रय एवं कारोबार किया जा सकेगा ताकि निवेशकों को इच्छानुसार निकासी की सुविधा हो। इसमें केवाईसी नियम स्वर्ण के समान ही होंगे।
- इन पर पूंजीगत लाभ कर व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सोने की तरह ही होंगे।
- बांड के परिपक्व होने पर उसकी वापसी केवल रुपये में होगी। बांडों की ब्याज दर निवेश के समय सोने के मूल्य के आधार पर तय की जाएगी। निवेश का मूलधन जो सोने के ग्राम आधार पर होगा, उसकी वापसी उस समय की सोने की कीमत के आधार पर होगी।
- सोने की कीमत निवेश के समय की कीमत से कम होने या कोई अन्य कारण उत्पन्न होने पर जमाकर्ता को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह बांड की अवधि को 3 या अधिक वर्षों के लिए बढ़ा सके।

भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों को सैद्धांतिक स्वीकृति

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा देश में भुगतान बैंकों (Payment Banks) और लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks) की स्थापना हेतु मानक एवं दिशा-निर्देश 27 नवंबर, 2014 को जारी किए गए थे तथा इन बैंकों के लिए आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी, 2015 तक भुगतान बैंकों के लिए 41 और लघु वित्त बैंकों के लिए 72 आवेदन आरबीआई को प्राप्त हुए थे।
- भुगतान बैंकों हेतु आवेदनों की जांच आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति तथा लघु वित्त बैंकों हेतु आवेदनों की जांच आरबीआई की पूर्व गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई और तत्पश्चात 19 अगस्त, 2015 को भुगतान बैंक की स्थापना हेतु 11 आवेदनों एवं 16 सितंबर, 2015 को लघु वित्त बैंकों की स्थापना हेतु 10 आवेदनों को आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक : एक तुलना

भुगतान बैंक (Payment Bank)	लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank)
● ये मुख्य रूप से घरेलू भुगतान सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनकी स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना तथा प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों और अन्य उपयोगकर्त्ताओं को भुगतान/विप्रेषण (Payment/ Remittances) सेवाएं उपलब्ध कराना है। ● ये विभिन्न चैनलों के माध्यम से भुगतान और धन प्रेषण सेवाएं उपलब्ध कराएंगे तथा व्यवसाय प्रतिनिधियों (BCs : Business Correspondents) पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत अन्य बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधि बन सकेंगे। ये म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों जैसे गैर-जोखिम सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण भी कर सकेंगे तथापि ये ऋण देने का कार्य नहीं कर सकते। ● ये मांग जमाएं (Demand Deposits) स्वीकार कर सकेंगे तथापि प्रारंभिक रूप से प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक इनमें अधिकतम 1 लाख रु. की शेष राशि (किसी कार्यदिवस के अंत में) ही रख सकेगा। ये एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकेंगे, परंतु क्रेडिट कार्ड नहीं। ये सावधि जमाएं, मियादी जमाएं, आवर्ती जमाएं (FDs, TDs एवं RDs) अथवा एनआरआई जमाएं भी नहीं ले सकेंगे। ● अपनी मांग और मियादी देयताओं में से आरबीआई के पास रखी जाने वाली नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की राशि के अतिरिक्त इन्हें अपनी 'मांग जमा राशि के शेष' का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) के लिए पात्र 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में रखना होगा तथा वे अपने परिचालनात्मक प्रयोजनों हेतु अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में चालू और मियादी/ सावधि जमाओं के तहत रख सकेंगे। ● भुगतान बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रवर्तक का न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान बैंक के अपने कारोबार की शुरूआत से पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत होना आवश्यक है।	● इनकी स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बचत माध्यमों का प्रावधान करना और छोटी कारोबारी इकाइयों, छोटे एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को उच्च तकनीकी एवं कम लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण एवं बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। ● लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंकों की तरह ही भुगतान और प्रेषण सेवाएं तथा गैर-जोखिम सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण कर सकेंगे, परंतु जहां ये ऋण भी प्रदान कर सकेंगे वहीं ये अन्य बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। हालांकि ये व्यवसाय प्रतिनिधियों का अपना नेटवर्क बना सकेंगे। ● ये मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्रों से वंचित और अल्प सेवा प्राप्त तबकों को जमा और ऋण जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। इन बैंकों को अपने वार्षिक शाखा विस्तार की कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सेवा से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों (9,999 तक जनसंख्या वाले) में खोलनी आवश्यक होगी। इनके परिचालन क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ● लघु वित्त बैंक विद्यमान वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले आरबीआई के सभी मानदंडों एवं विनियमों, जिनमें नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) शामिल है, के अधीन होंगे। इन बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 75 प्रतिशत आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में वर्गीकृत पात्र क्षेत्रों को प्रदान करें। साथ ही इन बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा 25 लाख रु. तक के ऋणों एवं अग्रिमों का होना आवश्यक है। ● लघु वित्त बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रवर्तक का हिस्सा प्रारंभ में कम से कम 40 प्रतिशत होगा तथा इसे अधिक होने पर बैंक के कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर 40 प्रतिशत तक, 10 वर्ष के भीतर 30 प्रतिशत तक तथा 12 वर्ष के भीतर इसे 26 प्रतिशत तक लाना होगा।

- इस सैद्धांतिक स्वीकृति की वैधता 18 माह है तथा इस अवधि में समुचित और संतोषजनक कार्य करने वाली इकाइयों को ही इन बैंकों के लिए अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।
- भुगतान बैंकों के लिए स्वीकृत प्राप्त आवेदनकर्ता हैं—
  1. आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड
  2. डाक विभाग
  3. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  4. टेक महिंद्रा लिमिटेड
  5. वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड
  6. एयरटेल एम. कॉमर्स सर्विसेज लिमिटेड
  7. दिलीप शांतिलाल सांघवी (सन फार्मा के संस्थापक)
  8. विजय शेखर शर्मा (पेटीएम की स्वामी कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के सीईओ)
  9. चोलमंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड
  10. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
  11. फिनो पेटेक लिमिटेड
- लघु वित्त बैंकों के लिए स्वीकृति प्राप्त आवेदनकर्त्ता हैं—
  1. एयू फाइनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर
  2. कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जालंधर
  3. दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद
  4. इक्विटास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
  5. ईएसएएफ माइक्रोफाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
  6. जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरू
  7. आरजीवीएन (नॉर्थ ईस्ट) माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, गुवाहाटी
  8. सूर्योदय माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई
  9. उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरू
  10. उत्कर्ष माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी

- इन बैंकों की स्थापना किए जाने का उद्देश्य देश में निचले स्तर तक वित्तीय समावेशन का विस्तार तथा बचत आदतों का संवर्धन कर विकास हेतु घरेलू निवेश को गति प्रदान करना है। साथ ही इस प्रकार के बैंक देश में वित्तीय जागरूकता की अभिवृद्धि में भी सहायक होंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों दोनों के लिए न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी (Minimum Paid-up Share Capital) 100 करोड़ रु. निर्धारित की गई है तथा उन्हें अपने लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करना होगा।
- इन दोनों प्रकार के बैंकों में विदेशी अंशधारिता (Foreign Holding) निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमाओं (वर्तमान में स्वचालित रूट के तहत 49 प्रतिशत तक और अनुमोदन रूट के तहत 49 से ऊपर 74 प्रतिशत तक) के समकक्ष अनुमन्य होगी।
- इनकी निवल संपत्ति के 500 करोड़ रु. तक पहुंचने पर इन्हें 3 वर्ष के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना आवश्यक होगा, तथापि वे पहले भी पूंजी बाजार नियामक के मानकों को पूरा कर स्वैच्छिक रूप से सूचीबद्ध हो सकते हैं।
- इन बैंकों का परिचालन प्रारंभ से ही पूर्णतः नेटवर्क और प्रौद्योगिकी साधित तथा सामान्यतः स्वीकृत मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए तथा साथ ही इनमें उच्च अधिकार प्राप्त ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था भी होनी आवश्यक है। ये बैंक आरबीआई की 'बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना, 2006' के दायरे में आएंगे। दोनों ही बैंकों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत आवश्यक होगा।
- इन बैंकों को अपने नाम में क्रमशः 'भुगतान बैंक' एवं 'लघु वित्त बैंक' शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होगा।
- इनमें से लघु वित्त बैंक, पूर्ण (सार्वभौमिक) बैंक के रूप में भविष्य में अंतरित हो सकता है पर ऐसा अंतरण स्वतः नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उसे पूर्ण वाणिज्यिक बैंकों पर लागू न्यूनतम चुकता पूंजी/निवल संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, एक लघु वित्त बैंक के रूप में उसका विगत कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो तथा उसे आरबीआई की समुचित सावधानी प्रक्रिया पर संतोषजनक सिद्ध होना होगा।

व्हाइट लेबल एटीएम परिचालन में एफडीआई सीमा हुई 100 प्रतिशत

- 9 सितंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में व्हाइट लेबल एटीएम (WLA : White Label ATM) परिचालनों में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई—
  - (i) डब्ल्यूएलए स्थापित करने के लिए किसी गैर-बैंकिंग निकाय की नवीनतम वित्त वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार न्यूनतम निवल संपत्ति (Net worth) 100 करोड़ रु. होनी चाहिए, जिसे हर समय बरकरार रखना होगा।
  - (ii) यदि कोई निकाय, 18 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) गतिविधियों में से किसी अन्य में संलग्न है तो डब्ल्यूएलए स्थापित करने वाली कंपनी में हुए विदेशी निवेश को भी एनबीएफसी से जुड़ी गतिविधियों में विदेशी निवेश के लिए तय न्यूनतम पूंजीकरण मानकों के अनुरूप रखना होगा।
  - (iii) डब्ल्यूएलए परिचालनों में एफडीआई भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट मानदंडों और दिशा-निर्देशों के तहत होगा।
- इस निर्णय से डब्ल्यूएलए परिचालनों में विदेशी निवेश अंतर्वाह सुगम और तीव्र होगा तथा यह प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित देश में वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने संबंधी सरकार के प्रयासों में सहायक होगा।
- यह देश के अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों (मुख्यतः टियर III से VI क्षेत्रों) में एटीएम नेटवर्क को बढ़ाने में भी सहायक होगा।

व्हाइट लेबल एटीएम (WLA)

गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले एटीएम (ATM : Automated Teller Machine) को व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) की संज्ञा दी जाती है। ये किसी भी बैंक द्वारा संचालित एटीएम मशीनों के समान ही कार्य करते हैं तथा इनसे किसी भी बैंक के वित्तीय/गैर-वित्तीय लेन-देन किए जा सकते हैं। आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य बैंकों के एटीएम के अधिकतम निःशुल्क उपयोग की सीमा का नियम इन पर लागू नहीं होता। आरबीआई द्वारा जून, 2012 में डब्ल्यूएलए के संदर्भ में नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए गए जिनके तहत अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे न्यूनतम दो-तिहाई डब्ल्यूएलए स्थापित किया जाना इच्छुक गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया। भारत में सर्वप्रथम टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लि. (TCPSL) द्वारा पहला व्हाइट लेबल एटीएम 'इंडीकैश' नाम के तहत 27 जून, 2013 को थाणे (महाराष्ट्र) के ग्रामीण क्षेत्र चंद्रपाड़ा में स्थापित किया गया। इस कंपनी के अतिरिक्त आरबीआई द्वारा तीन अन्य कंपनियों प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि., मुथूट फाइनेंस लि. और वक्रांगी लि. को डब्ल्यूएलए स्थापित करने की अनुमति दी गई है जिनमें से प्रथम दो द्वारा क्रमशः 'मनीस्पॉट' और 'मुथूट एटीएम' के नाम से डब्ल्यूएलए परिचालन प्रारंभ किए जा चुके हैं।

'पेय एल्कोहॉल' का विनियमन प्राधिकार राज्यों को देने हेतु संशोधन स्वीकृत

- विधि आयोग द्वारा अपनी 158वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुरूप 9 सितंबर, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पेय एल्कोहॉल' (Potable Alcohol) का विनियमन प्राधिकार राज्यों को हस्तांतरित करने हेतु 'उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951' की प्रथम अनुसूची में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी।
- इसके तहत उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि 26 में 'किण्वन उद्योग' (Fermentation Industries) के स्थान पर 'किण्वन उद्योग' (पेय एल्कोहॉल के अतिरिक्त) अंतःस्थापित किया जाएगा जिसके लिए एक विधेयक संसद में लाया जाएगा।
- इस संशोधन के साथ पेय एल्कोहॉल और औद्योगिक एल्कोहॉल पर केंद्र एवं राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार को लेकर लंबे समय से चला आ रहा भ्रम समाप्त होगा।

- इस संशोधन से एल्कोहॉल के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन सृजित होगा। इससे कानून और एल्कोहॉल के दुरुपयोग की संभावना नहीं रहेगी तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि पेय उद्देश्यों हेतु एल्कोहॉल विनिर्माण में संलग्न उद्योग सभी मामलों में राज्यों के पूर्ण और अनन्य नियंत्रण के तहत होंगे। इसके अतिरिक्त इससे पेय एल्कोहॉल के विनिर्माण के संदर्भ में राज्यों का उत्तरदायित्व भी तय हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि 1997 में बिहार डिस्टलरी बनाम भारत संघ वाद में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पेय उद्देश्यों हेतु एल्कोहॉल विनिर्माण में संलग्न उद्योगों को राज्यों के नियंत्रण में होना चाहिए जबकि औद्योगिक एल्कोहॉल से संबंधित नियंत्रण केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के तहत होना चाहिए। साथ ही विधि आयोग द्वारा भी इस संदर्भ में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में तत्संबंधी संशोधन की सिफारिश अपनी 158वीं रिपोर्ट (जून, 1998 में प्रस्तुत) में की गई थी।

कृषिगत उत्पादन के नवीनतम आंकड़े

- 17 अगस्त, 2015 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में देश में कृषिगत उत्पादन के चतुर्थ अग्रिम अनुमान (4th Advance Estimates) जारी किए गए जिसके अनुसार इस वर्ष देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 252.68 मिलियन टन ही रहने का आकलन है, जो कि गत वर्ष (2013-14) की तुलना में 12.36 मिलियन टन (4.66 प्रतिशत) कम है। 13 मई, 2015 को जारी कृषिगत उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमान में इसके 251.12 मिलियन टन रहने का अनुमान था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 265.04 मिलियन टन रहा जो कि अब तक का सर्वोच्च वार्षिक स्तर है।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 2014-15 के दौरान खरीफ फसलों के उत्पादन को खराब मानसून से नुकसान पहुंचा तथा फरवरी-मार्च, 2015 के दौरान बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से रबी फसलों के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा। रबी तथा खरीफ दोनों ही फसलों पर पड़े दुष्प्रभाव के परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान देश में अधिकतर फसलों के उत्पादन में कमी आई जो कि खाद्यान्न उत्पादन में पिछले एक दशक की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट के रूप में प्रत्यक्ष हुई है।
- हालांकि उत्पादन में इस गिरावट के बावजूद यह देश में अब तक का चौथा सर्वाधिक वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन (क्रमशः 2013-14, 2011-12 एवं 2012-13 के बाद) है।
- 2014-15 में चावल का कुल उत्पादन गत वर्ष के 106.65 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन से गिरकर 104.80 मिलियन टन तथा गेहूं का कुल उत्पादन गत वर्ष के 95.85 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन से गिरकर 88.94 मिलियन टन ही रहने का अनुमान है। मोटे अनाज, दालों, तिलहन, कपास तथा जूट का उत्पादन भी कम होने का आकलन है।
- प्रमुख फसलों में गन्ना ही एकमात्र फसल है जिसका उत्पादन गत वर्ष से अधिक रहने का आकलन है। वर्ष 2014-15 में गन्ने का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 7.19 मिलियन टन बढ़कर 359.33 मिलियन टन रहने का अनुमान है जो कि वर्ष 2011-12 (361.04 मिलियन टन) के बाद तब तक का दूसरा शीर्ष उत्पादन स्तर है।
- कृषिगत उत्पादन के वर्ष 2013-14 के अंतिम आंकड़ों के साथ वर्ष 2014-15 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़े संलग्न तालिका में प्रदर्शित हैं—

भारत में कृषिगत उत्पादन

(मिलियन टन में)

उपज	2013-14 (अंतिम आंकड़े)	2014-15 (4th A.E.)
कुल अनाज	245.79	235.49
(i) चावल	106.65	104.80
(ii) गेहूं	95.85	88.94
(iii) मोटे अनाज	43.29	41.75
कुल दलहन	19.25	17.20
कुल खाद्यान्न	265.04	252.68
कुल नौ तिलहन	32.75	26.68
गन्ना	352.14	359.33
कपास*	35.90	35.48
जूट एवं मेस्ता**	11.69	11.45

*170 किग्रा. की मिलियन गांठें

**180 किग्रा. की मिलियन गांठें

खरीफ उत्पादन 2015-16 के प्रथम अग्रिम अनुमान

- वर्ष 2015-16 के खरीफ उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 16 सितंबर, 2015 को जारी किए गए जिसका विवरण अग्रलिखित तालिका में प्रदर्शित है—

फसल	उत्पादन (मि. टन)
खाद्यान्न	124.04
चावल	90.61
मोटे अनाज	27.88
मक्का	15.51
दलहन	5.56
तूर	2.61
उड़द	1.37
तिलहन	19.89
सोयाबीन	11.83
मूंगफली	5.11
गन्ना	341.43
कपास	33.51 मि. गांठें (प्रत्येक 175 किग्रा.)

- उल्लेखनीय है कि वर्तमान मानसून सीजन में संचयी वर्षा 15 प्रतिशत तक कम हुई है जबकि 2014-15 में यह 12 प्रतिशत तक कम हुई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में सुधार हेतु 'इंद्रधनुष' योजना

- 14 अगस्त, 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Banks) में सुधार लाने तथा उनका पुनरोत्थान करने के उद्देश्य से एक सात-सूत्रीय योजना की घोषणा की गई, जिसे 'इंद्रधनुष' नाम दिया गया है।
- केंद्र सरकार के अनुसार पीएसयू बैंकों के रूपांतरण हेतु तैयार इंद्रधनुष रूपरेखा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद किया जाने वाला सर्वाधिक व्यापक सुधार है जो कि वर्तमान में तेजी से परिवर्तित हो रही वित्तीय सेवा आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- पीएसयू बैंकों के लिए इंद्रधनुष योजना के सात सूत्रों में शामिल हैं—

(i) नियुक्तियां (Appointments) : सरकार द्वारा इन बैंकों के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) के पद को पृथक करते हुए सीईओ को एमडी एंड सीईओ का पदनाम दिया गया है तथा साथ ही इनमें पृथक गैर-कार्यकारी (Non-Executive) चेयरमैन नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता-आधारित होगी।

(ii) बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank Board Bureau) : पीएसयू बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी चेयरमैन की नियुक्ति हेतु वर्तमान नियुक्ति बोर्ड के स्थान पर बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात पेशेवर और अनुभवी अधिकारी शामिल होंगे। यह 1 अप्रैल, 2016 से कार्य प्रारंभ करेगा।

(iii) पूंजीकरण (Capitalization) : वर्तमान में सभी पीएसयू बैंक बेसल III और आरबीआई मानकों के संदर्भ में पर्याप्त पूंजी से युक्त हैं। तथापि सरकार द्वारा बेसल III के न्यूनतम मानकों के ऊपर एक सुरक्षित बफर हेतु अगले 4 वर्षों में इन बैंकों के लिए 1,80,000 करोड़ रु. की पूंजी आवश्यकता का आकलन किया गया है जिसमें से सरकार बजटीय आवंटन के माध्यम से कुल 70,000 करोड़ रु. (2015-16 एवं 2016-17 में 25-25 हजार करोड़ रु. तथा 2017-18 एवं 2018-19 में 10-10 हजार करोड़ रु.) की पूंजी इन्हें उपलब्ध कराएगी।

(iv) पीएसयू बैंकों को दबाव-मुक्त करना (De-stressing) : इसके तहत बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या से निपटने हेतु विशिष्ट उपाय किए जाएंगे जिनमें अवसंरचना एवं कोर सेक्टर की रुकी हुई परियोजनाओं (जो इन बैंकों के एनपीए बोझ का एक प्रमुख कारण हैं) को गतिमान करने हेतु उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जोखिम नियंत्रण उपायों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार द्वारा 6 नए डीआरटी-ऋण वसूली अधिकरणों (चंडीगढ़, बंगलुरू, एर्नाकुलम, देहरादून, सिलिगुड़ी एवं हैदराबाद) की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है।

(v) सशक्तिकरण (Empowerment) : सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी कर यह घोषणा की गई है कि सरकार की तरफ से इन बैंकों की कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और इन बैंकों को अपने संगठन के वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि स्वायत्तता के साथ बैंकों को उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करना होगा और उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ बनाना होगा।

(vi) निष्पादन रूपरेखा (Performance Framework) : वर्तमान प्रणाली के तहत बैंक अपने वार्षिक लक्ष्यित आंकड़ों को वित्त मंत्रालय के समक्ष स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SOI) के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। कभी-कभी तो इन्हें वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिया जाता है जो कि उचित नहीं हैं। इसके स्थान पर मुख्य निष्पादन संकेतकों (KPIs : Key Performance Indicators) की नई रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसके आधार पर बैंकों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। यह मूल्यांकन इन बैंकों के एमडी एवं सीईओ को दिए जाने वाले निष्पादन बोनस (निजी बैंकों की तरह) का भी आधार होगा।

(vii) शासनिक सुधार (Governance Reforms) : इस संदर्भ में पीएसयू बैंकों की कार्यप्रणालियों में आमूलचूल सुधार लाने के उपाय किए जाएंगे जिनमें जोखिम प्रबंधन उपागमों का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इस संदर्भ में 2015 के प्रारंभ में पुणे में आयोजित बैंकिंग कॉन्क्लेव 'ज्ञान संगम' में प्रस्तुत अनुशंसाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पूंजी को अनुकूलतम करने, प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत करने, जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, प्रबंधकीय निष्पादन में सुधार और वित्तीय समावेशन के संवर्धन हेतु प्रत्यक्ष शासनिक सुधार किए जा सकें।

भारत में प्रत्यक्ष होता 'राजकोषीय संघवाद'

- 'राजकोषीय संघवाद' (Fiscal Federalism) संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच राजस्वों के समुचित विभाजन के साथ-साथ वित्तीय साधनों के हस्तांतरण और व्यय पक्ष के संदर्भ में राज्यों को समुचित स्वायत्तता उपलब्ध कराए जाने को अभिव्यक्त करता है। यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के आर्थिक/वित्तीय संदर्भों में व्यावहारिक पक्ष को भी प्रदर्शित करता है।
- भारतीय संविधान के तहत यद्यपि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के तहत वित्तीय शक्तियों का भी विभाजन किया गया है परंतु यह संघ के पक्ष में अधिक है। भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक कराधान शक्तियां प्राप्त हैं और इस राजकोषीय असंतुलन को देखते हुए ही संविधान के तहत केंद्र से राज्य सरकारों को वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से राजकोषीय समायोजन की प्रणाली अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित होने वाले वित्त आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद भारत में राजकोषीय संघवाद की स्थिति कमजोर ही रही क्योंकि वित्त आयोगों द्वारा किए जाने वाले हस्तांतरणों की तुलना में केंद्र द्वारा राज्यों को योजना अनुदान और विवेकाधीन अनुदान (जिनका निर्धारण योजना आयोग करता था और इनके संदर्भ में राज्यों को स्वायत्तता नहीं होती थी) की मात्रा उच्च स्तर पर रही। 1951-56 के दौरान वित्त आयोग हस्तांतरण जहां केंद्रीय राजस्व का मात्र सातवां भाग थे, वहीं इस अवधि में योजना और विवेकाधीन अनुदानों का हिस्सा राज्यों को केंद्र से कुल हस्तांतरणों में 70 प्रतिशत था।

- हालांकि विभिन्न वित्त आयोगों के द्वारा, राज्यों की विकास-वित्त के मामले में अधिक स्वायत्तता की मांगों को देखते हुए यह स्थिति क्रमिक रूप से परिवर्तित हुई तथापि योजनाओं संबंधी नीतिगत मामलों में योजना आयोग का हस्तक्षेप बना रहा और तदनुसार राजकोषीय संघवाद पृष्ठभूमि में ही रहा।
- 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाए गए 80वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा केंद्रीय करों के राज्यों के साथ विभाज्य पूल को विस्तारित करते हुए इसमें सभी केंद्रीय करों को शामिल किया गया जिससे यद्यपि राजकोषीय संघवाद को बल मिला परंतु तुलनात्मक रूप से केंद्र और राज्यों की राजस्व साझेदारी में कोई विशेष अंतर सामने नहीं आया तथा केंद्र द्वारा राज्यों को प्रभावी वित्तीय हस्तांतरण केंद्रीय राजस्व (कर एवं गैर-कर) के लगभग 40 प्रतिशत तक ही रहे और इसमें योजना आयोग एवं केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान भी शामिल थे।
- वर्ष 2015 में आकर ही वस्तुतः राजकोषीय संघवाद तब भारत में प्रत्यक्ष होता दिखाई दिया जब नवगठित केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के विचार के साथ 'नीति आयोग' की स्थापना की गई और '14वें वित्त आयोग' ने राज्यों को ऊर्ध्वाधर अंतरण को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाते हुए राज्य योजनाओं में केंद्रीय सहायता को कम करने पर जोर दिया।
- 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नीति आयोग (NITI : National Institution for Transforming India) देश में केंद्र से राज्य की ओर नीतियों के एकतरफा प्रवाह (जो कि योजना आयोग काल की विशिष्टता रही है) के स्थान पर एक महत्त्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी तथा राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग के साथ सहकारी संघवाद (जिसका राजकोषीय संघवाद एक महत्त्वपूर्ण एवं व्यावहारिक पक्ष है) को बढ़ावा देने की आवश्यकता के मद्देनजर लाया गया है।
- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचित समर्थन पहलों और प्रणालियों के माध्यम से सहकारी संघवाद को संवर्द्धित करने के उद्देश्य से गठित नीति आयोग राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रकाश में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होगा और इस प्रकार यह राजकोषीय संघवाद प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। नीति आयोग की शासी परिषद (Governing Council) और क्षेत्रीय परिषदों (Regional Councils) में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपालों को शामिल कर राज्यों को अब नीति निर्माण एवं निर्णयन में स्पष्ट भागीदारी दी गई है।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों (जिन्हें 24 फरवरी, 2015 को संसद में प्रस्तुत किया गया) के तहत भारत में राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने हेतु अनेक महत्त्वपूर्ण संस्तुतियां की गई हैं (जिनमें अधिकांश को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है)। इन संस्तुतियों में केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा (ऊर्ध्वाधर अंतरण) बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाना सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह 13वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के 32 प्रतिशत से 10 प्रतिशतांक की अभूतपूर्व वृद्धि है। विगत दो वित्त आयोगों ने इसमें केवल क्रमशः 1 प्रतिशतांक (29.5% से बढ़ाकर 30.5%) एवं 1.5 प्रतिशतांक (30.5% से बढ़ाकर 32.0%) की ही वृद्धि की थी।
- वस्तुतः 14वें वित्त आयोग का मुख्य जोर राज्य योजनाओं में केंद्रीय सहायता को कम करते हुए राज्यों को कर अंतरण में अधिक वृद्धि करने पर रहा है जिसे राज्यों को विकास योजनाओं के संदर्भ में अधिक स्वायत्तता और फलस्वरूप राजकोषीय संघवाद की दिशा में बढ़ने के रूप में देखा जाना चाहिए। राज्यों को अधिक कर अंतरण से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार स्कीमों के वित्तपोषण एवं उनकी परिकल्पना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्यों के योजना राजस्व व्यय की वित्तीय पूर्ति राज्यों के अपने संसाधनों, ऋण लेकर तथा संघ से प्राप्त योजना अनुदानों से की जाती है। राज्यों के योजना राजस्व व्यय का मूल्यांकन करने के लिए 14वें वित्त आयोग ने राज्य योजना में किए गए व्यय और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्यों द्वारा किए गए अंशदान को शामिल किया है। इसमें केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों, केंद्रीय योजना स्कीमों और उत्तर-पूर्वी परिषद योजना स्कीमों तथा संघ द्वारा अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित बाह्य सहायतार्थ परियोजनाओं पर संघ द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं किया गया है। वस्तुतः 14वें वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाएं राज्यों की इस विशेष मांग को स्वीकार करते हुए दी हैं कि केंद्रीय करों का अंतरण राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण का प्राथमिक रूट होना चाहिए तथा संसाधनों के आवंटन में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वास्तव में राज्य योजनाओं को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता एवं अनुदानों की भूमिका कम होनी चाहिए।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा राज्य विषयों से संबंधित 8 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को केंद्रीय सहायता से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है जो कि अब राज्यों द्वारा उनके वर्धित संसाधनों से चलाई जाएंगी अथवा 14वें वित्त आयोग के पंचाट में शामिल कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में केंद्र-राज्य भागीदारी पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है और राज्यों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उच्चतर वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है।
- राज्यों को उच्चतर मुक्त संसाधनों को उपलब्ध कराने से उन्हें अपने कार्यक्रमों और योजनाओं की डिजाइन, क्रियान्वयन और वित्तपोषण में परिवर्तन लाकर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षमता प्राप्त होगी। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तीव्रतर होगी जिससे समग्र राष्ट्रीय वृद्धि की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा और यही राजकोषीय संघवाद का मूल लक्ष्य होना चाहिए। तथापि राज्यों को वित्तीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और अधिक स्वायत्तता के साथ-साथ उच्चतर उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन कर इस संदर्भ में अपनी राजकोषीय दक्षता को सिद्ध करना होगा। तभी राजकोषीय संघवाद वास्तविक अर्थों में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सक्षम हो सकेगा।

जैम त्रयी (JAM Trinity)

- जैम त्रयी (JAM Trinity) व्यापक वित्तीय समावेशन की अवधारणा है।
- जन-धन योजना (J), आधार नंबर (A) एवं मोबाइल बैंकिंग (M) के सम्मिश्रण से लागू वित्तीय समावेशन को 'जैम त्रयी' (JAM Trinity) के रूप में अभिहित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर वित्त की मुख्य धारा से कटे गरीबों को इससे जोड़ने तथा सरकारी धन की चोरी को रोकने के उद्देश्य से जन-धन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस बैंक खाते खोलना तथा उनको आधार नंबर एवं मोबाइल से जोड़कर बीमा, खाद्य सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी एवं खाद सब्सिडी आदि की सुविधाएं आसानी से वहनीय लागत पर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। इस पहल को 'जैम त्रयी' की संज्ञा दी गई है।
- जैम त्रयी का मुख्य मकसद समाज के सबसे निचले तबके को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाना है।

फसल बीमा पोर्टल

- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने 18 जून, 2015 को देश के किसानों के लिए 'फसल बीमा पोर्टल' का लोकार्पण किया। यह एक नई वेबसाइट है, जोकि कृषि बीमा कवर हेतु बीमा और उनके अनुप्रयोगों पर किसानों के प्रश्नों पर शीघ्र कार्यवाही को सक्षम बनाएगी।
- अब देश के किसान इस सुविधा के जरिए विभिन्न कृषि बीमा कंपनियों के डाटाबेस में जाकर विभिन्न बीमा योजनाओं का विवरण एवं लागू प्रीमियम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा से किसानों को त्वरित एवं सही जानकारी मिल सकेगी। इससे सकल बीमित क्षेत्र का कवरेज बढ़ेगा।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में देश के किसान तीन योजनाओं– राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करवाते हैं। इन तीनों मुख्य योजनाओं से जुड़ी महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य सूचनाओं और जानकारियों की प्रविष्टियां इस पोर्टल में उपलब्ध कराई गई हैं।

मौसम चेतावनी सेवा (नाऊकास्ट)

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने 18 जून, 2015 को 'मौसम चेतावनी सेवा' (नाऊकास्ट) का लोकार्पण किया। यह कृषि एवं सहकारिता विभाग की वह नई पहल है, जो समय रहते किसानों को प्रतिकूल मौसम की चेतावनी देगी। इस मौसम चेतावनी सेवा के अंतर्गत आईएमडी (India Meteorological Department) द्वारा सृजित उग्र मौसम संबंधी डाटा को वेब सर्विस का उपयोग करते हुए एम. किसान पोर्टल पर डाला जाता है। इसके बाद एम. किसान पोर्टल द्वारा प्रभावित जिलों एवं प्रखण्डों के किसानों को प्रतिकूल एवं उग्र मौसम की चेतावनी एसएमएस के जरिए लगातार स्वतः दी जाती है।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

- जुलाई, 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु 20,000 करोड़ रु. के 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष' (NIIF : National Investment and Infrastructure Fund) के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।
- ज्ञातव्य है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2015-16 के संघीय बजट में इस महत्त्वपूर्ण कोष का गठन किए जाने की घोषणा की थी।
- एनआईआईएफ का गठन देश में बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु किया जा रहा है जो कि विशेष रूप से संसाधनों के अभाव में अवरोधित परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु कार्य करेगा।
- इसकी अभिदत्त पूंजी (Subscribed Capital) में सरकार की हिस्सेदारी अधिकतम 49 प्रतिशत तक होगी तथा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एवं ओवरसीज निवेशकों को इसमें निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- एनआईआईएफ देश की अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों (यथा-राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रेल वित्त निगम) को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराएगा जिसे ये कंपनियां आगे निवेश हेतु प्रदान करेंगी। इस प्रकार यह कोष एक ट्रस्ट या 'बैंकरों के बैंक' के रूप में कार्य करेगा।

ई-पर्यटक वीज़ा योजना का विस्तार

- केंद्र सरकार द्वारा नवंबर, 2014 में 'आगमन पर पर्यटक वीज़ा' (Tourist Visa on Arrival) योजना देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई थी।
- इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुज्ञप्ति (Electronic Travel Authorisation) आधारित यह योजना प्रारंभ में 43 देशों के नागरिकों हेतु देश के 9 हवाई अड्डों पर शुरू की गई थी।
- जनवरी, 2015 से यह सुविधा गुयाना तथा अप्रैल, 2015 से श्रीलंका के नागरिकों को भी प्रदान की गई थी तथा अप्रैल, 2015 में ही इस योजना का नाम परिवर्तित कर 'ई-पर्यटक वीज़ा' (E-Tourist Visa) योजना कर दिया गया था।
- तत्पश्चात मई, 2015 में इस योजना को 31 अन्य देशों और 15 अगस्त, 2015 को 36 अन्य देशों (एवं 7 अन्य भारतीय हवाई अड्डों) के लिए विस्तारित किया गया (कुल 113 देश) तथा 12 सितंबर, 2015 को इसके 37 अन्य देशों के लिए विस्तारित किए जाने की घोषणा की गई है जिससे इस सुविधा के तहत आच्छादित देशों की कुल संख्या 150 हो जाएगी जबकि इस सुविधा की उपलब्धता वाले देश के हवाई अड्डों की संख्या अब 16 हो गई है।
- 10 सितंबर, 2015 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में जनवरी से अगस्त माह के दौरान ई-पर्यटक वीज़ा के तहत कुल 169,976 विदेशी पर्यटक भारत आए जो कि गत वर्ष की समान अवधि में भारत आए पर्यटकों की संख्या से 893 प्रतिशत अधिक है।
- इस अवधि में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 देश क्रमशः अमेरिका, जर्मनी, यूएई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हेतु नई योजना के रूप में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' को स्वीकृति प्रदान की गई।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) हेतु कुल 50,000 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि 5,300 करोड़ रु. है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—
  - (i) क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेशों को अभिसरित करना।
  - (ii) सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना ताकि 'हर खेत को पानी' मिल सके।
  - (iii) खेतों में ही जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना ताकि पानी का अपव्यय कम से कम हो।
  - (iv) 'प्रति बूंद अधिक फसल' (More Crop Per Drop) के तहत परिशुद्ध-सिंचाई एवं अन्य जल बचत करने वाली तकनीकों को अपनाना।
  - (v) सतत जल संरक्षण प्राविधियों एवं जलवाही स्तरों के रिचार्ज के उन्नयन के साथ परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली में अधिक निवेश आकर्षित करना।
- पीएमकेएसवाई का कार्यक्रम अभिविन्यास एक 'विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय योजना एवं क्रियान्वयन' संरचना के रूप में होगा ताकि राज्य 'जिला सिंचाई योजना' (DIP) और 'राज्य सिंचाई योजना' (SIP) तैयार कर सकें।
- उल्लेखनीय है कि देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। इस दृष्टि से इस योजना का महत्त्व और बढ़ जाता है।
- इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में देगा जबकि राज्यों को शेष 25 प्रतिशत व्यय वहन करना होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी राज्य कृषि विभाग होगा।

परंपरागत कृषि विकास योजना

मार्च, 2015 में केंद्र सरकार द्वारा देश में जैविक कृषि (Organic Farming) को बढ़ावा देने तथा फलस्वरूप मृदा स्वास्थ्य को समुन्नत करने के उद्देश्य से 'परंपरागत कृषि विकास योजना' का शुभारंभ किया गया है। इस योजना हेतु संघीय बजट 2015-16 में 300 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। यह योजना देश के किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषि के पर्यावरण-मित्र तरीकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ उनकी रासायनिक उर्वरकों एवं कृषि रसायनों पर निर्भरता को कम करेगी।

राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रोत्साहन हेतु योजना

- 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में 'कृषि-तकनीकी अवसंरचना कोष' (ATIF : AgriTech Infrastructure Fund) के माध्यम से 'राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना' को स्वीकृति प्रदान की गई।
- कृषि एवं सहकारिता विभाग (DAC) इस योजना का क्रियान्वयन देश भर में चयनित विनियमित कृषि बाजारों में परिनियोजन योग्य साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के सृजन द्वारा लघु किसानों के लिए कृषि व्यवसाय संघ (SFAC : Small Farmers Agri-business Consortium) की स्थापना के माध्यम से करेगा।
- इस योजना हेतु वर्ष 2015-16 से 2017-18 के मध्य 200 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के तहत देश भर में वर्ष 2015-16 में 250 मंडियों, 2016-17 में 200 मंडियों तथा 2017-18 में 135 मंडियों (कुल 585 चयनित विनियमित मंडियों) को ई-मंडियों के रूप में आच्छादित किए जाने की योजना है।
- किसान और व्यापारी देश भर में पारदर्शी तरीके से अनुकूलतम कीमतों पर कृषि-पदार्थों के क्रय/विक्रय का अवसर प्राप्त कर सकें इस हेतु इन 585 विनियमित मंडियों को साझा ई-प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसकी पहुंच विस्तारित करने हेतु निजी मंडियों को भी इस ई-मंच के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
- कृषि हेतु 'राष्ट्रीय ई-बाजार' के विकास हेतु एसएफएसी मुख्य एजेंसी होगी तथा यह खुली बोली के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन करेगी।

एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

- 30 जून, 2015 को भारत सहित 50 संस्थापक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा चीन के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB : Asia Infrastructure Investment Bank) का विधिक ढांचा तय करने संबंधी समझौते पर बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ दि पीपुल में हस्ताक्षर किए गए।
- उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर, 2014 को भारत और 20 अन्य एशियाई देशों (चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, विएतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, कजाख्स्तान, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस, कुवैत, ओमान, कतर, ब्रुनेई, म्यांमार, मंगोलिया और उज्बेकिस्तान) द्वारा बीजिंग में ही एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) की स्थापना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तब से रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, द. कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक अन्य देश इस बैंक से संस्थापक सदस्यों के रूप में जुड़ चुके थे जिससे संस्थापक सदस्यों की संख्या कुल 50 पर पहुंची। 21 अगस्त, 2015 को मलेशिया, 1 अक्टूबर, 2015 को थाईलैंड, 9 अक्टूबर, 2015 को पोलैंड एवं 27 अक्टूबर, 2015 को डेनमार्क इसमें संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं। वर्ष 2015 के अंत तक कुवैत, फिलीपींस एवं दक्षिण अफ्रीका के इससे संस्थापक सदस्यों के रूप में जुड़ने की आशा है, जिससे इस बैंक के कुल संस्थापक सदस्य 57 होंगे।
- इस महत्त्वपूर्ण निवेश बैंक की स्थापना एशियाई विकास बैंक (ADB) के समानांतर की गई है तथा यह बैंक विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती निवेश मांग को पूरा करेगा। यह विशेषकर सदस्य देशों की ऊर्जा एवं परिवहन सहित वृहद अवसंरचना परियोजनाओं में सहायता प्रदान करेगा।
- एआईआईबी को विश्व बैंक और एडीबी (जिन पर अमेरिका, जापान एवं यूरोपीय देशों का प्रभुत्व है) के प्रतिस्पर्द्धी के रूप में

देखा जा रहा है। अब तक लगभग सभी एशियाई देश तथा एशिया के बाहर के अधिकांश प्रमुख देश एआईआईबी से जुड़ चुके हैं तथा प्रमुख देशों में अमेरिका, जापान एवं कनाडा ही इससे बाहर हैं। चीन द्वारा एआईआईबी की संभावित संस्थापक सदस्यता हेतु उत्तर कोरिया और ताइवान के आवेदनों को ठुकरा दिया गया था।

- एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में स्थापित किया जा रहा है तथा इसका परिचालन 2015-अंत तक प्रारंभ हो जाने की प्रत्याशा है।
- एआईआईबी की प्राधिकृत पूंजी (Authorised Capital) 100 बिलियन डॉलर होगी जबकि आरंभिक अभिदत्त पूंजी (Initial Subscribed Capital) लगभग 50 बिलियन डॉलर और प्रदत्त अनुपात (Paid-in Ratio) 20 प्रतिशत होगा।
- एआईआईबी के क्षेत्रीय (एशियाई) सदस्यों के पास इसकी लगभग 75 प्रतिशत अंशधारिता होगी। उन्हें उनकी पूंजी अंशधारिता का आवंटन कोटा आधार अर्थात उनके आर्थिक आकार पर किया गया है।
- एआईआईबी में प्रत्येक सदस्य का मताधिकार हिस्सा बैंक में उनकी प्राथमिक पूंजी अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर निर्धारित होगा।
- चीन 30.34 प्रतिशत अंशधारिता के साथ एआईआईबी में सबसे बड़ा शेयरधारक होगा। चीन को सर्वाधिक 26.06 प्रतिशत के मताधिकार के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों के संदर्भ में वीटो शक्ति भी प्राप्त होगी।
- भारत 83,673 शेयरों और 8.52 प्रतिशत अंशधारिता के साथ इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक होगा तथा उसे 7.50 प्रतिशत का मताधिकार प्राप्त होगा।
- एआईआईबी में अंशधारिता एवं मताधिकार की दृष्टि से शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों का क्रम इस प्रकार हैं—3. रूस, 4. जर्मनी, 5. दक्षिण कोरिया, 6. ऑस्ट्रेलिया, 7. फ्रांस, 8. इंडोनेशिया, 9. ब्राजील एवं 10. ब्रिटेन।

खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

- 17 जून, 2015 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की संस्तुतियों के आधार पर फसल वर्ष और विपणन वर्ष 2015-16 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs : Minimum Support Prices) को स्वीकृति प्रदान कर दी।
- वर्ष 2015-16 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके विगत वर्ष के एमएसपी के साथ (रु. प्रति क्विंटल में) अग्रलिखित तालिका में प्रदर्शित हैं—

खरीफ फसल	2014-15	2015-16	वृद्धि
धान (सामान्य)	1360	1410	50
धान (ग्रेड-ए)	1400	1450	50
ज्वार (संकर)	1530	1570	40
ज्वार (मालदांडी)	1550	1590	40
बाजरा	1250	1275	25
मक्का	1310	1325	15
रागी	1550	1650	100
तूर (अरहर)	4350	4625	275*
मूंग	4600	4850	250*
उड़द	4350	4625	275*
मूंगफली छिलकायुक्त	4000	4030	30
सोयाबीन (काली)	2500	—	—
सोयाबीन (पीली)	2560	2600	40
सूरजमुखी बीज	3750	3800	50
तिल (Sesamum)	4600	4700	100
रामतिल (Nigerseed)	3600	3650	50
कपास (मध्य रेशा)	3750	3800	50
कपास (लंबा रेशा)	4050	4100	50

* 200 रु. प्रति क्विंटल बोनस सहित

राष्ट्रीय आय 2014-15 के प्रॉविजनल आंकड़े

- 29 मई, 2015 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) जारी किए गए।
- अनंतिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 में वास्तविक जीडीपी (Real GDP) या स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीडीपी 106.44 लाख करोड़ रु. अनुमानित है जो कि 2013-14 की तुलना में 7.3 प्रतिशत (अग्रिम अनुमानों के तहत यह 7.4 प्रतिशत था) की वृद्धि दर्शाता है। 2013-14 में जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत और 2012-13 में 5.1 प्रतिशत रही थी।
- उल्लेखनीय है कि संघीय बजट 2015-16 में चालू वर्ष (2015-16) में 8-8.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का आकलन व्यक्त किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि जनवरी से मार्च, 2015 की तिमाही के दौरान 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारत, चीन (7%) को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक तीव्र विकास दर वाला देश हो गया है।
- अनंतिम अनुमानों के अनुसार मूल स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार जीवीए वृद्धि दर (% में) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निम्नानुसार रही है—

क्षेत्र	2013-14	2014-15
1. कृषि, वानिकी एवं मत्स्ययन	3.7	0.2
2. खनन एवं उत्खनन	5.4	2.4
3. विनिर्माण	5.3	7.1
4. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएं	4.8	7.9
5. निर्माण	2.5	4.8
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	11.1	10.7
7. वित्तीय, स्थावर संपदा एवं व्यावसायिक सेवाएं	7.9	11.5
8. लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	7.9	7.2
मूल कीमतों पर जीवीए	6.6	7.2

- 2014-15 में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (Per Capita NNI-प्रति व्यक्ति आय) 74,104 रु. के स्तर पर है जो 2013-14 (69,959 रु.) की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक है। 2013-14 में इसमें 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 87,748 रु. अनुमानित है जो कि 2013-14 (80,388 रु.) की तुलना में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

घाटे की प्रवृत्तियों संबंधी नवीनतम अनुमान

17 मई, 2015 को जारी वर्ष 2014-15 के अनंतिम (Provisional) आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.0 प्रतिशत ही रहने का आकलन है जो कि 2014-15 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों के तहत 4.1 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत था जबकि 2015-16 में इसके जीडीपी के 3.9 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है।

वर्ष 2014-15 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष राजस्व घाटा जीडीपी का 2.8 प्रतिशत ही रहने का आकलन है जो कि 2014-15 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों के तहत 2.9 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहा जबकि 2015-16 में इसके जीडीपी के 2.8 प्रतिशत के स्तर पर रहने का बजट अनुमान लिया गया है।

17 नए मेगा फूड पार्कों को स्वीकृति

- 24 मार्च, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा 17 नए मेगा फूड पार्कों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें से 7 मेगा फूड पार्क राज्यों की एजेंसियों के जबकि 10 मेगा फूड पार्क निजी एजेंसियों के हैं।
- राज्यों की एजेंसियों वाले मेगा फूड पार्क अलप्पुसा एवं पलक्कड़ (केरल), खम्माम (तेलंगाना), सोनीपत (हरियाणा), खुर्दा (ओडिशा), लुधियाना (पंजाब) एवं कृष्णा (आंध्र प्रदेश) में स्थापित किए जाएंगे जबकि निजी एजेंसियों वाले मेगा फूड पार्क कच्छ (गुजरात), वर्धा एवं अहमदनगर (महाराष्ट्र), देवास (मध्य प्रदेश), कृष्णागिरी एवं थिरूवल्लूर (तमिलनाडु), महबूबनगर (तेलंगाना), पानीपत (हरियाणा), बक्सर (बिहार) एवं कपूरथला (पंजाब) में स्थापित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि पहले से स्वीकृत 25 मेगा फूड पार्कों में से 3 का उद्घाटन किया जा चुका है (नवीनतम 28 मई, 2015 को असम के नालबाड़ी में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है) तथा शेष भी क्रमिक रूप से संचालित होने की प्रक्रिया में हैं।
- 17 नए मेगा फूड पार्कों को स्वीकृति के साथ देश में विभिन्न स्थानों पर अब तक स्वीकृत मेगा फूड पार्कों की कुल संख्या 42 हो गई है।
- बिहार के खगड़िया एवं रोहतास में क्रमशः 6 और 14 अगस्त, 2015 को मेगाफूड पार्कों की आधारशिला रखी गई है।

व्यापक नई यूरिया नीति, 2015 को स्वीकृति

- 13 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अगले 4 वित्तीय वर्षों हेतु 'व्यापक नई यूरिया नीति (Comprehensive New Uria Policy), 2015' को स्वीकृति प्रदान की गई। नई यूरिया नीति के प्रमुख उद्देश्यों में स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि करने और यूरिया उत्पादन इकाइयों की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने के साथ सरकार पर सब्सिडी के बोझ को कम करना शामिल है।
- ऊर्जा में बचत कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी और इस प्रकार यह अधिक पर्यावरण अनुकूल होगी। यह नीति घरेलू क्षेत्र की 30 यूरिया उत्पादन इकाइयों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने में मदद करेगी और सब्सिडी बोझ को युक्तिसंगत बनाने के साथ यूरिया इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे किसानों को समान एमआरपी पर यूरिया की समय से आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा यह यूरिया क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को भी कम करेगी।
- आकलन है कि इस नीति से आगामी 4 वर्षों में यूरिया क्षेत्र में ऊर्जा खपत के नए मानदंडों को अपनाने तथा आयात प्रतिस्थापन से कुल 4,829 करोड़ रु. की सब्सिडी बचत होगी जिसमें 2,618 करोड़ रु. की प्रत्यक्ष बचत तथा 2,211 करोड़ रु. की अप्रत्यक्ष बचत शामिल है। साथ ही इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त उत्पादन होने की भी प्रत्याशा है।
- नई यूरिया नीति के तहत किसानों के लिए यूरिया का मूल्य पूर्ववत (अर्थात स्थानीय करों को छोड़कर 268 रु. प्रति 50 किग्रा बैग) रखा गया है तथा नीम-लेपित यूरिया पर प्रति बैग मात्र 14 रु. अतिरिक्त देने होंगे।
- वर्तमान में भारत अपनी कुल 310 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवश्यकता में से लगभग 80 लाख मीट्रिक टन का आयात करता है तथा उपर्युक्त सभी प्रयत्नों से यूरिया के लिए देश की आयात निर्भरता के काफी कम होने का अनुमान है।

फोर्ब्स की 'ग्लोबल-2000' सूची

- लब्ध प्रतिष्ठ व्यावसायिक मैगजीन फोर्ब्स (Forbes) द्वारा मई, 2015 में विश्व की 2000 शीर्षस्थ कंपनियों की अपनी वार्षिक सूची 'ग्लोबल-2000' (Global-2000) वर्ष 2015 के लिए जारी की गई।
- इस सूची में प्रथम 4 स्थानों पर चीन की बैंकिंग कंपनियां हैं— 1. आईसीबीसी बैंक, 2. चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, 3. एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, 4. बैंक ऑफ चाइना। पांचवें स्थान पर अमेरिका की विविध क्षेत्र की कंपनी बर्कशायर हैथवे है।
- इस वर्ष इस सूची में भारत की 56 कंपनियां (गत वर्ष यह संख्या 54 थी) शामिल हैं जिनमें शीर्षस्थ 5 कंपनियां (और समग्र सूची में उनका स्थान) इस प्रकार हैं—

  (i) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (142वां स्थान)
  (ii) भारतीय स्टेट बैंक (152वां स्थान)
  (iii) ओएनजीसी (183वां स्थान)
  (iv) टाटा मोटर्स (263वां स्थान)
  (v) आईसीआईसीआई बैंक (283वां स्थान)

वर्ष 2014-15 में भारत का विदेशी व्यापार

- 17 अप्रैल, 2015 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम (Provisional) आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में भारत का **पण्य निर्यात** (Goods Export) 310.534 बिलियन डॉलर रहा जो कि 2013-14 में 314.416 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार इसमें डॉलर संदर्भ में 1.23 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।
- वर्ष 2014-15 में भारत का **पण्य आयात** (Goods Import) 447.548 बिलियन डॉलर रहा जो 2013-14 में 450.214 बिलियन डॉलर के स्तर पर था। इस प्रकार इसमें डॉलर संदर्भ में 0.59 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।
- वर्ष 2014-15 में **व्यापार घाटा** (Trade Deficit) 137.014 बिलियन डॉलर रहा है जो कि 2013-14 के 135.798 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा अधिक है।
- वर्ष 2014-15 में तेल आयात 138.262 बिलियन डॉलर के स्तर पर रहा जो कि गत वर्ष (164.770 बिलियन डॉलर) की तुलना में 16.09 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- वर्ष 2014-15 में देश के कुल आयात में तेल आयात का हिस्सा 30.89 प्रतिशत तथा तेल-भिन्न आयात का भाग 69.11 प्रतिशत रहा है। यह भी महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का तेल-आयात देश के व्यापार घाटे के लगभग समान आकार का रहा है।

सेशेल्स विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल

- 26 अप्रैल, 2015 को सेशेल्स विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इसके 161वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि सेशेल्स द्वारा डब्ल्यूटीओ की सदस्यता हेतु औपचारिक आवेदन इस संगठन के अस्तित्व में आने (1 जनवरी, 1995) के शीघ्र बाद मई, 1995 में ही प्रस्तुत किया गया था तथा 20 वर्षों की समझौता वार्ताओं के बाद अब जाकर यह इसकी सदस्यता हासिल कर सका है।
- हाल के वर्षों में डब्ल्यूटीओ के सदस्य बने अन्य देशों का विवरण इस प्रकार है—

यमन (160वां सदस्य)	—	जून, 2014
ताजिकिस्तान (159वां सदस्य)	—	मार्च, 2013
लाओस (158वां सदस्य)	—	फरवरी, 2013
रूस (157वां सदस्य)	—	अगस्त, 2012

प्रधानमंत्री 'मुद्रा' योजना का शुभारंभ

- 8 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' का शुभारंभ किया गया।
- इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रु. की प्रारंभिक निधि और 3,000 करोड़ रु. की गारंटी निधि के साथ 'सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (MUDRA : Micro Units Development Refinance Agency) बैंक' की स्थापना की गई है।
- 'मुद्रा बैंक' सभी सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (MFIs : Micro-Finance Institutions) को विनियमित (नीतिगत दिशानिर्देश निर्माण एवं उनके पंजीकरण के साथ) करेगा और उन्हें छोटी व्यावसायिक इकाइयों को ऋण प्रदान करने के संदर्भ में पुनर्वित्तीयन भी उपलब्ध कराएगा।
- 'मुद्रा बैंक' राज्य स्तरीय समन्वयक के साथ मिलकर सूक्ष्म/छोटे व्यावसायिक उद्यमों के निचले सिरे के ऋण प्रदाता को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा तथा यह सूक्ष्म/छोटे उद्यमों के लिए लॉस्ट माइल क्रेडिट डिलिवरी का एक अच्छा आर्किटेक्चर भी तैयार करेगा।
- इस ऋणप्रदाता एवं पुनर्वित्तीयन बैंक के लिए 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' मुख्य समर्थन प्रणाली होगी तथा यह बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के भाग के रूप में कार्य करेगा।
- 'मुद्रा बैंक' प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख रु. तक का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत ऋण लेने वालों को 'मुद्रा कार्ड' भी मिलेगा जिसे आकस्मिक आवश्यकता की स्थिति में क्रेडिट कार्ड की तरह प्रयोग कर 10 हजार रु. तक प्राप्त किए जा सकेंगे।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म/छोटी व्यावसायिक इकाइयों हेतु प्रारंभिक रूप से 3 प्रमुख ऋण योजनाओं की शुरुआत की गई है, जो कि व्यवसाय के 3 स्तरों पर वित्तीयन उपलब्ध कराएंगी। इनमें प्रथम योजना 'शिशु' है जिसके तहत किसी व्यक्ति को व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ के लिए 50 हजार रु. तक का ऋण मिलेगा। दूसरी योजना 'किशोर' है जिसके तहत 50 हजार से 5 लाख रु. तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। तीसरी योजना 'तरुण' के तहत 5 से 10 लाख रु. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

नई विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-2020

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत की नई 'विदेश व्यापार नीति (FTP : Foreign Trade Policy), 2015-2020' 1 अप्रैल, 2015 को जारी की गई।
- इस नीति का सर्वप्रमुख उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत को एक निर्यात पॉवरहाउस के रूप में स्थापित करना है। इस नीति के तहत वर्ष 2020 तक देश के निर्यात को 900 बिलियन डॉलर के स्तर तक तथा वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई विदेश व्यापार नीति दो नई योजनाओं- 'भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS : Merchandise Exports from India Scheme) तथा 'भारत से सेवा निर्यात योजना' (SEIS : Services Exports from India Scheme) पर आधारित है। इस नीति के तहत पूर्व की सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का विलय इन दोनों नई योजनाओं में कर दिया गया है।
- एमईआईएस योजना चयनित बाजारों में निर्धारित वस्तुओं के निर्यात के लिए है तथा इसमें निर्यातकों को 2 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन या रिवॉर्ड प्राप्त होगा।
- एसईआईएस योजना अधिसूचित सेवाओं के निर्यात संवर्धन हेतु है तथा चयनित सेवाओं के निर्यातकों को 3 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के निर्यातक भी इन दोनों योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त भी इस नीति में एसईजेड हेतु अनेक प्रोत्साहन उपाय (यथा- एमईआईएस एवं एसईआईएस के तहत निर्यात दायित्व में 25 प्रतिशत कमी) किए गए हैं।
- नई विदेश व्यापार नीति के तहत विदेश व्यापार को बढ़ाने में

महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले कारोबारियों एवं निर्यातकों को विशेष दर्जा मिलेगा तथा ऐसे व्यवसायियों को वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार और फाइव स्टार का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

- नई विदेश व्यापार नीति में घोषित प्रोत्साहनों के संदर्भ में भारत से आयात करने वाले बाजारों को तीन भागों में विभाजित किया गया है-
  - (i) परंपरागत बाजार : इसमें अमेरिका, कनाडा एवं यूरोपीय संघ सहित कुल 30 देश/अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
  - (ii) उभरते बाजार : इस श्रेणी में पूर्व सोवियत संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों सहित कुल 139 देश। अर्थव्यवस्थाएं हैं।
  - (iii) अन्य बाजार : इस तीसरी श्रेणी में शामिल देशों/ अर्थव्यवस्थाओं की संख्या 70 है।
- नई विदेश व्यापार नीति के तहत कालीकट एयरपोर्ट, केरल एवं अराकोनम आईसीडी, तमिलनाडु को निर्यात के लिए अतिरिक्त बंदरगाह घोषित किया गया है तथा विशाखापत्तनम और भीमावरम को 'टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' (उत्कृष्ट निर्यात शहर) का दर्जा दिया गया है।

परंपरागत मनीऑर्डर सेवा बंद

- 1 अप्रैल, 2015 से डाक विभाग द्वारा परंपरागत मनीऑर्डर सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि यह सेवा 135 वर्ष पूर्व वर्ष 1880 में प्रारंभ की गई थी।
- इससे पूर्व 14 जुलाई, 2013 की रात्रि 9 बजे से देश में टेलीग्राम सेवा भी स्थायी रूप से बंद कर दी गई थी।
- उल्लेखनीय है कि डाक विभाग द्वारा परंपरागत मनीऑर्डर के स्थान पर लोगों को त्वरित गति से नकद हस्तांतरण की सुविधा देने के लिए मोबाइल मनीऑर्डर, आईएमओ (इंस्टेंट मनीऑर्डर) और ईएमओ (इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर) सेवाएं प्रारंभ की गई हैं।
- हालांकि 10 अप्रैल, 2015 को डाक विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह कहा गया है कि डाकघरों द्वारा दी जाने वाली मनीआर्डर सेवा को बंद नहीं किया गया है बल्कि इसे तकनीकी के प्रयोग से आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

संघीय बजट 2015-16

- 28 फरवरी, 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा अपना दूसरा तथा पूरे वर्ष के संदर्भ में पहला 'संघीय बजट 2015-16' संसद में प्रस्तुत किया गया।
- संघीय बजट 2015-16 का कुल आकार (कुल प्राप्तियां = कुल व्यय) 1777477 करोड़ रु. है।

घाटे की प्रवृत्तियां (जीडीपी का %)

प्रवृत्ति	2013-14 (वास्तविक अनंतिम)	2014-15 (बजट अनुमान)	2014-15 (संशोधित अनुमान)	2015-16 (बजट अनुमान)
राजस्व घाटा	3.1	2.9	2.9	2.8
प्रभावी राजस्व घाटा	2.0	1.6	1.8	2.0
राजकोषीय घाटा	4.4	4.1	4.1	3.9
प्राथमिक घाटा	1.1	0.8	0.8	0.7

- केंद्रीय आय (2015-16) के स्रोत : 1. ऋण एवं अन्य देयताएं (24%), 2. निगम कर (20%), 3. आय कर (14%), 4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (10%), 5. गैर कर राजस्व (विनिवेश आदि) (10%), 6. सेवा कर एवं अन्य कर (9%), 7. सीमा शुल्क (9%) एवं 8. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (4%)।
- केंद्रीय व्यय (2015-16) के स्रोत : 1. करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा (23%), 2. ब्याज अदायगी (20%), 3. रक्षा (11%), 4. केंद्रीय आयोजना (11%), 5. अन्य गैर योजनागत खर्च (11%), 6. सब्सिडियां (10%), 7. राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को योजनागत सहायता (9%) एवं 8. राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को गैर-योजनागत सहायता (5%)।
- केंद्रीय आयोजना के क्षेत्रवार परिव्यय में शीर्ष आवंटन वाले क्षेत्र वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में क्रमशः इस प्रकार हैं— 1. परिवहन, 2. ऊर्जा, 3. सामाजिक सेवाएं, 4. उद्योग एवं खनिज, तथा 5. सामान्य सेवाएं।

संघीय बजट 2015-16 : महत्त्वपूर्ण तथ्य

- संघीय बजट 2015-16 में सब्सिडियों पर कुल व्यय 2,43,811 करोड़ रु. (सर्वाधिक खाद्य सब्सिडी पर) रखा गया है, जो 2014-15 के संशोधित अनुमान (2,66,692 करोड़ रु.) से कम है।
- 2014-15 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.1 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया है। 'राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना' के तहत मूलतः 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत के स्तर तक लाने (तथा राजस्व घाटा 1.5 प्रतिशत एवं प्रभावी राजस्व घाटा शून्य प्रतिशत तक लाने) का लक्ष्य एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तदनुसार वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य क्रमशः 3.9%, 3.5 प्रतिशत और 3.0% इस बजट में निर्धारित किए गए हैं। इस हेतु एफआरबीएम एक्ट के प्रति वित्त विधेयक द्वारा संशोधन किया गया।
- वर्ष 2015-16 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 2014-15 के 8 लाख करोड़ रु. (ब.अ.) से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रु.।
- 20,000 करोड़ रु. की निधि और 3,000 करोड़ रु. की गारंटी निधि के साथ 'सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (MUDRA : Micro Units Development Refinance Agency) बैंक' के सृजन का प्रस्ताव (प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ)।
- मनरेगा हेतु 34,699 करोड़ रु. का प्रारंभिक आवंटन; 5,000 करोड़ रु. वृद्धि किए जाने की घोषणा।
- 20,000 करोड़ रु. के वार्षिक प्रवाह के साथ 'राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि' (NIIF : National Investment and Infrastructure Fund) की स्थापना किए जाने की घोषणा।
- अल्पसंख्यक युवाओं को समर्थ बनाने हेतु इस वर्ष 'नई मंजिल' नामक एकीकृत शिक्षा और आजीविका स्कीम।
- पारसियों की सभ्यता एवं संस्कृति हेतु 2015-16 में 'दि एवरलास्टिंग फ्लेम' नामक प्रदर्शनी को सहायता दी जाएगी।
- शिक्षाविदों को शामिल करके नवोन्मेष (Innovation) संवर्धन प्लेटफार्म उपलब्ध कराने और नवोन्मेष, अनुसंधान एवं विकास

की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग में 'अटल नवोन्मेष मिशन' (AIM); इस हेतु 150 करोड़ रु. का आवंटन।

- कारोबार प्रारंभ करने के सभी तथ्यों को सहायता प्रदान करने के लिए टेक्नो-फाइनेंशियल, उद्भवन एवं सुगमता कार्यक्रम के रूप में 'स्व-नियोजन और प्रतिभा उपयोग-सेतु' (SETU : Self-Employment and Talent Utilization) की स्थापना हेतु नीति आयोग के तहत 1,000 करोड़ रु. की राशि।
- इस वर्ष विदेशी और घरेलू दोनों ही ऋणों को एक एजेंसी के तहत लाने के लिए 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी' (PDMA)।
- 'निर्भया निधि' हेतु अतिरिक्त 1,000 करोड़ रु. का आवंटन।
- संघीय बजट 2015-16 में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से 69,500 करोड़ रु. की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट करने का लक्ष्य।
- विभिन्न मंत्रालयों में फैले कौशल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समेकन हेतु 'राष्ट्रीय कौशल मिशन' (NSM)।
- ग्रामीण युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि हेतु 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' के लिए 1,500 करोड़ रु. का आवंटन।
- 'प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम' के जरिए सभी छात्रवृत्तियों के संचालन एवं मॉनीटरिंग हेतु छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण।

प्रमुख कर प्रस्ताव

- वैयक्तिक आय कर की दरों एवं विदेशी कंपनियों के लिए कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं।
- अगले वर्ष से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन का प्रस्ताव।
- अगले वित्त वर्ष से 4 वर्षों में निगम (कॉरपोरेट) कर चरणबद्ध रूप से मौजूदा 30 से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा।
- 1 करोड़ रु. से अधिक वार्षिक व्यक्तिगत आय पर वर्तमान 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की दर से प्रभार।
- 'सामान्य अपवंचन निवारक नियमावली' (गार) को दो वर्षों तक स्थगित करने का निर्णय; यह लागू किए जाने के बाद 1.4.2017 से या उसके बाद भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।
- जीएसटी में लाने के सुगमीकरण हेतु शिक्षा उप-कर सहित सेवा कर वर्तमान 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत (1 जून, 2015 से प्रभावी)।
- संपत्ति कर या धन कर को हटाए जाने का निर्णय।
- स्वच्छ पर्यावरण पहलों के वित्त पोषण हेतु कोयला आदि पर 'स्वच्छ ऊर्जा कर' 100 रु. से बढ़ाकर 200 रु. प्रति मीट्रिक टन।
- 'स्वच्छ भारत कोष' और 'स्वच्छ गंगा निधि' में सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अतिरिक्त अन्य अंशदानों के लिए 100 प्रतिशत कर छूट।
- आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के तहत योग को धर्मार्थ प्रयोजन के कार्यक्षेत्र में लाने का निर्णय।
- उपकरों सहित केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 12.36 प्रतिशत की सामान्य दर को 12.5 प्रतिशत के समतुल्य पूर्णांकित करने का निर्णय।

आर्थिक समीक्षा 2014-15

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 27 फरवरी, 2015 को वर्ष 2014-15 की आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) संसद में प्रस्तुत की गई।
- आर्थिक समीक्षा 2014-15 का व्यापक केंद्रीय विषय है— 'अवसर पैदा करना और असुरक्षा के हालात कम करना' (Creating Opportunity and Reducing Vulnerability)।

आर्थिक समीक्षा 2014-15 : महत्त्वपूर्ण तथ्य

- केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने 2004-05 के पूर्ववर्ती आधार वर्ष के स्थान पर 2011-12 के नए आधार वर्ष को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रीय लेखाओं में सकल राशियों को जनवरी, 2015 में संशोधित किया है। अब विकास को अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप स्थिर बाजार मूल्यों (Market Prices) पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापा जाएगा जबकि पूर्व में इसे स्थिर मूल्यों पर कारक लागत (Factor Cost) पर जीडीपी में वृद्धि की दृष्टि से मापा जाता था। साथ ही अब क्षेत्रवार आकलन मूल कीमतों (Basic Prices) पर सकल मूल्य वर्धन (GVA : Gross Value Added) के तहत प्रस्तुत किए जाएंगे।
- स्थिर (2011-12) मूल कीमतों पर जीवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (प्रतिशत में) अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस प्रकार रही है—

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15
कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	1.2	3.7	1.1
उद्योग (निर्माण सहित)	2.3	4.5	5.9
सेवाएं	8.0	9.1	10.6
मूल कीमतों पर जीवीए	**4.9**	**6.6**	**7.5**
जीडीपी (बाजार मूल्यों पर)	**5.1**	**6.9**	**7.4**

- विगत 10 वर्षों में, भारत का पण्य (वस्तु) व्यापार (सीमाशुल्क आधार पर) 2004-05 के 195.0 बिलियन डॉलर से कई गुना बढ़कर 2013-14 में 764.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इसके फलस्वरूप वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 के क्रमशः 0.8 एवं 1.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013 में क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है।
- वर्ष 2013-14 में भारत का व्यापार घाटा (सीमाशुल्क आधार पर) 2012-13 के 190.3 बिलियन डॉलर से घटकर 135.8 बिलियन डॉलर के स्तर पर रहा है जो कि मुख्यतः आयात वृद्धि में गिरावट के कारण हैं।
- वर्ष 2015-16 में जीडीपी वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत तक होने की संभावना इस आर्थिक समीक्षा में व्यक्त की गई है।
- 10वीं योजना के दौरान, देश के सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 के मूल्यों पर) में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 19 प्रतिशत था जो 11वीं योजनावधि में घटकर 15.2 प्रतिशत रह गया है।
- 2011-12 के मूल्यों पर 2013-14 में कुल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 18 प्रतिशत (फसलें-11.8%,

पशुधन-3.9%, वानिकी एवं लॉगिंग-1.4% तथा मत्स्यन-0.9%) था।

- वर्तमान मूल्यों पर 2013-14 में कुल सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 7.9 प्रतिशत (फसलें-6.6%, पशुधन-0.7%, वानिकी एवं लॉगिंग-0.1% तथा मत्स्यन-0.5%) था।
- भारत का सेवा क्षेत्र वर्ष 2014-15 में जीडीपी वृद्धि में 72.4 प्रतिशत की भागीदारी के साथ आर्थिक वृद्धि का बड़ा प्रेरक बना हुआ है। वर्ष 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेवाओं का हिस्सा लगभग सभी राज्यों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक रहा था।
- विगत 12 वर्षों के दौरान, 8.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि औसत (सीएजीआर) के साथ, भारत का सेवा क्षेत्र चीन (10.7 प्रतिशत) के पश्चात दूसरा सर्वाधिक वृद्धिमान सेवा क्षेत्र था। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में, भारत की इस अवधि के दौरान 20 प्रतिशत की उच्चतम सीएजीआर थी।
- भारत की वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 3.2 प्रतिशत हो गई है तथा इस संदर्भ में शीर्ष निर्यातकों में यह छठें स्थान पर है।
- वर्ष 2020 तक भारत के विश्व का सर्वाधिक युवा राष्ट्र होने (विश्व में न्यूनतम औसत आयु 29 वर्ष के साथ) का आकलन व्यक्त किया गया है तथा यह वर्ष 2020 तक भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जहां 47 मिलियन युवा अधिशेष होंगे।
- अमेरिका समग्र जीडीपी के साथ-साथ सेवा जीडीपी में भी विश्व में प्रथम स्थान पर है जबकि चीन एवं जापान दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं। जीडीपी के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 15 देशों में भारत का समग्र जीडीपी में 10वां तथा सेवा जीडीपी में 11वां स्थान है।

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

- संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2015-20 की अवधि के लिए 2 फरवरी, 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था।
- 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी तथा 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट तथा इसके साथ आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी स्पष्टीकारक ज्ञापन, संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण में 24 फरवरी, 2015 को संसद में प्रस्तुत किया गया।
- 14वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की है कि इसकी पंचाट अवधि के लिए केंद्रीय करों के शुद्ध आगमों (निवल प्राप्तियों) में राज्यों का हिस्सा (ऊर्ध्वाधर अंतरण) 42 प्रतिशत पर नियत किया जाए। यह अब तक का सर्वाधिक ऊर्ध्वाधर अंतरण है।
- केंद्र सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जो कि 13वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के 32 प्रतिशत से 10 प्रतिशतांक की अभूतपूर्व वृद्धि है।
- राज्यों के हिस्से के राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण के संदर्भ में 14वें वित्त आयोग ने 1971 की जनसंख्या, तब से जनसांख्यिकी परिवर्तन, आय अंतराल, क्षेत्रफल एवं वन क्षेत्र के व्यापक मानदंडों को निम्नानुसार भारिता प्रदान की है—

क्र.सं.	मानदंड	भारिता (%)
1.	जनसंख्या (1971)	17.5
2.	जनसांख्यिकी परिवर्तन (1971-2011)	10.0
3.	आय अंतराल	50.0
4.	क्षेत्रफल	15.0
5.	वन क्षेत्र	7.5

- उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा इस संदर्भ में लिए गए मानदंड (एवं उनका भारांश) इस प्रकार थे- राजकोषीय क्षमता अंतराल (47.5 प्रतिशत), जनसंख्या (25 प्रतिशत), राजकोषीय अनुशासन (17.5 प्रतिशत) एवं क्षेत्रफल (10 प्रतिशत)।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्रीय कर अंतरण पूल में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं प. बंगाल हैं।
- आयोग ने सिफारिश की है कि 90 प्रतिशत भारांश के साथ 2011 की जनसंख्या के आंकड़े और 10 प्रतिशत भारांश के साथ क्षेत्रफल के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को अनुदानों का वितरण होना चाहिए।
- आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए 2015-20 अवधि हेतु कुल 2,87,436 करोड़ रु. का अनुदान आकलित किया है।
- आयोग ने दो भागों में अनुदानों की सिफारिशें की हैं- विधिवत रूप से गठित ग्राम पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय निकायों) और नगरपालिकाओं (नगरीय स्थानीय निकायों) के लिए एक 'बुनियादी अनुदान' (Basic Grant) और दूसरा 'निष्पादन अनुदान' (Performance Grant)। बुनियादी से निष्पादन अनुदान का अनुपात ग्राम पंचायतों के लिए 90:10 तथा नगरपालिकाओं के लिए 80:20 है।
- 14वें वित्त आयोग ने 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' और 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' के संभावित क्रियान्वयन के आलोक में पंचाट अवधि के लिए सभी राज्यों की राज्य आपदा राहत निधि में कुल संग्रह राशि के रूप में 61,219 करोड़ रु. की राशि की सिफारिश की है जिसमें से पंचाट अवधि के दौरान राज्य 10 प्रतिशत (6,122 करोड़ रु.) का अंशदान करेंगे और शेष 90 प्रतिशत (55,097 करोड़ रु.) केंद्र सरकार से आएंगे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'श्रमेव जयते' योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना' का सूत्रपात किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में मजदूरों की दशा-दिशा सुधारना है।
- इस योजना के तहत पारदर्शी श्रम निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से इंस्पेक्टरों को दिए गए विवेकाधिकार वापस लिए जाएंगे। कंप्यूटर पर ड्रा के जरिए तय होगा कि कौन-सा इंस्पेक्टर किस फैक्टरी का निरीक्षण करने जाएगा। निरीक्षण के बाद संबंधित निरीक्षक को 72 घंटों में ऑनलाइन रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

- गंभीर मामले जहां अनिवार्य निरीक्षण सूची में आएंगे, वहीं ऐसे मामलों के लिए आपात सूची का भी प्रावधान होगा। आकस्मिक निरीक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से कंप्यूटरीकृत सूची बनाई जाएगी एवं शिकायतों पर आधारित जांच केंद्रीय स्तर पर आंकड़ों एवं साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।
- योजना के तहत पीएफ जमा करने वालों के लिए यूनिवर्सल खाता नंबर की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। नए नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी और उसका खाता स्वयं स्थानांतरित हो जाएगा।
- योजना के तहत शुरू किए गए श्रम सुविधा पोर्टल से 16 श्रम कानूनों का अनुपालन आसान बनाने के लिए एक ही ऑनलाइन फार्म पेश किया गया है।

'मेक इन इंडिया' वैश्विक पहल

- 25 सितंबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' (Make in India) वैश्विक पहल का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लोगो मशीनीकृत शेर है।
- 'मेक इन इंडिया' नामक इस नए वृहद राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। यह कार्यक्रम देश में निवेश को बढ़ाने, नवप्रवर्तन को तीव्रतर करने, कौशल विकास संवर्धन, बौद्धिक संपदा संरक्षण और उत्कृष्ट विनिर्माण अवसंरचना के निर्माण के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है।
- इसमें वर्तमान में शामिल क्षेत्र हैं—ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, निर्माण क्षेत्र, रक्षा विनिर्माण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी एंड बीपीएम, लेदर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, खनन, तेल एवं गैस, फार्मास्युटिकल्स, बंदरगाह, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क एवं राजमार्ग, अंतरिक्ष, वस्त्र एवं परिधान, तापीय ऊर्जा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी तथा वेलनेस (आयुर्वेदिक एवं वैकल्पिक औषधि क्षेत्र)।
- इस वृहद अभियान के तहत भारत में निवेश के संवर्धन के साथ व्यवसाय करने की व्यवस्थाओं को सरल बनाने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

- 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'राष्ट्रीय बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' के तहत बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए 'सुकन्या समृद्धि योजना' नाम से राष्ट्रीय लघु बचत योजना का शुभारंभ पानीपत से किया गया।
- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु की होने तक कभी भी किसी भी डाकघर अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक शाखा में बेटी के नाम से 1 हजार रु. की न्यूनतम राशि से खाता खोला जा सकेगा। हर वर्ष इस खाते में न्यूनतम 1 हजार और अधिकतम 1.5 लाख रु. तक जमा कराए जा सकेंगे जिन पर संबंधित वित्त वर्ष में लोक भविष्य निधि खाते की तरह कर छूट प्राप्त हो सकेगी।
- बेटियों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई इस योजना के तहत खाता खोलने से 14 वर्ष तक धन जमा कराना होगा।
- यह खाता उसे खोले जाने से 21 वर्ष पूरे होने या 18 वर्ष की आयु के पश्चात बालिका का विवाह होने तक संचालित रहेगा। बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर उसकी उच्चतर शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाते में शेष राशि की 50 प्रतिशत धनराशि निकाली जा सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना की सुविधा केवल दो बेटियों के लिए ही मिलेगी तथापि यदि पहली बेटी के बाद जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं तो ऐसी स्थिति में तीनों बेटियों के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा।

यूरेशियाई आर्थिक संघ (EEU) का गठन

- दिसंबर, 2014 के अंतिम सप्ताह में मॉस्को में रूस और 4 पूर्व सोवियत राष्ट्रों- कजाख्स्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान के मध्य संपन्न बैठक में यूरेशियाई आर्थिक संघ (EEU) की स्थापना को अंतिम रूप दिया गया तथा 1 जनवरी, 2015 से यह अस्तित्व में आ गया है।
- कजाख्स्तान की राजधानी अस्ताना में 29 मई, 2014 को आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कजाख्स्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा 'यूरेशियाई आर्थिक संघ' (EEU) की स्थापना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत इन तीनों देशों की संसदों द्वारा इस समझौते के अनुसमर्थन (Ratification) के बाद 1 जनवरी, 2015 यूरोपीय संघ की तर्ज पर गठित होने वाले इस आर्थिक संघ के अस्तित्व में आने की तिथि निर्धारित की गई थी।
- 10 अक्टूबर, 2014 को आर्मेनिया द्वारा तथा 23 दिसंबर, 2014 को किर्गिस्तान द्वारा यूरेशियाई आर्थिक संघ में शामिल होने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आर्मेनिया (ध्यातव्य है कि आर्मेनिया ही इस संघ में ऐसा देश है जिसकी अन्य किसी सदस्य देश के साथ साझा सीमा नहीं है तथा जॉर्जिया द्वारा उसे ट्रांजिट कॉरिडोर उपलब्ध कराया जा रहा है) की संसद के अनुसमर्थन के बाद वह 2 जनवरी, 2015 से तथा किर्गिस्तान की संसद द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन किए जाने के बाद वह 6 अगस्त, 2015 से इस संघ में शामिल हुआ है।
- 18 जून, 2015 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ द्वारा एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत दोनों पक्षों में मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ) समझौते हेतु वार्ताएं प्रारंभ हुईं हैं।

◆◆◆

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंथन

● वी-20 : जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य देशों का समूह ● INDC : जलवायु परिवर्तन पर भारत के अभिप्रेत योगदान ● 'मिशन इंद्रधनुष' के द्वितीय चरण का शुभारंभ ● नासा : मंगल ग्रह पर जल प्रवाह की घोषणा ● पीएसएलवी-सी30/एस्ट्रोसैट मिशन ● राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2015 ● जीएसएलवी-डी6 : स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पुनः सफल ● भारत जच्चा-बच्चा टिटनेस से मुक्त ● विश्व की प्रथम मलेरिया वैक्सीन ● ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम ● डॉ. कलाम के नाम पर यूएन का वैश्विक उपग्रह ● पश्चिमी घाट के चमगादड़ों का अस्तित्व खतरे में ● गुजरात के जंगली गधे विलोपन के कगार पर ● नैनो क्रिस्टल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत तृतीय ● एचपीसीएल का बायो डीजल ब्लेंडेड डीजल ● विटामिन बी-9 युक्त टमाटर ● पहली बार मिली 3D प्रिंटेड दवा को मंजूरी ● विश्व में पेड़ों की संख्या है तीन खरब ● अंतरिक्ष में उत्पादित खाद्य पदार्थ ● विलोपन के कगार पर भारत का बैंगनी मेंढक ● गूगल लून प्रोजेक्ट पर श्रीलंका का गूगल से समझौता ● माइक्रोसॉफ्ट शुरू करेगा व्हाइट-फाई टेक्नोलॉजी ● पांच विलुप्तप्राय जीवों के संरक्षण हेतु 20 करोड़ आवंटित ● ब्रेकथ्रू लिसेन प्रोजेक्ट ● विश्व तम्बाकू महामारी रिपोर्ट–2015 ● ई-बस्ता ● वैश्विक वन संसाधन आकलन-2015 रिपोर्ट ● द्वितीय साइलेंट स्प्रिंग : महासागरों में प्लास्टिक संकट ● ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाएं ● पीएसएलवी-सी28 की सफल उड़ान ● 'न्यू होराइजंस' : प्लूटो पहुंचा अंतरिक्ष अन्वेषण यान ● शनि के चंद्रमा पर ध्रुवीय हवाएं ● मानव भ्रूणों की जीन एडिटिंग ● अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन ● चीन द्वारा निर्मित प्रथम विद्युत चालित विमान ● नासा के 'मेसेंजर' अंतरिक्ष मिशन का समापन ● तुलसी की पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग ● दक्षिण कोरिया में मर्स (MERS) का प्रकोप ● 14वीं एशियाई शेर गणना 2015 ● सर्वाधिक वृहद क्षुद्रग्रह संघात क्षेत्र ● पोर्ट ब्लेयर चुंबकीय वेधशाला का उद्घाटन ● लार्ज हैड्रान कोलाइडर (LHC) पुनः प्रारंभ ● आईआरएनएसएस-1डी का सफल प्रक्षेपण ● डॉन : नासा का अंतरिक्ष अन्वेषण यान ● सोलर इम्पल्स-2 की उड़ान ● डायरिया नियंत्रण हेतु स्वदेशी टीके का शुभारंभ ● सफर : वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली ● राष्ट्रीय कृमि निवारण पहल ● भारत का पहला हाई-स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क ● भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC) का 102वां सत्र ● भारत-आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (INO) ● केपलर 2 मिशन द्वारा 'सुपर-अर्थ' की खोज

वी-20 : जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य देशों का समूह

- 8 अक्टूबर, 2015 को जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य 20 देशों के वित्त मंत्रियों के समूह 'वी-20' (V-20 : The Vulnerable Twenty Group) की उद्घाटन बैठक लीमा (पेरू) में आयोजित की गई। इस बैठक में इस समूह के सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने प्रतिभाग किया।
- 'वी-20' समूह के सदस्य देश हैं–अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बारबेडॉस, भूटान, कोस्टारिका, इथियोपिया, घाना, केन्या, किरिबाती, मेडागास्कर, मालदीव, नेपाल, फिलीपींस, रवांडा, सेंट लूसिया, तंजानिया, तिमोर-लेस्ते, तुवालू, वनुआतु और विएतनाम।
- उल्लेखनीय है कि मालदीव द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील 10 अन्य देशों के साथ मिलकर 2009 के कोपेनहेगेन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पूर्व नवंबर, 2009 में 'जलवायु सुभेद्य मंच' (CVF : Climate Vulnerable Forum) की स्थापना की गई थी तथा क्रमिक रूप से अन्य 9 देश (कुल 20) इस मंच में शामिल हुए थे।
- जलवायु सुभेद्य मंच द्वारा '2013-2015 के कोस्टारिका एक्शन प्लान' में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कार्यवाहियों को त्वरित करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए 'वी-20' समूह का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया था और तद्नुसार लीमा में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान इस समूह की स्थापना की गई है।
- 'वी-20' समूह का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से इन देशों के समक्ष उत्पन्न भीषण समस्याओं का समाधान करने हेतु संसाधन जुटाना तथा औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक तापन के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही हेतु दबाव डालना है।
- 'वी-20' समूह की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता फिलीपींस के वित्त मंत्री सीजर पुरीसिमा (Cesar Purisima) द्वारा की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में फिलीपींस ही जलवायु सुभेद्य मंच (CVF) का अध्यक्ष है।
- इस बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों द्वारा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिक्रिया को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानवीय प्राथमिकता माने जाने का आह्वान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और घरेलू संघटन सहित सभी स्रोतों से जलवायु कार्यवाही हेतु सार्वजनिक एवं निजी वित्त में सार्थक वृद्धि करने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- वे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आर्थिक और वित्तीय जोखिमों को वितरित करने, जलवायु-प्रेरित अतिशय मौसमी घटनाओं एवं आपदाओं से सामान्य स्थिति में वापसी तथा रोजगार, आजीविकाओं एवं व्यवसायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संप्रभु (Sovereign) 'वी-20 क्लाइमेट रिस्क पूलिंग मेकेनिज्म' (V-20 Climate Risk Pooling Mechanism) की स्थापना करने पर भी सहमत हुए।
- उन्होंने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष हेतु अतिरिक्त संसाधनों के संघटन में सहायता के लिए एक 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन कर' (International Financial Transaction Tax) के समर्थन का भी आह्वान किया।
- उन्होंने अनुकूलन और उपशमन कार्यवाहियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वित्तीयन तक पहुंच में सुधार तथा 'हरित जलवायु निधि' (GCF : Green Climate Fund) हेतु विकसित देशों की 100 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता को पूरा किए जाने की भी मांग की।
- उल्लेखनीय है कि वी-20/सीवीएफ देशों में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील अल्प और अल्पतम विकसित, मरुस्थलीय, स्थलरुद्ध, पर्वतीय और छोटे द्वीपीय एवं तटवर्ती देश शामिल हैं। इन देशों की जनसंख्या लगभग 700 मिलियन है जो कि कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग दसवां हिस्सा है। जलवायु परिवर्तनकारी हरितगृह गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में इन देशों का योगदान मात्र 2 प्रतिशत है तथापि वैश्विक तापन/जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले ये ही देश हैं। वर्तमान वैश्विक तापन स्तर में कमी न आने पर वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन से इन देशों को प्रतिवर्ष 400 बिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक हानि होने का आकलन व्यक्त किया गया है।

INDC : जलवायु परिवर्तन पर भारत के अभिप्रेत योगदान

- 1 अक्टूबर, 2015 को भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपने 'अभिप्रेत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान' (INDC :

Intended Nationally Determined Contribution) संबंधी दस्तावेज बॉन में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय' (UNFCCC : UN Framework Convention on Climate Change) को प्रस्तुत किए गए और इन्हें गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली में घोषित किया गया।

- उल्लेखनीय है कि वारसा में 2013 में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 19) में सभी देशों से 2015 में पेरिस में होने वाले सम्मेलन (COP 21; 30 नवंबर-11 दिसंबर, 2015) के पूर्व अपने-अपने आईएनडीसी तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ताकि जलवायु परिवर्तन पर सभी देशों की राष्ट्रीय स्तर पर वचनबद्धताओं को समेकित कर पेरिस में नए 'अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते' पर हस्ताक्षर का मार्ग प्रशस्त हो।
- वस्तुतः भावी पेरिस समझौते का व्यापक वैश्विक लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों से इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर सीमित करने के लिए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य के साथ 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल (जिसे 2012 में दोहा में संपन्न COP 18 में वर्ष 2020 तक बढ़ाए जाने पर सहमति बनी थी) को नए प्रारूप के अनुसार परिवर्तित करना है।
- यूएनएफसीसीसी के पक्षकार देशों से अपने आईएनडीसी में राष्ट्रीय स्तर पर हरित गृह उत्सर्जनों को कम करने के लिए उठाए जा रहे/जाने वाले कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- दिसंबर, 2014 में लीमा में संपन्न COP 20 में भारत और कई अन्य विकासशील देशों का यह पक्ष अंततः स्वीकृत किया गया था कि आईएनडीसी लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप देश स्वयं निर्धारित करेंगे और इसमें उपशमन (Mitigation) के अतिरिक्त अनुकूलन (Adap- tation), वित्त एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी वे शामिल कर सकेंगे।
- आईएनडीसी लक्ष्यों को प्रस्तुत करने की तिथि पहले 31 मार्च, 2015 तक थी (स्विट्ज़रलैंड 27 फरवरी, 2015 को इसे प्रस्तुत करने वाला पहला देश था) जिसे 1 अक्टूबर, 2015 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद प्रस्तुत होने वाले आईएनडीसी, पेरिस सम्मेलन के पूर्व पक्षकारों को दी जाने वाली यूएनएफसीसीसी रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- तद्नुसार भारत द्वारा डेडलाइन से कुछ ही समय पूर्व 38 पृष्ठों में विस्तारित अपना आईएनडीसी प्रस्तुत किया गया है, जिसके महत्त्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं—
  - (i) **सतत जीवनशैली** : परंपराओं और संरक्षण एवं संतुलन के मूल्यों पर आधारित स्वस्थ और सतत जीवन शैली का प्रतिपादन तथा प्रसार करना।
  - (ii) **स्वच्छ आर्थिक विकास** : आर्थिक विकास के समनुरूपी स्तर पर अन्य देशों द्वारा अब तक अनुसरण किए गए मार्ग पर चलने के स्थान पर एक जलवायु अनुकूल और स्वच्छतर मार्ग अपनाना।
  - (iii) **उत्सर्जन तीव्रता में कमी** : देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन गहनता (Emission Intensity) को वर्ष 2030 तक 2005 के स्तरों से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना।
  - (iv) **गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत के हिस्से में वृद्धि** : प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु निधि (GCF : Green Climate Fund) सहित कम लागत के अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक लगभग 40 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा की संचयी संस्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करना।
  - (v) **कार्बन सिंक में अभिवृद्धि** : वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनावरण एवं वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास (Carbon Sink) सृजित करना।
  - (vi) **अनुकूलन** : जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर रूप से अनुकूलन करना।
  - (vii) **वित्त प्रबंधन** : अपेक्षित संसाधनों और संसाधन अंतराल के आलोक में उपर्युक्त उपशमन और अनुकूलन कार्रवाइयों हेतु घरेलू संसाधन और विकसित देशों से नई एवं अतिरिक्त निधियां जुटाना।
  - (viii) **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण** : क्षमताओं का निर्माण करना तथा भारत में समुन्नत जलवायु प्रौद्योगिकी के शीघ्र प्रसार तथा ऐसी भावी प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास हेतु घरेलू ढांचा तथा अंतर्राष्ट्रीय वास्तुशिल्प का सृजन करना।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत द्वारा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित सभी सौर ऊर्जा समृद्ध देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन, आईएनएसपीए (INSPA : International Agency for Solar Policy and Application) का प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। इसका शुभारंभ आगामी COP 21 के दौरान 30 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेरिस में किए जाने की घोषणा की गई है।
- उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा अपने आईएनडीसी के तहत प्रस्तुत उत्सर्जन गहनता कम करने का लक्ष्य अब तक भारत द्वारा स्वैच्छिक तौर पर घोषित लक्ष्य (2020 तक 2005 के स्तर से जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में 20 से 25 प्रतिशत की कमी लाना) से 75 प्रतिशत अधिक है। इससे 3.59 बिलियन टन CO_2 समतुल्य उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।
- भारत ने 2005 से 2010 के मध्य जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 12 प्रतिशत की कमी की है तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की 'उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (Emission Gap Report), 2014' में भारत को अपने स्वैच्छिक लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर देशों में एक के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारत द्वारा वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य बढ़ाकर 175 GW कर दिया गया है जिसमें 100 GW सौर ऊर्जा, 60 GW पवन ऊर्जा, 10 GW बायोमास ऊर्जा तथा 5 GW लघु जलविद्युत शामिल हैं। इसके फलस्वरूप 326 मिलियन टन CO_2 समतुल्य प्रतिवर्ष उत्सर्जन में कमी होगी।

- भारत की 2030 तक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाहियों पर 2014-15 के मूल्यों पर 2.5 ट्रिलियन डॉलर की लागत आने का प्रारंभिक आकलन व्यक्त किया गया है।
- वर्तमान में भारत के जीडीपी की उत्सर्जन गहनता 0.36 किग्रा. CO_2 प्रति डॉलर के स्तर पर है जबकि विकसित देशों की वर्तमान भारत के समकक्ष आर्थिक स्तर पर यह लगभग 0.9 किग्रा. CO_2 प्रति डॉलर थी अर्थात समकक्ष आर्थिक स्तर के संदर्भ में भारत की उत्सर्जन गहनता विकसित देशों की तुलना में 60 प्रतिशत कम है।
- वर्ष 2030 में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों के वर्तमान वैश्विक औसत (8.98 टन CO_2 समतुल्य) से कम ही रहेगा।

प्रमुख देशों द्वारा CO_2 उत्सर्जन (2012)

देश	CO_2 उत्सर्जन प्रतिवर्ष (बिलियन टन)	वैश्विक वार्षिक उत्सर्जन में प्रतिशत हिस्सा	प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन (टन/व्यक्ति)
चीन	9.86	28.6%	7.1
अमेरिका	5.19	15.1%	16.4
यूरोपीय संघ	3.74	10.9%	7.4
भारत	1.97	5.7%	1.6
रूस	1.77	5.1%	12.4
जापान	1.32	3.8%	10.4
विश्व	34.5	100.0%	4.9

प्रमुख देशों द्वारा प्रस्तुत आईएनडीसी

देश	उत्सर्जन कटौती लक्ष्य	लक्ष्यित वर्ष	संदर्भ वर्ष	क्रियान्वयन अवधि
चीन	प्रति इकाई जीडीपी का 60-65%	2030	2005	2030 तक
अमेरिका	26-28% समग्रतः	2025	2005	2020-2025
यूरोपीय संघ	≥ 40% समग्रतः	2030	1990	2021-2030
भारत	प्रति इकाई जीडीपी का 33-35%	2030	2005	2021-2030
रूस	25-30% समग्रतः	2030	1990	2020-2030
जापान	26% समग्रतः	2030	2013	1 अप्रैल, 2021-31 मार्च, 2031

'मिशन इंद्रधनुष' के द्वितीय चरण का शुभारंभ

- 5 अक्टूबर, 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण हेतु समयबद्ध रूप से लक्ष्यित कार्यक्रम 'मिशन इंद्रधनुष' के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत वर्ष 2020 तक देश के 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के जरिए सभी बच्चों को आवश्यक 7 टीके लगाना सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें डिप्थीरिया (Diptheria), काली खांसी (Whooping Cough), टिटनेस (Tetanus), पोलियो (Polio), तपेदिक (Tuberculosis), खसरा (Measles) और हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B) शाामिल हैं।
- मिशन इंद्रधनुष का अनावरण 25 दिसंबर, 2014 को प्रथम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था तथा इसके प्रथम चरण का पहला दौर देश के 28 राज्यों के 201 उच्च प्राथमिकता जिलों में 7 अप्रैल, 2015 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) से एक सप्ताह से अधिक समय के लिए चलाया गया था। तत्पश्चात इसके तीन और दौर मई, जून एवं जुलाई, 2015 में 7 तारीख से एक सप्ताह से अधिक समय तक क्रियान्वित हुए थे।
- ज्ञातव्य है कि प्रथम चरण के तहत चिह्नित 201 जिलों में देश के कुल टीकाकरण से वंचित या आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों के लगभग 50 प्रतिशत निवासित हैं। इनमें से चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश) के 82 जिले तो देश के कुल टीकाकरण से वंचित या आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों के 25 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं।
- मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण के चार दौर के दौरान 9.4 लाख सत्र आयोजित किए गए जिसमें लगभग 2 करोड़ टीके, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिलाए गए। इन प्रतिरक्षाकरण दौरों में लगभग 75.5 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया और लगभग 20 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 20 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड का टीका दिया गया और डायरिया की समस्या से निपटने हेतु बच्चों को लगभग 16 लाख ओआरएस पैकेट और लगभग 57 लाख जिंक टैबलेट भी वितरित की गईं।
- मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण में देश के 352 जिलों को चयनित किया गया है जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता जिले, उत्तर-पूर्वी राज्यों के 33 जिले तथा प्रथम चरण के 40 जिले शामिल हैं, जिनमें टीकाकरण से छूट गए बच्चों की एक बड़ी संख्या का पता चला था। दूसरे चरण का प्रथम दौर 7 अक्टूबर, 2015 से प्रारंभ कर एक सप्ताह तक चलाया गया। इसके बाद

नवंबर एवं दिसंबर, 2015 तथा जनवरी, 2016 में 7 तारीख से तीन अन्य दौर इस चरण में क्रियान्वित किए जाएंगे। इस चरण में 2 वर्ष से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सात टीका निवारणीय रोगों से प्रतिरक्षा हेतु पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

- उल्लेखनीय है कि देश में जहां 2009 में 61 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण हुआ था, वहीं 2013 में बच्चों में टीकाकरण कवरेज बढ़कर 65 प्रतिशत के स्तर पर ही पहुंचा जो कि मात्र 1 प्रतिशतांक की वार्षिक कवरेज वृद्धि दर्शाता है।
- इसे देखते हुए वर्ष 2020 तक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को प्राप्त करने के लिए इसमें 5 प्रतिशतांक और अधिक की त्वरित वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु मिशन मोड में इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत केंद्रित और सघन टीकाकरण अभियान चलाकर सभी बच्चों को आच्छादित करने का लक्ष्य है, जो टीकाकरण की प्रक्रिया से छूट जाते या बाहर रह जाते हैं। इसके माध्यम से 65 प्रतिशत के कवरेज को 90 प्रतिशत से ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य है तथा इसमें भारत के 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' (Universal Immunization Programme) के तहत सभी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

नासा : मंगल ग्रह पर जल प्रवाह की घोषणा

- 28 सितंबर, 2015 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) द्वारा मंगल ग्रह पर जल प्रवाह की खोज की घोषणा की गई।
- नासा के 'मार्स रिकॉनेंसिएंश ऑर्बिटर' (MRO; मार्च, 2006 से मंगल ग्रह की कक्षा में सक्रिय अंतरिक्ष यान) से ली गई तस्वीरों के अध्ययनों के आधार पर नासा ने यह पुष्टि की है कि इस ग्रह पर खारे पानी की बहती धाराएं उपस्थित हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे अब तक के अनुमानों के विपरीत मंगल कोई सूखा या बंजर ग्रह नहीं है।
- नासा के अनुसार इस बात के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं कि मंगल ग्रह पर ग्रीष्म और वसंत ऋतुओं में कुछ विशेष स्थानों पर खारे पानी की धाराएं बहती हैं। वस्तुतः खारे पानी के लवण उस तापमान को कम कर देते हैं, जिस पर पानी जमता है। गर्मी बढ़ने के साथ-साथ ये धाराएं और बड़ी होती जाती हैं तथा तापमान में गिरावट के साथ शीत ऋतु में ये लुप्त रहती हैं।
- मंगल ग्रह पर जल प्रवाह की खोज से संबंधित शोधपत्र विज्ञान जर्नल 'नेचर जियोसाइंस' (Nature Geoscience) में भी प्रकाशित हुआ है जिसे नेपाली मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक <u>लुजेंद्र ओझा</u> और उनके सहयोगी शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है। लुजेंद्र ओझा के नेतृत्व में ही शोधकर्ताओं की टीम ने मार्स रिकॉनेंसिएंश ऑर्बिटर के <u>हाईराइज</u> (Hi RISE : High Resolution Imaging Science Experiment) नीतिभार से प्राप्त चित्रों से सबसे पहले 2011 में मंगल ग्रह की ढलानों पर गहरी और संकरी धारियों की खोज की थी।
- इन धारियों में जलयोजित लवणों की उपस्थिति पाए जाने के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने यहां जल प्रवाह की पुष्टि की है और यह माना है कि ये धारियां खारे जल के प्रवाह को दर्शाती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आवर्ती ढलानों की इन धारियों का निर्माण पानी के प्रवाह के कारण हुआ है।
- ज्ञातव्य है कि पूर्व में मंगल ग्रह पर जमे हुए (हिम रूप में) पानी की उपस्थिति के ही संकेत मिलते रहे हैं तथा सतह पर तरल जल की उपस्थिति की खोज पहली बार की गई है।
- यद्यपि नासा ने मंगल ग्रह पर जल प्रवाह पाए जाने की पुष्टि कर दी है तथापि इसके बाद भी वहां जीवन के लिए फिलहाल कोई सुदृढ़ उम्मीद प्रत्यक्ष नहीं हुई है। मंगल पर जो पानी मिला है वह बेहद सुदृढ़ता से लवणीय क्रिस्टलों के साथ बंधा हुआ है जबकि पृथ्वी पर हम इससे अलग तरल जल पाते हैं।
- मंगल ग्रह की सतह भी पृथ्वी से काफी अलग है। वहां तापमान काफी ज्यादा है और उस पर ब्रह्मांडीय विकिरण की बमबारी होती रहती है। इससे बड़े और जटिल कण चूर-चूर हो जाते हैं जो जीवन के पनपने के लिए आवश्यक हैं।

मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की नासा की त्रिस्तरीय योजना

मंगल ग्रह पर खारे जल प्रवाह की पुष्टि के बाद 9 अक्टूबर, 2015 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अगले 25 वर्षों में '<u>जर्नी टू मार्स' मिशन</u> के तहत मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की त्रिस्तरीय योजना तैयार करने की घोषणा की है।

इस मिशन का पहला चरण '<u>अर्थ रिलायंट एक्सप्लोरेशन</u>' है, जिसके तहत अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसे आंकने हेतु दो रूसी खगोलविदों को साल भर के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात किया गया है। नासा अंतरिक्ष यात्रियों से मिले आंकड़ों के आधार पर अंतरिक्ष के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, संचार व्यवस्था और सुदूर अंतरिक्ष यात्रा के लिए इंसानों को तैयार करने के उपायों पर शोध करेगा।

इस मिशन का द्वितीय चरण '<u>प्रूविंग ग्राउंड</u>' होगा जिसमें पृथ्वी से निर्भरता खत्म करने के तरीके खोजने के साथ नासा भारी निर्माण वस्तुओं को मंगल पर भेजने की कोशिश करेगा। संचार तकनीक के इस्तेमाल, थ्री-डी प्रिंटिंग तकनीक, सीमित संसाधनों में जीवन निर्वाह और चीजों की रिसाइकलिंग द्वारा उनका बारंबार उपयोग संभव बनाने की दिशा में प्रयास कर अंतरिक्ष यात्रियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस हेतु अंतरिक्ष यात्रियों को 'सिस्लूनर स्पेस' (चांद की कक्षा एवं आस-पास का अंतरिक्ष क्षेत्र) में प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है।

पहले और दूसरे चरण के नतीजों के आधार पर नासा तृतीय चरण '<u>अर्थ इंडिपेंडेंट</u>' के तहत मंगल पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना पर अंतिम निर्णय लेगा। इसकी तैयारियों के लिए 2020 के दशक में 'इनसाइट' सहित कई अंतरिक्ष यानों को मंगल ग्रह एवं इसके चंद्रमाओं पर भेजा जाएगा। ये यान मंगल ग्रह के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की तकनीक का परीक्षण भी करेंगे। नासा का उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर ऐसी संरचनाएं विकसित करना है जिससे लंबे समय तक वहां लोग रह सकें तथा मंगल के संसाधनों से ही ईंधन, भोजन, ऑक्सीजन एवं निर्माण सामग्री का उपयोग कर सकें।

क्या है 'मार्स वन' : नीदरलैंड्स के संगठन मार्स वन ने मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए 'मार्स वन' परियोजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा वर्ष 2012 में की थी। इसे नीदरलैंड्स के उद्यमी बास लैंसडोर्प ने प्रारंभ किया है। निजी पूंजी के आधार पर प्रारंभ की गई यह परियोजना शुरुआत से ही विवादों में फंसी रही है। अंतरिक्ष एवं एयरोस्पेस उद्योग जगत के अनेक वैज्ञानिक एवं इंजीनियर इसके विरुद्ध अपने-अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इस परियोजना के तहत वर्ष 2016 में शुरू किए जा रहे प्रशिक्षण में पृथ्वी पर ही मंगल ग्रह का कृत्रिम वातावरण बनाया जाएगा, जिसमें चुने हुए लोग प्रशिक्षण लेंगे। इनमें से केवल 24 को ही मंगल जाने के मिशन हेतु चयनित किया जाएगा। चयनित सभी लोगों को 6 समूहों में बांटा जाएगा जिनमें से 4 लोगों का पहला समूह वर्ष 2024 में मंगल ग्रह हेतु भेज जाने की योजना है।

- नासा के अनुसार, एक अहम समस्या यह भी है कि मंगल ग्रह पर जो तरल जल मिला है वह वहां कभी-कभी ही पाया गया है। यदि उसमें जीवन का कोई रूप होगा तो उसे चरम शुष्कता या निर्जलीकरण का सामना करना होगा।
- उल्लेखनीय है कि नासा मंगल ग्रह की मिट्टी को पृथ्वी पर लाने की कोशिश में भी लगा हुआ है। इस परियोजना को 'रेड ड्रैगन' नाम दिया गया है तथा इस अभियान की शुरुआत 2022 में हो सकती है।
- 26 अगस्त, 2015 को सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के वैज्ञानिकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की गिलमोर स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर मंगल ग्रह की सतह के नीचे से पानी को निकालने और उसे एकत्र करने में सक्षम एक रोवर का प्रोटोटाइप तैयार किए जाने की घोषणा की है। वैज्ञानिकों ने इस रोवर को 'मार्स एक्वा रिट्राइवल सिस्टम' (MARS) नाम दिया है। मात्र 10 हजार डॉलर की लागत वाला यह रोवर प्रोटोटाइप अभी मंगल के तापमान एवं दबाव की 30 प्रतिशत तक ही परिस्थितियों को सहन कर सकता है जिसे उन्नत करने हेतु प्रयास जारी हैं।

पीएसएलवी-सी30/एस्ट्रोसैट मिशन

- 28 सितंबर, 2015 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV : Polar Satellite Launch Vehicle) की 31वीं उड़ान के तहत पीएसएलवी-सी30 (PSLV-C30) को श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) स्थित भारत के स्पेसपोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) से सुबह 10:00 बजे प्रक्षेपित किया गया।
- पीएसएलवी-सी30 की यह लगातार 30वीं सफल उड़ान रही जिसके तहत भारत की 'बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला-एस्ट्रोसैट' (Multi Wavelength Space Observatory-ASTROSAT) को 6 विदेशी उपग्रहों के साथ भूमध्य रेखा से 6 डिग्री झुकाव पर 644.6×651.5 किमी. कक्षा (Low Earth Equatorial Orbit) में प्रक्षेपित किया गया।
- इन सातों उपग्रहों का कुल लिफ्ट-ऑफ वजन (प्रक्षेपण के समय उत्थापन भार) 1,631 किग्रा. था और इस कारण इस उड़ान में पीएसएलवी के सबसे भारी 'एक्सएल' (XL) संस्करण का प्रयोग किया गया जिसके प्रथम चरण में 6 स्ट्रैप-ऑन मोटर्स संलग्न थीं। इसके पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदकों तथा दूसरे और चौथे चरण में द्रव प्रणोदकों का प्रयोग किया गया था। एक्सएल वर्जन में पीएसएलवी की यह 10वीं उड़ान थी।
- 44.4 मीटर ऊंचे और 320.2 टन वजनी पीएसएलवी-सी30 के लिफ्ट-ऑफ के लगभग 22 मिनट बाद एस्ट्रोसैट उपग्रह प्रक्षेपणयान के चतुर्थ चरण से पृथक होकर अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया जिसके पश्चात 3 मिनट के भीतर शेष सभी सहयात्री उपग्रहों का पृथक्करण भी पूरा हो गया।
- पीएसएलवी-सी30 से पृथक होने के शीघ्र बाद एस्ट्रोसैट के दो सौर पैनल/एरै (Solar arrays) स्वचालित रूप से कार्यरत हो गए तथा इसरो के बंगलुरू स्थित टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (ISTRAC) के मिशन परिचालन कॉम्प्लेक्स (MOX) स्थित अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र द्वारा एस्ट्रोसैट पर नियंत्रण कायम कर लिया गया।
- एस्ट्रौसैट (इसका विस्तृत विवरण संलग्न बॉक्स में देखें) के साथ पीएसएलवी-सी30 द्वारा प्रक्षेपित 6 विदेशी उपग्रह इस प्रकार हैं—
  - (i) **चार लेमूर (LEMUR) नैनो उपग्रह** : इन चारों एक जैसे अमेरिकी उपग्रहों का कुल वजन लगभग 28 किग्रा. है। सैनफ्रांसिस्को (अमेरिका) की स्पायर ग्लोबल इंक. के ये चारों उपग्रह गैर-दृश्य दूर संवेदन उपग्रह हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) के द्वारा जलपोतों की ट्रैकिंग के माध्यम से वैश्विक समुद्री आसूचना उपलब्ध कराना तथा जीपीएस रेडियो ऑकुलेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उच्च-सटीकता के साथ मौसम पूर्वानुमान करना है।
  - (ii) **लापान-ए 2 (LAPAN-A2)** : इंडोनेशिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस (LAPAN) के इस माइक्रोसैटेलाइट का वजन 76 किग्रा. है। यह उपग्रह एआईएस के उपयोग से समुद्री निगरानी उपलब्ध कराने, आपदा राहत कार्यों हेतु इंडोनेशियाई-रेडियो एमेच्योर समुदायों को समर्थन प्रदान करने तथा वीडियो एवं डिजिटल कैमरे के द्वारा भू निरीक्षण हेतु भेजा गया है।
  - (iii) **एनएलएस-14 (ईवी 9)** : कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय उन्नत अध्ययन संस्थान (UTIAS) की स्पेस फ्लाइट लेबोरेटरी का यह नैनो उपग्रह 14 किग्रा. वजनी है। यह उपग्रह एआईएस के प्रयोग से समुद्री पर्यवेक्षण का कार्य करेगा।
- पीएसएलवी-सी30 की इस सफल उड़ान के तहत यह पहला अवसर है जब इसरो द्वारा अमेरिका के उपग्रहों का वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया गया।
- इस सफल प्रक्षेपण के 7 उपग्रहों के साथ इसरो द्वारा पीएसएलवी के माध्यम से अब तक कुल 84 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है जिसमें कुल मिलाकर 20 देशों के 51 उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण शामिल है।
- इसरो द्वारा सर्वप्रथम व्यावसायिक रूप से 26 मई, 1999 को पीएसएलवी-सी2 के माध्यम से जर्मनी के 'डीएलआर-टबसैट' और दक्षिण कोरिया के 'किटसैट-3' का प्रक्षेपण किया गया था। पीएसएलवी की पहली विशिष्ट व्यावसायिक उड़ान (पीएसएलवी-सी8) 23 अप्रैल, 2007 को संपन्न हुई थी

जिसके माध्यम से इटली के उपग्रह 'एजाइल' को प्रक्षेपित किया गया था। इसके पश्चात पीएसएलवी की पहली पूर्णतः व्यावसायिक उड़ान (जिसमें कोई भी भारतीय उपग्रह नहीं था) 23 जनवरी, 2008 को संपन्न हुई थी जब पीएसएलवी-सी10 के द्वारा इजरायल के उपग्रह 'टेकसार' का प्रक्षेपण किया गया था।

- पीएसएलवी-सी 30 की सद्यः उड़ान यह तीसरा अवसर है जब इस रॉकेट ने 7 (या अधिक) उपग्रहों को एक ही मिशन में प्रक्षेपित किया है।

एस्ट्रोसैट (ASTROSAT)

- एस्ट्रोसैट भारत की प्रथम समर्पित बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला (Multi Wavelength Space Observatory) है।
- 1513 किग्रा. लिफ्ट ऑफ वजन (ड्राई मास-1470 किग्रा.) वाली यह खगोलीय शोध को समर्पित वेधशाला पृथ्वी की निचली निकट भूमध्यरेखीय कक्षा (Low Earth Near Equatorial Orbit) में लगभग 650 किमी. की ऊंचाई पर स्थापित की गई है।
- चंद्रयान-I और मंगलयान की शानदार सफलता के बाद एस्ट्रोसैट की सफल स्थापना इसरो के महत्त्वाकांक्षी वैज्ञानिक मिशनों में से एक है।
- एस्ट्रोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत अब अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के ऐसे विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की है। ज्ञातव्य है कि चीन भी इस दिशा में अभी प्रयासरत है।
- इस वैज्ञानिक उपग्रह मिशन का उद्देश्य हमारे ब्रह्मांड (Universe) की अधिक विस्तृत और बेहतर जानकारियां उपलब्ध कराना है। एस्ट्रोसैट की अनन्य विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता इसका एक एकल उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय पिंडों के समकालिक बहु-तरंगदैर्ध्य निरीक्षणों में समर्थ होना है।
- एस्ट्रोसैट ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण विद्युत चुंबकीय (Electr-omagnetic) स्पेक्ट्रम के दृश्य (Optical), पराबैंगनी (Ultraviolet) तथा निम्न एवं उच्च ऊर्जा एक्स-किरण क्षेत्रों में करेगा जबकि अधिकांश अन्य वैज्ञानिक उपग्रह तरंगदैर्ध्य बैंड के सीमित रेंज में ही निरीक्षणों में सक्षम होते हैं।
- एस्ट्रोसैट के बहु-तरंगदैर्ध्य पर्यवेक्षणों को अन्य अंतरिक्ष यानों तथा भू-आधारित निरीक्षणों के उपयोग से समन्वित कर विस्तारित किया जा सकेगा।
- एस्ट्रोसैट को इसरो द्वारा इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA; पुणे), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR; मुंबई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIAP; बंगलुरू) तथा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI; बंगलुरू) सहित देश के सभी प्रमुख खगोलशास्त्र संस्थानों तथा कनाडा और ब्रिटेन के दो संस्थानों की सहायता से विकसित किया गया है।
- एस्ट्रोसैट की मिशन अवधि 5 वर्ष आकलित की गई है।
- एस्ट्रोसैट मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं—
  - (i) न्यूट्रॉन तारों एवं ब्लैक होलों से युक्त द्विआधारी तारा प्रणालियों (Binary Star Systems) में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना।
  - (ii) न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्रों का आकलन करना।
  - (iii) हमारी आकाशगंगा से दूर स्थित तारा प्रणालियों में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं और तारों के उत्पत्ति स्थानों का अध्ययन।
  - (iv) आकाश में नए संक्षिप्त चमकदार एक्स-किरण स्रोतों का संसूचन।
  - (v) पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के सीमित गहन क्षेत्र सर्वेक्षण का निष्पादन।
- एस्ट्रोसैट के 5 मुख्य वैज्ञानिक नीतिभार (Payloads) हैं—
  - (a) अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलिस्कोप (UVIT : Ultraviolet Imaging Telescope)—यह आकाश का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के दृश्य, निकट-पराबैंगनी और दूरस्थ-पराबैंगनी क्षेत्रों में पर्यवेक्षण में सक्षम है।
  - (b) लार्ज एरिया एक्स-रे प्रपोर्शनल काउंटर (LAXPC : Large Area X-ray Proportional Counter)—ब्रह्मांडीय स्रोतों (एक्स-रे बाइनरीज, क्रियाशील आकाशगंगा नाभिकों एवं अन्य अंतरिक्षीय स्रोतों) से एक्स किरणों के उत्सर्जन में विभिन्नताओं के अध्ययन हेतु इसे डिजाइन किया गया है।
  - (c) सॉफ्ट एक्स-रे टेलिस्कोप (SXT : Soft X-ray Telescope)—यह दूरवर्ती खगोलीय पिंडों से आने वाले 0.3-8 keV रेंज के एक्स-किरण स्पेक्ट्रम में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेगा।
  - (d) कैडमियम जिंक टेल्युराइड इमेजर (CZTI : Cadmium Zinc Telluride Imager)—यह उपकरण एक्स-किरण क्षेत्र में कार्य कर 10-100 keV रेंज में उच्च ऊर्जा युक्त एक्स-किरणों के संसूचन की उपग्रह की क्षमता को विस्तारित करेगा।
  - (e) स्कैनिंग स्काई मॉनीटर (SSM : Scanning Sky Monitor)—यह आकाश के गहन स्कैन के द्वारा द्विआधारी तारों में चमकदार एक्स-किरण स्रोतों का दीर्घकालीन पर्यवेक्षण करेगा तथा यह अल्प समयावधि में एक्स-किरण क्षेत्र में चमकने वाले स्रोतों की स्थिति का भी पता लगाएगा।
- इसरो के इन पांचों नीतिभारों से मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स (MOX) को प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का बंगलुरू के निकट ब्यालालू स्थित इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर (ISSDC) द्वारा संसाधन, विश्लेषण एवं वितरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2015

- भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (NHP : National Health Profile) वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (CBHI : Central Bureau of Health Intelligence) द्वारा तैयार किया जाता है।
- 22 सितंबर, 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा वर्ष 2015 का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (NHP) जारी किया गया।
- देश के जनांकिकीय, सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य स्तर एवं स्वास्थ्य-वित्त संकेतकों, स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन तथा स्वास्थ्य अवसंरचना (कुल 6 अध्यायों में विभाजित) को समाहित करने वाले इस व्यापक दस्तावेज से देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति की जानकारी के साथ भावी रणनीतियां तय करने में सहायता प्राप्त होती है।

■ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2015 : महत्त्वपूर्ण तथ्य

- एनएचपी, 2015 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में काफी कम है। देश में स्वास्थ्य पर कुल व्यय जीडीपी का 5 प्रतिशत है जिसका 80 फीसदी 'आउट ऑफ पॉकेट' व्यय (परिवारों का व्यय) है।
- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकारी (सार्वजनिक) व्यय 2012-13 में मात्र 1.08 प्रतिशत है तथा इसमें 2009-10 से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। स्वास्थ्य पर कुल सरकारी व्यय में केंद्र-राज्य भागीदारी 2012-13 में 33:67 के स्तर पर थी तथा केंद्र का भाग इस संदर्भ में विगत वर्षों में कम होता गया है।
- स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय बिहार एवं झारखंड में न्यूनतम है जबकि गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सबसे अधिक है।
- 2011-12 में आउट ऑफ पॉकेट चिकित्सा व्यय शहरी क्षेत्रों में 146 रु. तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 95 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह था। सभी राज्यों में केरल में यह सर्वाधिक था।
- 2013-14 में लगभग 22 करोड़ व्यक्ति किसी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित थे जो कि देश की कुल जनसंख्या का मात्र 18 प्रतिशत है।
- एनएचपी, 2015 के अनुसार देश में प्रति 61 हजार व्यक्तियों पर एक सरकारी अस्पताल (प्रति 1833 व्यक्तियों पर एक बेड) की उपलब्धता है।
- प्रत्येक लगभग 11 हजार व्यक्तियों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है। देश में 9.4 लाख एलोपैथिक चिकित्सक, 1.54 लाख दंत चिकित्सक और 7.73 लाख आयुष चिकित्सक (जिनमें से आधे से अधिक आयुर्वेद के हैं) हैं।
- वर्तमान में देश में चिकित्सा कॉलेजों की संख्या लगभग 400 है जहां प्रतिवर्ष लगभग 47 हजार छात्र प्रवेश पाते हैं।
- देश में मलेरिया से वार्षिक मौतें 2014 में घटकर लगभग 500 पर आ गई हैं जिनमें त्रिपुरा (96) सबसे ऊपर है। 2014 में देश में मलेरिया के सर्वाधिक मामले ओडिशा (388451) में दर्ज हुए।
- वायरल मेनिनजाइटिस के सर्वाधिक मामले ओडिशा में (2694) और सर्वाधिक मृत्युएं पुडुच्चेरी में (40) दर्ज हुईं।
- विश्व में काला-अजार दूसरा सबसे बड़ा घातक परजीवी (Parasite Killer) है। भारत में इसका वाहक लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी है। 2014 में देश में बिहार में काला-अजार के सर्वाधिक मामले (82%) एवं सर्वाधिक मृत्युएं (90%) दर्ज हुईं।
- वर्ष 2014 में डेंगू के 40 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए जिनमें मृत्युओं की संख्या 131 रही।
- 2013 की तुलना में 2014 में स्वाइन फ्लू से मौतों की संख्या में 68 प्रतिशत की कमी हुईं।
- 2014 में चिकेन पॉक्स के 3447 मामले दर्ज हुए जिसमें 57 मौतें हुई। इस वर्ष इसके सर्वाधिक मामले केरल में सामने आए जबकि सर्वाधिक मृत्युएं पश्चिम बंगाल में (29) हुईं।
- संक्रामक रोगों में मृत्युओं का सबसे बड़ा कारक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जिससे 2012 में 63261 मृत्युएं हुईं।
- 2014 में रेबीज के दर्ज सभी 104 मामलों में मृत्यु हो गई (100%) जबकि इसके बाद सर्वाधिक मृत्यु दर स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामले में 23.27% (937 मामलों में 218 मृत्युएं) रही।

जीएसएलवी-डी6 : स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पुनः सफल

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से युक्त अपने महत्त्वाकांक्षी प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-डी6 (GSLV : Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) का सफल प्रक्षेपण 27 अगस्त, 2015 को श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SHAR) से किया गया।
- इस उड़ान के तहत इस प्रक्षेपण यान ने 2,117 किग्रा. वजन के संचार उपग्रह 'जीसैट-6' (GSAT-6) को सफलतापूर्वक 'भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा' (GTO : Geosynchronous Transfer Orbit) में स्थापित कर दिया।
- कुल मिलाकर यह जीएसएलवी की नौवीं तथा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ तीसरी उड़ान थी। जीएसएलवी का यह छठां सफल प्रक्षेपण था और इससे पहले के 5 सफल प्रक्षेपणों (जिनमें 2 आंशिक सफल ही थे) में से 4 में रूसी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था।
- इससे पूर्व 5 जनवरी, 2014 को जीएसएलवी-डी5 का सफल प्रक्षेपण (उपग्रह जीसैट-14 को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने हेतु) किया गया था जो कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ इस प्रक्षेपण यान का प्रथम सफल प्रक्षेपण था (स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ इसकी पहली उड़ान 2010 में विफल हुई थी) और इस प्रक्षेपण के साथ भारत स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन क्षमता वाला अमेरिका, रूस, फ्रांस (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी), जापान और चीन के बाद विश्व का ऐसा छठां देश बना था।
- उल्लेखनीय है कि जीएसएलवी 49.1 मीटर ऊंचा और 3.4 मीटर व्यास वाला त्रिचरणीय रॉकेट है जिसमें सबसे ऊपरी चरण में क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। जीएसएलवी का लिफ्ट-ऑफ वजन 416 टन रहता है।
- जीएसएलवी भारी संचार उपग्रहों को भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को इसरो के 'तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र' (LPSC : Liquid Propulsion Systems Centre) द्वारा

विकसित किया गया है। क्रायोजेनिक इंजन युक्त प्रक्षेपण यान की अब तक अनुपलब्धता के कारण भारत अपने संचार उपग्रहों को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन रॉकेट से भेजता रहा है।

- ज्ञातव्य है कि अत्यधिक कम तापमान पर कार्य करने वाली क्रायोजेनिक तकनीक में तरल हाइड्रोजन (जो -253^{0}C तापमान पर तरल होती है) और तरल ऑक्सीजन (जो -183^{0}C तापमान पर तरल होती है) का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है।
- जीएसएलवी-डी6 के माध्यम से स्थापित किए गए भारत के 25वें भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह जीसैट-6 का विवरण संलग्न बॉक्स में प्रस्तुत किया गया है।
- भारत के भावी चंद्रयान II मिशन (जिसमें भारत लूनर ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा पर लैंडर और रोवर उतारेगा) का प्रक्षेपण जीएसएलवी के माध्यम से ही किए जाने की संभावना है।

जीसैट-6 : महत्त्वपूर्ण तथ्य

- घनाभ (Cuboid) आकार के इस उपग्रह का लिफ्ट-ऑफ वजन (प्रक्षेपण के समय उत्थापन भार) 2117 किग्रा. था जिसमें उपग्रह का मूल द्रव्यमान (Dry Mass) 985 किग्रा. तथा प्रणोदकों (Propellants) का वजन 1132 किग्रा. शामिल है।
- यह इसरो द्वारा निर्मित जीसैट श्रृंखला का 12वां तथा कुल 25वां स्वदेशी भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह है। इससे पूर्व जीसैट श्रृंखला के 11वें उपग्रह (भारत के 24वें संचार उपग्रह) 'जीसैट-16' (3,181.6 किग्रा. वजनी) का प्रक्षेपण 7 दिसंबर, 2014 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन-5 वीए-221 द्वारा कौरू, फ्रेंच गुयाना से किया गया था।
- 'जीसैट-6' की उन्नत विशेषताओं में इसका 6.0 मी. व्यास का S-बैंड अलफर्लेबल (Unfurlable) एंटिना शामिल है जो कि इसरो द्वारा तैयार अब तक का सर्वाधिक वृहद उपग्रह एंटिना है। यह प्रेषण और ग्रहण करने दोनों ही कार्यों में सक्षम है। साथ ही इसमें प्रयुक्त '70 वी बस' (70 V Bus) पहली बार किसी भारतीय संचार उपग्रह के साथ भेजा गया है।
- 'जीसैट-6' के संचार नीतिभारों (Payloads) में प्रयोक्ता संपर्कों (User links) के लिए भारत की मुख्य भूमि को कवर करने वाले 5 स्पॉट बीम के साथ S-बैंड नीतिभार (उपर्युक्त वृहद एंटिना के माध्यम से) तथा हब (hub) संपर्कों के लिए 1 बीम के साथ C-बैंड नीतिभार (0.8 मी. व्यास के स्थिर एंटिना के माध्यम से) शामिल हैं।
- इसकी स्पॉट बीमें आवृत्ति पुनर्प्रयोग (Frequency Reuse) युक्ति का प्रयोग करेंगी जिससे आवृत्ति स्पेक्ट्रम उपयोग की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।
- 'जीसैट-6' को इसके प्रणोदकों के माध्यम से 4 क्रमिक चरणों में कक्षोन्नयन (Orbit Raising) के द्वारा 6 सितंबर, 2015 को अपनी अपेक्षित भूस्थिर कक्षा (GSO) में 83^0 पूर्वी देशांतर पर इनसैट 4A, जीसैट 12, जीसैट 10 और आईआरएनएसएस-1C के साथ सह-स्थिति में स्थापित कर दिया गया।
- इस उपग्रह की मिशन अवधि 9 वर्ष आकलित है।
- ज्ञातव्य है कि जीसैट-6 का मूल नाम 'इनसैट-4ई' था तथा यह एक मल्टीमीडिया संचार उपग्रह है।
- यह उपग्रह आधारित डिजिटल मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग (S-DMB) सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसका प्रयोग सामाजिक एवं रणनीतिक दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह 4-जी फोन सेवाओं के संदर्भ में विशेष उपयोगी हो सकता है।

भारत जच्चा-बच्चा टिटनेस से मुक्त

- 27 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तृतीय वैश्विक 'कॉल टू एक्शन' शिखर सम्मेलन (Global 'Call to Action' Summit), 2015 का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा भारत को जच्चा-बच्चा टिटनेस (Maternal and Neonatal Tetanus) से मुक्त घोषित कर दिया है तथा दिसंबर, 2015 के वैश्विक लक्ष्य से पहले भारत ने यह कर दिखाया है।
- 27-28 अगस्त के दौरान आयोजित इस सम्मेलन में 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय 'रोकथाम योग्य मातृत्व एवं बाल मृत्युओं को समाप्त करना' (Ending Preventable maternal and child deaths) था तथा इसका आयोजन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडशेन, टाटा ट्रस्ट, यूनिसेफ, यूएसएड और डब्ल्यूएचओ के साथ साझेदारी में किया गया था। इस सम्मेलन के अंत में जारी 'दिल्ली घोषणापत्र' में मातृत्व, नवजात एवं बाल मर्त्यता में सार्थक रूप से कमी लाने हेतु स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने की बात कही गई है।
- जच्चा-बच्चा टिटनेस का मुख्य कारण असुरक्षित और गैर-रोगाणुमुक्त उपकरणों की सहायता से प्रसव कराना है। इसके लक्षण जन्म से 4-14 दिन बाद प्रकट होते हैं जो कि 70 से 100 प्रतिशत मामलों में मृत्यु का कारण बनते हैं। इससे बचाव हेतु महिलाओं को गर्भावस्था से पूर्व या उसके दौरान टिटनेस वैक्सीन की क्रमिक अंतराल पर तीन डोज दी जाती हैं जो कि उनके भावी बच्चों को प्रसव-प्रश्चात हो सकने वाली टिटनेस से सुरक्षित करता है।
- उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को जच्चा-बच्चा टिटनेस से मुक्त करने की आधिकारिक घोषणा 15 मई, 2015 को ही की गई थी।

विश्व की प्रथम मलेरिया वैक्सीन

- 24 जुलाई, 2015 को यूरोप की औषधि नियामक संस्था 'यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी' (EMA) द्वारा विश्व के प्रथम मलेरिया प्रतिरोधी टीके को अफ्रीका में मलेरिया के जोखिम वाले बच्चों पर प्रयुक्त किए जाने हेतु लाइसेंस प्रदान करने की अनुशंसा की गई।
- अब इस टीके को यूरोपीय आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद औषधि लाइसेंस प्राप्त होगा।

- 'मॉस्क्विरिक्स जैब' (Mosquirix Jab) या 'आरटीएस, एस' (RTS, S) नामक यह टीका (Vaccine) विश्व का किसी परजीवी रोग के विरुद्ध पहला लाइसेंस प्राप्त मानव वैक्सीन होगा।
- इस टीके का विकास लगभग 28 वर्षों के शोध एवं अनुसंधान के बाद ब्रिटेन आधारित औषधि निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) द्वारा पाथ (PATH) मलेरिया वैक्सीन इनीशिएटिव के सहयोग से किया गया है। इस टीके के लिए शोध एवं परीक्षणों के वित्तीयन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी योगदान दे रहा है।
- इस टीके के पहले परीक्षण 1998 में अफ्रीका में प्रारंभ हुए थे।
- 'आरटीएस, एस' (मॉस्क्विरिक्स इसका व्यापारिक नाम है) एक पुनर्योजित (Recombinant) प्रोटीन-आधारित वैक्सीन है जो मलेरिया परजीवी संक्रमण के 4 प्रतिरूपों (Strains) में से सर्वाधिक घातक 'प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम' (Plasmodium Falciparum) को लक्ष्यित करते हुए तैयार की गई है।
- इस वैक्सीन के 2011 एवं 2012 में जारी परीक्षण आंकड़ों के अनुसार इसके प्रयोग से 5-17 माह के बच्चों में मलेरिया की दर में 46 प्रतिशत और 6-12 सप्ताह के शिशुओं में केवल 27 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई।
- हालांकि यह अन्य टीकों द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम 80 से 90 प्रतिशत की संरक्षण दर से काफी कम है तथापि मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों की वृहद संख्या को देखते हुए 'आरटीएस, एस' की साधारण संरक्षण दर भी जनस्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
- उल्लेखनीय है कि 2013 में मलेरिया की वजह से 5.84 लाख मृत्युएं हुईं जिसमें से 5.23 लाख मृत्युएं तो केवल अफ्रीका (मुख्यतः उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र) में दर्ज हुईं। मलेरिया से होने वाली मौतों में 83 प्रतिशत हिस्सा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का था।
- वस्तुतः इस मलेरिया वैक्सीन का उद्देश्य पोलियो या स्मालपॉक्स वैक्सीन की तरह रोग का पूर्णतः उन्मूलन नहीं बल्कि बच्चों में इसके मामलों में सार्थक कमी लाना है। इस वैक्सीन के परीक्षण जिन क्षेत्रों में किए गए उनमें से कुछ में तो बच्चे वर्ष में औसतन 4 बार मलेरिया संक्रमण के शिकार होते हैं। वस्तुतः यह टीका अन्य उपायों (यथा- मच्छरदानियों के प्रयोग एवं मलेरिया-रोधी औषधियों) के साथ मलेरिया का प्रसार रोकने में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
- 23 अक्टूबर, 2015 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के विशेषज्ञों की सलाहकार समिति द्वारा आरटीएस, एस वैक्सीन के अफ्रीका में सीमित 'पायलट' अनुप्रयोग (10 लाख बच्चों तक के समूह पर) को अनुशंसित किया गया है।
- हालांकि डब्ल्यूएचओ की सलाहकार समिति ने इस टीके के महत्त्व को स्वीकार किया तथापि उसने इसकी सीमित प्रभावशीलता के कारण व्यापक उपयोग से पूर्व पायलट आधार पर इसके प्रयोग प्रारंभ करने के लिए कहा है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार शिशुओं को 18 माह की आयु के दौरान मलेरिया के विरुद्ध इस टीके की चार क्रमिक डोज दिए बगैर यह अप्रभावी ही रहेगा और प्रत्येक बच्चे को इसके चार डोज मिलना सुनिश्चित किए बगैर इसके व्यापक प्रयोग को स्वीकृति नहीं दी जा सकती।
- डब्ल्यूएचओ की सलाहकार समिति की मलेरिया वैक्सीन संबंधी उपर्युक्त संस्तुतियों को डब्ल्यूएचओ महानिदेशक द्वारा नवंबर, 2015 में औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तीन राज्यों–राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र की सरकारों के साथ मिलकर शीघ्र ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम प्रजनन (Artificial Breeding) कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है।
- उल्लेखनीय है कि कभी भारत और पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह विशिष्ट पक्षी प्रजाति अब गहन संकटपूर्ण (Critically Endangered) स्थिति में है तथा ये अब केवल मात्र 3 पश्चिमी राज्यों–राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ही सीमित संख्या में पाई जाती है। एक आकलन के अनुसार तो इसकी देश में कुल संख्या अब मात्र 200 से 300 के बीच सिमटकर रह गई है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कृत्रिम प्रजनन की प्रक्रियाएं वर्ष 2016 में उपर्युक्त तीनों राज्यों में प्रारंभ होंगी। इसके तहत पहले इनका कैप्टिव (संरक्षित) स्टॉक स्थापित किया जाएगा जो कि अंडे देंगे, फिर उनसे निकलने वाले चूजों को वयस्क होने के बाद पुनः जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रयुक्त किया जाएगा और तत्पश्चात उन्हें कैप्टिव से सेमी-कैप्टिव स्थिति में छोड़ा जाएगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया में प्रारंभिक रूप से कुछ समय लगेगा।
- इस कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम हेतु मंत्रालय के स्वायत्त निकाय भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून द्वारा तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी। डब्ल्यूआईआई इस कार्यक्रम हेतु योजना, प्रजनन, संरक्षण तथा अंडे सेने (hatching) की प्रक्रिया और उन्हें पुनः खुले में छोड़ने की स्थिति के साथ इस विशिष्ट प्रजाति की पारिस्थितिकी, कार्यात्मक प्रणाली, शारीरिकी एवं व्यवहार संबंधी पक्षों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- संबंधित भागीदार राज्य सरकारें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए आवश्यक और अनुकूल वासस्थान यथा, शुष्क और अर्द्ध-शुष्क घास भूमियां तैयार करने में सहायता करेंगी। गुजरात के कच्छ जिले में इस कार्यक्रम हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है।
- इस कार्यक्रम पर प्रारंभिक स्तर पर 8-9 करोड़ रु. तक का व्यय आने का आकलन व्यक्त किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में बस्टर्ड पक्षी की तेजी से कम होती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसकी तीन प्रजातियों– ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और लेसेर फ्लोरिकन के लिए वर्ष 2012 में रिकवरी कार्यक्रम तैयार किया गया था। जून, 2013 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इस दुर्लभ पक्षी (GIB) के आवागमन और इसके पसंदीदा वासस्थान को समझने के लिए इनकी उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रारंभ की गई थी।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- इसका वैज्ञानिक नाम 'आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स' (Ardeotis Nigriceps) है।
- 1 मीटर ऊंचाई और लगभग 15 किग्रा. वजन वाला ऑस्ट्रिच जैसा यह विशिष्ट पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है।
- यह आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature) की रेड डाटा बुक के तहत गहन संकटग्रस्त (Critically Endangered) प्रजातियों में शामिल है।
- 1972 के भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत इसे अनुसूची I में रखा गया है तथा इसका वैश्विक व्यापार प्रतिबंधित है।
- हालांकि यह कठिन मौसमी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है तथापि शिकार और वासस्थानों के समाप्त होने के कारण इसकी संख्या में भारी कमी आई है।

डॉ. कलाम के नाम पर यूएन का वैश्विक उपग्रह

- संयुक्त राष्ट्र (UN) फ्रेमवर्क के तहत एक प्रस्तावित वैश्विक उपग्रह का नाम भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (जिनका निधन 27 जुलाई, 2015 को हुआ) के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है।
- भू पर्यवेक्षण और आपदा जोखिम शमन हेतु इस वैश्विक उपग्रह (Globalsat for DRR : Global Satellite for Earth Observation and Disaster Risk Reduction) का नाम अब 'यूएन कलाम ग्लोबलसैट' होगा।
- इस उपग्रह को प्रक्षेपित किए जाने का प्रस्ताव मार्च, 2015 में सेंडाई (जापान) में संपन्न 'आपदा जोखिम शमन पर तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन' में रखा गया था।
- सामाजिक अनुप्रयोगों हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कनाडा आधारित सीएएनईयूस संगठन (CANADA–Europe-US-Asia) द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (बाह्य अंतरिक्ष मामलों पर यूएन कार्यालय, आपदा शमन हेतु यूएन अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं विश्व बैंक) के सहयोग से प्रस्तावित यह उपग्रह विभिन्न देशों की आपदा प्रबंधन एवं वैकासिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करेगा।
- इस उपग्रह प्रणाली का प्रस्ताव वैश्विक स्तर पर अंतर्संबंधित आपदा एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता के मद्देनजर किया गया है क्योंकि कोई भी देश अकेले बाढ़, सूखा, टायफून, भूकंप, दावानल, तूफान आदि के पूर्वानुमान, निरीक्षण और आपदा जोखिम कम करने हेतु आवश्यक सेंसरों एवं उपग्रह प्रणालियों का पूर्ण नेटवर्क विकसित करना वहन नहीं कर सकता है।
- इस उपग्रह प्रणाली का लक्ष्य डॉ. कलाम द्वारा अपने 'वर्ल्ड स्पेस विजन-2050' में प्रस्तुत विचार के समरूप है जिसमें उन्होंने मानवजाति की प्रमुख समस्याओं यथा–प्राकृतिक आपदाओं, ऊर्जा एवं जल की अभावग्रस्तता, मौसम पूर्वानुमान, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा जैसे मुद्दों के समाधान हेतु अंतरिक्ष-सक्षम राष्ट्रों से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया था।
- उल्लेखनीय है कि सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के दौरान ग्लोबलसैट के प्रक्षेपण सहित सेंडाई सम्मेलन की आपदा जोखिम शमन संबंधी सभी अनुशंसाओं को विश्व के 150 से अधिक देशों के नेतागणों द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

पश्चिमी घाट के चमगादड़ों का अस्तित्व खतरे में

- दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता क्षेत्र माने जाने वाले भारत के पश्चिमी घाट से चमगादड़ों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। यह बात उस संयुक्त सर्वेक्षण के बाद सामने आई जो कि 'लीड्स विश्वविद्यालय' के 'ब्रिटेन प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन' (Britain Nature Conservation Foundation) एवं 'राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केन्द्र' (National Center for Biological Sciences) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।
- सर्वेक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष दिया कि पश्चिमी घाट में मानव के बढ़ते हस्तक्षेप, कृषि के लिए की जा रही वनों की कटाई एवं आत्म-केन्द्रित विकास (Self-Centered Development) जैसी वजहों से वहां पाए जाने वाले चमगादड़ों (Bats) की प्रायः सभी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- ध्यातव्य है कि वनस्पतियों एवं जीवों पर मनुष्य के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में बताने वाले चमगादड़ सबसे प्रसिद्ध जैव-संकेतकों (Bio-Indicators) में से एक होते हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि वन्यजीव प्रबंधन टीम द्वारा उचित प्रबंधन कर यहां के चमगादड़ों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है।

गुजरात के जंगली गधे विलोपन के कगार पर

- प्रकृति के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची (The Red List of International Union for Conservation of Nature–IUCN) द्वारा कुछ समय पहले जारी की गई लुप्तप्राय जानवरों की सूची में गुजरात के कच्छ के छोटे रण में पाए जाने वाले जंगली गधों को भी शामिल किया गया है। इन जंगली गधों को 'गुडखर' (Gudkhar) भी कहा जाता है।
- लाल सूची में गुजरात के जंगली गधों (गुडखर) को सम्मिलित किए जाने से यह स्पष्ट है कि यदि समय रहते इनके संरक्षण के उपाय न किए गए तो ये विलुप्त हो जाएंगे।
- जंगली गधों के विलोपन का खतरा गुजरात के कच्छ के छोटे रण में बढ़ते मानव हस्तक्षेप एवं चरने वाले मवेशियों (Grazing Livestock) की बढ़ती संख्या के कारण पैदा हुआ है।

नैनो क्रिस्टल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत तृतीय

- संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैण्ड के बाद नैनो क्रिस्टल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत को विश्व का तीसरा देश बनने में कामयाबी मिली है।
- इस कामयाबी का श्रेय मोहाली (चंडीगढ़) स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च' (एनआईपीईआर) को जाता है, जिसने नैनो क्रिस्टल आधारित दवाइयों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री के निर्माण में दक्षता हासिल कर ली है। इस तकनीक को हासिल करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। एनआईपीईआर द्वारा 'नैनो क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्पर्सन' यानी 'नैनो क्राइस्सपी' (Nano Crystalline

Solid Dispersions called Nano Cry SP) का विकास किया गया है।

- ध्यातव्य है कि 'नैनो क्रिस्टल' दवा का एक ऐसा नैनोमीटर आकार का पार्टिकल होता है, जो परम्परागत दवाओं की तुलना में ज्यादा गति और कुशलता से काम करता है। 136 अरब डॉलर के नैनोटेक्नॉलॉजी समर्पित दवा के विश्व बाजार में इसका हिस्सा 60% है।

विटामिन बी-9 युक्त टमाटर

- गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाने वाले विटामिन बी-9 से युक्त टमाटर के उत्पादन में हैदराबाद विश्वविद्यालय ने सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय के 'रिपोजिटरी ऑफ टोमैटो जिनोमिक्स रिसोर्स' ने टमाटर की इस नई किस्म को पेटेंट कराने की पहल भी शुरू की है।
- ध्यातव्य है कि भारत में सब्जी के रूप में आलू के बाद सर्वाधिक उपभोग टमाटर का ही किया जाता है।

एचपीसीएल का बायो डीजल ब्लेंडेड डीजल

- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने भारत में कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन तथा हरित ईंधन की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए 10 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली, विशाखापत्तनम एवं हैदराबाद में बायो डीजल ब्लेंडेड डीजल (B5 HSD) की शुरुआत की।
- बायो डीजल ब्लेंडेड डीजल को पर्यावरण हितैषी ईंधन माना जाता है। इसमें जहां 10% निर्मित ऑक्सीजन होती है, वहीं सल्फर या एरोमेटिक्स की मात्रा नगण्य होती है।

पहली बार मिली 3D प्रिंटेड दवा को मंजूरी

- '<u>स्प्राइतम लेवेतिरासेतम</u>' (Spritam Levetiracetam) वह पहली 3D प्रिंटेड दवा है, जिसके सार्वजनिक प्रयोग की मंजूरी पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएलएफडीए) द्वारा प्रदान की गई है। ध्यातव्य है कि इस दवा के उत्पादन के लिए 3D (त्रिआयामी) प्रिंटेड तकनीक का प्रयोग किया गया है।
- '<u>स्प्राइतम लेवेतिरासेतम</u>' दवा का प्रयोग मिर्गी से ग्रस्त मरीजों के उपचार में किया जाता है। यह दवा वर्ष 2016 तक बाजार में उपलब्ध होगी। 'अप्रेसिया फार्मास्यूटिकल्स' दवा कंपनी ने इसका निर्माण किया है।

विश्व में पेड़ों की संख्या है तीन खरब

- समूचे विश्व में पेड़ों की कुल संख्या 3 ट्रिलियन (खरब) है। पेड़ों की संख्या से संबंधित यह आंकड़ा अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के थॉमस क्रोथेर द्वारा 2 सितंबर, 2015 को जारी किया गया।
- पेड़ों की संख्या पर यह सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ के 'बिलियन ट्री कैंपेन' के तहत 'प्लांट फॉर द प्लैनेट' के लिए येल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया।
- सर्वेक्षण में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार इन तीन खरब पेड़ों में से 1.39 ट्रिलियन उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध में, 0.61 ट्रिलियन शीतोष्ण कटिबंध में एवं 0.73 ट्रिलियन आर्कटिक के नीचे उदीच्य क्षेत्र में हैं। पेड़ों की गणना में उपग्रहीय प्रणाली का प्रयोग किया गया।

अंतरिक्ष में उत्पादित खाद्य पदार्थ

- स्कॉट केली, जेल लिंडग्रेन एवं किमिया यूई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वे पहले तीन अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में उत्पादित भोजन का रसास्वादन किया। यह संभव हुआ उस 'वेजी पादप उत्पादन प्रणाली' (Veggie Plant Growth System) द्वारा, जिसके विकास का श्रेय अमेरिकन कंपनी 'ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी कॉर्प' को जाता है।
- 'वेजी पादप उत्पादन प्रणाली' के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 'आउटरेडजियस लाल रोमैन सलाद' (Outredgeous Red Romaine Lettuce) न सिर्फ अंतरिक्ष में उगाया गया, बल्कि इसका सेवन भी उनके द्वारा 10 अगस्त, 2015 को किया गया।
- इसके लिए अप्रैल, 2014 में 'वेजी-01' (Veggie–01) को रोमैन बीज और जिन्नियास युक्त दो पादप गद्दों के साथ स्पेस एक्स-2 ड्रैगन कार्गो से रवाना किया गया, जिसे अंतरिक्ष यात्री केली द्वारा अंतरिक्ष पर 8 जुलाई, 2015 को सक्रिय किया गया तथा इसकी कटाई का काम 33 दिन बाद किया गया। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 8 जुलाई, 2015 को इसका सेवन किया गया तथा इसका कुछ हिस्सा शोध के लिए पृथ्वी पर भी भेजा गया।
- नासा का यह प्रयास अंतरिक्ष अभियानों की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

विलोपन के कगार पर भारत का बैंगनी मेंढक

- एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 'सलामोंद्र' (Salamondra) में प्रकाशित एक शोध के अनुसार भारतीय बैंगनी मेंढक (The Indian Purple Frog) विलोपन के कगार पर पहुंच चुका है।
- लुप्तप्राय इस स्थानिक उभयचर का जीव वैज्ञानिक नाम– 'Nasikabatrachus Sahyadrensis' है, जो कि भारत के दक्षिण-पश्चिमी घाट (Southern-Western Ghat) में पाया जाता है।
- स्थानीय जनजातियों द्वारा बहुतायत में भोजन के रूप में प्राचीन प्रजाति (डायनासोर का समकालीन) के इस बैंगनी मेंढक का सेवन किए जाने के कारण यह विलोपन के कगार पर पहुंचा है तथा यदि इसके संरक्षण के समुचित उपाय यथाशीघ्र न किए गए, तो आने वाले 10 वर्षों में यह विलुप्त हो जाएगा।

गूगल लून प्रोजेक्ट पर श्रीलंका का गूगल से समझौता

- अमेरिकी सर्च इंजन गूगल की समतापमंडलीय वाई-फाई आधारित इंटरनेट प्रौद्योगिकी परियोजना–<u>गूगल लून प्रोजेक्ट</u> पर गूगल और श्रीलंका सरकार के मध्य 29 जुलाई, 2015 को एक महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके तहत श्रीलंका के सभी हिस्सों में बाधा रहित इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अत्यधिक ऊंचाई पर गुब्बारे लगाए जाएंगे।
- ध्यातव्य है कि श्रीलंका विश्व का वह पहला देश है, जिसने गूगल के साथ 'गूगल लून प्रोजेक्ट' पर समझौता कर 'सार्वभौमिक इंटरनेट कवरेज' वाला पहला देश बनने की तरफ कदम बढ़ाया है।

- 'गूगल लून प्रोजेक्ट', गूगल कंपनी की गोपनीय गूगल एक्स प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई 'मून शॉट' परियोजना का एक हिस्सा है। इसमें पृथ्वी के ऊपर वायुमण्डल में गुब्बारों की शृंखला कुछ इस तरह से लगाई जाती है कि वे सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए नेटवर्क हेतु आपस में जुड़े रहते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट शुरू करेगा व्हाइट-फाई टेक्नोलॉजी

- माइक्रोसॉफ्ट द्वारा केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना 'डिजिटल इंडिया' को सफल एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से 'व्हाइट-फाई प्रौद्योगिकी' (White–Fi Technology) प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। इस तकनीक का एक दूसरा नाम— 'टीवी व्हाइट स्पेस टेक्नोलॉजी' (T.V. White Space Technology) भी है।
- व्हाइट-फाई तकनीक की विशेषता यह है कि इसमें इंटरनेट सेवा के लिए टेलीविजन संकेतों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होने वाली फ्रीक्वेंसी में अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है।
- माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उन एक अरब लोगों को यह तकनीक उपलब्ध करवाई जाएगी, जिनकी पहुंच इंटरनेट सेवा तक नहीं है। यह तकनीक सौर ऊर्जा से भी संचालित की जा सकती है।

पांच विलुप्तप्राय जीवों के संरक्षण हेतु 20 करोड़ आवंटित

- डुयूगांग (Dugong), गंगा डॉल्फिन (Gangetic Dolphin), ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustards), मणिपुर ब्रो एंटलर डीयर 'संगाई' (Manipur Brow Antler Deer–Sangai) तथा वन्य जल भैंसा (Wild Water Buffalo) भारत की लुप्तप्राय प्रजातियों वाले जीव-जन्तुओं की वे प्रमुख प्रजातियां हैं, जिन्हें संरक्षित करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है।
- इन जीव-जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। राशि आवंटन का यह निर्णय 'क्षतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण' (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority–CAMPA) की छठवीं बैठक में लिया गया।
- ध्यातव्य है कि सरकार इस प्राधिकरण (कैम्पा) के माध्यम से लुप्तप्राय जीव-जन्तुओं के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। संरक्षण के ये प्रयास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

ब्रेकथ्रू लिसेन प्रोजेक्ट

- पारलौकिक कुशाग्र जीवन पर अनुसंधान के लिए ब्रिटिश ब्रहमांडविज्ञानी स्टीफन हॉकिंस द्वारा एक 10 वर्षीय परियोजना की शुरुआत 20 जुलाई, 2015 को लंदन की 'रायल सोसायटी साइंस एकेडमी' में की गई, जिसे 'ब्रेकथ्रू लिसेन प्रोजेक्ट' (Breakthrough Listen Project : BLP) नाम दिया गया है।
- इस प्रकार की यह अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 100 मिलियन डॉलर है। इस परियोजना में रूसी अरबपति यूरी मिलनर, हॉकिंस को सहयोग दे रहे हैं।
- पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं की तलाश की दृष्टि से इस परियोजना को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
- इस परियोजना के तहत रूसी टेलीस्कोप 'मिलीमित्रोन' सहित अन्य अनेक रेडियो टेलीस्कोपों को स्थापित किया जाएगा, जो कि ब्रह्माण्ड में स्थित लाखों सितारों से आने वाले संकेतों को पकड़ेंगे। आस्ट्रेलिया और अमेरिका में पहले से ही ऐसे रेडियो टेलीस्कोप स्थापित हैं।

विश्व तम्बाकू महामारी रिपोर्ट–2015

- 7 जुलाई, 2015 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 'वैश्विक तम्बाकू महामारी रिपोर्ट, 2015' जारी की गई, जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि वर्ष 2013 में प्रकाशित की गई 'ग्लोबल टोबैको एपिडैमिक रिपोर्ट' के बाद से विश्व में तम्बाकू नियंत्रण में उल्लेखनीय कमी आई है।
- इस रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'एमपावर' (MPOWER) नामक तम्बाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क के आर (R) यानी 'तम्बाकू पर कर में वृद्धि' (Raise taxes on tobacco) पर विशेष बल दिया गया है।
- ध्यातव्य है कि 'एमपावर' (MPOWER) नामक इस फ्रेमवर्क में 'M' से अभिप्राय है—Monitor (तम्बाकू उपयोग की निगरानी एवं निवारण नीतियां), 'P' से—Project (तम्बाकू सेवन से लोगों की सुरक्षा), 'O' से—Offer (तम्बाकू का इस्तेमाल बंद करने के लिए मदद की पहल), 'W' से—Warn (तम्बाकू के खतरों के लिए चेतावनी), 'E' से—Enforce (तम्बाकू संवर्धन, प्रयोजन एवं विज्ञापनों पर प्रतिबंध) एवं 'R' से—Raise (तम्बाकू पर कर में वृद्धि)।

ई-बस्ता

- 'डिजिटल इंडिया' के तहत शुरू किए गए एक व्यापक प्लेटफॉर्म को 'ई-बस्ता' नाम दिया गया है, जो कि स्कूली किताबों एवं अध्ययन सामग्री को डिजिटल एवं 'ई-किताब' के रूप में उपलब्ध कराता है।
- ई-बस्ते का स्वरूप उस सहयोगात्मक मंच जैसा है, जो छात्रों, किताब प्रकाशकों एवं स्कूली शिक्षकों को एक मंच पर लाता है। यही इसका उद्देश्य भी है।
- लाने-ले जाने एवं इसकी पहुंच आसान होने के कारण जहां छात्रों के लिए इसका प्रयोग आसान है, वहीं वे इसे आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल सामग्री को आसानी से संरक्षित भी किया जा सकता है। ई-बस्ते को कहीं भी, कभी भी पढ़ा जा सकता है।
- ई-बस्ते का एक बड़ा लाभ प्रकाशकों के लिए यह है कि इसके माध्यम से वे अपने प्रकाशनों को प्रिंटिंग, वितरण एवं परिवहन की चिंता किए बगैर न सिर्फ हजारों स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि डिजिटल प्रारूप में इसका विक्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपनी सामग्री पर छात्रों एवं शिक्षकों से सीधे प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।

वैश्विक वन संसाधन आकलन-2015 रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई 'वैश्विक वन संसाधन आकलन-2015 रिपोर्ट' (Global Forest Resources Asses-sment-2015 Report) में समूचे विश्व में घट रहे वन क्षेत्रों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2015 तक समूचे विश्व में जंगलों का दायरा तीन प्रतिशत तक सिमट चुका है।
- यह रिपोर्ट बताती है कि विगत 25 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में सबसे तीव्र गति से कमी आई है।
- रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि विकास के नाम पर वनों की कटाई एवं जलवायु परिवर्तन के कारण वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। भूमंडलीय आर्थिक उदारवाद के बाद से जंगलों की कटाई में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है।

- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक 17 से 35 प्रतिशत सघन वन समाप्त हो जाएंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पेड़ों और जीव-जन्तुओं की प्रजातियों पर पड़ेगा। इससे जैव-विविधता संकट में पड़ जाएगी।
- रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सालाना 170 लाख हेक्टेयर की गति से वन लुप्त हो रहे हैं तथा विगत 25 वर्षों में दुनिया का जितना वन क्षेत्र नष्ट हुआ है, वह दक्षिण अफ्रीका के बराबर है।

द्वितीय साइलेंट स्प्रिंग : महासागरों में प्लास्टिक संकट

- हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी में रच-बस चुका प्लास्टिक महासागरीय पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में महासागरों में प्लास्टिक का भारी जमाव हुआ है।
- महासागरों में बढ़ रहे इस प्लास्टिक प्रदूषण को कनाडा के डलहौजी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानी बोरिस वार्म ने द्वितीय साइलेंट स्प्रिंग (Second Silent Spring) की संज्ञा दी है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1962 में रासेल कार्सन ने अपनी पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिंग' में आसन्न पर्यावरणीय खतरों के प्रति चेतावनी दी थी।
- वार्म के अनुसार महासागरों में बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण का अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव महासागरीय जीवन पर पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 80 लाख टन प्लास्टिक महासागरों में समा जाता है।

ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाएं

- ओवर-द-टॉप सेवाओं से अभिप्राय इंटरनेट पर उपलब्ध उन एप्लिकेशनों से है, जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क, मुफ्त गेमिंग डाउनलोड वेबसाइट, संगीत डाउनलोड वेबसाइट एवं अमेच्यर वीडियो एग्रीगेशन जैसी सुविधाएं सहजता से उपलब्ध कराती हैं। इनका स्वरूप पारंपरिक सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के विकल्प जैसा होता है, यानी ओटीअी सेवाओं के प्रदाता, टीएसपी के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर ग्राहकों तक पहुंचते हैं।
- ओवर-द-टॉप सेवाओं का उपभोग इंटरनेट से संबद्ध विभिन्न उपकरणों यथा–टैबलेट, फैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, ई-बुक्स एवं स्मार्ट फोन पर कहीं भी, किसी भी समय आप यथासुविधा कर सकते हैं।
- हाल के वर्षों में ओटीटी सेवाओं में निरंतर होती वृद्धि को देखते हुए इसके नियमन की मांग ने भी जोर पकड़ा है। इस परिप्रेक्ष्य में 'ट्राई' द्वारा इन सेवाओं के लिए नियामकीय व्यवस्था पर परामर्श पत्र जारी किया जा चुका है।

पीएसएलवी-सी28 की सफल उड़ान

- 10 जुलाई, 2015 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV : Polar Satellite Launch Vehicle) की 30वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
- इस उड़ान के तहत पीएसएलवी-सी28 (PSLV-C28) को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित भारत के स्पेसपोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) से रात 9:58 पर प्रक्षेपित किया गया।
- पीएसएलवी-सी28 की यह उड़ान पूर्णतः व्यावसायिक उड़ान थी जिसके माध्यम से इसरो (ISRO) द्वारा कुल 5 ब्रिटिश उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर उनकी अभीष्ट कक्षाओं में (17-19 मिनट की अवधि में) स्थापित किया गया। इन उपग्रहों का विवरण इस प्रकार है—
  - (a) **तीन डीएमसी3 उपग्रह** : ब्रिटेन के सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (SSTL) द्वारा विकसित।
  - (b) **सीबीएनटी-1 उपग्रह** : इस उपग्रह (CBNT-1) का निर्माण भी एसएसटीएल द्वारा किया गया है।
  - (c) **डी-ऑर्बिटसेल उपग्रह** : ब्रिटेन के सरे स्पेस सेंटर द्वारा निर्मित।
- इन पांचों विदेशी उपग्रहों का संयुक्त उत्थापन भार (Lift-off Mass) लगभग 1,440 किग्रा. था और इस प्रकार यह इसरो/एंट्रिक्स का अब तक का सर्वाधिक वजनी वाणिज्यिक प्रक्षेपण मिशन था।

'न्यू होराइजंस' : प्लूटो पहुंचा अंतरिक्ष अन्वेषण यान

- 'न्यू होराइजंस' (New Horizons) अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA : National Aeronautics and Space Administration) द्वारा सौर प्रणाली की बाह्य सीमाओं पर अवस्थित ड्वार्फ ग्रह 'प्लूटो' एवं इसके चंद्रमाओं तथा क्षुद्रग्रह-बहुल क्षेत्र 'क्यूपर बेल्ट' (Kuiper Belt) के अध्ययन हेतु भेजा गया अंतरिक्ष अन्वेषण यान (Space Probe) है जो जुलाई, 2015 में अपनी यात्रा पूरी कर प्लूटो के निकट पहुंचा। 15 जनवरी, 2015 को नासा द्वारा 'न्यू होराइजंस' के प्लूटो के लिए एप्रोच फेज में पहुंचना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी।
- न्यू होराइजंस का प्रक्षेपण नासा के 'न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम' (New Frontiers Program) के तहत 19 जनवरी, 2006 को केप केनवेरल स्पेस लांच सेंटर से एटलस V 551 रॉकेट द्वारा किया गया था।
- वर्ष 2015 के दौरान न्यू होराइजंस प्लूटो और इसके 5 चंद्रमाओं (चेरॉन (Charon), हाइड्रा, निक्स, कर्बेरोस एवं स्टाइक्स) का अन्वेषण करके आंकड़े और चित्र पृथ्वी पर संप्रेषित कर रहा है।
- 14 जुलाई, 2015 को न्यू होराइजंस प्लूटो के सर्वाधिक निकट स्थिति (Flyby) से गुजरा।
- प्लूटो के निकट से गुजरते हुए इसकी गति लगभग 14 किमी. प्रति सेकेंड थी। न्यू होराइजंस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्लूटो का व्यास 2,370 किमी. है जबकि पहले इसका व्यास 2300 किमी. माना जाता था।
- न्यू होराइजंस इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटरों, एक कॉम्पैक्ट मल्टीकलर कैमरा, एक हाई रिजॉल्यूशन टेलिस्कोपिक कैमरा (LORRI-Long Range Reconnaissance Imager), दो शक्तिशाली पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटरों तथा एक स्पेस डस्ट डिटेक्टर से युक्त है।
- वर्तमान में न्यू होराइजंस 'सैगिटैरियस' (Sagittarius) नक्षत्र की दिशा में गतिमान है तथा यदि यह वर्तमान गति से संचालित और क्रियाशील रहता है तो यह वर्ष 2038 तक सूर्य से 100 AU की दूरी पर होगा तथा तब यह बाह्य हीलियोस्फीयर के आंकड़े संभावित रूप से भेज सकेगा।

शनि के चंद्रमा पर ध्रुवीय हवाएं

- प्रतिष्ठित जर्नल जियोफिजिक्स रिसर्च लेटर्स (Geophysics Research Letters) में 18 जून, 2015 को प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार शनि के एक चंद्रमा 'टाइटन' पर पृथ्वी की तरह ध्रुवीय हवाओं (Polar Winds) की उपस्थिति पाई गई है जो उसके वायुमंडल से गैसों को अंतरिक्ष में जाने के लिए बाध्य करती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन के डॉ. एंड्रयू कोट्स (Dr. Andrew Coates) के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने यह महत्त्वपूर्ण खोज की है।
- अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि टाइटन के वातावरण तथा सौर चुंबकीय क्षेत्र एवं विकिरणों के मध्य पारस्परिक अंतर्क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोकार्बन एवं नाइट्रिल अणुओं की तीव्र पवनें सृजित होती हैं जो इसके ध्रुवीय क्षेत्रों से अंतरिक्ष में विक्षेपित हो जाती हैं। यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली पवनों के समान है।
- अनुसंधानकर्ताओं ने नासा के कैसिनी (Cassini) अंतरिक्ष यान (15 अक्टूबर, 1997 को प्रक्षेपित और 1 जुलाई, 2004 को शनि की कक्षा में पहुंचा) द्वारा 7 वर्षों से एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ये निष्कर्ष प्राप्त किए हैं।
- वैज्ञानिक अब तक यह पता लगा चुके हैं कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन ही पृथ्वी के इतर सौर प्रणाली में एक ऐसा पिंड है जहां नदियां, झरने और समुद्र होने चाहिए। अब ध्रुवीय पवनों की टाइटन पर उपस्थिति इसे पृथ्वी के और समान बनाती है।
- हालांकि टाइटन को जीवन की संभावना की दृष्टि से अत्यधिक ठंडा माना जाता है तथा वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल, यूरोपा (बृहस्पति का चंद्रमा) एवं इंसेलेडस (शनि का एक अन्य चंद्रमा) पूर्व या वर्तमान जीवन के संदर्भ में अधिक संभव लक्ष्य हो सकते हैं।

मानव भ्रूणों की जीन एडिटिंग

- हाल ही में प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन 'नेचर' (Nature) में प्रकाशित एक लेख में वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा मानव भ्रूण कोशिकाओं की जीन एडिटिंग पर नैतिक एवं सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं प्रकट की गई हैं।
- उनका कहना है कि मानव भ्रूण कोशिकाओं में जीनोम एडिटिंग तकनीक से बेहतर बुद्धिलब्धि या विशिष्ट शारीरिक गुणों (यथा-नीली आंखें) वाले डिजाइनर बेबी के सृजन की चिंताजनक संकल्पना की संभाव्यता बनती है जो कि सही कदम नहीं होगा।
- अमेरिका के जीवविज्ञान संस्थानों के वाशिंगटन डीसी स्थित संगठन 'एलाएंस फॉर रीजेनेरेटिव मेडिसिन' के इन वैज्ञानिकों ने विश्व भर के वैज्ञानिक समुदाय से इस प्रकार के अनुसंधानों को हतोत्साहित करने हेतु स्वैच्छिक प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। इनका कहना है कि मानव बीज रेखा (Grem Line) को संपादित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके भावी पीढ़ियों पर अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं।
- वस्तुतः जीनोम एडिटिंग तकनीक रोगयुक्त-जीनों को ठीक करने के संदर्भ में आशाजनक साधन हो सकती है तथा इसके द्वारा घातक उत्परिवर्तनों को जीनों से पृथक कर मानव रोगों यथा—एचआईवी/एड्स, हीमोफीलिया, सिकल-सेल एनीमिया एवं विभिन्न कैंसर रूपों आदि के इलाज उपलब्ध हो सकने की संभाव्यता बनती है।
- परंतु जब यह तकनीक मानव भ्रूण कोशिकाओं अर्थात शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं (जर्म लाइन) को लक्ष्यित कर उन्हें संपादित और परिवर्तित करेगी, तो ऐसे परिवर्तन आनुवांशिक होकर वंशानुक्रम में स्थानांतरित होंगे जो कि नैतिक, विधिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं खड़ी करेगा। साथ ही ऐसे अनुसंधानों का गैर-चिकित्सकीय रूपांतरणों हेतु भी दुरुपयोग हो सकता है।

अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन

- मई, 2015 में 'साइंस' मैगजीन में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया है कि वैश्विक तापन के कारण अंटार्कटिका में ग्लेशियरों की बर्फ की निचली परत के पिघलने के फलस्वरूप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (Gravitational Field) में परिवर्तन हो रहा है।
- ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता वैज्ञानिकों के समूह के नेतृत्वकर्ता बर्ट वाउटर्स (Bert Wouters) के अनुसार वैश्विक ताप वृद्धि के कारण अब तक लगभग स्थिर रहे अंटार्कटिक क्षेत्रों में भी हाल के वर्षों में बर्फ पिघलने की गति अचानक तीव्र हुई है।
- वैज्ञानिकों ने ये परिवर्तन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह 'क्रायोसैट-2' द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात किए।
- वस्तुतः इस क्षेत्र में बर्फ कम होने की दर इतनी अधिक है कि इससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भी लघु परिवर्तन हो रहे हैं जो कि एक अन्य उपग्रह मिशन 'ग्रेस' (GRACE : Gravity Recovery and Climate Experiment- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर का संयुक्त मिशन) से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ है।

चीन द्वारा निर्मित प्रथम विद्युत चालित विमान

- जून, 2015 में चीन द्वारा विश्व के प्रथम विद्युत चालित यात्री विमान को सफल उड़ान संबंधी प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। विद्युत चालित विमान बीएक्स 1 ई (BX 1E) के पंखों की लंबाई 14.5 मीटर है तथा यह 230 किग्रा. तक वजन उठाने में सक्षम है।
- 160 किमी. प्रति घंटा की अधिकतम गति वाला यह विमान 3,000 किमी. की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह विमान 2 घंटे के भीतर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और एक बार रिचार्ज हो जाने के बाद 45 मिनट से एक घंटे तक उड़ान भर सकता है।
- इस इलेक्ट्रिक विमान का निर्माण चीन की शेनयांग एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी और लियाओनिंग जनरल एविएशन एकेडमी द्वारा मिलकर किया गया है तथा इसकी कीमत 1.63 लाख डॉलर (लगभग 1.03 करोड़ रु.) है।

नासा के 'मेसेंजर' अंतरिक्ष मिशन का समापन

- 30 अप्रैल, 2015 को नासा का बुध (Mercury) ग्रह के पर्यवेक्षण हेतु प्रक्षेपित 'मेसेंजर' (Messenger) अंतरिक्ष यान

प्रणोदक ईंधन (Propellant) के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बुध ग्रह की सतह से टकरा गया।

- उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2004 में प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान मेसेंजर मार्च, 2011 में बुध ग्रह की कक्षा में पहुंचा था तथा इसने वहां की 100 प्रतिशत सतह के चित्र भेजे हैं जिसके माध्यम से नासा द्वारा यहां का विस्तृत त्रिआयामी मानचित्र जारी किया जा चुका है।
- उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2012 में नासा द्वारा मेसेंजर से प्राप्त तस्वीरों एवं आंकड़ों के आधार पर बुध ग्रह के उत्तरी ध्रुव के क्रेटरों में जल बर्फ (Water Ice) और कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति की पुष्टि की गई थी।
- गत वर्ष मेसेंजर से प्राप्त आंकड़ों एवं चित्रों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह आकलन व्यक्त किया था कि 4 बिलियन वर्ष पूर्व की तुलना में यह ग्रह ठंडा होने के साथ भीतरी भाग से लगभग 7 किमी. सिकुड़ गया है तथा इसकी सतह पर दरारें पड़ गई हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक बड़ी हैं।

तुलसी की पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग

- 28 मई, 2015 को बीएमसी जीनोमिक्स में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के लखनऊ स्थित 'केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पादप संस्थान' (CIMAP : Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants) ने 'तुलसी' (Holy basil) या 'ओसिमम सैंक्टम' के पौधे का पूर्ण जीनोम अनुक्रम (Genome Sequence) तैयार करने में सफलता प्राप्त की है।
- 'विष्णुप्रिया' नाम से भी अभिहित और हिंदू संस्कृति में पवित्र एवं पूजित माने जाने वाले इस पौधे को प्राकृतिक औषधियों की जननी माना जाता है। इसे हर रूप में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध इत्यादि औषधीय परंपराओं में उपयोग किया जाता रहा है।
- इस चमत्कारिक पौधे के जीन अनुक्रमण को तैयार करके अब वैज्ञानिक इसके अपार चिकित्सकीय गुणों के रहस्यों को उजागर करने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि तुलसी का न्यूक्लियर जीनोम लैमिएसी (Lamiaceae) फैमिली में सबसे छोटा (386 Mb) है जबकि इसका क्लोरोप्लास्ट जीनोम (142,245 bp) लैमिएल्स (Lamiales) ऑर्डर में सबसे छोटा है।

दक्षिण कोरिया में मर्स (MERS) का प्रकोप

- **'मर्स'** या **'मध्य-पूर्व श्वसन सिंड्रोम'** (MERS : Middle East Resipiratory Syndrome) एक घातक न्यूमोनिया-प्रकार का श्वसन संबंधी विषाणु-जनित रोग है जिसकी पहचान सर्वप्रथम अप्रैल, 2012 में सऊदी अरब के एक मरीज में हुई थी।
- इस रोग का कारक नया चिन्हित किया गया 'मर्स-कोरोना विषाणु' (MERS-COV : MERS-coronavirus) है। यह एकल-तंतु (Single-Stranded) आरएनए युक्त विषाणु की नवीन खोजी गई प्रजाति है जो सार्स (SARS) कोरोनाविषाणु और अन्य सामान्य फ्लू वाले कोरोना विषाणु से पृथक है।
- 'मर्स' को 'कैमल फ्लू' (Camle Flu) भी कहा जाता है क्योंकि मध्य-पूर्व में ऊंटों में इसके विषाणु के विरुद्ध रोग-प्रतिरक्षी (Antibodies) पाए गए हैं तथापि ऊंटों में इस विषाणु के संक्रमण का सटीक स्त्रोत अभी पता नहीं चल सका है।
- अप्रैल, 2012 में सऊदी अरब में इस रोग का पहला मामला सामने आने के बाद से 'मर्स' के 1200 से अधिक मामले विश्व के कम से कम 24 देशों (जिनमें मुख्यतः मध्य-पूर्व के ही देश हैं) में दर्ज किए जा चुके हैं तथा इसके कारण 500 से अधिक लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। इस रोग के संक्रमण के सर्वाधिक 688 मामले सऊदी अरब में सामने आए हैं जिनमें से 282 की मृत्यु हो चुकी है।
- 20 मई, 2015 को 'मर्स' का पहला मामला दक्षिण कोरिया में सामने आया जब 68 साल के एक व्यक्ति को सऊदी अरब की यात्रा के बाद इस रोग से संक्रमित पाया गया।
- 15 जुलाई, 2015 तक दक्षिण कोरिया में 'मर्स' के 186 मामले सामने आए जिनमें से 36 लोगों की इस घातक बीमारी से मृत्यु हो गई।
- उल्लेखनीय है कि 'मर्स' रोग के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्ति को तीव्र बुखार, खांसी, डायरिया और सांस लेने में गहन तकलीफ होती है। यह संक्रमित व्यक्ति से निकट संपर्क द्वारा विस्तारित होता है तथा इसके फलस्वरूप कुछ लोगों में किडनी फेल होने का भी खतरा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार इसके संक्रमण की चपेट में आए 27 प्रतिशत लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका अभी कोई सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका है।

14वीं एशियाई शेर गणना 2015

- गुजरात राज्य के वन विभाग द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर कराई जाने वाली नवीनतम '14वीं एशियाई शेर गणना (14th Asiatic Lion Census), 2015' इस वर्ष 1-5 मई के मध्य संपन्न हुई।
- गिर अभयारण्य (जो कि एशियाई शेरों का वर्तमान में विश्व में एकमात्र वास स्थान है) और इसके आस-पास के क्षेत्रों (लगभग 20,000 वर्ग किमी.) में आधुनिकतम जीपीएस तकनीक के माध्यम से कराई गई इस एशियाई शेर गणना के आंकड़े गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल द्वारा 11 मई, 2015 के दौरान जारी किए गए।
- 14वीं एशियाई शेर गणना के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गिर अभयारण्य एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में एशियाई शेरों की संख्या 523 दर्ज हुई जो कि विगत गणना (2010) की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।
- उल्लेखनीय है कि एशियाई शेर (Panthera leo persica) को इसके छोटे जनसंख्या आकार के कारण प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN : International Union for Conservation of Nature) द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों (Endangered Species) की सूची में रखा गया है।

सर्वाधिक वृहद क्षुद्रग्रह संघात क्षेत्र

- मार्च, 2015 में भू-भौतिकी जर्नल 'टेक्टोनोफिजिक्स' (Tectonophysics) में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (ANU) के डॉ. एंड्रयू ग्लिक्सन (Dr. Andrew Glikson) के नेतृत्व में भूविज्ञानियों की एक टीम ने 'विश्व के सर्वाधिक वृहद क्षुद्रग्रह संघात क्षेत्र' (World's largest asteroid impact zone) का पता लगाया है।

- मध्य ऑस्ट्रेलिया स्थित वारबर्टन बेसिन क्षेत्र में प्राप्त यह क्षुद्रग्रह संघात क्षेत्र 400 किमी. (250 मील) चौड़े क्षेत्र में विस्तारित है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी की सतह से टकराने से पूर्व दो भागों में टूट गया था और इनमें से प्रत्येक भाग 10 किमी. से अधिक चौड़ा था।
- शोधकर्ताओं के अनुसार यह क्षुद्रग्रह संघात कम से कम 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ होगा तथा यह इससे भी अधिक पहले का हो सकता है क्योंकि इसके चारों ओर की चट्टानें 300 मिलियन से 600 मिलियन वर्ष तक पुरानी हैं।

पोर्ट ब्लेयर चुंबकीय वेधशाला का उद्घाटन

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भू विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा 30 मार्च, 2015 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में शोएल बे (Shoal Bay) नं. 8 पर 'बहु-प्राचल भू भौतिकी वेधशाला' (Multi-Parametric Geophysical Observatory : MPGO) का उद्घाटन किया गया।
- यह चुंबकीय वेधशाला भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (IIG : Indian Institute of Geomagnetism) द्वारा स्थापित किए जा रहे 14 MPGOs के नेटवर्क का एक भाग है।
- इन बहु-प्राचल भूभौतिकी वेधशालाओं (MPGOs) का उद्देश्य विभिन्न प्राविधियों एवं तकनीकों के माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन व्यतिक्रमों का निरीक्षण करना है। ये वेधशालाएं भूकंपीय गतिविधियों संबंधी सूचनाओं एवं सिग्नलों को प्राप्त कर उनके विश्लेषण एवं रियल टाइम डाटा के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी।

लार्ज हैड्रान कोलाइडर (LHC) पुनः प्रारंभ

- 5 अप्रैल, 2015 को विश्व की सर्वाधिक वृहद और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक (Particle Accelerator) मशीन लार्ज हैड्रान कोलाइडर (LHC : Large Hadron Collider) को पुनः प्रारंभ कर दिए जाने की घोषणा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN) द्वारा जारी की गई है।
- फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर जेनेवा के निकट स्थापित इस अति वृहदाकार भूमिगत मशीन को 2 वर्षों तक गहन रखरखाव और उन्नयन (Upgradation) हेतु बंद किया गया था तथा कई माह की तैयारी के बाद इसे पुनः प्रारंभ किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि एलएचसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर ही जुलाई, 2012 में 'हिग्स-बोसान' (गॉड पार्टिकल) की खोज की घोषणा की गई थी जिसके फलस्वरूप फ्रांकोइस इंग्लर्ट और पीटर हिग्स को (जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस कण के अस्तित्व की परिकल्पना की थी) वर्ष 2013 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
- गॉड पार्टिकल की खोज के बाद इसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2 वर्ष पूर्व बंद किया गया था तथा सर्न का दावा है कि अब एलएचसी की कोलाइडर शक्ति अधिकतम 8 टेराइलेक्ट्रॉनवोल्ट्स (TeV) से बढ़कर 14 TeV हो गई है।
- 10 अप्रैल, 2015 को एलएचसी की प्रोटान बीम के 6.5 TeV के नए रिकॉर्ड ऊर्जा स्तर पर पहुंचने की घोषणा की गई।
- वैज्ञानिकों को आशा है कि एलएचसी के भावी प्रयोगों से भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के तहत ब्रह्मांड की कई अनुसुलझी गुत्थियों को सुलझाया जा सकेगा।

आईआरएनएसएस-1डी का सफल प्रक्षेपण

- 28 मार्च, 2015 को शाम को 5.19 बजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान 'पीएसएलवी-सी27' के माध्यम से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SHAR), श्रीहरिकोटा से भारतीय क्षेत्रीय नैविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) हेतु स्थापित किए जा रहे उपग्रहों की शृंखला का चौथा उपग्रह 'आईआरएनएसएस-1डी' सफलतापूर्वक भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) हेतु प्रक्षेपित किया गया। 1,425 किग्रा. लिफ्ट-ऑफ वजन वाले इस उपग्रह की कार्यकारी अवधि 10 वर्ष आकलित है।
- आईआरएनएसएस-1डी के प्रक्षेपण के साथ इसरो द्वारा नैविगेशन प्रणाली को प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम आवश्यक 4 उपग्रह प्रक्षेपित कर दिए गए हैं। इस प्रणाली के शेष 3 उपग्रह अभी प्रक्षेपित किए जाने हैं तथा सभी 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद लोकेशन, ट्रैकिंग, मैपिंग आदि के संदर्भ में भारत की अपनी नैविगेशन उपग्रह प्रणाली पूर्णतः उपलब्ध हो जाएगी।
- अमेरिका और रूस के बाद अपनी पृथक नैविगेशन उपग्रह प्रणाली पूर्णतः विकसित कर लेने वाला भारत विश्व का तीसरा देश होगा। वर्तमान में अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) तथा रूस का ग्लोनॉस सिस्टम ही पूर्णतः संचालित हैं तथा इन दोनों से भारत आंकड़े प्राप्त करता है। चीन का बेईडू (बीएसएनएस) तथा यूरोप का गैलीलियो नैविगेशन सिस्टम वर्ष 2020 तक ही पूर्णतः संचालित हो पाएंगे।

डॉन : नासा का अंतरिक्ष अन्वेषण यान

- 6 मार्च, 2015 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) का अंतरिक्ष अन्वेषण यान 'डॉन' (Dawn) ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस (Ceres) की कक्षा में प्रवेश कर गया तथा यह ऐसा करने वाला पृथ्वी का प्रथम अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है। इस अंतरिक्ष अन्वेषण यान को केप केनवेरल एयरफोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा (अमेरिका) से डेल्टा II 7925H रॉकेट के माध्यम से 27 सितंबर, 2007 को प्रक्षेपित किया गया था।
- 'डॉन' अंतरिक्ष प्रोब को एस्टेरॉयड बेल्ट के दो सर्वाधिक वृहद प्रोटोग्रहों वेस्टा (Vesta) और सेरेस के अध्ययन के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था। यह 16 जुलाई, 2011 को वेस्टा की कक्षा में प्रवेश कर ऐसा करने वाला पृथ्वी का पहला अंतरिक्षयान बना था तथा इसने लगभग 14 माह तक वेस्टा का सर्वेक्षण कर अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसके बाद इसने वहां से सेरेस के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तथा यह सेरेस के निकट पहुंचकर दिसंबर, 2014 से ही इसकी हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें पृथ्वी पर प्रेषित करने लगा था।
- उल्लेखनीय है कि एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्रग्रहों की पेटी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित है तथा 'सेरेस' इस बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है।

सोलर इम्पल्स-2 की उड़ान

- 9 मार्च, 2015 को सौर ऊर्जा से संचालित विमान 'सोलर इम्पल्स-2' (Solar Impulse-2) ने अबूधाबी (यूएई) से विश्व का पूरा चक्कर लगाने के लिए उड़ान भरी और यह 10 घंटे की उड़ान के बाद मस्कट (ओमान) पहुंचा। तत्पश्चात यह 10 मार्च को अहमदाबाद (भारत) और फिर 18 मार्च को वाराणसी पहुंचा। इसकी 12 स्टापेज (चीन एवं म्यांमार सहित) के साथ 35,000 किमी. की अपनी यात्रा पूरी कर प्रशांत महासागर को पार करने की योजना थी तथापि जापान से हवाई पहुंचने (3 जुलाई, 2015) के मध्य इसकी बैटरियों में ऊष्मीय क्षति के कारण इसकी यात्रा रोकनी पड़ी, जिसके अप्रैल, 2016 में पुनः प्रारंभ होने की आशा व्यक्त की गई है। यह सौर ऊर्जा चालित ऐसी पहली उड़ान होगी, जो पूरे विश्व का चक्कर लगाएगी।
- इस विमान द्वारा विश्व की यह यात्रा 'फ्यूचर इज क्लीन' अभियान के तहत की जा रही है।
- इससे पूर्व 2 जून, 2014 को 'सोलर इम्पल्स-2' ने सफलतापूर्वक स्विट्जरलैंड के पेयर्न हवाई अड्डे से परीक्षण उड़ान भरी थी। वर्ष 2013 के जुलाई माह में 26 घंटे में अमेरिका की अंतर्महाद्वीप यात्रा करने वाले सौर ऊर्जा संचालित विमान 'सोलर इम्पल्स' का उन्नत और बड़ा संस्करण है।
- स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक बर्टेंड पिकार्ड और पूर्व पायलट एंड्रे बोर्शबर्ग द्वारा सोलर इम्पल्स परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट, 2014

- 20 जनवरी, 2015 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 'अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट, 2014' जारी की गई।
- देश में बाघों की संख्या में नवीनतम (2014) आकलन के तहत वर्ष 2010 के आकलन की तुलना में 30.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवधि में देश में बाघों की संख्या वर्ष 2010 के 1,706 से बढ़कर वर्ष 2014 में 2,226 (अनुमानित संख्या 1,945 से 2,491 के मध्य) हो गई है। वर्ष 2006 के प्रथम राष्ट्र-स्तरीय बाघ आकलन के अनुसार देश में कुल बाघों की संख्या 1,411 ही आकलित थी।
- 2014 के बाघ आकलन के अनुसार विगत आकलन की तुलना में कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बाघों की संख्या में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में भी बाघों की संख्या बढ़ी है तथापि ओडिशा, झारखंड एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इनकी संख्या कम हुई है।
- वर्ष 2014 के आकलन के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य इस प्रकार हैं—1. कर्नाटक (406), 2. उत्तराखंड (340), 3. मध्य प्रदेश (308), 4. तमिलनाडु (229), 5. महाराष्ट्र (190), 6. असम (167), 7. केरल (136) एवं 8. उत्तर प्रदेश (117)।
- उल्लेखनीय है कि देश में बाघों के संरक्षण हेतु 'बाघ परियोजना' (Project Tiger) का प्रारंभ 1973 में किया गया था। इसके तहत देश के 18 राज्यों में वर्तमान में कुल 47 टाइगर रिजर्व हैं जिनके तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.08 प्रतिशत हिस्सा आच्छादित है।

डायरिया नियंत्रण हेतु स्वदेशी टीके का शुभारंभ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मार्च, 2015 को देश में डायरिया नियंत्रण हेतु भारत बायोटेक द्वारा स्वदेश में विकसित एवं निर्मित टीके 'रोटावैक' (Rotavac) का शुभारंभ किया गया।
- रोटावैक एक मुखीय टीका (Oral Vaccine) है, जिसकी पहली खुराक नवजात शिशुओं को 6 सप्ताह की अवस्था में तथा दो अन्य खुराकें इसके बाद 4-4 सप्ताह के अंतराल पर दी जाएंगी।
- यह टीका बच्चों में डायरिया (जो शिशु मृत्युओं का प्रमुख कारण बनता है) के कारक विषाणु 'रोटावायरस' के विरुद्ध अब तक विश्व में उपलब्ध कुल तीसरा टीका है तथा इनमें यह न्यूनतम कीमत का है।

सफर : वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली

- 'सफर' (SAFAR : System of Air quality Weather Forecasting And Research) प्रथम भारतीय वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली है जिसका विकास भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ मिलकर किया गया है। इस प्रणाली के एंड्रायड मोबाइल आधारित एप्लीकेशन (App) 'सफर-एयर' को 17 फरवरी, 2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- 'सफर-एयर' एप्लीकेशन से स्थानीय वायु गुणवत्ता संबंधी सूचनाओं के साथ-साथ भावी 3 दिनों की वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान भी प्राप्त किया जा सकता है।
- यह मोबाइल एप कलर कोडेड सिस्टम (जिसमें अच्छे से खराब तक 6 वायु गुणवत्ता स्तरों के लिए पृथक रंग निर्धारित हैं) के माध्यम से वायु गुणवत्ता सूचनाएं उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय कृमि निवारण पहल

- 9 फरवरी, 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी.नड्डा द्वारा जयपुर से 'राष्ट्रीय कृमि निवारण पहल' (National Deworming Initiative) का शुभारंभ किया गया।
- राष्ट्रीय डीवार्मिंग दिवस (10 फरवरी) की पूर्व संध्या पर प्रारंभ इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य देश के 1-19 वर्ष आयु वर्ग के सभी प्री-स्कूल या स्कूल जाने की आयु वाले (स्कूल में नामांकित या गैर-नामांकित) बच्चों को पेट के कीड़ों (आंत्र कृमियों; Intesinal Parasitic Worms) से मुक्ति दिलाना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में 1 से 14 वर्ष उम्र के 24 करोड़ बच्चों को इन कीड़ों का खतरा है। इस प्रकार यह पहल बच्चों को इन रोगाणुओं से बचाने हेतु विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है।
- इस पहल के प्रथम चरण में 11 राज्यों/संघीय क्षेत्रों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और तमिलनाडु) के 14 करोड़ बच्चों को लक्ष्यित किया जाएगा जिसके तहत यहां के सभी बच्चों को एल्बेडाजोल (Albendazole) की गोलियां (1-2 वर्ष आयु के लिए 1/2 गोली एवं 2-19 वर्ष हेतु 1 गोली)10 फरवरी से वितरित किया जाना प्रारंभ किया गया

तथा 14 फरवरी से छूटे हुए बच्चों के लिए विशेष मॉप-अप चरण प्रारंभ हुआ। इस अभियान के द्वितीय चरण में देश के शेष 10 करोड़ बच्चों को लक्ष्यित किया जाएगा।

- इस पहल का मूल उद्देश्य 'पोलियो-मुक्त' देश की तरह भारत को 'कृमि मुक्त' (Worm-Free) देश का दर्जा दिलाना है।

भारत का पहला हाई-स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क

- 12 जनवरी, 2015 को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा केरल के इडुक्की (Idukki) जिले में भारत के पहले हाई-स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क का शुभारंभ किया गया।
- इसके साथ ही देश में ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की महत्त्वाकांक्षी परियोजना 'राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क' की बहुप्रतीक्षित शुरुआत भी हुई। ज्ञातव्य है कि एनओएफएन अब प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' का एक भाग है।
- इडुक्की में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) के प्रारंभ के साथ ही यह भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जिसके सभी क्षेत्र हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि एनओएफएन विश्व में अपने तरह की विशालतम ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना है। पहले चरण में इस परियोजना के दायरे में 50,000 ग्राम पंचायतों को लाया जाएगा तथा शेष 2 लाख ग्राम पंचायतों को वर्ष 2016 तक चरणबद्ध रूप से आच्छादित किया जाएगा।
- पहले चरण में इस परियोजना का क्रियान्वयन तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों- बीएसएनएल, पीजीसीआईएल (पॉवरग्रिड) तथा रेलटेल द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC) का 102वां सत्र

- 3-7 जनवरी, 2015 के दौरान मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई में भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC-Indian Science Congress) का 102वां वार्षिक सत्र आयोजित किया गया।
- भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इस पांच-दिवसीय 102वें सत्र का केंद्रीय विषय था- 'मानव विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी'।
- भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 102वें अधिवेशन के दूसरे दिन 4 जनवरी को 'बाल विज्ञान कांग्रेस' (1993 से आईएससी के साथ प्रतिवर्ष आयोजित) का उद्घाटन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।
- इसी दिन चौथी 'महिला विज्ञान कांग्रेस' (2012 से आईएससी के साथ प्रतिवर्ष आयोजित) का प्रारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा किया गया। इस वर्ष महिला विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय 'महिला विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' था।
- भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अगला सत्र जनवरी, 2016 में मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर में आयोजित होगा।

भारत-आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (INO)

- 5 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'भारत-आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी' (INO : India-based Nutrino Observatory) की स्थापना की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। 1,500 करोड़ रु. (लगभग 236 मिलियन डॉलर) की अनुमानित लागत वाली इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के तहत इस ऑब्जर्वेटरी की स्थापना तमिलनाडु और केरल की सीमा पर तमिलनाडु के थेनी (Theni) जिले के बोडी पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में पोट्टीपुरम ग्राम के निकट 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में की जाएगी।
- इस परियोजना के तहत भारत में गैर-त्वरक आधारित उच्च ऊर्जा (Non-Accelerator based High Energy) और नाभिकीय भौतिकी अनुसंधानों के लिए भूसतह से लगभग 1200 मीटर चट्टानों के नीचे एक विश्वस्तरीय प्रयोगशाला बहु-संस्थानिक प्रयास के तहत स्थापित की जाएगी।
- भारत-आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (INO) परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य न्यूट्रिनो के व्यवहार का अध्ययन है। न्यूट्रिनो के द्रव्यमानों और इनके मिश्रित होने के प्राचलों का निर्धारण वर्तमान में भौतिकी के समक्ष उपस्थित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खुली समस्याओं में से एक है।
- यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि आईएनओ में विश्व का अब तक का सबसे वृहदाकार चुंबक (Magnet) स्थापित किया जाएगा जो कि जेनेवा (स्विट्जरलैंड) के निकट फ्रांस के सेसी में सर्न (CERN) द्वारा एलएचसी परियोजना के तहत स्थापित 'कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड डिटेक्टर' के लगभग 12,500 टन के चुंबक से चार गुना बड़ा होगा।

केपलर 2 मिशन द्वारा 'सुपर-अर्थ' की खोज

- 18 दिसंबर, 2014 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA-National Aeronautics and Space Administration) द्वारा अपने अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी मिशन केपलर 2 (K2 : Kepler 2) के माध्यम से पहली बार सौरमंडल के बाहर के एक ग्रह (Exoplanet) को खोजे जाने की घोषणा की गई।
- 'सुपर-अर्थ' (Super-Earth) श्रेणी का यह ग्रह पृथ्वी से 180 प्रकाशवर्ष (55 पारसेक) की दूरी पर है। इसे 'HIP 116454 B' नाम दिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि 'सुपर-अर्थ' की संज्ञा सौरमंडल के बाहर के ऐसे ग्रहों को दी जाती है जिनका द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक (सामान्यतः 10-12 गुना तक) होता है परंतु सौरमंडल के ही यूरेनस और नेप्च्यून जैसे छोटे गैसीय ग्रहों से अपेक्षाकृत कम होता है।
- केपलर 2 मिशन द्वारा खोजे गए सुपर-अर्थ का द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 12 गुना है तथा इसका व्यास (लगभग 32,000 किमी.) पृथ्वी का 2.5 गुना है। यह अपने तारे की 9 दिनों में परिक्रमा करता है।
- 6 जनवरी, 2015 को नासा ने केपलर स्पेस टेलिस्कोप द्वारा 1000वें सुनिश्चित एक्सोप्लैनेट की खोज की घोषणा की। इसके द्वारा खोजे गए नवीनतम 3 एक्सोप्लैनेट हमारे सूर्य के समकक्ष तारों के हैबिटेबल जोन (Habitable Zone) या गोल्डीलॉक्स जोन (Goldilocks Zone- ऐसा क्षेत्र जिसमें ग्रहीय पिंडों में सतह पर जल के समर्थन हेतु पर्याप्त वायुमंडलीय दाब होता है) के भीतर परिक्रमा करते हैं। इन तीन में से दो, 'केपलर-438b' एवं 'केपलर-442b' पृथ्वी के निकट आकार के हैं और संभवतः चट्टानी हैं जबकि एक, 'केपलर-440b' सुपर-अर्थ श्रेणी का है।

◆◆◆

रक्षा/प्रतिरक्षा

● प्रथम स्कॉर्पीन श्रेणी पनडुब्बी-'कलवारी' ● भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किए जाने को स्वीकृति ● 'निर्भय' प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण असफल ● 'आईएनएस अस्त्रधारिणी' नौसेना में शामिल ● 'आईएनएस कोच्चि' राष्ट्र को समर्पित ● भारत-अमेरिका हेलिकॉप्टर सौदा ● अमोघ-I : टैंक-रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र ● 'आईएनएस वज्रकोष' : नई नौसैनिक संस्थापना ● स्वदेशी तोप 'धनुष' का उन्नत संस्करण ● 'आकाश' प्रक्षेपास्त्र वायु सेना एवं थल सेना में शामिल ● भारतीय सेना का म्यांमार अभियान ● यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा लड़ाकू विमान ● आईएनएस कवरत्ती का जलावतरण ● आईएनएस सरदार पटेल नौसेना में शामिल ● आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण ● धनुष प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण ● भारत का अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र अग्नि-V ● 'तेजस' : भारतीय सुपरसोनिक एलसीए ● रक्षा : सैन्याभ्यास

प्रथम स्कॉर्पीन श्रेणी पनडुब्बी-'कलवारी'

- 29 अक्टूबर, 2015 को स्वदेश-निर्मित स्कॉर्पीन श्रेणी (Scorpene Class) की पहली पनडुब्बी 'आईएनएस कलवारी' (INS Kalvari) को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से सामुद्रिक परीक्षणों हेतु उतारा गया।
- इससे पूर्व 6 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की उपस्थिति में मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड (MDL) पर पनडुब्बी 'कलवारी' का जलावतरण (Undocking) संपन्न हुआ था।
- उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा फ्रांस के साथ वर्ष 2005 में हुए 3 बिलियन डॉलर के समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए फ्रेंच कंपनी डीसीएनएस के सहयोग से तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही स्कॉर्पीन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में यह प्रथम पनडुब्बी है।
- ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के महत्त्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट 75' के भाग के रूप में तैयार की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि 1999 में प्रारंभ इस प्रोजेक्ट के तहत 30 वर्षों में कुल 24 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है।
- स्कॉर्पीन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नामकरण 'कलवारी' भारत को रूस द्वारा 1968 में प्रदत्त 'फॉक्सट्रॉट' श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी (जो भारतीय नौसेना द्वारा परिचालित पहली पनडुब्बी थी) 'आईएनएस कलवारी' (S 23) के नाम पर ही किया गया है। ज्ञातव्य है कि 'कलवारी' गहन समुद्र में पाई जाने वाली टाइगर शार्क का भी नाम है।
- 1,565 टन विस्थापन (Displacement) भार वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 61.7 मीटर (202 फीट) है तथा यह डीजल-विद्युत प्रोपल्शन प्रणाली से युक्त है। समुद्र सतह पर यह 12 नाट्स (22 किमी./घंटा) तथा समुद्र के भीतर यह 20 नाट्स (37 किमी./घंटा) की गति प्राप्त कर सकने में सक्षम है।
- 'कलवारी' अत्यंत उत्कृष्ट स्टील्थ (रडार से बचने की) क्षमता से युक्त है तथा यह बहुविध युद्ध स्थितियों, पनडुब्बी-रोधी युद्ध आसूचना एकत्र करने, समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने, क्षेत्र निगरानी आदि सहित विभिन्न ऑपरेशनों में प्रयुक्त हो सकती है।
- अब अगले लगभग 10 माह तक आईएनएस कलवारी की विभिन्न क्षमताओं के समुद्री परीक्षण किए जाएंगे तथा सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद इसे सितंबर, 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।

भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किए जाने को स्वीकृति

- 24 अक्टूबर, 2015 को रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय वायुसेना में महिलाओं को युद्धक या लड़ाकू संवर्ग (Fighter/Combat Stream) में लड़ाकू पायलट (Fighter Pilots) के रूप में शामिल किए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 8 अक्टूबर, 2015 को वायुसेना के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष एयरचीफ मार्शल अरूप राहा ने इस संदर्भ में प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजे जाने की घोषणा की थी।
- यह प्रगतिशील कदम भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं और विकसित देशों के सशस्त्र बलों में समकालीन चलन के अनुरूप उठाया गया है। महिलाएं भारतीय वायुसेना में परिवहन विमानों और हेलिकॉप्टरों का संचालन पहले से कर रही हैं और इसमें उनका प्रदर्शन सराहनीय और अपने पुरुष समकक्ष सहकर्मियों जैसा ही रहा है।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एयरफोर्स एकेडमी में वर्तमान में प्रशिक्षण ले रही महिला पायलटों में से ही महिला लड़ाकू पायलटों के पहले बैच का चयन किया जाएगा तथा प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जून, 2016 में वे लड़ाकू संवर्ग में कार्य करने के लिए अधिकृत हो जाएंगी। इसके पश्चात उन्हें एक वर्ष के उन्नत प्रशिक्षण से गुजरना होगा तथा फिर वे जून, 2017 तक लड़ाकू विमान कॉकपिट में पायलट के रूप में प्रवेश कर लेंगी।
- वर्तमान में भारत की तीनों सेनाओं में वायुसेना में सर्वाधिक 1500 से अधिक महिला अफसर हैं जो वायु सेना के कुल अधिकारियों का 8.5 प्रतिशत है (तीनों सेनाओं में समग्र रूप से यह आंकड़ा 5.4 प्रतिशत है)। वायुसेना में लगभग 110 महिला पायलट हैं जो इस समय हेलिकॉप्टर और परिवहन विमान उड़ा रही हैं।
- भारतीय सेना में सर्वप्रथम महिलाओं को नर्सिंग सेवाओं के लिए 1927 में शामिल किया गया था तथा 1941 से सेना में बतौर चिकित्सा अधिकारी महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। सशस्त्र सेना की अन्य इकाइयों में 1992 में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दी गई तथापि इन्हें अब तक युद्धक संवर्ग से दूर ही रखा गया है।
- वर्तमान में, भारतीय सेना में महिलाओं को सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन (एयर ट्रैफिक कंट्रोल), आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, खुफिया कोर, सेना शिक्षा कोर और जज एडवोकेट जनरल शाखाओं/कैडरों में शामिल किया जाता है। भारतीय नौसेना ने महिलाओं को जज एडवोकेट जनरल, लॉजिस्टिक्स, प्रेक्षक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल इंस्ट्रक्टर और शिक्षा शाखाओं/कैडरों में शामिल किया है।
- भारतीय वायुसेना में वर्तमान में महिलाएं उड़ान शाखा के तहत

परिवहन एवं हेलिकॉप्टर संवर्ग (ज्ञातव्य है कि 1994 में पहली बार महिला पायलट वायुसेना में शामिल हुई थीं), नैविगेशन, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, लेखा, शिक्षा और मौसम विज्ञान शाखाओं के तहत कार्यरत हैं। महिलाओं को लड़ाकू संवर्ग में शामिल किए जाने के इस निर्णय के साथ महिलाएं अब वायुसेना की सभी शखाओं और संवर्गों में शामिल होने की पात्र बन गई हैं।

- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, सर्बिया, सऊदी अरब एवं तुर्की जैसे देशों की वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलट हैं। मलेशिया एवं श्रीलंका में युद्धक पोतों पर महिलाएं तैनात हैं तथा कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, नीदरलैंड्स, नार्वे, पोलैंड एवं रोमानिया जैसे देशों में महिलाओं को क्लोज कॉम्बैट भूमिका में सेना में शामिल किया गया है।

'निर्भय' प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण असफल

- 16 अक्टूबर, 2015 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल 'निर्भय' (NIRBHAY) को ओडिशा के बालासोर स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) के कॉम्प्लेक्स-3 से विशेष रूप से तैयार लांचर से सुबह 11:38 बजे प्रक्षेपित किया गया।
- प्रारंभिक तौर पर यह प्रक्षेपण सामान्य रहा तथा इसके बूस्टर प्रज्ज्वलन, बूस्टर के पृथक होने की प्रक्रिया, डैनों की स्थिति एवं इंजन ने सफलतापूर्वक कार्य किया तथा इस प्रक्षेपास्त्र ने निर्धारित क्रूज ऊंचाई भी प्राप्त कर ली थी। 700 सेकेंड की उड़ान के दौरान तक इसके सभी उपतंत्र सामान्य और संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे थे परंतु इसके बाद अचानक मिसाइल में तकनीकी खराबी आ गई जिससे यह परीक्षण मिशन असफल हो गया।
- उल्लेखनीय है कि एक वर्ष पूर्व 17 अक्टूबर, 2014 को निर्भय प्रक्षेपास्त्र का पहला पूर्णतः सफल परीक्षण चांदीपुर आईटीआर से ही किया गया था जो कि 15 नियत परीक्षण मानदंडों पर खरा उतरा था।
- सतह से सतह पर मार करने वाले इस द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र में टर्बोफैन इंजन प्रयुक्त होता है तथा इसे अमेरिकी 'टॉमहॉक' क्रूज मिसाइलों के समकक्ष माना जा रहा है।
- नाभिकीय और परंपरागत युद्धशीर्ष ले जाने में सक्षम यह प्रक्षेपास्त्र लंबी दूरी (आकलनों के अनुसार 1000-1500 किमी.) के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। साथ ही यह सतह से मात्र 10-15 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए (जिससे यह रडार की नजर में नहीं आएगा) अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
- इसका प्रक्षेपण जमीन, हवा एवं समुद्र के अलावा मोबाइल लांचर से किया जा सकता है। 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) प्रणाली से लैस इस प्रक्षेपास्त्र को लांचिंग के बाद दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती तथा इसमें हमले के सही कोण तथा समय का अनुमान लगाने की क्षमता है।
- निर्भय प्रक्षेपास्त्र की लंबाई 6 मीटर तथा वजन 1000 किग्रा. है तथा यह 4 किमी. की अधिकतम ऊंचाई पर 0.75 मैक (लगभग 918 किमी. प्रति घंटे) की अधिकतम गति से अपने लक्ष्य की ओर जा सकता है।
- यह प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी चालक रहित विमान 'लक्ष्य' के आधार पर ही पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसके थल संस्करण के विकास के बाद इसके पोत, वायु और पनडुब्बी संस्करण भी विकसित किए जाएंगे।

'आईएनएस अस्त्रधारिणी' नौसेना में शामिल

- 6 अक्टूबर, 2015 को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल सतीश सोनी द्वारा विशाखापत्तनम के नौसेना बेस पर आयोजित एक भव्य समारोह में स्वदेश निर्मित टारपीडो लांच एवं रिकवरी पोत 'आईएनएस अस्त्रधारिणी' (INS Astradharini) को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
- आईएनएस अस्त्रधारिणी का डिजाइन डीआरडीओ की नौसैन्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी (NSTL), मेसर्स शॉफ्ट शिपयार्ड तथा आईआईटी खड़गपुर के संयुक्त प्रयास के तहत किया गया है तथा स्वदेशी स्टील से निर्मित इस पोत में कैटमैरेन हल (Catamaran Hull; विशिष्ट प्रकार के समानांतर तल/पेंदे) का प्रयोग किया गया है जिससे विद्युत की काफी कम खपत होती है।
- यह टारपीडो लांच एवं रिकवरी पोत 50 मीटर लंबा है तथा यह 15 नॉट तक की गति प्राप्त कर सकने में सक्षम है। यह पोत आधुनिक विद्युत उत्पादन एवं वितरण, नैविगेशन तथा संचार प्रणालियों से युक्त है। यह उच्च समुद्री परिस्थितियों में कार्य कर सकता है तथा इसमें परीक्षणों के दौरान विभिन्न प्रकार के टारपीडो की तैनाती एवं रिकवरी हेतु टारपीडो लांचर के साथ एक वृहद डेक क्षेत्र है।
- इसकी पोत प्रणालियों का 95 प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी प्रारूप का है।
- आईएनएस अस्त्रधारिणी का उपयोग एनएसटीएल द्वारा विकसित अंतर्जलीय (Underwater) शस्त्रों एवं प्रणालियों के तकनीकी परीक्षणों हेतु किया जाएगा।
- यह 17 जुलाई, 2015 को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त टारपीडो लांच एवं रिकवरी पोत 'आईएनएस अस्त्रवाहिनी' (जो 1984 से नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा था) का उन्नत स्थानापन्न है।

'आईएनएस कोच्चि' राष्ट्र को समर्पित

- भारतीय नौसेना हेतु 'प्रोजेक्ट 16A' के तहत देश में निर्मित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक (Guided Missile Destroyer) युद्धपोतों की श्रृंखला (कोलकाता-श्रेणी) का दूसरा युद्धपोत 'आईएनएस कोच्चि' (INS KOCHI) रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा 30 सितंबर, 2015 को मुंबई स्थित नौसेना गोदी में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल करने के साथ राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- इससे पूर्व इस श्रृंखला के प्रथम युद्धपोत 'आईएनएस कोलकाता' को 16 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था।
- कोलकाता श्रेणी के ये युद्धपोत भारत में अब तक तैयार किए गए सर्वाधिक शक्तिशाली युद्धपोत हैं। इनकी परिकल्पना एवं डिजाइनिंग नौसैन्य डिजाइन निदेशालय (DND : Directorate of Naval Design) ने की है तथा इनका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट 15-ए 'कोलकाता' श्रेणी विध्वंसक पोत, 1990 के दशक के अंत में नौसेना में शामिल प्रोजेक्ट 15 'दिल्ली' श्रेणी विध्वंसक पोतों (आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई) के अनुवर्ती और

परिष्कृत संस्करण हैं। आईएनएस कोलकाता एवं आईएनएस कोच्चि के अतिरिक्त प्रोजेक्ट-15ए के तहत 'आईएनएस चेन्नई' नामक युद्धपोत निर्माणाधीन हैं जिसके 2016 के अंत तक नौसेना में शामिल होने की आशा है।

- नौसेना के पश्चिमी बेड़े में मुंबई तट के निकट तैनात किए जाने वाले 'आईएनएस कोच्चि' की लंबाई 164 मीटर और चौड़ाई लगभग 17 मीटर है तथा इसका पूर्ण भार विस्थापन (Total Load Displacement) 7,500 टन है।
- '<u>जही शत्रुन महाबाहो</u>' (शत्रु पर विजय के लिए शस्त्रबद्ध) का नारा (जो कि इसके ऊपरी हिस्से में संस्कृत में अंकित है) बुलंद करने वाला आईएनएस कोच्चि भारत में निर्मित 10वां युद्धपोत है। लगभग 4,000 करोड़ रु. की लागत से निर्मित इस युद्धपोत पर 40 अधिकारी और 350 नाविक नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं।
- इस विध्वंसक युद्धपोत में 4 शक्तिशाली रिवर्सिबल गैस टरबाइनों से युक्त 'संयुक्त गैस एवं गैस' (COGAG : Combined Gas and Gas) प्रणोदन प्रणाली (Propulsion System) लगी है और यह 30 नॉट से भी ज्यादा गति प्राप्त कर सकने में सक्षम है।
- इस युद्धपोत और आईएनएस कोलकाता में रडार से बच निकलने (Stealth) के लिए नई डिजाइन संकल्पना प्रयुक्त हुई है तथा इनमें वृहद स्वदेश निर्मित युद्धक घटक (Combat Component) सहित अनेक चीजें पहली बार शामिल की गई हैं।
- आईएनएस कोच्चि लंबवत प्रक्षेपण वाली लंबी दूरी की सतह से हवा मिसाइलों (LRSAM), लंबी दूरी की सतह से सतह सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों तथा एमएफ-स्टार मल्टीफंक्शन फेज्ड ऐरे रडार (जिसे केवल कोलकाता-श्रेणी के युद्धपोतों में ही लगाया गया है) सहित अत्यधिक उत्कृष्ट अत्याधुनिक शस्त्रों एवं संवेदकों से सुसज्जित है। शत्रु विमानों और सतह से हमलों से रक्षा हेतु स्वदेशी 76 एमएम एवं 30 एमएम की सुपर रैपिड तोपें भी इस पोत पर लगाई गई हैं। यह स्वदेशी रॉकेट लांचरों, ट्विन-ट्यूब टारपीडो लांचरों तथा नई पीढ़ी के 'हमसा' (HUMSA) सोनार सहित पनडुब्बी-रोधी शस्त्रों एवं सेंसरों से युक्त है। एक अत्याधुनिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS-15A) को इस युद्धपोत में लगे हथियारों और संवेदकों से एकीकृत किया गया है।
- आईएनएस कोच्चि से दो सी-किंग या चेतक हेलिकॉप्टरों को भी संचालित किया जा सकता है।
- कोलकाता-श्रेणी के युद्धपोतों को वास्तविक अर्थों में '<u>नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स</u>' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि यह उत्कृष्ट डिजिटल नेटवर्क्स यथा—एटीएम आधारित एकीकृत पोत आंकड़ा नेटवर्क (AISDN), सहायक नियंत्रण प्रणाली (ACS), स्वचालित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (APMS) तथा काम्बैट प्रबंधन प्रणाली (CMS) से लैस है।

भारत-अमेरिका हेलिकॉप्टर सौदा

- 28 सितंबर, 2015 को भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 3 बिलियन डॉलर (लगभग 19,800 करोड़ रु.) की लागत से अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग (Boeing) द्वारा निर्मित 37 अत्युन्नत हेलिकॉप्टरों की खरीद हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें <u>15 चिनूक और 22 अपाचे हेलिकॉप्टर</u> शामिल हैं।
- इससे पूर्व 22 सितंबर, 2015 को सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) द्वारा इस सौदे को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- इस भारत-अमेरिका हेलिकॉप्टर सौदे के तहत 15 <u>चिनूक</u> (Chinook) हेलिकॉप्टरों की खरीद हेतु भारत के रक्षा मंत्रालय एवं अमेरिकी बोइंग कंपनी के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ है जबकि 22 <u>अपाचे</u> (Apache) हेलिकॉप्टरों की खरीद हेतु दो समझौते (रक्षा मंत्रालय द्वारा एक बोइंग कंपनी के साथ और दूसरा अमेरिकी सरकार के साथ, जिसके तहत अमेरिका इनके लिए हथियारों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों की आपूर्ति करेगा) हस्ताक्षरित हुए हैं।
- अगले 3-4 वर्षों में पूर्ण होने वाले इस हेलिकॉप्टर सौदे की विशेष बात यह है कि एक शर्त (ऑफसेट क्लॉज) के तहत विदेशी कंपनी को 30 प्रतिशत धनराशि वापस भारत में निवेश करनी होगी। सरकार द्वारा 2005 में स्वीकृत रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) के तहत इसका प्रावधान किया गया था। साथ ही इस सौदे में एक प्रावधान यह भी है कि भारत 7 अतिरिक्त चिनूक और 11 अतिरिक्त अपाचे हेलिकॉप्टरों के लिए भी ऑर्डर दे सकेगा।
- इस सौदे के तहत बोइंग द्वारा भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में लगभग 1 बिलियन डॉलर का पुनर्निवेश किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि इन हेलिकॉप्टरों को खरीदने की प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई थी तथा 13 बार इनकी कीमतों में सुधार किए जाने के बाद 2013 में लागत वार्ता को अंतिम रूप दिया गया था और तब से यह सौदा लंबित था।
- **चिनूक हैवीलिफ्ट ट्विन रोटर हेलिकॉप्टर** : 5.68 मी. (18 फीट) ऊंचाई वाले इन हेलिकॉप्टरों का अधिकतम समग्र भार 22,680 किग्रा. हो सकता है तथा ये 302 किमी./घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भरने में सक्षम हैं। यह बोइंग श्रेणी का दो इंजनों वाला बहुभूमिका (Multirole) भारवाहक हेलिकॉप्टर है जो दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य टुकड़ियों, युद्धक सामान और ईंधन ले जाने में सक्षम है। यह आपदा राहत कार्यों और बड़े पैमाने पर प्रभावित लोगों को निकालने हेतु भी प्रयुक्त हो सकता है। वर्तमान में यह अमेरिका और ब्रिटेन सहित विश्व के 19 देशों के पास है।
- **अपाचे एएच 64 डी लांगबो (Longbow) हेलिकॉप्टर** : 17.73 मीटर (58.17 फीट) लंबाई और 4.05 मीटर (13.30 फीट) चौड़ाई वाले इस हेलिकॉप्टर के डैनों की लंबाई 5.2 मीटर (17.15 फीट) है। 6,838 किग्रा. वजन और 284 किमी./घंटा की अधिकतम गति वाला यह हेलिकॉप्टर दो शक्तिशाली टर्बोशॉफ्ट इंजनों से युक्त है तथा यह बोइंग श्रेणी का सबसे एडवांस बहुभूमिका लड़ाकू हेलिकॉप्टर है। रडार से बचने (Stealth) और उन्नत सेंसरों से युक्त यह हेलिकॉप्टर एक मिनट से कम समय में 128 लक्ष्यों को ट्रैक करने के साथ 16 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। यह सभी मौसमों में उड़ान भरने और रात में भी देख सकने में सक्षम है। वर्तमान में अमेरिका, जापान, इजरायल, ग्रीस, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। भारत इन हेलिकॉप्टरों में प्रयुक्त होने वाले रॉकेट और हेलफायर मिसाइलें भी अमेरिका से प्राप्त करेगा।
- इससे पूर्व अमेरिकी कंपनियों ने विगत दशक में भारत के साथ लगभग 10 बिलियन डॉलर के रक्षा सौदे किए हैं। इनमें P-81

नौसैनिक निगरानी विमान, C-130 J सुपर हरक्यूलिस विमान तथा C-17 ग्लोब मास्टर-III विमान शामिल हैं।

- उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2015 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आतंकरोधी अभियानों को तेज करने के लिए 'एएच-1 जेड वाइपर' लड़ाकू हेलिकॉप्टरों के विक्रय का निर्णय लिया गया है। साथ ही हाल ही में पाकिस्तान ने रूस के साथ 'एमआई-35' लड़ाकू हेलिकॉप्टर खरीदने का भी समझौता किया है।

इजरायल से ड्रोन विमान सौदे को स्वीकृति

11 सितंबर, 2015 को भारत सरकार द्वारा इजरायल से 10 मिसाइल-लैस ड्रोन विमानों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। 400 मिलियन डॉलर लागत वाले इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना इजरायल से 10 हेरॉन टीपी ड्रोन (Heron TP Drone) विमान प्राप्त करेगी जो कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होंगे। यह ड्रोन विमान 1000 किग्रा. से अधिक का पेलोड अपने साथ ले जाने के साथ-साथ शत्रु क्षेत्र में दूर के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी तुलना टोही, युद्धक और समर्थन भूमिकाओं में सक्षम होने के कारण अमेरिकी यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle) 'प्रीडेटर' से की जाती है।

अमोघ-I : टैंक-रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र

- भारत के हैदराबाद स्थित रक्षा प्रतिष्ठान 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड' (BDL : Bharat Dynamics Limited) द्वारा डिजाइन एवं विकसित किए गए द्वितीय पीढ़ी के स्वदेशी टैंक-रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र (ATGM : Anti-Tank Guided Missile) 'अमोघ-I' के दो सफल परीक्षण 10 सितंबर, 2015 को किए गए।
- इन परीक्षणों के तहत मध्य प्रदेश के बाबीना स्थित सैन्य रेंज से प्रक्षेपित दो अमोघ-I प्रक्षेपास्त्रों ने क्रमशः 2.6 किमी. और 2.8 किमी. की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा।
- ये दोनों प्रक्षेपण उड़ानें अपने प्रारूपित मार्ग से बगैर किसी विचलन के अपने सभी डिजाइन मानदंडों पर खरी उतरीं।
- 2.8 किमी. तक मारक क्षमता वाला यह प्रक्षेपास्त्र बीडीएल द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया पहला प्रक्षेपास्त्र है।

'आईएनएस वज्रकोष' : नई नौसैनिक संस्थापना

- 9 सितंबर, 2015 को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा कर्नाटक के कारवार (Karwar) में भारतीय नौसेना की नई संस्थापना 'आईएनएस वज्रकोष' (INS Vajrakosh) को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- 600 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तारित इस नौसैनिक स्टेशन का विकास नौसैन्य मिसाइलों एवं आयुधों के भंडारण एवं रखरखाव हेतु विशिष्ट सुविधाओं के साथ किया गया है।
- वस्तुतः निकट भविष्य में कारवार पश्चिमी कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना का एक प्रमुख आधार बनने जा रहा है जहां महत्त्वपूर्ण नौसेना परिसंपत्तियों (युद्धपोतों, पनडुब्बियों आदि) को तैनात रखा जाएगा। कारवार से गतिविधियां चलाने वाली नौसेना इकाइयों के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशिष्ट मिसाइलों एवं हथियारों से लैस किया जाए। इन संवेदनशील मिसाइलों और साजो-सामान के लिए भंडारण की विशेष सुविधाएं और विशिष्ट अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ही आवश्यक संरचनाओं और विशेषज्ञों की उपलब्धता वाले आईएनएस वज्रकोष का निर्माण किया गया है।
- यह कारवार में ही स्थापित भारतीय नौसेना के महत्त्वपूर्ण बेस 'आईएनएस कदंब' से लगभग 20 किमी. की दूरी पर स्थित है जो कि देश के नए विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य सहित अनेक महत्त्वपूर्ण युद्धपोतों का होमपोर्ट भी है। आईएनएस वज्रकोष यहां के युद्धपोतों की शस्त्र आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
- आईएनएस वज्रकोष का निर्माण नौसेना के अत्यंत महत्त्वपूर्ण 'प्रोजेक्ट सीबर्ड' (Project Seabird) के द्वितीय चरण के तहत किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि कारवार में नौसैन्य बेस की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट सीबर्ड को 1999 में स्वीकृति दी गई थी। इसका प्रथम चरण 2005 में पूरा हुआ था तथा बेस (आईएनएस कदंब) को 31 मई, 2005 को कमीशन किया गया था। इसके दूसरे चरण का निर्माण वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया था।
- 9 जून, 2014 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस द्वितीय चरण को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। वस्तुतः प्रोजेक्ट सीबर्ड के द्वितीय चरण के दो भाग हैं, जिसमें फेज-IIA के 2018-19 तथा फेज-IIB के 2024-25 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- कारवार में विशिष्ट रूप से नौसेना को समर्पित बेस की स्थापना का मुख्य कारण पश्चिमी तट पर मुंबई और पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम के बंदरगाहों पर अधिक संकुलन को कम करना है क्योंकि इन दोनों बंदरगाहों पर वाणिज्यिक जहाजरानी गतिविधियों का भी बोझ है। इसके अतिरिक्त मुंबई बंदरगाह की पाकिस्तान से निकटता (उसकी मिसाइलों की जद में होने) को देखते हुए रणनीतिक दृष्टि से भी इस नौसैन्य बेस का निर्माण महत्त्वपूर्ण है।

स्वदेशी तोप 'धनुष' का उन्नत संस्करण

- 16 जुलाई, 2015 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन एम. यमदाग्नि द्वारा कानपुर में अत्याधुनिक स्वदेशी तोप 'धनुष' के उन्नत संस्करण (एडवांस धनुष) का अनावरण किया गया।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा तीन दशक पुरानी बोफोर्स तोपों (स्वीडन से आयातित) का स्थान लेने हेतु एटीएजीएस (ATAGS : Advanced Towed Artillery Gun System) परियोजना के तहत धनुष और उसके उन्नत संस्करण का विकास किया गया है।
- इन स्वदेशी तोपों का डिजाइन डीआरडीओ की पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थापना (ARDE) द्वारा तैयार किया गया है।
- 155 mm/39 कैलिबर की बोफोर्स तोपों की मारक रेंज 28 किमी. ही है जबकि 155 mm/45 कैलिबर की धनुष तोप की मारक रेंज 38 किमी. और 155 mm/52 कैलिबर की एडवांस धनुष की मारक रेंज 42 किमी. है।
- ज्ञातव्य है कि 155 mm/39 कैलिबर से तात्पर्य 155 मिमी. व्यास और 155×39 मिमी. बैरल लंबाई वाली तोप से है। इस प्रकार बोफोर्स तोप के बैरल की लंबाई जहां 6045 मिमी. (लगभग 6 मीटर) ही है, वहीं धनुष तोप के बैरल की लंबाई 6975 मिमी. (लगभग 7 मीटर) और एडवांस धनुष तोप के बैरल की लंबाई 8060 मिमी. (लगभग 8 मीटर) है।
- धनुष और एडवांस धनुष देश की पहली ऐसी तोपें हैं जिनके 90 प्रतिशत उपकरण भारत में ही निर्मित हैं। इस तोप के गोले का वजन 46.5 किग्रा. है तथा यह 2 फायर प्रति मिनट की दर

से दो घंटे तक लगातार तथा 3 फायर प्रति मिनट की दर से डेढ़ घंटे तक लगातार फायर करने में सक्षम है। यह 12 फायर प्रति मिनट भी कर सकती है।

- सेना द्वारा अब तक 414 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया जा चुका है जिनके चरणबद्ध रूप से 2020 तक प्राप्त होने की प्रत्याशा है।
- उल्लेखनीय है कि एडवांस धनुष के विकास के साथ भारत अब अमेरिका, इजरायल और रूस जैसे विशिष्ट देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास 8 मीटर बैरल वाली तोपें हैं।

'आकाश' प्रक्षेपास्त्र वायु सेना एवं थल सेना में शामिल

- 10 जुलाई, 2015 को ग्वालियर के महाराजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा औपचारिक रूप से आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा को सौंपी गई जिन्होंने इसे भारतीय वायु सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की।
- इससे पूर्व 5 मार्च, 2015 को थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग को भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के प्रमुख द्वारा आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से सौंपी गई थी जिन्होंने इस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को कार्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस को समर्पित कर इसे भारतीय थल सेना में शामिल किया।
- भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (DRDO) के एकीकृत निदेशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP; प्रारंभ-1984) के तहत विकसित 5 स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों में 'आकाश' भी शामिल है।
- 96 प्रतिशत स्वदेशी घटकों वाली आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली सभी मौसमों में सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मध्यम दूरी की मिसाइल है जो 25 किमी. की दूरी तक और 20 किमी. की ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को निशाना बना सकने में सक्षम है। यह अपने साथ 60 किग्रा. तक का युद्धशीर्ष (Warhead) 2.5 मैक की सुपरसोनिक गति से ले जा सकता है।
- 720 किग्रा. वजनी और 5.78 मीटर लंबाई वाला यह प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी रडार 'राजेंद्र' की सहायता से अपने लक्ष्य को निशाना बनाता है। राजेंद्र रडार द्वारा निर्देशित आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के माध्यम से एक साथ 64 लक्ष्यों की निगरानी के साथ 4 स्वचालित परस्पर संयुक्त लांचरों से 12 प्रक्षेपास्त्रों के द्वारा 12 लक्ष्यों को समानांतर रूप से भेदा जा सकता है।

भारतीय सेना का म्यांमार अभियान

- 9 जून, 2015 को भारतीय सेना की विशेष कमांडो टुकड़ी द्वारा म्यांमार की सीमा के कुछ किमी. भीतर चलाए गए अपने अभियान के तहत कुल 38 उग्रवादियों को मार गिराया गया तथा 'नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग गुट' (NSCN-K) और 'कांगलेई यावोल कन्ना लुप' (KYKL) के दो शिविरों को भी नष्ट कर दिया गया। यह पहला मौका है जब भारत ने सीमा-पारीय अभियान के तहत ऐसी कार्रवाई की है।
- म्यांमार की सरकार और सेना से समन्वय के साथ भारतीय वायुसेना के सहयोग से सेना की कमांडो टुकड़ी द्वारा नगालैंड के तुएन सांग जिले और मणिपुर के उखरुल जिले से लगी म्यांमार सीमा के भीतर इस अभियान को अंजाम दिया गया।
- इस अभियान में सेना के असम रायफल्स और 21 पैरा स्पेशल फोर्स के 70 कमांडो शामिल थे। इस अभियान में वायुसेना के ध्रुव और एमआई-17 हेलिकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया।
- इस भारतीय सैन्य अभियान में मारे गए उग्रवादी एनएससीएन-के और केवाईकेएल के अतिरिक्त पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से जुड़े बताए गए हैं।
- ज्ञातव्य है कि 4 जून, 2015 को मणिपुर के चंदेल में उग्रवादियों द्वारा भारतीय सेना के 6 डोगरा रेजीमेंट के एक काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले से 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और भारतीय सेना के इस म्यांमार अभियान को उसी की प्रतिक्रिया माना जा रहा है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा लड़ाकू विमान

- 21 मई, 2015 को भारतीय विमानन इतिहास में पहली बार वायुसेना ने किसी सड़क पर लड़ाकू विमान को उतारने का सफल परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज-2000 विमान को सफलतापूर्वक उतारकर यह उपलब्धि हासिल की गई।
- विषम परिस्थिति में लड़ाकू विमान की आपात लैंडिंग के इस अभ्यास के तहत यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्वालियर एयरबेस से उड़े लड़ाकू विमान मिराज-2000 द्वारा 15 मिनट के भीतर दो बार टच लैंडिंग की गई। इस विमान ने लगभग दो किमी. तक एक्सप्रेसवे को रनवे की तरह इस्तेमाल किया और उड़ान भरी तथा फिर आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद पुनः यही प्रक्रिया दोहराई।
- भारतीय वायुसेना की भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों को हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है तथा पाकिस्तान सीमा के निकट गुजरात, राजस्थान और पंजाब में इस प्रकार के 'रोड रनवे' बनाए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में सड़कों का इस प्रकार निर्माण/पुनर्निर्माण किया जाएगा कि उनका हवाई पट्टी के रूप में भी प्रयोग किया जा सके।
- उल्लेखनीय है कि चीन, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में एक्सप्रेसवे और हाइवे पर विमानों की उड़ान और लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी है। पाकिस्तान में भी 2010 में एक अभ्यास के दौरान इस्लामाबाद-लाहौर हाइवे पर दो लड़ाकू जेट विमान उतारे गए थे।

आईएनएस कवरत्ती का जलावतरण

- 19 मई, 2015 को नौसेना के 'प्रोजेक्ट-28' के तहत डिजाइन किए गए स्वदेशी तकनीक से निर्मित चौथे स्टील्थ पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत 'आईएनएस कवरत्ती' (INS Kavaratti) का कोलकाता में जलावतरण (Launch) किया गया।
- आईएनएस कवरत्ती नौसैन्य डिजाइन निदेशालय (DND) द्वारा प्रोजेक्ट 28 के तहत डिजाइन किए गए चार पनडुब्बी-रोधी युद्ध एवं रडार की निगाहों से बचने में सक्षम जंगी पोतों (Corvettes) की श्रृंखला का प्रथम युद्धपोत है जिसमें लगभग 90 प्रतिशत घटक स्वदेशी हैं।
- 109.1 मीटर लंबाई तथा 13.7 मीटर बीम एवं 3,500 टन की विस्थापन क्षमता वाला यह 4 डीजल इंजनों से चालित युद्धपोत 25 नॉट की गति हासिल करने में सक्षम है तथा यह पनडुब्बी-रोधी रॉकेटों एवं टारपीडो, मध्यम और निकट दूरी की शस्त्र प्रणालियों तथा स्वदेशी निगरानी रडार 'रेवती' (Revathi)

से लैस है। इस युद्धपोत का नामकरण संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती के नाम पर किया गया है।

- उल्लेखनीय है कि 'प्रोजेक्ट-28' के तहत डिजाइन एवं निर्मित प्रथम युद्धपोत आईएनएस कामोर्ता का जलावतरण 19 अप्रैल, 2010 को हुआ था तथा 23 अगस्त, 2014 को विशाखापत्तनम नौसेना गोदी पर इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस शृंखला के द्वितीय युद्धपोत आईएनएस कदमत्त का जलावतरण 24 अक्टूबर, 2011 को तथा तीसरे युद्धपोत आईएनएस किलतान का जलावतरण 26 मार्च, 2013 को संपन्न हुआ था।

आईएनएस सरदार पटेल नौसेना में शामिल

- 9 मई, 2015 को भारतीय नौसेना के पोरबंदर (गुजरात) स्थित नवीनतम नौसैन्य बेस 'आईएनएस सरदार पटेल' को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल द्वारा औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया।
- इस नए पूर्ण नौसेना अड्डे के माध्यम से रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गुजरात राज्य की 1,600 किमी. लंबी तटीय सीमा की निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में काफी सहायता मिलेगी।
- गुजरात में भारतीय नौसेना के इस अग्रिम परिचालन बेस (FOB : Forward Operating Base) तथा गुजरात, दीव एवं दमन के नौसैन्य ऑफिसर-इन-चार्ज मुख्यालय के माध्यम से पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा सहित उत्तरी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना इकाइयों को बेहतर लॉजिस्टिक समर्थन उपलब्ध हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि गुजरात में स्थापित यह भारतीय नौसेना का द्वितीय नौसैन्य बेस है। इससे पूर्व ओखा के निकट नौसैन्य बेस 'आईएनएस द्वारका' स्थापित एवं परिचालित है।
- 21 अक्टूबर, 2015 को एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय के तहत महाराष्ट्र एवं गुजरात नौसैन्य क्षेत्र (Naval Area) को दो पृथक मुख्यालयों में विभाजित कर दिया गया है जो कि पृथक फ्लैग ऑफिसरों के तहत होंगे।

आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण

- 20 अप्रैल, 2015 को नौसेना के 'प्रोजेक्ट-15B' के तहत डिजाइन एवं मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा निर्मित किए जा रहे 4 निदेशित प्रक्षेपास्त्र युक्त विध्वंसक स्टील्थ युद्धपोतों की शृंखला के प्रथम युद्धपोत 'आईएनएस विशाखापत्तनम' (INS Visakhapatnam) का जलावतरण किया गया।
- नौसैन्य डिजाइन निदेशालय (DND) द्वारा प्रोजेक्ट-15B के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह 163 मीटर लंबा और 17.4 मीटर बीम वाला विध्वंसक युद्धपोत 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। इसका विस्थापन 7,300 टन है तथा यह 4 गैस टरबाइन इंजनों से चालित है।
- यह युद्धपोत निर्भय क्रूज प्रक्षेपास्त्रों, सुपरसोनिक एंटी-शिप ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्रों तथा सतह से हवा में मार करने वाले बराक-8 ER प्रक्षेपास्त्रों से युक्त होगा तथा इससे दो हेलिकॉप्टरों का भी परिचालन किया जा सकेगा। यह युद्धपोत लंबी दूरी पर स्थित तटीय और समुद्र स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकने में सक्षम होगा।
- इस युद्धपोत के सामुद्रिक परीक्षणों के पूर्ण होने के बाद वर्ष 2018 तक इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने की आशा व्यक्त की गई है।

धनुष प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण

- 9 अप्रैल, 2015 को भारत द्वारा स्वदेशी 'पृथ्वी-II' प्रक्षेपास्त्र के नौसैन्य संस्करण 'धनुष' का ओडिशा तट के निकट बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक पोत से सफल परीक्षण किया गया।
- 8.53 मीटर लंबा तथा 0.9 मीटर व्यास वाला यह एकल चरणीय एवं द्रव प्रणोदक युक्त प्रक्षेपास्त्र सतह से सतह/पोत से पोत पर मार करने वाला है जिसकी मारक क्षमता 350 किमी. है। इस प्रक्षेपास्त्र के द्वारा किसी युद्धपोत से किसी समुद्र स्थित या भूमि स्थित लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है।
- यह बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र पारंपरिक और नाभिकीय दोनों प्रकार के 500-1000 किग्रा. तक युद्धशीर्ष (Warhead) को ले जाने में सक्षम है तथा इसे भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

भारत का अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र अग्नि-V

- भारत द्वारा 31 जनवरी, 2015 को अपने लंबी दूरी के परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (ICBM : Intercontinental Ballistic Missile) अग्नि-V (AGNI-V) का ओडिशा तट के निकट व्हीलर द्वीप स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) 4 से सचल (मोबाइल) प्रक्षेपक के माध्यम से तीसरा सफल परीक्षण किया गया। यह पहला अवसर था जबकि अग्नि-V का प्रक्षेपण कैनिस्टर के माध्यम से किया गया।
- सतह से सतह (Surface to Surface) पर मार करने वाली 17.5 मीटर लंबी तथा 2 मीटर व्यास वाली इस मिसाइल का प्रक्षेपण वजन (Launch Weight) 50 टन है तथा यह 1-1.5 टन तक पारंपरिक और नाभिकीय युद्धशीर्ष (Warhead) अपने साथ ले जा सकने में सक्षम है।
- अग्नि-V एक ठोस ईंधन संचालित त्रिचरणीय रॉकेट मोटर्स से युक्त मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किमी. से अधिक है। यह मात्र 20 मिनट में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है और इस अति उन्नत मिसाइल को कैनिस्टर से सड़क या रेल मोबाइल प्रक्षेपकों के माध्यम से भी छोड़ा जा सकता है।
- अग्नि-V से बीजिंग सहित चीन और लगभग पूरे एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और ऑस्ट्रेलियाई तट तक लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है।
- इसमें अति उत्कृष्ट एवं अत्याधुनिक नैविगेशन प्रणालियों 'RINS' (Ring Laser Gyro based Inertial Navigation System तथा 'MINS' (Micro Navigation System) का प्रयोग किया गया है जो कि लक्ष्य बेधन की शुद्धता एवं अचूकता को काफी परिमार्जित करते हैं।
- अग्नि-V के विकास के साथ भारत आईसीबीएम क्षमता से युक्त विश्व का सातवां देश (अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं इजरायल के बाद) बना है।

'तेजस' : भारतीय सुपरसोनिक एलसीए

- 17 जनवरी, 2015 को भारत के पहले स्वदेश-निर्मित विमान 'तेजस' को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा बंगलुरू में आयोजित समारोह में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया।
- 'तेजस' (Tejas) भारत द्वारा मुख्यतः स्वदेशी तकनीकी से निर्मित चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक एलसीए (LCA-Light

Combat Aircraft) या हल्का लड़ाकू विमान है जो वायु सेना में मिग-21 विमानों का स्थान लेगा।

- इसे अंतिम परिचालनात्मक क्लीयरेंस (FOC-final Operational Clearance) वर्ष 2015 के अंत तक प्राप्त होने की आशा है।
- हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की शाखा वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की टीम ने मिलकर तैयार किया है।
- 13.20 मी. लंबे एलसीए तेजस की ऊंचाई 4.40 मीटर तथा इसके पंखों की लंबाई 8.20 मीटर है। 3,000 लीटर ईंधन क्षमता वाले इस विमान की अधिकतम गति 1.6 मैक (1,350 किमी. प्रति घंटा) है। हथियारों के साथ लगभग 13 टन वजनी यह विमान विश्व के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है। एक विमान की कीमत लगभग 200 करोड़ रु. है।

रक्षा : सैन्याभ्यास

- **स्लिनेक्स-15** : 27 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2015 के मध्य भारत व श्रीलंका की नौसेना के बीच श्रीलंका के त्रिंकोमाली में श्रीलंका-इंडिया एक्सरसाइज (Srilanka-India Exercise-SLINEX) के चौथे संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ। दोनों देशों के मध्य इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी।
- **मालाबार अभ्यास-2015** : 14 से 19 अक्टूबर, 2015 तक भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान की नौसेनाओं ने पूर्वी तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास, 2015 संपन्न किया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1992 से भारत और अमेरिका के मध्य प्रारंभ इस वार्षिक नौसैन्य अभ्यास में इस वर्ष (19वें संस्करण में) पहली बार जापान भी शामिल हुआ। इसमें भारत के आईएनएस सिंधुराज, आईएनएस रणविजय, आईएनएस बेतवा, आईएनएस शिवालिक एवं आईएनएस शक्ति ने प्रतिभाग किया।
- **हैंड इन हैंड** : 12 अक्टूबर, 2015 को भारत और चीन की सेनाओं के मध्य 5वां वार्षिक आंतकवाद निरोधक 12 दिवसीय संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 'हैंड इन हैंड' चीन के यून्नान प्रांत में शुरू हुआ। 23 अक्टूबर, 2015 को यह सैन्य अभ्यास समाप्त हुआ।
- **मित्र शक्ति-2015** : 29 सितंबर, 2015 से 12 अक्टूबर, 2015 तक पुणे के औंध सैन्य शिविर में भारत और श्रीलंका के मध्य तीसरा 14 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'मित्र शक्ति-2015' संपन्न हुआ।
- **ऑसिंडेक्स-15** : 11 से 19 सितंबर, 2015 के मध्य ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास 'ऑसिंडेक्स-15' भारत के पूर्वी तट पर आयोजित हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य बंदरगाह और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतःक्रिया को मजबूत करना था।
- **कोंकण-2015** : 5 से 11 सितंबर, 2015 के मध्य भारतीय नौसेना एवं ब्रिटेन की रॉयल नौसेना के मध्य कोंकण शृंखला के 10वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारत की ओर से 'आईएनएस-त्रिकंड' ने भाग लिया।
- **एक्सरसाइज एकुवेरियन-2015** : 31 अगस्त से 13 सितंबर, 2015 के मध्य भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'एक्सरसाइज एकुवेरिन-2015', पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन त्रिवेंद्रम, केरल में आयोजित हुआ। यह संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज एकुवेरिन का छठां संस्करण था।
- **अजेय वॉरियर-2015** : 13 जून, 2015 से भारत व ब्रिटेन की सेना के मध्य सकारात्मक सैन्य संबंधों के निर्माण के लिए ब्रिटेन के वेस्टडाउन कैम्प, सेलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया में 'अजेय वॉरियर-2015' नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया जो 28 जून, 2015 तक चला। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजीमेंट की एक बटालियन ने भाग लिया।
- **सिम्बेक्स-2015 :** 23 से 26 मई, 2015 के मध्य भारत व सिंगापुर के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'सिम्बेक्स-2015' का आयोजन सिंगापुर में किया गया। भारत की ओर से आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस कामोर्ता तथा पी8 आई विमान ने इसमें भाग लिया। यह नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों के मध्य वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।
- **'वरुण' नौसैनिक अभ्यास :** 23 अप्रैल से 2 मई, 2015 तक भारत और फ्रांस के मध्य 14वां नौसैनिक अभ्यास 'वरुण' गोवा में आयोजित किया गया। यह नौसैनिक अभ्यास पहली बार वर्ष 1983 में आयोजित किया गया था।
- **थीरा वेटा :** 28-29 अप्रैल 2015 के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में 'थीरा वेटा' नामक युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास कोच्चि नौसेना बेस स्थित संयुक्त अभियान केंद्र से संचालित हुआ।
- **खंजर 2015** : भारत और किर्गिस्तान के मध्य मार्च, 2015 में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का द्वितीय संस्करण किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। वर्ष 2011 में इसका प्रथम संस्करण भारत में संपन्न हुआ था। जुलाई, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की किर्गिस्तान यात्रा के दौरान इस संयुक्त सैन्याभ्यास को वार्षिक आधार पर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- **सूर्य किरण VIII** : 23 फरवरी, 2015 को भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण-VIII, समन्वित सैनिक प्रशिक्षण केंद्र सालझंडी, नेपाल में शुरू हुआ। इस सैन्याभ्यास का समापन 8 मार्च, 2015 को हुआ।
- **गरुड़ शक्ति-III** : 22 फरवरी, 2015 को भारत और इंडोनेशिया के सैनिकों के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास 'गरुड़ शक्ति-III' का मिजोरम में समापन हुआ। यह दोनों देशों के मध्य तीसरा संयुक्त सैन्याभ्यास था।
- **हार्ड (HARD) अभ्यास** : 9 फरवरी, 2015 को भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में एक मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HARD) अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में पश्चिमी और पूर्वी बेड़े के 20 से अधिक नौसैन्य पोतों ने भाग लिया।

◆◆◆

विधि एवं न्याय

● राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड ● भारत के 21वें विधि आयोग का गठन ● आंध्र प्रदेश में विशेष न्यायालयों की स्थापना ● बाल विकास व कानूनी अधिकार पर विधि आयोग की रिपोर्ट ● मृत्युदंड पर विधि आयोग की अनुशंसा ● डायन शिकार विधेयक, 2015 ● बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति ● दुष्कर्म मामलों में समझौता गलत : सर्वोच्च न्यायालय ● दिल्ली में उपराज्यपाल-मुख्यमंत्री विवाद ● सरकारी विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय ● कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 ● उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 ● आईटी एक्ट की धारा-66A असंवैधानिक करार

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड

- उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी. लोकुर द्वारा 19 सितंबर, 2015 को 'राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड' का उद्घाटन किया गया। ध्यातव्य है कि यह ग्रिड उस 'ई-कोर्ट परियोजना' का एक हिस्सा है, जो कि न्यायपालिका में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
- 'राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड' न सिर्फ देश भर के जिला न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सूचना देने में सक्षम है, बल्कि यह लंबित मामलों की पहचान, उनका वर्गीकरण एवं उनको कम करने में भी सहायक होगा।
- 'राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड' के जरिए लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके राष्ट्रीय ई-कोर्ट पोर्टल 'E-courts.gov.in' का उपयोग करना होगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी की इस नई सौगात से जहां न्यायिक कार्यों में त्वरितता एवं पारदर्शिता आने की संभावना है, वहीं लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे संबंधी नीतियों के निर्धारण में भी इससे मदद मिलेगी।

भारत के 21वें विधि आयोग का गठन

- 9 सितंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत के 21वें विधि आयोग (21st Law Commission of India) के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।
- इस आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर, 2015 से प्रभावी होकर 31 अगस्त, 2018 तक (कुल 3 वर्ष) का होगा।
- 21वें विधि आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे—
  - (i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
  - (ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (एक सदस्य-सचिव सहित);
  - (iii) विधिक मामलों के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पदेन सदस्य के रूप में; तथा
  - (iv) अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य।
- विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित या स्वतःसंज्ञान के आधार पर विधि संबंधी शोध करेगा और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा ताकि उनमें सुधार किया जा सके और नए कानून लाए जा सकें। इसके अलावा यह न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी को दूर करने, मुकदमों के शीघ्र निपटान और मुकदमों के खर्चों में कमी इत्यादि संबंधी न्याय डिलिवरी प्रणाली में सुधारों हेतु भी अध्ययन और अनुसंधान करेगा।
- विधि आयोग को सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों में शामिल हैं—
  - (a) अब अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की पहचान करना तथा बेकार एवं अनावश्यक कानूनों को रद्द करने की सिफारिश करना।
  - (b) संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति और नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक नए कानूनों को लागू करने के संबंध में सुझाव देना।
  - (c) विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामले विभाग के जरिए सरकार द्वारा संदर्भित विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित विषयों पर सरकार को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराना।
  - (d) सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर किसी विदेशी राष्ट्र के अनुसंधान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पर विचार करना।
  - (e) अपने द्वारा विचार किए गए सभी मुद्दों, विषयों, अध्ययनों और शोध पर केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और इन रिपोर्टों में केंद्र या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों हेतु अनुशंसा करना।
  - (f) अन्य कोई कार्य जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किए जाएं।
- उल्लेखनीय है कि भारत का विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला एक गैर-सांविधिक निकाय (Non-statutory body) है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में (अध्यक्ष-एम.सी.सीतलवाड़) किया गया था तथा प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। 20वें विधि आयोग (अध्यक्ष–न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शाह) का कार्यकाल 31 अगस्त, 2015 तक था। अब तक सभी विधि आयोगों द्वारा कुल मिलाकर 262 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं।
- ज्ञातव्य है कि ब्रिटिश भारत में विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम 1834 में (अध्यक्ष–लॉर्ड मैकाले) किया गया था और तत्पश्चात 1853, 1861 और 1879 में भी विधि आयोग गठित किए गए थे।

आंध्र प्रदेश में विशेष न्यायालयों की स्थापना

- आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा 3 सितंबर, 2015 को 'आंध्र प्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक (Andhra Pradesh Special Courts Bill), 2015' पारित कर दिया गया।
- इससे पूर्व राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने हेतु बिहार के विशेष न्यायालयों के मॉडल पर विशेष न्यायालयों की स्थापना किए जाने को आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 30 अगस्त, 2015 को स्वीकृति दी गई थी।
- इन विशेष न्यायालयों का गठन भ्रष्टाचार के मामलों के समयबद्ध निपटान हेतु किया गया है। ये विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार के मामलों में एक वर्ष के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे।
- इस विधेयक के तहत भ्रष्टाचारी लोक सेवकों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिकवरी और उनका लोक उद्देश्यों एवं राज्य के विकास हेतु उपयोग किए जाने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं।

बाल विकास व कानूनी अधिकार पर विधि आयोग की रिपोर्ट

- 27 अगस्त, 2015 को 20वें विधि आयोग द्वारा केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष 259वीं रिपोर्ट पेश की गई, जिसका शीर्षक है—'बाल विकास और कानूनी अधिकार'।
- इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं बचपन से संबंधित व्यवहारों तथा प्रस्तुत सुझावों द्वारा 6 वर्ष से कम अवस्था वाले बच्चों की स्थिति में सुधार की पेशकश की गई है।
- इस रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 51ए (के) में संशोधन की सिफारिश की गई है, ताकि माता-पिता/अभिभावक एक कर्त्तव्य के रूप में बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकें।
- बचपन के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए इस रिपोर्ट में एक सांविधिक प्राधिकरण अथवा बचपन विकास परिषद का एक क्रम में गठन किए जाने की सिफारिश की गई है।
- रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि देश में 6 वर्ष से कम अवस्था वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को विस्तारित करने के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 21ए में भी संशोधन किया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया है कि 6 वर्ष की अवस्था से कम के प्रत्येक बालक-बालिका को बगैर किसी शर्त के क्रेच और डे केयर सेंटर की देखभाल उपलब्ध कराने हेतु राज्य द्वारा विनियमित एवं संचालित अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

मृत्युदंड पर विधि आयोग की अनुशंसा

- दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.पी.शाह की अध्यक्षता वाले 20वें विधि आयोग ने 'दि डेथ पेनाल्टी' नामक अपनी 262वीं रिपोर्ट में 27 अगस्त, 2015 को सरकार से यह सिफारिश की है कि मृत्युदंड आतंकवाद से जुड़े अपराधों एवं देश के खिलाफ जंग छेड़ने के अपराधों में ही दिया जाए। इसे इसलिए आवश्यक बताया गया है कि ऐसा न किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी। ध्यातव्य है कि वर्ष 1962 में विधि आयोग ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड को जारी रखने की अनुशंसा की थी।
- इस रिपोर्ट के अनुसार मृत्युदंड से अपराध निवारण के लिए कोई दंडात्मक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसमें निकट भविष्य में सभी क्षेत्रों में शीघ्र-से-शीघ्र मृत्युदंड को समाप्त किए जाने के लिए चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इस रिपोर्ट में मृत्युदंड के 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (Rarest of Rare) के सिद्धांत को भी प्रश्नगत किया गया है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम भारत संघ के प्रकरण में यह कह कर मृत्युदंड की संवैधानिकता को स्थापित किया था कि यह दंड दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
- दुर्लभतम से दुर्लभ के सिद्धांत पर विधि आयोग की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई है कि मृत्युदंड 'दुर्लभतम से दुर्लभ' के सीमित माहौल के भीतर भी संवैधानिक तौर पर टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि सजा-ए-मौत को लगातार दिया जाना अत्यंत कठिन संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है।

डायन शिकार विधेयक, 2015

- असम राज्य में डायन के शक में लोगों को मारे जाने की कुरीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वहां की विधान सभा द्वारा 13 अगस्त, 2015 को 'डायन शिकार विधेयक, 2015' (Witch Hunting Act, 2015) पारित किया गया।
- इस कुरीति के विरुद्ध यह एक कड़ा कानून है, जिसमें किसी व्यक्ति को डायन बताने पर जहां 3 से 7 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है, वहीं किसी व्यक्ति को डायन बताकर उसे आत्महत्या के लिए बाध्य किए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
- ध्यातव्य है कि इस विधेयक को पारित करवाने में असम की बिरूबाला रामा नामक उस महिला का योगदान महत्वपूर्ण रहा, जिसके पुत्र की हत्या वर्ष 1996 में डायन के शक में की गई थी।

बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

- गुजरात के साबरकांथा की एक 14 वर्षीया बलात्कार पीड़िता अल्पवयस्क बालिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'जीवन के अधिकार' को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी गई। अनुमति मिलने के बाद 31 जुलाई, 2015 को गर्भवती बालिका के 25 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात चिकित्सकों द्वारा किया गया।
- ध्यातव्य है कि बलात्कार पीड़िता बालिका की तरफ से गुजरात उच्च न्यायालय से गर्भपात की अनुमति मांगी गई थी, क्योंकि वह होने वाले शिशु के पालन-पोषण के लिए शारीरिक, भावनात्मक एवं आर्थिक स्तरों पर सक्षम नहीं थी।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में 'गर्भकाल की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम, 1971' (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) का हवाला देते हुए गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि इसमें विशेष परिस्थितियों में 20 सप्ताह के भ्रूण के ही गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई है।
- गुजरात उच्च न्यायालय से अनुमति न मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार के बाद गर्भवती होना और ऐसे बच्चे को जीवनभर पालना एक बड़े सदमे जैसा है। इस प्रकार 'जीवन के अधिकार' को ध्यान में रखकर शीर्ष अदालत द्वारा गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई।

दुष्कर्म मामलों में समझौता गलत : सर्वोच्च न्यायालय

- 1 जुलाई, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि दुष्कर्म मामलों में दोषी और पीड़िता के विरुद्ध मध्यस्थता अथवा उदार दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास पीड़िता के सम्मान के खिलाफ और त्रुटिपूर्ण है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में मध्य प्रदेश सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अदालत द्वारा मध्यस्थता और सुलह करने का निर्देश दिया जाना असाधारण त्रुटि है।
- सर्वोच्च न्यायालय का सद्यः निर्णय दुष्कर्म मामलों में मध्यस्थता की सोच पर रोक लगाता है। इस मामले में मध्य प्रदेश की एक निचली अदालत ने दुष्कर्ष के दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को पीड़िता के माता-पिता एवं अभियुक्त के समझौते के आधार पर कम करके जेल में बिताए समय को समायोजित करने का फैसला दिया था जिसे राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई सबूतों को पूरी तरजीह देते हुए नए सिरे से करने का आदेश दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे मामलों में मध्यस्थता या सुलह-सफाई का न्यायालय द्वारा मौका दिया जाना पीड़िता के सम्मान के विरुद्ध है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी दुष्कर्म के एक मामले में मध्यस्थता और समझौते की संभावनाओं को देखते हुए सजा भुगत रहे अभियुक्त को पीड़िता से सुलह के लिए जमानत दी थी।

दिल्ली में उपराज्यपाल-मुख्यमंत्री विवाद

- मई, 2015 में नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मध्य गहन विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा।
- तत्पश्चात 21 मई, 2015 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि नौकरशाहों की नियुक्ति जैसे मामलों में उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से सलाह लेना अनिवार्य नहीं है।
- इस अधिसूचना के अनुसार लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और सेवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की विधान सभा के दायरे से बाहर हैं और उपराज्यपाल के क्षेत्राधिकार में हैं तथा वह सेवाओं से जुड़े विषयों में अपने 'विवेक' से आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से सलाह ले सकते हैं।
- साथ ही इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB : Anti-Corruption Bureau) केंद्र सरकार की सेवाओं वाले अधिकारियों के विरुद्ध मामलों का संज्ञान नहीं लेगी।
- 25 मई, 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए केंद्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना को 'संशयित' (Suspect) कहा और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दिल्ली सरकार के तहत तैनात सभी अधिकारियों के भ्रष्टाचार मामलों की जांच के अधिकार को बहाल कर दिया।
- केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निरीक्षण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है।
- वस्तुतः दिल्ली का उपराज्यपाल-मुख्यमंत्री विवाद राजनीतिक से कहीं अधिक संवैधानिक शक्तियों का विवाद है जिसके मूल में दोनों पक्षों द्वारा अपने दृष्टिकोण से परिस्थितियों का अवलोकन तथा दिल्ली की संविधान के तहत विशिष्ट स्थिति है।
- 1991 में <u>69वें संविधान संशोधन</u> के तहत संविधान में अनुच्छेद <u>239 AA</u> और <u>239 AB</u> के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया तथापि भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था को दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर रखा गया।
- यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दिल्ली वास्तव में पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि वह विधान सभा वाला संघीय क्षेत्र या अर्द्धराज्य ही है तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विधान सभा द्वारा किसी विषय पर बनाई गई विधि पर संसद की विधि अभिभावी होती है। दूसरी ओर, जहां तक दिल्ली में उपराज्यपाल के विवेकाधिकारों का प्रश्न है, चूंकि भूमि, पुलिस एवं लोक व्यवस्था दिल्ली विधान सभा के दायरे से बाहर हैं, वहां और उस सीमा तक उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने विवेक अनुसार कार्य करने में विधान सभा या मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र भी है।
- तथापि यदि अनुच्छेद 239AA के खंड (4) के 'सहायता एवं सलाह' को राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 163 (जिसमें राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान है) के समकक्ष माना जाए तो भी दिल्ली विधान सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों में यह समुचित नहीं होगा।
- कुल मिलाकर अब इस संवैधानिक शक्तियों के विवाद पर अंतिम निर्णय न्यायपालिका को ही करना है और तब तक दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे, इस हेतु दिल्ली के उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मध्य सामंजस्य अपेक्षित है।

सरकारी विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय

- 13 मई, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय देते हुए सरकारी विज्ञापनों में मंत्रियों और नेताओं की तस्वीर लगाए जाने पर रोक लगा दी। शीर्ष न्यायालय के अनुसार सरकारी विज्ञापनों में अब केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश की ही तस्वीर लगाई जा सकेगी और वह भी उनकी स्वीकृति के बाद ही लग सकेगी।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय सीपीआईएल और कॉमनकाज द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया गया है। इस याचिका में कहा गया था कि सरकार चला रही पार्टियां सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से राजनीतिक लाभ प्राप्त करती हैं। याचिका में सरकारी विज्ञापन सामग्री को नियंत्रित करने हेतु व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका के आधार पर गत वर्ष सरकारी विज्ञापनों के बारे में दिशा-निर्देश तय करने हेतु एक समिति गठित की थी जिसने अन्य संस्तुतियों के साथ यह सुझाव दिया था कि सरकारी विज्ञापन में पार्टी का नाम, पार्टी का प्रतीक चिह्न/झंडा या पार्टी नेता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त समिति के इस सुझाव से असहमति व्यक्त की कि राज्य में राज्यपाल या मुख्यमंत्री की तस्वीर सरकारी विज्ञापनों में लगाने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार राज्य सरकारों के सरकारी विज्ञापन भी इस निर्णय की परिधि में शामिल हैं।
- हालांकि न्यायालय ने दिवंगत नेताओं की वर्षगांठ या स्मृति में जारी होने वाले विज्ञापनों में उनकी तस्वीर लगाए जाने की अनुमति दी है।
- इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि वह 3-सदस्यीय समिति (जिसके सदस्य असंदिग्ध निष्ठा वाले और तटस्थ व्यक्ति हों) बनाए जो यह देखेगी कि सरकारी विज्ञापनों में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015

- 25 मई, 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु विधेयक को 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015' [Companies (Amendment) Act, 2015] के रूप में 26 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत 2013 के कंपनी अधिनियम में कुल 16 संशोधन किए गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य देश में कारोबारी माहौल को सतत और सुचारु बनाना है। इसके माध्यम से किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं—

  (a) व्यापार करने की सुगमता हेतु प्राइवेट कंपनियों के मामलों में 1 लाख रु. तथा सार्वजनिक कंपनियों के मामलों में 5 लाख रु. की न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी (Minimum Paid up Share Capital) की अपेक्षा को हटाना और तत्संबंधी परिवर्तन।

  (b) मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कार्पोरेट मांग के अनुरूप रजिस्ट्री में फाइल किए गए बोर्ड प्रस्तावों के सार्वजनिक निरीक्षण या जांच पर प्रतिबंध।

  (c) विशेष न्यायालयों द्वारा केवल 2 वर्ष या अधिक के कारावास वाले अपराधों की सुनवाई हेतु प्रावधान ताकि छोटे अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सके। साथ ही गंभीर आपराधिक मामलों तथा घोटालों के अतिरिक्त अन्य मामलों में जमानत के प्रावधानों को सरल किया गया है।

  (d) गैर-संबंधित शेयरधारकों द्वारा संबंधित पक्ष हस्तांतरणों (Related Party Transactions) की स्वीकृति के लिए 'विशेष प्रस्ताव' के स्थान पर 'साधारण प्रस्ताव' की व्यवस्था।

  (e) होल्डिंग कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों के मध्य संबंधित पक्ष हस्तांतरणों को गैर-संबंधित शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता से छूट।

  (f) सेबी (SEBI) की नीतियों के अनुरूप व्यवसाय सुगमता के लिए संबंधित पक्ष हस्तांतरणों को वार्षिक आधार पर बहुप्रयोजन स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए लेखा (Audit) समिति को सशक्त करने हेतु प्रावधान।

  (g) प्रवंचनाओं (Frauds) के केंद्र सरकार को रिपोर्ट किए जाने के लिए सीमा रेखा के निर्धारण हेतु प्रावधान जिससे नीचे की प्रवंचनाओं को लेखा समिति को रिपोर्ट किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

- 24 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद 'उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015' ध्वनि मत से पारित हो गया।
- 'उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015' के माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के विलय का प्रावधान किया गया है।
- इस विधेयक में नगर पंचायत अध्यक्ष को 'सभापति' पद नाम दिए जाने का प्रावधान है।
- विधेयक के प्रावधानों के तहत नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की ही तरह नगर निगमों के महापौर को भी सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और दोषी पाए जाने पर उसे भी सरकार द्वारा हटाए जा सकने की व्यवस्था की गई है।
- इस संशोधन विधेयक के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर क्रमशः 5 लाख रु. और 1 लाख रु. कर दिए गए हैं, जबकि नगर निगम के महापौर का वित्तीय अधिकार 15 लाख रु. ही रखा गया है।

आईटी एक्ट की धारा-66A असंवैधानिक करार

- 24 मार्च, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिद्वय जे. चेलमेश्वर और आर.एफ. नरीमन की पीठ द्वारा दिल्ली की विधि छात्रा श्रेया सिंघल एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट)' की धारा-66A को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करती है। न्यायालय के अनुसार इंटरनेट की व्यापक पहुंच अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकती है और न ही इस आधार पर इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि आईटी एक्ट की धारा-66A हाल के वर्षों में काफी विवादित रही थी। यह धारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करने की शक्ति देती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में हालांकि सरकार को इस बात की अनुमति दी है कि वह उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकती है जो साम्प्रदायिक तनाव या सामाजिक वैमनस्य फैला रही हों अथवा दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करती हों।
- इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के तहत आईटी एक्ट की धारा-69A और 79 को कुछ शर्तों के साथ संवैधानिक भी ठहराया। ज्ञातव्य है कि धारा-69A किसी कंप्यूटर से कोई सूचना सार्वजनिक करने से रोकने के निर्देश जारी करने की शक्ति देती है जबकि धारा-79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती की जवाबदेही से छूट का प्रावधान है।

लोढ़ा समिति का आईपीएल पर निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 जुलाई, 2015 को अपना निर्णय जारी करते हुए गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा पर क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही समिति ने आईपीएल में इंडिया सीमेंट्स की फ्रेंचाइजी टीम 'चेन्नई सुपरकिंग्स' तथा जयपुर आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम 'राजस्थान रॉयल्स' को 2 वर्ष के लिए आईपीएल से प्रतिबंधित करने का भी निर्णय दिया है। 18 अक्टूबर, 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा इस निर्णय के अनुसरण में 'चेन्नई सुपरकिंग्स' और 'राजस्थान रॉयल्स' को दो वर्षों (2016 एवं 2017) हेतु आईपीएल से निलंबित करने तथा इनके स्थान पर दो नई आईपीएल फ्रेंजाइची टीमों का गठन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने की घोषणा की गई है।

◆◆◆

प्राकृतिक आपदाएं

हिंदुकुश का भीषण भूकंप

- 26 अक्टूबर, 2015 को दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजकर 39 मिनट पर भीषण भूकंप आया।
- इस भूकंप का परिमाण (Magnitude) मूमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर 7.5 Mw था तथा इसका अधिकेंद्र (Epicentre) अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 250 किमी. दूर बदख्शां प्रांत के जुर्म इलाके में 'अलाकाहदारी- या किरन वा मुंजान' के 45 किमी. उत्तर में 212.5 किमी. गहराई में था। इसकी तीव्रता मरकेली स्केल पर VI (Strong) आंकी गई।
- इस भूकंप के झटके भारत के दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर तक अनुभव किए गए।
- इस भूकंप के कारण लगभग 400 लोग मारे गए जिनमें हताहतों की सर्वाधिक संख्या पाकिस्तान में रही। इसके कारण लगभग 2700 लोग घायल भी हुए। भारत में भी इसके फलस्वरूप 4 लोगों की मृत्यु हुई।
- इससे पूर्व इसी क्षेत्र में 2005 में आए 7.6 Mw परिमाण के भूकंप के कारण 87,351 मृत्युएं हुई थीं तथापि उस भूकंप की गहराई काफी कम (मात्र 15 किमी.) थी।

भारत में प्रचंड ग्रीष्म लहर

- मई-जून, 2015 के दौरान भारत का काफी हिस्सा प्रचंड ग्रीष्म लहर की चपेट में रहा। इस दौरान देश भर में भीषण गर्मी और लू के कारण 2,500 से अधिक लोग मारे गए।
- उल्लेखनीय है कि भारत में 1990 से अब तक 20,000 से अधिक व्यक्ति गर्मी से संबंधित कारणों से मृत्यु का शिकार हुए हैं परंतु इस वर्ष गर्मी से हुई मौतों की संख्या 1979 के बाद सर्वाधिक रही।
- इस भीषण गर्मी में अधिकतम तापमान खम्माम में 48^0C रिकॉर्ड हुआ जबकि इलाहाबाद 47.8^0C तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 40^0C से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30^0C से अधिक वायु तापमान की स्थिति ग्रीष्म लहर के रूप में वर्गीकृत की जाती है।
- वर्ष 2015 की इस प्रचंड ग्रीष्म लहर के कारण सर्वाधिक मृत्युएं आंध्र प्रदेश में (1,735 से अधिक) दर्ज हुईं जबकि इसके बाद तेलंगाना में (585 से अधिक) मौतें हुईं। ओडिशा में 35, उत्तर प्रदेश में 22 तथा प. बंगाल में 13 लोग इस भीषण गर्मी के शिकार हुए।
- जून, 2015 में पाकिस्तान में भी प्रचंड ग्रीष्म लहर का प्रकोप रहा जिसमें 1,400 से अधिक लोग मारे गए। वहां सिंध, दक्षिणी पंजाब एवं बलूचिस्तान इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहे।
- इस भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा गर्मी को भी प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत कोई भी राज्य सरकार चाहे तो गर्मी से होने वाली मौतों और अन्य नुकसान के लिए राज्य आपदा राहत कोष से सहायता दे सकती है तथा राज्यों के पास उपलब्ध आपदा राहत कोष का 10 प्रतिशत तक इस पर व्यय किया जा सकता है।
- 1 जुलाई, 2015 को विश्व के कई देशों में लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी पहली बार इसके खतरों का संज्ञान लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए विभिन्न देशों को इसके खतरे से सतर्क रहने के लिए कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने संयुक्त रूप से गर्मी से होने वाले खतरों को लेकर चेतावनी की व्यवस्था स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- जलवायु संबंधी आंकड़ों के अनुसार मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2014 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा था। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्रीय एवं वातावरण प्रशासन (NOAA) के अनुसार वर्ष 2015 के इससे भी गर्म वर्ष सिद्ध होने का आकलन है।

नेपाल का विनाशकारी भूकंप

- 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में स्थानीय समयानुसार सुबह 11.56 (भारतीय समयानुसार सुबह 11.41) पर भीषण भूकंप आया जिसका परिमाण (Magnitude) मूमेंट मैग्नीट्यूड स्केल (Mw) पर 7.8 तथा तीव्रता (Intensity) मरकेली स्केल पर उच्चतम (IX) थी।
- इस भूकंप का अधिकेंद्र (Epicenter) काठमांडू से लगभग 80 किमी. उत्तर-पश्चिम में लामजुंग जिले में 34 किमी. पूर्व में था जबकि इसका अंतःकेंद्र (Hypocenter) मात्र 15 किमी. की गहराई में था (जिसके कारण यह अधिक घातक सिद्ध हुआ)।
- इस भीषण भूकंप के विनाशकारी झटके लगभग 50 सेकेंड तक नेपाल के साथ-साथ तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान और भारत के प. बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों तक अनुभव किए गए।
- इस भीषण भूकंप के बाद उसी दिन 4.5 Mw या अधिक परिमाण के 38 से अधिक पश्चातवर्ती झटके (Aftershocks) दर्ज किए गए। इसके बाद भी कई दिन तक पश्चातवर्ती झटके अनुभव किए गए।
- इस विनाशकारी भूकंप से नेपाल में भारी तबाही हुई। इससे नेपाल में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8,857 लोग मारे गए और 22,304 लोग घायल हुए। नेपाल में इस भूकंप में मृत व्यक्तियों में 89 विदेशी नागरिक भी थे जिनमें सर्वाधिक क्रमशः भारत (40), फ्रांस (10) तथा स्पेन एवं ब्रिटेन (दोनों के 7-7) के थे।
- नेपाल में आए इस भूकंप से भारत में 130 (सर्वाधिक बिहार के), चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 27 तथा बांग्लादेश में 4 व्यक्ति मारे गए। इसके अतिरिक्त घायलों की संख्या भारत में 560, चीन में 383 तथा बांग्लादेश में 200 रही।

- इस भूकंप के फलस्वरूप माउंट एवरेस्ट में उत्पन्न हिमस्खलनों (Avalanches) के कारण भी 19 लोग मारे गए तथा कम से कम 120 घायल हुए। साथ ही लांगटांग (Langtang) घाटी में भी हिमस्खलनों के कारण 329 लोगों के लापता होने की बात सामने आई।
- नेपाल का यह भीषण भूकंप वर्ष 1934 के नेपाल-बिहार भूकंप (जिसमें 10 हजार से अधिक लोग मारे गए थे) के बाद वहां आई सर्वाधिक भयावह प्राकृतिक आपदा सिद्ध हुआ।
- इस भूकंप एवं पश्चातवर्ती झटकों के फलस्वरूप नेपाल के 80 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस भीषण भूकंप के कारण काठमांडू घाटी स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दरबार चौक, 1832 में निर्मित धरहरा टॉवर, स्वयंभूनाथ स्तूप आदि कई विख्यात इमारतें धराशायी या क्षतिग्रस्त हो गईं।
- इस भूकंप के कारण नेपाल में कुल 5 बिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक क्षति होने का आकलन है जो वहां के जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत है।
- 12 मई, 2015 को स्थानीय समयानुसार 12.51 पर नेपाल में पुनः 7.3 Mw परिणाम का बड़ा आफ्टरशॉक आया जिसका अधिकेंद्र कोडारी के 18 किमी. दक्षिण-पूर्व में (नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट दोलखा और सिंधुपाल चौक जिलों के मध्य) था। इनके कारण भी कुल 218 (जिनमें 62 भारत में) लोग मारे गए तथा 3,500 से अधिक लोग घायल हुए।
- नेपाल में 25 अप्रैल को आए भयावह भूकंप के तत्काल बाद सर्वप्रथम भारत द्वारा राहत एवं बचाव कार्य राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF), भारतीय सेना एवं वायुसेना के माध्यम से प्रारंभ किए गए जिसे 'ऑपरेशन मैत्री' के तहत समेकित किया गया था। 4 जून, 2015 तक चले इस अभियान के द्वारा 11,200 लोगों (780 मृतकों सहित) को बचाया/निकाला गया तथा लगभग 1700 टन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई गई।
- नेपाली सेना द्वारा वहां के अन्य सुरक्षा बलों के साथ राहत एवं बचाव कार्य हेतु 'ऑपरेशन संकटमोचन' चलाया गया था। चीन एवं अमेरिका सहित विश्व के 30 से अधिक देशों तथा रेडक्रॉस एवं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने भी नेपाल में राहत एवं बचाव कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नेपाल को अगले 3 माह में 423 मिलियन डॉलर की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करने संबंधी प्रस्ताव 15 मई, 2015 को पारित किया गया। यह प्रस्ताव भारत द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था।
- तदनुसार, 25 जून, 2015 को काठमांडू में 'अंतर्राष्ट्रीय दानदाता सम्मेलन' का आयोजन किया गया जिसमें भारत सहित 60 देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नेपाल में तत्काल सहायता और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के संदर्भ में वचनबद्धताएं व्यक्त की गईं।

नेपाल भूकंप से माउंट एवरेस्ट में विचलन

25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आया 7.8 Mw परिमाण का भीषण भूकंप इतना अधिक शक्तिशाली था कि इसने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 'माउंट एवरेस्ट' को अपने स्थान से भौतिक रूप से 3 सेंटीमीटर या लगभग 1.2 इंच खिसका दिया है। चीन के उपग्रह आधारित आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि माउंट एवरेस्ट का यह विचलन दक्षिण-पश्चिम दिशा में हुआ है। उल्लेखनीय है कि भूगर्भीय प्लेटों की गतियों के कारण (इंडियन एवं यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप) माउंट एवरेस्ट 2005 से 2015 के मध्य के आंकड़ों के आधार पर सामान्य रूप से प्रति वर्ष 4 सेमी. या लगभग 1.6 इंच की दर से उत्तर-पूर्व दिशा में खिसकता पाया गया है तथा इस भूकंप के कारण कुछ ही सेकेंड में इसका लगभग 9 माह का विचलन रिवर्स हो गया। हालांकि इस भूकंप के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं दर्ज हुआ है (जो कि सामान्यतः लगभग 0.1 इंच प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है)।

अन्य नवीनतम आपदाएं

- **उष्णकटिबंधीय तूफान 'पैट्रीशिया'** : अक्टूबर, 2015 के मध्य में आए उष्णकटिबंधीय तूफान 'पैट्रीशिया' से मध्य अमेरिका में भारी बारिश हुई। इसके अतिरिक्त 'ग्वाटेमाला', अल सल्वाडोर, निकारागुआ तथा मेक्सिको में भी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके चलते सैकड़ों घर नष्ट हुए तथा 12 लोगों की मृत्यु हुई।
- **टॉयफून कोप्पू** : अक्टूबर, 2015 में फिलीपींस 'कोप्पू' (Koppu) नामक टायफून से गहन प्रभावित हुआ। इससे लगभग 24 हजार लोग प्रभावित हुए। इसके कारण 57 लोगों की मृत्यु हो गई तथा इससे 211.8 मिलियन डॉलर की आर्थिक क्षति होने का आकलन है।
- **'मुजिगी' तूफान** : 7 अक्टूबर, 2015 को चीन के गुआंगदोंग प्रांत में आए 'मुजिगी' नामक तूफान के कारण 19 लोगों की मृत्यु हो गई तथा तकरीबन 35 लाख लोग प्रभावित हुए।
- **माउंट आसो सक्रिय हुआ** : 14 सितंबर, 2015 को जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट आसो सक्रिय हो उठा। यह ज्वालामुखी पर्वत जापान के क्युशु द्वीप पर स्थित है जो जापान की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी चोटियों में से एक है।
- **टायफून इताउ** : 9 सितंबर, 2015 को जापान के पूर्वी भाग में आये टायफून इताउ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
- **उष्णकटिबंधीय तूफान 'एरिका'** : अगस्त, 2015 के अंत में उष्णकटिबंधीय तूफान 'एरिका' के कहर से कैरेबियन द्वीप डोमिनिका में कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लापता हो गए।
- **चक्रवाती तूफान 'कोमेन'** : 30 जुलाई, 2015 को आए चक्रवाती तूफान 'कोमेन' से बांग्लादेश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी बुरी तरह जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए।

◆◆◆

रिपोर्टें/सूचकांक

रिपोर्ट/सूचकांक	जारीकर्ता संस्था/संगठन (जारी करने की तिथि)	सम्मिलित देश/ अर्थव्यवस्थाएं	शीर्ष स्थान वाले देश	निम्नतम स्थान वाले देश	भारत का स्थान/रैंक	भारत के पड़ोसी देशों के स्थान/रैंक
लेगाटम समृद्धि सूचकांक (Legatum Prosperity Index-LPI), 2015	लेगाटम इंस्टीट्यूट -2 नवंबर, 2015	142	1. नार्वे 2. स्विट्जरलैंड 3. डेनमार्क 4. न्यूजीलैंड 5. स्वीडन	142. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 141. अफगानिस्तान 140. हैती 139. चॉड 138. बुरुंडी	99	52. चीन 61. श्रीलंका 89. नेपाल 103. बांग्लादेश 130. पाकिस्तान
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, 2015	विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम-28 अक्टूबर, 2015	189	1. सिंगापुर 2. न्यूजीलैंड 3. डेनमार्क 4. द. कोरिया 5. हांगकांग	189. द. सूडान 188. लीबिया 187. इरीट्रिया	130	84. चीन 99. नेपाल 107. श्रीलंका 138. पाकिस्तान 174. बांग्लादेश
ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स 2015	हेल्पएज इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष -अक्टूबर, 2015	96	1. स्विट्जरलैंड 2. नार्वे 3. स्वीडन 4. जर्मनी 5. कनाडा	96. अफगानिस्तान 95. मलावी 94. मोजांबिक 93. वेस्ट बैंक और गाजा	71	46 श्रीलंका 52. चीन 70. नेपाल 92. बांग्लादेश
वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index-GHI) 2015	इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) -13 अक्टूबर, 2015	104	1. कुवैत 2. सऊदी अरब 3. तुर्की 4. स्लोवाक रिपब्लिक 5. रोमानिया	104. से. अफ्रीकन रि. 103. चाड 102. जाम्बिया 101. तिमोर लेस्ते	80	21. चीन 58. नेपाल 65. म्यांमार - 69. श्रीलंका 93. पाकिस्तान
वैश्विक नवाचार सूचकांक-2015 (Global Innvoation Index-2015)	कारनेल विश्वविद्यालय एवं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) -17 सितंबर, 2015	141	1. स्विट्जरलैंड 2. यू.के. 3. स्वीडन 4. नीदरलैंड्स 5. यूएसए	141. सूडान 140. टोगो 139. गिनी 138. म्यांमार 137. यमन	81	29. चीन 85. श्रीलंका 121. भूटान 129. बांग्लादेश 131. पाकिस्तान 135. नेपाल
बिजनेस ग्रोथ इनवॉयरमेंट-2015	ग्रांट थार्नटन -16 सितंबर, 2015	60	1. सिंगापुर 2. इजरायल 3. ऑस्ट्रेलिया 4. फिनलैंड 5. स्वीडन	60. अल्जीरिया 59. नाइजीरिया 58. अर्जेंटीना 57. वेनेजुएला 56. यूक्रेन	34	14. चीन 55. पाकिस्तान
वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index-GPI), 2015	इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस -17 जून, 2015	162	1. आइसलैंड 2. डेनमार्क 3. ऑस्ट्रिया 4. न्यूजीलैंड 5. स्विट्जरलैंड	162. सीरिया 161. इराक 160. अफगानिस्तान 159. द. सूडान 158. मध्य अफ्रीकी गणराज्य	143	18. भूटान 62. नेपाल 84. बांग्लादेश 114. श्रीलंका 124. चीन 130. म्यांमार 154. पाकिस्तान

रिपोर्ट/सूचकांक	जारीकर्ता संस्था/संगठन (जारी करने की तिथि)	सम्मिलित देश/ अर्थव्यवस्थाएं	शीर्ष स्थान वाले देश	निम्नतम स्थान वाले देश	भारत का स्थान/रैंक	भारत के पड़ोसी देशों के स्थान/रैंक
अस्थिर राष्ट्र सूचकांक (Fragile State Index), 2015	फॉरेन पॉलिसी और दि फंड फॉर पीस-जून, 2015	178	1. दक्षिणी सूडान 2. सोमालिया 3. मध्य अफ्रीकी गणराज्य 4. सूडान 5. डी.आर. कांगो (सर्वाधिक अस्थिर देश)	178. फिनलैंड 177. स्वीडन 176. नार्वे 175. डेनमार्क 174. लक्जमबर्ग (सर्वाधिक स्थिर देश)	68	8. अफगानिस्तान 13. पाकिस्तान 32. बांग्लादेश 34. श्रीलंका 36. नेपाल 74. भूटान 83. चीन
मदर इंडेक्स (Mother Index), 2015	सेव दि चिल्ड्रेन द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ दि वल्ड्र्स मदर्स रिपोर्ट' में प्रस्तुत-5 मई, 2015	179	1. नार्वे 2. फिनलैंड 3. आइसलैंड 4. डेनमार्क 5. स्वीडन	179. सोमालिया 178. डीआर कांगो 177. मध्य अफ्रीकी गणराज्य 176. माली 175. नाइजर	140	61. चीन 92. श्रीलंका 114. नेपाल 122. भूटान 130. बांग्लादेश 149. पाकिस्तान 152. अफगानिस्तान
विश्व प्रसन्नता सूचकांक (World Happiness Index), 2015	यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (UNSDSN) - 23 अप्रैल, 2015	158	1. स्विट्जरलैंड 2. आइसलैंड 3. डेनमार्क 4. नार्वे 5. कनाडा	158. टोगो 157. बुरुंडी 156. सीरिया 155. बेनिन 154. रवांडा	117	79. भूटान 81. पाकिस्तान 84. चीन 109. बांग्लादेश
नेटवर्क्ड रेडिनेस इंडेक्स (Networked Readiness Index-NRI), 2015	विश्व आर्थिक मंच (WEF) एवं इनसीड (INSEAD) - 15 अप्रैल, 2015	143	1. सिंगापुर 2. फिनलैंड 3. स्वीडन 4. नीदरलैंड्स 5. नार्वे	143. चाड 142. गिनी 141. बुरुंडी 140. अंगोला 139. म्यांमार	89	62. चीन 65. श्रीलंका 88. भूटान 112. पाकिस्तान 109. बांग्लादेश 118. नेपाल
सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index), 2015	सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव (SPI), अमेरिका - 8 अप्रैल, 2015	133	1. नार्वे 2. स्वीडन 3. स्विट्जरलैंड 4. आइसलैंड 5. न्यूजीलैंड	133. मध्य अफ्रीकी गणराज्य 132. चाड 131. अफगानिस्तान 130. गिनी 129. अंगोला	101	88. श्रीलंका 98. नेपाल 100. बांग्लादेश 122. पाकिस्तान
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index), 2015	रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस-12 फरवरी, 2015	180	1. फिनलैंड 2. नार्वे 3. डेनमार्क 4. नीदरलैंड 5. स्वीडन	180. इरीट्रिया 179. उ. कोरिया 178. तुर्कमेनिस्तान 177. सीरिया 176. चीन	136	104. भूटान 105. नेपाल 122. अफगानिस्तान 146. बांग्लादेश 159. पाकिस्तान 165. श्रीलंका
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Economic Freedom Index - EFI), 2015	दि हेरिटेज फाउंडेशन एवं वाल स्ट्रीट जर्नल - 27 जनवरी, 2015	178	1. हांगकांग 2. सिंगापुर 3. न्यूजीलैंड 4. ऑस्ट्रेलिया 5. स्विट्जरलैंड	178. उ. कोरिया 177. क्यूबा 176. वेनेजुएला 175. जिम्बाब्वे 174. इरीट्रिया	128	101. श्रीलंका 115. भूटान 121. पाकिस्तान 131. बांग्लादेश 139. चीन 152. नेपाल

रिपोर्ट/सूचकांक	जारीकर्ता संस्था/संगठन (जारी करने की तिथि)	सम्मिलित देश/ अर्थव्यवस्थाएं	शीर्ष स्थान वाले देश	निम्नतम स्थान वाले देश	भारत का स्थान/रैंक	भारत के पड़ोसी देशों के स्थान/रैंक
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index-CPI)	ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI)- 3 दिसंबर, 2014	175	1. डेनमार्क 2. न्यूजीलैंड 3. फिनलैंड, 4. स्वीडन 5. नार्वे	174 सोमालिया, उत्तर कोरिया 173. सूडान 172. अफगानिस्तान 171. दक्षिणी सूडान	85	30. भूटान 85. श्रीलंका 100. चीन 126. नेपाल 126. पाकिस्तान 145. बांग्लादेश 156. म्यांमार
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2015	क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एवं जर्मनवाच	58	1. डेनमार्क 2. स्वीडन 3. यूके 4. पुर्तगाल	—	31	—
वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक (Global (Competitiveness Index-GCI),2015-16	विश्व आर्थिक मंच (WEF) -सितंबर, 2015	140	1. स्विट्जरलैंड 2. सिंगापुर 3. अमेरिका 4. जर्मनी 5. नीदरलैंड्स	140. गिनी 139. चाड 138. मारितानिया 137. सिएरा लियोन	55	28. चीन 68. श्रीलंका 100. नेपाल 105 भूटान 107. बांग्लादेश 126. पाकिस्तान 131. म्यांमार
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक (International Intellectual Property Rights Index)	वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र (GIPC) - फरवरी, 2015	30	1. अमेरिका 2. ब्रिटेन 3. जर्मनी 4. फ्रांस 5. सिंगापुर	30. थाईलैंड 29. भारत 28. वियतनाम 27. इंडोनेशिया 26. अर्जेंटीना	29	17. चीन
'फ्रीडम ऑफ दि प्रेस' सूचकांक, 2015	फ्रीडम हाउस, अमेरिका द्वारा जारी,'फ्रीडम ऑफ दि प्रेस रिपोर्ट' में प्रस्तुत -29 अप्रैल, 2015	199	1. नार्वे एवं स्वीडन 2. बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स	199. उ. कोरिया 198. तुर्कमेनिस्तान एवं अफगानिस्तान	80	115. बांग्लादेश 118. नेपाल 127. भूटान 142. पाकिस्तान 169. श्रीलंका 186. चीन
वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक, 2015	विश्व आर्थिक मंच -13 मई, 2015	124	1. फिनलैंड 2. नार्वे 3. स्विट्जरलैंड	124. यमन	100	60. श्रीलंका 87. भूटान 99. बांग्लादेश 113. पाकिस्तान

जेंडर एंड एजुकेशन फॉर आल रिपोर्ट

- 12 अक्टूबर, 2015 को यूनेस्को ने 'जेंडर एंड एजुकेशन फॉर ऑल 2000-2015 : उपलब्धियां एवं चुनौतियां' नामक रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता का लक्ष्य विश्व के सभी देश हासिल नहीं कर पाये हैं, लेकिन वर्ष 2000 की तुलना में इसमें प्रगति हुई है। उपसहारा अफ्रीका का कोई भी देश लैंगिक समानता के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका।
- वर्ष 2000 के बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों क्षेत्रों में लैंगिक समानता को हासिल करने वाले देशों की संख्या 36 से बढ़कर 62 हो गई है।

स्टेट ब्रॉडबैंड रिपोर्ट-2015

- 21 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र ब्राडबैंड आयोग ने स्टेट ब्रॉडबैंड रिपोर्ट-2015 जारी की।
- इस रिपोर्ट के अनुसार 4 अरब लोग विश्व में अब भी ऑफलाइन हैं तथा 57 प्रतिशत लोग इंटरनेट नहीं प्रयोग करते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से इस आयोग की स्थापना वर्ष 2010 में न्यूयार्क में की गई थी।
- इस रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं—
  - ➔ विकसित देशों में इंटरनेट का उपयोग संतृप्त अवस्था में पहुंच चुका है जबकि विकासशील देशों में सिर्फ 35 फीसदी लोग ही इंटरनेट तक पहुंच रखते हैं।
  - ➔ विश्व में कुल 48 ऐसे देश हैं जहां पर 90 फीसदी लोग इंटरनेट की पहुंच के बाहर हैं।
  - ➔ घरेलू ब्रॉडबैंड के सबसे अधिक कनेक्शन कोरिया गणराज्य में हैं तथा कतर और सउदी अरब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं।
  - ➔ विश्व में कुल 79 देश ऐसे हैं जहां के 50 फीसदी लोगों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच है।
  - ➔ शीर्ष दस इंटरनेट उपभोगकर्ता देश यूरोप महाद्वीप के हैं।
  - ➔ व्यक्तिगत स्तर पर सबसे ज्यादा इंटरनेट आइसलैंड में उपयोग किया जाता है।
  - ➔ गिनी (1.7%), सोमालिया (1.6%), बुरुंडी (1.4%), इरीट्रिया (1.0%) जैसे देश न्यूनतम इंटरनेट उपयोगकर्ता देश हैं।

यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक : अगस्त, 2015 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी 'यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक-2015' में भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 के इस सूचकांक में भारत 65वें स्थान पर था।

महिला उद्यमिता सूचकांक : अगस्त, 2015 में अमेरिका के ग्लोबल इंटरप्रिन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी महिला उद्यमिता सूचकांक 2015 में भारत को 70वां स्थान प्राप्त हुआ।

एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट

- 16 जुलाई, 2015 को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने एशियाई विकास आउटलुक (Asian Development Outlook) रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5 फीसदी रहने की संभावना है।
- इस रिपोर्ट में चीन की 2015 में वृद्धि दर को पहले के 7.2 से घटाकर 7.0 फीसदी कर दिया गया है, जबकि वर्ष 2016 में चीन की वृद्धि दर 6.8 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

गवर्नमेंट एट-ए-ग्लांस-2015

- 6 जुलाई, 2015 को आर्गेनाइजशेन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) द्वारा गवर्नमेंट एट-ए-ग्लांस, 2015 रिपोर्ट जारी की गई।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में राष्ट्रीय सरकार में विश्वास रखने के मामले में भारत का 40 देशों की सूची में दूसरा स्थान है।
- इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को प्रथम और नार्वे को तीसरे स्थान पर रखा गया है।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिपोर्ट

अगस्त, 2015 के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 7 महीने में 41 बाघों की मृत्यु हो चुकी है।

शिशु मृत्यु दर में कमी

- अगस्त, 2015 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में शिशु मृत्यु दर में 55 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई।
- जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व में करीब साठ लाख बच्चे पांच साल की आयु पूरी नहीं कर पाते।
- इसमें से तीस लाख बच्चे अकेले भारत, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान तथा इथियोपिया के होते हैं।
- वर्तमान में भारत में एक लाख प्रसवों के दौरान 160 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तथा एक हजार बच्चों पर 40 बच्चों की मृत्यु हो जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2015

- 22 सितंबर, 2015 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2015 रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट के अनुसार ओईसीडी देशों में प्रवास तेजी से बढ़ रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका आव्रजन में प्रथम स्थान पर है तथा जर्मनी आव्रजन में दूसरे स्थान पर है।
- ओईसीडी देशों में प्रत्येक 10 अप्रवासियों में एक चीनी तथा 4.4 फीसदी भारतीय हैं।

विश्व आर्थिक परिदृश्य (अपडेट) रिपोर्ट

- 6 अक्टूबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook-Update) रिपोर्ट जारी की।
- आईएमएफ ने अगले वर्ष भारत की वृद्धि दर 7.5 फीसदी तथा चीन की वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान लगाया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीडीपी वृद्धि 3.3 फीसदी से घटकर 3.1 हो गई है।

डब्ल्यूटीओ की वार्षिक रिपोर्ट

- 30 सितंबर, 2015 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने वर्ष 2015 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व व्यापार वर्ष 2014 के 2.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015 में 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 से 2014 के बीच भारत 43 व्यापार विवादों में तथा चीन 44 व्यापार विवादों में शामिल हुआ।
- डब्ल्यूटीओ के भीतर एंटी डंपिंग इनिशिएशंस में भारत, ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है।

वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट-2015

- कैपजेमिनी एवं आरबीसी वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई 'वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट-2015' में करोड़पतियों की संख्या के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है।
- रिपोर्ट में प्रकाशित सूची में जहां 43,51,000 करोड़पतियों के साथ अमेरिका पहले पायदान पर है, वहीं 24,52,000 करोड़पतियों के साथ जापान दूसरे स्थान पर है।
- 11,41,000 करोड़पतियों के साथ जर्मनी तीसरे तथा 8,90,000 करोड़पतियों के साथ चीन चौथे पायदान पर है।
- पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें एवं दसवें पायदान पर क्रमशः ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं इटली हैं।
- करोड़पतियों की टॉप टेन सूची में भारत अपना स्थान नहीं बना सका है। वह 1.98 लाख करोड़पतियों के साथ 11वें पायदान पर है।
- यह रिपोर्ट बताती है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अति धनाढ्यों की संख्या सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में अति धनाढ्यों की संख्या में अच्छे विस्तार की संभावना भी व्यक्त की गई है, क्योंकि इस क्षेत्र के चीन, भारत, इंडोनेशिया और थाइलैंड उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 तक ग्लोबल वेल्थ में भारत और चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 10% होनी संभावित है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट

- विश्व बैंक द्वारा 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (Confederation of Indian Industry–CII) के सहयोग से तैयार की गई 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' (Ease of doing Busines Report) 14 सितंबर, 2015 को जारी की गई।
- यह राज्यवार कारोबार सुगमता रिपोर्ट है, जिसमें व्यापार करने के लिए भारत के बेहतर राज्यों की रैंकिंग की गई है।
- रिपोर्ट तैयार करने में जिन बातों को आधार बनाया गया है, वे हैं–जमीन आवंटन और निर्माण की अनुमति प्राप्त करना, कारोबार स्थापित करना, पंजीकरण और कर प्रक्रियाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रक्रिया, अनुबंध लागू करना, पर्यावरण अनुपालन प्रक्रियाएं, श्रम नियमों का अनुपालन एवं बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करना।
- रिपोर्ट में 71.14 स्कोर के साथ गुजरात राज्य पहले पायदान पर है। यानी यह राज्य व्यापार करने की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है।
- इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश (70.12 स्कोर), झारखण्ड (63.09 स्कोर), छत्तीसगढ़ (62.45 स्कोर) एवं मध्य प्रदेश (62.00 स्कोर) क्रमशः दूसरे, तीसरे एवं चौथे पायदान पर हैं, वहीं उत्तर प्रदेश (47.37 स्कोर), पंजाब (36.73 स्कोर) एवं बिहार (16.41 स्कोर) के साथ दसवें, सोलहवें एवं 21वें पायदान पर हैं। 01.23 स्कोर के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है।
- ध्यातव्य है कि उपक्षेत्रीय राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित इस प्रकार की रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा पहली बार जारी की गई है।

अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट

- 24 जून, 2015 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report) जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पुनः विश्व के सबसे आकर्षक 10 निवेश स्थलों में शामिल हो गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में 34 अरब डॉलर (22 प्रतिशत वृद्धि) का विदेशी निवेश हुआ जिससे वह निवेश आकर्षित करने वाले देशों की कतार में 9वें स्थान पर पहुंच गया।
- अंकटाड द्वारा जारी इस रिपोर्ट में एफडीआई अंतर्वाह वाले शीर्ष पांच देश क्रमशः चीन, हांगकांग (चीन), अमेरिका, यूके व सिंगापुर हैं।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार रिपोर्ट

जून, 2015 के तीसरे सप्ताह में इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) ने वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में दाखिल किये गये बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) संबंधी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्यों में इस सूची में सबसे ऊपर है तथा बंगलुरू शहरों में सबसे ऊपर है।

ग्लोबल ट्रेंड : वर्ल्ड एट वार रिपोर्ट

- 18 जून, 2015 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त (UNHCR) ने जबरन विस्थापन पर 'ग्लोबल ट्रेंड : वर्ल्ड एट वार' नामक रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के अंत तक जबरन विस्थापित लोगों की संख्या बढ़कर 59.5 मिलियन हो गई है जो वर्ष 2013 में 51.2 मिलियन थी।
- वर्ष 2014 के अंत में सीरिया आंतरिक विस्थापितों व शरणार्थियों का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अफगानिस्तान व सोमालिया आते हैं। वर्ष 2014 तक भारत में 199937 शरणार्थी हैं।

वैश्विक शिशु मृत्यु दर में कमी

- 16 मई, 2015 को यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शिशु मृत्यु दर में वर्ष 1990 से वर्ष 2013 के मध्य 49 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 1990 में प्रति 1000 शिशुओं पर यह संख्या 90 थी जो वर्ष 2013 में

घटकर 46 हो गयी।

- रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल शिशु मृत्यु दर का 50 प्रतिशत दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका के पांच देशों में है। यह भारत में 21 प्रतिशत, नाइजीरिया में 13 प्रतिशत, पाकिस्तान में 6 प्रतिशत, कांगो में 5 प्रतिशत तथा चीन में 4 प्रतिशत है। भारत में शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रति 1000 पर 92 है तथा केरल में सबसे कम 14 है।

ई-कचरा फैलाने में भारत पांचवें स्थान पर

अप्रैल, 2015 के अंत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 'वैश्विक ई-कचरा निगरानी-2014' रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2014 में 17 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न किया तथा ई-कचरा उत्पन्न करने वाले देशों की सूची में भारत पाचवें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका प्रथम और चीन दूसरे स्थान पर हैं।

विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं : फोर्ब्स

- 26 मई, 2015 को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स (Forbes) द्वारा वर्ष 2015 में विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है
- इस सूची में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं—अरुंधती भट्टाचार्य (भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख) : 30वां स्थान; चंदा कोचर (आईसीआईसीआई बैंक की एमडी) : 35वां स्थान; किरण मजूमदार शॉ (बायोकॉन की चेयरपर्सन) : 85वां स्थान; शोभना भरतिया (एचटी मीडिया की चेयरपर्सन) : 93वां स्थान।

वर्ष 2015 में विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स सूची

- 2 मार्च, 2015 को जारी इस सूची के अनुसार 79.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक अमेरिकी बिल गेट्स लगातार दूसरी बार (कुल मिलाकर 16वीं बार) विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति बने हैं।
- वर्ष 2015 में इस सूची में कुल 90 भारतीय अरबपतियों को स्थान प्राप्त हुआ है जिसमें शीर्ष स्थान वाले सर्वाधिक अमीर भारतीय क्रमशः हैं—मुकेश अंबानी (39वां स्थान), दिलीप सांघवी (44वां स्थान) तथा लक्ष्मी निवास मित्तल (48वां स्थान)। 4 मार्च, 2015 को फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अपडेट के अनुसार सन फार्मा के प्रमुख दिलीप सांघवी (समग्रतः 37वां स्थान) भारत के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे परंतु अब पुनः मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर आ गए हैं।
- इस सूची में शामिल पांच भारतीय महिलाओं में सर्वाधिक धनी महिला हैं—सावित्री जिंदल तथा उनके बाद इंदु जैन का स्थान है।

खुशहाल देशों में पराग्वे शीर्ष पर

- मार्च, 2015 में जारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी गैलप के 143 देशों में खुशहाली आंकने संबंधी रिपोर्ट में पराग्वे प्रथम स्थान पर है।
- भारत का स्थान 62वां है। इस सूची में सबसे निचले स्थान पर सूडान (143वें) है।

फॉर्च्यून पत्रिका की महानतम नेताओं की सूची

- मार्च, 2015 के अंतिम सप्ताह में फार्च्यून पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की।
- इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पांचवें तथा नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को 28वें स्थान पर जगह दी गई। सूची में शीर्ष पर एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं।

कंट्री थ्रेट इंडेक्स

मार्च, 2015 के अंत में इंटेल सेंटर द्वारा जारी (मार्च, 2015 तक की स्थिति) इस रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 10 खतरनाक देशों की सूची में इराक पहले और सीरिया दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक देश बताया गया है।

ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स

- 25 मार्च, 2015 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने दुनिया के 102 देशों के संबंध में ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स जारी किया।
- इसमें शीर्ष स्थान पर क्रमशः स्वीडन (प्रथम), न्यूजीलैंड (द्वितीय) एवं नार्वे (तृतीय) रहे। भारत ने इस सूची में 37वां स्थान प्राप्त किया।

विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की फोर्ब्स सूची

- 4 नवंबर, 2015 को फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2015 की विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत वर्ष के 15वें स्थान से 6 पायदान ऊपर 9वें स्थान पर आ गए हैं।
- वर्ष 2015 में इस सूची में शामिल विश्व की 73 शख्सियतों में शीर्ष 5 स्थान पर क्रमशः हैं—1. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 2. जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, 3. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, 4. रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस एवं 5. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग।

◆◆◆

लघु सामान्य ज्ञान

निधन (राष्ट्रीय)

- **ब्रजमोहन मुंजाल** : 1 नवंबर, 2015 को भारत के प्रमुख व्यवसायी एवं हीरो मोटोकॉर्प के संस्थापक चेयरमैन ब्रजमोहन मुंजाल का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **जुगल किशोर** : 25 अक्टूबर, 2015 को वरिष्ठ रंगकर्मी एवं अभिनेता जुगल किशोर का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **लभ जंजुआ** : 22 अक्टूबर, 2015 को बॉलीवुड गायक एवं गीतकार लभ जंजुआ का 56 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया।
- **केएसएल स्वामी** : 20 अक्टूबर, 2015 को प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्मकार किकेरी समन्ना लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **सैय्यद जहूर कासिम** : 20 अक्टूबर, 2015 को प्रख्यात समुद्र जीव विज्ञानी सैय्यद जहूर कासिम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **एम.एम. कालबुर्गी** : 30 अगस्त, 2015 को कन्नड़ साहित्यकार एवं कन्नड़ विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति एम.एम. कालबुर्गी की हत्या कर दी गई। वे मूर्तिपूजा एवं अंधविश्वास के खिलाफ दिए बयानों से कट्टरपंथियों के निशाने पर थे।
- **रमाकांत पाठक** : 19 अक्टूबर, 2015 को मशहूर पखावज वादक पंडित रमाकांत पाठक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **राधाकृष्ण हरिराम तहिलियानी** : 14 अक्टूबर, 2015 को भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल राधाकृष्ण हरिराम तहिलियानी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे आईएनएस विक्रांत पर सी हॉक लड़ाकू विमान से उतरने वाले पहले पायलट थे।
- **रवीन्द्र जैन** : 9 अक्टूबर, 2015 को प्रसिद्ध संगीतकार रवीन्द्र जैन का मुंबई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2015 में 'पद्म श्री' सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अंखियों के झरोखों से, नदिया के पार, चोर मचाए शोर, राम तेरी गंगा मैली जैसी कई फिल्मों के साथ मशहूर टीवी धारावाहिक 'रामायण' में भी संगीत दिया था।
- **एन. रमानी** : 9 अक्टूबर, 2015 को प्रख्यात बांसुरीवादक डॉ. एन. रमानी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कर्नाटक संगीत में बांसुरी की शुरुआत के लिए जाने जाते थे।
- **वीरेन डंगवाल** : 28 सितंबर, 2015 को हिंदी कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार वीरेन डंगवाल का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- **सैयद अहमद** : 27 सितंबर, 2015 को मणिपुर के सोलहवें राज्यपाल सैयद अहमद का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 16 मई, 2015 को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी।
- **होपिंग स्टोन लिंगदोह** : 26 सितंबर, 2015 को मेघालय में सबसे लम्बे समय तक विधायक रहे 'होपिंग स्टोन लिंगदोह' का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **प्रशांत सिन्हा** : 22 सितंबर, 2015 को पूर्व भारतीय फुटबाल खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वर्ष 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे थे।
- **राधिका थिलक** : 20 सितंबर, 2015 का मलयालम पार्श्व गायिका राधिका थिलक का 45 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया।
- **निजाम** : 21 सितंबर, 2015 को ओडिया के प्रसिद्ध गीतकार निजाम का 62 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **जगमोहन डालमिया** : 20 सितंबर, 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष (2 मार्च, 2015 को इस पद हेतु निर्वाचित) जगमोहन डालमिया का हृदयाघात के कारण 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे दो बार बीसीसीआई एवं एक बार आईसीसी के अध्यक्ष रहे थे।
- **साधन गुप्ता** : 19 सितंबर, 2015 को कम्युनिस्ट नेता व सांसद साधन गुप्ता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारत के पहले नेत्रहीन व्यक्ति थे जो सांसद हुए।
- **कालामंडलम सत्यभामा** : 13 सितंबर, 2015 को पद्मश्री मोहनीअट्टम नृत्यांगना कलामंडलम सत्यभामा का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **बाल पंडित** : 18 सितंबर, 2015 को मराठी क्रिकेट कमेंटेटर बाल पंडित का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने क्रिकेट पर 30 किताबें लिखीं तथा सुनील गावस्कर की आत्मकथा 'सनी डेज' का मराठी अनुवाद किया था।
- **रामास्वामी आर. अय्यर** : 9 सितंबर, 2015 को प्रख्यात जल नीति विशेषज्ञ रामास्वामी आर. अय्यर का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1987 में भारत की पहली राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार किया था। वर्ष 2014 में उन्हें 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था।
- **आदेश श्रीवास्तव** : 5 सितंबर, 2015 को बॉलीवुड गायक और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का 49 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया।
- **प्रणब कुमार बोराह** : 24 अगस्त, 2015 को वरिष्ठ पत्रकार प्रणब कुमार बोराह का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे असमी समाचार पत्र दैनिक जन्मभूमि से जुड़े थे।
- **शुभ्रा मुखर्जी** : 18 अगस्त, 2015 को रवीन्द्र संगीत की गायिका एवं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **परावुर भारतन** : अगस्त, 2015 में मलयालम फिल्म अभिनेता परावुर भारतन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **ओम प्रकाश मुंजाल** : 13 अगस्त, 2015 को हीरो साइकिल लिमिटेड के संस्थापक ओम प्रकाश मुंजाल का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **भालचंद्र पेंधरकर** : 11 अगस्त, 2015 को मराठी रंगमंच अभिनेता भालचंद्र पेंधरकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **कैय्यारा किन्हन्ना राय** : 9 अगस्त, 2015 को प्रख्यात कन्नड़ कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैय्यारा किन्हन्ना राय का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **कर्नल हरवंत सिंह** : 4 अगस्त, 2015 को द्वितीय विश्व युद्ध के नायक कर्नल हरवंत सिंह (सेवानिवृत्त) का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1944 में ब्रिटिश सेना के सर्वोच्च पुरस्कार मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

- भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से विख्यात शीर्ष वैज्ञानिक डॉ. अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम (डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम) का निधन 27 जुलाई, 2015 को 83 वर्ष की अवस्था में उत्तर-पूर्व के शिलांग में हुआ, जहां के एक संस्थान आईआईएम (IIM) में वह 'जीवन योग्य ग्रह' (Livable Planet) विषय पर व्याख्यान देने गए थे। कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें हृदयाघात हुआ और बाद में 'बेथनी अस्पताल' में उनकी इहलीला समाप्त हो गई।
- डॉ. कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को भारत के तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। मां का नाम आशियम्मा एवं पिता का नाम जैनुल आबिदीन था। डॉ. कलाम ने रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। रामनाथपुरम के एक विद्यालय से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिरुचरापल्ली के सेंट जोसेफ कालेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की तथा 'एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग' में चेन्नई के 'मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी की।
- डॉ. कलाम ने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत वर्ष 1958 में बंगलुरू के सिविल विमानन तकनीकी केंद्र से की, जहां पराध्वनिक लक्ष्यभेदी विमान का डिजाइन तैयार कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 1962 में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (इसरो) में नियुक्ति मिली, जहां रहकर उन्होंने वर्ष 1980 में 'रोहिणी उपग्रह' को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
- वर्ष 1992 में डॉ. कलाम को भारत के 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (डीआरडीओ) का निदेशक बनाया गया। इसी वर्ष मद्रास के 'अन्ना विश्वविद्यालय' द्वारा उन्हें 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की मानद उपाधि प्रदान की गई।
- 'अग्नि' और पृथ्वी' जैसी मिसाइलों को विकसित कर उन्होंने भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाया तथा देश-देशांतर में 'मिसाइल मैन' के नाम से विख्यात हुए।
- डॉ. कलाम जुलाई, 1992 से दिसंबर, 1998 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे।
- भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में वर्ष 1998 में पोखरण के द्वितीय परमाणु परीक्षण में डॉ. कलाम ने केंद्रीय भूमिका निभाई।
- वर्ष 2002 में डॉ. कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भाजपा द्वारा समर्थित एनडीए के घटक दलों द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। 25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007 तक वह पद पर रहे।
- डॉ. कलाम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 में 'पद्म भूषण', वर्ष 1990 में 'पद्म विभूषण' तथा वर्ष 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया। वर्ष 1997 में ही उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया।
- एक लेखक के रूप में डॉ. कलाम की चर्चित कृतियां हैं—'इंडिया 2020-ए विजन फ़ॉर द न्यू मिलेनियम', 'मॉय जर्नी', 'इग्नाइटेड माइंड्स : अनलीशिंग द पॉवर विद इन इंडिया', 'एनविजनिंग अनएक्पावर्ड नेशन : टेक्नोलॉजी फॉर सोसायटल ट्रांसफॉर्मेशन'। इनकी जीवनी का नाम 'विंग्स ऑफ फायर' है, जिसके लेखक अरुण तिवारी हैं।
- डॉ. अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद ओडिशा के मिसाइल परीक्षण स्थल 'व्हीलर द्वीप' का नाम बदल कर ओडिशा सरकार ने 'अब्दुल कलाम द्वीप' कर दिया। इसके अतिरिक्त दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम रोड किया गया।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय' का नाम डॉ. अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की घोषणा की।
- तमिलनाडु सरकार ने डॉ. अब्दुल कलाम के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष 'युवा जागरूकता दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की।
- केंद्र सरकार ने डॉ. कलाम के द्वारा ही उद्घाटित 'राष्ट्रीय आविष्कार मिशन' का नाम उन्हीं के नाम पर रखने की घोषणा की।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने डॉ. अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए 15 अक्टूबर, 2015 'विश्व छात्र दिवस' मनाया तथा इसके पहले 7 अगस्त, 2015 को अपने वैश्विक उपग्रह 'ग्लोबलसैट डीआआर' को डॉ. कलाम को समर्पित किए जाने की घोषणा की।

- **वसुंधरा कोमकली** : 29 जुलाई, 2015 को प्रख्यात गायिका वसुंधरा कोमकली का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वे भारत की प्रमुख शास्त्रीय गायिकाओं में से थीं।
- **सुनीति सोलोमन** : 28 जुलाई, 2015 को एचआईवी शोधकर्ता डॉ. सुनीति सोलोमन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1986 में पहली बार भारत में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि की थी।
- **रामकृष्णा सूर्यभान गवई** : 25 जुलाई, 2015 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता रामकृष्णा सूर्यभान गवई का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे बिहार के गवर्नर भी रहे थे।
- **पी.आर. चारी** : 24 जुलाई, 2015 को परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रवक्ता पी.आर. चारी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे रक्षा एवं सामरिक विश्लेषण संस्थान के पूर्व निदेशक भी रहे थे।
- **बिशेशर प्रदीप** : 19 जुलाई, 2015 को उर्दू लेखक डॉ. बिशेशर प्रदीप का 80 वर्ष की अवस्था में लखनऊ में निधन हो गया।
- **वी. रामाकृष्णा** : 15 जुलाई, 2015 को वरिष्ठ तेलुगू पार्श्व गायक वी. रामाकृष्णा का 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **शीला रमानी** : 15 जुलाई, 2015 को अभिनेत्री शीला रमानी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय फिल्मों के अलावा पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया था।
- **पशुपतिनाथ राय** : 13 जुलाई, 2015 को भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पशुपति नाथ राय का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **एम.एस. विश्वनाथन** : 13 जुलाई, 2015 को दक्षिण भारत के मशहूर संगीतकार एम.एस. विश्वनाथन का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **बशर नवाज** : 8 जुलाई, 2015 को उर्दू कवि, लेखक एवं वक्ता बशर नवाज का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

- **अरुण शर्मा** : 5 जुलाई, 2015 को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज के डीन डॉ. अरुण शर्मा का दिल्ली के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच से जुड़े थे। ज्ञातव्य है कि जुलाई माह में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस घोटाले की जांच का उत्तरदायित्व सीबीआई को सौंप दिया गया है।
- **वाई.के. सभरवाल** : 3 जुलाई, 2015 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे वर्ष 2005 से 2007 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे।
- **महेंद्र भल्ला** : 2 जुलाई, 2015 को वरिष्ठ कथाकार और नाटककार महेन्द्र भल्ला का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **प्रफुल्ल बिदवई** : 23 जून, 2015 को प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक प्रफुल्ल बिदवई का नीदरलैंड के एमस्टर्डम में निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे।
- **सिस्टर निर्मला जोशी** : 22 जून, 2015 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की पूर्व प्रमुख सिस्टर निर्मला जोशी का 81 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया।
- **शशि बाला** : 21 जून, 2015 को भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान शशि बाला का उनके पुत्र सहित एक सड़क हादसे में निधन हो गया।
- **चार्ल्स कोरिया** : 16 जून, 2015 को भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **शीला कौल** : 13 जून, 2015 को पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **नेकचंद सैनी** : 12 जून, 2015 को चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद सैनी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **हेमंत कानितकर** : 9 जून, 2015 को पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हेमंत कानितकर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **दशरधि रंगाचार्य** : 8 जून, 2015 को प्रख्यात तेलुगू लेखक दशरधि रंगाचार्य का 87 वर्ष की अवस्था में हैदराबाद में निधन हो गया।
- **प्रेमनाथ** : 1 जून, 2015 को पहलवान प्रेमनाथ का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1974 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।
- **अरुणा शानबाग :** 18 मई, 2015 को मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत नर्स अरुणा शानबाग का 42 वर्ष तक कोमा में रहने के बाद निधन हो गया। वे 1973 में यौन हिंसा एवं बलात्कार का शिकार हुई थीं जिसके बाद वे कोमा में चली गई थीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।
- **सुधा शिवपुरी :** 20 मई, 2015 को वरिष्ठ अभिनेत्री सुधा शिवपुरी का 78 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया।
- **मृणाल दत्त चौधरी :** 19 मई, 2015 को अर्थशास्त्री और शिक्षाविद् मृणाल दत्त चौधरी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **सुचित्रा भट्टाचार्य :** 12 मई, 2015 को प्रख्यात बंगाली लेखिका सुचित्रा भट्टाचार्य का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **बिंदुमाधव जोशी :** 11 मई 2015 को भारत में उपभोक्ता आंदोलन के प्रणेता एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संस्थापक बिंदुमाधव जोशी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **अमलेंदु गुहा :** 7 मई, 2015 को इतिहासकार अमलेंदु गुहा का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **अमिताभ चौधरी :** 2 मई, 2015 को वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक अमिताभ चौधरी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें बंग विभूषण एवं रेमन मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया था।
- **बिम्बा मोदक :** 29 अप्रैल, 2015 को प्रख्यात मराठी फिल्म एवं रंगमंच अभिनेत्री बिम्बा मोदक का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **जानकी बल्लभ पटनायक :** 21 अप्रैल, 2015 को असम के पूर्व राज्यपाल व ओडिशा के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके जानकी बल्लभ पटनायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **अंकित केसरी :** 20 अप्रैल, 2015 को ईस्ट बंगाल क्लब के क्रिकेटर अंकित केसरी की बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के एक मैच में चोट लगने के कारण 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई।
- **अवध नारायण मुद्गल** : 15 अप्रैल, 2015 को हिंदी की पत्रिका सारिका के पूर्व संपादक अवध नारायण मुद्गल का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **विद्युत चक्रवर्ती :** 15 अप्रैल, 2015 को असम के फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता विद्युत चक्रवर्ती का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह :** 11 अप्रैल, 2015 को महावीरचक्र प्राप्तकर्ता लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह का देहरादून में निधन हो गया। उन्होंने 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान 17 पूना हॉर्स रेजीमेंट का नेतृत्व किया था।
- **ईएम हनीफा** : 8 अप्रैल, 2015 को धार्मिक गीतों के गायक ईएम हनीफा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **जयकांतन** : 8 अप्रैल, 2015 को तमिल उपन्यासकार एवं आलोचक जयकांतन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **सुनीता तोमर** : 1 अप्रैल, 2015 को टीवी एवं सिनेमा के परदे पर अपनी कहानी सुनाकर तंबाकू के खतरों से लोगों को जागरूक करने वाली सुनीता तोमर का 27 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया।
- **मल्ली मस्तान बाबू** : 4 अप्रैल, 2015 को देश के श्रेष्ठ पर्वतारोही मल्ली मस्तान बाबू के मृत होने की पुष्टि की गई। वे 24 मार्च, 2015 को अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित एंडीज की पहाड़ियों पर चढ़ाई के दौरान लापता हो गये थे।
- **कमल भानाद्री** : 2 अप्रैल, 2015 को सात बार के पूर्व राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन कमल भानाद्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **कैलाश बाजपेयी** : 1 अप्रैल, 2015 को हिंदी के वरिष्ठ कवि कैलाश बाजपेयी का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। आधुनिक हिंदी कविता में शिल्प, संक्रात, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, सूफीनामा, हवा में हस्ताक्षर आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं।
- **थेनफुन्ना सैलो** : 27 मार्च, 2015 को मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री ब्रिगेडियर थेनफुन्ना सैलो का 93 वर्ष की उम्र में आइजोल में निधन हो गया।
- **विजयमोहन सिंह** : 25 मार्च, 2015 को हिंदी के प्रख्यात आलोचक एवं कहानीकार विजयमोहन सिंह का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **साहिर कृष्णराव सेबल** : 20 मार्च, 2015 को मराठी लोक गायक एवं नाटककार साहिर कृष्णराव सेबल का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **नारायण देसाई** : 14 मार्च, 2015 को प्रख्यात गांधीवादी नारायण देसाई का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई के पुत्र थे।
- **श्रीकृष्णचंद्र तिवारी** : 3 मार्च, 2015 को बाल साहित्यकार श्रीकृष्ण चंद्र तिवारी 'राष्ट्रबंधु' का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **विनोद मेहता :** 8 मार्च, 2015 को आउटलुक पत्रिका के संस्थापक सम्पादक एवं वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- **राम सुंदर दास** : 6 मार्च, 2015 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता राम सुंदर दास का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **लव कुमार खच्चर** : 3 मार्च, 2015 को प्रख्यात पक्षी विज्ञानी के. एस. लवकुमार खच्चर का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **मास्टर हुकुम सिंह** : 26 फरवरी, 2015 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह का गुड़गांव में 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **मीरा कौशांबी** : 26 फरवरी, 2015 को प्रसिद्ध समाजशास्त्री मीरा कौशांबी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध इतिहासकार डी.डी. कौशांबी की बेटी थीं।
- **आर.सी. शक्ति** : 23 फरवरी, 2015 को तमिल फिल्म निर्देशक आर.सी. शक्ति का चेन्नई में 75 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **आद्या शर्मा** : 23 फरवरी, 2015 को असम के मोबाइल थियेटर के जनक एवं चित्रकार आद्या शर्मा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **गोविंद पंसारे** : 20 फरवरी, 2015 को महाराष्ट्र के वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता गोविंद पंसारे का 82 वर्ष की आयु में अज्ञात हमलावरों के हमले के बाद निधन हो गया।
- **डी. रामा नायडू** : 18 फरवरी, 2015 को प्रख्यात फिल्म निर्माता डी. रामा नायडू का 78 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया। वर्ष 2009 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित रामा नायडू का नाम भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक फिल्में बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
- **राजिंदर पुरी** : 15 फरवरी, 2015 को प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और लेखक राजिंदर पुरी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **केशव रेड्डी** : 13 फरवरी, 2015 को प्रसिद्ध तेलुगू उपन्यासकार केशव रेड्डी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **आत्माराम गोविंद भेंडे** : 7 फरवरी, 2015 को प्रसिद्ध मराठी रंगमंच कलाकार और फिल्म अभिनेता आत्माराम गोविंद भेंडे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **मृणालिनी मुखर्जी** : 2 फरवरी, 2015 को मूर्तिकार एवं कलाकार मृणालिनी मुखर्जी का नई दिल्ली में 65 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **घेलूभाई नाईक** : 16 जनवरी, 2015 को सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी रहे घेलूभाई नाईक का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे।
- **रामेश्वर ठाकुर** : 15 जनवरी, 2015 को स्वतंत्रता सेनानी रहे रामेश्वर ठाकुर का 91 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, प. बंगाल तथा असम के राज्यपाल पद पर रहे थे।
- **सुभाष घीसिंग** : 29 जनवरी, 2015 को गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक सुभाष घीसिंग का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **आर. के. लक्ष्मण** : 26 जनवरी, 2015 को मशहूर कार्टूनिस्ट एवं पद्म विभूषण से सम्मानित आर. के. लक्ष्मण का पुणे में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने 'आम आदमी' (कॉमन मैन) के कार्टून के लिए विशेष रूप से चर्चित रहे।
- **रजनी कोठारी** : 19 जनवरी, 2015 को प्रख्यात राजनीति विज्ञानी एवं सिद्धांतकार रजनी कोठारी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **बेबी शकुंतला** : 18 जनवरी, 2015 को मशहूर अभिनेत्री बेबी शकुंतला का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम उमादेवी नाडगोंडे था।
- **आर.के. मणिसाना** : 9 जनवरी, 2015 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.के. मणिसाना का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मणिपुर के महाधिवक्ता तथा वर्ष 1995 में पत्रकारों व गैरपत्रकारों के लिए गठित वेतन बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे।
- **वी. आर. गोवरिकर** : 2 जनवरी, 2015 को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं इसरो के पूर्व अध्यक्ष वसंत रणछोड़ गोवरिकर का 82 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया।
- **बी.जी. वर्गीज** : 30 दिसंबर, 2014 को हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के पूर्व संपादक एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1975) से सम्मानित बी.जी. वर्गीज का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **राजन देवदास** : 26 दिसंबर, 2014 को प्रख्यात फोटो पत्रकार राजन देवदास का 93 वर्ष की आयु में वाशिंगटन में निधन हो गया।
- **माधवी सरदेसाई** : 22 दिसंबर, 2014 को कोंकणी लेखिका व वर्ष 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित माधवी सरदेसाई का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **के. बालचंदर** : 23 दिसंबर, 2014 को तमिल फिल्म निर्माता एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता के. बालचंदर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **सितारा देवी** : 25 नवंबर, 2014 को प्रख्यात कथक नृत्यांगना सितारा देवी का 94 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया।

निधन (अंतर्राष्ट्रीय)

- **लॉर्ड गुलाम नून** : 27 अक्टूबर, 2015 को भारतीय व्यंजनों के मशहूर व्यवसायी भारतीय मूल के लॉर्ड गुलाम नून का 79 वर्ष की उम्र में लंदन में निधन हो गया।
- **बेसिल विलियम्स** : 27 अक्टूबर, 2015 को वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी बेसिल विलियम्स का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **अली सलेम** : 22 सितंबर, 2015 को लोकप्रिय हास्य नाटकों की रक्षा करने वाले मिस्र के जाने-माने व्यंग्यकार अली सलेम का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **हेनिंग मैकनेल** : 5 अक्टूबर, 2015 को प्रसिद्ध स्वीडिश अपराध लेखक हेनिंग मैनकेल का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **फ्रैंक टायसन** : 27 सितंबर, 2015 को इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज फ्रैंक टायसन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 'टायफून' के नाम से प्रसिद्ध थे।
- **लारेंस पीटर 'योगी' बेरा** : 22 सितंबर, 2015 को अमेरिका के प्रसिद्ध बेसबाल खिलाड़ी लारेंस पीटर 'योगी' बेरा का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 13 बार विश्व सीरीज के चैंपियन रहे थे।
- **जैकी कॉलिंस** : 19 सितंबर, 2015 को प्रसिद्ध लेखिका जैकी कॉलिंस का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं—'वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैरिड मैन', 'रॉक स्टार', 'हॉलीवुड वाइब्स : द न्यू जनरेशन' आदि।
- **फ्रैंक डी. गिलरॉय** : 12 सितंबर, 2015 को प्रसिद्ध अमेरिकी नाटककार एवं निर्देशक फ्रैंक डी. गिलरॉय का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **चंद्र बहादुर डांगी** : 3 सितंबर, 2015 को विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति चंद्र बहादुर डांगी का अमेरिका के समोआ में 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी लंबाई 1 फीट 9.5 इंच थी। उनका जन्म नेपाल में हुआ था।
- **आर्थर मोरिस** : 22 अगस्त, 2015 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर आर्थर मोरिस का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **ओल्डम केल्सी** : 7 अगस्त, 2015 को कनाडा की चिकित्सक फ्रांसिस ओल्डम केल्सी का 101 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने थैलीडोमाइड नामक दवा को अमेरिका में वितरित किए जाने पर रोक लगवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- **आर्नोल्ड स्कासी** : 5 अगस्त, 2015 को कनाडा में जन्मे वस्त्र डिजायनर आर्नोल्ड स्कासी का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **सिला ब्लैक** : 1 अगस्त, 2015 को प्रसिद्ध ब्रिटिश गायिका सिला ब्लैक का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 'यू आर माई वर्ल्ड' गीत के लिए विश्व प्रसिद्ध थीं।
- **क्लाइव राइस** : 28 जुलाई, 2015 को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव राइस का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **पी. हरिहरन** : 27 जुलाई, 2015 को अमेरिका में भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी पी. हरिहरन का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने बहुरंगी होलोग्राम विकसित किया था।
- **टॉम मूरे** : 20 जुलाई, 2015 को कार्टूनिस्ट टॉम मूरे का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वे आर्ची कॉमिक्स के कार्टूनिस्ट थे।
- **ओल्फ पूले** : 14 जुलाई, 2015 को प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म अभिनेता और लेखक ओल्फ पूले का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **जॉन सेबास्टियन** : 13 जुलाई, 2015 को मेक्सिकन संगीतकार जॉन सेबास्टियन का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 7 लैटिन ग्रैमी अवॉर्ड एवं 5 ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके थे।
- **अब्दुल्ला हुसैन** : 5 जुलाई, 2015 को पाकिस्तान के जाने-माने उर्दू उपन्यासकार अब्दुल्ला हुसैन का 84 वर्ष की उम्र में लाहौर में निधन हो गया।
- **जेरालीन टेली** : 19 जून, 2015 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला जेरालीन टेली का अमेरिका में 116 साल की अवस्था में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिका की ही सुसान्नाह मुसहत जोंस विश्व की सबसे वृद्ध जीवित व्यक्ति हैं जिनकी आयु 1 नवंबर, 2015 को 116 वर्ष 3 माह एवं 25 दिन है।
- **बियू बिडेन** : 31 मई, 2015 को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन के बड़े बेटे बियू बिडेन का कैंसर से 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **ह्योन योंग चोल** : अप्रैल, 2015 में उत्तरी कोरिया के रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को सरकारी आदेशों की अवहेलना के आरोप में तोप से उड़ा दिया गया।
- **क्रिस्टोफर ली** : 7 जून, 2015 को प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता क्रिस्टोफर ली का 93 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर बनी फिल्म में जिन्ना की भूमिका अदा की थी।
- **मैटी मैकोनेन** : 30 जून, 2015 को मोबाइल की एसएमएस तकनीक की अवधारणा के जनक मैटी मैकोनेन का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **सुलेमान देमिरल** : 17 जून, 2015 को तुर्की के पूर्व राष्ट्रपति सुलेमान देमिरल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **इरविन रोज** : 2 जून, 2015 को वर्ष 2004 में रसायनशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जैव रसायनशास्त्री इरविन रोज का 88 वर्ष की अवस्था में मेसाच्युसेट्स में निधन हो गया।
- **डोरिस हार्ट** : 30 मई, 2015 को विश्व की पूर्व नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी डोरिस हार्ट (अमेरिका) का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कुल 35 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे।
- **मेरी एलेन मार्क** : 25 मई, 2015 को विख्यात फोटोग्राफर मेरी एलेन मार्क का 75 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क में निधन हो गया। उन्होंने फोटोग्राफी पर 17 पुस्तकें लिखी हैं।
- **क्रिस्टियन गोमेज** : 24 मई, 2015 को अर्जेंटीना के फुटबाल खिलाड़ी क्रिस्टियन गोमेज का खेल के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके पहले मिडफिल्डर एमैनुएल ओर्टेगा की 14 मई, 2015 को खेल के दौरान सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई थी।
- **जॉन नैश** : 24 मई, 2015 को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एवं गणितज्ञ जॉन नैश की 86 वर्ष की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्हें वर्ष 1994 में 'गेम थ्योरी' पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके जीवन पर आधारित फिल्म 'ब्यूटीफुल माइंड' को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
- **विजय मोहन** : 18 मई, 2015 को भारतीय अमेरिकी फिल्मकार विजय मोहन की फिलाडेल्फिया में एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के एक हफ्ते बाद मृत्यु हो गई।
- **पीटर गे** : 12 मई, 2015 को प्रसिद्ध इतिहासकार पीटर गे का न्यूयार्क में 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने 'नाइंटींथ सेंचुरी तथा 'एन्लाइटमेंट' जैसी पुस्तकें लिखी।
- **आस्कर होल्डरर** : 5 मई, 2015 को चंद्रयान (वर्ष 1969 में चंद्रमा पर उतरने वाले यान) की डिजाइन करने वाली टीम के अंतिम जीवित सदस्य ऑस्कर होल्डरर का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **लू पिंग** : 3 मई, 2015 को हांगकांग को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्ति दिलाने वाले चीनी राजनयिक लू पिंग का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **स्टानिस्लाव** : 16 अप्रैल, 2015 को चेक गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री स्टानिस्लाव का मात्र 45 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
- **सूर्य बहादुर थापा** : 15 अप्रैल, 2015 को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **गुंटर ग्रास** : 13 अप्रैल, 2015 को वर्ष 1999 के नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता जर्मन लेखक गुंटर ग्रास का निधन हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं- 'दि टिन ड्रम', 'दि कॉल ऑफ दि टोड', 'कैट एंड माउस' आदि। उन्होंने कोलकाता के अपने अनुभवों पर 1989 में 'शो योर टंग' नामक पुस्तक लिखी थी।
- **रिची बेनो** : 10 अप्रैल, 2015 को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, क्रिकेट पत्रकार और मशहूर कमेंटेटर रिची बेनो का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **ली कुआन यू** : 23 मार्च, 2015 को सिंगापुर के संस्थापक और प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **लिन यंग वेन** : 8 मार्च, 2015 को उर्दू के नामवर शायर और दंत सर्जन लिन यंग वेन (शैदा चीनी) का 84 वर्ष की उम्र में जमशेदपुर में निधन हो गया।
- **मैलकॉम फ्रेजर** : 20 मार्च, 2015 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एवं लिबरल पार्टी के नेता मैलकॉम फ्रेजर का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
- **लिया वैन लीर** : 13 मार्च, 2015 को इजरायली सिनेमा की अग्रदूत लिया वैन लीर का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **कैमिले मुफात** : 9 मार्च, 2015 को लंदन ओलंपिक (2012) में तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली 25 वर्षीया कैमिले मुफात की अर्जेंटीना में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
- **डॉ. लोठार लुत्से** : 5 मार्च, 2015 को प्रख्यात हिंदी शिक्षक एवं भारतविद् डॉ. लोठार लुत्से का 87 वर्ष की आयु में जर्मनी के बर्लिन में निधन हो गया।
- **केंजी इकुऑन** : 9 फरवरी, 2015 को बुलेट ट्रेन के जापानी औद्योगिक डिजाइनर केंजी इकुऑन की 85 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई।
- **कार्ल जेरासी** : 1 फरवरी, 2015 को अमेरिकी वैज्ञानिक एवं गर्भ निरोधक दवा के जनक 'कार्ल जेरासी' का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- **न्यायमूर्ति राणा भगवान दास** : 23 फरवरी, 2015 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राणा भगवान दास का 72 वर्ष की आयु में कराची में निधन हो गया। वे पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के पहले हिन्दू मुख्य न्यायाधीश रहे थे।
- **शाह अब्दुल्ला** : 23 जनवरी, 2015 को सऊदी अरब के शाह (राजा) अब्दुल्ला का 90 वर्ष की आयु में रियाद में निधन हो गया। वे अगस्त, 2005 से सऊदी अरब के शाह के पद पर थे।
- **गुरु चित्रेश** : 4 जनवरी, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी कथक गुरु चित्रेश का सैन फ्रांसिस्को में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

नियुक्ति (राष्ट्रीय)

- **जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर :** भारत के अगले (43वें) मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर होंगे। वे 2 दिसंबर, 2015 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू के स्थान पर 13 माह के कार्यकाल (4 जनवरी, 2017 तक) के लिए पदभार ग्रहण करेंगे।
- **शरद कुमार** : 30 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के पद पर वर्ष 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को नियुक्त किया गया।
- **शक्तिकांत दास** : 30 अक्टूबर, 2015 को केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल में नामित किया।
- **आलोक रावत** : 21 अक्टूबर, 2015 को पूर्व जल संसाधन सचिव आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वे राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य हैं। इसके पहले अगस्त, 2015 में आयोग में दो महिला सदस्यों क्रमशः सुषमा साहू एवं रेखा शर्मा को भी नियुक्त किया गया था।
- **अनिल कुंबले** : 20 अक्टूबर, 2015 को पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुंबले को रायपुर रेंजर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रायपुर रेंजर्स, चैंपियंस टेनिस लीग (सीटीएल) की सदस्य टीम है।
- **वी. के. मल्होत्रा** : 19 अक्टूबर, 2015 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ खेल प्रशासक वी. के. मल्होत्रा को अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। वी. के. मल्होत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।
- **बाईचुंग भूटिया** : 18 अक्टूबर, 2015 को अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को फुटबाल महासंघ का सलाहकार नियुक्त किया।
- **सौरव गांगुली** : 16 अक्टूबर, 2015 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 'बंगाल क्रिकेट संघ' (सीएबी) के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया।
- **कुंधावी कदिरेसन** : 14 अक्टूबर, 2015 को भारतीय नागरिक कुंधावी कदिरेसन को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का सहायक निदेशक तथा एशिया-पैसिफिक क्षेत्र का स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।
- **शेखर बसु** : 9 अक्टूबर, 2015 को भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शेखर बसु को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा का सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 23 अक्टूबर, 2015 को डॉ. आर. के सिन्हा का स्थान लिया।
- **शशांक मनोहर** : 4 अक्टूबर, 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष के रूप में 'शशांक मनोहर' का चयन किया गया।
- **जयंत प्रसाद** : 29 सितंबर, 2015 को नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत जयंत प्रसाद को नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- **अरविंद पनगड़िया** : 24 सितंबर, 2015 को केंद्र सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को जी-20 वार्ता का नया शेरपा नियुक्त किया। शेरपा, जी-20 शिखर सम्मेलन में संबंधित सरकार का प्रतिनिधि होता है।
- **स्तुति नारायण कक्कड़** : 23 सितंबर, 2015 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्तुति नारायण कक्कड़ को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
- **जैन खान** : 22 सितंबर, 2015 को जैन खान सर्वसम्मति से भारतीय मोटर स्पोर्ट्स क्लब संघ (एफएमएससीआई) के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए।
- **होरमुस्जी एन. कामा** : 14 सितंबर, 2015 को बंबई समाचार के प्रबंध निदेशक होरमुस्जी एन. कामा को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **विनिता ठाकुर** : 11 सितंबर, 2015 को भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी विनिता ठाकुर को 'नैटग्रिड' (National Intelligence Grid-NATGRID) का निदेशक नियुक्त किया गया।
- **रमेश चंद्र** : सितंबर, 2015 के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश चंद्र को नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया।
- **महेश रंगराजन** : 17 सितंबर, 2015 को महेश रंगराजन ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।
- **राघव चंद्र** : 31 अगस्त, 2015 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राघव चंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- **राजीव महर्षि** : 31 अगस्त, 2015 को पूर्व वित्त सचिव राजीव महर्षि को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया।
- **गिरीश साहनी** : 24 अगस्त, 2015 को डॉ. गिरीश साहनी को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- **मदनलाल लक्ष्मण दास तहलियानी** : 24 अगस्त, 2015 को मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदनलाल लक्ष्मण दास तहलियानी को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
- **अश्विनी लोहानी** : 20 अगस्त, 2015 को अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक एवं चेयरमैन नियुक्त किया गया।
- **ओम प्रकाश रावत** : 13 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओम प्रकाश रावत को भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। वर्तमान में इनके साथ भारत के 3-सदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. नसीम जैदी और निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार जोति हैं।
- **अलका पांडा** : 1 अगस्त, 2015 को आईएएस अधिकारी अलका पांडा को भारतीय मानक ब्यूरो की महानिदेशक नियुक्त किया गया।
- **देबजानी घोष** : 30 जुलाई, 2015 को मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमएआईटी) का अध्यक्ष देबजानी घोष को बनाया गया। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।

- **स्वाति मालीवाल** : 27 जुलाई, 2015 को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की गई।
- **आशीष बहुगुणा** : 28 जुलाई, 2015 को केंद्र सरकार ने आशीष बहुगुणा को खाद्य नियामक संस्था 'भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण' का अध्यक्ष नियुक्त किया।
- **रामसेवक शर्मा** : 27 जुलाई, 2015 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए अध्यक्ष के रूप में रामसेवक शर्मा को नियुक्त किया गया।
- **पंकज मुंजाल** : 20 जुलाई, 2015 को पंकज मुंजाल को हीरो मोटर्स ग्रुप का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया।
- **कमोडोर सी.डी. बालाजी** : 3 जुलाई, 2015 को कमोडोर सी.डी. बालाजी ने वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) और हल्के लड़ाकू विमान के कार्यक्रम निदेशक (एलसीए) का पदभार ग्रहण किया।
- **गजेंद्र चौहान** : 9 जून, 2015 को केंद्र सरकार ने अभिनेता गजेंद्र चौहान को फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे का चेयरमैन नियुक्त किया।
- **जगमोहन यादव** : 30 जून, 2015 को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जगमोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया।
- **अर्चना रामासुंदरम** : 17 जून, 2015 को अर्चना रामासुंदरम को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का निदेशक नियुक्त किया गया।
- **शरद पवार** : 17 जून, 2015 को एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के अध्यक्ष के रूप में 7वीं बार चुना गया।
- **डॉ. बिमल के. रॉय** : 10 जून, 2015 को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डॉ. बिमल के. रॉय को भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक पद से हटा दिया। उनके स्थान पर नामित निदेशक प्रो. एस. बंधोपाध्याय ने पद ग्रहण किया।
- **के. वी. चौधरी** : 8 जून, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) नियुक्त किए गए।
- **विजय शर्मा** : 8 जून, 2015 को केंद्र सरकार ने विजय शर्मा को 'मुख्य सूचना आयुक्त' तथा सुधीर भार्गव को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया।
- **आर.सी. तायल** : जून, 2015 में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आर.सी. तायल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया।
- **राहुल द्रविड़** : 6 जून, 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को भारत 'ए' एवं अंडर 19 टीमों का कोच नियुक्त किया। उल्लेखनीय है कि इसके पहले बीसीसीआई ने भारत के तीन पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली व वीवीएस लक्ष्मण को अपनी सलाहकार समिति में शामिल करने की घोषणा की थी।
- **नरेंद्र भूषण** : 5 जून, 2015 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेंद्र भूषण को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- **आर. सेशासाई** : 5 जून, 2015 को इंफोसिस ने आर. सेशासाई को कंपनी का गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया।
- **सैय्यद आसिफ इब्राहिम** : 3 जून, 2015 को सैय्यद आसिफ इब्राहिम को आतंकवाद के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष दूत नियुक्त किया गया।
- **ललित भनोट** : 1 जून, 2015 को चीन के वुहान में आयोजित चुनावों में भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव ललित भनोट को एशियाई एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। कतर के दहलान अल-हमद को दोबारा एशियाई एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष चुना गया।
- **के. सिवान** : 1 जून, 2015 को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. सिवान को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- **पी. कुनीकृष्णन** : 1 जून, 2015 को पी. कुनीकृष्णन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नियुक्त किए गए। उन्होंने एमवाईएस प्रसाद का स्थान ग्रहण किया।
- **मीणा हेमचंद्र** : 1 जून, 2015 को मीणा हेमचंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया।
- **अखिलेश दासगुप्ता** : 26 अप्रैल, 2015 को भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) के अध्यक्ष अखिलेश दासगुप्ता को बैडमिंटन एशिया परिसंघ (बीएसी) का उपाध्यक्ष चुना गया।
- **जी. सतीश रेड्डी :** 29 मई, 2015 को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का वैज्ञानिक सलाहकार डॉ.जी. सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया।
- **वीना जैन :** 29 मई, 2015 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वीना जैन को दूरदर्शन का नया महानिदेशक नियुक्त किया।
- **प्रदीप कुमार सिन्हा :** 29 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी प्रदान की। उन्होंने 13 जून, 2015 को अपना पद ग्रहण किया।
- **एस. क्रिस्टोफर :** 28 मई, 2015 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस. क्रिस्टोफर को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया।
- **मैत्रेयी पुष्पा :** 20 मई, 2015 को दिल्ली सरकार ने हिंदी की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया।
- **कुलदीप मलिक :** 18 मई, 2015 को भारतीय कुश्ती महासंघ ने कुलदीप मलिक को भारतीय कुश्ती टीम का मुख्य राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया।
- **अचल कुमार ज्योति :** 13 मई, 2015 को अचल कुमार ज्योति ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- **के.सतीश रेड्डी :** 11 मई, 2015 को डॉ. के. सतीश रेड्डी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। उन्होंने वेणु श्रीनिवासन का स्थान लिया।
- **साइरेक जोसेफ :** 11 मई, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायमूर्ति साइरेक जोसेफ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 11 मई, 2015 को ही इस पद से सेवानिवृत्त हुए के.जी. बालाकृष्णन का स्थान लिया।
- **के.वी. थॉमस :** 10 मई, 2015 को लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने के.वी. थॉमस को दोबारा लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया।
- **मुकेश खन्ना :** 29 अप्रैल, 2015 को फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना को भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी (सीएफएसआई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **सीताराम येचुरी :** 19 अप्रैल, 2015 को वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) का महासचिव चुना गया। वे सीपीएम के पांचवे महासचिव बने। उन्होंने प्रकाश करात का स्थान लिया।
- **मीनाक्षी मदन राय :** 15 अप्रैल, 2015 को मीनाक्षी मदन राय ने सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- **संदीप जाजोदिया :** 3 मई, 2015 को बाक्सिंग इंडिया की आम सभा की विशेष बैठक में बाक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष संदीप जाजोदिया को उनके पद से हटा दिया गया।
- **ब्रजभूषण शरण सिंह** : 13 अप्रैल, 2015 को उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का 4 वर्षों के लिए दोबारा अध्यक्ष चुना गया।

- **सुमित मजूमदार** : अप्रैल, 2015 में सुमित मजूमदार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **नसीम जैदी** : 9 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी को भारत का 20वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। जैदी का कार्यकाल जुलाई, 2017 तक है।
- **राजीव शुक्ला** : 6 अप्रैल, 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कांग्रेस सांसद और पूर्व आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला को आईपीएल की संचालन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने रंजीब बिस्वाल का स्थान लिया।
- **गुलशन राय** : 1 अप्रैल, 2015 को गुलशन राय प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधीन भारत के पहले साइबर सुरक्षा प्रमुख बनाए गए।
- **डॉ. मायिलसामी अन्नादुरै** : 1 अप्रैल, 2015 को डॉ. मायिलसामी अन्नादुरै ने इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरू के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- **सुधाकर रेड्डी** : 29 मार्च, 2015 को एस. सुधाकर रेड्डी को लगातार दूसरी बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का महासचिव चुना गया।
- **के. एम. मणि** : 24 मार्च, 2015 को केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **विकास स्वरूप** : 26 मार्च, 2015 को वरिष्ठ राजनयिक विकास स्वरूप को विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता नियुक्त किया गया। उनके उपन्यास 'क्यू एंड ए' पर बनी फिल्म 'स्लम डॉग मिलियनेयर' ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था।
- **यदुपति सिंघानिया** : 22 मार्च, 2015 को यदुपति सिंघानिया को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
- **नरेंद्र मोदी** : 20 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले तीन वर्षों के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय (प. बंगाल) का कुलाधिपति नियुक्त किया गया।
- **एन. रामचंद्रन** : 17 मार्च, 2015 को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष एन. रामचंद्रन को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संघ (ANOC) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **सुरेश कलमाड़ी** : 12 मार्च, 2015 को भारतीय खेल प्रशासक सुरेश कलमाड़ी को एशियन एथलेटिक्स (एएए) का आजीवन अध्यक्ष जकार्ता (इंडोनेशिया) में मनोनीत किया गया।
- **जूही सिंह** : 16 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह को बाल अधिकार संरक्षण आयोग (बाल आयोग) की पहली अध्यक्षा नियुक्त किया।
- **बलदेव शर्मा** : 2 मार्च, 2015 को पांचजन्य के पूर्व संपादक बलदेव शर्मा को नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **आर.के. पचौरी** : 24 फरवरी, 2015 को 'दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' (टेरी) के चेयरमैन आर.के. पचौरी ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
- **जावेद उस्मानी** : 17 फरवरी, 2015 को उ. प्र. के राज्यपाल राम नाइक द्वारा जावेद उस्मानी को उ. प्र. का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया।
- **एम.ओ. गर्ग** : 5 फरवरी, 2015 को एम.ओ. गर्ग को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) का महानिदेशक नियुक्त किया गया।
- **जसपाल सिंह कंधारी** : 30 जनवरी, 2015 को जसपाल सिंह कंधारी को भारतीय जिमनास्टिक महासंघ (जीएफआई) का अध्यक्ष चुना गया।
- **एस. जयशंकर** : 29 जनवरी, 2015 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी एस. जयशंकर ने विदेश सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। इसके पहले वे अमेरिका में भारत के राजदूत थे। उन्होंने सुजाता सिंह का स्थान लिया।
- **शेखर सेन** : 29 जनवरी, 2015 को संगीतकार व अभिनेता शेखर सेन को संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने लीला सैमसन का स्थान लिया।
- **सरस्वती मेनन** : 24 जनवरी, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने शांति निर्माण पैनल में भारतीय समाजशास्त्री सरस्वती मेनन की नियुक्ति की।
- **पहलाज निहलानी** : 19 जनवरी, 2015 को फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) के नए अध्यक्ष नियुक्त।

नये राज्यपालों के नाम	राज्य	अवधि
पी. सदाशिवम	केरल	(5 सितंबर, 2014 से)
पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्या	असम	(12 दिसंबर, 2014 से)
कप्तान सिंह सोलंकी	पंजाब	(22 जनवरी, 2015 से)
बी. षणमुगंथन	मेघालय	(20 मई, 2015 से)
निर्भय शर्मा	मिजोरम	(26 मई, 2015 से)
कृष्णकांत पाल	उत्तराखंड	(8 जनवरी, 2015 से)
द्रौपदी मुर्मू (झारखंड की पहली महिला राज्यपाल)	झारखंड	(18 मई, 2015 से)
ज्योति प्रसाद राजखोवा	अरुणाचल प्रदेश	(1 जून, 2015 से)
आचार्य देवव्रत	हिमाचल प्रदेश	(12 अगस्त, 2015 से)
रामनाथ कोविंद	बिहार	(16 अगस्त, 2015 से)
वी. षणमुगंथम	मणिपुर	(30 सितंबर, 2015 से)
केसरी नाथ त्रिपाठी	त्रिपुरा	(30 सितंबर, 2015 से)

- **अतुल खरे** : जनवरी, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अतुल खरे को फील्ड सपोर्ट विभाग (डीएफएस) का प्रमुख नियुक्त किया।
- **अलुर सीलिन किरन कुमार** : 12 जनवरी, 2015 को 62 वर्षीय अलुर सीलिन किरन कुमार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का आठवां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के सचिव तथा अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का भी पदभार ग्रहण किया।
- **एम. सत्यवती** : जनवरी, 2015 में संघ शासित कैडर की अधिकारी एम. सत्यवती को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का महानिदेशक बनाया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।
- **दिनेश्वर शर्मा** : 13 दिसंबर, 2014 को इंटेलीजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में दिनेश्वर शर्मा की नियुक्ति 1 जनवरी, 2015 से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण।
- **राजिंदर खन्ना** : 20 दिसंबर, 2014 को एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के विशेष सचिव राजिंदर खन्ना को इसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया।
- **न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद** : 25 नवंबर, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के 14वें अध्यक्ष नियुक्त। उन्होंने न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू का स्थान लिया।
- **ललिता कुमार मंगलम** : 17 सितंबर, 2014 को ललिता कुमार मंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की आठवीं अध्यक्षा हैं।
- **हंद्याला लक्ष्मीस्वामी नारायण दत्तू** : 3 सितंबर, 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति हंद्याला लक्ष्मीस्वामी नारायण दत्तू की नियुक्ति को मंजूरी दी तथा 28 सितंबर, 2014 को श्री दत्तू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

- **अविनाश चंदर** : 13 जनवरी, 2015 को केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष रक्षा विकास अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख अविनाश चंदर को पद से हटाने की घोषणा की। वे 31 जनवरी, 2015 तक इस पद पर रहे।

नियुक्ति (अंतर्राष्ट्रीय)

- **नंद किशोर पुन** : 31 अक्टूबर, 2015 को नेपाल की संसद ने देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में नंद किशोर पुन का निर्वाचन किया। वे माओवादियों के सशस्त्र आंदोलन के समय गुरिल्ला कमांडर रहे थे।
- **नवतेज सिंह सरना** : 31 अक्टूबर, 2015 को भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1980 बैच के अधिकारी नवतेज सिंह सरना को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।
- **बिद्या देवी भंडारी** : 28 अक्टूबर, 2015 को नेपाल की संसद ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) की उपाध्यक्ष बिद्या देवी भंडारी को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद भंडारी, रामबरन यादव (2008-2015) के बाद वहां की दूसरी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं।
- **नासिर खान जंजुआ** : 22 अक्टूबर, 2015 को पाकिस्तान में सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया गया। उन्होंने सरताज अजीज का स्थान लिया है।
- **जिओजी कोंरोते** : 12 अक्टूबर, 2015 को फिजी की संसद ने जिओजी कोंरोते को फिजी का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। वे फिजी के मेजर जनरल रह चुके हैं।
- **के. पी. शर्मा ओली** : 11 अक्टूबर, 2015 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) के नेता के.पी. शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया।
- **अजय शर्मा** : 4 अक्टूबर, 2015 को भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनयिक अजय शर्मा को ब्रिटेन ने कतर में अपना नया राजदूत नियुक्त किया।
- **ओनसारी घरती मागर** : 16 अक्टूबर, 2015 को नेपाल की संसद ने सर्वसम्मति से यूसीपीएन-माओवादी की सांसद ओनसारी घरती मागर को सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। वे नेपाल की संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनीं हैं।
- **हो सुंग ली** : 6 अक्टूबर, 2015 को दक्षिण कोरिया के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ 'हो सुंग ली' को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। उन्होंने राजेंद्र पचौरी का स्थान लिया है।
- **जॉन टी. चैंबर्स** : 21 सितंबर, 2015 को सिस्को के कार्यकारी अध्यक्ष जॉन टी. चैंबर्स को अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वे 1 दिसंबर, 2015 को इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे अजय बंगा का स्थान लेंगे।
- **मैलकॉम टर्नबुल** : 14 सितंबर, 2015 को लिबरल पार्टी के मैलकॉम टर्नबुल ने ऑस्ट्रेलिया के 29वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।
- **ई. श्रीधरन** : सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारतीय मेट्रो मैन ई. श्रीधरन को सतत परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी एसटी) का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। सदस्य के रूप में श्रीधरन का कार्यकाल तीन वर्ष का है।
- **शेरिफ इस्माइल** : 19 सितंबर, 2015 को मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में शेरिफ इस्माइल ने शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने शपथ दिलाई। वे दिसंबर, 2015 के संसदीय चुनावों तक अपने पद पर बने रहेंगे।
- **जेरेमी कोर्बिन** : 12 सितंबर, 2015 में यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी के नेता के रूप में जेरेमी कोर्बिन का चयन किया गया। इसके साथ ही वे हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष के नेता बन गए।
- **अनवर जहीर जमाली** : 10 सितंबर, 2015 को अनवर जहीर जमाली ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। वे पाकिस्तान के 24वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
- **विन्स छाबरिया** : 24 अगस्त, 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के विन्स छाबरिया को कैलिफोर्निया की अदालत का पूर्णकालिक संघीय न्यायाधीश नियुक्त किया।
- **राफी फ्रीडमन गुरुस्पैन** : 18 अगस्त, 2015 को ह्वाइट हाउस में पहली बार ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राफी फ्रीडमन गुरुस्पैन की नियुक्ति कर्मचारी निदेशक के रूप में की गई।
- **जगदीप ग्रेवाल** : 3 सितंबर, 2015 को भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जगदीप ग्रेवाल ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर की पहली महिला पोस्टमास्टर के रूप में शपथ ग्रहण की। वे पिछले 166 वर्षों में सैक्रामेंटो शहर में पोस्टमास्टर बनने वाली पहली महिला हैं।
- **अतुल केशप** : 5 अगस्त, 2015 को भारतीय मूल के अतुल केशप को श्रीलंका एवं मालदीव में संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया।
- **मौरिस ओब्सफेल्ड** : 20 जुलाई, 2015 को ह्वाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार मौरिस ओब्सफेल्ड को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 सितंबर, 2015 को ओलिवियर ब्लैंकार्ड का स्थान लिया।
- **ओटो पेरेज** : 3 सितंबर, 2015 को ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ओटो पेरेज ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में इस्तीफा दे दिया।
- **अब्दुल्ला अलथिनी** : 12 अगस्त, 2015 को लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अलथिनी ने देश में अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण पद से इस्तीफा दे दिया।
- **जिन लीकुन** : 6 जुलाई, 2015 को चीन के पूर्व वित्त मंत्री जिन लीकुन को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का पहला अध्यक्ष नामित किया गया।
- **अमीना गुरीब फकीम** : 5 जून, 2015 को अमीना गुरीब फकीम मॉरीशस की प्रथम निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इससे पूर्व मोनीक ओहसान मार्च-जुलाई, 2012 के दौरान वहां की कार्यकारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं।
- **कीथ वाज** : 18 जून, 2015 को भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज को ब्रिटिश संसद की गृह विभाग की प्रभावशाली प्रवर समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया। वे इस पद पर लगातार तीसरी बार चुने गये।
- **आकार पटेल** : 18 जून, 2015 को लेखक-पत्रकार आकार पटेल को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- **मोंगेस लुकेटॉफ्ट** : 15 जून, 2015 को डेनमार्क की संसद के स्पीकर मोंगेस लुकेटॉफ्ट को एक वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान 70वें सत्र के अध्यक्ष हैं।
- **विनीता बाली** : 4 जून, 2015 को ग्लोबल अलाएंस फॉर इंप्रूवमेंट न्यूट्रीशन (GAIN) के बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में विनीता बाली की नियुक्ति की गई।
- **फाउरे नासिंगबे** : 29 अप्रैल, 2015 को अफ्रीकी देश टोगो में हुए राष्ट्रपति चुनाव में टोगो के राष्ट्रपति फाउरे नासिंगबे तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए।

- **जॉर्ज इयो :** 30 मई, 2015 को सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज इयो को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में चयनित किया गया। इसके पहले इस पद पर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे।
- **एस. चंद्र दास :** 27 मई, 2015 को सिंगापुर ने भारतीय मूल के व्यक्ति एस. चंद्र दास को श्रीलंका में अपना राजदूत नियुक्त किया।
- **सेप ब्लेटर :** 29 मई, 2015 को सेप ब्लेटर को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबाल (फीफा) के अध्यक्ष पद हेतु पांचवी बार चुने गये। हालांकि अमेरिकी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में कई फीफा अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 2 जून, 2015 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की तथापि वे अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे।
- **परविंदर सिंह बट्ट :** 22 मई, 2015 को भारतीय मूल के परविंदर सिंह बट्ट को ब्रिटेन स्थित बकिंघम शहर के मेयर पद के लिए चुना गया।
- **रंजीत सिंह बक्शी :** मई, 2015 के तीसरे सप्ताह में भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्यमी रंजीत बक्शी को वैश्विक संगठन 'ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइक्लिंग (बीआईआर) का प्रमुख चुना गया।
- **के.वी. कामथ :** 11 मई, 2015 को के.वी. कामथ नव विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक (NDB) के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।
- **प्रीती पटेल :** 10 मई, 2015 को भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक प्रीती पटेल को ब्रिटेन सरकार ने रोजगार मंत्री नियुक्त करने की घोषणा की।
- **मोहम्मद बिन नायेफ :** 29 अप्रैल, 2015 को सउदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नायेफ को क्राउन प्रिंस (युवराज) नियुक्त किया।
- **विवेक हैलगेर मूर्ति :** 23 अप्रैल, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक हैलगेर मूर्ति को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका के सर्जन जनरल पद की शपथ दिलाई। वे इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं।
- **अतुल केशप** : 26 मार्च, 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के अतुल केशप को श्रीलंका एवं मालदीव का नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया।
- **मुस्तफा कमाल** : 1 अप्रैल, 2015 को बांग्लादेश के मुस्तफा कमाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर 25 जून, 2015 को पाकिस्तान के जहीर अब्बास आईसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए।
- **एश्टन कार्टर** : 13 फरवरी, 2015 को अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के 25वें रक्षा सचिव (मंत्री) के रूप में एश्टन कार्टर को चुना। उन्होंने चक हेगेल की जगह ली।
- **अजय पाल सिंह बंगा** : 5 फरवरी, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी अजय पाल सिंह बंगा को अमेरिका में व्यापार नीति और वार्ता हेतु सलाहकार समिति (एसटीपीएन) का सदस्य नियुक्त किया गया।
- **सर्जियो मात्तारेला** : 3 फरवरी, 2015 को सर्जियो मात्तारेला ने इटली के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
- **जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा** : 17 जनवरी, 2015 को जस्टिस सुरेन्द्र कुमार सिन्हा ने बांग्लादेश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले हिन्दू न्यायाधीश हैं।
- **अमित प्रियवदन मेहता** : 17 दिसंबर, 2014 को अमेरिकी सीनेट ने कोलंबिया क्षेत्र के संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अमित प्रियवदन मेहता के नाम की घोषणा की। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले एशिया-प्रशांत मूल के अमेरिकी हैं।
- **अर्जुन मजूमदार** : 4 दिसंबर, 2014 को भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अर्जुन मजूमदार को अमेरिका का विज्ञान दूत नियुक्त किया गया।

नवीनतम पुस्तकें

- **स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप** —रघुवीर सिंह 'अरविंद' (संपादित)
- **अर्ली हिंदू टेम्पल्स ऑफ गुजरात** —वरुण मायरा
- **जर्नी ऑफ ए क्यूरियस माइंड** —डॉ. जगन्नाथ पटनायक
- **लॉर्ड जगन्नाथ** —प्रसन्ना कुमार पटसामी
- **ड्रीमिंग बिग : माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया** —सैम पित्रोदा
- **'इंडियन फैमिली बिजनेस मंत्रास'** —पीटर लीच एवं तत्वमसी दीक्षित
- **दि चिनार लीव्स : ए पॉलिटिकल मेमॉयर** —माखन लाल फोतेदार

हिंदू लिटरेरी अवॉर्ड, 2015 हेतु शार्टलिस्ट पुस्तकें

- **'ओडिसिस एब्रॉड'** —अमित चौधरी
- **'फ्लड ऑफ फायर'** —अमिताव घोष
- **'स्लीपिंग ऑन ज्यूपिटर'** —अनुराधा रॉय
- **'व्हेन दि रिवर स्लीप्स'** —ईस्टरीन काइर
- **'सी हॉर्स'** —जैनिस पैरिएट
- **'दि पटना मैनुअल ऑफ स्टाइल'** —सिद्धार्थ चौधरी

- **हलंत** —हृषिकेश सुलभ
- **काले अध्याय** —मनोज रूपड़ा
- **हिजरत से पहले** —वंदना राग

डॉ. अब्दुल कलाम की पुस्तकें

- डेवलपमेंट इन फ्लूड मेकैनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी (सहलेखक-रोद्दाम नरसिम्हा)
- इंडिया 2020 : ए विजन फॉर दि न्यू मिलेनियम (सह लेखक- वाई. एस. राजन)
- इन विजनिंग एन एंपावर्ड नेशन (सह लेखक- शिवतनु पिल्लई)
- यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम (सह लेखक- अरूम तिवारी)
- टारगेट 3 बिलियन, 2011 (सह लेखक- सृजन पाल सिंह)
- ए मैनीफेस्टो फॉर चेंज : ए सिक्वेल टू इंडिया 2020 (सह लेखक- वीपोन राज)
- रीइग्नाइटेड : साइंटिफिक पाथवेज टू ए ब्राइटर फ्यूचर, 2015 (सह लेखक- सृजन पाल सिंह)
- ट्रांसडेंस माई स्पीरिचुअल एक्सपीरियंसेज विद प्रमुख स्वामीजी 2015
- माई जर्नी : ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन, 2013
- इनडॉमिटेबल स्पिरिट
- इग्नाइटेड माइंड्स : अनलीजिंग दि पॉवर विद इन इंडिया, 2002
- दि लूमिनस स्पार्क्स
- मिशन इंडिया इंस्पायरिंग थॉट्स
- फॉर्ज योर फ्यूचर : कैंडिड, फोर्थराइट, इंस्पायरिंग
- टर्निंग प्वाइंट्स : ए जर्नी थ्रू चैलेंजेज
- एडवांटेज इंडिया : फ्रॉम चैलेंजेज टू अपॉर्च्युनिटीज (सह लेखक- सृजन पाल सिंह; प्रकाशनाधीन)

- **फेमिनिस्ट एंड ओरियंटलिस्ट पर्सपेक्टिव्ज** —डॉ. फरहा हिबा परवेज
- **वीमेन इन पॉवर : देअर वॉयसेज, देयर स्टोरीज** —नैना लाल किदवई
- **शान बढ़ाने आया हूं** —कृष्ण मोहन झा
- **रूल्ड ऑर मिसरूल्ड : स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार** —संतोष सिंह
- **आर. डी. बर्मन : द प्रिंस ऑफ म्यूजिक** —खगेश देव बर्मन
- **द क्लिंटन्स वॉर ऑन वीमेन**—रोजर स्टोन एवं राबर्ट मोरो
- **घोस्ट ऑफ कोलकाता** —सेबस्टियन ओर्तिज
- **लोकेल, एवरी डे इस्लाम एंड मॉडर्निटी** —एम. रईसुर्रहमान
- **ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस** —डॉ. मूलचंद्र शर्मा
- **द ड्यूल्स ऑफ द हिमालयन ईगल** —भरत कुमार
- **टू द ब्रिंक एंड बैक : इंडियाज 1991 स्टोरी** —जयराम रमेश
- **स्मिता पाटिल : ए ब्रीफ इनकैंडेसेस** —मैथिली राव
- **कश्मीर : द वाजपेयी ईयर्स** —ए.एस. दुलत और आदित्य सिन्हा
- **आरुषि** —अविरुक सेन
- **37 ब्रिजेज एवं अन्य कहानियां** —आमिर हुसैन
- **द व्हाइट जोन** —कैरोलिन मार्सडेन
- **ग्रीन सिग्नल्स : इकोलॉजी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया** —जयराम रमेश
- **गॉड्स ऑफ करप्शन** —प्रेमिला शंकर
- **द टिन ड्रम** —गुंटर ग्रास
- **सील ऑफ द सूर्य** —श्री अमृतांशु
- **उनीकि (शाब्दिक अर्थ-Existence)** —सी. विद्यासागर राव (महाराष्ट्र के राज्यपाल)
- **संघर्ष के प्रयोग** —प्रो. राम गोपाल यादव
- **योग और इस्लाम** —डॉ. इमरान चौधरी एवं श्री अभिजीत सिंह
- **गोपाल कृष्ण गोखले-गांधीज पॉलिटिकल गुरु** —गोविंद तलवलकर
- **द इमर्जेंसी-ए पर्सनल हिस्ट्री** —कूमी कपूर
- **इन इक्वैलिटी-व्हॉट कैन बी डन?** —एंथनी बी. एटकिंसन
- **1400 बनानाज, 76 टाउन्स एंड 1 मिलियन पीपुल**—समीर नजारेथ
- **एजुनेशन-द ड्रीम ऑफ एन इंडिया इम्पावर्ड**—के.एम. वासुदेवन पिल्लई
- **बियोंड डाउट-ए डोजिअर ऑन गांधीज असैसिनेशन**—तीस्ता सीतलवाड़
- **इंडियन इकोनॉमी इन ट्रांजिशन**—एस. जनकराजन, एल. वेंकटचलम, आर. मारिया सालेठ (संपादित)
- **दि पाकिस्तान पैराडॉक्स-इनस्टैबिलिटी एंड रेजिलिएंस**—क्रिस्टोफर जैफरलट
- **दि राइट टू बी : एन इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रेंस बुक ऑन ह्यूमन राइट्स** —जेना सोराबजी
- **ट्रांसडेंस : माई स्प्रीचुअल एक्सपीरिएंस विद प्रमुख स्वामी जी** —अब्दुल कलाम एवं अरुण तिवारी
- **रेड टेप टू रेड कार्पेट** —जीना राइनहार्ट
- **बीहमी सदी द डोगरी द गद्य साहित्य** —डॉ. विजय सेठ
- **बेनजीर भुट्टो : ए मल्टीडायमेंशनल पोर्ट्रेट** —डॉ. अन्ना सुवोरोवा
- **बिखरे खयालात** —अब्दुल हक
- **द कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स : टूजी पॉवर एंड प्राइवेट इंटरप्राइज : ए प्रैक्टिसनर डायरी** —प्रदीप बैजल
- **फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट : द सिंगापुर स्टोरी** —ली कुआन यू
- **चाइना-कन्फ्यूशियस इन शैडो** —पूनम सूरी
- **अनबिलीवेबल - डेहली टू इस्लामाबाद** —प्रो. भीम सिंह
- **राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर** —यशवंत सिंह
- **मैनेज, लिव एंड लीड** —वेंकट चंगावल्ली
- **ड्राइविंग यूपीज ग्रोथ थ्रू पॉवर सेक्टर** —ए.के. माथुर (संपादन)
- **गीत श्री** —डॉ. गोपालदास 'नीरज'
- **टू ईयर्स एट मंथ्स एंड ट्वेंटी एट नाइट्स** —सलमान रूश्दी
- **गॉड बैंकर्स : ए हिस्ट्री ऑफ मनी एंड पॉवर** —गेराल्ड पोजनर
- **इंडियन पार्लियामेंटरी डिप्लोमेसी-स्पीकर्स पर्सपेक्टिव** —मीरा कुमार
- **फ्लड ऑफ फायर** —अमिताव घोष
- **द राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट** —पैट्रिक कॉकबर्न
- **आतंक के साये में** —गरिमा संजय
- **फेसेज एंड प्लेसेज** —प्रो. दीपक नायर
- **फरिश्ता** —कपिल ईशापुरी
- **माई नेम इज अबु सलेम** —एस. हुसैन जैदी
- **मेकर्स ऑफ मॉर्डन एशिया** —रामचंद्र गुहा
- **लखनऊ ब्वॉय : ए मेमोयर (आत्मकथा)** —विनोद मेहता
- **एडीटर अनप्लग्ड : मीडिया, मैग्नेट्स नेताज एंड मी** —विनोद मेहता
- **मीना कुमारी** —विनोद मेहता
- **द संजय स्टोरी फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी** —विनोद मेहता
- **रशिया इन ट्रांजीशन** —विनोद मेहता
- **द इंटरनेट इज नॉट द आंसर** —एंड्रयू कीन
- **सूफी लौट आए हैं** —डॉ. चन्द्र त्रिखा
- **मैंडेट : विल ऑफ द पीपुल** —वीर सांघवी
- **द नेमसेक एवं द लोलैंड** —झुम्पा लाहिड़ी
- **इंडिया : द फ्यूचर इज नॉउ, विजडम ट्री (संपा.)** —शशि थरूर
- **ए गॉड इन इवरी स्टोन** —कमिला शम्सी
- **नूनटाइड टॉल** —रामेश गुणेसकेरा
- **द मिरर ऑफ ब्यूटी** —शमसुर रहमान फारुकी
- **दौड़** —ममता कालिया
- **द बेटरमैन** —अनिता नायर
- **दैट लांग साइलेंस** —शशि देशपांडे
- **स्माल रेमिडीज** —शशि देशपांडे
- **बुक ऑफ कॉमन साइंस** —अशोक श्रीनिवासन
- **फर्स्ट ड्रॉफ्ट** —बी.जी. वर्गीज
- **पोस्ट हेस्ट** —बी.जी. वर्गीज
- **फिगर्स ऑफ हिस्ट्री** —जैक्स रेंसियर
- **लिटरेचर एज हिस्ट्री** —छंदा चटर्जी

- **एन. ओडिशी इन तिब्बत - ए पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर** —तरुण विजय
- **सोनिया गांधी - एन एक्स्ट्रा आर्डिनरी लाइफ** —रानी सिंह
- **एन. ओडिशी इन वॉर एंड पीस** —ले.जन. (रिटा.) जेएफआर जैकब
- **सरेंडर एट ढाका** —ले. जन. (रिटा.) जेएफआर जैकब
- **वंदेभारतम्** —पं. प्रमोद कुमार मिश्र
- **इन द लाइट ऑफ व्हॉट वी नो** —जिया हैदर रहमान
- **हैंगवीमेन** —के. आर. मीरा
- **इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ एडमंड बर्क** —डेविड ब्रोमविक
- **माई प्रामिस्ड लैंड : द ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ इजराइल** —अरी शावित
- **मुस्लिम जिओन** —फसेल देवजी
- **बोस एंड नेहरू : पैरेलल लाइव्स** —रुद्राहंशू मुखर्जी
- **कैपिटल इन द 21st सेंचुरी** —थॉमस पिकेटी
- **आर्डोर (Ardor)** —राबर्ट कलासो
- **फायर इन द अननेमेबल कंट्री** —गालिब इस्लाम
- **इंडियन चेस हिस्ट्री** —मेनुअल आरो, विजय डी पंडित
- **हाउ मोदी वोन इन** —हरीश खरे
- **रॉक-कट वोन इन** —हरीश खरे
- **ए कनसाइज हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया** —नोबोरू काराशिमा
- **द डेमोक्रेटिक डिकेड ; द इंदिरा गांधी ईयर्स** — प्रणब मुखर्जी (आत्मकथा त्रयी की पहली पुस्तक)
- **द वे थिंग्स वर** —आतिश तासीर
- **नेक्रोपोलिस** —अवतार सिंह
- **द बर्निंग रूम** —माइकल कॉनेली
- **रिवाइवल** —स्टेफल फिंग
- **प्रिंसलेस्टेट** —एन. राइस
- **41** —जॉर्ज डब्ल्यू. बुश
- **अ पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर** —जॉर्ज डब्ल्यू. बुश
- **यस प्लीज़** —एमी पोहलर
- **स्मॉल विक्टरीज** —एन. लैमट
- **एंपायर टू इंडिपेंडेंस** —मेजर जनरल जय कृष्ण कौशिक
- **आईएम मलाला : द गर्ल हू स्टुड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय तालिबान** —मलाला युसुफजई व क्रिस्टीना लैम्ब
- **माई ब्रीफ हिस्ट्री** —स्टीफन हॉकिंग

दिवस/वर्ष/दशक

राष्ट्रीय (National) दिवस

- **राष्ट्रीय एकता दिवस** : 31 अक्टूबर, 2015 को पूरे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाने का निर्णय लिया था।
- **अभियंता दिवस** : 15 सितंबर, 2015 को देश भर में अभियंता दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'ज्ञान के इस युग में इंजीनियरिंग की चुनौतियां' था।
- **शिक्षक दिवस** : 5 सितंबर, 2015 को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की 125वीं जयंती मनाई गई।
- **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस** : 7 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' का उद्घाटन किया।
- **कारगिल विजय दिवस** : 26 जुलाई, 2015 को देश भर में कारगिल विजय दिवस की 16वीं सालगिरह मनाई गई।
- **राष्ट्रीय प्रसारण दिवस** : 23 जुलाई, 2015 को देश भर में 'राष्ट्रीय प्रसारण दिवस' मनाया गया। 23 जुलाई को ही देश में सर्वप्रथम 1927 में बंबई से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस** : 29 जून, 2015 को भारत में नौवां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस की थीम 'सामाजिक विकास' थी। यह दिवस प्रो. पी. सी. महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
- **भूजल सप्ताह** : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 16 से 22 जुलाई, 2015 के मध्य जन सहभागिता के माध्यम से भूगर्भ जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 'भूजल सप्ताह' का आयोजन किया गया।
- **आतंकवाद विरोधी दिवस :** 21 मई, 2015 को देश भर में 'आतंकवाद विरोधी दिवस' मनाया गया। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है।
- **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस** : 11 मई, 2015 को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' का नारा दिया।
- **राष्ट्रीय बंधुत्व भव/समरसता दिवस** : 14 अप्रैल, 2015 को देश भर में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में 'राष्ट्रीय बंधुत्व भव/समरसता दिवस' मनाया गया।
- **राष्ट्रीय विज्ञान दिवस** : 28 फरवरी, 2015 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'राष्ट्र निर्माण के लिए विज्ञान' था।
- **कुष्ठ रोग-विरोध दिवस** : 30 जनवरी, 2015 को देश भर में कुष्ठ रोग विरोध दिवस मनाया गया।
- **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** : 25 जनवरी, 2015 को भारत में पांचवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (वर्ष 2011 से प्रारंभ) मनाया गया।
- **राष्ट्रीय युवा दिवस** : 12 जनवरी, 2015 को स्वामी विवेकानंद की 152वीं जयंती के अवसर पर 'राष्ट्रीय युवा दिवस' देश भर में मनाया गया।
- **भारत जल सप्ताह-2015** : 13 जनवरी, 2015 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने इसका उद्घाटन किया।
- **राष्ट्रीय गणित दिवस** : 22 दिसंबर, 2014 को देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती थी।
- **राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस** : 14 दिसंबर, 2014 को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया।
- **विजय दिवस** : 16 दिसंबर, 2014 को 43वां विजय दिवस वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की याद में मनाया गया।
- **राष्ट्रीय सुशासन दिवस** : 25 दिसंबर (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर)।
- **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** : 26 नवंबर, 2014 को श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की 93वीं जयंती के अवसर पर इस दिन को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' के रूप

में मनाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय (International) दिवस

- **विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस :** 21 अक्टूबर, 2015 को आयोडीन की जरूरत के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए दुनियाभर में 'विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस' मनाया गया।
- **विश्व सांख्यिकी दिवस :** 20 अक्टूबर, 2015 को दुनियाभर में 'बेहतर डेटा बेहतर जीवन' की थीम के साथ 'विश्व सांख्यिकी दिवस' मनाया गया।
- **विश्व छात्र दिवस :** 15 अक्टूबर, 2015 को दुनियाभर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 84वीं जयंती के अवसर पर 'विश्व छात्र दिवस' मनाया गया।
- **विश्व ऑडियो विजुअल विरासत :** 27 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'आरकाइव्स एट रिस्क : प्रोटेक्टिंग दि वर्ल्ड्स आइडेंटिटीज' विषय के साथ 'विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस' मनाया गया।
- **विश्व पोलियो दिवस :** 24 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में पोलियो के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए 'विश्व पोलियो दिवस' मनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस :** 17 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'धारणीय भविष्य का निर्माण : गरीबी एवं भेदभाव को खत्म करने के लिए साथ आना' विषय के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस' मनाया गया।
- **विश्व खाद्य दिवस :** 16 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'विश्व खाद्य दिवस' मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'सोशल प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर' था।
- **ह्वाइट केन दिवस :** 15 अक्टूबर, 2015 को विश्व भर में ह्वाइट केन दिवस मनाया गया। यह दिवस नेत्रहीन एवं दृष्टिबाधित लोगों की चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए मनाया गया।
- **ग्लोबल हैंड वाशिंग डे :** 15 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'गलोबल हैंड वाशिंग डे' मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'रेज ए हैंड फॉर हाइजीन' था।
- **अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस :** 15 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस' मनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस :** 13 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस' मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'नॉलेज फॉर लाइफ' था।
- **विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस :** 10 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ' विषय के साथ 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' मनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण दिवस :** 11 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर, 2015 को 'अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण दिवस' (International Day of Commemoration & Dignity of the Victims of Genocide) मनाने का निर्णय लिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस :** 11 अक्टूबर, 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 'द पॉवर ऑफ एडोलसेंट गर्ल : विजन फॉर 2030' विषय के साथ मनाया गया।
- **विश्व डाक दिवस :** 9 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'बदलते संचार परिदृश्य में डाक का महत्त्व' था।
- **विश्व दृष्टि दिवस :** 8 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में 'आई केयर फॉर ऑल' विषय के साथ 'विश्व दृष्टि दिवस' मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है।
- **विश्व पर्यावास दिवस :** 5 अक्टूबर, 2015 को 'पब्लिक स्पेसेज फॉर ऑल' विषय के साथ दुनिया भर में विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया। यह दिवस वर्ष 1985 से अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है।
- **विश्व पशु दिवस :** 4 अक्टूबर, 2015 को दुनिया भर में विश्व पशु दिवस मनाया गया। यह दिवस पशुओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस :** 2 अक्टूबर, 2015 को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' मनाया गया। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' मनाने की घोषणा की गई थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस :** 1 अक्टूबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दुनिया भर में मनाया गया। इस दिवस की थीम 'सस्टेनेबिलिटी एंड ऐज इंक्लूज़िवनेस इन द अर्बन इनवायरमेंट' थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस :** 30 सितंबर, 2015 को दुनिया भर में 'द चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग' विषय के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस' मनाया गया।
- **विश्व हृदय दिवस :** 29 सितंबर, 2015 को दुनिया भर में 'क्रिएटिंग हार्ट-हेल्थी एनवायरमेंट' विषयवस्तु के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया।
- **विश्व रेबीज दिवस :** 28 सितंबर, 2015 को दुनिया भर में 'एंड रेबीज टूगेदर' विषय के साथ 'विश्व रेबीज दिवस' मनाया गया।
- **विश्व पर्यटन दिवस :** 27 सितंबर, 2015 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के पर्यटन दिवस का विषय 'वन बिलियन टूरिस्ट, वन बिलियन अपॉर्च्युनिटीज' था।
- **विश्व गैंडा दिवस :** 22 सितंबर, 2015 को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस मनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस :** 21 सितंबर, 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'पार्टनरशिप फॉर पीस-डिग्निटी फॉर ऑल' था।
- **विश्व अल्जाइमर दिवस :** 21 सितंबर, 2015 को दुनिया भर में 'रिमेंबर मी' थीम के साथ 'विश्व अल्जाइमर दिवस' मनाया गया।
- **ओजोन परत संरक्षण दिवस :** 16 सितंबर, 2015 को ओजोन परत संरक्षण के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय '30 ईयर ऑफ हीलिंग द ओजोन टूगेदर-ओजोन : आल देयर इज बिटवीन यू एंड अल्ट्रावायलेट' था। वर्ष 2015 ओजोन परत संरक्षण के वियना कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ है।
- **विश्व आत्महत्या निवारण दिवस :** 10 सितंबर, 2015 को दुनिया भर में 'प्रिवेंटिंग सुसाइड : रीचिंग आउट एंड सेविंग लाइव्स' नामक थीम के साथ विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया गया।

- **विश्व मानवता दिवस** : 19 अगस्त, 2015 को दुनिया भर में 'इंस्पायरिंग द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी' थीम के साथ विश्व मानवता दिवस मनाया गया।
- **विश्व फोटोग्राफी दिवस** : 19 अगस्त, 2015 को दुनिया भर में 'विश्व फोटोग्राफी दिवस' मनाया गया।
- **विश्व जैव ईंधन दिवस** : 10 अगस्त, 2015 को विश्व भर में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया।
- **हिरोशिमा दिवस** : 6 अगस्त, 2015 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम के हमले के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 70वां हिरोशिमा दिवस मनाया गया।
- **मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस** : 30 जुलाई, 2015 को विश्व भर में मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने 'गिव होप' नामक विश्वव्यापी अभियान प्रारंभ किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस** : 29 जुलाई, 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया।
- **नेल्सन मंडेला दिवस** : 18 जुलाई, 2015 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया।
- **विश्व युवा कौशल दिवस** : 15 जुलाई, 2015 को विश्व भर में पहली बार 'विश्व युवा कौशल दिवस' (WYSD) मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र म
- **विश्व जनसंख्या दिवस** : 11 जुलाई, 2015 को दुनिया भर में 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'आपात स्थिति में असुरक्षित जनसंख्या' था। यह दिवस वर्ष 1989 से मनाया जा रहा है।
- **विश्व पर्यावरण दिवस** : 5 जून, 2015 को दुनियाभर में 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस की थीम 'सात अरब सपने, एक ग्रह, सावधानी से करें उपभोग' थी। इस वर्ष इस दिवस का वैश्विक मेजबान इटली था।
- **यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग डे** : 29 मई, 2015 को विश्व भर में 'यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग डे' मनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस** : 22 मई, 2015 को दुनिया भर में 'अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस' मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'निरंतर विकास के लिए जैव विविधता' था।
- **मदर्स डे** : 10 मई, 2015 को विश्व भर में 'मदर्स डे' मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है।
- **विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस** : 3 मई, 2015 को विश्व स्तर पर 'प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया गया।
- **विश्व मजदूर दिवस** : 1 मई 2015 को दुनिया भर में 'विश्व मजदूर दिवस' मनाया गया।
- **विश्व नृत्य दिवस** : 29 अप्रैल, 2015 को दुनिया भर में विश्व नृत्य दिवस मनाया गया।
- **विश्व मलेरिया दिवस** : 25 अप्रैल, 2015 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम-'भविष्य में निवेश करें, मलेरिया को हराएं' थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस** : 22 अप्रैल, 2015 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'इट्स अवर टर्न टू लीड' था।
- **विश्व विरासत दिवस** : 18 अप्रैल, 2015 को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया गया।
- **विश्व स्वास्थ्य दिवस** : 7 अप्रैल, 2015 को दुनिया भर में 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' मनाया गया, जिसका केंद्रीय विषय 'खाद्य सुरक्षा' था।
- **अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस** : 27 मार्च, 2015 को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस' मनाया गया।
- **अर्थ ऑवर, 2015** : 28 मार्च, 2015 को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के तत्वाधान में 'अर्थ ऑवर' का आयोजन हुआ।
- **विश्व मौसम विज्ञान दिवस** : 23 मार्च, 2015 को दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया।
- **विश्व जल दिवस** : 22 मार्च, 2015 को विश्व भर में 'विश्व जल दिवस' मनाया गया जिसका केंद्रीय विषय 'पानी एवं सतत विकास' था।
- **अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस** : 21 मार्च, 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया जिसकी थीम 'जलवायु परिवर्तन और वन' थी।
- **विश्व गौरैया दिवस** : 20 मार्च, 2015 को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया।
- **विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस** : 15 मार्च, 2015 को पूरे विश्व में 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' मनाया गया। ज्ञातव्य है कि भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- **भेड़ वर्ष** : 19 फरवरी, 2015 को चीन में प्रारंभ हुए नये चंद्र वर्ष को 'भेड़ वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2014 को चीन ने 'घोड़ा वर्ष' तथा वर्ष 2013 को 'सर्प वर्ष' के रूप में मनाया था जबकि वर्ष 2016 को 'बंदर वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।
- **विश्व वन्यजीव दिवस** : 3 मार्च, 2015 को दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के इस दिवस का विषय 'वन्यजीव अपराध गंभीर है, इसके बारे में गंभीर हों' था।
- **अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस** : 21 फरवरी, 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया।
- **विश्व ब्रेल दिवस** : 4 जनवरी, 2015 को पूरे विश्व में लुई ब्रेल के जन्मदिवस के अवसर पर 'विश्व ब्रेल दिवस' मनाया गया।
- **विश्व हिन्दी दिवस** : 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय विभाग ने लिया।
- **प्रथम विश्व मृदा दिवस** : 5 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रथम विश्व मृदा दिवस मनाया गया तथा वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** : 21 जून (संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित)।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस** : 18 दिसंबर, 2014 को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस** : 9 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया।
- **विश्व शौचालय दिवस** : 19 नवंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र विश्व शौचालय दिवस मनाया गया।
- **20 मार्च** : अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ; भूटान के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में घोषित।
- **अर्थ ओवर शूट डे, 2015** : अर्थ ओवर शूट डे (Earth Over Shoot Day) इस वर्ष 13 अगस्त को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का तात्पर्य यह है कि चालू वर्ष हेतु प्रकृति द्वारा आवंटित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग मानव ने इस दिन तक कर लिया है।

वर्ष

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष** : वर्ष 2015 को प्रकाश एवं प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का वर्ष मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिया गया।
- **वर्ष 2015-16 : जल संरक्षण वर्ष** (भारत में)
- **सांस्कृतिक विरासत का दक्षेस वर्ष** : 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में हुए सार्क देशों के संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में वर्ष 2016-17 को सार्क विरासत के दक्षेस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया।
- **2016** : खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा 'दलहन वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की गई।

चर्चित व्यक्ति (राष्ट्रीय)

- **छोटा राजन** : 26 अक्टूबर, 2015 को भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया। वह पिछले 27 साल से फरार चल रहा था। उसे भारत को प्रत्यर्पित करने की प्राक्रिया जारी है।
- **अर्जुन वाजपेयी एवं भूपेश कुमार** : 20 अक्टूबर, 2015 को भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी एवं भूपेश कुमार की जोड़ी ने हिमाचल प्रदेश की स्पीती घाटी की एक 6180 ऊंची अनाम पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी करके वापसी की। उन्होंने इस पर्वत का नाम भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में माउंट कलाम रखा।
- **शाहरुख खान** : 16 अक्टूबर, 2015 को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान परोपकार व मानवतावाद के क्षेत्र में उनके योगदान तथा अभिनेता के रूप में उनकी वैश्विक पहुंच को देखते हुए दिया गया।
- **अरुण जेटली** : अक्टूबर, 2015 में भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली लंदन की प्रतिष्ठित पत्रिका 'इमर्जिंग मार्केट्स' द्वारा 'फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, एशिया' चुने गए।
- **ए. आर. रहमान** : 8 अक्टूबर, 2015 को भारतीय संगीतकार ए. आर. रहमान को सेशेल्स के सांस्कृतिक दूत के रूप में मनोनीत किया गया।
- **अंकित फाडिया** : सितंबर, 2015 के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार ने अंकित फाडिया को 'डिजिटल इंडिया' का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की।
- **राघवेंद्र गडगकर** : 7 अगस्त, 2015 को भारतीय समाज जैवविज्ञानी राघवेंद्र गडगकर को जर्मनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। वे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रोफेसर हैं।
- **डी. परुलेकर** : 7 अगस्त, 2015 को गोवा के पर्यटन मंत्री डी. परुलेकर को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन (पटवा-PATWA) सफारी इंडिया साउथ एशिया ट्रेवल अवॉर्ड-2015 से सम्मानित किया गया।
- **अमोल पालेकर** : अगस्त, 2015 में फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता अमोल पालेकर को भारत की ऑस्कर ज्यूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- **सैयद हैदर रजा** : 14 जुलाई, 2015 को आधुनिक भारतीय चित्रकार सैयद हैदर रजा को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया।
- **डॉ. कमल बावा** : 3 जुलाई, 2015 को भारत के जैव और पर्यावरण विज्ञानी डॉ. कमल बावा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। उन्हें वर्ष 2014 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
- **मनोज गंभीर** : ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय में महामारी एवं रोकथाम औषध विभाग में सहायक प्रोफेसर मनोज गंभीर ने इबोला वायरस के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सबसे प्रभावी मानवीय परीक्षणों के प्रकार की पहचान की।
- **सनी वर्के** : जून, 2015 के प्रथम सप्ताह में दुबई में रहने वाले भारतीय शिक्षा उद्यमी सनी वर्के अपनी आधे से अधिक संपत्ति दुनियाभर के शिक्षकों की मदद के लिए दान कर 'द गिविंग प्लेज' कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
- **भंवर लाल जैन दोषी** : 31 मई, 2015 को दिल्ली के अरबपति व्यापारी भंवर लाल जैन दोषी ने अपनी सारी संपत्ति त्यागकर अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में लाखों धर्मावलंबियों के बीच जैन आचार्य गुणरत्न सूरीश्वरजी से दीक्षा ली।
- **स्वामी शिवानंद** : 22 मई, 2015 को हरिद्वार में स्वामी शिवानंद ने गंगा में अवैध खनन के खिलाफ कठोर तप शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्राण त्यागने की अनुमति मांगी है।
- **यदुवीर कृष्णदत्त वॉडेयार** : 28 मई, 2015 को मैसूर राजघराने के 27वें महाराजा के रूप में 'यदुवीर कृष्णदत्त वॉडेयार' की ताजपोशी की गई।
- **आयुष्मान खुराना** : 10 अप्रैल, 2015 को फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को 'विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन' का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था। 'विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन' 3 मई, 2015 को 6 महाद्वीपों के 35 देशों में आयोजित किया गया।
- **विश्वनाथन आनंद** : 1 अप्रैल, 2015 को लघु ग्रह केंद्र समिति ने वर्ष 1988 में जापान द्वारा मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य एक लघु ग्रह का नाम भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सम्मानित करते हुए '4538 विश्वानंद' रखने की घोषणा की।
- **सैफ अली खान** : 10 मार्च, 2015 को ब्रिटेन की राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी 'विजिट ब्रिटेन' ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को 'बॉलीवुड ब्रिटेन' नामक अभियान का प्रचारक बनाया।
- **अमिताभ बच्चन** : 22 फरवरी, 2015 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को 'द फिल्म हेरीटेज फाउंडेशन' का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया। 6 जनवरी, 2015 को अमिताभ बच्चन को आंध्र प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर भी नामित किया गया।
- **बाबा रामदेव** : 15 जनवरी, 2015 को योग गुरु बाबा रामदेव को हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया।
- **मधु किन्नर** : 4 जनवरी, 2015 को निर्दलीय उम्मीदवार एवं ट्रांसजेंडर मधु किन्नर ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर का चुनाव जीता। मधु किन्नर छत्तीसगढ़ के प्रथम ट्रासजेंडर मेयर हैं।
- **वीएस गायतोंडे** : 2 जनवरी, 2015 को चित्रकार वीएस गायतोंडे की कलाकृति 'अमूर्त लैंडस्केप' 23 करोड़ रुपए में बिकी। वे सबसे महंगे भारतीय चित्रकार बनकर उभरे।
- **के. राधाकृष्णन** : दिसंबर, 2014 के अंत में दुनिया की प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका 'नेचर' ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के तत्कालीन प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन को विश्व के शीर्ष 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया।

चर्चित व्यक्ति (अंतर्राष्ट्रीय)

- **दलाई लामा** : 27 अक्टूबर, 2015 को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को पूरे विश्व में करुणा और मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया।
- **अहमद अदीब** : 24 अक्टूबर, 2015 को मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को सितंबर, 2015 में हुए एक बम विस्फोट के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

- **जॉन ऐश** : 7 अक्टूबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष जॉन ऐश समेत पांच लोगों को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जॉन ऐश पर चीनी उद्योगपति से 13 लाख डॉलर से अधिक की रिश्वत लेकर उसे सरकारी ठेका दिलाने का आरोप है। वे महासभा के 68वें सत्र के अध्यक्ष थे।
- **सियोंग जिन चो** : 20 अक्टूबर, 2015 को दक्षिण कोरिया के सियोंग जिन चो ने वारसा (पोलैंड) में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेडरिक चोपिन पियानो प्रतियोगिता में जीत हासिल की।
- **कार्तिक चंद्रन** : सितंबर, 2015 में भारतीय मूल के अमेरिकी पर्यावरण इंजीनियर कार्तिक चंद्रन को वर्ष 2015 के मैक आर्थर 'जीनियस ग्रांट' की 6.25 फेलोशिप के लिए चयनित किया गया। चंद्रन को यह फेलोशिप अपशिष्ट जल को उर्वरक, ऊर्जा और स्वच्छ जल में बदलने की दिशा में कार्य करने के लिए मिली है।
- **डी. पटेल** : सितंबर, 2015 के अंत में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा भारतीय-ब्रिटिश वैन ड्राइवर डी. पटेल को 'प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवॉर्ड' से सम्मानित करने की घोषणा की। डी. पटेल ने अपनी जान पर खेलकर एक कार चालक की जान बचाई थी।
- **अशोक अलेक्जेंडर श्रीधरन** : 14 सितंबर, 2015 को जर्मनी के बॉन शहर के मेयर के रूप में निर्वाचित होने वाले अशोक अलेक्जेंडर श्रीधरन भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। उन्होंने 21 अक्टूबर, 2015 को अपना कार्यभार ग्रहण किया।
- **गेनाडी पैडलका** : 12 सितंबर, 2015 को रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पैडलका ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया। अपने पांचवें अंतरिक्ष मिशन में पैडलका ने 168 दिन अंतरिक्ष में बिताये। वे अब तक कुल 879 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। इसके पहले यह रिकॉर्ड रूस के सर्गेई क्रिकालेव के नाम था।
- **तेजिंदर पाल सिंह** : 31 अगस्त, 2015 को भारतीय मूल के ड्राइवर तेजिंदर पाल सिंह को ऑस्ट्रेलिया में कामनवेल्थ बैंक द्वारा 'ऑस्ट्रेलियन ऑफ दि डे' घोषित किया गया।
- **नोवाक जोकोविक** : 26 अगस्त, 2015 को दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया।
- **अजीज हक्कानी** : अगस्त, 2015 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के नए नेता अजीज हक्कानी को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया।
- **शिव पांडे** : 17 जुलाई, 2015 को भारतीय मूल के डॉक्टर शिव पांडे को इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर ने साधारण चिकित्सक के रूप में उनके सामुदायिक योगदान के लिए मानद फेलोशिप से सम्मानित किया।
- **एंथनी ब्रूटो** : मई, 2015 में अमेरिका के एंथनी ब्रूटो ने 94 साल की उम्र में वर्जीनिया यूनीवर्सिटी से डिग्री हासिल की।
- **बराक ओबामा :** 20 मई, 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का ट्विटर अकाउंट खोले जाने के पांच घंटे के भीतर एक मिलियन फालोवर्स के जुड़ने से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
- **अखिल अमर :** 20 मई, 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने येल विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर अखिल अमर को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मानविकी परिषद (नेशनल काउंसिल ऑन ह्यूमेनिटीज) के सदस्य के रूप में नामित किया।
- **करण मेनन :** 13 मई, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र करण मेनन ने नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली भूगोल प्रतियोगिता 'नेशनल ज्योग्राफिक बी' जीती।
- **डेनियल मुखी :** 12 मई, 2015 को भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई डेनियल मुखी ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सांसद पद की शपथ ग्रहण की। उन्होंने <u>गीता</u> पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की।
- **थॉमस बाख :** 22 अप्रैल, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख को यूएन वीमेन द्वारा लैंगिक समानता के लिए आयोजित अभियान 'ही फॉर शी' का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया।
- **मोहम्मद मुर्सी :** 16 मई, 2015 को मिस्र की एक अदालत ने मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी सहित 100 से अधिक आरोपियों को वर्ष 2011 में जेल तोड़कर कैदियों को भगाने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई।
- **री सू योंग :** 12 से 14 अप्रैल, 2015 के मध्य उत्तरकोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग ने भारत की तीन दिवसीय यात्रा की। वे उत्तर कोरिया के पहले विदेश मंत्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की।
- **मुहम्मद कमरुज्जमां** : 11 अप्रैल, 2015 को बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में युद्ध अपराधों और सामूहिक हत्याओं के आरोप में जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता मुहम्मद कमरुज्जमां को फांसी पर लटका दिया गया।
- **ओवन डन** : अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में ब्रिटेन के नॉर्थ यॉर्कशायर के 11 वर्षीय स्कूली छात्र ओवन डन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेंसा आइक्यू (बौद्धिक ज्ञान) परीक्षण में 162 अंक हासिल किए। इस छात्र का मस्तिष्क विख्यात भौतिकशास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग से भी तेज बताया जा रहा है जिनके मस्तिष्क के आइक्यू का आकलन 160 आंका गया था।
- **मुल्ला फजलुल्ला** : 7 अप्रैल, 2015 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला को प्रतिबंधित आतंकवादी घोषित किया है।
- **मुहम्मदू बुहारी** : 1 अप्रैल, 2015 को नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व सैन्य तानाशाह मुहम्मदू बुहारी (ऑल प्रोग्रेसिव्स कांग्रेस-एपीसी) ने 25.7 लाख वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने 29 मई, 2015 को नाइजीरिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।
- **वेंकटरमन रामकृष्णन** : 18 मार्च, 2015 को भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार (रसायन शास्त्र) विजेता सर वेंकटरमन रामकृष्णन को ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष पद हेतु चयनित किया गया। वे 1 दिसंबर, 2015 को अपना पद ग्रहण करेंगे। वे सर पॉल नर्स का स्थान लेंगे।
- **विजय कुमार** : मार्च, 2015 के मध्य में भारतीय मूल के अमेरिकी विशेषज्ञ विजय कुमार पेंसिलवेनिया विश्वविद्यालय के डीन पद हेतु नामित हुए।
- **मोहम्मद नशीद** : 14 मार्च, 2015 को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को आतंकवाद मामले में 13 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
- **स्टीफन हॉकिंग** : मार्च, 2015 के अंत में विश्व के प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टीफन हाकिंग ने अपने नाम को ब्रांड बनाने की घोषणा की।
- **कुमार धर्मसेना** : 29 मार्च, 2015 को आईसीसी क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मुकाबले में फील्ड अम्पायर श्रीलंका के 'कुमार धर्मसेना' विश्व के पहले ऐसे अम्पायर बने जो बतौर खिलाड़ी विश्व कप फाइनल (वर्ष 1996 में) का भी हिस्सा थे।
- **बेंजामिन नेतान्याहू** : 18 मार्च, 2015 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की लिकुड पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने चौथी बार इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।
- **राहुल जिंदल** : 3 मार्च, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक राहुल जिंदल को प्रतिष्ठित <u>फुटब्राइट-नेहरू विशिष्ट सम्मान</u> के लिए चयनित किया गया।

- **एलेक्स रुकिन** : 12 जनवरी, 2015 को ब्रिटेन के नौ वर्षीय एलेक्स रुकिन ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं।
- **लैरी पेज** : 6 जनवरी, 2015 को गूगल के सहसंस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लैरी पेज को प्रतिष्ठित पत्रिका फार्च्यून ने 'पर्सन ऑफ द ईयर-2014' घोषित किया।
- **जेम्स डी. वॉटसन** : दिसंबर, 2014 में जेम्स डी. वॉटसन ने 4.8 मिलियन डॉलर में अपने नोबेल पुरस्कार पदक की नीलामी कर दी। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। उल्लेखनीय है कि उन्हें वर्ष 1962 में डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

चर्चित महिलाएं (राष्ट्रीय)

- **स्टेफी ग्राफ** : 23 जून, 2015 को जर्मनी की पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ को केरल पर्यटन विभाग की 'विजिट केरल योजना' को प्रोत्साहित करने के लिए केरल की आयुर्वेद ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया।
- **एन.एल. बेनो जेफीन** : 12 जून, 2015 को चेन्नई की एन.एल. बेनो जेफीन भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली नेत्रहीन महिला बनीं।
- **मानबी बंधोपाध्याय :** 9 जून, 2015 को भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल के रूप में मानबी बंधोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर वीमेन्स कॉलेज में शपथ ली।
- **जे. जयललिता :** 23 मई, 2015 को जे. जयललिता ने पांचवी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके पहले 11 मई, 2015 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था।
- **दीपा कुमारी :** 23 मई, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की अंपायरिंग समिति ने भारत की दीपा कुमारी को पदोन्नत करके अंतर्राष्ट्रीय आउटडोर अंपायर का दर्जा प्रदान किया।
- **वी. सरिता :** 17 अप्रैल, 2015 को वी. सरिता को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की पहली महिला बस ड्राइवर नियुक्त किया गया। वे तेलंगाना की हैं।
- **ऊषा** : 8 अप्रैल, 2015 को राजस्थान की ऊषा ने 'ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज' (बीएएसएएस) के सालाना सम्मेलन में 'भारत में स्वच्छता और महिलाओं के अधिकार' विषय पर संबोधित किया। वे सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ी हुई हैं।
- **मरियम सिद्दीकी** : 3 अप्रैल, 2015 को मुंबई की कास्मोपॉलिटन हाईस्कूल की कक्षा छह की बारह वर्षीया छात्रा मरियम आसिफ सिद्दीकी ने इस्कॉन द्वारा अयोजित अंतरविद्यालय भगवद्गीता प्रतियोगिता जीती।
- **सतवंत अटवाल त्रिवेदी** : 20 मार्च, 2015 को आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं।
- **एम.सी. मैरीकॉम** : 14 मार्च, 2015 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज एम.सी. मैरीकॉम को पूर्वोत्तर क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया।
- **सुमित्रा महाजन** : फरवरी, 2015 में लोक सभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन का नाम 'लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स' में दर्ज किया गया। उनके नाम एक ही पार्टी के टिकट पर लगातार 8 बार लोक सभा के लिए निर्वाचित होने का रिकॉर्ड है। वे ऐसा करने वाली देश की पहली महिला हैं।
- **दीपिका मिश्रा** : 21 फरवरी, 2015 को भारतीय वायु सेना की महिला स्क्वैड्रन लीडर दीपिका मिश्रा भारतीय एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर-फार्मेशन टीम की पहली महिला पायलट बन गईं।
- **रेखा** : दिसंबर, 2014 में पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा (PETA) ने बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा को भारत की सबसे लोकप्रिय शाकाहारी शख्सियत के रूप में चुना। उनके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सबसे लोकप्रिय शाकाहारी हस्ती के रूप में चुना गया।
- **ताशी और नुंग्शी मलिक** : दिसंबर, 2014 में भारत की जुड़वां बहनों ताशी और नुंग्शी मलिक ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विन्सन का सफल आरोहण कर सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने (सेवन समिट अभियान) का रिकॉर्ड बनाया। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 2015 को इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग कर ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड भी बनाया।
- **पूर्णिमा गुप्ते** : 12 जनवरी, 2015 को केंद्र सरकार ने पूर्णिमा गुप्ते को द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) का सदस्य नियुक्त किया। वे इरडा (IRDA) की सदस्य नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।

चर्चित महिलाएं (अंतर्राष्ट्रीय)

- **स्वेथा प्रभाकरन** : 15 सितंबर, 2015 को भारतीय मूल की 15 वर्षीय छात्रा स्वेथा प्रभाकरन ने अमेरिका में व्हाइट हाउस द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार प्राप्त किया। स्वेथा 'एवरीबडी कोड नॉऊ' नामक गैर सरकारी संस्था की संस्थापक हैं जो अगली पीढ़ी के युवाओं को इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं उद्यमी बनाने के लिए सशक्त करती है।
- **गीता** : 26 अक्टूबर, 2015 को पंद्रह साल पहले गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचने वाली मूक-बधिर गीता भारत वापस लौटी। बिहार के जनार्दन महतो ने गीता के अपनी बेटी होने का दावा किया है। गीता ईदी फाउंडेशन की मदद से लाहौर एवं कराची में रह रही थी।
- **सुमित्रा महाजन** : 4 सितंबर, 2015 को भारतीय लोक सभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनियाभर के संसदीय अध्यक्षों के सत्र की अध्यक्षता की।
- **प्रीथिका कुमार** : 4 सितंबर, 2015 को अमेरिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत भारतीय मूल की प्रोफेसर प्रीथिका कुमार को 'आउटस्टैंडिंग टीचर अवॉर्ड' के लिए चुना गया।
- **महारानी एलिजाबेथ द्वितीय** : 9 सितंबर, 2015 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के शाही तख्त पर सबसे लंबे समय तक रहने वाली शासिका बनी। उन्होंने महारानी विक्टोरिया के 63 वर्ष तक शासन करने के रिकॉर्ड को तोड़ा।
- **सुनीता विश्वनाथ** : 16 जुलाई, 2015 को भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुनीता विश्वनाथ को अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस द्वारा 'चैंपियंस ऑफ चेंज' से सम्मानित किया गया। वे पिछले 14 वर्षों से महिला अधिकारों के लिए काम कर रही हैं।
- **मुतुल काया** : 24 जून, 2015 को तुर्की की गायिका मुतुल काया कोमा से बाहर आ गईं। उन्हें कट्टरपंथियों ने रिएलिटी शो में हिस्सा लेने के चलते सिर में गोली मार दी थी। मुतुल काया को 'तुर्की की मलाला' कहा जा रहा है।
- **लुइस रिचर्डसन** : मई, 2015 के अंत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रो. लुइस रिचर्डसन को अपनी पहली महिला कुलपति बनाने का फैसला लिया है। वे जनवरी, 2016 से अपना पद ग्रहण करेंगी।

- **तस्लीमा नसरीन** : मई, 2015 के अंत में 'लज्जा' जैसे चर्चित उपन्यास की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में फरवरी, 2015 में हुई तीन धर्मनिरपेक्ष ब्लागरों की हत्या के बाद भारत छोड़ अमेरिका में शरण ली।
- **हरभजन कौर धीर :** 12 मई, 2015 को भारतीय मूल की महिला हरभजन कौर धीर को ब्रिटेन में मेयर निर्वाचित किया गया। वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की प्रथम महिला हैं।
- **राजराजेश्वरी :** 27 अप्रैल, 2015 को भारतीय मूल की महिला राजराजेश्वरी ने न्यूयॉर्क की आपराधिक अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें यह पद प्राप्त हुआ है।
- **लोरेटा लिंच :** 27 अप्रैल, 2015 को लोरेटा लिंच ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 83वें अटार्नी जनरल के रूप में शपथ ली। वे इस पद पर पहुँचने वाली पहली अफ्रीकी-अमेरिकी महिला हैं।
- **मार्जीह अफखाम** : 14 अप्रैल, 2015 को ईरान द्वारा 36 वर्षों के बाद अपने राजदूत के रूप में किसी महिला की नियुक्ति की घोषणा की गई है। मार्जीह अफखाम ईरान की अब तक की केवल दूसरी महिला राजदूत होंगी।
- **मलाला यूसुफजई** : 11 अप्रैल, 2015 को नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के नाम पर एक एस्टेराइड (क्षुद्र ग्रह) का नाम 'मलाला एस्टेरॉइड' रखा गया।
- **मिएको नागाओका** : 4 अप्रैल, 2015 को जापान की सौ वर्षीया तैराक मिएको नागाओका ने जापान के मात्सूयामा शहर में हुए मास्टर्स मीट की 1500 मीटर स्पर्धा में प्रतिभाग किया।
- **रेणु खटोर** : 16 मार्च, 2015 को भारतीय मूल की अमेरिकी रेणु खटोर को अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया।
- **फोलोरुनशो अलाकिजा** : दिसंबर, 2014 के अंत में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे अमीर अश्वेत महिला नाइजीरिया की तेल एवं फैशन व्यवसायी फोलोरूनशो अलाकिजा हैं।
- **रेवरेंड लिबि लेन** : 17 दिसंबर, 2014 को ब्रिटेन की पहली महिला बिशप के रूप में रेवरेंड लिबि लेन के नाम की घोषणा की गई। वह बिशप ऑफ स्टॉकपोर्ट बनी हैं।

चर्चित स्थल (राष्ट्रीय)

- **अमरावती** : 22 अक्टूबर,2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की नींव गुंटूर जिले में रखी। यह आंध्र प्रदेश के व्यावसायिक हब विजयवाड़ा से मात्र 40 किमी. की दूरी पर स्थित है। अमरावती, प्राचीन भारत में सातवाहनों के काल में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहां के स्तूप बहुत चर्चित हैं जिन पर भित्ति प्रतिमाओं में बुद्ध के जीवन के विविध दृश्य उकेरे गये हैं। यहां पर वास्तुकला एवं मूर्तिकला की स्वदेशी शैली (अमरावती स्कूल) विकसित हुई थी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को सिंगापुर की मदद से बनाया जा रहा है।
- **आगरा** : 8 अक्टूबर, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 के 4-5 जनवरी को आगरा में उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों के जरिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 'उ. प्र. एनआरआई दिवस' मनाने की घोषणा की। यह राज्य का पहला एनआरआई दिवस होगा।
- **ललितपुर** : 20 सितंबर, 2015 को ललितपुर के 1980 मेगावाट बिजलीघर से उत्पादन शुरू हो गया। उत्पादन के लिहाज से यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजलीघर है। ललितपुर की दूसरी 660 मेगावाट की इकाई नवंबर, 2015 में शुरू हो जाएगी।
- **अब्दुल कलाम द्वीप** : सितंबर, 2015 के प्रथम सप्ताह में ओडिशा सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए मिसाइल परीक्षण स्थल 'व्हीलर द्वीप' का नाम बदलकर 'अब्दुल कलाम' द्वीप रख दिया।
- **झारखंड** : 8 सितंबर, 2015 को झारखंड सरकार ने 'आतंकवाद निरोधी दस्ते' का गठन किया।
- **हरियाणा** : सितंबर, 2015 में हरियाणा सरकार ने प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी।
- **सिरसिला** : 2 अक्टूबर, 2015 को तेलंगाना के सिरसिला विधान सभा क्षेत्र ने देश के पहले पूर्ण शौचालययुक्त विधान सभा के लक्ष्य को पूरा किया। सिरसिला के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है।
- **कानपुर** : 8 सितंबर, 2015 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावर चंद गहलोत ने कानपुर में 'निचले अंग कृत्रिम प्रणाली' (Lower Limb prosthetic System) के नए केंद्र का उद्घाटन किया।
- **तंजावुर** : सितंबर, 2015 में तमिल विश्वविद्यालय के समुद्र इतिहास और समुद्र पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने तमिलनाडु के तंजावुर में संगमकालीन और मध्य चोलकालीन समृद्ध बंदरगाह शहर के अस्तित्व की खोज की।
- **जबलपुर** : 1 सितंबर, 2015 को पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, जबलपुर (मध्य प्रदेश) को मानवरहित लेवल क्रॉसिंग खत्म करने वाला देश का पहला रेलवे जोन घोषित किया गया।
- **श्री वडक्कुम्नाथन मंदिर** : 1 सितंबर, 2015 को यूनेस्को ने केरल के श्री वडक्कुम्नाथन मंदिर को 'अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया। इस मंदिर को यह पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार की श्रेणी में दिया गया।
- **जैसलमेर** : 24 अगस्त, 2015 को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन में स्थापित 'जैसलमेर युद्ध संग्रहालय' का उद्घाटन किया गया। इसे भारत-पाक युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया।
- **पेइकंरुबू** : तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित पेइकंरुबू में 30 जुलाई, 2015 को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार किया गया। इस स्थल पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा तमिलनाडु सरकार ने एक स्मारक बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत एक पुस्तकालय, संग्रहालय तथा ध्यान केंद्र शामिल होंगे।
- **दीघा-पहलेजा रेल पुल** : 8 अगस्त, 2015 को देश के सबसे लंबे रेल पुल 'दीघा-पहलेजा' का उद्घाटन किया गया। यह पाटिलपुत्र जंक्शन से पहलेजा के मध्य पड़ता है। इससे उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जुड़ने में आसानी होगी।
- **बस्तर** : अगस्त, 2015 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में मगरमच्छों के पार्क बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया। इस पार्क का निर्माण इंद्रावती टाइगर रिजर्व में करीब 6 हेक्टेयर के तालाब में किया जाएगा।
- **कोच्चि** : 10 अगस्त, 2015 को चीन के बीजिंग स्थित वर्ल्ड टूरिज्म सिटीज फेडरेशन काउंसिल के सदस्य के रूप में शामिल होने वाला कोच्चि भारत का पहला शहर बन गया।
- **गुरुदासपुर** : 27 जुलाई, 2015 को पंजाब के गुरुदासपुर जिले के दीनानगर पुलिस थाने पर तीन आतंकवादियों ने हमला कर दिया। पुलिस एवं आतंकियों की बीच चली 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकी मार गिराए गए। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए।

- **जुआरी नदी** : 15 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ, गोवा) ने गोवा की जुआरी नदी पर 3500 ई. पू. से 1000 ई. के मध्य के एक प्राचीन बंदरगाह के अवशेषों की खोज की।
- **राजमुंदरी** : 14 जुलाई, 2015 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित क्षेत्र राजमुंदरी में 'महापुष्करम' मेले के पहले दिन हुई भगदड़ में 27 लोगों की मृत्यु हो गई।
- **वरुणाव्रत पर्वत** : जुलाई, 2015 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित वरुणाव्रत पर्वत श्रृंखला की तंबाखानी सुरंग के ऊपरी हिस्से में 25 मीटर लम्बी व 4 से 5 इंच चौड़ी दरार आ गई जिससे उस क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।
- **कोल्लम (ववारा)** : केरल प्रांत के कोल्लम जिले के ववारा में स्थित 'केरल मिनरल एंड मेटल्स' में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा स्थापित किए गए '<u>स्वदेशी टाइटेनियम स्पॉन्ज संयंत्र</u>' ने गत दिनों पूर्णतः काम करना शुरू किया। इसी के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक टाइटेनियम का यहां वाणिज्यिक उत्पादन किया जाने लगा है।
- **परासी (तमाड़)** : भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा झारखंड प्रांत के तमाड़ नामक स्थान के परासी गांव में सोने की खान का पता लगाया गया है। यहां भूगर्भ में एक लाख टन सोना दबा होने का अनुमान है। परासी गांव स्वर्णरिखा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी बालू में सोने के कण पाए जाते हैं।
- **समेरा (पलामू)** : झारखंड प्रांत के पलामू के समेरा नामक गांव में 'कोमाटिआइट चट्टान' की खोज की गई है, जिसमें 0.7% प्लेटिनम के अंश पाए गए हैं।
- **ओट्टापल्लम** : 'मेक इन इंडिया' एवं 'मेक इन केरल' पहलों के तहत केरल प्रांत में स्थित '<u>ओट्टापल्लम</u>' नामक स्थान में देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क (Defence Industrial Park) स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2015 को प्रदान की गई।
- **सिंगहोली ब्राह्मण (बागपत)** : 'यमुना-हिन्डन दोआब पुरातत्व अन्वेषण परियोजना' के तहत की गई खुदाई में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के 'सिंगहोली ब्राह्मण' (Singholi Brahmin) नामक गांव में हड़प्पा युग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार ये बर्तन 17वीं सदी ई.पू. के हैं।
- **जतिंगा** : भारत के असम प्रांत के दिमा हसाओ जिला की हाफलौंग चोटी पर अवस्थित जतिंगा नामक स्थान विश्व में पक्षियों के आत्महत्या स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां (लगभग डेढ़ किलोमीटर दायरे में) बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भवनों और पेड़ों से टकराकर आत्महत्या करते हैं। जतिंगा में यह घटना अक्टूबर-नवंबर महीनों में प्रतिवर्ष देखने को मिलती है।
- **नालकोंडा (तेलंगाना)** : भारत के नवसृजित राज्य तेलंगाना के नालकोंडा जिले में 'डिन्डी नदी' (Dindi River) के समीप 'पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग' द्वारा लगभग 200 मीटर गहराई में एक प्राचीन एवं प्राकृतिक जुड़वां गुफा (Twin Caves) की खोज की गई है।
- **चामराजनगर (कर्नाटक)** : 'जीनस एंटीलोप' (Genus Antilope) प्रजाति के जीवित मृगों में शामिल भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले कृष्णमृगों (Blackbucks) को संरक्षित करने के उद्देश्य से कर्नाटक के 'चामराजनगर' में एक 'कृष्णमृग कंजर्वेशन अभयारण्य' (Blackbuck Conser-vation Resere) की स्थापना प्रस्तावित है। इसे लगभग 1504.39 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जाने की योजना है।
- **रामदेवरा बेट्टा (कर्नाटक)** : लंबी चोंच वाले दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों को संरक्षित करने के उद्देश्य से कर्नाटक प्रांत के रामनगरम में स्थित रामदेवरा बेट्टा (Ramdevara Betta) में राज्य सरकार एक गिद्ध भोजन केंद्र खोलने जा रही है, जहां गिद्धों को डाइक्लोफेनेक से मुक्त मरे हुए जानवर भोजन हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **नासिक** : 14 जुलाई से 25 सितंबर, 2015 के मध्य महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर नासिक में 'सिंहस्थ कुंभ' का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि कुंभ मेले का आयोजन देश में चार स्थानों—हरिद्वार (गंगा), इलाहाबाद (प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम), नासिक (गोदावरी) एवं उज्जैन (क्षिप्रा) में होता है।
- **छपरा** : 24 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान बिहार के छपरा जिले के लाला का टोला में एक 'राष्ट्रीय स्मारक' की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।
- **मुंबई** : जून, 2015 के अंत में ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी दुनिया में पर्यटकों की दृष्टि से 10 महत्त्वपूर्ण शहरों की सूची में मुंबई पांचवां बजट अनुकूल (सस्ता) शहर बताया गया है। मुंबई को हनोई (वियतनाम), वारसा (पोलैंड), शर्म अल शेख (मिस्र) तथा बैंकाक (थाईलैंड) के बाद रखा गया है।
- **अयोध्या** : 25 जून, 2015 को केंद्र सरकार ने अयोध्या (फैजाबाद) में रामायण संग्रहालय बनाने की घोषणा की।
- **त्रिपुरा** : 27 मई, 2015 को त्रिपुरा सरकार ने राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) हटाने का फैसला लिया। त्रिपुरा में यह कानून वर्ष 1997 से लागू किया गया था।
- **विष्णुपुर** : 20 मई, 2015 को पश्चिम बंगाल सरकार ने मध्ययुगीन टेराकोटा मंदिरों और गौरवशाली अतीत के लिए मशहूर शहर विष्णुपुर को अपना पहला धरोहर शहर बनाने की घोषणा की।
- **रीवा** : 28 अप्रैल, 2015 को मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की रीवा जिले की गुढ़ तहसील में स्थापना को हरी झंडी दे दी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 750 मेगावाट होगी।
- **बर्नपुर :** 10 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट (आइएसपी) राष्ट्र को समर्पित किया।
- **थाणे** : वर्ष 2015 में महाराष्ट्र के थाणे को 'नेशनल अर्थ ऑवर कैपिटल' बनाया गया। वर्ष 2014 में यह सम्मान कोयंबटूर को मिला था।
- **विशाखापत्तनम एवं भीमावरम** : 3 अप्रैल, 2015 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम एवं भीमावरम को समुद्री उत्पाद वर्ग में 'उत्कृष्ट निर्यातक नगर' के रूप में चिह्नित किया गया।
- **लखनऊ** : 14 मार्च, 2015 को लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों के लिए वाई-फाई सुविधा की शुरुआत हुई। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा रेलवे जंक्शन है (आगरा कैंट के बाद) तथा पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन है जो वाई-फाई सुविधा से लैस हुआ।
- **लद्दाख** : 6 मार्च, 2015 को लद्दाख (J & K) के यांग गांव में बर्फीले स्तूप के आकार के कृत्रिम ग्लेशियर जलाशय का उद्घाटन किया गया। इसके निर्माण का उद्देश्य यांग गांव में जल संग्रह करना है।
- **राजस्थान** : मार्च, 2015 में दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलंतरी गांव, बालिका शिशु के जन्म के समय एक सौ ग्यारह पेड़ लगाने की परंपरा के कारण चर्चा में रहा।
- **त्रिपुरा** : 6 मार्च, 2015 को त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने उत्तर-पूर्व के पहले किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन प्रदेश की राजधानी अगरतला में किया।
- **बरेली** : 14 मार्च, 2015 को केंद्रीय कपड़ा सचिव ने उत्तर प्रदेश के बरेली में टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क के स्थापना की घोषणा की।
- **मिजोरम** : 9 मार्च, 2015 को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का उत्तर-पूर्वी भारत में औपचारिक शुभारंभ मिजोरम के सैहा (Saiha) जिले से किया गया।

- **हरियाणा** : 27 फरवरी, 2015 को हरियाणा सरकार ने 'अंतर्जातीय विवाह योजना' के तहत मिलने वाली नकद पुरस्कार राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रु. कर दिया।
- **सैफई** : 4 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई स्थित 'उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान' को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया।
- **कोलकाता** : 5 फरवरी, 2015 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में वाई-फाई परिसेवा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलकाता वाई-फाई सुविधा वाला देश का पहला शहर बन गया।
- **मुकुंदपुर** : मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर नामक स्थान पर स्थित प्राणी उद्यान में विश्व की प्रथम ह्वाइट टाइगर सफारी स्थापित की जा रही है।
- **लखनऊ में प्लास्टिक क्लस्टर** : मार्च, 2015 के प्रारंभ में चैम्बर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ निर्यात-केंद्रित प्लास्टिक क्लस्टर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव दिया है।
- **जगदीशपुर** : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर नामक स्थान पर 'पेपर मिल' लगाने को मंजूरी दी।
- **लमही** : जनवरी, 2015 में साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के गांव 'लमही' को देश के दस प्रांतों से चुने गए दस गांवों में शामिल किया गया। लमही को उत्तर प्रदेश का पहला 'मॉडल ई-पंचायत' गांव बनाया जाएगा।
- **हरियाणा** : 15 जनवरी, 2015 को हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हरियाणा में हजारों एकड़ भूमि पर विश्व का पहला 'वर्ल्ड हर्बल फारेस्ट' बनाया जाएगा।
- **दांडी कुटीर म्यूजियम** : 13वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में दांडी कुटीर म्यूजियम का उद्घाटन किया जो महात्मा गांधी के जीवन व कार्यों पर आधारित है।
- **नमक पर्वत (साल्ट माउंटेन)** : 13वें पीबीडी के दौरान 8 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधी नगर में महात्मा मंदिर परिसर के निकट स्थापित किए गए महात्मा गांधी को समर्पित 'साल्ट माउंटेन' स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह 60 हजार वर्ग फीट में विस्तारित महात्मा मंदिर का ही भाग है।
- **असम** : युनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड (यूनीसेफ) ने असम का चाय एटलस (Tea Atlas) तैयार करने का निर्णय लिया है जो राज्य के चाय मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों एवं चाय बागानों का एक व्यापक डाटाबेस होगा।
- **सुखना झील** : 19 दिसंबर, 2014 को चंडीगढ़ की सुखना झील की मृत बत्तखों में एवियन इंफ्लूएंजा वायरस पाया गया।
- **गुजरात** : 23 नवंबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर गुजरात सरकार ने 'एमएलए आदर्श ग्राम योजना' की शुरुआत की।
- **कच्छ** : नवंबर, 2014 में गुजरात के कच्छ में सुजलोन एनर्जी द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची एवं पहली हाइब्रिड पवन टरबाइन की शुरुआत की गई। यह टरबाइन 120 मीटर ऊंची है जिसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1100 मेगावॉट है।
- **सूर्य मंदिर** : 13 जनवरी, 2015 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने ओडिशा के सूर्य मंदिर को 'आदर्श स्मारक' (Adarsh Monument) का टैग दिया। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के हजारदुआरी पैलेस, बिहार के वैशाली-कोल्हाआ तथा असम के रंग घर को भी आदर्श स्मारक (Adarsh Monument) का टैग दिया गया।
- **कलाग्रामम** : 29 दिसंबर, 2014 को भारत के पहले वैश्विक कलाकार ग्राम 'कलाग्रामम' की स्थापना केरल के कन्नूर जिले में की गई।
- **सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान** : 11 जनवरी, 2015 को हरियाणा के गुड़गांव स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस उद्यान में 47 प्रवासी पक्षी मृत पाए गए थे।

चर्चित स्थल (अंतर्राष्ट्रीय)

- **बुखारेस्ट** : 30 अक्टूबर, 2015 को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एक नाइट क्लब में हुए विस्फोट से 27 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 150 से अधिक घायल हो गए। यह विस्फोट नाइट क्लब के भीतर आतिशबाजी के कारण हुआ।
- **मियामी** : 26 अक्टूबर, 2015 को अमेरिका के मियामी शहर ने दुनिया का सबसे बड़ा रेत का किला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसे गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी।
- **न्यूयॉर्क** : अक्टूबर, 2015 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाये जा रहे दुनिया के पहले अंडरग्राउंड पार्क के कुछ हिस्से को खोला गया। लॉलाइन नामक इस पार्क के मुख्य निर्माणकर्ता नासा के पूर्व इंजीनियर जेम्स रामसे हैं।
- **तुर्की** : 10 अक्टूबर, 2015 को तुर्की की राजधानी अंकारा में दो आत्मघाती बम धमाकों में 86 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 186 अन्य घायल हो गए। हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ होने की आशंका है।

आईएस द्वारा धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का विध्वंस

- फरवरी, 2015 में इराक के मोसुल शहर में 7वीं सदी के चर्च 'अल-तहेरा' को विस्फोट से आईएस आतंकियों ने उड़ा दिया।
- मार्च, 2015 में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इराक के मोसुल शहर में वर्ष 1880 में निर्मित मस्जिद 'हमू-अल-कादू' को जमींदोज कर दिया।
- 10 मार्च, 2015 को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने मोसुल में स्थित 10वीं सदी के 'काल्डियन कैथोलिक सेंट मार्कोकस चर्च' को विध्वंस से उड़ा दिया।
- 5 अप्रैल, 2015 को सीरिया के तेल नसरी में स्थित असीरियन क्रिश्चियन वरजिन मैरी चर्च को आईएस ने ढहाया।
- **बालशामिन मंदिर** : 23 अगस्त, 2015 को सीरिया के पल्माइरा शहर के बालशामिन मंदिर को 'इस्लामिक स्टेट' (आईएस) के आतंकियों ने विस्फोट से उड़ा दिया। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था, यह सीरिया के सर्वोच्च देवता का मंदिर था। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था।
- 30 अगस्त, 2015 को सीरिया के पल्माइरा में स्थित बेल मंदिर को उड़ा दिया गया।
- **आर्च ऑफ ट्रियंफ** : 5 अक्टूबर, 2015 को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के आर्च ऑफ ट्रियंफ को विस्फोट से उड़ा दिया। सीरिया की यह इमारत पल्माइरा शहर में स्थित है जिसे 2000 वर्ष पहले रोमन सम्राट के पल्माइरा आगमन पर बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि रेगिस्तान के मोती के रूप में पहचाने जाने वाला प्राचीन मरुउद्यान शहर पल्माइरा सीरिया की राजधानी दमिश्क से 210 किमी. पूर्वोत्तर में स्थित है। यहां बने दुर्ग एवं अवशेषों को यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 28 मार्च, 2015 को यूनेस्को की महानिदेशिका इरीना बोकोवा ने 'यूनाइट फोर हेरिटेज' (Unite 4 Heritage) नामक अभियान प्रारंभ किया है जिससे कट्टरपंथियों के खतरे से ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों को बचाया जा सके।

- **कुंदुज** : 3 अक्टूबर, 2015 को अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के कुंदुज में किए हमले में मैडिसंस सैंस फ्रंटियर्स (एमएसएफ) के अस्पताल में 22 लोगों की मृत्यु होने के बाद अमेरिका ने अपनी गलती मानी। इसके पहले अफगान सुरक्षा बलों ने कुंदुज पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का दावा किया है। रणनीतिक रूप से अह्म इस शहर पर तालिबानी आतंकियों ने 28 सितंबर, 2015 को कब्जा कर लिया था।
- **जापान** : 19 सितंबर, 2015 को जापान की संसद द्वारा उस कानून को पारित किया गया, जिसके तहत जापान की सेना अपने मित्र देशों की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में भी जाकर युद्ध कार्रवाइयों में भाग ले सकेगी।
- **लंदन** : 27 अगस्त, 2015 को भारत ने लंदन स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर के तीन मंजिला मकान का मालिकाना हक हासिल कर लिया। अब इस ऐतिहासिक इमारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1921-22 में अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान यहां रहते थे।
- **सउदी अरब** : 30 अगस्त, 2015 को सउदी अरब में महिलाओं को पहली बार स्थानीय चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने का अधिकार मिल गया। सउदी अरब में 12 दिसंबर, 2015 को स्थानीय चुनाव होने हैं। उल्लेखनीय है कि दिवंगत शाह अब्दुल्ला ने वर्ष 2011 में महिलाओं को वर्ष 2015 तक मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी।
- **कोनाक्री** : 21 जुलाई, 2015 को यूनेस्को ने गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री को वर्ष 2017 के 'वर्ल्ड बुक कैपिटल' के रूप में चुना। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया था।
- **गढ़ीमाई मंदिर** : नेपाल में स्थित गढ़ीमाई मंदिर में प्रत्येक पांचवें वर्ष आयोजित किए जाने वाले पशुबलि मेले में पशुओं की दी जाने वाली बलि पर 28 जुलाई, 2015 को मंदिर ट्रस्ट द्वारा रोक लगा दी गई। अनेक मानवतावादी एवं पशु कल्याण के कार्यों से जुड़े संगठन लगातार यहां पशुबलि रोकने की मांग कर रहे थे।
- **उत्तर कोरिया** : 15 अगस्त, 2015 को उत्तर कोरिया ने अपने लिए अलग टाइम जोन की स्थापना करते हुए घड़ी को 30 मिनट पीछे कर दिया, जिसे 'प्योंगयांग टाइम' नाम दिया गया।
- **टस्कनी** : इटली में स्थित 'टस्कनी' नामक स्थान पर विश्व का पहला ऐसा अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जो भूतापीय (Geothermal) एवं बायोमास (Biomass) ऊर्जा को समन्वित करने में सक्षम है।

- **कनाडा** : जून, 2015 के प्रथम सप्ताह में कनाडा की एक अदालत ने तीन बड़ी तंबाकू कंपनियों पर 12 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया।
- **जापान** : 17 जून, 2015 को जापान की संसद डाइट द्वारा वहां मतदान की आयु 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया गया।
- **हवाई** : 19 जून, 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य ने धूम्रपान (स्मोकिंग) की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने संबंधी कानून पारित किया। ऐसा करने वाला वह अमेरिका का पहला राज्य है।
- **हुसैनीवाला गांव** : 8 जुलाई, 2015 को भारतीय सेना ने सैनिकों के बलिदान के सम्मान में पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला गांव में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया।
- **जेवर** : जून, 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में नागरिक उड्डयन के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए ग्रेटर नोएडा के जेवर नामक स्थान पर एक अन्य हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया।
- **क्यूबा** : 30 जून, 2015 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की महानिदेशिका मार्गरेट चान ने क्यूबा को माँ से बच्चे को होने वाले एचआईवी संक्रमण को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया।
- **हसनपुर** : 24 जून, 2015 को हरियाणा के सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित देश के प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र 'नन्दघर' का उद्घाटन किया गया।
- **बेलान्दुर झील** : जून, 2015 के प्रथम सप्ताह में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) के शोधकर्ताओं ने बंगलुरू स्थित बेलान्दुर झील के पानी में लगी आग के कारण की खोज की। वैज्ञानिकों के अनुसार 16 मई, 2015 को झील के पानी में लगी आग दूषित औद्योगिक प्रवाह के कारण थी।
- **कनॉट प्लेस** : 18 जून, 2015 को जारी ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस दुनिया का पांचवां सबसे महंगा कार्यालय स्थल है। सर्वे के अनुसार लंदन का वेस्ट एंड विश्व का सबसे महंगा कार्यालय स्थल है।
- **कुशीनगर** : 14 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुशीनगर जिले में दो नई तहसीलों क्रमशः <u>खड्डा</u> एवं <u>कप्तानगंज</u> का उद्घाटन किया।
- **मुल्लिवाईकल** : 19 मई, 2015 को श्रीलंका के उत्तर दिशा में स्थित मुल्लिवाईकल नामक गांव में लोगों ने लिट्टे व श्रीलंका सेना के बीच हुए युद्ध में मारे गये लोगों की याद में 'स्मरणोत्सव' मनाया। इसी गांव में लिट्टे व श्रीलंकाई सेना के बीच 37 वर्षीय युद्ध का समापन 19 मई, 2009 को हुआ था।
- **रमादी** : 17 मई, 2015 को इराक की राजधानी बगदाद के निकट स्थित शहर रमादी पर इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आंतकियों ने कब्जा कर लिया।
- **भूमध्य सागर** : 19 अप्रैल, 2015 को भूमध्य सागर में एक जहाज में हादसा होने से 800 से अधिक लोगों की समुद्र में डूबकर मृत्यु हो गई। जहाज में सीरिया, सोमालिया व इरीट्रिया के नागरिक सवार थे।
- **मलेशिया** : 7 अप्रैल, 2015 को मलेशिया की संसद ने आतंकवाद रोकथाम विधेयक (पोटा) पारित किया। यह कानून 'इस्लामिक स्टेट' (आईएस) जैसे आतंकी संगठनों की ओर से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए लाया गया है।
- **फ्रांस** : 3 अप्रैल, 2015 को फ्रांस के निचले सदन नेशनल असेंबली में कानून बनाकर अत्यधिक दुबली-पतली मॉडलों के कैटवॉक करने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस ने यह कदम एनोरेक्सिया (भूख न लगने वाला रोग) पर रोकथाम के लिए उठाया है। उल्लेखनीय है कि इटली, स्पेन और इजरायल में यह कानून पहले से है।
- **केन्या** : 2 अप्रैल, 2015 को केन्या की गैरीसा यूनिवर्सिटी में आतंकी संगठन अल शबाब ने हॉस्टल में सो रहे छात्रों पर हमला किया जिसमें 147 छात्र मारे गये तथा 79 से ज्यादा घायल हुए।
- **ट्यूनीशिया** : 18 मार्च, 2015 को ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस स्थित बार्डो संग्रहालय पर इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें 18 विदेशी नागरिकों समेत 23 लोगों की मौत हो गई।
- **लंदन** : 14 मार्च, 2015 को लंदन में ब्रिटिश संसद के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बापू की नौ फीट कांसे की इस प्रतिमा का अनावरण ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया।
- **एल. कैमिनिटो डेल रे** : 28 मार्च, 2015 को स्पेन के मालगा में स्थित विश्व का सबसे खतरनाक रास्ता 'एल कैमिनिटो डेल रे' तकरीबन 15 साल बाद पुनः खोला गया। इसे 'महाराजा का छोटा रास्ता' भी कहते हैं, जो कि दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस रास्ते की लंबाई 3 किमी. तथा चौड़ाई एक मीटर से भी कम है।
- **द किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी** : 21 मार्च, 2015 को सऊदी अरब के रेगिस्तान में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से भी बड़े शहर का डिजाइन दुनिया

के सामने पेश किया गया। इस नये शहर का नाम 'द किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी' होगा।

- **थाईलैंड** : 19 फरवरी, 2015 को थाईलैंड की अंतरिम संसद ने किराये की कोख यानी सरोगेसी के कारोबार को खत्म करने के लिए एक कानून पास किया।
- **स्वीडन** : 30 अक्टूबर, 2014 को स्वीडन यूरोपीय यूनियन का पहला देश बना जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी।
- **जॉर्डन** : फरवरी, 2015 के प्रथम सप्ताह में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकियों ने जॉर्डन के एक लेफ्टिनेंट कमांडर पायलट अल-कसाबेह को जिंदा जलाने का वीडियो जारी किया। इस घटना से पूरे जॉर्डन में तनाव उत्पन्न हुआ।
- **हातरा एवं निमरुद :** मार्च, 2015 के प्रारंभ में इराकी सरकार की घोषणा के अनुसार आईएस (इस्लामिक स्टेट) के कट्टरपंथियों ने हातरा एवं निमरुद के ऐतिहासिक शहरों को नष्ट कर दिया है।
- **द मरानी टॉर्च** : 21 फरवरी, 2015 को दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत 'द मरानी टॉर्च' में आग लग गई जिस पर बाद में काबू पा लिया गया।
- **बागा** : जनवरी, 2015 के प्रथम सप्ताह में नाइजीरिया के बागा शहर में इस्लामी चरमपंथी आतंकी संगठन बोको हराम ने दो हजार लोगों को मार डाला। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा यह बोको हराम का अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार बताया गया।
- **पेरिस** : 7 जनवरी, 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने चर्चित फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका '<u>शार्ली एब्दो</u>' के ऑफिस पर हमला करते हुए पत्रिका के संपादक स्टीफन शार्बोनिय (शार्ब) सहित कुल 12 लोगों की हत्या कर दी।
- **नेपाल** : दिसंबर, 2014 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ई-ज्यूडिशिअरी सिस्टम की शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी 90 न्यायालयों को ई-न्यायालय में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
- **म्यांमार** : 27 दिसंबर, 2014 को म्यांमार में पिछले 60 वर्षों के दौरान पहली बार नगरपालिका के चुनाव हुए। म्यांमार के सबसे बड़े शहर 'यंगून' में 'यंगून सिटी डेवलपमेंट कमेटी' (YCDC) के चुनाव में 300 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
- **सिडनी** : 15 दिसंबर, 2015 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक कैफे में ईरानी मूल के हारून मोनिस नामक कट्टरपंथी आतंकी ने लोगों को बंधक बना लिया। बंधकों में दो भारतीय नागरिक विश्वकांत अकी रेड्डी और पुष्पेंदु घोष भी थे जिन्हें सुरक्षित बचाया गया।
- **पेशावर** : 16 दिसंबर, 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में एक सैनिक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले में 136 बच्चों सहित कुल 160 लोग मारे गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ली। यह हमला पाकिस्तान सेना द्वारा चलाए जा रहे '<u>ऑपरेशन जर्ब ए-अज्ब</u>' का बदला लेने के लिए आतंकियों ने किया।
- **मालदीव** : दिसंबर, 2014 के प्रारंभ में मालदीव में समुद्र के खारे पानी को साफ पानी में बदलने वाले डिसेलिनेशन प्लांट के खराब हो जाने के कारण वहां भयंकर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत द्वारा सहायता के रूप में विमानों व जलयानों से मालदीव पानी उपलब्ध कराया गया।
- **नामीबिया** : 28 नवंबर, 2014 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला नामीबिया अफ्रीका का पहला देश बन गया है।
- **फर्ग्युसन :** अमेरिका के फर्ग्युसन शहर में अश्वेत नागरिक माइकल ब्राउन को मामूली विवाद में गोली मार देने वाले श्वेत पुलिस अधिकारी को ग्रैंड ज्यूरी ने क्लीनचिट दे दी जिससे पूरे अमेरिका में नस्लीय तनाव व्याप्त हो गया।
- **ऑलफोंस एरीना** : 17 नवंबर, 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के अवसर पर सिडनी स्थित <u>ऑलफोंस एरीना स्टेडियम</u> में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया।
- **सार्क की सांस्कृतिक राजधानी** : 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में संपन्न सार्क देशों के संस्कृति मंत्रियों की तीसरी बैठक में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक शहर 'बामियान' को वर्ष 2015-16 के लिए सार्क की 'सांस्कृतिक राजधानी' बनाया गया। वर्ष 2016-17 के लिए सार्क सांस्कृतिक राजधानी के रूप में 'ढाका' का चयन किया गया।

<u>परियोजनाएं/कार्यक्रम</u>

- **एनआरआई मिशन** : 22 सितंबर, 2015 को अमेरिका में 30 लाख अनिवासी भारतीयों ने 'कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज' के सहयोग से 'मिशन 2022' की शुरुआत की। इसके तहत अगले सात वर्षों में कई वार्ताएं आयोजित की जाएंगी जिससे भारत एवं अमेरिका के सहयोग संबंधों को और मजबूती दी जा सके।
- **पीड़िता क्षतिपूर्ति स्कीम** : 15 सितंबर, 2015 को दिल्ली सरकार ने 'पीड़िता क्षतिपूर्ति स्कीम' का प्रारंभ किया जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 3 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रु. तथा तेजाब हमले की पीड़िता को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 3 लाख रु. से बढ़ाकर 7 लाख रु. कर दी गई।
- **ई-प्रगति परियोजना** : 5 सितंबर, 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए 'एपी स्टेट इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर' ई-प्रगति परियोजना की शुरुआत की।
- **शतकीय महिला पहल** : सितंबर, 2015 के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'शतकीय महिला पहल' योजना की शुरुआत की। इसके द्वारा 100 कामयाब महिलाओं के नाम फेसबुक के जरिए मांगे गए हैं जिन्होने पूरे देश में समुदाय और राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है।
- **नीलगिरि परियोजना** : सितंबर, 2015 में रेल टेल एवं गूगल के संयुक्त प्रयास से नीलगिरि परियोजना की शुरुआत की गई जिसके तहत देश के 400 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई सेवा प्रदान की जाएगी। इसके द्वारा उपयोगकर्ता पहले 30 मिनट में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके हाईस्पीड इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे।
- **नई मंजिल** : 8 अगस्त, 2015 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के संबंध में समग्र दृष्टिकोण एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 'नई मंजिल' योजना का शुभारंभ किया। यह योजना अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों की शैक्षिक एवं जीविकोपार्जन की जरूरतों में मदद करेगी। यह योजना ड्रॉप आउट छात्रों को भी लक्ष्यित करने के लिए बनाई गई है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 17-35 वर्ष के आयु समूह के लोगों को शामिल किया जाएगा।
- **नियतम कार्यक्रम** : 'नियतम' (Niti Initiative to Yield Aspirational Targets and Actionable Means–NIYATAM) नीति आयोग का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत जहां राज्यों की प्रशासन में दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे, वहीं राज्यों में लोककल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम को 'नियतम' नाम श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक के आधार पर दिया गया है। 'नियतम' की शुरुआत अभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल एवं झारखण्ड से की जानी है। आंकड़े जुटाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों में मौजूदा योजनाओं एवं विभागों की संख्या भी कम की जानी है। आदर्श स्थिति में किसी भी राज्य में विभागों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **स्कूल नर्सरी योजना** : राष्ट्र को स्वच्छ एवं हरित बनाने, छात्र-छात्राओं को प्रकृति

के निकट लाने एवं उन्हें पर्यावरण के महत्त्व से अवगत कराने के उद्देश्यों से 10 अगस्त, 2015 को केंद्र सरकार के 'वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' द्वारा 'स्कूल नर्सरी योजना' का सूत्रपात किया गया। इस योजना के तहत जहां स्कूली छात्र-छात्राओं को स्कूल की नर्सरियों में पौधा तैयार करने के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा, वहीं उनसे स्कूलों एवं आस-पास के क्षेत्रों में लगे हुए वृक्षों की गणना भी करवाई जाएगी। यह उनकी पाठ्यक्रम से अतिरिक्त गतिविधि होगी। इस योजना में वर्ष 2017 तक लगभग 10,000 स्कूलों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत स्कूलों को वाटर रीसाइकिलिंग, वर्षा जल के संचय एवं कम्पोस्ट खाद बनाने जैसी गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

- **कायाकल्प** : 15 मई, 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनस्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कृत करने की एक 'कायाकल्प' नामक पहल शुरू की। इसके तहत कुल पांच पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल, दो सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रत्येक जिले में) को पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
- **निर्मल गंगा सहभागिता कार्यक्रम** : 7 मई, 2015 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने गंगा को साफ करने के उद्देश्य से गंगा के किनारे अवस्थित नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर निर्मल गंगा सहभागिता कार्यक्रम नामक एक संपोषणीय पहल प्रारंभ की है।
- **यूजीसी की 'एक छात्र एक पेड़' योजना** : मई, 2015 के मध्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में सर्कुलर जारी कर 'एक छात्र एक पेड़' योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।
- **वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन योजना** : इस योजना के द्वारा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मूल्यांकन और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित किया जाएगा।
- **भारत माला परियोजना** : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भारत माला सड़क परियोजना के माध्यम से सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए लगभग 5000 किमी. लंबे सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना है। इसमें 50 हजार करोड़ रु. का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना भारत के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी।
- **उस्ताद योजना :** 14 मई, 2015 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने उस्ताद (अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट) नामक योजना का प्रारंभ वाराणसी से किया। इस योजना का उद्देश्य कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण द्वारा पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास करना है। इससे बुनकरों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षित करके उनके उत्पादों की बिक्री में मदद की जाएगी।
- **नर्मदा मास्टर प्लान** : 5 अप्रैल, 2015 को गुजरात सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी पेयजल पाइप लाइन परियोजना 'नर्मदा मास्टर प्लान' की शुरुआत की। 2500 करोड़ लागत की इस परियोजना से रोजाना 165 करोड़ लीटर पानी को 75 मीटर ऊपर लिफ्ट कर 5587 गांवों एवं 116 शहरों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के पौने दो करोड़ लोगों को पीने का पानी प्राप्त होगा।
- **'माई स्टाम्प' योजना** : मार्च, 2015 में डाक विभाग ने माई स्टाम्प योजना प्रारंभ की। इसके लिए 12 डाक टिकटों वाली एक 'माई स्टाम्प' शीट के लिए 300 रुपये शुल्क अदा करना होगा। इस शीट पर ग्राहक की फोटो, किसी संस्थान का चित्र एवं लोगो, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक शहर, वन्य जीवन या अन्य पशु-पक्षियों का चित्र अंकित होगा।
- **डिजिटल गांव योजना** : 2 जनवरी, 2015 को आईसीआईसीआई बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल होते हुए 'डिजिटल गांव परियोजना' शुरू की है। इसके तहत बैंक ने गुजरात के साबरकांठा जिले के अकोदरा नामक गांव को गोद लिया है।
- **वन बंधु कल्याण योजना** : 5 अगस्त, 2014 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 'वन बंधु कल्याण योजना' की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय परिवारों के लिए संपोषणीय रोजगार, गुणात्मक रूप से अवसंरचना निर्माण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- **ईशान उदय स्कीम** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अकादमिक सत्र 2014-15 से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप स्कीम 'ईशान उदय' की शुरुआत की है।
- **'कर्नाटक मोबाइल वन' प्रोजेक्ट** : 8 दिसंबर, 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कर्नाटक में एक मोबाइल गवर्नेंस प्रोजेक्ट 'कर्नाटक मोबाइल वन' लांच किया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बिल भुगतान, यातायात एलर्ट्स, यातायात भुगतान व अन्य उपयोगी सेवाओं मोबाइल फोन से ही उपलब्ध होंगी।

सम्मेलन/समारोह

- **14वां प्रवासी भारतीय दिवस :** अगला प्रवासी भारतीय दिवस समागम नई दिल्ली में 8 से 10 जनवरी, 2016 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व 14 से 15 नवंबर, 2015 के दौरान लॉस एंजेलेस (यूएसए) में 9वां क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस संपन्न होगा।
- **समुद्री सुरक्षा सहयोग पर त्रिपक्षीय सम्मेलन** : 30 सितंबर, 2015 को न्यूयॉर्क में भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक समुद्री सुरक्षा सहयोग के विषय पर संपन्न हुई। यह तीनों देशों के बीच के इस मुद्दे पर हुई पहली त्रिपक्षीय वार्ता है। भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई तथा विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे, नौवहन की स्वतंत्रता एवं अपने समुद्री क्षेत्र में निर्बाध वैध करोबार के मुद्दों को भी रेखांकित किया गया।
- **विश्व हिंदी सम्मेलन** : 10 सितंबर से 12 सितंबर, 2015 के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन दिवसीय दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय 'हिंदी जगत : विस्तार एवं संभावनाएं' था। उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार किया गया था। अगला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में मॉरीशस में आयोजित किया जाएगा।
- **वैश्विक हिंदू-बौद्ध सम्मेलन** : 3-5 सितंबर, 2015 के दौरान नई दिल्ली एवं बोधगया में वैश्विक हिंदू-बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस तीन दिवसीय वैश्विक हिंदू बौद्ध सम्मेलन का केंद्रीय विषय 'संघर्ष बचाव एवं पर्यावरण चेतना' था। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ तथा टोक्यो फाउंडेशन के सहयोग से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया की वर्तमान समस्याओं के समाधान में हिंदू एवं बौद्ध धर्म के महत्त्व को चिह्नित करना था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया।
- **भागवतगीता पर प्रथम सम्मेलन** : 25 सितंबर, 2015 को लंदन में भागवतगीता की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) एवं भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा किया गया।
- **कॉल टू एक्शन सम्मिट** : 27 से 28 अगस्त, 2015 के मध्य नई दिल्ली में मातृ एवं शिशु मृत्यु रोकने के लिए 'कॉल टू एक्शन सम्मिट' का आयोजन किया गया।

- **हेमिस महोत्सव** : 26-27 जून, 2015 को जम्मू एवं कश्मीर के सबसे बड़े मठ लद्दाख हेमिस गोम्पा में गुरु पद्मसंभव के लिए समर्पित दो दिवसीय 'हेमिस महोत्सव' का आयोजन हुआ।
- **अंबुबचि महोत्सव** : 23 से 26 जून, 2015 के मध्य असम के गुवाहाटी स्थित कामायनी देवी मंदिर में चार दिवसीय अंबुबचि महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव को कामाख्या देवी पूजा के नाम से भी जाना जाता है।
- **विश्व संस्कृत सम्मेलन** : 28 जून, 2015 से 2 जुलाई, 2015 के मध्य थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 60 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी। 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन वर्ष 2018 में कनाडा के वैंकूवर में होगा।
- **राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन** : 22 से 26 जून, 2015 के मध्य बहामास की राजधानी नसाऊ में राष्ट्रमंडल देशों के शिक्षामंत्रियों का 19वां सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस सम्मेलन में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया। उन्होंने 'द मालवीय कॉमनवेल्थ चेयर फॉर क्रॉस बार्डर टीचर एजुकेशन' के स्थापना की भी घोषणा की।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 104वां सत्र** : 1 से 13 जून, 2015 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 104वें सत्र का आयोजन किया गया।
- **संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का 39वां सत्र** : 7 से 8 जून, 2015 के मध्य इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के 39वें सत्र का आयोजन हुआ।
- **जी-20 कृषि मंत्रियों का सम्मेलन** : 7 मई, 2015 को तुर्की के इस्तांबुल में जी-20 के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ।
- **सीएमटी-2016** : 16 से 24 जनवरी, 2016 के मध्य जर्मनी के स्टुटगार्ट में कारवन मोटरिंग एंड टूरिज्म (सीएमटी)-2016 का आयोजन किया जायेगा। भारत इस आयोजन में पहली बार साझीदार राष्ट्र के रूप में शामिल होगा।
- **30वां इंडिया कॉरपेट एक्सपो** : केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा 11 अक्टूबर, 2015 से 14 अक्टूबर, 2015 के मध्य वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में 30वां इंडिया कॉरपेट एक्सपो आयोजित किया गया।
- **पूर्वोत्तर युवा महोत्सव** : 29 मई, 2015 को असम के माजुली में चौथे पूर्वोत्तर युवा महोत्सव की शुरुआत हुई।
- **68वीं विश्व स्वास्थ्य सभा** : 18 से 27 मई, 2015 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 68वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। भारत ने इस आयोजन की अध्यक्षता की। भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने आयोजन में भाग लिया। भारत ने 19 वर्ष बाद विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) की अध्यक्षता की है।
- **परमाणु ऊर्जा पर राष्ट्रीय सम्मेलन** : 15 मई, 2015 को नई दिल्ली में एसोचैम ने परमाणु ऊर्जा पर छठें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की विषय वस्तु 'परमाणु ऊर्जा : स्वच्छ ऊर्जा विकल्प' थी।
- **अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय सम्मेलन, 2015** : 12 से 19 अप्रैल, 2015 के मध्य दोहा की राजधानी कतर में '13वें संयुक्त राष्ट्र अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय सम्मेलन-2015' का आयोजन किया गया।
- **सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक** : 8 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई।
- **अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन** : 3-5 अप्रैल, 2015 के दौरान 88वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन पंजाब के गुरुदासपुर जिले के घुमान गांव में आयोजित किया गया।
- **राष्ट्रीय जैवविविधता सम्मेलन** : 23 से 27 फरवरी, 2015 के मध्य केरल की राजधानी तिरूवनंतपुरम में द्वितीय राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम—'जैवविविधता : अभिगम और लाभ साझाकरण' थी।
- **विश्व पुस्तक मेला, 2015** : 14 से 22 फरवरी, 2015 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 'विश्व पुस्तक मेले' का आयोजन किया गया। वर्ष 2015 के इस मेले में सिंगापुर को 'अतिथि देश' तथा दक्षिण कोरिया को 'फोकस कंट्री' घोषित किया गया था। इस मेले की थीम-'सूर्योदय : इमर्जिंग वॉयसेज फ्रॉम नार्थ ईस्ट इंडिया' थी।
- **कछुआ महोत्सव** : फरवरी, 2015 में पर्यावरण एवं वन विभाग ने तृतीय कछुआ महोत्सव का आयोजन असम के दीमा हसाओ जिले के हेजोंग झील के तट पर किया। इस झील को कछुओं की झील के नाम से जाना जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन** : 19 से 21 मार्च, 2015 के मध्य राजस्थान के जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- **आपदा जोखिम शमन पर विश्व शिखर सम्मेलन** : 18 मार्च, 2015 को जापान के सेंडाई शहर में आपदा जोखिम शमन पर संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- **आपदा जोखिम शमन पर सातवां एशियाई सम्मेलन** : 17 मार्च, 2015 को जापान के सेंडाई में आयोजित आपदा जोखिम शमन पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विश्व सम्मेलन के दौरान भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2016 में आपदा जोखिम शमन पर सातवें एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन भारत में करने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि आपदा जोखिम शमन पर छठां एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 23-26 जून, 2014 को थाइलैंड में आयोजित हुआ था।
- **महिलाओं का वैश्विक सम्मेलन, 2015** : 14-16 मई, 2015 के दौरान साओ पाउलो (ब्राजील) में महिलों का वैश्विक बिजनेस फोरम 'ग्लोबल सम्मिट ऑफ वुमेन' आयोजित किया गया जो इस फोरम की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुआ।
- **राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव-2015** : 13 से 18 फरवरी, 2015 के मध्य नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव-2015 'वनज' का आयोजन किया गया।
- **सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला** : 1 से 15 फरवरी, 2015 के मध्य हरियाणा के फरीदाबाद में 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन हुआ। इसमें सहभागी देश लेबनान था तथा इसका विषय 'छत्तीसगढ़ राज्य' था।
- **विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस (WOSC)** : 5 से 8 फरवरी, 2015 के दौरान केरल के कोच्चि में प्रथम विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस (WOSC) का आयोजन किया गया।
- **15वां दिल्ली सतत विकास सम्मेलन** : 5 से 7 फरवरी, 2015 के मध्य नई दिल्ली में 'टेरी' द्वारा 15वें दिल्ली सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- **7वीं वाइब्रेंट गुजरात सम्मिट** : 11 से 13 जनवरी, 2015 के मध्य गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 7वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मिट का आयोजन गुजरात सरकार द्वारा किया गया।
- **आपी हेल्थ सम्मिट** : 2 जनवरी, 2015 को आपी (American Association of Physicians of Indian Origin-AAPI) ने मुंबई में 'ग्लोबल हेल्थ सम्मिट' का आयोजन किया।

- **'ज्ञान संगम'** : 2-3 जनवरी, 2015 के मध्य पुणे में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का दो दिवसीय विचार सम्मेलन 'ज्ञान संगम' (GYAN SANGAM) आयोजित हुआ।
- **विश्व डायमंड कांफ्रेंस** : 11 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में 'विश्व डायमंड कांफ्रेंस' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। यह पहला अवसर था जब भारत में हीरा व्यापारियों की वैश्विक कांफ्रेंस आयोजित की गई।
- **कॉमनवेल्थ साइंस कांफ्रेंस** : नवंबर, 2014 में बंगलुरू में कॉमनवेल्थ साइंस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया।
- **'संस्कृति' महोत्सव** : 25 दिसंबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पांच दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 'संस्कृति' का उद्घाटन किया।
- **लद्दाख क्षेत्र का बौद्ध पर्व 'लोसार'** : 22 दिसंबर, 2014 को जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का बौद्ध पर्व 'लोसार' शुरू हुआ। लद्दाख क्षेत्र के लोग इस त्योहार को नये वर्ष के आगमन के अवसर पर मनाते हैं।
- **हॉर्नबिल महोत्सव** : 1 से 10 दिसंबर, 2014 के मध्य नगालैंड के कोहिमा के पास किसामा नामक स्थान पर पर्यटन प्रोत्साहन के उद्देश्य से हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हुआ। यह महोत्सव वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है।

संस्थान/संगठन

- **तीन नए 'एम्स' की स्थापना को मंजूरी** : 7 अक्टूबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसयू) के तहत तीन नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी। ये नए संस्थान क्रमशः महाराष्ट्र के नागपुर, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी तथा पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्थापित किए जाएंगे।
- **भौमिक (Terrestrial) शोध एवं विकास केंद्र** : 4 अक्टूबर, 2015 को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा जम्मू-कश्मीर में लेह के नजदीक चांगला में समुद्र तट से 17,600 फीट की ऊंचाई पर बने शोध केंद्र (विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शोध केंद्र) का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र लेह के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च (डीआईएचएआर) द्वारा स्थापित किया गया है। यह केंद्र कृषि एवं जैव चिकित्सा अनुसंधान के साथ अत्यधिक ऊंचाई पर तैनात सेना के जवानों के लिए खाद्य आदि के संदर्भ में भी शोध करेगा।
- **केंद्रीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान संस्थान** : 22 सितंबर, 2015 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में केंद्रीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। यह संस्थान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा।
- **नाम फाउंडेशन** : 15 सितंबर, 2015 को अभिनेता नाना पाटेकर ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किसानों की मदद करने हेतु 'नाम फाउंडेशन' की स्थापना की।
- **हिंदुस्तान अवाम मोर्चा-हम (सेकुलर)** : 29 जुलाई, 2015 को भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा-हम (सेकुलर) को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की।ाग में आये टायफून इताउ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
- **मरकोसर** : लैटिन अमेरिका के वाणिज्यिक ब्लॉक 'मरकोसर' का गठन वर्ष 1991 में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से सदस्य देशों के मध्य सेवाओं, सामान, पूंजी एवं नागरिकों के मुक्त आवागमन की सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। मरकोसर में सम्मिलित पांच एसोसिएट देश हैं– पेरु, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर एवं बोलिविया। इसमें सम्मिलित उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला एवं पराग्वे वे देश हैं, जिन्हें मताधिकार का तो पूर्ण अधिकार नहीं है, किंतु इन्हें सदस्य देशों के बाजारों में टैक्स में छूट प्राप्त है। भारत वर्ष 2005 में इस वाणिज्यिक ब्लॉक के साथ 'प्रीफ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- **इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट** : 28 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही तहसील के गोरिया करमा गांव में 'इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट' की स्थापना की।
- **गंगातीरी गाय संरक्षण एवं विकास केंद्र** : 15 जून, 2015 को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने वाराणसी के शहंशाहपुर में गंगातीरी गौ संरक्षण एवं विकास केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' का हिस्सा है।
- **मालवीय चेयर** : मई, 2015 के अंत में रेल मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू में रेल प्रौद्योगिकी के लिए 'मालवीय चेयर' के गठन का निर्णय लिया। रेल मंत्रालय इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगा।
- **बायोटेक इनोवेशन सेक्टर** : 17 मई, 2015 को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं भूविज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 'बायोटेक इनोवेशन सेक्टर' का उद्घाटन किया। यह राजीव गांधी सेंटर फॉर बॉयोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्थापित किया गया।
- **मैरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट** : 5 मई, 2015 को भारत सरकार ने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के पिंडारा गांव में 'मैरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' (MPTI) स्थापित करने का निर्णय लिया।
- **डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान** : 20 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
- **साइकिल एकेडमी** : 14 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज में एक 'साइकिल एकेडमी' की स्थापना की घोषणा की।
- **नोट पेपर फैक्ट्री** : 30 मई, 2015 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नोट पेपर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। इस फैक्ट्री में एक हजार रुपये के नोट बनेंगे जिसके लिए अब तक पेपर विदेशों से आयात करना पड़ता था।
- **इंडिया हेरिटेज सेंटर** : 7 मई, 2015 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने सिंगापुर के 'लिटिल इंडिया' में भारतीय इतिहास को समर्पित पहले संग्रहालय 'इंडिया हेरिटेज सेंटर' का उद्घाटन किया।
- **प्रकाश स्तंभ संग्रहालय** : अप्रैल, 2015 के अंत में देश में प्रकाश स्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का चौथा प्रकाश स्तंभ संग्रहालय केरल के कन्नूर में खोला गया।
- **ग्रीनपीस** : 9 अप्रैल, 2015 को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'ग्रीनपीस' के विदेशी सहायता लेने पर रोक लगा दी।
- **अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र** : अप्रैल, 2015 के प्रारंभ में हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए अमेरिका में एक 'अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र' स्थापित करने की घोषणा की गई।
- **समुद्री अध्ययन केंद्र** : 1 अप्रैल, 2015 को पुडुचेरी विश्वविद्यालय के पोर्ट ब्लेयर परिसर में केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 'समुद्री अध्ययन केंद्र' का उद्घाटन किया।
- **ब्रह्मपुत्र स्टडी सेंटर** : 31 मार्च, 2015 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 'ब्रह्मपुत्र स्टडी सेंटर' खोलने की घोषणा की।

- **तीन केंद्रीय संस्थानों का शिलान्यास** : 28 मार्च, 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) की आधारशिला रखी।
- **भाजपा** : 28 मार्च, 2015 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसके पहले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास था जिसके 8 करोड़ 67 लाख सदस्य हैं।
- **राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार** : नवंबर, 2014 में जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- **महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय** : 27 नवंबर, 2014 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई।
- **सेंटर फॉर जू साइंसेज** : 3 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने सेंटर फॉर जू साइंसेज (चिड़ियाघर विज्ञान केंद्र) की स्थापना करने की घोषणा की।

ऑपरेशन/अभियान

- **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान** : 9 जुलाई, 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' (आरएए) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान एवं गणित के लिए उत्सुकता, सृजनशीलता एवं प्रेम की भावना का समावेश करना है। डॉ. कलाम के निधन के बाद इस अभियान का नाम 'एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' कर दिया गया है।
- **ऑपरेशन 'स्माइल'** : जुलाई, 2015 के दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड में पुलिस द्वारा लापता बच्चों को ढूंढ़ने के लिए 'ऑपरेशन स्माइल' चलाया गया।
- **ऑपरेशन शिवा** : जुलाई, 2015 के प्रथम सप्ताह में जम्मू एवं कश्मीर में शुरू हुई 59 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन शिवा' का शुभारंभ किया।
- **'गर्ल राइजिंग' अभियान** : जून, 2015 में लड़कियों को सशक्त व शिक्षित बनाने के लिए एक वैश्विक एक्शन अभियान 'गर्ल राइजिंग' के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
- **ऑपरेशन राहत** : मार्च-अप्रैल, 2015 में युद्ध से ग्रस्त मध्य एशियाई देश यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना एवं नौसेना ने 'ऑपरेशन राहत' चलाया। इस ऑपरेशन के माध्यम से लगभग 4000 भारतीयों को यमन से भारत लाने में सफलता प्राप्त की गई।
- **गिव इट अप** : 27 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न वर्ग से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध करते हुए 'गिव इट अप' नामक अभियान चलाया। इस अभियान की शुरुआत ऊर्जा केंद्रित वार्षिक शिखर सम्मेलन 'ऊर्जा संगम-2015' के अवसर पर हुई।
- **स्वच्छाग्रह अभियान** : 12 मार्च, 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गांधीजी के सत्याग्रह की तर्ज पर 'स्वच्छाग्रह' अभियान चलाने की घोषणा की।
- **ऑपरेशन 'ऑल आउट'** : दिसंबर, 2014 में केंद्र सरकार ने असम के बोडो उग्रवादियों के खिलाफ 'ऑपरेशन ऑल आउट' की शुरुआत की।
- **उन्नत भारत अभियान** : दिसंबर, 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी एवं एनआईटी संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए 'उन्नत भारत अभियान' की शुरुआत की।
- **पुनर्जागरण अभियान :** 2 अक्टूबर, 2014 को कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्र के विकास में युवाओं की भागीदारी के लिए 'पुनर्जागरण' नामक जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान को देश के चार जिलों क्रमशः कन्याकुमारी (तमिलनाडु), लेह (जम्मू एवं कश्मीर), ओखा (गुजरात) तथा रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) में शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अभियान का समापन उ.प्र. के मथुरा जिले में 25 सितंबर, 2015 को हुआ।
- **लैंगिक असमानता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का अभियान** : 20 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 69वीं बैठक के दौरान विश्व में लैंगिक असमानता के खिलाफ 'ही फॉर शी' (He for She) अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नेतृत्व एम्मा वाटसन एवं वुल्फ ब्लिट्ज़र कर रहे हैं।

दुर्घटना

- **रूस का विमान दुर्घटनाग्रस्त** : 31 अक्टूबर, 2015 को रूस का यात्री विमान एयरबस ए-321 मिस्र के शर्म अल शेख से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरने के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे जहाज में सवार सभी 224 व्यक्ति मारे गए। उल्लेखनीय है कि इस विमान को सिनाई प्रायद्वीप के ऊपर इस्लामिक स्टेट के आंतकियों ने मार गिराने का दावा किया है।
- **मक्का में वार्षिक हज के दौरान भगदड़** : 24 सितंबर, 2015 को सउदी अरब के मक्का शहर में मीना नामक स्थान पर वार्षिक हज के दौरान हुई भगदड़ में 769 तीर्थयात्रियों (अनाधिकारिक आंकड़ों के तहत यह आंकड़ा 2,000 से अधिक था) की मृत्यु हो गई तथा 924 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके पहले 12 सितंबर, 2015 को मक्का की बड़ी मस्जिद में एक विशाल क्रेन के गिरने से 115 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- **हरदा ट्रेन दुर्घटना** : 4 अगस्त, 2015 को मध्य प्रदेश में हरदा के निकट देर रात कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के 17 डिब्बे और एक इंजन पटरी से उतरकर माचक नदी में गिर गए। इस दुर्घटना में 31 लोगों की मृत्यु हुई तथा 100 से अधिक घायल हुए। देश में एक ही जगह लगभग एक ही वक्त पर दो ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का यह पहला मामला है।
- **इंडोनेशिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त** : 30 जून, 2015 को इंडोनेशियाई वायुसेना का परिवहन विमान 'हरक्यूलिस सी-130' उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। यह विमान सुमात्रा द्वीप के मेदान शहर में गिरा।
- **ताइवान के वॉटर पार्क में आग लगी** : 27 जून, 2015 को ताइवान की राजधानी ताइपे के बाहरी इलाके स्थित फारमोसा फन कोस्ट वॉटर पार्क में एक रंगीन पाउडर के छिड़काव से आग लग गई जिससे 500 लोग झुलस गये।
- **चीन में जहाज डूबा** : 1 जून, 2015 को चीन के हुबेई प्रांत में, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी (चीन) में चक्रवात की चपेट में आकर एक यात्री जहाज के डूबने से 400 यात्री मारे गए जबकि मात्र 15 लोगों को बचाने में सफलता मिली।
- **स्पेसएक्स फाल्कन-9 रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त** : 28 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य सामग्री ले जा रहे अंतरिक्षयान 'स्पेसएक्स फाल्कन-9' के तरल ऑक्सीजन टैंक में अत्यधिक दाब के कारण विस्फोट होने से यान दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया।
- **थाईलैंड के सोंगक्रन महोत्सव में भगदड़ :** 13 अप्रैल, 2015 को थाईलैंड के सोंगक्रन महोत्सव के दौरान मची भगदड़ में 120 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 1281 लोग घायल हुए।
- **फ्रांस में विमान हादसा** : 24 मार्च, 2015 को फ्रांस में जर्मन विंग्स के विमान एयरबस ए 320 में दुर्घटना के बाद 150 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना फ्रांस के मेसिफ देस ब्रोइस एवेस नामक स्थान पर हुई।

- **देहरादून-वाराणसी जनता एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त** : 20 मार्च, 2015 को उ. प्र. के रायबरेली जिले के बछरावां स्टेशन के पास ब्रेक फेल हो जाने से देहरादून-वाराणसी जनता एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 36 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 150 से अधिक घायल हो गए।
- **दक्षिणी प्रशांत महासागर में चक्रवात** : 14 मार्च, 2015 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह वनुआतू में श्रेणी-5 का चक्रवात आया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। पैम नामक यह तूफान दक्षिण प्रशांत महासागर में पिछले कुछ वर्षों में आया सबसे भीषण तूफान था।

आयोग/समिति

- **नॉन-नेट फेलोशिप की समीक्षा के लिए समिति** : 25 अक्टूबर, 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नॉट नेट फेलोशिप की समीक्षा के लिए प्रो. गौतम बरुआ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने 7 अक्टूबर को नॉट नेट फेलोशिप बंद करने का फैसला किया था जिसका छात्र विरोध कर रहे थे।
- **गुलशन राय कमेटी रिपोर्ट** : निरंतर बढ़ रहे साइबर अपराधों से निपटने एवं इनकी रोकथाम के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से गठित की गई गुलशन राय कमेटी ने सितंबर, 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। इस रिपोर्ट में साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को आसान बनाने के अलावा नए तौर-तरीकों से साइबर अपराधों की निगरानी एवं विश्लेषण के उद्देश्य से गृहमंत्रालय के 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (एनसीआरबी) के अधीन 'इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेन्टर' नामक निकाय के गठन की सिफारिश की गई है।
- **धीरेन्द्र सिंह कमेटी रिपोर्ट** : रक्षा खरीद प्रक्रिया में 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को शामिल करने एवं खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित की गई धीरेन्द्र सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गत दिनों सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में कुल 43 सिफारिशें की गई हैं, जिनमें से 15 'मेक इन इंडिया' से संबंधित हैं तथा शेष 28 का संबंध खरीद प्रक्रियाओं से है। इस रिपोर्ट में रक्षा खरीद प्रक्रिया हेतु निजी क्षेत्र से संबंधित तीन मॉडलों का सुझाव दिया गया है, जो इस प्रकार हैं–'सामरिक भागीदारी मॉडल', 'विकास भागीदारी मॉडल' एवं 'प्रतिस्पर्धी मॉडल'।
- **वी.के. आत्रे कमेटी** : केंद्र सरकार द्वारा सितंबर, 2015 में डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष वी.के. आत्रे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे रक्षा के छह नाजुक क्षेत्रों में सहयोग के लिए निजी कंपनियों के चयन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
- **सुमित बोस समिति की रिपोर्ट** : वित्तीय निवेश उत्पाद पर पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस के नेतृत्व में गठित की गई समिति ने सितंबर, 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में जहां वित्तीय उत्पादों के लिए लचीले निवेश विकल्प की बात कही गई है, वहीं यह भी कहा गया है कि उत्पाद को लौटाते वक्त लागत कम होनी चाहिए।
- **विष्णु सहाय आयोग रिपोर्ट** : सितंबर, 2015 के अंत में न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित जांच रिपोर्ट उ. प्र. के राज्यपाल राम नाइक को सौंपी। रिपोर्ट में दंगों के लिए स्थानीय नेताओं के साथ प्रशासन तथा पुलिस को भी जिम्मेदार माना गया है। उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में 60 लोगों की मृत्यु व 50 हजार से अधिक लोगों के बेघर हो जाने के बाद 9 सितंबर, 2013 को विष्णु सहाय आयोग का गठन किया गया था।
- **अर्येन्द्र कुमार सक्सेना आयोग** : 15 सितंबर, 2015 को मध्य प्रदेश सरकार ने पेटलावद में हुए विस्फोट की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्येन्द्र कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। यह आयोग तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर, 2015 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद इलाके में एक घर में हुए विस्फोट से लगभग 89 लोग मारे गए तथा 100 से अधिक घायल हो गए थे।
- **टी. हक समिति** : सितंबर, 2015 के अंतिम सप्ताह में नीति आयोग ने पट्टे पर भूमि आवंटन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष टी. हक हैं। समिति में कुल 10 सदस्य हैं।
- **मिहिर शाह समिति** : 11 सितंबर, 2015 को जल संसाधन मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीबी) के पुनर्गठन हेतु योजना आयोग के पूर्व सदस्य मिहिर शाह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया।
- **बी.एस. बस्वां समिति** : 12 अगस्त, 2015 को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न पर पुनः विचार करने के लिए बी. एस. बस्वां की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
- **डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती हेतु समिति का गठन** : 30 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती को मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015, अंबेडकर की 125वीं जयंती है।
- **केलकर समिति** : 26 मई, 2015 को केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के पीपीपी मॉडल के पुनरावलोकन के लिए डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय समिति का गठन किया।
- **ए.पी. शाह समिति :** 20 मई, 2015 को वित्त मंत्रालय ने 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने विदेशी संस्थागत निवेशकों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से संबंधित विवाद को निपटाने के तरीके सुझाए हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त, 2015 को सौंपी जिसके तहत की गई अनुशंसाओं को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
- **'कायाकल्प' परिषद का गठन** : 19 मार्च, 2015 को रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल की नवाचार परिषद के रूप में 'कायाकल्प परिषद' का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे में सुधार, व्यापक बदलाव और आधुनिकीकरण के लिए सुझाव देना है। परिषद का अध्यक्ष प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा को नियुक्त किया गया है।
- **सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एसआईटी** : 12 फरवरी, 2015 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की दोबारा जांच के लिए प्रमोद अस्थाना की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

विविध

- **देश की पहली एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन** : 25 अक्टूबर, 2015 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई एवं गोवा के बीच देश की पहली एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन चलाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि पहली एसी डबल डेकर ट्रेन हावड़ा एवं धनबाद के बीच अक्टूबर, 2011 में शुरू की गई थी।
- **गोवध रोकने के लिए कानून बनाए सरकार** : 14 अक्टूबर, 2015 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह गोहत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए। न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र को तीन माह का समय दिया है।

- **बीपीएल की आय सीमा में वृद्धि** : 17 अक्टूबर, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में 46 हजार रुपये सालाना तथा शहरों में 56 हजार रुपये सालाना तक की आमदनी वाले परिवारों की गणना बीपीएल (BPL : Below Poverty Line) में करने की घोषणा की। इसके पहले ग्रामीण क्षेत्र में 19,984 रुपये सालाना तथा शहरी क्षेत्रों में 25, 546 रुपये सालाना आय वाले परिवार बीपीएल श्रेणी में आते थे।

- **चालक रहित विमान ने भरी उड़ान** : 15 अक्टूबर, 2015 को ब्रिटेन में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में ड्रोन के प्रायोगिक इस्तेमाल के तौर पर पहले चालक रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया। विमान ने वेल्स के दक्षिण पश्चिम तट पर एक पारंपरिक विमान के साथ तीन घंटे की उड़ान भरी। यह विश्व में नागरिक हवाई मार्ग पर किसी मानव रहित विमान का पहला उड़ान परीक्षण था।

- **रिचार्ज के साथ जीवन बीमा भी** : 7 अक्टूबर, 2015 को टेलिनॉर इंडिया ने पहली बार मोबाइल रिचार्ज के साथ जीवन बीमा का कवरेज देने की पेशकश की। इसके तहत टेलीनॉर के हर ग्राहक को मोबाइल फोन कनेक्शन रिचार्ज कराते ही एक महीने का जीवन बीमा मिल जाएगा।

- **सिख पगड़ी पहनकर काम कर सकेंगे** : 1 अक्टूबर, 2015 से ब्रिटेन में रोजगार कानून में हुए संशोधन के तहत सिखों को कार्यस्थलों पर पगड़ी पहनने की आजादी होगी। इसके अलावा जोखिम भरे कार्य स्थलों पर भी हेलमेट या पगड़ी में से एक का चुनाव सिख कर सकेंगे।

- **मुंबई धमाकों में पांच को मृत्युदंड** : 30 सितंबर, 2015 को मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने वर्ष 2006 के लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में पांच दोषियों क्रमशः कमाल अहमद अंसारी, नवीद हुसैन खान, एहसान सिद्दीकी, फैजल शेख तथा आसिफ खान को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इन धमाकों में 188 लोग मारे गए थे तथा 800 से अधिक घायल हुए थे।

- **नाबालिग मुस्लिम का निकाह गैरकानूनी** : सितंबर, 2015 के अंत में गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में नाबालिग मुस्लिम लड़की के निकाह को पूरी तरह गैरकानूनी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग मुस्लिम लड़की के शादी के मसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं, बल्कि चाइल्ड मैरिज एक्ट का प्रावधान लागू होता है।

- **'ट्विटर' के जवाब में आया 'मूषक'** : 8 सितंबर, 2015 को पुणे के अनुराग गौड़ ने विश्व हिंदी सम्मेलन, भोपाल के दौरान ट्विटर की तर्ज पर हिंदी में कार्य करने वाली 'मूषक' सोशल नेटवर्किंग साइट प्रस्तुत की। जहां ट्विटर में शब्द सीमा 140 है वहीं मूषक में यह 500 है। मूषक का उद्देश्य हिंदी और देवनागरी को आज की पीढ़ी के लिए सामयिक और प्रचलित करना है।

- **विदेशी निवेश में भारत प्रथम** : सितंबर, 2015 के अंत में लंदन से प्रकाशित होने वाली बिजनेस पत्रिका फाइनेंशियल टाइम्स ने जनवरी, 2015 से जून, 2015 के आंकड़ों के आधार पर कहा है कि वर्ष 2015 की पहली छमाही में भारत, चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आकर्षक देश बन गया है। इस अवधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 31 अरब डॉलर, चीन में 28 एवं अमेरिका में 27 अरब डॉलर रहा।

- **माउंट 'मैकिनले' का नाम बदला** : अगस्त, 2015 के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम माउंट मैकिनले से बदलकर माउंट 'डेनाली' कर दिया।

- **मोबाइल एप से खाता खोलने की सुविधा** : 6 अगस्त, 2015 को देश में पहली बार मोबाइल एप से बैंक खाता खोलने की सुविधा फेडरल बैंक ने दी। इसके लिए 'फेडबुक' नामक मोबाइल एप की व्यवस्था की गई है।

- **भारती एयरटेल ने शुरू की 4जी सेवा** : 6 अगस्त, 2015 को देश की सबसे बड़ी निजी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने देश के 296 शहरों में हाईस्पीड 4जी सेवा शुरू करने की घोषणा की। दिसंबर, 2015 तक रिलायंस जियो भी 4जी सेवा शुरू करेगा।

- **एचडीएफसी ने 'वॉच बैंकिंग' की शुरुआत की** : जुलाई, 2015 के प्रथम सप्ताह में निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने एप्पल वॉच के लिए 'वॉच बैंकिंग' की शुरुआत भारत में पहली बार की।

- **किशाऊ प्रोजेक्ट पर समझौता** : जून, 2015 में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य किशाऊ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए।यह परियोजना देहरादून की टोंस नदी (यमुना की सहायक) पर निर्माणाधीन है।

- **झारखंड में थर्माकोल की प्लेट पर प्रतिबंध** : जून, 2015 में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने राज्य में पत्तियों से बनी प्लेट को बढ़ावा देने के लिए थर्मोकोल प्लेट के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे गरीब व आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।

- **परमाणु बिजली घरों के लिए नये स्थानों को मंजूरी** : केंद्र सरकार ने परमाणु बिजली घरों की स्थापना के लिए 10 नये स्थानों को मंजूरी प्रदान की है। ये दस नये स्थान देश के कुल नौ राज्यों में अवस्थित हैं। इनके नाम क्रमशः गोरखपुर (हरियाणा), चुटका एवं भीमपुर (म. प्र.), कैगा (कर्नाटक), माही बंसवारा (राजस्थान), कुडनकुलम (तमिलनाडु), जैतपुर (महाराष्ट्र), छाया मिठी विरदी (गुजरात), कोव्वाडी (आंध्र प्रदेश) तथा हरिपुर (प. बंगाल) हैं।

- **भारत में विदेशियों के लिए किराये की कोख पर प्रतिबंध** : अक्टूबर, 2015 के अंत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि भारत में विदेशी नागरिक किराये की कोख नहीं ले सकते। किराये की कोख की सेवा सिर्फ भारतीय दंपतियों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने विदेशियों के लिए व्यावसायिक किराये की कोख के जरिए मानव भ्रूण के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन अनुसंधान कार्य के लिए भ्रूण के आयात पर प्रतिबंध नहीं होगा।

- **बदरपुर-फरीदाबाद मेट्रो लाइन की शुरुआत** : 6 सितंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो को विस्तार देते हुए 'बदरपुर-फरीदाबाद मेट्रो लाइन' का उद्घाटन किया। यह नई मेट्रो लाइन 13.875 किमी. वॉयलेट लाइन-6 (Violet Line-6) है जो फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ेगी।

- **आईआईटी भुवनेश्वर में ओडिसी नृत्य का पाठ्यक्रम** : सितंबर, 2015 में आईआईटी भुवनेश्वर ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य 'ओडिसी' को अपने बीटेक पाठ्यक्रम में शामिल किया। यह भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने अपने पाठ्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य को शामिल किया है।

- **भारतीय रेलवे का नॉलेज पोर्टल** : 28 सितंबर, 2015 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के नॉलेज पोर्टल www. kportal.indianrail ways.gov.in का उद्घाटन किया। यह पोर्टल नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, बड़ोदरा द्वारा तैयार किया गया है। इसमें भारतीय रेल से जुड़ी सभी जानकारियां संग्रहित हैं।

- **अम्बेडकर की स्मृति में डाक टिकट जारी** : 30 सितंबर, 2015 को केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने वर्ष 2015 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती की स्मृति में डाक टिकट जारी किया।

- **राधाकृष्णन की याद में सिक्के जारी** : 4 सितंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं महान शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 125 रुपए व 10 रुपए के सिक्के जारी किए।

- **अमृता शेरगिल द्वारा बनाया चित्र 17 लाख पाउंड में नीलाम** : 8 अक्टूबर, 2015 को भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल द्वारा वर्ष 1931 में बनाया गया एक दुर्लभ चित्र लंदन के साउथबी नीलामघर में 17 लाख पाउंड में नीलाम हुआ।
- **फोर्ब्स की एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची** : 8 अक्टूबर, 2015 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा एशिया के कुल 50 अमीर परिवारों की सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष दस स्थान में से तीन भारतीय परिवार हैं। अंबानी परिवार सूची में तीसरे स्थान पर है। अजीज प्रेमजी एवं साइरस मिस्त्री परिवार शीर्ष दस में अन्य भारतीय परिवार हैं। सूची में सबसे ऊपर दक्षिण कोरिया का 'ली परिवार' है।
- **नेल्सन मंडेला रूल** : 7 अक्टूबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए अपने मानक न्यूनतम नियमों में संशोधन करके इसका नाम 'नेल्सन मंडेला रूल' कर दिया। यह नियम विश्व स्तर पर जेल कानूनों और नीतियों के विकास के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा, इस नियम की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी।
- **अरुणाचल प्रदेश की तीन परियोजनाओं को हरी झंडी** : सितंबर, 2015 में पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी बेसिन की तीन परियोजनाओं क्रमशः 'पॉक', 'हियो' तथा 'तातो-1' को हरी झंडी दी। इन परियोजनाओं की संभावित जल विद्युत क्षमता 571 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि सियांग नदी बेसिन में सरकार ने 44 जल विद्युत परियोजनाएं लगाने की योजना बनाई है।
- **भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची** : 23 सितंबर, 2015 को फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने भारत के सर्वाधिक धनी 100 व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में लगातार नौवीं बार मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति चुने गए।
- **ऑस्कर में 'कोर्ट' भारतीय प्रविष्टि** : सितंबर, 2015 में चैतन्य तम्हाने द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म 'कोर्ट' को 88वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर में भेजा गया। उल्लेखनीय है कि 'कोर्ट' को 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। इस फिल्म ने वर्ष 2014 के वेनिस फिल्मोत्सव में भी 17 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए।
- **आरबीआई व नेपाल राष्ट्र बैंक के मध्य समझौता** : 14 सितंबर, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नेपाल राष्ट्र बैंक के मध्य पर्यवेक्षकीय सहयोग एवं सूचना विनिमय हेतु समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम वेब पोर्टल** : 10 सितंबर, 2015 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 'राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम' के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की। इस वेब पोर्टल के माध्यम से स्नातकों, डिप्लोमाधारकों तथा 12वीं पास वोकेशनल डिप्लोमाधारकों को प्रशिक्षित दिया जाएगा। इस वेब पोर्टल का नारा है—'सशक्त युवा सशक्त भारत'।
- **मनरेगा के तहत काम के दिनों में वृद्धि** : 9 सितंबर, 2015 को केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत दैनिक कार्य दिवसों में 50 दिन की बढ़ोत्तरी की। इसके पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 150 दिन का कार्य मिलेगा।
- **'पॉवरिंग दि फ्यूचर वी वांट' अनुदान** : 14 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विभाग (डीईएसए) द्वारा प्रदान किए जाने वाले 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान 'पावरिंग द फ्यूचर वी वांट' कम कीमत पर अक्षय ऊर्जा प्रदान करने वाली संस्था 'वी केयर सोलर' ने प्राप्त किया।
- **वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के दो संस्थान** : सितंबर, 2015 के दूसरे सप्ताह में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा विश्व के टॉप-200 संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत के दो संस्थान क्रमशः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बंगलुरू 147वें स्थान पर तथा इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), दिल्ली 179वें स्थान पर रखे गए। रैंकिंग में पहले स्थान पर मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) तथा दूसरे स्थान पर हावर्ड यूनिवर्सिटी है।
- **विश्व की 50 सबसे ताकतवर उद्यमी महिलाएं** : सितंबर, 2015 में वैश्विक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा उद्योग क्षेत्र की 50 ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई। सूची में एकमात्र भारतीय मूल की महिला पेप्सिको की सीईओ इंद्रा नूयी को स्थान दिया गया है। इस सूची में शीर्ष पर जनरल मोटर्स की सीईओ मैरी बारा हैं।
- **रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण** : 31 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी द्वारा तैयार किए गए 'रामचरितमानस' के विशेष डिजिटल संस्करण को जारी किया। इसमें रामचरितमानस की चौपाईयों एवं दोहों को भोपाल घराने के गायकों ने आवाज दी है।
- **सम्राट अशोक पर डाक टिकट** : 24 अगस्त, 2015 को केंद्रीय दूरसचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सम्राट अशोक की स्मृति में 5 रु. का डाक टिकट जारी किया।
- **वेनिस फिल्म फेस्टिवल में तमिल फिल्म** : 2 सितंबर, 2015 से 12 सितंबर, 2015 के मध्य संपन्न 72वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेंस्टिवल में तमिल फिल्म 'वीसारनई' को प्रदर्शित किया गया। यह फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता धनुष द्वारा निर्मित फिल्म है तथा वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाने वाली पहली तमिल फिल्म है।
- **ताजमहल विश्व का पांचवां सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल** : अगस्त, 2015 में पर्यटन गाइड पुस्तकों के विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन 'लोनली प्लेनेट' (ब्रिटेन) ने भारत के 'ताजमहल' को विश्व का पांचवां सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल घोषित किया। प्रथम स्थान पर कंबोडिया का 'अंकोरवाट मंदिर', द्वितीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की 'ग्रेट बैरियर रीफ', तीसरे स्थान पर पेरू की 'इंका सिटी' तथा 'ग्रेट वॉल ऑफ चाइना' चौथे स्थान पर है।
- **'पहल' योजना गिनीज बुक में शामिल** : 13 अगस्त, 2015 को केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स द्वारा विश्व के सबसे बड़े नकद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई। इस योजना के दायरे में लगभग 10 करोड़ एलपीजी ग्राहक आते हैं।
- **देवघर दुर्घटना** : 10 अगस्त, 2015 को झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम में हुई भगदड़ में 11 कावड़ियों की मृत्यु हो गई तथा 50 से अधिक घायल हो गए। यहां सावन के सोमवार में लाखों श्रद्धालु आते हैं।
- **'स्वच्छ भारत अभियान' की रैंकिंग** : 8 अगस्त, 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 'स्वच्छ भारत अभियान' को बेहतर ढंग से लागू करने वाले 476 शहरों की रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में कर्नाटक के मैसूर शहर को प्रथम तथा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर को दूसरा स्थान प्रदान किया गया। स्वच्छ शहर रैंकिंग में शीर्ष 100 शहरों में दक्षिण राज्यों के 39 शहर, पूर्वी राज्यों के 27, पश्चिमी राज्यों के 15, उत्तरी राज्यों के 12 तथा पूर्वोत्तर के 7 शहर शामिल हैं।
- **फोर्ब्स की सबसे कमाऊ अभिनेताओं की सूची** : अगस्त, 2015 के पहले सप्ताह में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची नाम से जारी की। कुल 34 अभिनेताओं की सूची में पांच भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम क्रमशः अमिताभ बच्चन, सलमान खान,

अक्षय कुमार, शाहरुख खान एवं रणबीर कपूर हैं। सूची में प्रथम स्थान पर राबर्ट डाउनी जूनियर तथा दूसरे स्थान पर जैकी चॉन हैं।

- **सरोगेट मदर को भी मातृत्व अवकाश का अधिकार** : 17 जुलाई, 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी कर रही महिला यदि किराए की कोख से मां बनती हैं तब भी वह मातृत्व अवकाश की हकदार हैं।
- **फार्च्यून की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की सूची** : जुलाई, 2015 में फार्च्यून पत्रिका ने दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की। इसमें भारत की सात कंपनियां क्रमशः इंडियन ऑयल (119वें स्थान पर), रिलायंस इंडस्ट्रीज (158वें स्थान पर), टाटा मोटर्स (254वें स्थान पर), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (260वें स्थान पर), भारत पेट्रोलियम (280वें स्थान पर), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (327वें स्थान पर) और ऑयल एंड नेचुरल गैस (449वें स्थान पर) शामिल हैं। इस सूची में शीर्ष पर अमेरिकी रिटेल कंपनी वालमार्ट है जबकि चीन की पेट्रोलियम कंपनी साइनोपेक ग्रुप दूसरे एवं नीदरलैंड्स की रॉयल डच शेल तीसरे स्थान पर हैं।
- **सुपर 30 पर फीचर फिल्म 'द बिग डे'** : अगस्त, 2015 में फ्रांस के फिल्मकार पास्कल प्लिसन ने विश्व के 4 अभावग्रस्त बच्चों की सफलता पर 'द बिग डे' नामक फिल्म बनाई। फिल्म में बिहार के आनंद कुमार द्वारा शुरू किए गए 'सुपर 30' की एक छात्रा निधि झा की सफलता की कहानी को भी शामिल किया गया है।
- **परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत 12वें स्थान पर** : मई, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा वर्ष 2015 हेतु जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बिजली उत्पादन में भारत विश्व में 12वें स्थान पर है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहे संयंत्रों की संख्या के मामले में भारत छठें स्थान पर है। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 5780 मेगावाट है।
- **ग्रीनपीस का पंजीकरण रद्द** : 'विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए)' का उल्लंघन किए जाने तथा देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ काम करने के आरोपों में केंद्र सरकार द्वारा 9 अप्रैल, 2015 को 'ग्रीनपीस इंडिया' के लाइसेंस (पंजीकरण) को रद्द कर दिया गया। अब यह संगठन विदेश से धनराशि प्राप्त नहीं कर सकेगा, जो उसके समग्र संचालन व्यय का करीब 30% है।
- **बरदेउरी समाज को कामाख्या मंदिर का प्रबंधन** : भारत के महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर के प्रबंधन का दायित्व 7 जुलाई, 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'बरदेउरी समाज' (Bordeuri Samaj) को सौंप दिया गया, जो कि प्रबंधन का कार्य परम्परागत रूप से देखता था। ध्यातव्य है कि वर्ष 1988 में पुजारियों के एक प्रतिद्वंद्वी समूह द्वारा मंदिर के संचालन के लिए 'कामाख्या देवोत्तर बोर्ड' का गठन किया गया था और इसके बाद 'बरदेउरी समाज' एवं 'कामाख्या देवोत्तर बोर्ड' के मध्य प्रबंधन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी।
- **देश की पहली पीपीपी मॉडल रेलवे लाइन** : गैर-सरकारी रेलवे नीति-2012 के तहत सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर तैयार की गई देश की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन 14 जुलाई, 2015 को केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा किया गया। कांडला पोर्ट ट्रस्ट एवं पश्चिमी रेलवे जोन की वित्तीय मदद से यह रेलवे लाइन गुजरात में गांधीधाम एवं टुना-टेकरा बंदरगाह के मध्य निर्मित की गई है, जो कि पीपीपी मॉडल के आधार पर तैयार की गई भारत की पहली रेलवे लाइन है।
- **अमोनियम नाइट्रेट के खुले आयात पर प्रतिबंध** : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विस्फोटकों में किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को यह निर्देशित किया गया है कि अमोनियम नाइट्रेट का खुले में बड़ी मात्रा में आयात रोका जाए। इस प्रतिबंध के बाद अब अमोनियम नाइट्रेट को केवल बैग में ही आयातित किया जा सकेगा, भले ही उसकी मात्रा कितनी ही क्यों न हो। ध्यातव्य है कि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग असैनिक विस्फोटों के लिए खनन एवं विनिर्माण उद्योग में किया जाता है। भारत को अपने कुल उपभोग (700000 टन) का 15% अमोनियम नाइट्रेट आयात करना पड़ता है। विस्फोटकों में इसके दुरुपयोग को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया।
- **रेलवे का पहला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट** : भारतीय रेलवे ने अपने पहले 'हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलट' (Hybrid Vacuum Toilet) का संयोजन परीक्षण के तौर पर 'दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस' में किया है, जो कि भारतीय रेलवे के 'डेवलपमेंट सेल' द्वारा विकसित किया गया है। हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट की विशेषता है कि यह मल को रेलवे कोच के नीचे लगे बायोडाइजेस्टर टैंक में प्रवाहित कर देता है, जिसमें मौजूद अवायवीय जीवाणु (Anacrobic Bacteria) मल को जल एवं गैस में तब्दील कर देते हैं। इस परीक्षण की सफलता के बाद इस प्रकार के टायलेट अन्य ट्रेनों में भी लगाए जाएंगे।
- **मानव के नए पूर्वज की खोज** : दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग से 50 किमी. दूर राइजिंग स्टार गुफा में वैज्ञानिकों ने मानव की नई प्रजाति की 1500 हड्डियां खोज निकाली हैं। वैज्ञानिक अभी इसकी तिथि का सही-सही निर्धारण नहीं कर पाए हैं। इस नई प्रजाति के आदि मानव को वैज्ञानिकों द्वारा 'होमो नालेदी' नाम दिया गया है, जिसमें 'नालेदी' से अभिप्राय (सेसेथो भाषा में) 'सितारा' होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव परम्पराओं के अनुरूप होमा नालेदी मृतकों को जमीन में दफ़नाते थे।
- **पाकिस्तान-चीन मैत्री सुरंग परियोजना** : 46 बिलियन डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के आगे के रूप में पाकिस्तान-चीन मैत्री सुरंग परियोजना के तहत गिलगित-बलूचिस्तान से होकर चीन तक जाने वाली पांच सुरंगों का उद्घाटन 14 सितंबर, 2015 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा किया गया। 24 किलोमीटर लंबे कराकोरम राजमार्ग की हिस्सा बनी इन पांचों सुरंगों की लंबाई 7 किलोमीटर है तथा इनके निर्माण पर 27.50 करोड़ डॉलर की लागत आई है।
- **चक्रवातीय तूफान लिंफा** : 6 जुलाई, 2015 को उत्तरी फिलीपींस में 'लिंफा' नामक चक्रवातीय तूफान ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया।
- **यूनियन बैंक की एम-पासबुक सुविधा** : 6 जुलाई, 2015 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए तत्काल भुगतान सेवा तथा एम-पासबुक (मोबाइल-पासबुक) सुविधा शुरू की। एम-पासबुक के जरिए ग्राहक अपने एकाउंट स्टेटमेंट मोबाइल पर देख सकेंगे।
- **कोलंबिया में मिली इच्छामृत्यु** : 3 जुलाई, 2015 को लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में मुंह के कैंसर से पीड़ित एक 79 वर्षीय व्यक्ति को इच्छामृत्यु दे दी गई। यह वहां इच्छामृत्यु का पहला मामला है।
- **प्रीमियम की जगह सुविधा ट्रेनें** : 1 जुलाई, 2015 से भारतीय रेलवे द्वारा प्रीमियम ट्रेनों की जगह सुविधा ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। इन ट्रेनों में वेटिंग टिकटों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल कनफर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे।
- **एसबीआई ने शुरू किया 'प्रोजेक्ट तत्काल'** : 3 जुलाई, 2015 को देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने घर तक सेवाएं उपलब्ध कराने और आवास कर्ज आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट तत्काल' नामक पहल शुरू की।

- **रूसी औद्योगिक व्यापार मेले का भागीदार देश बना भारत** : 22 जून, 2015 को रूस के प्रमुख औद्योगिक व्यापार मेले 'इन्नोप्रोम' में भारत ने भागीदार देश के रूप में भाग लेने का रूस का आमंत्रण स्वीकार किया। यह व्यापार मेला जुलाई, 2016 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित होगा।
- **चक्रवातीय तूफान अशोबा** : 8 जून, 2015 को पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर 'अशोबा' नामक चक्रवातीय तूफान आया जो मुंबई से करीब 590 किमी. तथा गुजरात के वेरावल से 470 किमी. दूर था।
- **न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई** : 7 जुलाई, 2015 को केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को 137 रु. रोजाना से बढ़ाकर 160 रु. कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर 1 जुलाई, 2015 से इसे लागू करने का सभी राज्यों को निर्देश भी दिया गया।
- **विश्व का नंबर एक होटल बना उदय विलास** : जुलाई, 2015 के दूसरे सप्ताह में ट्रेवल प्लस लेजर पत्रिका ने सर्वे के आधार पर विश्व के शीर्ष 100 होटलों की एक सूची जारी की। इसमें राजस्थान के उदयपुर स्थित ओबेराय उदय विलास होटल को वर्ष 2015 का सर्वश्रेष्ठ होटल चुना गया।
- **संयुक्त राष्ट्र प्रदर्शनी** : 27 जून, 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर दुनिया भर के 16 विचारकों एवं कलाकारों की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगी जिसके माध्यम से मानवता की राह में उनके योगदान को याद किया गया। 'द ट्रांसफारमेटिव पॉवर ऑफ आर्ट' नामक यह प्रदर्शनी 30 जून, 2015 तक चली। इन 16 कलाकारों में भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित निर्देशक सत्यजीत राय भी शामिल थे।
- **सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य में भारी वृद्धि** : 17 जून, 2015 को केंद्र सरकार ने 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन' (JNNSM) के तहत वर्ष 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 20 हजार मेगावॉट से 5 गुना बढ़ाकर 1 लाख मेगावॉट कर दिया। इसके लिए 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इसके अंतर्गत 40 हजार मेगावाट उत्पादन रूफटॉप (ऑफ ग्रिड) परियोजनाओं से तथा 60 हजार मेगावाट उत्पादन बड़े एवं मध्यम स्तर के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्रोजेक्टों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
- **आनंदपुर साहिब का 350वां स्थापना दिवस** : 17 जून, 2015 से 19 जून, 2015 के मध्य पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थित तख्त श्रीकेशगढ़ साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने 'श्री आनंदपुर साहिब' का 350वां स्थापना दिवस मनाया गया। आनंदपुर साहिब की स्थापना वर्ष 1665 में सिक्खों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने की थी।
- **मैग्नाकार्टा की 800वीं वर्षगांठ मनाई गई** : 15 जून, 2015 को ब्रिटेन ने 'मैग्नाकार्टा' (स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों का घोषणापत्र) की 800वीं वर्षगांठ मनाई। इस घोषणा पत्र के तहत पहली बार राजा को कानून के दायरे में लाया गया था तथा 'सभी मनुष्य समान हैं' यह उद्घोषणा की गई थी।
- **चीन ने किया बुद्ध की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा का जीर्णोद्धार** : जून, 2015 में चीन ने गौतम बुद्ध की 1000 हाथों वाली आठ सौ वर्ष पुरानी प्रतिमा के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया। चीन के दाजू काउंटी में स्थित इस प्रतिमा को यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
- **योग एक्सप्रेस** : 15 जून, 2015 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन संख्या 19031-19032 अहमदाबाद-हरिद्वार मेल का नाम बदलकर 'योग एक्सप्रेस' कर दिया।
- **ताजमहल शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल** : 2 जून, 2015 को लंदन की एक प्रमुख ट्रैवेल वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने विश्व के तीन शीर्ष पर्यटन स्थलों में भारत के ऐतिहासिक स्थल ताजमहल को भी शामिल किया। प्रथम स्थान पर पेरू के माचू पिचू एवं दूसरे स्थान पर कंबोडिया के अंकोरवाट को रखा गया है।
- **गोवा सरकार ने सी प्लेन को मंजूरी दी** : 23 मई, 2015 को गोवा सरकार ने राज्य के बीचोंबीच से गुजरने वाली मंडोवी नदी में 'सी प्लेन' के उतरने के परीक्षण के बाद वहां 'सी प्लेन' के संचालन को मंजूरी दे दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह की सेवा शुरू करने वाला महाराष्ट्र के बाद गोवा दूसरा राज्य बन गया है।
- **डॉक्टरी की भी पढ़ाई होगी आईआईटी खड़गपुर में** : 22 जून, 2015 को आईआईटी खड़गपुर (प. बंगाल) ने डॉ. बीसी राय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के निर्माण की घोषणा की जो वर्ष 2017 तक तैयार होगा। इसके जरिए खड़गपुर आईआईटी अब मेडिकल पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई करायेगा।
- **छह नये भारतीय प्रबंधन संस्थान** : 24 जून, 2015 को केंद्र सरकार ने देश में छह नये भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। ये नये संस्थान विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), बोध गया (बिहार), सिरमौर (हिमाचल प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), संभलपुर (ओडिशा) तथा अमृतसर (पंजाब) में स्थापित किए जाएंगे।
- **नवाबगंज पक्षी विहार के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव** : जून, 2015 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखने का प्रस्ताव वन विभाग ने शासन को भेजा है।
- **भारतीय सेना एवं पीएनबी के बीच समझौता** : 9 जून, 2015 को भारतीय सेना एवं पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मध्य 'डिफेंस सेलरी पैकेज' के मुद्दे पर एक समझौता हुआ। इसके तहत पीएनबी द्वारा सैनिकों को मुफ्त ड्राफ्ट, चेक बुक, भारत के किसी बैंक में फंड स्थानांतरण एवं एटीएम कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **देश की पहली सीसीटीवी कैमरे वाली ट्रेन** : अगस्त, 2015 से प्रारंभ 'शान-ए-पंजाब' ट्रेन देश की पहली पूर्ण सीसीटीवी कैमरे युक्त ट्रेन है। ट्रेन के प्रत्येक कोच में आठ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
- **चण्डीगढ़ सबसे खुश शहर** : 11 जून, 2015 को जारी एलजी इंडिया की गुड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देश का सबसे खुश शहर चण्डीगढ़ को घोषित किया गया। इस सूची में दूसरा स्थान लखनऊ, तीसरा दिल्ली तथा चौथा चेन्नई का है। सबसे कम खुश रहने वाले शहर क्रमशः गुवाहाटी, मुंबई, जयपुर एवं कोच्चि हैं।
- **सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध** : 3 जून, 2015 को सोमनाथ मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गैर-हिंदुओं के प्रवेश के लिए अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- **भारतीय मूल के छात्रों ने जीती स्पेलिंग बी प्रतियोगिता** : 29 मई, 2015 को विश्व की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता दो भारतीय अमेरिकी छात्रों—वान्या शिवशंकर एवं गोकुल वेंकटचलम ने जीती।
- **वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार के लिए बजट स्वीकृत** : 29 मई, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 'वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार' के लिए 4.40 लाख रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की। वन्यजीवों, वन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह पुरस्कार वर्ष 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार ने कांशीराम पुरस्कार नाम से शुरू किया था जिसे बदल कर वर्ष 2012 में अखिलेश सरकार ने वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार कर दिया था।
- **हवा से चलने वाली कार** : मई, 2015 में जापान की प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने अपनी नई कार 'टोयोटा मिराई' वर्ष 2015 के अंत तक लांच करने की घोषणा की जिसकी खासियत यह होगी कि यह हवा से चलेगी। इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी जो वायुमंडल की हवा से क्रिया करके फ्यूल सेल के माध्यम से कार को ऊर्जा प्रदान करेगी।
- **वेटिकन सिटी ने दी फिलिस्तीन को मान्यता** : 13 मई, 2015 को वेटिकन सिटी ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी।

- **पाक सीनेट का नाम बदला** : 6 मई, 2015 को पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन सीनेट का नाम बदलकर 'हाउस ऑफ फेडरेशन' कर दिया गया।
- **'डीडी किसान' चैनल** : 26 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को समर्पित देश के प्रथम टीवी चैनल 'डीडी किसान' का उद्घाटन किया।
- **देश में 15 हरित क्षेत्र एयरपोर्ट के निर्माण को सिद्धांततः मंजूरी** : 12 मई, 2015 को केंद्र सरकार ने देश में 15 हरित क्षेत्र एयरपोर्ट के निर्माण के सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया। इन स्थानों के नाम क्रमशः मोपा (गोवा), नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र), बीजापुर, गुलबर्गा, हसन और शिमोगा (कर्नाटक), कुन्नूर एवं अर्नमुला (केरल), दुर्गापुर (प. बंगाल), डाबरा (म. प्र.), पाक्योंग (सिक्किम), करैकाल (पुदुचेरी) एवं कुशीनगर (उ. प्र.) हैं।
- **महाराष्ट्र सरकार नियुक्त करेगी 'स्वच्छता दूत'** : 22 अप्रैल, 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक गांव में 'स्वच्छता दूत' नियुक्त करने का फैसला किया है जिससे राज्य में अगले 5 वर्षों में 56 लाख शौचालयों का निर्माण करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
- **नेपाली राष्ट्रकवि की रचनाओं का हिंदी अनुवाद** : मार्च, 2015 के मध्य में नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत राय ने नेपाल के राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे की साहित्यिक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किए जाने की घोषणा की।
- **दो फिलिस्तीनी नन संत घोषित :** 17 मई, 2015 को पोप फ्रांसिस ने 19वीं सदी की दो फिलिस्तीनी ननों—मेरी अलफोनसीन घट्टास तथा मरियम बवारडी को 'संत' घोषित किया। ज्ञातव्य है कि पहली बार अरबी मूल के किसी ईसाई के संत होने की घोषणा की गई है।
- **चतुरंगी क्रांति** : 3 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चतुरंगी क्रांति (हरा, सफेद, केसरिया, नीला) लाने की घोषणा की। उनके अनुसार हरे रंग से हरित क्रांति, सफेद से दुग्ध क्रांति, केसरिया से ऊर्जा क्रांति तथा नीले रंग से समुद्र के संसाधनों के उपयोग में क्रांति लाई जाएगी।
- **आईसीसी का सदस्य बना फिलिस्तीन** : 1 अप्रैल, 2015 को फिलिस्तीन स्विट्जरलैंड के हेग स्थित 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत' (International Criminal Court) का नया सदस्य बना।
- **भारत के सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति** : मार्च, 2015 में आयी फिलैन्थ्रपी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 69वें स्थान पर है। भारत के शीर्ष दानवीरों में अजीज प्रेमजी प्रथम स्थान पर हैं।
- **आर्क ऑफ रिटर्न** : 25 मार्च, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने अंतर्राष्ट्रीय गुलाम पीड़ित स्मरण दिवस के अवसर पर अफ्रीकी दासों के साथ हुए अन्याय को याद करते हुए न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में एक स्थायी स्मारक का अनावरण किया।
- **संघीय क्षेत्र पुलिस में महिलाओं को आरक्षण** : 20 मार्च, 2015 को केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया।
- **पहली बार लिंग का ट्रांसप्लांट** : मार्च, 2015 के मध्य में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के डॉक्टरों ने विश्व में पहली बार लिंग के प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) का दावा किया। उल्लेखनीय है कि विश्व में सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण भी दक्षिण अफ्रीका में (क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा 1967 में) किया गया था।
- **हस्तशिल्प निर्यात क्लस्टर** : 19 मार्च, 2015 को कपड़ा मंत्रालय ने हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भुज (गुजरात), बरेली (उ.प्र.) तथा लखनऊ (उ.प्र.) में निर्यात हब बनाने की घोषणा की।
- **डिजिटल जेंडर एटलस** : 9 मार्च, 2015 को बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया। यूनीसेफ (UNICEF) के माध्यम से विकसित इस एटलस का उद्देश्य विकलांग बालिकाओं सहित असुरक्षित बालिकाओं की एक समान शिक्षा सुनिश्चित करना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं हाशिए की बालिकाओं की पहचान करना है।
- **श्रीरंगनाथ जी मंदिर से जारी हुआ एक रुपये का नोट** : 6 मार्च, 2015 को वित्त सचिव राजीव महर्षि ने राजस्थान के नाथ द्वारा में श्रीरंगनाथ जी मंदिर से एक रुपये का नोट बीस साल बाद फिर से जारी किया। ज्ञातव्य है कि सरकार ने नवंबर, 1994 में एक रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी थी। उल्लेखनीय है कि एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव तथा अन्य सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
- **पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा तारा** : फरवरी, 2015 में विज्ञान पत्रिका एस्ट्रोफिजिक्स में छपे एक शोध के अनुसार अमेरिका, यूरोप, चिली और दक्षिणी अफ्रीका के खगोलविदों के एक समूह ने 'स्कोल्ज' नामक एक तारे की पहचान की जो 70 हजार साल पहले सौरमंडल के पास से होकर गुजरा था। उस समय पृथ्वी से इस तारे की दूरी मात्र 0.8 प्रकाशवर्ष थी। यह दूरी वर्तमान में सौरमण्डल के सबसे नजदीक स्थित तारे 'प्रोक्सिमा सेंटोरी' से लगभग पांच गुना कम है।
- **पिंक एक्सप्रेस** : 27 फरवरी, 2015 को दिल्ली से लखनऊ के बीच महिलाओं के लिए 'पिंक एक्सप्रेस' नामक बस सेवा की शुरुआत हुई। यह बस वातानुकूलित होने के साथ-साथ 'वाई-फाई सिस्टम' से भी लैस है। सुरक्षा के लिए बस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
- **इथियोपिया में मिला पहले मानव का जीवाश्म** : मार्च, 2015 के प्रारंभ में अफ्रीकी हॉर्न कंट्री इथियोपिया में 28 लाख वर्ष पूर्व के मानव जीवाश्म के प्राप्त होने की घोषणा की गई।
- **'इंडियाज डाटर' पर भारत ने लगाया प्रतिबंध** : 4 मार्च, 2015 को भारत सरकार ने ब्रिटिश फिल्मकार लेस्ली उडविन द्वारा दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को हुए गैंगरेप पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री 'इंडियाज डाटर' (India's Daughter) पर रोक लगा दी।
- **पोप ने दी भारतवंशी मिशनरी को संत की उपाधि** : 14 जनवरी, 2015 को पोप फ्रांसिस ने भारतीय मूल के दिवंगत कैथोलिक मिशनरी जोसेफ वाज को श्रीलंका के पहले संत की उपाधि दी। उनका जन्म 1651 में गोवा में हुआ था।
- **केरल में हुआ देश का पहला हाथ प्रत्यारोपण** : 13 जनवरी, 2015 को केरल के कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में 30 वर्षीय व्यक्ति मनु को 24 वर्षीय व्यक्ति बिनॉय का हाथ प्रत्यारोपण सर्जरी के माध्यम से लगाया गया।
- **लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप 'प्रगति'** : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लड़कियों की तकनीकी शिक्षा में सहयोग करने के लिए वर्ष 2014-15 से 'प्रगति स्कॉलरशिप' की शुरुआत की।
- **पंजाब ने खुली सिगरेट व तंबाकू पर लगाया प्रतिबंध** : जनवरी, 2015 में पंजाब खुली सिगरेट व तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- **फ्लेमिंगो फेस्टिवल** : जनवरी, 2015 के प्रथम सप्ताह में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पुलीकट झील के पास तीन दिवसीय फ्लेमिंगो महोत्सव की शुरुआत हुई। यह महोत्सव जिले में पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco Tourism) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया।

◆◆◆

पुरस्कार/सम्मान

■ राष्ट्रीय

- **पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कार** : अक्टूबर, 2015 में मद्रास विश्वविद्यालय में अपराध विज्ञान के प्रोफेसर के. चोकलिंगम को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) द्वारा पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार** : 26 अक्टूबर, 2015 को संगीतकार ए. आर. रहमान को पाचवें हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में यह पुरस्कार अभिनेत्री सुलोचना ताई को दिया गया था।
- **जे.सी. डेनियल पुरस्कार** : 12 अक्टूबर, 2015 को प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता आई.वी. शशि को वर्ष 2014 के लिए प्रतिष्ठित जे.सी. डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 1992 में केरल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
- **शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार** : 26 सितंबर, 2015 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की। जैव विज्ञान के क्षेत्र में बालासुब्रमण्यम गोपाल तथा राजीव कुमार वार्ष्णेय को, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिरंजन श्रीचंदन को, इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में योगेश जोशी को, गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में रिताब्रता मुंशी को, एप्लीकेबल गणित के क्षेत्र में के. संदीप को, स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में विदिता वैद्य को, शारीरिक विज्ञान वर्ग में बेदंगदास मोहंती एवं मंदर देशमुख को तथा रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में डी. श्रीनिवास रेड्डी एवं प्रद्युत घोष को पुरस्कार हेतु चयनित किया गया।
- **शास्त्र रामानुजन पुरस्कार** : सितंबर, 2015 में टोरंटो विश्वविद्यालय के गणितज्ञ जैकब शिमरमैन को वर्ष 2015 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार हेतु चयनित किया गया।
- **ज्ञान गरिमा मानद अलंकरण पुरस्कार** : 20 सितंबर, 2015 को भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रख्यात उर्दू साहित्यकार शमीम हनफी को अपने 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ 'ज्ञान गरिमा मानद अलंकरण पुरस्कार' से सम्मानित किया।
- **राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार** : 18 सितंबर, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2013-14 हेतु राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। गुजरात को पर्यटन श्रेणी के व्यापक विकास में शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया। गुजरात को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन परियोजना का पुरस्कार भी मिला। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित एवं विकलांगों के लिए अनुकूल राष्ट्रीय स्मारक उपलब्ध कराने हेतु सम्मानित किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवॉर्ड मिला।
- **उ. प्र. हिन्दी संस्थान के पुरस्कार** : 14 सितंबर, 2015 को उ. प्र. के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिंदी दिवस के अवसर पर उ. प्र. हिंदी संस्थान, लखनऊ में हिंदी भाषा के क्षेत्र में योगदान देने वाले विद्वानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया—
    - ➔ <u>भारत-भारती सम्मान</u> : केदारनाथ सिंह (गत वर्ष यह सम्मान दूधनाथ सिंह को प्रदत्त)।
    - ➔ <u>लोहिया साहित्य सम्मान</u> : मृदुला गर्ग।
    - ➔ <u>हिंदी गौरव सम्मान</u> : विनोद कुमार शुक्ल।
    - ➔ <u>महात्मा गांधी साहित्य सम्मान</u> : डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र।
    - ➔ <u>पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान</u> : डॉ अभिराज राजेंद्र मिश्र।
    - ➔ <u>अवंतीबाई साहित्य सम्मान</u> : डॉ. रामकृष्ण राजपूत।
    - ➔ <u>राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सम्मान</u> : कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, बंगलुरू।
    - ➔ <u>पत्रकारिता भूषण सम्मान</u> : विष्णु नागर।
- **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार** : 14 सितंबर, 2015 को हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेल मंत्रालय को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया।
- **गांधी शांति पुरस्कार** : 9 सितंबर, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को वर्ष 2014 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसरो की ओर से यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष ए.एस. किरन कुमार ने ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि इसरो को वर्ष 2014 हेतु 'शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ था।
- **वीरता पुरस्कार, 2015** : 15 अगस्त, 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2015 के वीरता पुरस्कार प्रदान किए। कीर्ति चक्र सेना के कर्नल संजेनबाम को तथा नायब सूबेदार राजेश कुमार (मरणोपरांत) को प्रदान किया गया। शौर्य चक्र सेना के कर्नल मनींद्र नाथ राय (मरणोपरांत), मेजर तनुज ग्रोवर, कैप्टन वरुण कुमार सिंह, हवलदार मान बहादुर छेत्री (मरणोपरांत) एवं हवलदार टनका कुमार लिंबू को, वायु सेना के विंग कमांडर पायलट संदीप सिंह को तथा नौसेना के कमांडर मोहन मिलिंद मोकाशी को प्रदान किया गया।
- **गूजरमल मोदी अवॉर्ड फॉर इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी** : 14 अगस्त, 2015 को प्रो. मुतंशिर वर्मा को वर्ष 2015 के लिए 'गुजरमल मोदी अवॉर्ड फॉर इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी' से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया। प्रो. मुतंशिर वर्मा टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, मुंबई के पूर्व निदेशक हैं।
- **कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार** : 13 अगस्त, 2015 को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मराठी लेखक श्याम मनोहर को चुना गया।यह पुरस्कार प्रसिद्ध कन्नड़ कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित किया गया था। इसके तहत पांच लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
- **हिंदी रत्न सम्मान** : 2 अगस्त, 2015 को वरिष्ठ लेखक रंगनाथ रामदयाल तिवारी को 'हिंदी रत्न सम्मान' से नवाजा गया।
- **पाटा पुरस्कार** : 18 जुलाई, 2015 को केरल पर्यटन विभाग की 'मुजिरिस विरासत परियोजना' (एमएचपी) को विरासत और संस्कृति श्रेणी में मकाऊ सरकार पर्यटन कार्यालय द्वारा प्रायोजित पैसिफिक एशिया ट्रेवेल एसोसिएशन (पाटा) पुरस्कार देने की घोषणा की गई। मुजिरिस विरासत परियोजना का उद्देश्य विभिन्न विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को शामिल करना है।
- **18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता** : 15 जुलाई, 2015 को जवाहर नवोदय विद्यालय, चुराचांदपुर, मणिपुर ने 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता वर्ष 1997-98 से संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
- **घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार** : 1 जुलाई, 2015 को वर्ष 2014 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार प्रो. संजीव गलांडे को देने की घोषणा की गई। उन्हें आनुवंशिकी एवं कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
- **मूर्तिदेवी पुरस्कार** : 26 जून, 2015 को हिंदी साहित्य के समालोचक डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी को उनकी रचना 'व्योमकेश दरवेश' के लिए वर्ष 2014 के मूर्तिदेवी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।
- **पुण्यभूषण पुरस्कार** : 26 जून, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सकाल मीडिया ग्रुप (एसएमजी) के प्रमुख प्रतापराव पवार को 'पुण्यभूषण पुरस्कार' से सम्मानित किया।
- **साहित्य अकादमी भाषा एवं युवा पुरस्कार** : 23 जून, 2015 को साहित्य अकादमी ने भाषा पुरस्कारों एवं युवा पुरस्कारों की घोषणा की। शास्त्रीय एवं मध्यकालीन साहित्य में योगदान हेतु वर्ष 2013 के लिए (दक्षिणी क्षेत्र) डॉ. के. मीनाक्षी सुंदरम तथा वर्ष 2014 के लिए (पूर्वी क्षेत्र) आचार्य मुनिश्वर झा को चुना गया। अकादमी द्वारा 23 भाषाओं के लिए युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। इसमें हिंदी में इंदिरा डांगी और अंग्रेजी में शौभेंद्र शेखर को उपन्यास के लिए तथा उर्दू में अमीर इमाम को कविता संग्रह के लिए चुना गया।

- **ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार** : 17 जून, 2015 को हिंदी कवयित्री बाबुशा कोहली एवं उपासना को भारतीय ज्ञानपीठ का 10वां नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। बाबुशा कोहली को उनकी कविता संग्रह 'प्रेम गिलहरी दिल अखरोट' के लिए तथा उपासना को उनकी कहानी 'एक ज़िंदगी एक-एक स्क्रिप्ट भर' के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं पुरस्कार, 2014** : 12 जून, 2015 को संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2014 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार घोषित किए। फेलोशिप प्राप्तकर्ताओं के नाम क्रमशः- आर. जानकीरामन (संगीतज्ञ), एस. सथ्यु (फिल्म निर्माता), विजय किचलू (शास्त्रीय गायक) एवं तुलसीदास बोरकर (संगीतकार) हैं।
- **संसद रत्न पुरस्कार 2015 :** 27 मई, 2015 को चार लोक सभा सांसदों का चयन 'संसद रत्न पुरस्कार-2015' के लिए किया गया। उनके नाम क्रमशः पीपी चौधरी (भाजपा), चंदू बार्ने शिरंग (शिव सेना) निशिकांत दूबे (भाजपा) तथा सुप्रिया सूले (एनसीपी) हैं।
- **पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार :** 15 मई, 2015 को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड की सीएमडी अनुराधा प्रसाद को 'पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार' से सम्मानित किया।
- **शास्त्रीय तमिल हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार :** 14 मई, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के लिए शास्त्रीय तमिल के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए। इसके अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए शास्त्रीय तमिल भाषा एवं साहित्य में आजीवन उपलब्धि का तोल्काप्पियर पुरस्कार एस.वीषणमुगम को तथा वर्ष 2012-13 के लिए यह पुरस्कार श्री राम सुब्बु कृष्णामूर्ति को प्रदान किया गया।
- **संस्कृत साहित्य सम्मान** : 25 जून, 2015 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में संस्कृत साहित्य सम्मान प्रदान किए। प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं—
  - ➔ <u>विश्व भारती पुरस्कार</u> : आचार्य रामयत्न शुक्ल (वाराणसी)।
  - ➔ <u>महर्षि व्यास पुरस्कार</u> : प्रभुनाथ द्विवेदी (मिर्जापुर) व शशि तिवारी।
- **राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता** : 26 जून, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल चार पुरस्कार प्राप्त हुए।
- **मंडलोई सम्मान** : 2 मई, 2015 को 'लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई सम्मान' युवा कवि मोहन सगोरिया को प्रदान किया गया।
- **कलाश्री पुरस्कार :** 21 अप्रैल, 2015 को दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन ने फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को 'कलाश्री पुरस्कार' से सम्मानित किया।
- **प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार :** अप्रैल, 2015 में आय कर विभाग को गुणवत्ता पूर्ण सेवा के जरिए आसान कर नियमों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **बिहारी पुरस्कार** : 13 अप्रैल, 2015 को के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक ओम थानवी को उनके यात्रा वृत्तांत 'मुआनजोदड़ो' हेतु बिहारी पुरस्कार, 2014 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
- **कुमार असन पुरस्कार** : अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में सीरियाई साहित्यकार अली अहमद को वर्ष 2015 के कुमारन असन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।
- **साहित्य शिरोमणि सम्मान** : 8 अप्रैल, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मशहूर कवि डॉ. गोपाल दास नीरज एवं वरिष्ठ साहित्य डॉ. उदय प्रताप सिंह को उनकी उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए 21-21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का 'साहित्य शिरोमणि सम्मान' देने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि गोपाल दास नीरज को उत्तर प्रदेश सरकार ने 'राष्ट्र रत्न सितार-ए-हिंद' की उपाधि से भी विभूषित करने की घोषणा की।
- **कंबन अकादमी सम्मान** : 3 अप्रैल, 2015 को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पत्रकार-लेखक तरुण विजय को कंबन अकादमी सम्मान प्रदान किया गया।
- **ज्ञानपीठ फेलोशिप-2015** : अप्रैल, 2015 के प्रारंभ में भारतीय ज्ञानपीठ के 70वें और ज्ञानपीठ पुरस्कार के स्वर्ण जयंती के अवसर पर वर्ष 2015 की ज्ञानपीठ फेलोशिप की घोषणा की गई। यह फेलोशिप युवा कवि यतीन्द्र मिश्र तथा वरिष्ठ कवि मदन कश्यप को दी गई।
- **प्रथम बेगम अख्तर पुरस्कार** : 30 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बेगम अख्तर पुरस्कार की घोषणा की। गायकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार जरीना बेगम और सुनीता झिंगरन को दिया जाएगा।
- **उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के वर्ष 2014 के राष्ट्रीय पुरस्कार** : 30 मार्च, 2015 को अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार अफसाना निगार और लघु कहानीकार इकबाल मजीद को दिये जाने की घोषणा की गई।
- **लाडली वॉइस ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार** : 20 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय मीडिया और विज्ञापन पुरस्कार के छठें संस्करण में जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को लाडली वॉइस ऑफ द सेंचुरी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त बेस्ट मूवी अवार्ड-क्वीन फिल्म को दिया गया।
- **सरस्वती सम्मान-2014** : 9 मार्च, 2015 को वर्ष 2014 का साहित्य जगत का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान कन्नड़ लेखक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री <u>डॉ. एम. वीरप्पा मोइली</u> को दिए जाने का निर्णय के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा लिया गया। उन्हें यह 24वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2007 में प्रकाशित उनके कन्नड़ महाकाव्य '<u>श्री रामायण महान्वेषण</u>' के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 10 अगस्त, 2015 को प्रदान किया गया।
- **दादा साहेब फाल्के पुरस्कार** : 10 मई, 2015 को मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता शशि कपूर को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अरुण जेटली द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह 46वें व्यक्ति हैं। वे कपूर खानदान के तीसरे शख्स हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। इसके पहले उनके पिता पृथ्वीराज कपूर तथा बड़े भाई राजकपूर को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जा चुका है।

यश भारती सम्मान, 2013-14 एवं 2014-15

9 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 56 विभूतियों को इस वर्ष यश भारती सम्मान से नवाजा गया। इसके तहत प्रत्येक को 11 लाख रु. की नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। इनमें प्रमुख विभूतियां हैं—नवाजुद्दीन सिद्दीकी (अभिनेता), विनोद मेहता (पत्रकार), राहत अली साबरी (सूफी गायक), अलका तोमर (कुश्ती), कैलाश खेर (पार्श्व गायक), रवींद्र जैन (संगीतकार), शुभा मुद्गल (शास्त्रीय गायिका), पूनम यादव (भारोत्तोलन), जगद्‌गुरू स्वामी भद्राचार्य टी. पी. त्रिवेदी (ज्योतिषविद्), डॉ. उर्मिल कुमार थपलियाल (लोक नाट्य साहित्य), कुमकुम धर (कथक), रीता गांगुली (अर्द्ध-शास्त्रीय गायन), जिम्मी शेरगिल (अभिनेता), रूद्र प्रताप सिंह एवं अवनीश कुमार (खेल) आदि (2014-15 के लिए)। अनूप जलोटा (भजन गायक), समीर (गीतकार), रेखा भारद्वाज (पार्श्व गायिका), राजन एवं साजन मिश्र (शास्त्रीय गायक- संयुक्त रूप से), अशोक कुमार (हॉकी खिलाड़ी), योगेंद्र सिंह यादव (परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता), अभिषेक यादव (विशिष्ट कमांडो प्रशिक्षण), वंश गोपाल यादव (आल्हा गायक), हीरा लाल यादव (भोजपुरी बिरहा गायक), धर्मेंद्र सिंह (मुक्केबाज), भगत सिंह, लाल बचन यादव एवं विजय पाल यादव (तीनों कुश्ती), देवी प्रसाद पांडेय एवं माता प्रसाद त्रिपाठी (दोनों लेखक), पं. विकास महाराज (सरोद वादक), रमेश भैया (सामाजिक कार्यकर्ता), बेकल उत्साही (कवि), श्वेता प्रियदर्शी (शतरंज खिलाड़ी), राजेश कुमार यादव (रोविंग खिलाड़ी) मुनव्वर अंजार (जूडो रेफरी) एवं जगदीश गांधी (शिक्षाविद) (ये सभी 2013-14 हेतु)। इनके अतिरिक्त <u>महारानी अहिल्याबाई होल्कर अवॉर्ड</u> सीमा तिवारी को तथा <u>रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार</u> रेशम फातिमा को प्रदान किया गया।

- **भारत रत्न** : 27 मार्च, 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को दिल्ली में उनके घर जाकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त 30 मार्च, 2015 को राष्ट्रपति भवन में महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद एवं बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल 45 व्यक्तियों को 1954 से अब तक यह सम्मान प्रदान किया गया है।
- **पद्म विभूषण** : लालकृष्ण आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल एवं के.के. वेणुगोपाल (सार्वजनिक कार्य क्षेत्र), अमिताभ बच्चन एवं दिलीप कुमार (कला क्षेत्र), डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े (समाज कार्य), स्वामी रामभद्राचार्य (अन्य क्षेत्र), प्रो. मलूर श्रीनिवासन (विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र) और फ्रांस/ब्रिटेन के करीम अल हुसैनी आगा खान (व्यापार एवं वाणिज्य)। वर्ष 2014 में यह सम्मान 2 व्यक्तियों- डॉ. रघुनाथ ए. माशेलकर और बी.के.एस. अयंगार को प्रदत्त।
- **भाषा सम्मान पुरस्कार** : 11 मार्च, 2015 को साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित भाषा सम्मान पुरस्कार की घोषणा की गई। यह सम्मान संयुक्त रूप से जसपाल सिंह और वसंत निर्गुण को दिया जाएगा।
- **राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण** : 17 मार्च, 2015 को कवि एवं टी.वी. पत्रकार आलोक श्रीवास्तव का चयन वर्ष 2014 के 'राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण' के लिए किया गया। वे यह अलंकरण पाने वाले सबसे कम उम्र के साहित्यकार हैं।
- **संस्कृत साहित्य सम्मान** : 20 मार्च, 2015 को उत्तर-प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से संस्कृत साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2009 का विश्व भारती पुरस्कार प्रो. आद्या प्रसाद मिश्र को, वर्ष 2010 का आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी को, वर्ष 2011 का आचार्य किशोर नाथ झा को, वर्ष 2012 का स्वामी रामभद्राचार्य (गिरिधर लाल मिश्र) को तथा वर्ष 2013 का विश्व भारती आचार्य भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी को प्रदान किया गया। इसके तहत 2 लाख 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
- **स्त्री शक्ति पुरस्कार, 2014** : 8 मार्च, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्त्री शक्ति पुरस्कार, 2014 प्रदान किए।
  - ➔ रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार : सीमा प्रकाश (म. प्र.)
  - ➔ रानी रूद्रम्मा देवी पुरस्कार : आस्था संस्थान (एनजीओ, राजस्थान)।
  - ➔ माता जीजाबाई पुरस्कार : चंद्रप्रभा बीके (महाराष्ट्र)।
  - ➔ कन्नगी पुरस्कार : डॉ. पी. भानुमति (केरल)
  - ➔ रानी गेडिन्ल्यू जेलियांग पुरस्कार : सिस्टर मारियोला (राजस्थान)।
  - ➔ देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार : अन्यायरहित जिंदगियां (एनजीओ, गोवा)।
- **बाबू गुलाब राय पुरस्कार** : 23 जनवरी, 2015 को उपन्यासकार एवं समालोचक वीरेंद्र यादव को बाबू गुलाब राय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **चिश्ती इंडिया हार्मनी अवॉर्ड** : 5 फरवरी, 2015 को इंडिया हार्मनी फाउंडेशन ने प्रसिद्ध पुरातत्वविद् एवं भारतीय पुरातात्विक सर्वे (एएसआई) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के.के. मुहम्मद को 'चिश्ती इंडिया हार्मनी अवॉर्ड' से सम्मानित किया।
- **हाफिज अली खान पुरस्कार, 2014** : 3 मार्च, 2015 को 30वां हाफिज अली खान पुरस्कार (2014) भारतीय वायलिन वादक एल. सुब्रमण्यम और कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी (जयपुर घराना) को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया।
- **50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार** : 6 फरवरी, 2015 को मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार भालचन्द्र नेमाड़े को वर्ष 2014 के लिए 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई।
- **49 वां ज्ञानपीठ पुरस्कार** : केदारनाथ सिंह (हिन्दी साहित्यकार)।
- **48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार (2012)** : डॉ रावुरी भारद्वाज (तेलगू साहित्यकार)
- **श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान** : 31 जनवरी, 2015 को हिन्दी उपन्यासकार 'मिथिलेश्वर' को वर्ष 2014 का 'श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान' प्रदान किया गया।
- **खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार** : 24 जनवरी, 2015 को जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान कवयित्री अरुंधती सुब्रह्मण्यम को उनके कविता संग्रह 'व्हेन गॉड इज ट्रेवलर' के लिए 'खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- **दि हिंदू लिटरेरी प्राइज** : 17 जनवरी, 2015 को वर्ष 2014 के लिए यह पुरस्कार अशोक श्रीनिवासन को उनकी पुस्तक 'दि बुक ऑफ कॉमन साइन्स' हेतु प्रदत्त।
- **अशोक चक्र** : 26 जनवरी, 2015 को 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारतीय सेना के मेजर मुकुंद वरदराजन और नायक नीरज कुमार सिंह को भारत का शांति काल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'अशोक चक्र' मरणोपरांत प्रदान किया गया जिसे उनकी पत्नियों ने ग्रहण किया।
- **राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार-2014** : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी, 2015 को 24 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम इस प्रकार हैं—

  भारत पुरस्कार : कुमारी रेशम फातिमा ($16^1/_2$ वर्ष) (उत्तर प्रदेश)।

  संजय चोपड़ा पुरस्कार : मास्टर देवेश कुमार ($16^1/_2$ वर्ष) (उत्तर प्रदेश)।

  गीता चोपड़ा पुरस्कार : कुमारी गुंजन शर्मा ($13^1/_2$ वर्ष) (असम)

  बापू गैधानी पुरस्कार : 21 बच्चों को ।
- **आचार्य विद्यानिवास स्मृति सम्मान** : 14 जनवरी, 2015 को वरिष्ठ साहित्यकार नंदकिशोर आचार्य को उनकी पुस्तक 'रचना का अंतरंग' के लिए आचार्य विद्यानिवास स्मृति सम्मान से नवाजा गया।
- **व्यास सम्मान-2014** : 13 जनवरी, 2015 को हिन्दी के प्रख्यात लेखक डॉ. कमल किशोर गोयनका को वर्ष 2014 के व्यास सम्मान (24वें) के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार 'प्रेमचंद की कहानियों के कालक्रमानुसार अध्ययन' के लिए दिया गया है। वर्ष 2013 में डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी को यह पुरस्कार दिया गया था।
- **साहित्य अकादमी पुरस्कार** : 9 मार्च, 2015 को साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के लिए प्रख्यात साहित्यकार पद्म श्री डॉ. रमेश चंद्र शाह और उर्दू के लिए मुनव्वर राणा को वर्ष 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉ. रमेशचंद्र शाह को उनके उपन्यास 'विनायक' के लिए तथा मुनव्वर राणा को उनके काव्य संग्रह 'शहदाबा' के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। संस्कृत भाषा के लिए यह पुरस्कार 'प्रभुनाथ द्विवेदी' को उनकी रचना 'कनक आलोचना' के लिए प्रदान किया गया।
- **वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार** : कुमार अनुपम (बारिश मेरा घर है- काव्य संग्रह, हिन्दी भाषा)।
- **प्रवासी भारतीय सम्मान, 2015** : प्रवासी भारतीय दिवस समागम, 2015 में प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्तकर्ता व्यक्ति इस प्रकार हैं—माला मेहता - ऑस्ट्रेलिया, इसोप गुलाम पाहद - दक्षिण अफ्रीका, सत्यानारायण नडेला - अमेरिका, डॉ. कमलेश लुल्ला - अमेरिका, महेंद्र नांजी मेहता - युगांडा, लॉर्ड राज लुम्बा - ब्रिटेन, प्रो. नाथूराम पुरी - ब्रिटेन, डॉ. संजय राजाराम - मेक्सिको, जस्टिस दुराईकन्नू करुनाकरन - सेशेल्स, राजामल पारख - ओमान, भरत कुमार जयंतीलाल शाह - संयुक्त अरब अमीरात, अशरफ पलारकुन्नमल - संयुक्त अरब अमीरात, नंदिनी टंडन - अमेरिका, कंवलजीत सिंह बक्शी - न्यूजीलैंड (सांसद), डोनाल्ड रबिंदरनाथ रामोतार - गुयाना (राष्ट्रपति)

  (इन व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्ष 2014 के प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्तकर्ताओं में से एक ऑस्ट्रेलिया की सीनेटर लिजा सिंह को भी यह अवॉर्ड इस वर्ष प्रदान किया गया)।
- **कृषि कर्मण पुरस्कार** : 15 दिसंबर, 2014 को मध्य प्रदेश को गेहूं पैदावार में उत्कृष्ट कार्य के लिए तथा अरुणाचल प्रदेश को अनाज पैदावार बढ़ाने के लिए वर्ष 2013-14 के लिए प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश को प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने का यह लगातार तीसरा साल है। अरुणाचल प्रदेश को लगातार दूसरे साल यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

■ अंतर्राष्ट्रीय

नोबेल पुरस्कार-2015

वर्ष 1895 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश रसायनशास्त्री अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल (Alfred Bernhard Novel) की वसीयत के आधार पर की गई थी। सर्वप्रथम 1901 में प्रदत्त विश्व के ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य, शांति, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। इन पांच क्षेत्रों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) प्रदान किया जाता है (1968 में स्थापित और 1969 में पहली बार प्रदत्त) जिसे भ्रमवश अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कह दिया जाता है। 'भौतिक विज्ञान' एवं 'रसायन विज्ञान' के नोबेल पुरस्कार तथा 'अर्थशास्त्र' का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा, 'चिकित्सा विज्ञान' का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा तथा 'साहित्य' का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है जबकि 'शांति' का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के संगठन द्वारा नहीं बल्कि नार्वे की नोबेल कमेटी द्वारा घोषित होता है। वर्ष 2015 के नोबेल पुरस्कार के तहत 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग 0.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2015 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का विवरण निम्नानुसार है—

1. साहित्य (Literature) : बेलारूस की 67 वर्षीया लेखिका (जन्म-तत्कालीन सोवियत संघ के यूक्रेन में) स्वेतलाना एलेक्सीविच (Svetlana Alexievich) को। वे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 14वीं महिला हैं। उनकी कृतियों को 'वॉयसेज ऑफ यूटोपिया' नाम दिया गया है जिनमें पूर्व सोवियत संघ की जीवन परिस्थितियों का चित्रण है। इनकी पुस्तकें विश्व की कई भाषाओं में अनूदित होकर प्रकाशित हुई हैं। एलेक्सीविच की महत्त्वपूर्ण एवं चर्चित पुस्तकें हैं—'वार्स अनवूमैनली फेस' (1985 में प्रकाशित प्रथम पुस्तक), 'वॉयसेज फ्रॉम चेरनोबिल : दि ओरल हिस्ट्री ऑफ ए न्यूक्लियर डिजास्टर' (1997), 'जिंकी ब्वॉएज : सोवियत वॉयसेज फ्रॉम दि अफगानिस्तान वॉर' (1991), 'दि लॉस्ट विटनेसेज : ए हंड्रेड ऑफ अनचाइल्डलाइक' (1985), 'एनचैंटेड विद डेथ' (1994) आदि।

विगत 3 वर्षों के नोबेल साहित्य प्राप्तकर्ता

2014 : फ्रांसीसी उपन्यासकार ज्यां पैट्रिक मोदियानो (प्रमुख कृतियां- डोराब्रूडर, एल'हॉरिजन, अन पेडिग्री, एक्सीडेंट नाक्टर्न, मेमोरी लेन इत्यादि)।

2013 : कनाडा की समकालीन लघु कथा लेखिका एलिस मुनरो (प्रमुख कृतियां- डियर लाइफ, टू मच हैप्पीनेस, रन अवे, ओपन सीक्रेट्स, दि प्रोग्रेस ऑफ लव, दि बेगर मेड इत्यादि)।

2012 : चीन के उपन्यासकार एवं लघु कथा लेखक मो यान (प्रमुख कृतियां- रेड सॉरगम क्लैन, दि गार्लिक बलाड्स, थर्टीन स्टेप्स, रेड फॉरेस्ट, सैंडलवुड डेथ, दि वूमेन विद फ्लावर्स इत्यादि)।

2. शांति (Peace) : ट्यूनीशिया के चार संगठनों के समूह 'नेशनल डॉयलॉग क्वार्टेट' को ट्यूनीशिया से प्रारंभ 2011 की अरब क्रांति (जैस्मीन क्रांति) के बाद देश में बहुलतावादी लोकतंत्र की मजबूती और सभी धर्मों एवं समुदायों की समानता वाले समाज की स्थापना में उल्लेखनीय योगदान हेतु। इस क्वार्टेट समूह में शामिल 4 सिविल सोसायटी संगठन हैं- ट्यूनीशयन जनरल लेबर यूनियन; दि ट्यूनिशियन कंफेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स; दि ट्यूनीशियन ह्यूमन राइट्स लीग; तथा ट्यूनीशियन ऑर्डर ऑफ लॉयर्स।

विगत 3 वर्षों के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता

2014 : भारत के कैलाश सत्यार्थी ('बचपन बचाओ आंदोलन' के प्रणेता) तथा पाकिस्तान की बहुचर्चित बाल-अधिकार कार्यकत्री किशोरी मलाला युसुफजई; संयुक्त रूप से।

2013 : रासायनिक हथियारों के प्रतिषेध हेतु संगठन- ओपीसीडब्ल्यू (OPCW : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)।

2012 : यूरोपीय संघ (European Union; दो विश्व युद्धों के बाद यूरोप के एकीकरण के लिए)।

3. भौतिक विज्ञान (Physics) : जापान के तकाकी काजिता (Takaaki Kajita) और कनाडा के आर्थर बी. मैकडोनाल्ड (Arthur B. McDonald) को संयुक्त रूप से न्यूट्रिनो स्पंदनों (Neutrino Oscillations) या न्यूट्रिनो के प्रकारों में परिवर्तनों की खोज के लिए जो दिखाता है कि न्यूट्रिनो में द्रव्यमान होता है। वर्ष 2014 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जापान के इसामू आकासाकी (Isamu Akasaki) एवं हिरोशी अमानो (Hiroshi Amano) तथा पहले जापान और अब अमेरिका के नागरिक शूजी नाकामुरा (Shuji Nakamura) को संयुक्त रूप से नीली एलईडी (LED : Light Emitting Diode) लाइट के आविष्कार हेतु दिया गया था जिससे नई ऊर्जा-दक्ष सफेद प्रकाश वाले एलईडी का निर्माण संभव हो सका है।

4. रसायन विज्ञान (Chemistry) : स्वीडन के टॉमस लिंडाल (Tomas Lindahl), अमेरिका के पॉल मॉडरिच (Paul Modrich) और तुर्की-अमेरिकी नागरिक अजीज सैंकर (Aziz Sancar) को डीएनए की मरम्मत (DNA Repair) संबंधी अध्ययनों और जेनेटिक सूचनाओं की रक्षा करने वाले कोशिकाओं के 'टूलबॉक्स' की खोज करने के लिए। वर्ष 2014 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के एरिक बेत्जिग (Eric Betzig) एवं विलियम ई. मोएरनर (William E. Moerner) तथा रोमानियाई मूल के जर्मन नागरिक स्टीफन हेल (Stefan Hell) को संयुक्त रूप से नैनो माइक्रोस्कोपी के विकास हेतु प्रदान किया गया था।

5. चिकित्सा (Phisiology or Medicine) : आयरिश मूल के अमेरिकी नागरिक विलियम सी. कैम्पबेल (William C. Campbell) और जापान के सातोशी ओमुरा (Satoshi Omura) को गोलकृमि (Roundworm) परजीवियों से होने वाले संक्रामक रोगों (यथा- रिवर ब्लाइंडनेस, लिम्फैटिक फाइलेरिया आदि) के इलाज (दवा-एवेरमैक्टिन) की खोज करने तथा चीन की यूयू तु (Youyou Tu) को मलेरिया के इलाज हेतु नई औषधियों (आर्टेमिसाइनिन एवं डाइहाइड्रोआर्टेमिसाइनिन) की खोज के लिए संयुक्त रूप से। यूयू तु पुरस्कार राशि के आधे हिस्से की हकदार होंगी जबकि आधी पुरस्कार राशि शेष दोनों प्राप्तकर्ताओं में बराबर विभाजित होगी। वर्ष 2014 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के जॉन ओ' कीफ (John O' Keefe) तथा नार्वे के पति-पत्नी एडवर्ड आई. मोजर एवं मे-ब्रिट मोजर (Edvard I. Moser & May Britt Moser) को जीपीएस की तरह स्थान निर्धारण प्रणाली का संघटन करने वाली मस्तिष्क की कोशिकाओं की खोज के लिए प्रदान किया गया था।

6. अर्थशास्त्र (Economic Sciences) : स्कॉटिश (ब्रिटिश) मूल के ब्रिटिश-अमेरिकी नागरिक एंगस डिएटन (Angus Deaton) को उपभोग, निर्धनता और कल्याण के विश्लेषण हेतु। वर्ष 2014 में अर्थशास्त्र का यह नोबेल मेमोरियल स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार फ्रांस के ज्यां टिरोल (Jean Tirole) को उनके द्वारा वृहद एवं शक्तिशाली कंपनियों की बाजार शक्ति एवं विनियमन के विश्लेषण हेतु प्रदान किया गया था।

- **सखारोव पुरस्कार, 2015** : 29 अक्टूबर, 2015 को सऊदी अरब के ब्लॉगर एवं एक्टिविस्ट रैफ बदावी को मानवाधिकार और विचारों की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संघ ने वर्ष 2015 के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सखारोव पुरस्कार वर्ष 1988 से प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार, 2015** : 22 अक्टूबर, 2015 को जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार, 2015 से सम्मानित किया गया। यह चीन द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार के समकक्ष समझा जाता है। वर्ष 2014 में यह पुरस्कार फिदेल कास्त्रो को दिया गया था।
- **मार्टिन एन्नेल्स पुरस्कार** : 7 अक्टूबर, 2015 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को मानवाधिकारों के नोबेल कहे जाने वाले मार्टिन एन्नेल्स पुरस्कार से नवाजा गया।
- **हावर्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर** : 16 अक्टूबर, 2015 को हावर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2015 के प्रतिष्ठित 'हावर्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- **यूनेस्को आर्टिस्ट फॉर पीस अवॉर्ड** : 13 अक्टूबर, 2015 को यूनेस्को की महानिदेशक इरीना बोकोवा ने पेरिस में चीनी चित्रकार, मूर्तिकार और डिजाइनर 'हान मेइलिन' को 'यूनेस्को आर्टिस्ट फॉर पीस' अवॉर्ड से सम्मानित किया।

- **मैन बुकर पुरस्कार, 2015** : 13 अक्टूबर, 2015 को जमैका के लेखक मार्लोन जेम्स को उनके उपन्यास 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स' के लिए वर्ष 2015 का प्रतिष्ठित 'मैन बुकर पुरस्कार' प्रदान किया गया। वे जमैका के साहित्यिक इतिहास में बुकर जीतने वाले पहले लेखक हैं। उन्होंने यह पुरस्कार पाने के लिए ब्रिटिश-भारतीय लेखक संजीव सहोता की पुस्तक 'द ईयर ऑफ रनवेज' सहित चार अन्य लेखकों की किताबों को पीछे छोड़ा। इन चार अन्य लेखकों व उनकी किताबों के नाम क्रमशः टॉम मैककार्थी की 'सातिन आईलैंड', चिगोजी ओबिओमा की 'द फिशरमैन', हान्या याहिगिहारा की 'ए लिटिल लाइफ' तथा एवी टेलर की 'ए स्पूल ऑफ ब्लू थ्रेड' हैं। मार्लोन जेम्स को पुरस्कार के रूप में 50 हजार यूरो की राशि तथा एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
- **पॉपुलर च्वाइस अवॉर्ड** : 7 अक्टूबर, 2015 को नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कंपनी नुआल्गी को मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के क्लाइमेट कोलैब में पॉपुलर च्वाइस अवॉर्ड प्रदान किया गया। एमआईटी का क्लाइमेट कोलैब जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं चलाता है।
- **पेन पिंटर पुरस्कार** : 6 अक्टूबर, 2015 को सउदी अरब के ब्लॉगर एवं सामाजिक कार्यकर्ता रैफ बदावी तथा ब्रिटिश कवि, पत्रकार एवं आलोचक जेम्स फेंटन को संयुक्त रूप से लंदन में पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2009 से नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरॉल्ड पिंटर के सम्मान में दिया जाता है।
- **द राइट लाइवलीहुड अवॉर्ड्स-2015** : 1 अक्टूबर, 2015 को वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध 'द राइट लाइवलीहुड अवॉर्ड्स-2015' की घोषणा की गई। परमाणु हथियार रखने वाले नौ देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर करने वाले मार्शल द्वीप समूह के टॉनी डी ब्रूम, कनाडा की शीला वॉट क्लाउटियर, युगांडा की काशा जैकलीन नाबागेसेरा तथा इटली के गिनो स्ट्रादा एवं उनकी संस्था 'इमरजेंसी' को इस पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी।
- **मर्लिन अवॉर्ड** : सितंबर, 2015 के अंत में भारत की जेनिया बुमगारा को मर्लिन अवॉर्ड (जादू का ऑस्कर) से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड जादू के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जादूगर को 'अंतर्राष्ट्रीय जादूगर सोसायटी' द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड-2015** : 29 जुलाई, 2015 को रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड, 2015 के विजेताओं की सूची जारी की गई। विजेताओं के नाम क्रमशः कोम्माली चांतावोंग (लाओस), लिगाया फर्नांडो-अमिलबांग्सा (फिलीपींस), अंशु गुप्ता (भारत), क्याव थू (म्यांमार) तथा संजीव चतुर्वेदी (भारत) हैं। विजेताओं को 31 अगस्त, 2015 को फिलीपींस में पुरस्कृत किया गया। भारत के अंशु गुप्ता 'गूंज' नामक संस्था के निदेशक हैं तथा संजीव चतुर्वेदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) नई दिल्ली के डिप्टी सेक्रेटरी हैं।
- **कम्युनिटी इम्पैक्ट अवॉर्ड** : 22 सितंबर, 2015 को कैलिफोर्निया में आयोजित पांचवें गूगल साइंस फेयर में प्रतिष्ठित कम्युनिटी इम्पैक्ट अवॉर्ड ओडिशा के कोरापुट जिले की 13 वर्षीय छात्रा ललिता प्रसिदा श्रीपद श्रीसाई को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कम लागत वाले जैव-शोषक आधारित वॉटर प्यूरिफायर बनाने के लिए दिया गया।
- **वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार-2015** : सितंबर, 2015 में पेप्सिको की प्रमुख इंदिरा नूई और हिंदुस्तान टाइम्स समूह की प्रमुख शोभना भरतिया को अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार-2015 से सम्मानित किया गया।
- **फुकुओका एशियन कल्चर प्राइज** : 17 सितंबर, 2015 को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा को जापान के फुकुओका अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्र में अकादमिक श्रेणी में 'फुकुओका एशियर कल्चर प्राइज' प्रदान किया गया।
- **नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल** : सितंबर, 2015 में भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को वर्ष 2014 के प्रतिष्ठित नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल से ह्वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवाजा।
- **ऑनर्ड गेस्ट ऑफ टेक्सास अवॉर्ड** : 7 सितंबर, 2015 को भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को सिनेमा और कला जगत में उनके योगदान के लिए टेक्सास राज्य के गवर्नर की ओर से 'ऑनर्ड गेस्ट ऑफ टेक्सास अवॉर्ड' प्रदान किया गया। अनुपम खेर को 19 अगस्त, 2015 को 'लैंगिक समानता के अभियान ही फॉर शी' के लिए संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी बनाया गया।
- **नानसेन रिफ्यूजी अवॉर्ड-2015** : 15 सितंबर, 2015 को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने नानसेन रिफ्यूजी अवॉर्ड-2015 से अफगान शरणार्थी शिक्षिका अकीला असिफी को सम्मानित किया। असिफी पाकिस्तान में शरणार्थी लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। यूएनएचसीआर द्वारा यह पुरस्कार शरणार्थियों, आंतरिक स्तर पर विस्थापितों एवं राज्यविहीन लोगों के लिए असाधारण मानवीय कार्यों को करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसके तहत एक लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है।
- **चैंपियन ऑफ दि अर्थ-2015** : 7 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा दक्षिण अफ्रीका की ब्लैक मुंबा एंटी-पोचिंग यूनिट (एपीयू) को वर्ष 2015 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। 27 सितंबर, 2015 को एपीयू को यह पुरस्कार न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया। यह वर्ष 2004 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जा रहा यह पर्यावरण के क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार है। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को तथा नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, ब्राजील की कॉस्मेटिक फर्म नेचुरा को भी चैंपियन ऑफ द अर्थ-2015 पुरस्कार से नवाजा गया।
- **पीटर मैकलर अवॉर्ड-2015** : 22 अगस्त, 2015 को सीरिया की महिला पत्रकार जैना इरहैम को साहसी एवं नैतिक पत्रकारिता के लिए वर्ष 2015 का पीटर मैकलर अवॉर्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2008 में ग्लोबल मीडिया फोरम तथा एजेंसी फ्रांस प्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- **टेट ब्लैक प्राइज** : 18 अगस्त, 2015 को ब्रिटेन के सबसे पुराने साहित्यिक सम्मान 'टेट ब्लैक प्राइज' से बांग्लादेशी मूल के ब्रिटिश लेखक जिया हैदर रहमान को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक 'इन द लाइट ऑफ ह्वाइट वी नो' के लिए दिया गया।
- **सॉलिडेरिटी पुरस्कार-2015** : 5 अगस्त, 2015 को रूस के पूर्व राजनीतिज्ञ बोरिस नेम्तसोव की बेटी जहाना नेम्तसोव को पोलैंड के सॉलिडेरिटी पुरस्कार-2015 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार लोकतंत्र और मानव अधिकारों हेतु कार्य के लिए प्रदान किया गया।
- **प्रथम नेल्सन मंडेला रोहिल्हाला पुरस्कार** : 24 जुलाई, 2015 को नामीबिया की महिला नेत्र रोग विशेषज्ञ हेलेना न्ड्यूम तथा पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पायो को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'प्रथम नेल्सन मंडेला रोहिल्हाला पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में की थी।
- **अमेरिकन बुक अवॉर्ड-2015** : 20 जुलाई, 2015 को कोलंबस फाउंडेशन ने 36वें वार्षिक अमेरिकन बुक अवॉर्ड-2015 की घोषणा की।
- **विश्व खाद्य पुरस्कार, 2015** : 1 जुलाई, 2015 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने वर्ष 2015 का विश्व खाद्य पुरस्कार बांग्लादेश के सर फजले हसन आबिद को देने की घोषणा की। वर्ष 2014 का यह पुरस्कार भारत में जन्मे मेक्सिको के डॉ. संजय राजाराम को दिया गया था।
- **विश्व कृषि पुरस्कार** : सितंबर 2015 में ग्लोबल कंफेडरेशन फॉर हॉयर एजुकेशन एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस द्वारा नानजिंग में भारतीय मूल के अमेरिकी प्रो. आर. पॉल सिंह को जीसीएचईआरए विश्व कृषि पुरस्कार, 2015 प्रदान किया गया।
- **सीबीई सम्मान** : 22 जून, 2015 को टाटा लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक एस.ए. हसन को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी सेवा के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एंपायर (सीबीई) नियुक्त किया गया।
- **संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, 2015** : 26 जून, 2015 को पश्चिम बंगाल के 'नदिया' जिले को 'साबार शौच घर परियोजना' (सबके लिए शौचालय) के लिए 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, 2015' प्रदान किया गया।

- **ओरडेन डी ला डेमोक्रेसिया सिमॉन बोलिवर अवॉर्ड** : जून, 2015 के अंतिम सप्ताह में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को कोलंबिया के इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया।
- **वी.के. कृष्ण मेनन पुरस्कार 2015** : 21 जून, 2015 को ब्रिटेन में रहने वाले बेन्री जोसेफ मावेलिल को प्रतिष्ठित वी.के. कृष्ण मेनन पुरस्कार 2015 के लिए चयनित किया गया। जोसेफ मावेलिल मूलतः केरल के रहने वाले हैं।
- **द क्वींस यंग लीडर्स पुरस्कार** : 22 जून, 2015 को वर्ष 2015 के लिए 'द क्वींस यंग लीडर्स पुरस्कार' से कुल 60 लोगों को सम्मानित किया गया। उनमें तीन भारतीय क्रमशः अश्विनी अगादी, देविका मलिक तथा अक्षय जाधव भी शामिल थे।
- **बैलीज वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, 2015** : 3 जून, 2015 को ब्रिटेन की लेखिका अली स्मिथ को उनकी पुस्तक 'हाउ टू बी बोथ' के लिए 'बैलीज वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, 2015' का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **डैग हैमरशोल्ड पदक :** 29 मई, 2015 को दो भारतीय शांति सैनिकों—लांस नायक नंद राम और राजू यूसुफ को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया। इस पदक की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव के नाम पर वर्ष 2000 से की गई थी।
- **मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार :** 19 मई, 2015 को हंगरी के लेखक <u>लैस्कालो करास्जनाहोर्कोई</u> को वर्ष 2015 का 'मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार' वैश्विक स्तर पर इंग्लिश फिक्शन में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रति दो वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। वर्ष 2013 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लीडिया डेविस को दिया गया था।
- **इंटेल फाउंडेशन युवा वैज्ञानिक पुरस्कार :** 16 मई, 2015 को भारतीय मूल के 18 वर्षीय अमेरिकी छात्र करन जेराथ ने अमेरिका में इंटेल फाउंडेशन युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीता।
- **गवर्नर्स पुरस्कार :** 9 मई, 2015 को उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता सिवानादानें मंदजिने को अध्यापन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2015 के गवर्नर्स पुरस्कार से नवाजा गया। वे मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी हैं।
- **टॉप सिविलियन सुपरवाइजर ऑफ द ईयर :** 18 मई, 2015 को भारतीय अमेरिकी पुलिसकर्मी हरकीरत सिंह सैनी को अमेरिका के पुलिस अवॉर्ड 'टॉप सिविलियन सुपरवाइजर ऑफ द ईयर' से सम्मानित किया गया था।
- **एनकोर पुरस्कार :** 12 मई, 2015 को लेखक <u>नील मुखर्जी</u> को उनके उपन्यास 'द लाइव्स ऑफ अदर्स' के लिए ब्रिटेन के एनकोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **यूनेस्को प्रेस फ्रीडम पुरस्कार :** 3 मई, 2015 को यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम पुरस्कार (गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार-2015) सीरियाई पत्रकार एवं मानवाधिकार कार्यकर्त्ता माजेन डेरविश को प्रदान करने की घोषणा की।
- **पेन पुरस्कार :** 6 मई, 2015 को न्यूयार्क में फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो को पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पेन अमेरिकन सेंटर द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है।
- **सैयदियाना इमाम अल हसन इब्न अली शांति पुरस्कार :** 30 अप्रैल, 2015 को प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन को संयुक्त अरब अमीरात में उनके ज्ञान व शांति कायम रखने के प्रयासों के कारण 'सैयदियाना इमाम अलहसन इब्न अली शांति पुरस्कार' से नवाजा गया।
- **व्हिटले अवार्ड :** अप्रैल, 2015 के अंत में वन्य जीव संरक्षण पर कार्य करने वाले भारतीयों क्रमशः <u>डॉ. आनन्द कुमार</u> एवं <u>डॉ. प्रमोद पाटिल</u> को ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले 'व्हिटले अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- **नाइट ऑफ द लिजन ऑफ ऑनर :** 25 अप्रैल, 2015 को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को राजनीतिक व सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान 'नाइट ऑफ द लिजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया।
- **राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार :** अप्रैल, 2015 के अंत में उपन्यासकार सिद्धार्थ गिगू को उनके उपन्यास 'द अम्ब्रेला मेन' के लिए 2015 के एशिया क्षेत्र के <u>राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार</u> से सम्मानित किया गया।
- **हेंज पुरस्कार :** 26 अप्रैल, 2015 को मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में भारतीय मूल की वैज्ञानिक संगीता भाटिया को टिश्यू इंजीनियरिंग एवं रोग नियंत्रण के लिए 20वां हेंज पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **एशियन बैंकर अचीवमेंट अवॉर्ड 2015 :** 23 अप्रैल, 2015 को भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) को 'एशियन बैंकर अचीवमेंट अवॉर्ड-2015' दिया गया। भारतीय महिला बैंक की चेयरमैन व प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रह्मण्यम ने हांगकांग में आयोजित एशियाई बैंकिंग सम्मेलन में यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- **एशियन अवॉर्ड :** 19 अप्रैल, 2015 को लंदन में पांचवें वार्षिक एशियन अवॉर्ड से भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरूख खान और वन डायरेक्शन बैंड के पूर्व गायक जायन मलिक को सम्मानित किया गया।
- **हेवेजी मेडल पुरस्कार-2015 :** 12 अप्रैल, 2015 को साहा परमाणु भौतिकी संस्थान में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर सुशांत लाहिडी तथा मिसौरी विश्वविद्यालय के रेडियोलॉजिकल रिसर्च केंद्र में प्रोफेसर केट्टेश वी कट्टी को रेडियो एवं परमाणु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'हेवेजी मेडल अवॉर्ड-2015' से सम्मानित किया गया।
- **इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स प्राइज :** अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में ब्रिटेन में भारतीय मूल के 15 वर्षीय छात्र प्रताप सिंह को अल्बर्ट आइंसटाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के प्रभाव को सत्यापित करने वाले प्रयोग के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स प्राइज' से पुरस्कृत किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि पुरस्कार** : 21 जून, 2015 को भारतीय मूल की नर्स डॉ. सुभदा देवी को महिलाओं और शरणार्थियों की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सिंगापुर में प्रत्येक दो वर्ष पर दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 'अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- **एबेल प्राइज, 2015** : नार्वे की विज्ञान एवं साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के जॉन एफ. नैश जूनियर और मेसाच्युसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के लुइस निरेनबर्ग को 19 मई, 2015 को नार्वे की राजधानी ओस्लो (Oslo) में नार्वे के राजा हेराल्ड द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 'गणित का नोबेल' पुरस्कार कहा जाता है।
- **टॉयलर पुरस्कार, 2015** : भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिक माधव गाडगिल तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. जेन ल्युब्चेंको को पर्यावरण उपलब्धि के लिए वर्ष 2015 का टॉयलर पुरस्कार 4 अप्रैल, 2015 को लॉस एंजेलेस में संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान और नीति के क्षेत्र में दिया जाता है।
- **यू.एस. प्रेसीडेंशियल अवॉर्ड** : मार्च, 2015 के अंत में भारतीय मूल के अमेरिकी जीवविज्ञानी मूर्ति एस. कंभमपति को यू.एस. प्रेसीडेंशियल अवॉर्ड के लिए चुना गया।
- **मोहम्मद इब्राहिम पुरस्कार, 2014** : 2 मार्च, 2015 को नामीबिया के निवर्तमान राष्ट्रपति हिफिकेपुन्ये लुकास पोहाम्बा को वर्ष 2014 का मोहम्मद इब्राहिम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई।
- **अंतर्राष्ट्रीय पुश्किन सम्मान, 2012** : 24 मार्च, 2015 को हिंदी कवि और अनुवादक दिनकर कुमार का चयन रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुश्किन सम्मान, 2012 के लिए किया गया।

- **प्रित्जकर प्राइज, 2015** : 10 मार्च, 2015 को जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेई ओट्टो को वर्ष 2015 का प्रित्जकर प्राइज मरणोपरांत प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उनका 9 मार्च, 2015 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।
- **फोलियो पुरस्कार, 2015** : 23 मार्च, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार अखिल शर्मा को उनके उपन्यास 'फैमिली लाइफ' के लिए वर्ष 2015 का फोलियो पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **स्टॉकहोम वॉटर प्राइज** : 21 मार्च, 2015 को प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ('तरुण भारत संघ' के संस्थापक) को भारतीय गांवों में जल संरक्षण के प्रयासों और समुदायों को सशक्त करने के लिए वर्ष 2015 के प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वॉटर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई। 23 से 28 अगस्त, 2015 के मध्य स्टॉकहोम में आयोजित 'विश्व जल सप्ताह' के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार** : 3 मार्च, 2015 को वर्ष 2015 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार से दक्षिण एशिया की तीन महिलाओं को चयनित किया गया। उनके नाम क्रमशः नीलोफर रहमानी (अफगानिस्तान), नादिया शरमीन (बांग्लादेश) तथा तबस्सुम अदनान (पाकिस्तान) हैं।
- **एनॉलिटिक केमेस्ट्री जे. केलविन गिडिंग्स अवॉर्ड** : 20 फरवरी, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर पुर्णेंद्र दासगुप्ता को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2015 के 'अमेरिकन केमिकल सोसाइटी डिवीजन ऑफ एनॉलिटिक केमेस्ट्री जे. केलविन गिडिंग्स अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।
- **चार्ल्सटोन-ईएफजी जॉन मेनार्ड कीन्स पुरस्कार** : 9 फरवरी, 2015 को भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को चार्ल्सटोन-ईएफजी जॉन मेनार्ड कीन्स पुरस्कार से उनके कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
- **किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** : 1 मार्च, 2015 को सउदी अरब का प्रतिष्ठित किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गैरअरबी भारतीय इस्लामिक स्कॉलर डॉ. जाकिर नाइक सहित पांच लोगों को प्रदान किया गया।
- **डीएससी प्राइज, 2015** : भारतीय-अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को उनकी पुस्तक 'दि लोलैंड' के लिए 50 हजार डॉलर का दक्षिण एशिया का यह प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार 22 जनवरी, 2015 को प्रदत्त।
- **जिराफ हीरो पुरस्कार-2015** : 22 जनवरी, 2015 को भारतीय आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल को अमेरिका के स्वयंसेवी संगठन जिराफ हीरो प्रोजेक्ट ने 'जिराफ हीरो पुरस्कार-2015' से सम्मानित किया।
- **गोल्डेन पीकॉक अवॉर्ड** : 21 जनवरी, 2015 को कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) पर आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'गोल्डेन पीकॉक अवॉर्ड फॉर कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी' से नवाजा गया।
- **मार्टिन लूथर किंग जूनियर पुरस्कार** : 18 जनवरी, 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी फ्रेंक इस्लाम को मार्टिन लूथर किंग जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी।
- **अजेक्जेंडर स्वार्जकॉफ प्राइज, 2015** : 9 जनवरी, 2015 को कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रो. पोनिस्सेरिल सोमसुंदरन को प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन हेतु अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त।
- **प्रथम 'जस्टिस नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार'** : 5 दिसंबर, 2014 को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंटरनेशनल गुडविल सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित यह पुरस्कार न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी को प्रदान किया।
- **गवर्नर ऑफ द ईयर-2014** : 13 जनवरी, 2015 को ब्रिटिश पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन को गवर्नर ऑफ द ईयर-2014 पुरस्कार से सम्मानित किया।
- **इसरो को स्पेस पायनियर अवॉर्ड** : जनवरी, 2015 के दूसरे सप्ताह में अमेरिका की नेशनल स्पेस सोसायटी द्वारा प्रदत्त इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2015 का स्पेस पायनियर अवॉर्ड मार्स ऑर्बिटर कार्यक्रम के लिए इसरो ने जीता।
- **चीन का सर्वोच्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार** : जनवरी, 2015 में चीन के भौतिक विज्ञानी यु मिन को वर्ष 2014 का चीन का सर्वोच्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **ओलोफ पाल्मे मानवाधिकार पुरस्कार** : दिसंबर, 2014 में स्वीडन ने चीनी लोकतंत्र समर्थक नेता जु योयुयु को ओलोफ पाल्मे मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार स्वीडिश श्रम आंदोलन द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **टर्नर पुरस्कार** : 1 दिसंबर, 2014 को आयरलैंड के फिल्म कलाकार डंकन कैम्पबेल ने 25,000 पाउंड की इनामी राशि वाला टर्नर पुरस्कार 'काल्ड इट फॉर अदर्स' नामक वीडियो के लिए प्राप्त किया।
- **शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक पुरस्कार** : 24 नवंबर, 2014 को पाकिस्तानी लेखक बिलाल तनवीर की पुस्तक 'द स्केटर हियर इज टू ग्रेट' को वर्ष 2014 के 'शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक पुरस्कार' के लिए चुना गया।
- **फील्ड्स मेडल 2014 :** 13 अगस्त, 2014 को ईरानी मूल की महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जाखानी, अर्तुर अवीला, भारतीय मूल के मंजुल भार्गव तथा मार्टिन हेरर को वर्ष 2014 का फील्ड्स मेडल प्रदान किया गया। प्रत्येक 4 वर्ष पर प्रदत्त इस पुरस्कार को 'गणित का नोबेल पुरस्कार' भी कहा जाता है।

■ फिल्म पुरस्कार

- **छठें जागरण फिल्म पुरस्कार** : 5 अक्टूबर, 2015 को मुंबई में छठां जागरण फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर अभिनेता शशि कपूर को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया।
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक : सुजीत सरकार (फिल्म-पीकू)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म : बंगाली फिल्म चोटोदेर चोबी (निर्देशक- कौशिक गांगुली)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : दुलाल सरकार (चोटोदेर चोबी)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री : भूमि पेडनेकर (दम लगा के हइशा)
  - ➔ भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए : पंढारी जुकर (वयोवृद्ध मेकअप कलाकार)
- **67वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स** : 20 सितंबर, 2015 को लॉस एंजेलेस में 67वें प्राइम टाइम एमी अवॉर्ड्स में प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी शृंखला 'गेम ऑफ थ्रोंस' ने कुल 12 पुरस्कार जीते।
- **40वां टोरंटो फिल्म महोत्सव** : 20 सितंबर, 2015 को कनाडा के 40वें टोरंटो फिल्म महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान फिल्म 'रूम' (निर्देशक-लेनी अब्राह्मसन) को पीपुल्स च्वाइस अवॉर्ड प्रदान किया गया। भारतीय निर्देशक पाल नलिन की फिल्म 'एंग्री इंडियन गॉडेस' को पीपुल्स च्वाइस अवॉर्ड श्रेणी में उपविजेता का पुरस्कार मिला।
- **सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2015** : सितंबर, 2015, चीन में आयोजित सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2015 में भारतीय अभिनेत्री स्वरा भास्कर को अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म 'निल बटे सन्नाटा' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। हांगकांग के एंडी लाउ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।
- **मेलबर्न फिल्म महोत्सव-2015** : 15 अगस्त, 2015 को मेलबर्न में आयोजित 'इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न' (IFFM-2015) में पुरस्कार वितरित किए गए—
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ फिल्म : पीकू
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक : सुजीत सरकार (पीकू)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री : भूमि पडनेकर (दम लगा के हइशा)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : इरफान खान (पीकू)
  - ➔ विश्व सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार : अनिल कपूर

- **मैड्रिड फिल्म फेस्टिवल** : जुलाई, 2015 में भारतीय फिल्मकार बिनॉय बहल के द्वारा बनाई गई डाक्यूमेंट्री 'इंडियन रूट्स ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म' के लिए उन्हें मेड्रिड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म 'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' ने विदेशी भाषा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता।
- **इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवॉर्ड (आइफा), 2015** : 5 जून, 2015 को मलेशिया के कुआलालम्पुर में प्रदत्त—
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ फिल्म : क्वीन
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक : राजकुमार हिरानी (पीके)
  - ➔ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि : सुभाष घई
- **68वें कॉन फिल्म पुरस्कार** : 13 से 24 मई, 2015 के मध्य कॉन फिल्म महोत्सव का 68वां संस्करण फ्रांस के कॉन शहर में आयोजित हुआ। इसमें जैक्स आदियार्द द्वारा निर्देशित फ्रेंच फिल्म 'धीपन' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 'पाम डि' ओर' पुरस्कार दिया गया।
- **वाशिंगटन डीसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल** : 16 से 26 अप्रैल, 2015 को अमेरिका में आयोजित 29वें वाशिंगटन डीसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म अभिनेत्री कल्कि कोचलिन की फिल्म ' मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह** : 19 अप्रैल, 2015 को स्वीडन में आयोजित 'स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह' में भारतीय फिल्म 'मैरीकॉम' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया।
- **62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार** : 3 मई, 2015 को 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रदत्त—
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म : कोर्ट (मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म : मैरीकॉम
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार : आशा जोआर माझे (बांग्ला)
  - ➔ नवोदित निर्देशक के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार : आदित्य विक्रम सेनगुप्ता
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक : श्रीजित मुखर्जी (बंगाली फिल्म-चतुष्कोण)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : विजय (कन्नड़ फिल्म-नानू अवनल्ला अवालु)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री : कंगना रानावत (हिंदी फिल्म- क्वीन)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक : सुखविंदर सिंह (गीत-बिस्मिल; फिल्म-हैदर)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक : विशाल भारद्वाज (फिल्म-हैदर के गानों के लिए)
  - ➔ सामाजिक मुद्दों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म : कांट टेक दिस शिट एनीमोर
- **ग्रैमी पुरस्कार** : 9 फरवरी, 2015 को लॉस एंजेलेस में वितरित।
  - ➔ बेस्ट न्यू एज एलबम अवॉर्ड : भारत के रिकी केज ('विंड्स ऑफ संसार' के लिए); वे इस श्रेणी में ग्रैमी अवॉर्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हैं।
  - ➔ बेस्ट चिल्ड्रेन एलबम : भारत की नीला वासवानी ('आई एम मलाला : हाउ वन गर्ल स्टुडफॉर एजुकेशन एंड चेंज्ड द वर्ल्ड' के लिए)
  - ➔ सांग ऑफ द ईयर : सैम स्मिथ (स्टे विद मी)
  - ➔ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर : सैम स्मिथ (स्टे विद मी)
- **ऑस्कर पुरस्कार, 2015** : 23 फरवरी, 2015 को अमेरिका के लॉस एंजेलेस में घोषित किए गए।
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ फिल्म : बर्डमैन
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : एडी रेड मेन (द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री : जूलियाना मूर (स्टिल एलिस)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक : एलीजेंड्रो गोंसालेस (बर्डमैन)
- **65वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार** : 5 से 15 फरवरी, 2015 के मध्य बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित।
  - — बेस्ट फीचर फिल्म के लिए स्पेशल मेंशन पुरस्कार : 'धनक' (निर्देशक-नागेश कुकुनूर)
  - — ऑनररी गोल्डन बियर फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट : विम वेंडर्स (जर्मन फिल्म निर्देशक)
  - — गोल्डेन बियर फॉर बेस्ट फिल्म : 'टैक्सी' (ईरानी निर्देशक जफर पनाही की फिल्म)
- **यश चोपड़ा मेमोरियल अवॉर्ड** : 25 दिसंबर, 2014 को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीएच विद्यासागर राव ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा मेमोरियल अवॉर्ड प्रदान किया।
- **सिंगापुर सिल्वर स्क्रीन अवॉर्ड्स** : 14 दिसंबर, 2014 को भारतीय फिल्म निर्माता चैतन्य तम्हाने ने अपनी फिल्म 'कोर्ट' के लिए 'सिंगापुर सिल्वर स्क्रीन अवॉर्ड्स' में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया।

सौंदर्य प्रतियोगिताएं

- **मिस इंडिया-कनाडा, 2015** : 19 अगस्त, 2015 को मनस्वी नोएल ने मिस इंडिया-कनाडा, 2015 का खिताब जीता। वर्ष 2014 का मिस इंडिया-कनाडा खिताब अन्नू गेदू ने जीता था।
- **मिस यूनिवर्स, 2014** : 25 जनवरी, 2015 को कोलंबिया की पाउलिना वेगा को यह खिताब प्राप्त हुआ।

◆◆◆

खेल-कूद

प्रमुख आयोजन

ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट

यूएस ओपन, 2015

- 31 अगस्त, 2015 से 13 सितंबर, 2015 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)	रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड)
महिला एकल	फ्लाविया पेनेट्टा (इटली)	रॉबर्टा विंसी (इटली)
पुरुष युगल	पियरे ह्यूज हर्बर्ट एवं माहुत (दोनों फ्रांस)	जेमी मरे (यूके) एवं जॉन पियर्स (ऑस्ट्रेलिया)
महिला युगल	सानिया मिर्जा (भारत) एवं मार्टिना हिंगिस (स्विट्ज़रलैंड)	कैसी डेलाकुआ (ऑस्ट्रेलिया) एवं यारोस्लावा श्वेदोवा (कजाख्स्तान)
मिश्रित युगल	मार्टिना हिंगिस (स्विट्ज़रलैंड) एवं लिएंडर पेस (भारत)	बेथनी माटेक सैंड्स एवं सैम क्यूरे (दोनों अमेरिका)

विम्बलडन :

- 29 जून से 12 जुलाई, 2015 के मध्य लंदन में संपन्न।
- 12 जुलाई, 2015 को विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने फाइनल में दूसरी सीड स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर को 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 से शिकस्त दी।
- 11 जुलाई, 2015 को महिला एकल के फाइनल में टॉप सीड अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने स्पेन की 20वीं सीड गारबाइन मुगुरेजा को आसानी से 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। सेरेना का यह छठां विम्बलडन खिताब था।
- सेरेना 33 वर्ष और 289 दिन की आयु में यह खिताब जीत कर मार्टिना नवरातिलोवा को पीछे छोड़ते हुए ओपन युग में महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला खिलाड़ी बनीं।
- 11 जुलाई, 2015 को भारत की सानिया मिर्जा एवं स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने रूसी जोड़ी ई. मकारोवा एवं ई. वेस्नीना को 5-7, 7-6 व 7-5 के अंतर से हराकर महिला युगल का खिताब जीता।
- 12 जुलाई, 2015 को भारत के लिएंडर पेस व स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर पेया व हंगरी की टिमिया बाबोस को 6-1, 6-1 से हराकर विम्बलडन का मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया।
- युवा भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने विम्बलडन में वियतनाम के हुआंग ली के साथ मिलकर अमेरिका की रीली ओपेल्का और जापान के अकीरा संतिलान की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराकर लड़कों का युगल खिताब जीता।
- विम्बलडन, 2015 के पुरुष युगल का खिताब नीदरलैंड्स के ज्यॉं जूलियन रोजर और रोमानिया के होरिया तेकाऊ की जोड़ी ने ब्रिटेन के जैमी मरे व ऑस्ट्रेलिया के जॉन पीयर्स की जोड़ी को 7-6, 6-4, 6-4 से हराकर जीता।

फ्रेंच ओपन : 7 जून, 2015 को पेरिस में संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	स्टेनिसलास वावरिका (स्विट्जरलैंड)	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)
महिला एकल	सेरेना विलियम्स (अमेरिका)	लूसी सफारोवा (चेक गणराज्य)
पुरुष युगल	इवान डोडिज (क्रोएशिया) एवं मार्सिलो मेलो (ब्राजील)	माइक एवं बॉब ब्रॉयन (अमेरिकी जोड़ी)
महिला युगल	बेथानी माटेक (अमेरिका) एवं लूसी सफारोवा (चेक गणराज्य)	कैसी डेलाकुआ (ऑस्ट्रेलिया) एवं यरोस्लावा श्वेदा (कजाख्स्तान)
मिश्रित युगल	बेथानी माटेक एवं माइक ब्रायन (दोनों अमेरिका)	लूसी हरादेका (चेक) एवं मार्सिन माटकोवस्की (पोलैंड)

ऑस्ट्रेलियन ओपन : 1 फरवरी, 2015 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में संपन्न।

स्पर्द्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)	एंडी मरे (ब्रिटेन)
महिला एकल	सेरेना विलियम्स (अमेरिका)	मारिया शारापोवा (रूस)
पुरुष युगल	सिमोने बोलेली एवं फाबियो फोगिनी (दोनों इटली)	पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट एवं निकोलस महुट (दोनों फ्रांस)
महिला युगल	बैथानी माटेक सैंड्स (अमेरिका) एवं लूसी सफारोवा (चेक गणराज्य)	झेंग चिये (चीन) एवं चान युंग जान (ताइवान)
मिश्रित युगल	लिएंडर पेस (भारत) एवं मार्टिना हिंगिस (स्विट्जरलैंड)	डेनियल नेस्टर (कनाडा) एवं क्रिस्टीना म्लादेनोविच (फ्रांस)

- **राष्ट्रमंडल युवा खेल :** 5 से 11 सितंबर, 2015 के मध्य पॉलीनेशियन देश समोआ की राजधानी अपिया में पांचवें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन हुआ। इसमें 9 खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में 63 देशों के एक हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ था। पदक तालिका में शीर्ष पांच देश इस प्रकार हैं—

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1. ऑस्ट्रेलिया	25	19	19	63
2. द. अफ्रीका	13	7	15	35
3. इंग्लैंड	12	16	16	44
4. मलेशिया	11	3	3	17
5. भारत	9	5	6	20

- **14वां स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स, 2015 :** 25 जुलाई, 2015 से 2 अगस्त, 2015 के मध्य 14वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स-2015 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजेलेस में हुआ। भारत ने इन खेलों में 47 स्वर्ण, 54 रजत तथा 72 कांस्य पदकों सहित कुल 173 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा तथा चीन दूसरे स्थान पर रहा।
- **विश्व यूनिवर्सिटी खेल :** 3 जुलाई, 2015 के मध्य दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में 28वें विश्व यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन किया गया। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 5 पदक जीतकर पदक तालिका में 35वां स्थान प्राप्त किया। भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले इंदरजीत सिंह (शॉटपुट) विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले

एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने। इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया 47 स्वर्ण, 32 रजत एवं 29 कांस्य पदकों सहित कुल 108 पदक पाकर शीर्ष पर रहा। वर्ष 2015 के विश्व यूनिवर्सिटी खेलों (समर यूनिवर्सियाड) का शुभंकर 'नुरिबी' था। वर्ष 2017 के 29वें विश्व यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजक ताइवान के ताइपे में होना प्रस्तावित है।

वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप

- 5 जुलाई, 2015 को अमेरिका ने जापान को 5-2 से हराकर कनाडा के वैंकूवर में खेले गये 'फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप' का खिताब जीत लिया।
- इस प्रतियोगिता में गोल्डेन बॉल अवॉर्ड-कार्ली लॉयड (अमेरिका), अमान डाइन हेनरी (फ्रांस) तथा अया मियामा (जापान) को दिया गया।
- प्रतियोगिता का गोल्डेन बूट अवॉर्ड- सीलिया सासिक (जर्मनी), कार्ली लॉयड (अमेरिका) तथा अंजा मिटैग (जर्मनी) को दिया गया।

कोपा अमेरिका फुटबाल टूर्नामेंट

- 4 जुलाई, 2015 को चिली के सैंटियागो में खेले गये फाइनल मुकाबले में चिली ने अर्जेंटीना को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबाल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।
- चिली ने यह प्रतिष्ठित फुटबाल टूर्नामेंट पहली बार जीता है। इसके अतिरिक्त चिली द्वारा फुटबाल में जीती गई यह पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी है।

एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2015

- 3-7 जून, 2015 के मध्य चीन के वुहान में 21वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ।
- भारत ने 4 स्वर्ण, 5 रजत एवं 4 कांस्य पदकों सहित कुल 13 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम हैं—ललिता बब्बर (महिलाओं की 3000 मी. स्टीपलचेज), टिंटू लूका (महिलाओं की 800 मी. दौड़), विकास गौड़ा (डिस्कस थ्रो) एवं इंदरजीत सिंह (शॉटपुट)।
- चीन ने 15 स्वर्ण, 13 रजत एवं 13 कांस्य पदकों के साथ प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कतर 7 स्वर्ण, 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

आईपीएल-8 का चैंपियन मुंबई इंडियंस

- 24 मई, 2015 को कोलकाता के ईडेन गार्डेन में खेले गये फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दो बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स को 41 रन से हराकर आईपीएल-8 का खिताब जीता।
    - ➔ फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने निर्धारित बीस ओवरों में 5 विकेट पर 202 रनों का स्कोर बनाया, चेन्नई लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवरों में आठ विकेट पर 161 रन ही बना पाई।
    - ➔ इसके पहले वर्ष 2013 में भी मुंबई इंडियंस ने कोलकाता के ईडेन गार्डेन पर चेन्नई को हराकर खिताब जीता था।
    - ➔ आईपीएल-8 में तीसरा स्थान रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू को प्राप्त हुआ।
    - ➔ आईपीएल-8 में ऑरेंज कैप (सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज) का खिताब सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज डेविड वार्नर को मिला जिन्होंने 562 रन बनाए थे।
    - ➔ आईपीएल-8 में पर्पल कैप (सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज) चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाज ड्वेन ब्रावो को प्राप्त हुई जिन्होंने कुल 26 विकेट प्राप्त किये।
    - ➔ आईपीएल-8 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (50 रन) बने।
    - ➔ आईपीएल-8 का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बनाया (133 रन नॉट आउट)।
    - ➔ आईपीएल-8 के 'उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार' श्रेयस अय्यर को तथा 'कैच ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार ड्वेन ब्रावो को दिया गया।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप, 2015

- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित की जाने वाली पुरुषों की 'एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप' प्रतियोगिता का 11वां संस्करण 14 फरवरी से 29 मार्च, 2015 के मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया।
- 29 मार्च, 2015 को खेले गये विश्व कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर न्यूजीलैंड को 101 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर पांचवीं बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। विश्व कप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए 45 ओवरों में 183 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी।
- फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेम्स फॉकनर ने 36 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए जिन्हें 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विश्व कप, 2015 का 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड दिया गया।
- इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज—मार्टिन गुप्टिल (547 रन, न्यूजीलैंड) एवं कुमार संगकारा (541 रन, श्रीलंका)।
- विश्व कप, 2015 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज—मिशेल स्टार्क (22 विकेट, ऑस्ट्रेलिया), ट्रेंट बोल्ट (22 विकेट, न्यूजीलैंड)।
- ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप में एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम बनी। उसने 4 मार्च, 2015 को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 6 विकेट पर 417 रन बनाए। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नबाद 237 रन बनाकर विश्व कप के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया। विश्व कप के इतिहास का पहला दोहरा शतक (215 रन) वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 24 फरवरी, 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था।
- विश्व कप, 2015 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (6 पारी में 26 छक्के) के नाम रहा।

35वें राष्ट्रीय खेल

- 35वें राष्ट्रीय खेल 31 जनवरी, 2015 से 14 फरवरी, 2015 के मध्य केरल में आयोजित किए गए। 35वें राष्ट्रीय खेलों के सद्भावना दूत सचिन तेंदुलकर थे तथा इन खेलों का शुभंकर केरल का राज्य पक्षी 'ग्रेट हार्नबिल' था जिसे 'अम्मू' नाम दिया गया था।
- सेना (सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड) ने पदक तालिका में लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त कर 'राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी' जीती।
- उल्लेखनीय है कि 36वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन रांची, झारखंड में हुआ था।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण के साथ सर्वाधिक पदक (6 स्वर्ण एवं 2 रजत के साथ कुल 8 पदक) केरल के तैराक साजन प्रकाश ने प्राप्त किए।
- महाराष्ट्र की तैराक आकांक्षा वोरा और अंडमान एवं निकोबार तथा मध्य प्रदेश की कैनोइंग खिलाड़ियों क्रमशः राजिना कीरो एवं इनाओचा देवी - ये तीनों खिलाड़ी पदक तालिका में 5 स्वर्ण एवं एक रजत (कुल 6 पदक) प्राप्त कर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान तथा महिलाओं में प्रथम स्थान पर रहीं।
- उत्तर प्रदेश का 7 स्वर्ण, 31 रजत एवं 30 कांस्य (कुल 68 पदक) के साथ पदक तालिका में 14वां स्थान रहा।
- इन खेलों में 100 मीटर दौड़ के पुरुष वर्ग के विजेता हरियाणा के धरमबीर रहे जबकि महिला वर्ग की विजेता ओडिशा की दुती चंद रहीं।
- 35वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक की 12 वर्षीया स्कूली छात्रा सलोनी दलाल सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनीं, जिन्होंने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी स्पर्द्धा में कांस्य पदक जीता।

टेनिस

- **डब्ल्यूटीए फाइनल्स :** 1 नवंबर, 2015 को सिंगापुर में संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
महिला एकल	एग्निस्का रद्वांस्का (पोलैंड)	पेत्रा क्वितोवा (चेक गणराज्य)
महिला युगल	मार्टिना हिंगिस (स्विट्जरलैंड) एवं सानिया मिर्जा (भारत)	गार्बिन मुगुरुजा एवं कार्ला सुआरेज (दोनों स्पेन)

नोट : उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी सानिया मिर्जा ने जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक के साथ यह खिताब अपने नाम किया था।

- **एयर एशिया ओपन :** 25 अक्टूबर, 2015 को साकेत माइनेनी और सरम सिंह की भारतीय जोड़ी ने 50 हजार डॉलर की इनामी राशि वाले एयर एशिया ओपन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब फाइनल में अमेरिका के जॉन पॉल फ्रुतेरो और भारत के विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी को हराकर जीता।

- **विएतनाम ओपन :** 18 अक्टूबर, 2015 को विएतनाम में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	साकेत माइनेनी (भारत)	जॉर्डन थॉम्पसन (ऑस्ट्रेलिया)
पुरुष युगल	ट्रिस्टन लेमसिने (फ्रांस) एवं निल्स लैंगर (जर्मनी)	साकेत माइनेनी एवं सनम सिंह (दोनों भारत)

- **चाइना ओपन-2015 :** 11 अक्टूबर, 2015 को चीन के बीजिंग में संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)	राफेल नडाल (स्पेन)
महिला एकल	गार्बिन मुगुरूजा (स्पेन)	टीमिया बासिंस्की (स्विट्जरलैंड)
महिला युगल	सानिया मिर्जा (भारत) एवं मार्टिना हिंगिस (स्विट्जरलैंड)	हाओ चिंग चान एवं यूंग जान चान (दोनों चीनी ताइपे)

- **वुहान ओपन, 2015 :** 3 अक्टूबर, 2015 को चीन के वुहान में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
महिला एकल	वीनस विलियम्स (अमेरिका)	गार्बिन मुगुरेजा (स्पेन)
महिला युगल	सानिया मिर्जा (भारत) एवं मार्टिना हिंगिस (स्विट्जरलैंड)	इरिना कैमिलिया बेगू एवं मोनिका निकूलेस्को (दोनों रोमानिया)

- **ग्वांगझू ओपन, 2015 :** 26 सितंबर, 2015 को चीन के ग्वांगझू में संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
महिला एकल	येलेना यानकोविक (सर्बिया)	डेनिशा एलिर्टोवा (चेक गणराज्य)
महिला युगल	सानिया मिर्जा (भारत) एवं मार्टिना हिंगिस (स्विट्जरलैंड)	शिलिन शू एवं शियाओडी यू (दोनों चीन)

- **शंघाई चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, 2015 :** 7 सितंबर से 13 सितंबर, 2015 के मध्य चीन के शंघाई में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	युकी भांबरी (भारत)	डी वु (चीन)
पुरुष युगल	डी वु (चीन) एवं चु-हुआनशी (चीनी ताइपे)	थॉमस फैबियानो एवं लुका वन्नी (दोनों इटली)

- **विंस्टन सलेम ओपन, 2015 :** 23 अगस्त से 30 अगस्त, 2015 के मध्य अमेरिका के विंस्टन सलेम में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	केविन एंडरसर (द. अफ्रीका)	पियरे ह्यूज हरबर्ट (फ्रांस)
पुरुष युगल	डोमिनिक इंग्लोट (ब्रिटेन) एवं रॉबर्ट लिंड्सटेड्ट (स्वीडन)	एरिक ब्युटोरैक एवं स्कॉट लिपस्की (दोनों अमेरिका)

- **कनेक्टीकट ओपन, 2015 :** 23 अगस्त से 29 अगस्त, 2015 के मध्य अमेरिका के न्यू हैवेन में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
महिला एकल	पेत्रा किवतोवा (चेक गणराज्य)	लूसी साफारोवा (चेक गणराज्य)
महिला युगल	जूलिया गॉर्गेस (जर्मनी) एवं लूसी हरादेका (चेक गणराज्य)	चुआंग चिया-जुंग (चीनी ताइपे) एवं लियांग चेन (चीन)

- **वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, 2015 :** (सिनसिनाटी ओपन) 15 अगस्त 2015 से 23 अगस्त, 2015 के मध्य अमेरिका के ओहायो में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)
महिला एकल	सेरेना विलियम्स (अमेरिका)	सिमोना हालेप (रोमानिया)

- **रोजर्स कप 2015 :** 16 अगस्त, 2015 को कनाडा में संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	एंडी मरे (ब्रिटेन)	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)
महिला एकल	बेलिंडा बेंसिस (स्विट्जरलैंड)	सिमोना हालेप (रोमानिया)

- **सिटी ओपन, 2015 :** 9 अगस्त, 2015 को अमेरिका के वाशिंगटन में संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	केई निशिकोरी (जापान)	जॉन इश्नर (अमेरिका)
महिला एकल	स्लोएन स्टीफेंस (अमेरिका)	अनास्तासिया पॉवल्युचेंकोवा (रूस)

- **बी.बी. एंड टी. अटलांटा ओपन, 2015 :** 28 जुलाई, 2015 से 2

अगस्त, 2015 के मध्य अमेरिका के अटलांटा में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	जॉन इश्नर (अमेरिका)	मार्कोस बाघदातिस (साइप्रस)
पुरुष युगल	बाब एवं माइक ब्रायन (दोनों अमेरिका)	कोलिन फ्लेमिंग (ब्रिटेन) एवं गाइल्स मुलर (लक्जमबर्ग)

- **हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप** : 11 से 19 जुलाई, 2015 के मध्य अमेरिका के न्यू पोर्ट में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	राजीव राम (अमेरिका)	इवो कार्लोविक (क्रोएशिया)
पुरुष युगल	जोनाथन मरे (ब्रिटेन) एवं ऐसाम उल-हक-कुरैशी (पाकिस्तान)	निकोलस मोनरोई (अमेरिका) एवं मैट पेविक (क्रोएशिया)

- **गैरी वेबर ओपन, 2015** : 13 से 21 जून, 2015 के मध्य जर्मनी के हाले में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)	आंद्रियास सेप्पी (इटली)
पुरुष युगल	रावेन क्लासेन (द. अफ्रीका) एवं राजीव राम (अमेरिका)	रोहन बोपन्ना (भारत) एवं फ्लोरीन मर्गिया (रोमानिया)

- **स्वीडिश ओपन** : 13 से 26 जुलाई, 2015 तक स्वीडन के बैसटाड में स्वीडिश ओपन 2015 का आयोजन किया गया।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	बेनोइट पैरे (फ्रांस)	टॉमी रोब्रेडो (स्पेन)
महिला एकल	जोहान्ना लारसन (स्वीडन)	मोना बर्थेल (जर्मनी)

- **इंटरनेशनल जर्मन ओपन, 2015** : 27 जुलाई, 2015 से 2 अगस्त, 2015 के मध्य जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	रॉफेल नडाल (स्पेन)	फैबियो फोगनीनी (इटली)

- **एगॉन ओपन** : 21 जून, 2015 को लंदन के क्वींस क्लब में संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	एंडी मरे (ब्रिटेन)	केविन एंडरसन (द. अफ्रीका)
पुरुष युगल	पियरे ह्यूग्स हर्बट (फ्रांस) एवं निकोलस माहुत (फ्रांस)	मेतोवस्की (पोलैंड) एवं नेनाद जिमोनिक (सर्बिया)

- **स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट** : 14 जून, 2015 को भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी ने स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब एलेक्जेंडर एवं सोर्स की जोड़ी को हराकर जीता।
- **यूनियन स्पोर्टिव इंटरनेशनल चैंपियनशिप** : 31 मई से 6 जून, 2015 तक जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित 20वीं यूनियन स्पोर्टिव इंटरनेशनल चैंपियनशिप-टेनिस स्पर्धा में भारतीय रेलवे ने फ्रांस को 3-1 से हराकर प्रतियोगिता जीती। यूनियन स्पोर्टिव इंटरनेशनल चैंपियनशिप (यूएसआईसी) एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे खेल एसोसिएशन है।
- **रोम मास्टर्स टूर्नामेंट :** 17 मई, 2015 को इटली के रोम में संपन्न

प्रतियोगिता	विजेता	उपविजेता
महिला एकल	मारिया शारापोवा (रूस)	कार्ला सुओरेज (स्पेन)
महिला युगल	टिमीया बाबोस (हंगरी) एवं मार्टिना हिंगिस (स्विट्जरलैंड)	सानिया मिर्जा (भारत) एवं क्रिस्टीना म्लादेनोविक (फ्रांस)
पुरुष एकल	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)	रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)

- **मैड्रिड ओपन मास्टर्स टूर्नामेंट-2015 :** 10 मई, 2015 को भारत के रोहन बोपन्ना व रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी ने सर्बियाई और पोलिश जोड़ी नेनाद जिमोनजिक व मार्टिन मातकोवस्की को 6-2, 6-7, 11-9 से हराकर मैड्रिड ओपन मास्टर्स टूर्नामेंट 2015 के पुरुष युगल का खिताब जीता।
- **इस्ताम्बुल ओपन :** 3 मई, 2015 को स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने उरुग्वे के पाब्लो चुवास को 6-3, 6-4 से हराकर इस्ताम्बुल ओपन का खिताब जीत लिया।
- **एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप :** 18 अप्रैल, 2015 को भारत की वाई. प्रांजला ने चीन की झेंग वुशुअंग को हराकर एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया।
- **मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब :** 20 अप्रैल, 2015 को सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने चेक गणराज्य के टामस बर्डिच को हराकर दूसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस खिताब जीता।
- **फैमिली सर्किल कप, 2015** : 6 से 12 अप्रैल, 2015 के मध्य अमेरिका के चार्ल्सटन में हुए फैमिली सर्किल कप-2015 (चार्ल्सटन कप-2015) के महिला एकल का खिताब जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने अमेरिका की मैडिसन कीज को हराकर जीता। महिला युगल का खिताब भारत की सानिया मिर्जा एवं स्विट्ज़रलैंड की मार्टिना हिंगिस ने ऑस्ट्रेलिया की सेसी डेलाकुआ एवं क्रोएशिया की दारिजा जुराक की जोड़ी को 6-0, 6-4 से हराकर जीता।
- **मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट** : अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में आयोजित।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	नोवाक जोकोविक (सर्बिया)	एंडी मरे (ब्रिटेन)
महिला एकल	सेरेना विलियम्स (अमेरिका)	कार्ला सुआरेजनावारो (स्पेन)
महिला युगल	सानिया मिर्जा (भारत) एवं मार्टिन हिंगिस (स्विट्ज़रलैंड)	एलिना वेस्नीना एवं एकातेरिना माकारोवा (रूसी जोड़ी)

- **इंडियन वेल्स खिताब** : 23 मार्च, 2015 को विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने रोजर फेडरर को 6-3, 6-7, 6-2 से हराकर इंडियन वेल्स का खिताब कायम रखा। महिला एकल में रोमानिया की सिमोना हालेप ने सर्बिया की पूर्व चैंपियन येलेना यांकोविच को 2-6, 7-5, 6-4 से हराकर इंडियन वेल्स डब्ल्यूटीए टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता।
- **बीएनपी पारिबास ओपन** : 22 मार्च, 2015 को भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा एवं स्विट्जरलैंड मार्टिना हिंगिस ने बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में एकातेरिना माकारोवा और एलेना वेस्नीना की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की।
- **अर्जेंटीना ओपन-2015** : 1 मार्च, 2015 को स्पेन के राफेल नडाल ने जुआन मोनाको (अर्जेंटीना) को 6-4, 6-1 से हराकर अर्जेंटीना ओपन टेनिस प्रतियोगिता-2015 का खिताब जीत लिया।
- **दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट** : 22 फरवरी, 2015 को सोमदेव देववर्मन ने युकी भांबरी को 3-6, 6-4, 6-0 से हराकर दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब लगातार दूसरी बार जीता।
- **ऑकलैंड ओपन :** 17 जनवरी, 2015 को भारत के लिएंडर पेस और दक्षिण अफ्रीका के रेवेन क्लासेन की जोड़ी ने डोमिनिक इंगलोट और फ्लोरिन मेरगिया की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराकर ऑकलैंड ओपन का खिताब जीता।
- **सिडनी ओपन** : 17 जनवरी, 2015 को भारत के रोहन बोपन्ना एवं कनाडा के डेनियल नेस्टर की जोड़ी ने जूलियन रोजर और होरिया टेकाऊ की जोड़ी को 6-4, 7-6 से हराकर सिडनी ओपन का खिताब जीता।

- **सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट** : 16 जनवरी, 2015 को भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और अमेरिका की बेथानी माटेक सैंडस की जोड़ी ने अबिगेल स्पीयर्स और राकेल कोप्स जोंस की शीर्ष वरीय अमेरिकी जोड़ी को 6-3, 6-3 से हराकर सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता।
- **चेन्नई ओपन एटीपी टेनिस टूर्नामेंट** : 11 जनवरी, 2015 को संपन्न।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	स्टेनिस्लास वावरिंका (स्विट्जरलैंड)	एल्जाज बेदेने (स्लोवेनिया)
पुरुष युगल	येन सुन लू (चीनी ताइपे) एवं जोनाथन मरे (ब्रिटेन)	लिएंडर पेस (भारत) एवं रावेन क्लासेन (द. अफ्रीका)

- **डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट** : 29 दिसंबर, 2014 को अंकिता रैना ने पुणे में आयोजित विश्व टेनिस एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय महिला टूर्नामेंट में सिंगल्स का खिताब ब्रिटेन की केटी ड्यूने को हराकर जीता। इसके पहले यह टूर्नामेंट वर्ष 2001 में राधिका तुलपुले नामक भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता था।

एथलेटिक्स

- **बीजिंग इंटरनेशनल मैराथन-2015** : 20 सितंबर, 2015 को केन्या के मारिको किपचुंबा ने वर्ष 2015 का बीजिंग इंटरनेशनल मैराथन जीता। महिला वर्ग में यह खिताब इथियोपिया की धावक बेथेलहम चेरेनेट ने जीता।
- **49वां एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक चैंपियनशिप-2015** : 29 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2015 के मध्य उजबेकिस्तान में 49वें एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक चैंपियनशिप, 2015 का आयोजन किया गया। भारतीय महिला बॉडी बिल्डर श्वेता राठौर ने इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। वे इस प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं।
- **राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2015** : 16 से 19 सितंबर, 2015 के मध्य 55वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स का आयोजन कोलकाता में हुआ। प्रतियोगिता में सेना के आरोक्य राजीव को पुरुषों में तथा रेलवे की ललिता बाबर को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। रेलवे की मनप्रीत कौर ने 17.96 मीटर तक चक्का फेंक कर चक्का फेंक स्पर्धा में वर्ष 1997 में हरबंस कौर द्वारा बनाया गया 17.43 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। रेलवे की ही दुती चंद ने व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक तीन पदक जीते। प्रमुख स्पर्धाओं एवं उनके पदक विजेताओं के नाम निम्नलिखित हैं—

स्पर्धा	पुरुष वर्ग	महिला वर्ग
100 मी.	मनिकंदन राज (रेलवे) 10.70	दुती चंद (रेलवे) 11.68
200 मी.	मनिकांडा अरमुगम (रेलवे) 21.35	दुती चंद (रेलवे) 23.69
400 मी.	आरोक्य राजीव (सेना) 45.70	एम.आर. पूवम्मा (ओएनजीसी) 53.55
800 मी.	अजय कुमार सरोज (ओएनजीसी) 1:54:87	टिंटू लूका (रेलवे) 2:00:56
5000 मी.	जी लक्ष्मनन (सेना) 14:00:77	ओ.पी. जैशा (रेलवे) 15:31:73
10000 मी.	गोपी टी (सेना) 30:07:70	एन सूर्या (रेलवे) 33:44::84
4×100 मी.	सेना 40:66	रेलवे 45:92
4×400 मी.	सेना 3:06:63	ओएनजीसी 3:42:49
शॉटपुट	इंदरजीत सिंह (हरियाणा) 19.82 मी.	मनप्रीत कौर (रेलवे) 17.96मी.

- **15वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2015** : 22 से 30 अगस्त, 2015 के मध्य चीन के बीजिंग में 15वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2015 का आयोजन हुआ। जमैका के उसैन बोल्ट ने 3 स्वर्ण पदक क्रमशः 100 मीटर, 200 मीटर व 4×100 मीटर रिले स्पर्धा में जीते। प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण, 6 रजत व 3 कांस्य पदकों सहित केन्या शीर्ष पर रहा। जमैका कुल 12 पदकों के साथ दूसरे स्थान तथा मेजबान चीन 1 स्वर्ण, 7 रजत व 1 कांस्य पदक के साथ 11वें स्थान पर रहा। इस विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत का 17 सदस्यीय दल एक भी पदक नहीं पा सका।
- **55वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप** : 10 जुलाई, 2015 के मध्य चेन्नई में 55वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का टीम खिताब हरियाणा ने तथा महिला वर्ग का टीम खिताब केरल ने जीता। प्रतियोगिता में हरियाणा के शॉटपुट खिलाड़ी इंदरजीत सिंह ने 20.44 मीटर दूरी तक गोला फेंक कर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। उन्हें पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। कर्नाटक की एम.आर. पूवम्मा को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया।
- **प्रीमियर माउंटेन बाइकिंग रेस** : 4 अक्टूबर, 2015 को पुर्तगाल के लुईस लियो पिंटो ने एशिया की प्रीमियर माउंटेन बाइकिंग रेस जीता। इसके पहले उन्हें वर्ष 2013 में भी 'किंग ऑफ द हिमालय' का खिताब मिल चुका था। इंग्लैंड की कैथरीन विलियमसन ने महिला एकल श्रेणी में जीत हासिल की।
- **फीबा एशियन बॉस्केटबॉल चैंपियनशिप** : 3 अक्टूबर, 2015 को चीन ने फाइनल मुकाबले में फिलीपींस को 78-67 से हराकर 'फीबा एशियन बॉस्केटबॉल चैंपियनशिप' का खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ चीन ने वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। चीन के 'यी जिआनलियान' को टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर चुना गया। भारत को इस प्रतियोगिता में 8वां स्थान प्राप्त हुआ।
- **21वीं एशियन एथलेटिक्स** : 3 से 7 जून, 2015 के मध्य चीन के वुहान में आयोजित। भारत को इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण (इंदरजीत सिंह, विकास गौड़ा, टिंटू लुंका व ललिता बाबर), 5 रजत व 4 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक प्रापत हुए। भारत का प्रतियोगिता में तीसरा स्थान रहा। चीन 15 स्वर्ण, 13 रजत व 13 कांस्य पदकों सहित कुल 41 पदक पाकर शीर्ष पर रहा।
- **विश्व पुलिस एवं फायर खेल** : 7 जुलाई, 2015 को वाशिंगटन में संपन्न हुए विश्व पुलिस एवं फायर खेलों में भारत ने 89 स्वर्ण और 50 रजत समेत रिकॉर्ड 156 पदक जीते। सीआरपीएफ की तैराक रिचा मिश्रा ने भारत की ओर से सबसे अधिक 6 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते।
- **एशियाई एथलेटिक्स ग्रां. प्री** : 23 जून, 2015 को भारत के इंद्रजीत सिंह और जिनसन जॉनसन ने बैंकाक में एशियाई एथलेटिक्स ग्रां. प्री. के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीते। इंद्रजीत सिंह ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक तथा जिनसन जॉनसन ने पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
- **यूरोपीय टीम एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2015** : 21 जून, 2015 को रूस ने यूरोपीय टीम एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती। जर्मनी इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा तथा फ्रांस को तीसरा स्थान मिला।
- **पैदल चाल** : 6 जून, 2015 को चीन की धावक लियू होंग ने स्पेन में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स (आईएएएफ) द्वारा आयोजित 20 किमी. पैदल चाल रेस 'ला कोरुना' में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 1 घंटा, 24 मिनट और 38 सेकेंड में 20 किमी. की दूरी तय की।
- **100 मीटर की रेस में नया विश्व रिकॉर्ड** : 4 जून, 2015 को इटली के रोम में आयोजित रोम डायमंड लीग में अमेरिकी धावक जस्टिन गैटलिन ने 100 मीटर की दौड़ रिकॉर्ड 9.75 सेकेंड में पूरी की। उन्होंने जमैका के उसैन बोल्ट के वर्ष 2012 में 9.76 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ पूरी करने के रिकॉर्ड को तोड़ा।
- **19वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप** : 3 मई, 2015 को भारतीय सेना ने 19वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की टीम रही। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हरियाणा के इंदरजीत सिंह तथा महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओडिशा की सर्बाणी नंदा रहे।

क्रिकेट

- **गांधी-मंडेला सीरीज** : 25 अक्टूबर, 2015 को दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पांच एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की गांधी-मंडेला सीरीज के अंतिम मैच में भारत को रिकॉर्ड 214 रनों से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम की। पांचवें मैच में मिली हार भारत की घरेलू मैदान पर सबसे बड़ी व कुल मिलाकर दूसरी सबसे बड़ी हार थी।
- **अफगानिस्तान-जिम्बाब्वे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज** : 25 अक्टूबर, 2015 को अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैचों की एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का खिताब 3-2 से जीत लिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ऐसा पहला सहयोगी क्रिकेट देश बन गया है जिसने टेस्ट खेलने वाले देश को एकदिवसीय क्रिकेट सीरीज में हराया।
- **अफगानिस्तान-जिम्बाब्वे टी-20 सीरीज** : 28 अक्टूबर, 2015 को अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दो टी-20 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराकर इतिहास रचा। अफगानिस्तान आईसीसी का पहला एसोसिएट देश है जिसने दो टी-20 मैचों की सीरीज जीती।
- **भारत-जिम्बाब्वे** : दो टी-20 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर रही।
- **भारत-न्यूजीलैंड** : तीन टी-20 मैचों की श्रृंखला को न्यूजीलैंड की टीम ने 2-1 से जीता।
- **मोइनुद्दौला गोल्ड कप** : 2 सितंबर, 2015 से 16 सितंबर, 2015 के मध्य हैदराबाद में अखिल भारतीय कोरोमंडल किंग मोइनुद्दौला गोल्ड कप टूर्नामेंट 2015-16 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का खिताब इंडिया सीमेंट्स ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एकादश को हराकर जीता।
- **भारत-श्रीलंका टेस्ट श्रृंखला** : 6 अगस्त, 2015 से 1 सितंबर, 2015 के मध्य भारत व श्रीलंका के मध्य तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला आयोजित की गई। भारतीय टीम ने 22 वर्षों बाद श्रीलंका से उसी की धरती पर यह टेस्ट श्रृंखला 2-1 से जीत ली। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को 21 विकेट प्राप्त करने के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब दिया गया। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तथा श्रीलंकाई टीम के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज थे।
- **एशेज श्रृंखला 2015** : 8 जुलाई, 2015 से 23 अगस्त, 2015 के मध्य इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की एशेज श्रृंखला आयोजित की गई। वर्ष 2015 की एशेज श्रृंखला इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर जीती। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस रोजर्स तथा इंग्लैंड के जो रूट को संयुक्त रूप से 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार दिया गया।
- **भारत-जिम्बाब्वे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला** : भारत ने 10 से 14 जुलाई, 2015 के मध्य जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई तीन एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली। तीसरे व अंतिम एकदिवसीय मैचों में केदार जाधव (105 रन) को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 'मैन ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार अम्बाती रायडू को दिया गया।
- **भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज** : 8 जुलाई, 2015 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को पाचवें और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में नौ विकेट से हराकर सीरीज 3-2 से जीत ली।
- **भारत-बांग्लादेश एकदिवसीय श्रृंखला** : 24 जून, 2015 को बांग्लादेश ने ढाका में भारत के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2-1 से जीत ली। बांग्लादेश की भारत के खिलाफ यह पहली श्रृंखला जीत थी। बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को सीरीज में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया।
- **सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी** : 7 अप्रैल, 2015 को गुजरात ने फाइनल में पंजाब को दो विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।
- **ईरानी कप** : 20 मार्च, 2015 को रणजी चैंपियन कर्नाटक ने शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) को 246 रन से हराकर लगातार दूसरी बार एवं कुल छठीं बार ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। मैन ऑफ द मैच मनीष पांडे ने नाबाद 123 रन बनाए।
- **रणजी ट्रॉफी** : 12 मार्च, 2015 को मौजूदा चैंपियन कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी का खिताब तमिलनाडु को पारी और 217 रन से हराकर लगातार दूसरी बार जीता।
- **कर्नल सी.के. नायडू अंडर-23 ट्रॉफी, 2014-15** : 28 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम ने फाइनल में प्रथम पारी की बढ़त के आधार पर हिमाचल प्रदेश को हराकर प्रतिष्ठित अंडर-23 कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी 2014-15 का खिताब जीता।
- **राष्ट्रीय स्कूली क्रिकेट चैंपियनशिप** : 2 मार्च, 2015 को यूपी की अंडर-14 क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय स्कूली क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब चंडीगढ़ को 48 रन से हराकर जीता। लखनऊ के अभिनव श्रीवास्तव मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने।
- **एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता** : 13 फरवरी, 2015 को भारत ने शारीरिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों के लिए आयोजित एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में अफगानिस्तान को तीन विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। भारत का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के इकलाख ने किया था।
- **कार्लटन मिड त्रिकोणीय श्रृंखला** : ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के मध्य यह एकदिवसीय श्रृंखला 16 जनवरी-1 फरवरी, 2015 के बीच संपन्न हुई। इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित किया। इस श्रृंखला के 'प्लेयर ऑफ दि सीरीज' ऑस्ट्रेलिया के माइकल स्टार्क रहे।
- **कूच बिहार ट्रॉफी 2014-15** : 6 फरवरी, 2015 को फाइनल मुंबई और पंजाब की अंडर-19 टीमों के बीच खेला गया जो कि ड्रा रहा और पहली पारी की बढ़त के आधार पर मुंबई ने इस ट्रॉफी पर कब्जा किया।
- **बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी** : 10 जनवरी, 2015 को संपन्न भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत कर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस चार टेस्ट मैचों की सीरीज में कुल 5870 रन बने जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है।
- **नेत्रहीन विश्व कप क्रिकेट** : 8 दिसंबर, 2014 को भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने कप्तान शेखर नाइक की अगुवाई में केपटाउन में गत विजेता पाकिस्तान को हराकर नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता।

हॉकी

- **सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट** : 18 अक्टूबर, 2015 को ब्रिटेन की जूनियर हॉकी टीम ने भारतीय जूनियर हॉकी टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। मेजबान मलेशिया ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया को प्रतियोगिता का फेयरप्ले पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रिटेन के ल्यूक टेलर (10 गोल) सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। ब्रिटेन के क्रिस वेवर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे तथा भारत के हरजीत सिंह को बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया। यह टूर्नामेंट वर्ष 2011 से अंडर-21 स्तर पर मलेशिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में भी सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट का विजेता रहा है।
- **भारत-न्यूजीलैंड हॉकी टेस्ट श्रृंखला** : 11 अक्टूबर, 2015 को भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार मैचों की पुरुषों की हॉकी टेस्ट श्रृंखला 2-1 से जीत ली।
- **बेटन कप** : 11 अक्टूबर, 2015 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने पेनाल्टी शूट में इंडियनऑयल कारपोरेशन (आईओसी) को 5-3 से हराकर बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। पीएनबी के गोलकीपर जसबीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह टूर्नामेंट बंगाल हॉकी संघ द्वारा वर्ष 1895 में स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है।

- **24वां अखिल भारतीय बाबा फरीद गोल्ड कप** : 23 सितंबर, 2015 को पंजाब के फरीदकोट में भारतीय वायुसेना ने आर्मी इलेवन को 2-1 से हराकर 24वें अखिल भारतीय बाबा फरीद गोल्ड कप का खिताब जीत लिया।
- **भारत की फ्रांस एवं स्पेन से टेस्ट शृंखला** : अगस्त, 2015 में भारतीय हॉकी टीम ने सरदार सिंह की अगुवाई में फ्रांस को दो टेस्ट मैचों की शृंखला में 2-0 से हराया तथा स्पेन को तीन टेस्ट मैचों की शृंखला में 2-1 से हराया।
- **महिला इंडोर एशिया कप** : 12 से 16 अगस्त, 2015 के मध्य थाईलैंड में एशियन हॉकी महासंघ (एएचएफ) द्वारा 5वीं महिला इंडोर एशिया कप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का खिताब कजाख्स्तान ने थाईलैंड को 4-2 से हराकर जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हांगकांग के चान यिन चिंग टिफ्फैनी को दिया गया। कजाख्स्तान की नताल्या गाटाउलिना ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल किए।
- **गुरू तेग बहादुर ट्रॉफी** : अगस्त, 2015 में मुंबई में आयोजित गुरू तेग बहादुर ट्रॉफी का खिताब एयर इंडिया ने सेना एकादश को 3-1 से हराकर जीत लिया।
- **मुरुगप्पा गोल्ड कप** : जुलाई, 2015 में चेन्नई में 89वें मुरुगप्पा गोल्ड कप का खिताब इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) ने सेना एकादश को 3-2 से हराकर जीता।
- **भारत-जापान टेस्ट शृंखला** : 3 से 9 मई, 2015 तक भारत व जापान के मध्य 4 मैचों की हॉकी टेस्ट शृंखला खेली गई। भारत ने यह शृंखला 3-0 से जीती।
- **हॉकी वर्ल्ड लीग** : 4 जुलाई, 2015 को ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स ने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर महिला हॉकी वर्ल्ड लीग का खिताब जीत लिया। भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से खेलते हुए 1-5 से हराकर चौथा स्थान प्राप्त किया। इस विश्व लीग सेमीफाइनल्स में अंतिम चार में जगह बनाने वाली सभी टीमें 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर गई हैं। 5 जुलाई, 2015 को हॉकी वर्ल्ड लीग में पुरुषों का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान बेल्जियम को 1-0 से हराकर जीता। प्रतियोगिता में कुल 7 गोल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक गोवर्स को हीरो सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी घोषित किया गया।
- **ऑइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप** : 17 मई, 2015 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आईआईएचएफ (IIHF) वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 (आइस हॉकी) के फाइनल में कनाडा ने रूस को हराकर यह खिताब जीत लिया।
- **जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप** : 10 मई, 2015 को झारखंड के राजनांदगांव में खेले गये फाइनल मैच में हरियाणा ने झारखंड को 6-1 से पराजित कर पांचवीं जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता।
- **सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप** : 3 मई, 2015 को रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) ने सैफई के मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गये सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2015 के फाइनल में झारखंड को हराकर खिताब जीता। 28 अप्रैल, 2015 को रेलवे ने उत्तर प्रदेश को हराकर सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2015 का खिताब जीता था।
- **'सुल्तान अजलान शाह कप' हॉकी, 2015** : 12 अप्रैल, 2015 को न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर दूसरी बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 6 देशों की इस महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता का कांस्य पदक (तीसरा स्थान) जीता। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व सरदार सिंह ने किया था तथा भारतीय टीम के कोच नीदरलैंड्स के पॉल वान एस थे।
- **हॉकी वर्ल्ड लीग-2** : 15 मार्च, 2015 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एफआईएच विश्व हॉकी लीग-2 के फाइनल में पोलैंड को 3-1 से हरा दिया।
- **हॉकी इंडिया लीग-2015** : 22 फरवरी, 2015 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गये फाइनल मैच में रांची रेंज ने पंजाब वारियर्स को हराकर हॉकी इंडिया लीग-2015 (तीसरा संस्करण) का खिताब जीत लिया।
- **चैंपियंस ट्रॉफी-2014** : 14 दिसंबर, 2014 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जर्मनी ने पाकिस्तान को 2-0 से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी खिताब जीत लिया।

फुटबाल

- **अंडर-18 जूनियर राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप** : 21 अक्टूबर, 2015 को मणिपुर ने ओडिशा को 5-0 से हराकर लड़कियों की अंडर-18 जूनियर राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया।
- **कॉनकाकफ गोल्ड कप-2015** : 7 से 26 जुलाई, 2015 के मध्य अमेरिका व कनाडा में संयुक्त रूप से कॉनकाकफ गोल्ड कप-2015 का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट का खिताब मेक्सिको ने जमैका को 3-1 से हराकर दसवीं बार जीता।
- **यूएफा सुपर कप-2015** : 11 अगस्त, 2015 को यूएफा (यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबाल एसोसिएशन-UEFA) सुपर कप प्रतियोगिता का आयोजन यूएफा चैंपियंस लीग की विजेता बार्सिलोना और यूएफा यूरोपा लीग की विजेता सेविला फुटबाल क्लब के मध्य मैच से हुआ। इसमें सेविला को 5-4 से हराकर स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने यूएफा सुपर कप का खिताब जीत लिया। बार्सिलोना के लियोनेल मेसी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
- **56वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबाल टूर्नामेंट** : 24 सितंबर, 2015 को मिजोरम के सरकारी चौंगफिआंग मिडल स्कूल ने अफगानिस्तान के ऐस्तेकलाल स्कूल को 3-2 से हराकर 56वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबाल टूर्नामेंट का अंडर-14 खिताब जीता।
- **दक्षिण एशिया फुटबाल फेडरेशन अंडर-16 टाइटल** : 18 अगस्त, 2015 को बांग्लादेश ने पहली बार दक्षिण एशिया फुटबाल फेडरेशन (एसएएफएफ) का अंडर-16 खिताब फाइनल में भारत को 4-2 से हराकर जीता।
- **अंडर-20 फुटबाल विश्व कप** : 20 जून, 2015 को न्यूजीलैंड के आकलैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में सर्बिया ने ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार अंडर-20 फुटबाल विश्व कप 2015 का खिताब जीता।
- **आईलीग (राष्ट्रीय फुटबाल लीग) खिताब** : 31 मई, 2015 को कोलकाता के अग्रणी फुटबाल क्लब मोहन बागान ने 13 वर्षों बाद बंगलुरु एफसी को अंकों के आधार पर हराकर आई लीग का खिताब जीता।
- **इंग्लिश प्रीमियम लीग 2014-15** : 3 मई, 2015 को इंग्लिश फुटबाल क्लब चेल्सी ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेले गये फाइनल मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस को 1-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग 2014-15 का खिताब जीत लिया।
- **संतोष ट्रॉफी** : 15 मार्च, 2015 को सेना ने लुधियाना में पंजाब को 5-4 से हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप का खिताब जीता।
- **फेडरेशन कप** : 11 जनवरी, 2015 को बंगलुरू एफसी ने डेंपो एफसी को 2-1 से हराकर फेडरेशन कप फुटबाल टूर्नामेंट जीता।
- **प्रथम इंडियन सुपर लीग (ISL)** : 20 दिसंबर, 2014 को मुंबई में खेले गए प्रथम इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के फाइनल में 'एटलेटिको डि कोलकाता' ने केरल ब्लास्टर्स को 1-0 से हराकर खिताब पर कब्जा किया।

बैडमिंटन

- **विश्व बैंडमिंटन चैंपियनशिप-2015** : 10 से 16 अगस्त, 2015 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2015 का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने वाली साइना नेहवाल प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं।

स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	चेन लांग (चीन)	ली चोंग वेई (मलेशिया
महिला एकल	कैरोलीना मारिन (स्पेन)	साइना नेहवाल (भारत)

- **कोरिया ओपन** : 20 सितंबर, 2015 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने सियोल में आयोजित कोरिया ओपन में रजत पदक जीता। वे चीन के चेन लोंग से फाइनल में 14-21, 12-21 से हार गये। फिर भी कोरिया ओपन में

पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दक्षिण कोरिया की सुंग जी ह्यून महिला एकल की विजेता बनी।

- **जापान सुपर सीरीज-2015 :** 8 से 13 सितंबर, 2015 के मध्य जापान के टोक्यो में आयोजित जापान सुपर सीरीज-2015 के पुरुष एकल का खिताब चीन के लिन डान ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर जीता। महिला एकल का खिताब जापान की नोजोमी ओकुहारा ने अकाने यामागुची को हराकर जीता।
- **विएतनाम ओपन ग्रां. प्रि.-2015 :** 24 अगस्त से 30 अगस्त, 2015 के मध्य संपन्न विएतनाम ओपन ग्रां. प्रि. बैडमिंटन के पुरुष एकल का खिताब इंडोनेशिया के टॉमी सुगिआर्तो तथा महिला एकल का खिताब जापान की साएना कावाकामी ने जीता।
- **कनाडा ओपन :** 28 जून, 2015 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा एवं अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने सेलेनी पीक एवं मुस्कीन्स की जोड़ी को हराकर कनाडा ओपन का खिताब जीता।
- **अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट :** 22 जून, 2015 को भारत के मनु अत्री व बी. सुमित रेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी को चीन के जुनहुई ली और युचेन ल्यू की जोड़ी ने हराकर अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट युगल का खिताब जीता।
- **ऑस्ट्रेलियन ओपन :** 31 मई, 2015 को पुरुष एकल का खिताब विश्व के नंबर एक खिलाड़ी चेन लोंग ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर जीता तथा महिला एकल का खिताब स्पेन की कैरोलीना मारिन ने चीन की वांग शिजियान को हराकर जीता।
- **इंडोनेशिया ओपन :** 7 जून, 2015 को इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गये फाइनल मुकाबले में जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंतो मोमोता ने इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। महिला एकल वर्ग का खिताब थाईलैंड की रत्चनोक इंतानोन ने जीता।
- **बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप-2015 :** 26 अप्रैल, 2015 को चीन के लिन डान ने चीन के वुहान में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप-2015 में पुरुष एकल का खिताब हमवतन तियान हुवेई को 21-19, 21-8 से हराकर जीता। महिला एकल का खिताब थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन ने चीव की ली श्यूरूई को 20-22, 23-21, 21-12 से हराकर जीता।
- **मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट :** 5 अप्रैल, 2015 को चीन के चेन लोंग और स्पेन की कैरोलिना मारिन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष व महिला एकल का खिताब जीता।
- **इंडिया ओपन सुपर सीरीज :** 29 मार्च, 2015 को विश्व की नंबर एक खिलाड़ी साइना नेहवाल ने थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन को 21-16, 21-14 से हराकर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता। इसके अतिरिक्त पुरुष वर्ग में किदांबी श्रीकांत ने डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन को 18-21, 21-13, 21-12 से हराकर खिताब जीता। दोनों पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंडिया ओपन का खिताब जीता है।
- **स्विस ओपन ग्रां. प्री. गोल्ड :** 15 मार्च, 2015 को भारतीय बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत ने पुरुष एकल के फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन को हराकर स्विस ओपन ग्रां. प्री. गोल्ड का खिताब जीत लिया।
- **79वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप :** 29 जनवरी से 5 फरवरी, 2015 के मध्य विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में आयोजित की गई। पुरुष एकल में साईं प्रणीत तथा महिला एकल में रुतविका शिवानी विजेता बने।
- **सैय्यद मोदी ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2015**

स्पर्द्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	परुपल्ली कश्यप (भारत)	के. श्रीकांत (भारत)
महिला एकल	साइना नेहवाल (भारत)	कैरोलीना मारिन (स्पेन)

बिलियड्र्स/स्नूकर

- **विश्व बिलियड्र्स चैंपियनशिप :** 27 सितंबर, 2015 को पंकज आडवाणी ने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में आयोजित फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर विश्व बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह उनका 14वां विश्व बिलियड्र्स चैंपियनशिप खिताब है।
- **IBSF विश्व टीम एवं 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप :** 6 से 15 अगस्त, 2015 के मध्य इंटरनेशनल बिलियड्र्स एंड स्नूकर फेडरेशन (IBSF) द्वारा विश्व टीम एवं 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन पाकिस्तान के कराची में किया गया। प्रतियोगिता में भारत के पंकज आडवाणी ने चीन के यान बिंताओ को हराकर 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। महिला वर्ग में हांगकांग की न्ग ओन यी ने भारत की विद्या पिल्लई को हराकर खिताब जीता। वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब मलेशिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता।
- **IBSF वर्ल्ड अंडर-21 स्नूकर चैंपियनशिप :** 18 से 26 जुलाई, 2015 के मध्य रोमानिया के बुखारेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय बिलियड्र्स एवं स्नूकर महासंघ द्वारा वर्ल्ड अंडर-21 स्नूकर चैंपियनशिप-2015 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का खिताब थाइलैंड के बून्यारित किआट्टीकुन ने वेल्स के जैमी क्लार्क के हराकर जीता।
- **स्नूकर विश्व कप, 2015 :** 21 जून, 2015 को चीन के वूशी में आयोजित फाइनल मैच में चीन ने स्कॉटलैंड को 4-1 से हराकर स्नूकर विश्व कप, 2015 का खिताब जीत लिया। इस स्नूकर विश्व कप में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- **एसीबीएस एशियाई बिलियड्र्स चैंपियनशिप :** 13 अप्रैल, 2015 को मुंबई के क्यू खिलाड़ी ध्रुव सितवाल ने कई बार के विश्व चैंपियन हमवतन पंकज आडवाणी को हराकर एसीबीएस एशियाई बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है।
- **सीनियर राष्ट्रीय पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप :** 24 जनवरी, 2015 को पंकज आडवाणी ने कोलकाता में वरुण मदान को 6-3 से हराकर सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती।
- **सीनियर नेशनल बिलियड्र्स चैंपियनशिप :** 17 जनवरी, 2015 को पंकज आडवाणी ने सातवीं सीनियर नेशनल बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब ध्रुव सितवाला को 5-0 से हराकर जीता।
- **सीनियर राष्ट्रीय महिला स्नूकर चैंपियनशिप :** 24 जनवरी, 2015 को मध्य प्रदेश की अमी कमानी ने कर्नाटक की विद्या पिल्लई को हराकर महिला वर्ग का राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता।
- **सीनियर राष्ट्रीय महिला बिलियड्र्स चैंपियनशिप :** 22 जनवरी, 2015 को महाराष्ट्र की अरांशा सांचिस (Arantxa Sanchis) ने महाराष्ट्र की ही मीनल ठाकुर को हराकर महिला वर्ग का राष्ट्रीय बिलियड्र्स चैंपियनशिप का खिताब जीता।

गोल्फ

- **81वीं सिंघा थाईलैंड ऐमेच्योर ओपन, 2015 :** 8 से 11 सितंबर, 2015 के मध्य थाईलैंड के बैंकाक में आयोजित 81वीं सिंघा थाईलैंड ऐमेच्योर ओपन गोल्फ प्रतियोगिता 2015 का खिताब पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक प्रोवबर्स ने जीता तथा भारतीय ऐमेच्योर गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक ने महिला वर्ग का खिताब जीता।
- **ड्यूश बैंक चैंपियनशिप-2015 :** 7 सितंबर, 2015 को अमेरिका के मेसाच्यूसेट्स में आयोजित ड्यूश बैंक चैंपियनशिप-2015 का खिताब अमेरिका के गोल्फर रिकी फाउलर ने जीता।
- **द ओपन चैंपियनशिप :** 20 जुलाई, 2015 को द ओपन चैंपियनशिप का

आयोजन स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का खिताब अमेरिका के 'जाच जॉनसन' ने जीता।

- **यू. एस. ओपन** : 21 जून, 2015 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में यू.एस. ओपन गोल्फ का आयोजन संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का खिताब अमेरिका के 'जॉर्डन स्पीथ' के नाम रहा।
- **मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट** : 7 जून, 2015 को अमेरिका के ओहियो में संपन्न मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब स्वीडन के डेविड लिंगमर्थ ने जीता।
- **अहमदाबाद मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट** : 3 अप्रैल, 2015 को खालिन जोशी ने पीजीटीआई अहमदाबाद मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता।
- **इंडियन ओपन गोल्फ** : 22 फरवरी, 2015 को भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने इंडियन ओपन खिताब जीता।

फॉर्मूला वन

- **यूएस ग्रां. प्रि.** : 26 अक्टूबर, 2015 को मौजूदा चैंपियन मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने यूएस ग्रां. प्रि. का खिताब जीता। उन्होंने इसके साथ ही तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप पर कब्जा किया। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन की इस सत्र में यह 10वीं जीत है।
- **इटैलियन ग्रां. प्रि.** : सितंबर, 2015 में आयोजित इटैलियन ग्रां. प्रि. का खिताब मर्सिडीज टीम के लुईस हैमिल्टन ने जीता।
- **बेल्जियन ग्रां. प्रि.** : 23 अगस्त, 2015 को आयोजित बेल्जियम ग्रां. प्रि. का खिताब मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक लुईस हैमिल्टन ने जीता।
- **रूसी ग्रां. प्रि.** : 11 अक्टूबर, 2015 को मर्सिडीज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने रूसी ग्रां. प्रि. फार्मूला वन रेस जीती।
- **सिंगापुर ग्रां. प्रि.** : 20 सितंबर, 2015 को सिंगापुर ग्रां. प्रि. का खिताब फरारी टीम के सेबेस्टियन वेट्टल ने जीता।
- **जापान ग्रां. प्रि.** : 7 सितंबर, 2015 को ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने जापान के सुजुका सर्किट में आयोजित जापान ग्रां. प्रि. फार्मूला वन का खिताब जीता। मर्सिडीज के ड्राइवर निको रोसबर्ग दूसरे स्थान पर रहे।
- **हंगरी ग्रां. प्रि.** : 26 जुलाई, 2015 को फेरारी के जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन वेट्टेल ने बुडापेस्ट में हंगरी ग्रां. प्रि. का खिताब जीता। इस जीत के साथ वेट्टेल ने कुल 41 ग्रां. प्रि. जीतने के आर्यटन सेन्ना के रिकॉर्ड की बराबरी की।
- **ब्रिटिश ग्रां. प्री.** : 5 जुलाई, 2015 को फार्मूला वन विश्व चैंपियन ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने लगातार दूसरे वर्ष यह खिताब जीत लिया।
- **कनाडा ग्रां. प्री.** : 8 जून, 2015 को ब्रिटिश मर्सिडीज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने निको रोसबर्ग को हराकर कनाडा ग्रां. प्री. रेस जीती।
- **मोनाको ग्रैंड प्रिक्स** : 24 मई, 2015 को मर्सिडीज के जर्मन ड्राइवर निको रोसबर्ग ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस लगातार तीसरे वर्ष जीती।
- **बहरीन ग्रैंड प्रिक्स** : 19 अप्रैल, 2015 को ब्रिटेन के मर्सिडीज़ फार्मूला वन ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता।
- **चाइनीज ग्रां. प्री.** : 12 अप्रैल, 2015 को मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीत लिया।
- **मलेशियन ग्रां. प्री.** : 29 मार्च, 2015 को फरारी के सेबेस्टियन वेट्टल ने वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को हराकर मलेशियन ग्रां. प्री. का खिताब जीता।

निशानेबाजी

- **8वीं एशियाई एअरगन चैंपियनशिप** : 30 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं एशियाई एअरगन चैंपियनशिप में भारत की महिला पिस्टल शूटर हिना सिद्धू ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने छह स्वर्ण, पांच रजत व छह कांस्य पदकों सहित कुल 17 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईरान व ताइपे क्रमशः 12 व 5 पदकों के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। स्वर्ण पदक विजेताओं में अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग व चैन सिंह भी शामिल रहे। 15 वर्षीय सत्यजीत खंडोल ने 10 मी. यूथ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
- **ISSF विश्व कप फाइनल 2015** : 1 सितंबर से 7 सितंबर, 2015 के मध्य जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप फाइनल राइफल/पिस्टल 2015 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में चीन 3 स्वर्ण, 1 रजत व 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक प्राप्त कर शीर्ष पर रहा। भारत की ओर से अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता।
- **गगन नारंग ने जीता कांस्य पदक** : 15 मई, 2015 को भारतीय निशानेबाज गगन नारंग ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (आईएसएसएफ) की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
- **अपूर्वी चंदेला ने जीता कांस्य पदक** : 10 अप्रैल, 2015 को भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईएसएसएफ) की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
- **आईएसएसएफ वर्ल्ड कप** : 12 अप्रैल, 2015 को भारतीय निशानेबाज जीतू राय ने आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

शतरंज

- **हूगेवीन इंटरनेशनल ओपन** : 26 अक्टूबर, 2015 को भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने हमवतन नीलोत्पल दास को हराकर हूगेवीन (हॉलैंड) इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।
- **विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप** : 13 अक्टूबर,2015 को नार्वे के मैग्नस कार्लसन ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। दूसरे स्थान पर रूस के इयान नेपोमनियाचतची तथा तीसरे स्थान पर अजरबैजान के तैमूर रादजाबोव रहे। भारत के विश्वनाथन आनंद 25वें स्थान पर रहे।
- **फिडे विश्व शतरंज कप-2015** : 5 अक्टूबर, 2015 को रूस के सर्जेई कर्जेकिन ने रूस के ही पीटर स्विदलर को हराकर फिडे विश्व शतरंज कप 2015 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता अजरबैजान के बाकू में 10 सितंबर, 2015 से 5 अक्टूबर, 2015 के मध्य आयोजित की गई।
- **कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप** : 22 से 30 जून, 2015 के मध्य नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने जीता। महिला वर्ग का खिताब भारत की पद्मिनी राउत ने जीता।
- **एशियन युवा शतरंज चैंपियनशिप** : 3 अगस्त, 2015 से 11 अगस्त, 2015 के मध्य द. कोरिया के सुवान में संपन्न हुई। एशियन युवा शतरंज चैंपियनशिप 2015 में भारत ने खिताब जीतते हुए 5 स्वर्ण, 5 रजत तथा 7 कांस्य पदकों सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए।
- **पॉलिटिकेन कप-2015** : 25 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 के मध्य डेनमार्क के हेल्सिंगर में पॉलिटिकेन कप शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता का खिताब ऑस्ट्रिया के ग्रैंड मास्टर मार्कस रैगर ने जीता।
- **बील इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव** : 18 से 31 जुलाई, 2015 के मध्य स्विट्जरलैंड में बील इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2015 का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में फ्रांस के मैक्सिमे वाचिर-लाग्रेव ने ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का खिताब जीता तथा इजरायल के इमिल सुतोवस्की ने मास्टर्स ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता।

- **लीडेन शतरंज टूर्नामेंट-2015** : 17 से 26 जुलाई, 2015 के मध्य नीदरलैंड्स में लीडेन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का खिताब इंग्लैंड के ग्रैंडमास्टर डेविड डब्ल्यू एल. हॉवेल ने जीता।
- **नार्वे शतरंज टूर्नामेंट, 2015 :** 25 जून, 2015 को वेसलिन टोपालोव ने विश्वनाथन आनंद को ड्रा से हराकर नार्वे शतरंज टूर्नामेंट 2015 का खिताब जीता।
- **वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप :** 28 अप्रैल, 2015 को आर्मेनिया में संपन्न वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप में भारत नौवें स्थान पर रहा। चीन इस प्रतियोगिता का विजेता रहा तथा यूक्रेन दूसरे स्थान पर रहा। 29 अप्रैल, 2015 को महिला विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जॉर्जिया ने जीता।
- **शमकीर शतरंज टूर्नामेंट :** 26 अप्रैल, 2015 को नार्वे के मैग्नस कार्लसन ने अजरबैजान में आयोजित शमकीर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारत के विश्वनाथन आनंद इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे।
- **दुबई ओपन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट** : 15 अप्रैल, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर सायंतन दास (भारतीय शतरंज खिलाड़ी) इटली के डेनियले वोकातुरो पर जीत दर्ज करके दुबई ओपन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे।
- **वर्ल्ड महिला शतरंज चैंपियनशिप** : 6 अप्रैल, 2015 को भारतीय ग्रैंडमास्टर द्रोणावल्ली हरिका ने वर्ल्ड महिला शतरंज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर स्वीडन की ग्रैंडमास्टर पिया क्रैमलिंग के साथ कांस्य पदक जीता।
- **चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट** : 6 जनवरी, 2015 को रूस के ग्रैंड मास्टर पोपोव इवान ने सुपर टाइबेकर के जरिए सातवें चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।

टेबल टेनिस

- **दक्षिण एशियाई जूनियर एवं कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप** : 18 जून, 2015 को भारत के खिलाड़ियों ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई जूनियर एवं कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता।
- **76वीं सीनियर टेबल टेनिस नेशनल चैंपियनशिप :** 17 जनवरी, 2015 को 76वीं सीनियर टेबल टेनिस नेशनल चैंपियनशिप में सौम्यजीत घोष ने जी साथियान को हराकर दूसरी बार पुरुष सिंगल्स खिताब जीता तथा मौमा दास ने पौलमी घटक को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीता।

अन्य प्रमुख खेल

- **तीरंदाजी वर्ल्ड कप** : 25 अक्टूबर, 2015 को दिल्ली के अभिषेक वर्मा ने मेक्सिको सिटी में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप के फाइनल में कंपाउंड वर्ग में रजत पदक जीता। वे फाइनल में तुर्की के इलमागकली से हारकर स्वर्ण जीतने से चूक गये। इसके अतिरिक्त दीपिका कुमारी ने फाइनल में रजत पदक जीता। यह पिछले पांच साल में विश्व कप में उनका चौथा रजत पदक है। वे फाइनल में दुनिया की नंबर एक मिसुन से हार गई।
- **विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप-2015** : 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 के मध्य डेनमार्क के कोपेनहेगेन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का 48वां संस्करण आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया ने 6 स्वर्ण व 3 कांस्य पदकों सहित कुल 9 पदक प्राप्त कर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने 2 रजत पदक प्राप्त कर प्रतियोगिता में 7वां स्थान प्राप्त किया। भारत की ओर से महिलाओं की रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी, रिमिल ब्यूरीयूली और लक्ष्मीरानी माझी ने रजत पदक प्राप्त किए। भारत के रजत चौहान ने कंपाउंड वर्ग में रजत पदक जीता।
- **ताइवान कप ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक टूर्नामेंट** : अक्टूबर, 2015 में भारतीय महिला साइकिलिस्ट देबोरा ने ताइवान कप ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक टूर्नामेंट में एक स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक सहित कुल पांच पदक जीते। देबोरा ने महिलाओं की इलीट स्प्रिंट में मलेशिया की शीर्ष राइडर को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- **यूरोपियन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप** : 5 अक्टूबर, 2015 को रूस की महिला वॉलीबॉल टीम ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर यूरोपियन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। रूस ने लगातार दूसरी बार तथा कुल 19वीं बार यह खिताब जीता है। रूस की तातियाना कोशेलेवा को टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का खिताब दिया गया।
- **16वीं एशियाई रोइंग चैंपियनशिप** : 28 सितंबर, 2015 को चीन के बीजिंग में आयोजित 16वीं एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने पांच रजत व दो कांस्य पदकों सहित कुल सात पदक जीते।
- **विश्व कुश्ती चैंपियनशिप** : 13 सितंबर, 2015 को अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फ्रीस्टाइल स्पर्धा में भारत के नरसिंह पंचम यादव ने 74 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही नरसिंह पंचम यादव ने रियो ओलंपिक, 2016 के लिए क्वालीफाई किया।
- **FIVB वॉलीबाल महिला विश्व कप-2015** : 22 अगस्त से 6 सितंबर, 2015 के मध्य जापान में इंटरनेशनल वॉलीबाल फेडरेशन (FIVB) द्वारा वॉलीबाल महिला विश्व कप-2015 का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में चीन ने जापान को 3-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। दूसरा स्थान सर्बिया को तथा तीसरा स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ। विश्व कप की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) चीन की झू टिंग रहीं।
- **प्रो. कबड्डी लीग-2015** : 18 जुलाई से 23 अगस्त, 2015 के मध्य भारत के विभिन्न शहरों में प्रोफेशनल कबड्डी लीग-2015 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का खिताब यू मुम्बा ने बंग्लुरू बुल्स को पराजित कर जीता।
- **विश्व एक्वैटिक्स चैंपियनशिप-2015** : 24 जुलाई से 9 अगस्त, 2015 के मध्य रूस के कजान शहर में 16वीं विश्व एक्वैटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। चीन ने 15 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदकों सहित कुल 35 पदक जीतकर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता प्रति दो वर्ष पर आयोजित होती है। 17वें विश्व एक्वैटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2017 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा।
- **विक्टोरियन ओपन स्क्वैश** : 27 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में विक्टोरियन ओपन स्क्वैश का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब ऑस्ट्रेलिया के रेयान कुसकेली ने स्कॉटलैंड के ग्रेग लेबनान को हराकर जीता। महिला वर्ग का खिताब भारतीय खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने डेनमार्क की लिने हैनसेन को हराकर जीता।
- **राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप** : 12 जुलाई, 2015 को केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में 63वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित हुई। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब तमिलनाडु के सौरव घोषाल ने हरिंदर पाल सिंह संधु को हराकर जीता तथा महिला वर्ग का खिताब तमिलनाडु की ही जोशना चिनप्पा ने दिल्ली की हर्षित कौर जवांडा को हराकर जीता।
- **टूर डी फ्रांस का 102वां संस्करण** : 26 जुलाई, 2015 को स्काई टीम के ब्रिटिश चालक क्रिस फ्रूम ने पेरिस में साईकिलिंग में टूर डी फ्रांस का 102वां संस्करण जीता। वे दूसरी बार टूर डी फ्रांस जीतने वाले ब्रिटिश चालक बने। इसके पहले उन्होंने वर्ष 2013 में यह खिताब जीता था।
- **यूएस पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप** : 11 जुलाई, 2015 को अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित यूएस पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप-2015 का जूनियर खिताब भारतीय मूल के अमेरिकी अमितोज छाबड़ा ने जीता।

- **तीरंदाजी विश्व कप** : 31 मई, 2015 को भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
- **दक्षिण एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप** : 5 जुलाई, 2015 को भारत ने बंगलुरू में श्रीलंका को 93-44 से हराकर चौथी दक्षिण एशिया बास्केटबाल चैंपियनशिप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता।
- **सबसे महंगा मुकाबला :** 3 मई, 2015 को लास वेगास (अमेरिका) में मुक्केबाजी इतिहास के सबसे महंगे मुकाबले में अमेरिका के फ्लॉयड मेवेदर ने फिलीपींस के मैनी पैकियाओ को हराया। मेवेदर ने इस जीत से 1142 करोड़ रुपये और पैकियाओ ने हार के बावजूद 761 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
- **प्रेसीडेंट्स कप ओपन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट :** 27 अप्रैल, 2015 को भारत ने 4 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीतकर इंडोनेशिया में आयोजत 22 वें प्रेसीडेंट्स कप ओपन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- **थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट** : 8 अप्रैल, 2015 को भारतीय मुक्केबाज श्याम कुमार ने पट्टाया में आयोजित थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता।
- **एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता** : 19 मार्च, 2015 को संजय बोरो एवं मधु वेदवान की भारतीय रिकर्व मिश्रित टीम ने एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।

चर्चित खिलाड़ी

- **हाशिम अमला** : 25 अक्टूबर, 2015 को भारत के खिलाफ खेलते हुए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के ओपनर हाशिम अमला ने एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 6000 रन (123वीं पारी में) बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले यह रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम था जिन्होंने 136 पारियों में 6000 रन बनाए थे।
- **जैक कैलिस** : 21 अक्टूबर, 2015 को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने दक्षिण अफ्रीका के आलराउंडर जैक कैलिस को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। उन्होंने ट्रेवर बोलिस की जगह ली।
- **अनिर्बान लाहिड़ी** : 21 अक्टूबर, 2015 को भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी को हाल में अपने शानदार प्रदर्शन के आधार पर 'मासिक हिल्टन एशियन टूर गोल्फर पुरस्कार' से नवाजा गया। विश्व के 39वें नंबर के गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान को यह पुरस्कार जून, 2015 से लेकर सितंबर, 2015 तक के प्रत्येक महीने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया।
- **वीरेंद्र सहवाग** : 20 अक्टूबर, 2015 को दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शुमार वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया। उन्होंने 104 टेस्ट मैचों में 8586 रन बनाये जिसमें 23 शतक व 32 अर्धशतक शामिल हैं। वे टेस्ट में दो तिहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। सहवाग ने 251 वनडे मैचों में 8273 रन बनाये जिसमें 15 शतक व 38 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 19टी-20 मैचों में 394 रन बनाये। वे वर्ष 2007 के टी-20 विश्व कप व वर्ष 2011 आईसीसी वनडे विश्व कप की विजेता टीम के सदस्य थे। सहवाग ने अपना आखिरी टेस्ट मैच मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अप्रैल 2009 में सहवाग को वर्ष 2008 में प्रदर्शन के लिए विजडन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6 दोहरे शतक भी लगाये हैं। टेस्ट क्रिकेट में 82.83 तथा वनडे क्रिकेट में 104.33 का उनका स्ट्राइक रेट उल्लेखनीय है।
- **युकी भांबरी** : 19 अक्टूबर, 2015 को जारी एटीपी रैंकिंग में भारत के डेविस कप स्टार युकी भांबरी को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली। वे 99वें स्थान पर पहुंच गए।
- **सारा टेलर** : 17 अक्टूबर, 2015 को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज सारा टेलर ने ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दन डिस्ट्रिक्ट्स की पुरुषों की टीम का हिस्सा बनकर ए ग्रेड मैच खेला। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
- **जहीर खान** : 15 अक्टूबर, 2015 को भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट तथा 200 एकदिवसीय मैचों में 282 विकेट लिये। जहीर खान ने अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी, 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तथा आखिरी एकदिवसीय मैच अगस्त, 2012 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था।
- **यूनिस खान** : 13 अक्टूबर, 2015 को पाकिस्तान के बल्लेबाज यूनिस खान पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा।
- **महेन्द्र सिंह धौनी** : 27 सितंबर, 2015 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को झारखंड सरकार ने राज्य के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया।
- **अंजिक्य रहाणे** : 18 सितंबर, 2015 को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) ने भारतीय बल्लेबाज अंजिक्य रहाणे को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भी सीसीआई की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई।
- **फ्लॉयड मेवेदर जूनियर** : 12 सितंबर, 2015 को अमेरिका के प्रसिद्ध मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर जूनियर ने अपना 49वां और अंतिम मुकाबला वेल्टरवेट विश्व चैंपियनशिप के लिए आंद्रे बर्टो को हराकर जीता। इसके साथ ही उन्होंने पेशेवर मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की।
- **वेन रूनी** : सितंबर, 2015 में इंग्लैंड फुटबाल टीम के कप्तान वेन रूनी इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल (50) करने वाले खिलाड़ी बने।
- **कुमार संगकारा** : 23 अगस्त, 2015 को श्रीलंका के बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भारत के खिलाफ कोलंबो में अंतिम टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अपनी अंतिम पारी में उन्होंने मात्र 18 रन बनाये। उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 57.40 की औसत से 12,400 रन बनाये तथा 404 वनडे मैचों में 41.98 की औसत से 14,234 रन बनाये। उन्होंने टेस्ट व वनडे कैरियर मिलाकर कुल 63 शतक लगाये।
- **दीपा करमाकर** : अगस्त, 2015 में भारत की दीपा करमाकर ने हिरोशिमा में आयोजित छठीं सीनियर एशियाई आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप में वार्ल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया।
- **अदिति चौहान** : अगस्त, 2015 में भारतीय महिला फुटबाल टीम की गोलकीपर अदिति चौहान के साथ इंग्लैंड के फुटबाल क्लब 'वेस्ट हैम' की महिला फुटबाल टीम ने करार किया। इसके साथ ही वे इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) के किसी शीर्ष फुटबाल क्लब से जुड़ने वाली प्रथम भारतीय फुटबाल महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
- **सेबास्टियन कोए** : 19 अगस्त, 2015 को ब्रिटेन के पूर्व ओलंपियन सेबास्टियन कोए को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (IAAF) का छठां अध्यक्ष चुना गया।
- **अनिर्बान लाहिड़ी** : 16 अगस्त, 2015 को अमेरिका में संपन्न पीजीए चैंपियनशिप में भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी अमेरिका के ब्रूक्स कोएप्का के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहे। किसी प्रमुख गोल्फ टूर्नामेंट के शीर्ष पांच में जगह बनाने वाले अनिर्बान प्रथम भारतीय गोल्फर हैं।
- **एबी डिविलियर्स** : अगस्त, 2015 में द. अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने सबसे कम (182वीं) पारियों में 8000 रन एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बनाये। इसके पहले यह रिकॉर्ड सौरव गांगुली के नाम था। जिन्होंनें 200 पारियों

में 8000 रन बनाये थे।

- **एमिली मारेस्मो** : 18 जुलाई, 2015 को पूर्व फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी एमिली मॉरेस्मो को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
- **हिकेन शाह** : 13 जुलाई, 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुंबई के रणजी खिलाड़ी हिकेन शाह को निलंबित कर दिया। उन्हें आईपीएल के दौरान साथी खिलाड़ी को भ्रष्टाचार की पेशकश के आरोप में निलंबित किया गया।
- **कैगिसो रबादा** : 10 जुलाई, 2015 को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा ने अपने पहले ही मैच में आठ ओवर में 16 रन देकर 6 विकेट लिए। यह वनडे इतिहास में किसी गेंदबाज का पहले मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रबादा दक्षिण अफ्रीका की ओर से वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज भी बने। पहले मैच में हैट्रिक लेने वाले वे दूसरे गेंदबाज बने।
- **क्रिस गेल** : 8 जुलाई, 2015 को वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल टी-20 में 8000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
- **मिताली राज** : 6 जुलाई, 2015 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी बनीं।
- **विजेंदर सिंह** : 29 जून, 2015 को ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने आईओएस स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट के जरिए क्वींस बैरी प्रमोशंस के साथ बहुवर्षीय प्रमोशनल करार किया जिसके तहत वे एक वर्ष में कम से कम 6 मुकाबले लड़ेंगे।
- **रजा हसन** : 25 मई, 2015 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोप टेस्ट में विफल रहने वाले बाएं हाथ के स्पिनर रजा हसन पर दो साल का प्रतिबंध लगाया।
- **सचिन तेंदुलकर** : जून, 2015 के अंत में घोषित एक ऑनलाइन सर्वे के परिणाम के तहत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को '21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी' चुना गया।
- **सतनाम सिंह** : 25 जून, 2015 को भारत के सतनाम सिंह अमेरिका की बॉस्केट बॉल लीग 'एनबीए' में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने।
- **सुनील छेत्री** : 16 जून, 2015 को सुनील छेत्री 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले भारत के पहले फुटबाल खिलाड़ी बने।
- **हैरिएट थॉम्पसन** : 1 जून, 2015 को 92 वर्षीय हैरिएट थॉम्पसन ने सैन डिएगो में आयोजित मैराथन में विश्व की सबसे अधिक उम्रदराज महिला धावक के रूप में भाग लेकर दौड़ पूरी करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
- **राफेल नडाल** : 1 मई, 2015 को स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को स्पेन में उत्कृष्ट कार्य के लिए <u>गोल्डन मेडल फॉर मेरिट</u> प्रदान किया गया। यह स्पेन का शीर्ष नागरिक सम्मान है।
- **लियम लिविंगस्टोन** : 20 अप्रैल, 2015 को लंकाशायर के 21 वर्षीय खिलाड़ी लियम लिविंगस्टोन ने एक क्लब मैच में 138 गेंदों में 350 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। लिविंगस्टोन ने 2008 में हैदराबाद के निखिलेश सुरेन्द्रन द्वारा बनाये गये 334 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
- **सानिया मिर्जा** : 12 अप्रैल, 2015 को डब्ल्यूटीए युगल रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनीं।
- **मेग लेनिंग** : 8 अप्रैल, 2015 को क्रिकेट का बाइबिल नाम से मशहूर इंग्लैंड की विजडन पत्रिका ने अपने 152वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग को 'विश्व की शीर्ष महिला क्रिकेटर' चुना। विजडन द्वारा पहली बार महिला खिलाड़ियों में शीर्ष खिलाड़ी घोषित की गई हैं।
- **कुमार संगकारा** : 8 अप्रैल, 2015 को ही श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा को विजडन क्रिकेटर एलमानेक ने वर्ष 2014 का दुनिया का शीर्ष (Leading) क्रिकेटर चुना। संगकारा को दूसरी बार विजडन ने दुनिया का शीर्ष क्रिकेटर चुना है।
- **कुमार संगकारा** : 8 मार्च, 2015 को श्रीलंका के बल्लेबाज कुमार संगकारा ने आईसीसी विश्व कप-2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए विश्व कप में लगातार तीन पारियों में शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही वे एकदिवसीय मैचों में 14000 रन बनाने वाले वे सचिन के बाद दूसरे खिलाड़ी भी बने। इसी मैच में तिलकरत्ने दिलशान ने लगातार सात गेंदों पर सात चौके लगाने के साथ एक ओवर में 6 चौके भी लगाये जो एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का रिकॉर्ड है।
- **साइना नेहवाल** : 7 मार्च, 2015 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल स्पेन की कैरोलिना मारिन से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में 21-16, 14-21, 7-21 से पराजित हो गईं। <u>साइना नेहवाल इस खिताब के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।</u>
- **मार्टिन क्रो** : 28 फरवरी, 2015 को न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्टिन क्रो को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि 22 फरवरी, 2015 को इस श्रेणी में भारत के <u>अनिल कुंबले</u> एवं ऑस्ट्रेलिया के <u>बैटी विल्सन</u> को भी शामिल किया गया था।
- **ए.बी. डिविलियर्स** : 26 फरवरी, 2015 को दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ए.बी. डिविलियर्स ने वर्ल्ड कप के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए वनडे के सबसे तेज 150 रन बनाए। उन्होंने 66 गेंदों में कुल 162 रन बनाए। इससे पूर्व उन्होंने 18 जनवरी, 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 31 गेंदों में शतक बनाकर सबसे कम गेंदों में शतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। डिविलियर्स ने अपनी इस पारी के दौरान मात्र 16 गेदों में अर्द्धशतक पूरा कर श्रीलंका के सनत जयसूर्या द्वारा 1996 में 17 गेदों में बनाए गए अब तक के सबसे तेज अर्द्धशतक का भी रिकॉर्ड तोड़ा था।
- **सुनील छेत्री** : 14 फरवरी, 2015 को भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने 2014 के सर्वश्रेष्ठ फुटबालर पुरस्कार से नवाजा।

खेल : विविध

- **पैराग्लाइडिंग विश्व कप** : 23 से 31 अक्टूबर, 2015 के मध्य हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन किया गया। यह पहला मौका है जब भारत के किसी राज्य ने पैराग्लाइडिंग विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी की।
- **वर्ष 2022 के एशियाई खेल** : 15 सितंबर, 2015 को एशियाई ओलंपिक परिषद ने वर्ष 2022 के (19वें) एशियाई खेलों की मेजबानी चीन के शहर हांगझू (Hangzhou) को सौंपने का निर्णय लिया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया में प्रस्तावित हैं।
- **वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक** : 31 जुलाई, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन के बीजिंग शहर को सौंप दी।
- **एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2017** : अक्टूबर, 2015 के अंत में फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स संघ की 83वीं परिषदीय बैठक के दौरान 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2017 को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित करने की घोषणा की गई। भारत ने इसके पहले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी वर्ष 1989 में नई दिल्ली में तथा वर्ष 2013 में पुणे में की थी।
- **आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में तीन खिलाड़ी आरोपमुक्त** : 25 जुलाई,

2015 को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भरतीय क्रिकेटर एस. श्रीसंत, अजित चंदीला और अंकित चह्वाण को आरोपमुक्त कर दिया।

- **फीफा ने कुवैत फुटबाल एसोसिएशन को प्रतिबंधित किया** : 16 अक्टूबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल संस्था फीफा (FIFA) ने कुवैत फुटबाल एसोसिएशन (KAF) को प्रतिबंधित करने की घोषणा की।
- **आईसीसी महिला टीमों की आधिकारिक रैंकिंग की शुरुआत** : 1 अक्टूबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों क्रमशः टेस्ट, एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एवं टी-20 के परिणामों को समान रूप से शामिल करके आईसीसी महिला टीमों की आधिकारिक रैंकिंग प्रदान की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम प्रथम, इंग्लैंड की द्वितीय, न्यूजीलैंड की तृतीय तथा भारत की महिला क्रिकेट टीम चौथे स्थान पर है। वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा आयरलैंड क्रमशः पांचवें, छठें, सातवें, आठवें, नौवें एवं दसवें स्थान पर हैं।
- **पैरालम्पिक खेल-2020 का प्रतीक चिह्न जारी** : 25 जुलाई, 2015 को जापान की राजधानी टोक्यो में वर्ष 2020 में होने वाले पैरालम्पिक खेलों के लिए प्रतीक चिह्न जारी किया गया। यह जापानी कलाकार केनजीरो सातों द्वारा तैयार किया गया है जो टोक्यो के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर 'टी' पर आधारित है।
- **अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन** : 24 जुलाई, 2015 को केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया। यह परिषद युवा मामले और खेल मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी। परिषद द्वारा दी गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। मंत्री स्तर का व्यक्ति परिषद का अध्यक्ष होगा।
- **भारतीय कलारीपयट्टू फेडरेशन को क्षेत्रीय खेल फेडरेशन का दर्जा** : सितंबर, 2015 में भारतीय कलारीपयट्टू फेडरेशन को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय खेल फेडरेशन का दर्जा दिया। कलारीपयट्टू, केरल व तमिलनाडु में खेले जाने वाला एक प्रकार का मार्शल आर्ट है।
- **भारतीय मुक्केबाजी परिषद का गठन** : 8 जुलाई, 2015 को भारत में पेशेवर मुक्केबाजी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय मुक्केबाजी परिषद (आईबीसी) का गठन किया गया। भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ के पूर्व महासचिव बिग्रेडियर मुरलीधरन राजा आईबीसी के पहले अध्यक्ष चुने गए।
- **मेवेदर से डब्ल्यूबीओ वेल्टरवेट खिताब छिना** : 7 जुलाई, 2015 को विश्व मुक्केबाजी संगठन ने फ्लायड मेवेदर से वेल्टरवेट खिताब छीन लिया जो उन्होंने मैनी पेकियाओ को हराकर जीता था।
- **एशिया का सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने वाला देश बना पाकिस्तान** : 21 जून, 2015 को गाले में श्रीलंका पर दस विकेट से जीत दर्ज करने के साथ ही पाकिस्तान एशिया का सबसे अधिक टेस्ट मैच जीतने वाला देश बन गया। पाकिस्तान की यह 390 टेस्ट मैचों में 123वीं जीत है। विश्व स्तर पर सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है जिसने 775 टेस्ट मैचों में 364 जीत दर्ज की है।
- **आईटीटीएफ सबसे बड़ी खेल संस्था बनी** : 29 अप्रैल, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय टेबलटेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्था बन गई। आईटीटीएफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संघों की संख्या 222 तक पहुंच गई है। अंतिम दो सदस्यता लेने वाले सदस्य देश क्रमशः साओ टोम एंड प्रिंसेप तथा दक्षिणी सूडान हैं।
- **डोपिंग रोधी निर्देश उल्लंघन (एडीआरबी) रिपोर्ट, 2013** : 15 जून, 2015 को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने डोपिंग रोधी निर्देश उल्लंघन (एडीआरबी) रिपोर्ट, 2013 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में रूस में सबसे अधिक 212 डोपिंग के मामले दर्ज किए गए। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर तुर्की (155) तथा तीसरे स्थान पर भारत (91) है।
- **शाहरुख खान ने सीपीएल में टीम खरीदी** : 9 जून, 2015 को कोलकाता नाइट राइडर्स (के.के.आर.) के मालिक शाहरुख खान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) की टी-20 टीम त्रिनिदाद एवं टोबैगो (T&T) की फ्रेंचाइजी खरीदी।
- **फोर्ब्स की धनी खिलाड़ियों की सूची में महेंद्र सिंह धौनी** : जून, 2015 के प्रथम सप्ताह में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के 100 सबसे धनी खिलाड़ियों की सूची जारी की। इसमें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी 23वें स्थान पर हैं। शीर्ष स्थान पर मुक्केबाज फ्लायड मेवेदर हैं। इस सूची में शामिल होने वाले धौनी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं।
- **आईसीसी की विश्व कप एकादश टीम घोषित** : 30 मार्च, 2015 को आईसीसी ने बेंडन मैकुलम की अगुवाई में आईसीसी विश्व कप एकादश की टीम घोषित की जिसमें किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है। टीम में न्यूजीलैंड के पांच, ऑस्ट्रेलिया के तीन, दक्षिण अफ्रीका के दो तथा श्रीलंका के एक बल्लेबाज को जगह मिली। 12वें खिलाड़ी के रूप में जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर को शामिल किया गया। टीम क्रमशः- मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड), ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड-कप्तान), कुमार संगकारा (श्रीलंका-विकेटकीपर), स्टीवन स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), एबी डिविलियर्स (द. अफ्रीका), कोरे एंडरसन (न्यूजीलैंड), डेनियल विटोरी (न्यूजीलैंड), मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया), ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड), मोर्ने मॉर्कल (द. अफ्रीका) और ब्रेंडन टेलर (जिम्बाब्वे, 12वें खिलाड़ी)।
- **ओलंपिक और पैराओलंपिक खेलों के शुभंकर घोषित** : 14 दिसंबर, 2014 को वर्ष 2016 में रियो डि जेनेरियो (ब्राजील) में होने वाले ओलंपिक एवं पैराओलंपिक खेलों के शुभंकर घोषित किए गए जिनके नाम क्रमशः <u>विनीसिअस</u> (Vinicious) तथा <u>टॉम</u> (Tom) हैं।

खेल पुरस्कार

- **यूरोपीय गोल्डेन बूट पुरस्कार** : 13 अक्टूबर, 2015 को पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरोप के घरेलू सत्र 2014-15 में सर्वाधिक गोल करने के लिए चौथी बार यूरोपियन गोल्डेन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे चार बार यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबालर हैं।
- **राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2015** : 29 अगस्त, 2015 को खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 'राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2015' का वितरण किया। वर्ष 2015 का '<u>राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार</u>' टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत उन्हें एक पदक, प्रमाणपत्र एवं 7.5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई।
- वर्ष 2015 के <u>द्रोणाचार्य पुरस्कार</u> क्रमशः नवल सिंह (एथलेटिक्स), अनूप सिंह (कुश्ती), हरबंश सिंह (एथलेटिक्स-लाइफटाइम), स्वतंत्रराज सिंह (मुक्केबाजी-लाइफटाइम) तथा निहार अमीन (तैराकी-लाइफटाइम) को प्रदान किए गए। वर्ष 2015 के <u>ध्यानचंद पुरस्कार</u> क्रमशः रोमियो जेम्स (हॉकी), शिव प्रकाश मिश्रा (टेनिस) तथा टी.पी.पी. नायर (बॉलीबॉल) को प्रदान किए गए।
- इसके अतिरिक्त 17 खिलाड़ियों को <u>अर्जुन पुरस्कार</u> के तहत अर्जुन की प्रतिमा, प्रमाणपत्र एवं 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इन खिलाड़ियों के नाम क्रमशः नायब सूबेदार संदीप कुमार (तीरंदाजी), एम. आर. पूवम्मा (एथलेटिक्स), के. श्रीकांत (बैडमिंटन), मंदीप जांगड़ा (बॉक्सिंग), रोहित शर्मा (क्रिकेट), दीपा कर्माकर (जिम्नास्टिक), पी. आर. श्रीजेश (हॉकी), मंजीत चिल्लर (कबड्डी), अभिलाषा शशिकांत म्हात्रे (कबड्डी), स्वर्ण सिंह (नौकायन), अनूप कुमार मामा (रोलर स्केटिंग), जीतू राय (निशानेबाजी), एस. सतीश कुमार (भारोत्तोलन), बजरंग (कुश्ती), बबिता कुमारी (कुश्ती), वाई. सनाथोई देवी (वुशु) एवं शरथ एम. गायकवाड़ (पैरा स्विमिंग) हैं।

- **मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी :** 29 अगस्त (खेल दिवस), 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2014-2015 के लिए 'मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी' पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला को (लगातार चौथे वर्ष) प्रदान की गई।
- **लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार-2015 :** 15 अप्रैल, 2015 को चीन के शंघाई में सात श्रेणियों में वर्ष 2015 का लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार दिया गया।

  —लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर - नोवाक जोकोविच (सर्बिया)

  —लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर-गेंजेबी डिबाबा (इथियोपिया की धाविका)

  —लॉरिअस वर्ल्डटीम ऑफ द ईयर - जर्मनी पुरुष फुटबाल टीम

  —लॉरिअस असाधारण उपलब्धि पुरस्कार- ली ना (चीन)
- **सिएट इंटरनेशनल क्रिकेट पुरस्कार 2014-15 :** 25 मई, 2015 को मुंबई में 'सिएट इंटरनेशनल क्रिकेट पुरस्कार 2014-15' प्रदान किये गये।

  —पापुलर च्वाइस अवॉर्ड - कीरोन पोलार्ड

  —वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज - हाशिम अमला

  —सिएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर- कुमार संगकारा

  —लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड - कपिल देव

  —सिएट इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर- अंजिक्य रहाणे

  —टी 20 प्लेयर ऑफ द ईयर - ड्वेन ब्रावो

  —वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज- रंगना हेराथ
- **फीफा पुरस्कार** : 12 जनवरी, 2015 को ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड) में प्रदत्त—
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (पुरुष) : क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल/रियल मैड्रिड)
  - ➔ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (महिला) : मैदिने केस्लर (जर्मनी/फॉक्सबर्ग)
- **उ. प्र. राज्य खेल पुरस्कार** : 8 अप्रैल, 2015 को उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित राज्य खेल पुरस्कार 'लक्ष्मण' व 'रानी लक्ष्मीबाई' पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष अनुसार खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं—
  - ➔ वर्ष 2010-11 : देवेश कुमार-जिम्नास्टिक (इलाहाबाद), हिमांशु तिवारी-तैराकी (लखनऊ), सुधा सिंह-एथलेटिक्स (रायबरेली)।
  - ➔ वर्ष 2011-12 : चंद्रोदय नारायण सिंह-एथलेटिक्स (इलाहाबाद), श्रद्धा दीक्षित-ताइक्वांडो (बलरामपुर), वेटरन : रामआसरे यादव-कुश्ती (देवरिया)।
  - ➔ वर्ष 2012-13 : अनिरुद्ध सिंह-शूटिंग (संभल), रंजना गुप्ता-शूटिंग (कानपुर), अस्थवी अस्थाना-घुड़सवारी (लखनऊ), रविकांत मिश्रा-टेनिस बॉल क्रिकेट-फतेहपुर। वेटरन : एमपी सिंह-हॉकी (मेरठ), पन्नेलाल यादव-कुश्ती (गोरखपुर)।
  - ➔ वर्ष 2013-14 : इंदु गुप्ता-हैंडबॉल (लखनऊ), अतुलश्री पटेल-साफ्ट टेनिस (इलाहाबाद), मेघा सारस्वत-सॉफ्ट टेनिस (लखनऊ), तुषार खांडेकर-हॉकी (झांसी), अजीत कुमार सिंह-शूटिंग (वाराणसी)। वेटरन : शकील अहमद खान-हॉकी (इटावा)।
- **हॉकी इंडिया पुरस्कार** : 28 मार्च, 2015 को हॉकी इंडिया ने अपने प्रथम वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए। तीन बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम (लंदन-1948, हेलसिंकी-1952, मेलबर्न-1956) के सदस्य बलबीर सिंह सीनियर को हॉकी इंडिया ने मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी खिलाड़ी का ध्रुव पुरस्कार क्रमशः पुरुष हॉकी टीम के डिफेंडर बीरेंद्र लाकड़ा और महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर वंदना कटारिया को मिला।

आगामी खेल प्रतियोगिताएं

खेल स्पर्धाएं	आयोजन स्थल	वर्ष
ओलंपिक खेल (31वें)	रियो डि जेनेरो (ब्राजील)	2016
ओलंपिक खेल (32वें)	टोकियो (जापान)	2020
शीतकालीन ओलंपिक खेल (23वें)	दक्षिण कोरिया	2018
राष्ट्रमंडल खेल (21वें)	गोल्डकोस्ट सिटी (ऑस्ट्रेलिया)	2018
36वें राष्ट्रीय खेल	गोवा	2016
37वें राष्ट्रीय खेल	छत्तीसगढ़	2018
18वें एशियाई खेल	जकार्ता (इंडोनेशिया)	2018
विश्व कप फुटबाल (21वें)	रूस	2018
विश्व कप फुटबाल (22वें)	कतर	2022
यूरो कप फुटबाल	फ्रांस	2016
कोपा अमेरिका कप	अमेरिका	2016
U-17 फुटबाल विश्व कप	भारत	2017
14वां पुरुष विश्व कप हॉकी	भारत	2018
14वां महिला विश्व कप हॉकी	लंदन (इंग्लैंड)	2018
6ठां आईसीसी टी-20 विश्व कप	भारत मार्च-अप्रैल,	2016
12वां एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप	इंग्लैंड-वेल्स	2019
13वां एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप	भारत	2023
चैंपियंस ट्रॉफी (क्रिकेट)	इंग्लैंड	2017
एकदिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप	इंग्लैंड	2017
टी-20 महिला विश्व कप	वेस्टइंडीज	2018
1st टेस्ट चैंपियनशिप	इंग्लैंड	2017
2nd टेस्ट चैंपियनशिप	भारत	2021

- **फीफा महिला विश्व कप, 2019** : फ्रांस।
- **फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप, 2018** : फ्रांस।
- **हॉकी इंडिया वर्ल्ड लीग, 2015** : 28 नवंबर से 6 दिसंबर, 2015 के मध्य रायपुर (छत्तीसगढ़) में।

◆◆◆